



## FOREWORD

The University of Rajasthan has very recently revised its Syllabus for the B. Ed. examination, as a consequence of which its syllabus of the paper on "Problems of Indian Education" has been very considerably amplified. The present book, entitled "Problems of Indian Education", is a commendable effort by Shri Ratan Lal Sharma, Head of a department in the Jawaharlal Nehru Teachers Training College, Kota, to bring under one volume the treatment of various problems of Indian Education, keeping in view the requirements of Rajasthan University syllabus.

The treatment of most of the "Problems" is detailed and painstaking. While it fully meets the requirements of the Rajasthan University syllabus, its comprehensive sweep covers almost all the Problems one has to face in the vast field of Indian education. Even such topical problems as the "Language problem" and the "problem of emotional integration" find a place in it.

Apart from its patent usefulness for teacher's training institutions in Rajasthan, I feel it will be found to be useful in a much wider area. It is notable contribution to the literature on the subject and I hope it will be well received amongst educationists and workers in the sphere of teacher education.

(Kamala Kant Chaturvedi

M. A., T. Dip (London), B. Ed. (Edinburgh)

Principal,

Jawaharlal Nehru Teachers Training,

College, Kota. (Rajasthan)

Dated Kota,

December 18, 1968.

## प्राकथन

प्रस्तुत पुस्तक पाठकों के समक्ष है। राष्ट्र-भाषा में पुस्तक लिखने का यह दूसरा प्रयास है। मुझे आना ही नहीं अनिष्ट विस्वास है कि यह पुस्तक विद्यालयों की आवश्यकताओं को पूर्ति करेगी।

भारतीय शिक्षा की अनेकों समस्याएँ हैं, प्रायः सभी समस्याओं को इस पुस्तक में समाहित करने का प्रयास किया गया है। सामान्यतया समस्याओं का प्रारम्भ पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से होता है और वस्तुतः पुस्तक का प्रारम्भ भी इसी शैक्षिक समस्या से किया गया है। पुस्तक में कुल बाईस अध्याय हैं। सभी अध्यायों को लिखने में अनेकों सदर्थ में पुस्तकों की सहायता ली गई है।

इस पुस्तक को लिखने में एक वर्ष से अधिक समय लगा है और समस्त समस्याओं को भारतीय परिघेन में सामयिक बनाने का पूर्ण प्रयास किया गया है।

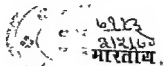
मैं उन सभी भारतीय एवं विदेशी शिक्षा शास्त्रियों का हृदय से आभारी हूँ जिनके अमूल्य विचारों को प्रस्तुत पुस्तक में आवश्यकतानुसार स्थान दिया गया है। इस पुस्तक को सम्पूर्ण करने में मेरे सहयोगी प्राध्यापकों ने जिस प्रकार से मेरा उत्साहवर्धन किया है, उसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। इस पुस्तक का प्रारम्भ मेरे मित्र श्री जितेंद्रसिंह नेगी की सूझ का स्रोतक है अतः इस पुस्तक में उनका सहयोग भी विवक्षनीय है। प्रकाशक श्री चौधमल जैन, जिनके अथक् प्रयास से यह पुस्तक प्रकाशित हो सकी है, उनका आभार प्रदर्शन करना भी आवश्यक है।

अन्त में मैं अपनी पत्नी श्रीमती सन्तोष शर्मा का भी आभारी हूँ। जिन्होंने समय-समय पर पाठ्यलिपि को पढ़कर महत्वपूर्ण सुझाव दिये और पुस्तक को यथाशीघ्र पूर्ण करने के लिए सदैव प्रोत्साहित किया।

पाठकों के सुभावात्मक विचार सादर आमन्त्रित हैं।

रत्नलाल शर्मा

जवाहरलाल नेहरू शिक्षक  
प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोटा  
मंगलवार 2, दिसम्बर 2069



शिक्षा की समस्याएँ

*PROBLEMS  
OF  
INDIAN EDUCATION*

— १५५१



12/11/21

## विषय-सूची

पृ० सं०

### पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

1-18

#### Pre-Primary Education

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का अर्थ एवं क्षेत्र-2, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य-2, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा क्यों ? -5, ऐतिहासिक विकास-7, पूर्व-प्राथमिक शालाओं के प्रकार-9, माण्डेसरी शालाएँ, किण्डर गार्टन, पूर्व-बैसिक शालाएँ, विदेशों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा-12, रूस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, आस्ट्रेलिया, नीदरलैंडस्, भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा-14, समस्याएँ-प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की कमी, प्रशिक्षणालयों की कमी, बाल-साहित्य की कमी, कीठारी आयोग के सुझाव-16, एन्व-सूची-18.

#### सार्वभौमिक शिक्षा और सार्वलौकिकता

19-46

#### Education & Universalisation

क्षेत्र-20, ऐतिहासिक विकास-21,

1857-1882,

1911-

शिक्षा प्राप्ति तक,

जना की समाप्ति

इतिहास-25, अनिवार्य

7, ऐतिहासिक सुविधाओं में

पहली कक्षा में प्रवेश,

की शिक्षा, अवस्यय और



सक माध्यमिक शिक्षा का विकास-७१, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा का विकास-७१, केन्द्रीय शिक्षा समीक्षक समितिके (१९४७), साधारण शिक्षा (१९४८), विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (१९४८-४९), माध्यमिक शिक्षा आयोग (१९५२-५३), शिक्षा आयोग (१९६४-६६), उच्च-मूची-७४, विश्वविद्यालय प्रान्त-७५

छ:

माध्यमिक शिक्षा आयोग

७६-१

Secondary Education Commission

आयोग का विवरण-७७, आयोग की विचारों और सुझाव-७८, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र, माध्यमिक शिक्षा का नव अवस्था बन, भाषाओं का अध्ययन, माध्यमिक विद्यालयों का वास्तविक, माध्यमिक स्तर पर वास्तविक-गुण, मनीषीय विज्ञान विषयों, विषय निर्माण की शिक्षा, माध्यमिक छात्राओं में मान्यता और वसति, माध्यमिक स्तर पर परीक्षा और सुधार, अध्यापकों की स्थिति, अध्यापकों का प्रशिक्षण, माध्यमिक शिक्षा का प्रसारण, माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा व्यवस्था, माध्यमिक शिक्षा आयोग का आलोचनात्मक सुझाव-११२, उच्च-मूची-११५, विश्वविद्यालय प्रान्त-११६.

छान



माध्यमिक शिक्षा की प्रगति और समस्याएँ

११७-१

Progress &amp; Problems of Secondary Education

माध्यमिक शिक्षा की प्रगति (१९४७-६८)-११७, माध्यमिक शिक्षा की आगे प्रगति (१९६९-१९८६) हेतु सुझाव-१२४, माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता-१२९, माध्यमिक शिक्षा की समस्याएँ एवं समाधान-१३१, वास्तविक, अनुमानित हीनता, परीक्षा प्रणाली, प्रशिक्षित अध्यापक, एकता का अभाव, राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा की विशेषताएँ-१४२, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता पर बल, शिक्षा द्वारा प्रशान्ति-प्रधानताओं का विकास, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता का विकास, उच्च मूची-



पाठ्यक्रम का विभिन्नोकरण  
Diversification of Curriculum

147-158

पाठ्यक्रम के विभिन्नोकरण हेतु प्रदान-149, पाठ्यक्रम का विभिन्नोकरण-सूची-151, पाठ्यक्रम के विभिन्नोकरण के पक्ष में विचार-156, ग्रन्थ-सूची-157, विश्वविद्यालय प्रश्न-158.

माध्यमिक स्तर पर निर्देशन व समुपदेशन, पाठ्य- 150-176  
पुस्तकें, शिक्षक निर्देशिकाएँ और शिक्षण सामग्री

Guidance & Counselling, Text Books,  
Teachers, Guides and Instructional  
Material at Secondary Stage

निर्देशन व समुपदेशन-160, निर्देशन सेवाओं की वर्तमान स्थिति-161, माध्यमिक शिक्षा आयोग के निर्देशन एवं समुपदेशन हेतु सुझाव, शिक्षा आयोग (1964-66) के निर्देशन और समुपदेशन हेतु सुझाव, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षक निर्देश पुस्तकें और शिक्षण सामग्री-166, शिक्षा आयोग के सुझाव, ग्रन्थ सूची-174, विश्वविद्यालय प्रश्न-175.

परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता 177-196  
और मूल्यांकन की नवीन विधियाँ

Need for Reform in Examination System  
& New Methods of Evaluation.

वर्तमान परीक्षा-प्रणाली के दोष-180, परीक्षा पद्धति में सुधार की आवश्यकता-184, मूल्यांकन का क्षेत्र-185, मूल्यांकन की नवीन विधियाँ-188, माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशें-191, शिक्षा आयोग (1964-66) की सिफारिशें-192, ग्रन्थ सूची-194, विश्वविद्यालय प्रश्न-195.

भारत

## भारतवर्ष में उच्च (विश्वविद्यालय) शिक्षा का विस्तार

197-217

### Expansion of Higher (University) Education in India

प्राचीन काल में उच्च शिक्षा-198, मध्यकाल में उच्च शिक्षा-199, ब्रिटिश काल में उच्च शिक्षा-200, प्रारम्भिक ब्रिटिश शासन से 1857 तक, सन् 1857-1917 तक, सन् 1917 से 1947 तक, स्वतन्त्र भारत में उच्च शिक्षा-205, भारत में विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा का प्रसार, केन्द्रीय विश्व-विद्यालय, ग्रामीण उच्च शिक्षा, ग्रन्थ-सूची-217

भारत

## उच्च शिक्षा की समस्याएँ

218-251

### Problems of Higher Education:

अध्यापन की समस्या-220, समस्या का समाधान, कोटारी आयोग के सुझाव, स्तर की समस्या-229, स्तर के विराट्ट के कारण-231, समान प्रवेश नीति का अभाव, बारह वर्षीय विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था, विश्वविद्यालयों में शिक्षण सुविधाओं की कमी, अध्यापन विद्या का अवांछनीय स्वरूप, विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनेक परीक्षा पद्धतियाँ, अच्छे स्तर हेतु सुझाव-238, अनुशासन और सामाजिक समायोजन की समस्या-245, अनुशासन हीनता और सामाजिक कुसमा-योजन के कारण-245, समस्या का समाधान-248, ग्रन्थ-सूची-250, विश्वविद्यालय प्रश्न-251.

भारत

## अध्यापक शिक्षा

252-287

### Teacher Education

अध्यापक शिक्षा की परिवर्तित धारणा-254, धारणा में परिवर्तन के कारण, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अध्यापक शिक्षा-257, शाला अध्यापकों की योग्यताएँ, अध्यापकों की संस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, शिक्षक प्रशिक्षण शालाएँ, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, विभिन्न स्तरों के लिए अध्यापकों की

हेतु प्रशिक्षण, प्राथमिक स्तर हेतु प्रशिक्षण विद्यालय, माध्यमिक स्तर हेतु प्रशिक्षण विद्यालय, शिक्षा के क्षेत्रों में महाविद्यालय, स्नातकोत्तर प्रशिक्षण महाविद्यालय, समाकलन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, विशेष प्रशिक्षण केन्द्र, सेवाकालीन अभ्यापक शिक्षा-274, (अ) सेवाकालीन अभ्यापक शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य-274, व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि, छैदिकताओं की प्राप्ति, नवीन ज्ञान की सम्भावनाएँ, (ब) शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए सेवाकालीन शिक्षा-276, प्राथमिक क्षात्रा के अभ्यापक और सेवाकालीन शिक्षा, माध्यमिक क्षात्रा के अभ्यापकों की सेवाकालीन शिक्षा, उच्च शिक्षा स्तर के अभ्यापकों की सेवाकालीन शिक्षा, अभ्यापक शिक्षा की समस्याएँ और समाधान-278, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और स्कूल कार्य में सम्बन्ध विहीनता-279, अभ्यापकों का सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक स्तर-281, अभ्यापकों के स्तर को विकसित करने की आवश्यकता, भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशें, वेतन क्रम, पदोन्नति की आवश्यकता, सेवा निवृत्ति लाभ धन्य-सूची-280, विश्वविद्यालय प्रश्न-287

और

प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा

288-311

Technical and Vocational Education

प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के विद्योत और उद्देश्य-290, मानवीय धन की महत्ता, पारिषिक एवं मान-मिक दोषपूर्ण व्यक्तियों की सहजता करना, समाज के परि-वर्तित रूप में तकनीकी ज्ञान आवश्यक, स्वतंत्र भारत में प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा-291, विभिन्न मायोग और प्रारिषिक एवं व्यावसायिक शिक्षा, प्रारिषिक शिक्षा का प्रसार, व्यावसायिक संस्थाएँ और उनके प्राविधिक शिक्षा हेतु महत्ता-296, (अ) व्यावसायिक और प्राविधिक संस्थाएँ और उनके कार्यक्रम-298, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, शिल्पोद्योग प्रदान करने वाली संस्थाएँ,

शिरी प्रदान करने वाली संस्थाएँ, स्नातकोत्तर और अनु-  
संधान प्रदान करने वाली संस्थाएँ, भारतीय शिल्प विज्ञान  
संस्थान और उनके पाठ्य विषय, विज्ञान मन्दिर, (ब) प्रावि-  
धिक संस्थाओं का प्रशासन-298, अखिल भारतीय तकनीकी  
शिक्षा परिषद् प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा प्रशासन  
हेतु कोठारी आयोग के सुझाव, प्राविधिक और व्यावसायिक  
✓ शिक्षा की समस्याएँ-299, मानव शक्ति का उपयोग, प्रावि-  
धिक और व्यावसायिक शिक्षा में भिन्न व्यवस्थाओं की कमी  
व्यावहारिक प्रशिक्षण में उद्योगों के सहयोग की कमी,  
अध्यापकों की समस्याएँ, पाठ्य पुस्तकों का प्रभाव, उत्कृष्टतर  
माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की कमी, राज्यों में  
पारस्परिक सहयोग की कमी, अनुसंधान की कमी, सैद्धान्तिक  
और व्यावहारिक शिक्षा में असंतुलन, विदेशों में प्राविधिक  
शिक्षा-305, जर्मनी में प्राविधिक शिक्षा-305, प्राविधिक  
शिक्षा व्यवस्था, व्यावसायिक निर्देशन की सुविधाएँ, रूस में  
प्राविधिक शिक्षा-307, प्राथमिक व्यावसायिक प्रशिक्षण,  
माध्यमिक व्यावसायिक प्रशिक्षण, टेक्नीकल, ग्रन्थ सूची-309  
विश्वविद्यालय प्रश्न-310,

समाज शिक्षा की परिवर्तित धारणा-315, प्रौढ़ शिक्षा का  
अर्थ, प्रौढ़ शिक्षा की नवीन धारणा, समाज शिक्षा का अर्थ,  
समाज शिक्षा क्यों, प्रौढ़ साक्षरता, समाज शिक्षा के लक्ष्य  
एवं उद्देश्य-323 व्यावसायिक क्षमता का विकास, सामा-  
जिक जीवन का विकास, मनोरंजनात्मक अभिवृत्ति का  
विकास, आत्म विकास की सुविधाएँ प्रदान करना, राष्ट्रीय  
स्रोतों की सुरक्षा और उन्नति करना, प्रौढ़ पाठ्यक्रम के लक्ष्य  
-324, समाज शिक्षा की समस्याएँ-325, प्रौढ़ों की शिक्षा  
का संगठन, कोठारी आयोग के सुझाव, नव-साक्षरों के लिए

साक्षरता का उत्थान, पुनः निरक्षरता की ओर, शिक्षण विधियों, कार्यवर्तियों और उनके प्रतिष्ठान का अभाव, महिलाओं की निरक्षरता की समस्या, ग्रन्थसूची-331, विश्व विद्यालय प्रश्न-332

नारी शिक्षा की आवश्यकता-334, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व नारी शिक्षा का प्रसार-335, प्रथम काल 1813 से 1881 तक, द्वितीय काल 1882 से 1921 तक, तृतीय काल 1922 से 1947 तक, स्वतंत्रता के पश्चात् नारी शिक्षा का प्रसार-337, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) और नारी शिक्षा, राष्ट्रीय नारी शिक्षा समिति (1948), राष्ट्रीय नारी शिक्षा परिषद (1950), कोटारी आयोग (1961-66) और नारी शिक्षा, राजस्थान में नारी शिक्षा-342, नारी शिक्षा की समस्याएँ और समाधान-343, अनारम्भक परम्परागत दृष्टिकोण, अतिशिथ जनसंख्या, निधनता, पुरुष-वाहुयजन का अभाव, अध्यापिकाओं का अभाव, दीर्घपूर्ण शिक्षा प्रसारण, ग्रन्थसूची-347 विश्वविद्यालय प्रश्न 348.

भाषा-एक समस्या-351, शिक्षा का माध्यम-ऐतिहासिक दृष्टि-भूमि-352, शिक्षा माध्यम के प्रारम्भिक प्रयास (1813-33) और भाषा, अंग्रेजी के लिए साठे मैकाले प्रयास, बुद्ध का घोषणा पत्र और शिक्षा का माध्यम, भारतीय शिक्षा आयोग (ह्यूडर कमिशन) और माध्यम, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (1902) और भाषा, राष्ट्रीय आन्दोलन और भाषा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भाषा-356,

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग(1948-49), माध्यमिक शिक्षा शिक्षा आयोग (1952-53)-358 केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सुझाव-359, भावनात्मक एकता समिते (1961) और भाषा, राष्ट्रीय एकता समिति (1962) और भाषा, शिक्षा आयोग (1964-66) और भाषा, प्रत्येक भाषा की समयावधि, भारत में भाषाओं की स्थिति-362, त्रिभाषी सूत्र और उसके कार्यान्वयन में कठिनाई-364, ऐतिहासिक भार, मनोवैज्ञानिक हल, अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक, हिन्दी भाषी क्षेत्रों पर आवश्यक भार, हिन्दी भाषी क्षेत्रों में व्यावहारिक कठिनाईयाँ, अंग्रेजी का स्थान-367, माध्यमिक शिक्षा आयोग और अंग्रेजी, शिक्षा आयोग और अंग्रेजी, ग्रन्थ सूची-371, विश्वविद्यालय प्रश्न-372.

प्रकार

## पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण

373-392

### Nationalization of Text Books

पाठ्य-पुस्तकों का महत्व-375, पाठ्य-पुस्तकों के दोष-376 मुद्रण दोष, मोक्षित चित्रों का अभाव, प्रकाशकों की लोभी प्रवृत्ति, अवांछनीय शब्दावली का प्रयोग, विषय-वस्तु से सम्बन्धित दोष, पाठ्य पुस्तकों के सुधार हेतु सुझाव-377, भाषाई नरेशदेव समिति प्रतिवेदन (1953), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953) के सुझाव, सुझावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन, कोठारी आयोग (1966) के सुझाव, आलोचनात्मक मूल्यांकन, पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण क्यों ?-383, पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न समस्याएँ-385, प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्तों के विच्छेद, राजनैतिक प्रचार की सम्भावना, प्रकाशन से विच्छेद, वितरण की समस्या, राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के मूल्य में अधिभार, लेखकों पर बुरा प्रभाव, राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों के सुधार हेतु सुझाव-387, राजस्थान में पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण-388, पत्रिका पाठ्य-पुस्तक समिति, राष्ट्रीयकरण बोर्ड, अन्य व्यवस्थाएँ, निष्कर्ष,-389, ग्रन्थ-सूची-391, विश्वविद्यालय प्रश्न-392.

[illegible]

श्री १०० राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की समस्याएँ 410-418  
Education & Problem of National Development  
पुनर्निर्माण की समस्याएँ—412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 118

विमान की लक्ष्यार्थ—412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

विभाग की समीक्षाएँ—412, राज्य शासकीय मे  
र, आर्थिक शिक्षा और औद्योगिक-व्यवस्था,  
राष्ट्रीय एकात्मता, राजनैतिक हस्त, समीक्षाओं  
शिक्षा आयोग के सुझाव—418, विज्ञान की  
न, कार्यशुभव, स्वास्थ्यविचार, ग्राम-सुखी

एन सी ई आर  
National Indian Education

ent Indian Education

419-433

उद्देश्य एवं आग्रह—  
निर्माण, व्यवस्था

का विकास, सामाजिक भावनाओं का विकास, सांस्कृतिक  
 मूल्यों का प्रसार, शिक्षा की विशेषताएँ—424, तर्क और  
 साधना का प्रतीक, सर्वांग विकास, मुकुल प्रणाली, शिष्य  
 गुरु सम्बन्ध, नि गुरु शिक्षा, स्त्री शिक्षा, शिक्षा में विभिन्न  
 चरण—425, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, मुख्य शिक्षा  
 केन्द्र और विश्वविद्यालय—427, तकशिक्षा, मातृशिक्षा विश्व-  
 विद्यालय, जगहला शिक्षा

विश्वविद्यालय, नदिया विश्वविद्यालय, ग्रन्थ-सूची—432

विश्वविद्यालय प्रश्न—433

✓ इंग्लैण्ड अमेरिका और रूस में शिक्षा

434454

Education in England, America, Russia

इंग्लैण्ड में शिक्षा—436 प्राथमिक शिक्षा का ऐतिहासिक  
 विकास—437, सर जैम्स ब्राह्म विल, म्यू कास्टिल आयोग  
 (1861), फोर्सेटर अधिनियम (1870), नास कमीशन  
 (1888), शिक्षा अधिनियम (1902), फिशर अधिनियम  
 (1918), हैरो आयोग (1926), स्लेम्स प्रतिवेदन (1938),  
 शिक्षा अधिनियम (1944), प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य—  
 439, माध्यमिक शिक्षा का ऐतिहासिक विकास—439,  
 ब्राह्म आयोग (1894-95), माध्यमिक शिक्षा और भण्डूरी  
 दलीय सरकार (1924), हैरो प्रतिवेदन (1926), नारबुड  
 आयोग (1943), शिक्षा अधिनियम (1944), माध्यमिक  
 शिक्षा की वर्तमान स्थिति—441, उच्च शिक्षा—442, अधिम  
 शिक्षा का ऐतिहासिक पर्यावलोकन, विश्वविद्यालयों का  
 स्वरूप, अमेरिका में शिक्षा—443 प्राथमिक शिक्षा—443,



माध्यमिक शिक्षा-444, पाठ्यक्रम के अनुसार सामग्री 4  
 वर्गीकरण, उच्च-शिक्षा-446, उच्च शिक्षा का ऐतिहासिक  
 विकास, उच्च शिक्षा के उद्देश्य एवं मूल्य, उच्च शि-  
 प्रदान करने वाली संस्थाएँ, उच्च शिक्षा का प्रकार, उच्च शि-  
 शिक्षा-448, उच्च शिक्षा का ऐतिहासिक विकास-449  
 सन् 1917 से वर्तमान समय तक, शिक्षा का मूल्य-450,  
 शिक्षा के विभिन्न स्तर-450, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक  
 शिक्षा, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा की प्रगति,  
 प्राथमिक-शिक्षा-454 ।

**अध्याय एक**  
**Chapter One**  
**पूर्व प्राथमिक शिक्षा**  
**Pre-Primary Education**  
**अध्याय बिन्दु**  
**Learning Points**

- 1.01 पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का अर्थ एवं क्षेत्र  
 (Meaning and Scope of Pre-Primary Education)
- 1.02 पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य  
 (Aims and Objectives of Pre-Primary Education)
  1. यू.एस.आर. के मतानुसार
  2. कोठारी आयोग (1964-66) के अनुसार
- 1.03 पूर्व-प्राथमिक शिक्षा क्यों ?  
 (Why Pre-Primary Education ? )
- 1.04 ऐतिहासिक विकास  
 (Historical Development)
- 1.05 पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के प्रकार  
 (Kinda of Pre-Primary Schools)
- 1.06 विदेशों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा  
 (Pre-Primary Education in Foreign Countries)
- 1.07 भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा  
 (Pre-Primary Education in India)
- 1.08 पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु कोठारी आयोग की सिफारिशें  
 (Recommendations of Kothari Commission for the  
 Development of Pre-Primary Education)

## पूर्व प्राथमिक शिक्षा Pre-Primary Education

बालकों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है। यदि कोई वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय तो हम शिक्षा का मनुष्य के अन्तर्गत बालक के दार्शनिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक विकास के लिए विद्यमान आवश्यक है। 3 वर्ष से पूर्व का समय ही ऐसा समय है जब हम बालक के अन्तर्गत बालक के व्यक्तित्व को वांछित अनुभवों से द्वारा विविध कर सकते हैं। बड़ी-बड़ी हमारे देश का प्रत्येक सामान्य परिवार बालक के लिए उच्च पाठ्यक्रम का अध्ययन करने में सक्षम नहीं है जो हम बालकों द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। बालक वह शिक्षा अवस्था है जिसके लिए तो सबसे अधिक आवश्यक है, जो उचित वातावरण में बालक को करने में सक्षम है।

### 1.01 पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अर्थ एवं क्षेत्र Meaning and Objectives of Pre-Primary Education

यह शिक्षा जो बालकों में वांछित सामाजिक गुणों का विकास कर, मनुष्य के व्यक्तित्व का गठन कर सके और प्राथमिक स्तर के गुण बालकों को तैयार कर सके से सम्बन्धित हो सके—पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहलाती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक शिक्षा—बालकों द्वारा स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास शिक्षा का सामान्यतया हमारे देश में इस स्तर की समस्यायुक्त 3 वर्ष से 5 वर्ष तक जारी रहती है। अन्य देशों में इसके लिए भिन्न आयु स्तरों को माना गया है जो कि देश-देशों की अनिवार्य शिक्षा योजना, आर्थिक विकास एवं औद्योगिकरण पर निर्भर है।

### 1.02 पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य Aims and Objectives of Pre-Primary Education

देश जीवन के मतानुसार—

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए, मिस ऐल माकेन के 'The First Five Years' में अनेक विचार निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किये हैं:—

1. बालकों को स्वस्थ बालावरण प्रदान करना जैसे प्रकाश, धूप, स्वच्छ वायु, स्वच्छ स्थान आदि ।
2. बालकों को प्रफुल्ल, स्वस्थ एवं नियमित जीवन प्रदान करना तथा चिकित्सा सुविधाएं देना ।
3. बालकों में समग्र व्यक्तित्व आदर्शों का निर्माण करना ।
4. बालकों को कल्पना शक्ति, विभिन्न प्रकार की रुचिओं तथा क्षमताओं को विकसित करने के सुप्रबल प्रदान करना ।
5. बालकों में तपु स्तर पर सामूहिक जीवन के अनुभव प्रदान कर समान आयु तथा अन्य आयु स्तर के बालकों के साथ कार्य करने एवं खेलने के अनुभव प्रदान करना ।
6. पारिवारिक जीवन की वास्तविक एकता प्राप्त करना ।

उपरोक्त उद्देश्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का मूल उद्देश्य बालकों में वांछित शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं का विकास कर उनमें सहकारिता, सहयोग और गवेषात्मक स्थिरता प्रदान करना है । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस शिक्षा का उद्देश्य बालकों का मनोवैज्ञानिक रूप से विकास करना है जिससे वे प्रसन्न, नियमित, सहयोगी और प्रेममय जीवन-यापन कर अपने नवी जीवन को सुन्दर बनाने में समर्थ हो सकें ।

**कोठारी आयोग (1964-66) के अनुसार—**

कोठारी आयोग ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित किये हैं—

1. — To develop in the child good health habits, and to build up basic skills necessary for personal adjustment, such as dressing, toilet habits, eating, washing, cleaning etc.
- To develop desirable social attitudes and manners; and to encourage healthy group participation, making the child sensitive to the rights and privileges of others.
- To develop emotional maturity by guiding the child to express, understand, accept and control his feelings and emotions
- To encourage aesthetic appreciations,
- To — To use the beginnings of intellectual curiosity the environment and to help him understand the world in which he lives, and to foster new

1. बालकों में अच्छी स्वस्थ आदतों का विकास और व्यक्तिगत समस्याओं की समस्याओं जैसे बदन पहनना, शौचालय, छाने, धोने, सफाई में की बिकसित करना ।
  2. बालिक सामाजिक क्षमकृतियों एवं हर्गो का विकास करना, स्व सामूहिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, हास्य अपने अधिकारों तथा दूसरों के विशेषाधिकारों के प्रति जागरूक करना
  3. बालक को अपने सवेगों पर नियन्त्रण करने हेतु निर्देश देना जिस सवेगात्मक परिपक्वता का विकास हो ।
  4. सीखनेवाली प्रशंसा हेतु प्रोत्साहित करना ।
  5. बालक को उसके सत्कार जिसमें वह रहता है एवं वातावरण सम्बन्धित बौद्धिक उत्तमता प्रदान करना और उसे नवीन द्रव्यों प्रवर्तन प्रदान करना ।
  6. बालक को स्वतन्त्रता और सृजनारम्भता के प्रोत्साहन हेतु स्वयं की व्यक्ति के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना ।
  7. बालकों में स्पष्ट एवं सही भाषा द्वारा अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना ।
  8. बालकों के शारीरिक गठन एवं शारीरिक क्षमताओं को बिकसित करना ।
- पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति सभी की जा सकती है जबकि हम बालकों को वे अनुभव और वातावरण सम्बन्धी दशाएँ प्रदान कर सकें जिससे उनका शारीरिक, मानसिक, सवेगात्मक और सामाजिक विकास हो सके । यह सब ही सम्भव जबकि इस शिक्षा के प्रकार हेतु अच्छी जानाओं का निर्माण हो । वर्तमान शिक्षा के पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल है, विशेष कर उन बालकों के लिए जिनका पारिवारिक वातावरण असन्तोषजनक है । यही यह दिशा है जिस ओर

interest through opportunities to explore, investigate and experiment.

To encourage independence and creativity by providing the child with sufficient opportunities for self-expression.

To develop in the child a good physique, adequate muscular coordination and basic motor skills,

cation Commission (1964-66)

में अप्रसर होना है<sup>1</sup>। संशे में कहा जा सकता है कि हम इस शिक्षा व्यवस्था द्वारा देश के भावी नागरिकों का निर्माण कर सकते हैं जो कि सामाजिक रूप से व्यवस्थित एवं समायोजित होंगे।

### 1.03 पूर्व-प्राथमिक शिक्षा क्यों ?

#### Why Pre-Primary Education ?

यह हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा को समग्र शिक्षा व्यवस्था में यथोचित स्थान नहीं दिया गया और इसका प्रवर्ध प्रमाण यह है कि हमारे देश का वर्तमान शिक्षा स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है तथा इसका मूल कारण यह है कि बालकों को प्रारम्भिक वर्षों में वे संस्कार प्रदान नहीं किये जाते जो भावी शिक्षा-स्तर को सुधारने हेतु अनिवार्य हैं। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रति जागरूक हों।

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा समिति मैसूर<sup>2</sup> (1961) ने यह निश्चित धारणा प्रकट की थी कि 'पूर्व प्राथमिक शिक्षा का योजनाबद्ध और तीव्र प्रसार हमारे विकास हेतु अत्यन्त आवश्यक है।' शिक्षा आयोग<sup>3</sup> (1964-66) ने इसकी महत्ता पर विचार स्पष्ट करते हुए लिखा है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा बालक के शारीरिक, संवेगात्मक और बौद्धिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है और विशेषकर उन बालकों के लिए जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि असंतोषजनक है।"

इसके अतिरिक्त "एक सामान्य परिवार ढाई वर्ष से छः वर्ष के बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है और यदि इन आवश्यकताओं की पूर्ति उचित रूप से नहीं होती है तो स्पष्ट अवस्था स्पष्ट रूप से बालक का भावी जीवन सकटमय हो जाता है। इसीलिए हमारी यह निश्चित धारणा है कि पूर्व-

1. The modern trend in educational policy, therefore, is to emphasize pre-primary education especially for children with unsatisfactory home backgrounds. This is the direction in which we also should move.

—*Ibid*, p. 148.

2. We are of the firm opinion that planned and immediate expansion of Pre-Primary Education is essential at the present stage of our development.

3. Pre-Primary education is of great significance to the physical, emotional and intellectual development of children, especially those with unsatisfactory home backgrounds.

—*The Education Commission 1964-56*

प्रतिभा है। 'आधुनिक शिक्षा में नैतिक शिक्षा का स्थान' को देखते हुए हमारा निष्कर्ष यह है कि नैतिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा में ही देना चाहिए। इसके बिना आधुनिक शिक्षा का फल सकारात्मक नहीं होगा। नैतिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा में ही देना चाहिए। इसके बिना आधुनिक शिक्षा का फल सकारात्मक नहीं होगा।

प्राथमिक शिक्षा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह नैतिक शिक्षा का आधार है। नैतिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा में ही देना चाहिए। इसके बिना आधुनिक शिक्षा का फल सकारात्मक नहीं होगा। नैतिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा में ही देना चाहिए। इसके बिना आधुनिक शिक्षा का फल सकारात्मक नहीं होगा।

नैतिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा में ही देना चाहिए। इसके बिना आधुनिक शिक्षा का फल सकारात्मक नहीं होगा। नैतिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा में ही देना चाहिए। इसके बिना आधुनिक शिक्षा का फल सकारात्मक नहीं होगा।

The average home is in many ways inadequate to the needs of Children of the age of 2½-6 and if these needs are not met at the right stage, the child's future development is in very great danger of being hampered, either physically or imperceptibly. We would therefore urge for the establishment of good Pre-Primary Schools in rural and urban areas.

—Bombay Report.

In the rural areas, Pre-Primary Education is essential. It should be provided by the state with the help, if possible, of voluntary agencies. For the rural areas, we must have the facilities for fifty per cent of the children must be in classes, in which parents did not see -

विकास<sup>1</sup> के क्षेत्र में हुए अनुसंधान इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बालक के प्रारम्भिक पाँच वर्ष सम्पूर्ण जीवन के लिए निश्चित गति एवम् दिशा निर्धारित करते हैं जो अन्ततोगत्वा जीवन के आधारभूत रूप में संचालित होते हैं। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के माध्यम द्वारा बालकों को स्वस्थ एवम् मुखरित वातावरण प्रदान किया जाये परन्तु यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में शिक्षा के इस आधार स्तम्भ की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व तो अंग्रेजों ने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया और स्वतन्त्रता के पश्चात् भी बीस वर्षों में इस ओर आनीतिगत प्रगति नहीं हो पाई है।

## 10.4 ऐतिहासिक विकास

### Historical Development

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का इतिहास 'पर्यन्त' अत्यन्त उपजनक रहा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व ब्रिटिश शासन ने व्यवस्था में इस शिक्षा को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया तथा क्योंकि अंग्रेजों का मूल उद्देश्य भारतीयों को शिक्षित करना नहीं था बल्कि शासन में 'फरमा' को और हमारे लिए वे पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के प्रति सदैव अनास्था ही प्रगट करते रहे।

सन् 1939 में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ और 1944 तक प्राथमिक शिक्षा ही संभाला था। इस समय सर जॉन गार्नेट को भारतीय शिक्षा सलाहकार के रूप में युद्धोत्तर शिक्षा विकास पर एक स्मृतिपत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। उन्होंने 1944 में भारतीय शिक्षा पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सम्मुख स्मृतिपत्र प्रस्तुत किया जिसमें पहली बार पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर विचार व्यक्त किये गये जो निम्नलिखित थे—

- राष्ट्रीय शिक्षा योजना हेतु पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों की प्रारम्भ करना आवश्यक है।
- इस शिक्षा हेतु 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए विद्यालयों की व्यवस्था की जाये।

1. "A number of writers have suggested that children go through critical periods during which bearing opportunities are especially effective and beyond which they are less effective. If opportunities to learn during a given developmental period do not occur, children may fail to learn a given behaviour pattern."

George G. Thompson, *Child Psychology*, The Times of India Press, Bombay, 1965, p. 124.



- इन शालाओं के लिए केवल उन्हीं अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जावे जो विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त हों।
- प्रत्येक दशा में यह शिक्षा नि शुल्क होनी चाहिए।
- यद्यपि इस शिक्षा को अनिवार्य बनाना कठिन है तथापि माताओं-पिताओं को अनुमय द्वारा बालकों को इन शालाओं में भेजने हेतु कहा जावे विशेष रूप से जहाँ माताएँ घर से बाहर कार्य करने जाती हैं और/अथवा पारिवारिक दशा असन्तोषजनक है।
- शहरों में, जहाँ बालकों की संख्या पर्याप्त है वही पृथक् रूप से शालाएँ स्थापित की जावें अन्यथा बेसिक प्राथमिक शालाओं में इन बालकों के लिए पृथक् कक्षाओं की व्यवस्था की जावे।
- इस शिक्षा का उद्देश्य बालकों को सामाजिक अनुभव एवम् सदाचार प्रदान करना है न कि औपचारिक शिक्षा देना।

इस प्रकार सार्जेंट कमेटी ने इस शिक्षा का विधिवत मूल्यांकन किया। बैसे 1939 में भी दूसरी वर्षा शिक्षा समिति ने इस ओर ध्यान दिया था परन्तु इससे कोई वांछित उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकी।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भी इस शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यद्यपि यह सत्य है कि सरकार के सम्मुख भन्म क्षेत्रिक समस्याएँ अधिक महत्त्वपूर्ण थीं तथापि इस शिक्षा के प्रति कम ध्यान देना भी क्षम्य नहीं है। तालिका 1-1 से हमें यह स्पष्ट होता है कि इस ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

तालिका 1-1

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् पूर्व-प्राथमिक शिक्षा<sup>1</sup>

वर्ष	स्कूलों की संख्या	छात्रों की संख्या	अध्यापकों की संख्या	प्रत्यक्ष भय (मात्रों में)
1934-35	302	21,640	866	11.98
1935-36	830	45,828	1,880	24.99
1960-61	1,909	1,21,184	4,007	53.73
1961-62	2,240	1,48,888	4,895	74.01
1962-63	2,502	1,64,695	5,221	82.31
1963-64	2,717	1,78,968	5,453	82.20

तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस शिक्षा के प्रकार पर विशेष बल दिया गया। वा

बाल-बाहियों में सुधार करने की ओर नई बाल-बाहियाँ लाने की व्यवस्था है। शिक्षा क्रम में से शिक्षा कल्याण और सम्बद्ध योजनाओं के लिए तीन रुपये केन्द्र में एक करोड़ रुपये राशियों में रखे गए। यह राशि सामुदायिक और समाज कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाले साधन पर विरक्त थी।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को अधिकतर प्रयास<sup>1</sup> पर छोड़ा गया है। योजना में यह स्वीकार किया गया है कि यह पूर्ण चेष्टा है परन्तु सीमित साधनों एक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य प्राप्ति के कारण सरकार छोड़ा ही उत्तरदायित्व निभा सकती है। अतः सरकारी ध्यान कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे अध्यापकों का प्रशिक्षण, शैक्षिक सामग्री का और भारतीय दशाओं के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधियों आदि पर रहेगा।

जहाँ तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का प्रश्न है;— ऐसे जालाओं की संख्या 3,500 है जिसमें करीब 6,500 अध्यापिकाएँ बालकों की कुल संख्या 250,000 है। इनके लिए प्रत्यक्ष व्यय में भी वृद्धि जो कि सम्पूर्ण शिक्षा व्यय का 0.2 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय कल्याण बोर्ड (CSWB) और सामुदायिक विकास प्रशासन ने सन्तोष किया है। इस समय कुल मिलाकर 20,000 बाल-बाहियाँ हैं जिनमें बा कुल संख्या 600,000 है।

यदि हम सम्पूर्ण विकास पर दृष्टिाव करें तो निम्नलिखित रूप से सकता है कि सम्पूर्ण सध्यों को ध्यान में रखते हुए तो यह प्रगति बहुत परन्तु ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से काफी प्रगति की है।<sup>2</sup>

### 1.05 पूर्व-प्राथमिक शालाओं के प्रकार

#### Kinds of Pre-Primary Schools

हमारे देश में मुख्य रूप से निम्नलिखित पूर्व-प्राथमिक शालाएँ हैं—

#### 1. माण्टेसरी शालाएँ

##### Montessori Schools

इन शालाओं का आरम्भ डा० मेरिया माण्टेसरी ने किया था।

से 1950 तक भारत में वहीं और एक नवीन शिक्षण पद्धति पर का

#### 1. Private Initiative

2. The progress is no doubt small in relation to goals, but it marks a 'tremendous advance over achievements.

न सिखा के पुत्र भी किरम माफे मरि की अन्तर्गत मन्त्रजुमि हेत ११ दशमे संके  
 मरि की सिखा नर विदेर अर विद्या । द्रव्य विदेर अर नर वि बाणवी के  
 प्रभाव विद्या हेतु वा ११ द्रव्य अन्तर्गत मन्त्र अर विद्या ११ द्रव्ये द्वा  
 तारिण सिखा मन्त्रि के दि १ बाण माफे मन्त्रि के अन्तर्गत मन्त्रि  
 माफे मन्त्राणि हे । मन्त्रि के द्रव्य माफे मन्त्रि के अन्तर्गत मन्त्रि हे :—

- ज्ञाना द्वारा अस्तित्व विधीन,
- ज्ञानहीन है परन्तु धारणों का निर्वोक्त वर्णना,
- धारणाएँ हैं निरर्थक धारणों को पर्यटन वर्णना,
- ज्ञानीविषय विज्ञान के अति ज्ञानमयता,
- स्वयम्भूत ज्ञान का प्रतिपादन,
- विज्ञान द्वारा सीखने (निष्कर्ष) का रूप,
- स्वयम्भूत ज्ञान का विज्ञान,
- तीन धारणों (3 R's) का निष्कर्ष,
- अन्तर्गत एवम् अन्तर्गत के विज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञानों का प्रमाण,
- निष्कर्ष एवम् अन्तर्गत के रूप में,

ਸੰਸਥਾਨਿਕ ਭਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧੇਗੀ। ਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ  
ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰਕ ਵਿਚਾਰਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

**क्लिङ्गमार्ग**  
Klingenberg

रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना मध्यमम 1849 में जर्मन शिक्षा छात्रों  
द्वारा की गयी। हमारे देश में रिपब्लिकन स्कूलों की संख्या अधिक नहीं है  
जु शिक्षण स्तर मतापवाद है। ये स्कूल 3 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चों के लिए  
मध्य रूप में इन शाखाओं की विस्तारित विशेषताएं हैं —

(घ) बालक द्वारा किया—इस विधा से बालक अपनी सत्ता को पहचानना और अपने सत्कार का निर्माण करता है। बालक द्वारा विधा स्वतः होती है। सुशिक्षाएक द्वारा निरीक्षण पर्याप्त आवश्यक है। बालक की वार्षिक क्रियाओं को सततता उनके विकास को ध्वस्त करना है। पहले का कार्य यह है कि बालक में बालक की काफी स्वतन्त्रता हो पाती है।

(ब) सृजनात्मकता—विष्टरगार्टन छात्रागणों में नाटक की सृजनात्मकता को ध्यान दिया है। स्वतन्त्र चिन्तन पर ही सृजनात्मकता निर्भर करती है। नाटक का कार्य उसे सृजनकारी करना है जिससे बालक इस दिशा में प्रगति सके।

(स) स्वस्थ अनुभव—बालकों को स्वस्थ अनुभव प्रदान करने हेतु में एक छोटी फुलवारी, जोडास्थान, खेलकूद के अन्य साधन, संगीत, अभिनय, पोथे, पत्ती आदि की व्यवस्था होती है।

(द) गिफ्ट्स और ओकूपेशन द्वारा प्रेरणा—बालकों को प्रेरणा प्रदान हेतु इस शिक्षा पद्धति में पारितोषक स्वरूप गिफ्ट्स और ओकूपेशनस् व्यवस्था की है। पहले गिफ्ट में 6 अलग-अलग रंगों के ऊन के गोले हैं जिनको बालकों के लिए स्थिति, दिशा आदि के ज्ञानस्वरूप रखा गया है। दूसरी गिफ्ट में लकड़ी के और त्रिकोण हैं, यह बालकों को वस्तु का ज्ञान देने के लिए रखे गये हैं। तीसरी गिफ्ट में लकड़ी के समानाकार के घाठ टुकड़े हैं, इनसे बालकों में निर्माण की भावना का विकास होता है। इन गिफ्ट्स के प्रतिरिक्त कुछ ओकूपेशनस् हे जिनमें मिट्टी, चाय, आदि सामग्रियों को रखा गया है। इन सबका उद्देश्य बालकों की कलात्मक एवं शारीरिक क्षमताओं का विकास करना है।

### 3. पूर्व-प्राथमिक शालाएँ

#### Per Basic Schools

गंधीजी के 'बाल-शिक्षा' विचारों के आधार पर इन शालाओं का स्थापना हुआ है। इस शिक्षा का प्रारम्भ देशव्याप्त में हुए प्रयोगों के आधार पर भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय ने 1953 में एक पुस्तिका 'बाल शिक्षा में प्रकाशित की। इस पुस्तिका में इन शालाओं का विस्तृत रूप से वर्णन है। इस पुस्तिका के संक्षेप में निम्नलिखित चरण हैं—

- (i) गर्भाधान से जन्म तक
- (ii) जन्म से दस वर्ष तक
- (iii) दस वर्ष से पंद्रह वर्ष तक
- (iv) पंद्रह वर्ष से आठ वर्ष तक

प्रथम चरण में गर्भवती माता की आवश्यक निर्देशन की व्यवस्था है। माता का भोजन, दिनचर्या, स्वस्थप्रद वातावरण, बालक के लिए आवश्यक सामग्री का माला एवम् माता के बालक के प्रति करीब आदि की रखा गया है। कोई संदेह नहीं कि गर्भावस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था है, बालक का विकास इस अवस्था में ही होता है। अतः इस समय माता की आवश्यकता होती है।

द्वितीय चरण में बालक के प्रथम दस वर्ष आते हैं। इस अवस्था में बालक की आवश्यकता होती है अतः यह आवश्यक है कि माता की आवश्यकताओं की पूर्ति की जावे और माता की आवश्यकताओं की पूर्ति की जावे।

तोसरे चरण में बालकों के लिए शालाघों की व्यवस्था है। ये शालाघें पूर्ण-  
 रूप से भारतीय हैं जो कि भारतीय बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक  
 हैं। परन्तु हमारे देश में इस प्रकार की शालाघें बहुत कम हैं क्योंकि सम्पूर्ण व्यवस्था  
 लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है  
 पूर्व-वेस्तिक शालाघों की सम्पूर्ण व्यवस्था को परिवर्तित किया जावे और प्रथम  
 चरणों को छोड़कर अन्तिम दो चरणों को ही क्रियान्वित किया जावे। यद्यपि  
 पूर्व-वेस्तिक शिक्षा व्यवस्था अपने में एक आदर्श है, परन्तु सभी आदर्श वास्तविक  
 होते हैं।

### 1.00 विदेशों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

#### Pre-Primary Education in Foreign Countries

विदेशों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बहुत प्रगति हुई है। रूस, अमेरिका  
 जर्मनी, आस्ट्रेलिया आदि देशों में इस शिक्षा को एक आवश्यक शिक्षा  
 के रूप में माना गया है। विदेशों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था  
 निम्नलिखित है—

रूस  
 Russia

सोवियत संविधान में नवमी एवम् किन्डरगार्टन शालाघों को स्थान दिया  
 है। संविधान में स्पष्ट रूप से पूर्व प्राथमिक शिक्षा को देश की प्रगति के लिए  
 कहा गया है। 1914 में किन्डरगार्टन शालाघों की संख्या बहुत कम थी  
 4,000 बालकों की ही व्यवस्था थी और ये शालाघें प्राइवेट रूप से  
 चली जाती थीं। 1961 में रूस की पुनर्जागरणी 20 करोड़ की बजट में  
 वर्ष के 20 लाख बालकों की शिक्षा व्यवस्था की।

जर्मनी  
 1960

जहाँ पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को वैश्विक धर्म का आधार माना जाता है।  
 यह शिक्षा प्रक्रिया के लिए बाल शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है। यदिवापस शिक्षा  
 के आधार होती है। दो वर्ष के बाल बच्चों तक के बालकों के लिए पूर्व-  
 प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है। जहाँ बालकों की परिचितता, आनंद का बोध और  
 बालों के विकास की जाती है। जहाँ तक सम्भव होगा है बालकों को बाल्य  
 में ही रहने के आधार पर प्रारंभ किया जाये है।

### 3. संयुक्त राज्म अमेरिका

#### United States of America

यहाँ किन्डरगार्टन शालाएँ बहुत लोकप्रिय हो गई हैं और शनैः शनैः पब्लिक स्कूल का रूप धारण कर रही हैं। यहाँ की किन्डरगार्टन शालाओं में वास्तविक के आधार पर शिक्षण पद्धतियों को अपनाया गया है। इन शालाओं में साढ़े ५ वर्ष से छः वर्ष के बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है। बालकों को क्रियाशीलता और वांछित सामाजिक अनुभव प्रदान किये जाते हैं। बालसुलभ भाषण शालाओं के अनुसार समस्त अनुभव प्रदान करना इस शिक्षा की विशेषता है। शालाओं की दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है।

### 4. डेनमार्क

#### Denmark

यहाँ पूर्ण-प्राथमिक शिक्षा सरकार के कार्यधीन है। इस शिक्षा में छह से सात वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की शालायें हैं—

(i) नर्सरी शालायें (Nurseries)

(ii) दैनिक घर (Day Homes)

(iii) ग्रीड रूम (Play Rooms)

इस शिक्षा हेतु 30 प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा, 40 प्रतिशत नगरपालिका द्वारा एवम् प्रतिष्ठित पन दान द्वारा भ्रषवा जाता-पिता से लिया जाता है। शिक्षा व्यवस्था की एक अन्य विशेषता यह है कि शालाओं में पारिवारिक वातावरण प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है।

### 5. ऑस्ट्रेलिया

#### Australia

बाल कक्षाएँ स्थानीय प्राथमिक शालाओं से सम्बन्धित होती हैं। सामान्यतः कक्षाएँ पाँच वर्ष के बालकों के लिए होती हैं। देश में कहीं इस शिक्षा हेतु शालाएँ भी हैं। आवागमनवाणी द्वारा भी पूर्ण प्राथमिक शिक्षा का आयोजन है। शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक को सामान्य रूप से विकसित करना है तथा बालक के सर्जनशील विकास हेतु अनेकों प्रकार के अवसर प्रदान किये जाते हैं।

### 6. नीदरलैंड्स

#### Netherlands

नगरपालिकाओं की बाल शालाएँ खोलने का अधिकार है। बालक

नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या पर आधारित है।

राजीवना चाहे तो नगरपालिका द्वारा सहयोग प्रदान किया जा-  
 ता के साथ समिमावकों का सम्बन्ध होता है। समिमावकों द्वारा  
 सहयोग प्रदान किया जाता है जिससे वे अपने कामों की प्रगति से सा-  
 निग होने में सक्षम हैं। यही सामान्य रूप से तीन प्रकार की शिक्षण पद्ध-  
 तियाँ दी जाती हैं—विष्टरमाटन, माण्डेसरी, सामयिक विधि। इस-  
 से साफ दिशा के लिए बार दप में सात वर्ष की आयु निश्चित की गई है।

# 1. 17 भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा Pre Primary Education in India

यद्यपि, जैसा की हम पहले कह चुके हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सर्व-  
 व्यापक है। स्वतन्त्रता से पूर्व की स्थिति के विषय में हम विस्तृत रूप  
 से बर्चा कर चुके हैं परन्तु सार्जेंट समिति के ये विचार काफी  
 कि यदि इस शिक्षा हेतु पूरे प्रयास भी किये जायें तो भी सामान्य  
 त करना बहुत कठिन है क्योंकि वे अपने बच्चों के सा-  
 एण को और स्वस्थप्रद बनाने हेतु जागरूक हैं जो यह।  
 पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को और अधिक सफल बनाने के लि-  
 हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

हम में बहुत हद तक सत्यता है क्योंकि हमारे देश में ऐसे  
 हैं जो अपने बालकों की शिक्षा के लिए बिल्कुल भी  
 शिक्षा की धारणा तो बहुत दूर है—वे तो अपने बाल-  
 के के हक में नहीं हैं। परन्तु सम्भव है कि सामाजिक  
 लक्ष्यो हुई जातियों तथा आदिवातियों में इस ओर जाग-  
 र विद्या में काफी प्रगमनीय विकास हो रहा है। अ-  
 जो बीस वर्ष पूर्व था।

अधिक लोकप्रिय न होने का एक कारण हमारी भा-  
 तो हम अपने उन उद्देश्यों की प्राप्ति भी नहीं कर सके-

if proper facilities are provided, it would be  
 easy matter to persuade the Indian mothers to  
 natural effects in the interest of a more  
 and mental environment for her children. A  
 propaganda and training of public opinion will  
 be a system of Pre Primary Education can be  
 effected."

—Sargent Committee

जो हमने बीग वर्क पूर्व निर्धारित किये थे क्योंकि आर्थिक स्थिति से हम सम्पन्न नहीं हैं। हमारे देश में ऐसे परिवारों की कमी नहीं जहाँ दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी कठिन है—वहाँ यदि हम पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो निरर्थक ही होगा। यदि हम यह बर्हे कि सरकार के आगच्छक न होने के कारण इस शिक्षा को प्राइवेट तोर पर इतना अधिक महँगा बना दिया है कि यह केवल सम्पन्न परिवारों की निधि बनकर रह गई है तो कोई अनिश्चयबोक्ति नहीं होगी।

वातावरण सम्बन्धी और आर्थिक कारणों के अतिरिक्त एक अन्य कारण मौखिक भी है। शिक्षा की दृष्टि से वे बालाएँ नन शैक्षिक मूल्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हैं जो इस आयु स्तर पर बाँझनीय है। बालाओं में वे सामर्थियाँ नहीं हैं जो छोटे बालकों की शिक्षा के लिए आवश्यक हैं। यही कारण है कि अधिकतर अधिभावक इन बालाओं में अपने बच्चों को भेजना बेकार समझते हैं।

उपरोक्त तथ्यों के कारण हमारे देश में इस शिक्षा की प्रवृत्ति में आशाहीन वृद्धि नहीं हो पाई है। इन कारणों के अतिरिक्त पूर्व प्राथमिक शिक्षा की निम्न-लिखित समस्याएँ हैं—

### 1. प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की कमी

#### Lack of Trained Lady Teachers

प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की कमी के कारण यह शिक्षा समुचित नहीं हो पाई है। अप्रशिक्षित अध्यापिकाएँ बालकों को समझने में असमर्थ रहती हैं और उनका मनोवैज्ञानिक उत्थार नहीं हो पाता। अतः यह आवश्यक है कि अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित किया जाये और अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं को सेवाएँ उस समय तक पक्की न की जायें जब तक वे प्रशिक्षण प्राप्त न कर लें।

### 2. प्रशिक्षणालयों की कमी

#### Lack of Training Schools

पूर्व प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में प्रशिक्षणालयों की बहुत कमी है। देश में बालकों की संख्या को देखते हुए प्रत्येक अध्यापिकाएँ प्रशिक्षित होनी हैं वे इस शिक्षा की माँग का पूरा करने में प्रायः असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त जो भी प्रशिक्षण केन्द्र हैं वे उन सुविधाओं से पूर्ण नहीं हैं जो प्रभावशाली शिक्षण के लिए आवश्यक हैं।

### 3. बाल साहित्य की कमी

#### Lack of Juvenile Literature

यद्यपि इस आयु स्तर पर पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना आवश्यक नहीं है तथापि बाल साहित्य का गृहजन्म निम्न आवश्यक है। इन आयु के बालकों को विशेष माँग होती है अतः मनोवैज्ञानिक आधार पर इन बालकों के मानसिक योग्य-



सार साहित्य का होना बहुत जरूरी है। हमारे देश में न तो इस प्रकार के  
 अध्ययन के लिए प्रयास ही किया जाता है और न इस साहित्य के प्रति गं-  
 नी ही है। केन्द्रीय एवं राज्य सरकार को चाहिए कि वे इस ओर ध्यान  
 प्रदान करने का प्रयास करें।

8 पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु कोठारी आयोग की सिफारिशों  
*Recommendations of Kothari Commission for the Development*  
*of Pre-Primary Education*

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के विस्तार हेतु कोठारी आयोग (1964-66) ने  
 निम्नलिखित सिफारिशों की हैं—

- (1) पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु राजकीय शिक्षा संस्थान में एक  
 केन्द्र राजकीय स्तर का होना चाहिये। इसके अतिरिक्त लगभग 20  
 वर्षों में प्रत्येक जिले के अन्तर्गत इस प्रकार के केन्द्रों की स्थापना की  
 जाये। इन केन्द्रों का मुख्य कार्य पूर्व-प्राथमिक अध्यापकों की प्रशि-  
 क्षण, निर्देशन एवं मार्ग प्रदर्शन करना, माताओं पिताओं को बालक  
 की देखभाल के लिए शिक्षित करना होना चाहिए। इसके अतिरिक्त  
 अध्यापकों की प्रारम्भिक प्रशिक्षण की समस्त सुविधाएँ भी इन्हीं  
 केन्द्रों के द्वारा प्रदान की जा सकती हैं।<sup>1</sup>
- (2) इन विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन वर्तमान स्थिति में, व्यक्ति-  
 गत प्रयत्नको द्वारा होना चाहिए। इन शाखाओं को राज्य सरकारों  
 द्वारा उदार आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए क्योंकि राज्य सरकारों

- (3) पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित प्रत्येक अनुसन्धान को प्रोत्साहित किया जाये, विशेष रूप से कम कीमती मिलान विधियों के परीक्षणों को विकसित किया जाये :
- (4) प्राथमिक शालाओं से सम्बन्धित बाल ग्रीष्म केन्द्रों को स्थापित किया जाये । इन केन्द्रों में सामूहिक गान, कहानी पढ़ाई, विभिन्न प्रकार के खेल आदि को बालकों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित किया जाये ।
- (5) राज्य सरकार इस प्रकार के केन्द्रों को राज्य एवं जिला स्तर पर स्थापित करे जिसका कार्य बालकों को प्रशिक्षण देना, अनुसन्धान करना, साहित्य सृजन करना, पूर्व प्राथमिक शालाओं को निर्देशन देना तथा प्रशिक्षण शालाओं का निरीक्षण करना आदि हो ।

उपरोक्त समस्त सुझावों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय में महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं और उन्हें पथ-प्रदर्शक बनाना नितांत आवश्यक है । यह हमारा पुनीत कर्तव्य है कि भारतीय संस्कृति के आधारानुसार आज के बालकों में उन संस्कारों को डालें जिससे भविष्य में प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर हम सचरित्र सकल नागरिक बनाने में समर्थ हो सकें । भारत की सभ्यता की ध्यान में रखते हुए यह नितांत आवश्यक है कि अधिक से अधिक मन्दिरों की स्थापना हो जिससे केवल गहरी बालक ही नहीं बल्कि ग्रामीण बालक भी लाभान्वित हों ।

# ग्रन्थ-सूची

## Bibliography

1. Baruch, Dorothy W.  
*Nursery School and the Kindergarten*, Scott Foreman & Co., Chicago, 1939.
2. D. Souza Avelar A.  
*Aspects of education in India and abroad*, Orient Longmans 1953.
3. De Young C. A.  
*Introduction to American Public Education*, Mc Graw Hill Book Co Inc., New York, 1956.
4. *Education in India*, Vol. 1, Ministry of Education, New Delhi, 1958.
5. *Elementary Education Record* Lok Sabha's Estimate Committee Report, Lok Sabha Secretariat, New Delhi, 1958.
6. *Education in the States*, (1955-57), Ministry of Education New Delhi, 1959.
7. *India 1963*, 66, 67, Publication Division, Ministry of Information & Broadcasting Govt of India.
8. Hurlock, Elizabeth B.  
*Child Development*, Mc. Graw Hill Book Co., Inc., New York, 1959
9. Huns N.  
*Comparative Education*, Routledge, London, 1959.
10. King Hall, Magdalen.  
*Story of the Nursery*, Routledge and Kegan Paul, London, 1953
11. Mukerji, S. N.  
*Education in India Today and Tomorrow*, Acharya Book Depot, Baroda, 1964
12. Medinsky, Y. N.  
*Public Education in U.S.S.R.*, Foreign Language Publication House, Moscow, 1956.
13. *Report of the Education Commission*, (1964-66), Ministry of Education, Govt. of India 1966.
14. *Report of working Group on Education for Draft Third Five Year Plan*, Ministry of Education, New Delhi, 1960
15. *Report of working Group on Education for Draft Fourth Five Year Plan*, (A Draft Outline) Govt. of India, 1967.

# अध्याय दो

## Chapter Two

### प्राथमिक शिक्षा और सार्वसंगिकता

### Primary Education & Universalisation

#### अध्ययन बिन्दु

#### Learning Points

- \* 2.01 प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य  
Aims of Primary Education
- \* 2.02 ऐतिहासिक विकास  
Historical Development
  - 1813-1854; 1854-1857; 1857-1882;  
1881-1911,  
अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रयास  
1911-21; 1921-1937,  
1937 से स्वतन्त्रता प्राप्ति तक . . . . .  
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् पञ्चवर्षीय योजना की समाप्ति तक
- \* 2.03 अनिवार्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास  
Brief History of Compulsory Education
- \* 2.04 अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की समस्याएँ  
Problems of Compulsory Primary Education
  - 1. शैक्षिक सुविधाओं की असमानता
    - \* प्राथमिक सुविधाओं में असमानता
    - \* मनोवैज्ञानिक कारण
    - \* सामाजिक विच्छेदन
  - 2. प्रशासकीय समस्याएँ
  - 3. पहली बच्चा में प्रवेश
  - 4. अध्यापकों की समस्या
    - \* अध्यापकों के प्रशिक्षण की समस्या
    - \* आदिवासियों के लिए अध्यापकों की समस्या
    - \* बालिकाओं के लिए अध्यापिकाओं की समस्या
  - 5. सड़कियों की शिक्षा
  - 6. अक्षर्यता और अक्षरोंपन
  - 7. अक्षरित क्षेत्रों की समस्या
  - 8. अन्य समस्याएँ

## प्राथमिक शिक्षा और सार्वलौकिकता

### PRIMARY EDUCATION & UNIVERSALISATION

प्राथमिक शिक्षा वह प्रकाश है जो जीवन के समस्त घन्टवारों को दूर कर बालक में उन पुनीत सरकारों, पवित्र मान्यताओं, निश्चित हृष्टिकोण और मानव विचारों को जन्म देता है जिससे बालक का माथी जीवन प्रकाशित होता है। सच में हम यह सचते हैं कि प्राथमिक शिक्षा मात्र के बालकों और माथी नागरिकों को साक्षर करने का प्रयास है।

#### 2.01 प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य

##### Aims of Primary Education

एशिया क्षेत्रीय सभा<sup>1</sup> में प्राथमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये—

1. सीखने के सिद्धान्तों पर आधारित मौलिक शिक्षा प्रदान करना।
2. बालक का शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेदात्मक, सौन्दर्यात्मक, नैतिक विकास पर सर्वाङ्ग विकास करना।

---

1. Regional Meeting of Members, Primary & Compulsory Education, December 1959—January 1960

3. बालक में देश की सांस्कृतिक एवम् परम्पराओं के प्रति प्रेम जागृत कर प्रादेशी नागरिक बनाना ।
4. बालक में अन्तर्राष्ट्रीय चेतना का विकास कर विश्व भागृत्व की भावना का विकास करना ।
5. बालकों में श्रम की महत्ता विकसित करना ।
6. बालकों को क्रियात्मक अनुभव प्रदान कर, मावी जीवन के लिए तैयार करना ।

उपरोक्त उद्देश्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बालकों के ज्ञान की वृद्धि करना, उनमें बाल गुणम रूचि तथा समिचि विकसित करना और उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है जिससे वे प्रज सम्भारक देश के प्रादेशी नागरिक हो सकें ।

## 202 ऐतिहासिक विकास Historical Development

भारत में प्राथमिक शिक्षा का इतिहास बहुत प्राचीन है । वैदिक काल में ही हमें प्राथमिक शिक्षा के दर्शन होते हैं । उस समय शिक्षा व्यवस्था परम्परा मनोवैज्ञानिक थी और बालक के सम्पूर्ण विकास को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती थी परन्तु धीरे-धीरे सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन के साथ-साथ शिक्षा का स्वरूप परिवर्तित होता जाता गया ।

हमारे देश पर मुस्लिम राज्य का प्राधिपत्य हुआ और शिक्षा का उद्देश्य मुस्लिम धर्म का प्रसार हो गया । सल्तननाट निजामदियों ने अपने धर्म का प्रसार करना आरम्भ कर दिया और उनका माध्यम भी शिक्षा ही बनी । इसके परभाव मीरजों का आगमन हुआ और हमारी संस्कृति पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा । मीरजों के आगमन के कारण या अतः धार्मिक प्रसार की ओर उन्होंने विशेष और नज़र की के काल में भी ईसाई धर्म का प्रसार होता रहा । समाज की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा का ऐतिहासिक विकास

यस शिक्षा प्रसार की ओर ध्यान गया जिसके लक्ष्य की स्थापना की गई । 1835 में विलियम प्रोविडेंट प्रस्तुत किया । इस प्रतिवेदन में प्राथमिक शिक्षा को उठाये का प्रयास किया गया । सर्वप्रथम धर्म से बचाने के लिए शिक्षा व्यवस्था बनाई

सरसक प्रयत्न किये । देश में राजनैतिक चेतना आई । पराधीन राष्ट्र ने ज-  
के निम्ने अनिवार्य शिक्षा को महत्व प्रदान किया और अनेकों बार प्रयास नि-  
सफलता प्राप्त न हो सकी ।

१९१२ में मोक्षले ने केन्द्रीय विधान सभा में अनिवार्य शिक्षा हेतु नि-  
किया । कांग्रेसी सत्ता ने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह मुसलमानों को  
करने से घबराती हानि सोचती थी । इसके पश्चात् प्रथम विस्मयुक्त हुआ जिसने  
मद्रासी सत्ता ने अनिवार्य शिक्षा के अर्थ 'बो' लहने करने में अतिसमर्थता प्रदर्शित  
बड़ीदा मरेश ने अपने राज्य में अनिवार्य शिक्षा हेतु प्रशंसनीय प्रयास नि-  
रूपानों पर बालकों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी परन्तु इसके सम्पूर्ण  
आवश्यकता की पूर्ति न हो सकी और अनिवार्य शिक्षा हेतु आन्दोलन जारी  
मद्रासी सत्ता इस मार्ग को ठुकराती रही और सर्वत्र यह दलील देती रही कि  
निक तथा आर्थिक आधार पर अनिवार्य शिक्षा सम्भव नहीं है ।

अन्त में राष्ट्र स्वतन्त्र हुआ और अनिवार्य शिक्षा को वास्तविक रूप  
करने के लिए भारतीय संविधान की धारा ५३ में यह स्पष्ट किया गया कि  
साथ होने से दस वर्षों में बीसह वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क  
अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी ।<sup>१</sup> परन्तु यह प्रतिज्ञा केवल मात्र  
ही रही और इस दृष्टि में अभी तक अत्यन्त प्रयास ही रहे । कुछ राज्यों जैसे  
मध्यप्रदेश, आन्ध्र, मैसूर, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश आदि ने अनिवार्य शिक्षा नि-  
रूपित कर दिये हैं । अन्य राज्यों में अभी तक प्रयास जारी है परन्तु अनिवार्य  
को लागू करने में असमर्थ रहे ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि सरकार ने इस ओर काफी ध्यान दिया  
अनेकों प्रयास किये परन्तु आर्थिक अड़चनों के कारण तथा दो मुद्दों (बी-  
पारिवर्तन) के कारण हमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है । जब तक हम सम्पूर्ण  
में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप नहीं देते तब तक हम शैक्षिक उद्देश्यों को  
नहीं कर पायेंगे । प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाकर ही हम देश में संपूर्ण  
शुद्धता ही ला सकने हैं । अभी हमें अपनी अनपक्व जनता को साक्षर बनाता  
मानवस्य के पश्चात् ही गुणात्मक शिक्षा के विषय में सोचा जा सकता है । गो-  
के बच्चों में अनिवार्यता की शिक्षा का भूख उद्देश्य निराकरण को भारत भूमि  
समाप्त करना है, शिक्षा का गुणात्मक रूप भी महत्त्वपूर्ण है परन्तु यह निरा-

1. The state shall endeavour to provide free and comp-  
ulsory education for all children upto the age of fourteen years with

प्राप्त करने के पश्चात् ही सम्भव है।<sup>1</sup> परन्तु प्राथमिक शिक्षा के मार्ग में बहुत समस्याएँ हैं और जब तक इन समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जायेगा तब तक जनसाधारण के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना असम्भव है।

## 2.04 अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की समस्याएँ

### *Problems of Compulsory Primary Education*

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सर्वविधान निर्माताओं ने यह सख्त निर्धारित किया था कि सर्वविधान लागू होने से दस वर्षों में चौदह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। क्या कारण है कि अभी तक हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाये हैं ?

इसके बावजूद कि स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या में प्रचण्वनीय वृद्धि हुई परन्तु फिर भी 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान जो सर्वैधानिक आदेश था, अबसे हम अभी तक बहुत दूर हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति 1981 से पूर्व नहीं की जा सकती।<sup>2</sup> इसका अर्थ है हमारा कि वर्तमान नीतियों के आधार पर हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कम से कम 20 वर्ष पिछड़ गए हैं—परन्तु ऐसा क्यों ?

इस प्रश्न का उत्तर शिक्षा आयोग (1964-66) ने देने का प्रयास किया है। और हम सर्वप्रथम में कुछ वास्तविक समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए निम्ना है कि बच्चों की कठिनाइयों के कारण जैसे वास्तविक संतों की कमी, जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि, लड़कियों की शिक्षा के प्रति अपेक्षित हल, विद्यार्थी हुई आतियों के बच्चों की अत्यधिक संख्या, गरीबी और माता पिता की निरक्षरता के कारण प्राथमिक शिक्षा के विकास में तथा सर्वैधानिक नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने में असमर्थ रहे हैं।<sup>3</sup>

1. "The primary purpose to mass education is to banish illiteracy from the land, the quality of education is a matter of importance that comes, only after illiteracy has been banished."

—Gokhale's Speech, 1920

2. "The primary purpose of mass education is to banish illiteracy from the land, the quality of education is a matter of importance that comes, only after illiteracy has been banished."

Fourth Five Year Plan, A Draft Outline, p. 313

3. But in view of the immense difficulties involved such as lack of adequate resources, tremendous increase in population, rising



हमने कोई गारंटी नहीं दी हम लक्ष्य की प्राप्ति हमें नीतिनिर्देश करनी चाहिए क्योंकि यदि हम साक्षरता चाहते हैं और देश को प्रगति के पथ पर चलाना चाहते हैं तो यह निम्नलिखित आवश्यक है कि हम संविधान में निर्दिष्ट लक्ष्य को मोटा पूर्ण करें। आयोग ने इस लक्ष्य के प्रति हमसे अपेक्षा की है कि हम इसे प्रति हमें पूर्ण गम्भीरता है और हमारा विश्वास है कि निःशुल्क और सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान सर्वोत्कृष्ट नीतिगत चुनौती है। केवलमान सामाजिक न्याय और समाज के कारण ही नहीं बल्कि प्रोग्रेस प्रमोशन की क्षमता तथा राष्ट्रीय उत्पादकता की दृष्टि के लिए यह आवश्यक है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि देश के दिन के लिए यह आवश्यक है कि प्राथमिक शिक्षा के अवसर प्रत्येक बालक को प्रदान किये जायें। इसमें राष्ट्र की प्रति प्रतिनिधित्व है। इन समस्याओं पर विचार करने के पश्चात् यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप प्रदान करने के क्षेत्र में अनेकों समस्याएँ सम्मुख आईं और कुछ समस्याएँ अब भी अनेकों विराट रूप में प्रस्तुत हैं। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप प्रदान करने में निम्नलिखित समस्याएँ एक कठिनाई हैं—

## (1) शैक्षिक सुविधाओं में असमानता

### *Inequality of Educational Opportunities*

अनुसूचित राष्ट्रीय गोष्ठी<sup>2</sup>, पुरी में अनिवार्य शिक्षा के प्रसार पर विचार किया गया। गोष्ठी के सदस्यों का मत था कि शैक्षिक सुविधा की असमानता के कारण प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप प्रदान नहीं किया जा सकता। कुछ राज्यों में तो इस क्षेत्र में इतनी कम प्रगति हुई है कि यह राष्ट्रीय लक्ष्यों को देखते हुए बहुत ही

lances to the education of girls, large numbers of children of the backward classes, general poverty of the people and the illiteracy and apathy of parents, it was not possible to make adequate progress in primary education and the constitutional directive has remained unfulfilled.

*Report of the Education Commission, 1964-66, Minutes of Education, Govt of India, 1966, p. 151*

1. We are in sympathy with this demand and we believe

जिन राज्यों में अनिवार्य शिक्षा के लिए घनेकों वर्षों से प्रयास हो रहे हैं वहाँ वर्षों की सख्या में काफी कमी है। इसका प्रमुख कारण यही है कि हमारे देश के सुविधाओं में समानता नहीं है।

शैक्षिक सुविधा की असमानताओं के कारण भारत के विभिन्न राज्यों में अनिवार्य शिक्षा की स्थिति भिन्न है। तालिका न० ३.२ से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्यों में अनिवार्य शिक्षा की स्थिति में काफी विभिन्नता है। बालिकाओं की स्थिति से तो यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि शैक्षिक सुविधाओं की समानता के कारण विभिन्न राज्यों की स्थिति में कितना अन्तर है। मुख्य रूप से इन कारणों को निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं—

### तालिका न० ३.२

६ से ११ वर्ष के पाठशाळा में पढ़ने वाले बालकों की

प्रतिशत संख्या

राज्य	बालक	बालिकाएँ	कुल प्रतिशत
असम	73.6	45.6	60.5
बिहार	76.4	41.2	58.8
गुजरात	43.9	16.1	35.1
कर्नाटक प्रदेश	61.5	13.6	33.3
केरल	100.0	91.0	95.5
महाराष्ट्र	38.5	9.3	24.5
मध्य प्रदेश	41.2	8.9	25.7
पंजाब	74.6	32.4	55.1
राजस्थान	67.8	16.6	42.7
सिक्किम प्रदेश	77.7	14.1	47.2
तमिल नाडु	48.6	23.5	36.4
उत्तर प्रदेश	60.6	40.4	62.0
बंगाल	95.1	48.8	72.2
हरियाणा	97.8	41.2	70.5
झारखण्ड	97.0	82.0	89.6
कोलकाता	85.1	61.0	73.5
लद्दाख	55.8	11.9	34.0
मणिपुर	15.8	2.1	9.5
मेघालय	88.1	64.4	71.3
मिजोरम	84.0	50.0	67.5
औसत	69.0	33.0	51.0

## \* आर्थिक सुविधाओं में असमानता

### Inequality in Economic Opportunities

हमारे देश में सभी राज्यों के घन्तगंत आर्थिक सुविधा समान नहीं है। कुछ राज्य आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हैं जबकि कुछ राज्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इसके प्रतिरिक्त कुछ राज्यों में शिखा सम्बन्धी योजनाएँ मिलती हैं।

## \*\* मनोवैज्ञानिक कारण

### Psychological Causes

हमारे देश में अब भी इस प्रकार की जातियाँ हैं जो अपने लहके लहकियों को स्कूल भेजना नहीं चाहते। कहीं पर पर्दा प्रथा इतनी अधिक है कि लड़कियों को घर के बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता है। कुछ आदिवासियों की परम्पराएँ बिना लड़कें हैं और वे अपने लड़कों को निराला शिक्षा भी दिसवाना नहीं चाहते।

## \*\* सामाजिक विघटन

### Social Disintegration

अनिवार्य शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का विघटन हो चुका है। आज हमारा समाज अनेकों बर्गों से विभाजित है जैसे पिछड़े हुई जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, निम्नवर्ग, अल्पवर्ग आदि। इन प्रकार के सामाजिक विघटन से सबका समान सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो पाती जिससे बर्गों की लड़ाई प्रतिदिन फैलती जा रही है।

उपरोक्त समस्याओं के हल की आवश्यकता है। यदि हम अनिवार्य शिक्षा करना चाहते हैं तो यह नितांत आवश्यक है कि उपरोक्त असमानताओं को समाप्त किया जाये। जिन राज्यों की आर्थिक दशा ठीक नहीं है और जो शिक्षा पर अधिक व्यय करने में असमर्थ हैं, वही केन्द्रीय सरकार आधिकार से अधिक सहायता प्रदान करने बिना सम्पूर्ण भारत के नागरिक किन्हीं राज्य विशेष की आर्थिक कठिनाई के कारण इस अधिकार से वंचित न रह सकें। जिन जातियों व्यवस्था सामाजिक व्यवस्थाओं में लड़कियों की शिक्षा को ठीक नहीं समझा जाता, वही उन्हें अनुसूचित की वास्तविकता से परिचित कराना नितांत आवश्यक है। इसका हल ढोड़े समय में नहीं होगा परन्तु परिवर्तित सामाजिक व्यवस्था तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रयत्न इस क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रगति प्राप्त कर सकते हैं।

## (2) प्रशासकीय समस्याएँ

### Administrative Problems

आर्थिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों प्रशासकीय समस्याएँ हैं जिनमें कारण सही परिवर्तन व्यवस्था का बल नहीं करना। सर्वप्रथम अधिकारियों की संख्या तो

कम है और शासकों की सख्या अधिक है। इसके अतिरिक्त जहाँ पर प्राथमिक शिक्षा पंचायत समितियों के अधीन है वहाँ तो स्थिति और भी गम्भीर है। स्कूल सरपंचों तथा पंचों के अधीन होने से राजनैतिक दाव पैचों का बसाड़ा मात्र बन कर रह गये हैं। जाति विरोध के बालको के साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है जिसके कारण अनिवार्य रूप प्राप्त नहीं हो पाता। गाँवों में अध्यापकों की सरपंचों का दास बनकर रहना पड़ता है, यदि अध्यापक छात्रों का उत्प्रेषण करता है तो उसे प्रशासनिक यातनाएँ सहन करनी पड़ती हैं। हमारे कहने का अर्थ यह नहीं कि सभी स्थानों पर इस प्रकार होना होगा परन्तु इनका निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा को पंचायत समिति में देने के स्थान पर यदि जिला निरीक्षक कार्यालय के अधीन रखला जाये तो अधिक उपादेय हो। इसके अतिरिक्त इससे सबसे बड़ा लाभ यह भी है कि शिक्षा से सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा किया गया प्रमाणित अनिवार्य शिक्षा की दृष्टि से बिना पड़े निम्ने लोगों के प्रशासन की अपेक्षा अधिक सन्तोष प्रद हो रहेगा। इस क्षेत्र में यदि अनुसन्धान किया जाये तो और भी वस्तुनिष्ठ कानों की प्राप्ति हो सकती है तथा अन्य प्रशासकीय समस्याओं तथा उनके निराकरण के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

इस समय सम्पूर्ण भारत में प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन मुख्यतः तीन प्रकार का है।

(1) वे राज्य निम्नलिखित हैं जहाँ पंचायत राज को लागू नहीं किया है—

(i) जम्मू काश्मीर।

(ii) मैसूर।

(2) वे राज्य निम्नलिखित हैं जहाँ पंचायत राज अभिनियम को लागू तो कर दिया गया है परन्तु शिक्षा को पंचायत राज के अधीन स्थानान्तरित नहीं किया गया है—

(i) केरल

(ii) पश्चिमी बंगाल

(iii) आसाम

(iv) मध्य प्रदेश

(v) बिहार

(3) वे राज्य निम्नलिखित हैं जहाँ पंचायत राज अभिनियम को लागू करके शिक्षा को पंचायत राज में स्थानान्तरित कर दिया गया है—

(i) उत्तर प्रदेश

(ii) राजस्थान





रे-वीरे यह समस्या दूर हो सकती है और धनले 5-10 वर्षों में यह समस्या  
 जल्दी दूर हो सकती है।

#### (4) अध्यापकों की समस्या

(Problem of Teachers)

अध्यापकों की समस्या को हम निम्नलिखित भागों में विभाजित कर  
 सकते हैं:—

सांख्यिक नं० 2.4

प्राथमिक स्तर के अध्यापकों की शिक्षा

निम्नतर प्राथमिक शालाएँ			उच्चतर प्राथमिक शालाएँ		
सनातन धर्म अधिक	सैकण्डरी अथवा सनातन से कम	सैकण्डरी से कम	सनातन धर्म अधिक	सैकण्डरी अथवा सनातन से कम	सैकण्डरी से कम
1950-51 कुल 898 (0.2)	14,730 (9.8)	410,609 (90.0)	1950-51 पुरुष 3,920 (6.4)	31,267 (43.1)	37,422 (51.5)
स्त्री 410 0.5	9,670 11.8	72,201 87.7	स्त्री 887 (6.9)	4,323 (33.5)	7,677 (59.6)
कुल 1,308 (1.7)	34,400 (10.1)	482,210 (89.6)	कुल योग 4,807 (5.6)	35,590 (41.6)	45,099 (52.8)
1965-66 कुल 1,410,652 (1.8)	410,652 (1.8)	412,260 (1.8)	1965-66 पुरुष 23,600 (2.8)	212,200 (2.8)	144,300 (2.8)

(1) अध्यापकों के प्रशिक्षण की समस्या  
**Problem of Teachers' Training**

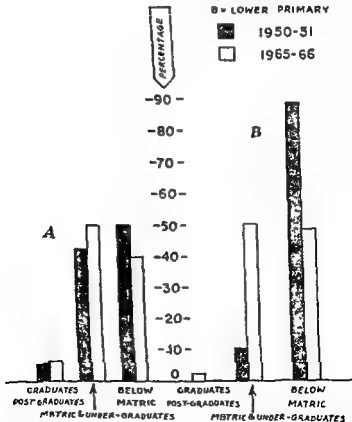
बहुत से राज्यों में अप्रशिक्षित अध्यापकों की प्रचुरता है। जब तक प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था नहीं होगी तब तक न तो शिक्षा का स्तर ही ऊपर

**QUALIFICATIONS  
 OF  
 PRIMARY TEACHERS**

A = HIGHER PRIMARY

B = LOWER PRIMARY

■ 1950-51  
 □ 1965-66



उठ सकता है और न प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्यता ही प्रदान की जा सकती है।



धीरे-धीरे यह समस्या दूर हो सकती है और अपने 5-10 वर्षों में यह समस्या लुप्त हो सकती है।

(4) **शिक्षकों की समस्या**

*(Problem of Teachers)*

शिक्षकों की समस्या को हम निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं:—

सामिका नं० 2.4

प्रयास करें और माता-पिताओं को प्रेरित करें। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि वर्ष में एक बार अध्यापक अभिभावक सम्मेलन हो और जो माता-पिता अपने-बालकों के शैक्षिक विकास में रुचि नहीं रखते उन्हें इसके प्रति सचेत किया जावे।

तालिका नं० 2.5

राज्य	अध्यापकों की कुल संख्या एवं प्रतिशत	
	उच्चतर प्राथमिक स्तर	निम्नतर प्राथमिक स्तर
1. आंध्र प्रदेश	15,628 (80.5)	86,501 (90.0)
2. आसाम	14,810 (22.4)	37,500 (55.0)
3. बिहार	32,918 (72.5)	99,663 (82.7)
4. गुजरात	83,650 (61.4)	उच्चतर प्राथमिक स्तर में सम्मिलित
5. जम्मू काश्मीर	3,467 (54.2)	48,74 (54.0)
6. केरला	39,406 (82.7)	59,703 (93.0)
7. मध्य प्रदेश	27,961 (72.0)	67,0006 (80.0)
8. महाराष्ट्र	59,440 (93.1)	76,638 (96.7)
9. महाराष्ट्र	151,500 (74.8)	उच्चतर प्राथमिक स्तर में सम्मिलित
10. मैसूर	91,952 (59.9)	उच्चतर प्राथमिक स्तर में सम्मिलित
11. नागालैंड	745 (8.7)	1,784 (20.3)
12. उड़ीसा	10,322 (31.0)	48,339 (60.0)
13. पंजाब	14,011 (88.0)	34,863 (89.0)
14. राजस्थान	18,352 (71.0)	41,600 (75.0)
15. उत्तर प्रदेश	46,819 (87.1)	162,472 (73.5)
16. पश्चिमी बंगाल	12,041 (16.3)	98,306 (38.3)

यह वह निगम्य आवश्यक है कि प्राथमिक ज्ञानाधों के अन्तर्गत प्रतिनिधि  
 की भी आवश्यकता हो। यह जमीनसमय है जबकि प्रतिनिधि विद्यमान प्रविष्ट  
 न होने जाये। प्रतिनिधि प्राप्त करने के लिए गुरुत्व योग्यता मैट्रिक्स/हायर  
 ० रखनी जाये। कुछ राज्यों में अभी तक भी यह स्थिति है जहाँ मैट्रिक्स के  
 पास गिरित नाम अन्तर्गत पड़ा रहे है। प्राथमिक धोरणों के आधार पर  
 'म० 2.1' में यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक ज्ञानाधों के अन्तर्गत में  
 अन्तर्गत मैट्रिक्स नाम भी नहीं है, इसके अतिरिक्त कुछ अन्तर्गत स्थापक  
 स्पष्ट भी है परन्तु इन प्रकार के अन्तर्गतों की संख्या बहुत कम है। जो  
 : सेटिंग्स की बात नहीं है उन्हें छोड़ ही से छोड़ हायर सेटिंग्स की बात करने  
 प्रेरित किया जाये।

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि प्राथमिक ज्ञानाधों में अग्रिमिनिधि अन्तर्गत  
 में अग्रिमिनिधि है। इसके लिए यह निगम्य आवश्यक है कि अग्रिमिनिधि अन्तर्गत  
 प्रमोदित किया जाये। तानिका 2.5 से यह स्पष्ट होता है कि बहुत से  
 में अभी तक अग्रिमिनिधि अन्तर्गतों की संख्या बहुत कम है जिसमें आयात,  
 : उद्दीप्ता और परिपक्व बगान विशेष उल्लेखनीय हैं। यदि विभिन्न राज्यों  
 : अग्रिमिनिधि अन्तर्गतों की संख्या एक प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाये तो  
 : अग्रिमिनिधि अन्तर्गतों की संख्या 21-25 वर्ष के अन्तर्गतों की संख्या  
 : मोडैरनातिक दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा के विकास में अग्रिमिनिधि है। तानिका  
 : में विभिन्न आयु स्तरों पर अग्रिमिनिधि प्राथमिक अन्तर्गतों की प्रतिशत

—————

कोठारी आयोग ने इस समस्या के समाधान के लिए बताया है कि उन अध्यापकों के लिए जो आदिवासियों को शिक्षा प्रदान कर सकें, भवन एवं अधिक वेतन की व्यवस्था करनी चाहिए। इन अध्यापकों को उस आदिवासी भाषा और संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए तथा उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसके लिए विशेष स्थान होना चाहिए। इन पाठशालाओं के कार्यक्रमों में भी आदिवासी जीवन की झलक होनी चाहिए।<sup>12</sup> यदि आदिवासियों के लिए उचित अध्यापकों की व्यवस्था हो जाये तो निश्चित रूप से अनिवार्य शिक्षा की बगो में एक बहुत बड़ी पूर्ति हो सकती है।

(iii) बालिकाओं के लिए अध्यापकों की समस्या

### Problems of Lady Teachers for Girls

शिक्षा की अनिवार्य रूप प्रदान करने में एक अन्य समस्या स्त्री शिक्षकों का भ्रमाव भी है। हमारा देश कृषिवादी देश है और इसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि शिक्षा कार्यक्रमों को इस प्रकार का बनाया जाये जिसमें सामाजिक मूल्यों को

तालिका न० 27

महिला अध्यापकों की प्रतिशत संख्या

राज्य	पुरुषों की तुलना में महिला अध्यापकों की प्रतिशत संख्या
केरल	46
मद्रास	33
मैसूर	25
पश्चिमी बंगाल	14
राजस्थान	10
उड़ीसा	5

ठेक न पहुँचे। हमारे देश में इस प्रकार के भाषा-विवादों का भ्रमाव नहीं है जो अपनी बालिकाओं को लड़कों के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहते। इसके

1. The obvious remedy seems to lie in providing better scales to pay and adequate housing facilities for those who are prepared to take up the task of teaching in tribal areas. The teacher must know the tribal language and culture, and a study of these should be included in their training programmes. The programme of the school will have to be redesigned to suit tribal life.

# 11) आदिवासियों के लिए अध्यापकों की समस्या

## Problems of Teachers for Tribals

प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए एक समस्या आदिवासियों के मामलों को शिक्षा प्रदान करने की है। इस समस्या का मूल कारण अध्यापकों की कमी है। प्रदेश अध्यापक आदिवासियों को शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता, इसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उनकी भाषा को तथा संस्कृति को समझा जाये।

तालिका नं० 2.6

विभिन्न आयु श्रेणियों में अग्रशिक्षित अध्यापक (1985)

आयु	अग्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत			
	निम्नतर प्राथमिक स्तराएँ		उच्चतर प्राथमिक स्तराएँ	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
20 से नीचे	8.9	11.9	11.0	9.0
21—25	40.7	31.7	30.1	30.3
26—30	23.2	23.8	26.9	27.6
31—35	11.6	13.7	13.7	15.3
36—40	6.6	7.9	8.9	8.6
41—45	3.7	5.0	4.0	4.5
46—50	2.4	3.1	2.5	2.7
51—55	1.9	2.2	1.9	1.2
56—60	0.9	0.7	0.9	0.6
60 से ऊपर	0.2	—	0.1	0.2
कुल प्रतिशत	100.0	100.0	100.0	100.0

कोठारी आयोग ने इस समस्या के समाधान के लिए बताया है कि उन अध्यापकों के लिए जो आदिवासियों की शिक्षा प्रदान कर सकें, भवन एवं अधिक वेतन की व्यवस्था करनी चाहिए। इन अध्यापकों को उस आदिवासी भाषा और संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए तथा उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसके लिए विशेष स्थान होना चाहिए। इन पठशालाओं के कार्यक्रमों में भी आदिवासी जीवन की झलक होनी चाहिए।<sup>1</sup> यदि आदिवासियों के लिए उचित अध्यापकों की व्यवस्था हो जाये तो निश्चित रूप से अनिवार्य शिक्षा की कमी में एक बहुत बड़ी पूर्ति हो सकती है।

(iii) बालिकाओं के लिए अध्यापकों की समस्या

#### Problems of Lady Teachers for Girls

शिक्षा को अनिवार्य रूप प्रदान करने में एक अन्य समस्या स्त्री शिक्षकों का अभाव भी है। हमारा देश रुढ़िवादी देश है और इसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि शिक्षा कार्यक्रमों को इस प्रकार का बनाया जाये जिसमें सामाजिक मूल्यों को

तालिका न० 27

महिला अध्यापकों की प्रतिशत संख्या

राज्य	पुरुषों की तुलना में महिला अध्यापकों की प्रतिशत संख्या
केरल	46
मद्रास	33
मिजोर	25
पश्चिमी बंगाल	14
राजस्थान	10
छत्तीसगढ़	6

हट न पहुँचे। हमारे देश में इस प्रकार के भाषा-विनाशों का अभाव नहीं है जो अपनी बालिकाओं को सड़कों के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहते। इससे

1. The obvious remedy seems to lie in providing better scales to pay and adequate housing facilities for those who are prepared to take up the task of teaching in tribal areas. The teacher must know the tribal language and culture, and a study of these should be included in their training programmes. The programme of the school will have to be redesigned to suit tribal life.

Report of the Education Commission, p. 16

अध्यापिकाओं का अभाव है इसका एक प्रमुख कारण यह है कि स्त्री शिक्षकों की तुलना में बहुत कम है जब कि सत्यता यह है कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका अधिक प्रयोजनीय सिद्ध हो सकती है। इसीलिए शैक्षिक दृष्टि से बहुत कम है जैसा कि तालिका न० 27 में स्पष्ट किया गया है। तालिका न० 28: राज्यों के आकड़े ही प्रदर्शित किये गये हैं और इसका एक मात्र आधार पर हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में अभी बहुत काम करना है। स्वतन्त्रता के पश्चात् हमने प्रगति की है तथापि अनिवार्य शिक्षा के कार्य करने में अभी बहुत कुछ करना है।

तालिका नं० 2-8<sup>1</sup>

प्राथमिक स्तर पर शिक्षा पा रहे लड़कों और लड़कियों की तुलना

स्तर/वर्ष	000' में प्रवेस		
	लड़के	लड़कियाँ	योग
वर्ग 1 से 4 तक			
1950—51	10,102 (4.1)	3,519 (7.2)	13,651 (4.9)
1955—56	12,369 (6.8)	5,011 (9.3)	17,380 (7.5)
1960—61	16,170 (14.3)	7,826 (9.9)	24,996 (8.2)
1965—66	24,536 (7.8)	12,554 (10.2)	37,090 (8.1)
1970—71	34,447 (20)	26,850 (10.4)	61,297 (5.5)
1975—76	38,066 (1.6)	33,484 (2.8)	71,550 (2.2)
1980—81	41,173	38,515	79,688
1985—86	39,509	36,730	76,239
वर्ग 5 से 7 तक			
1950—51	2,669 (6.5)	559 (10.8)	3,228 (7.6)
1955—56	3,659 (8.8)	933 (15.0)	4,592 (10.2)
1960—61	5,587 (9.9)	1,876 (13.8)	7,463 (11.0)
1965—66	8,962 (10.0)	3,587 (15.6)	12,549 (11.1)
1970—71	14,433 (6.5)	6,786 (13.2)	21,218 (8.8)
1975—76	19,774 (3.8)	12,620 (7.9)	32,394 (5.5)
1980—81	23,847 (1.1)	18,456 (5.0)	42,323 (2.9)
1985—86	25,214	23,500	48,714



- बालिका शिक्षा के विषय में परम्परागत धारणा को समाप्त कर नए सिद्धि कराना;
- अध्यापिकाओं की नियुक्ति;
- मिश्रित प्राथमिक शाळाओं को लोकप्रिय बनाना, और जहाँ पर लागू के लिए पृथक शाळा खुलाना सम्भव है वहाँ उच्चतर प्राथमिक शाळाओं को खुलाने का प्रावधान हो;
- पुस्तकों, अन्य सामग्री और छावश्यकता बढ़ने पर शर्तों की व्यवस्था, और
- 11 से 13 वर्ष की उन लड़कियों के लिए, जो पूरे समय शाला न पढ़ सकें, उनके लिए कम समय की शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान।

उपरोक्त समाधानों को क्रियान्वित करना निम्न आवश्यक है। कोयला आयोग ने इन सभी समाधानों से सहमति प्रकट की है। प्राथमिक शिक्षा को प्रचारित बनाने की दृष्टि से यह निम्न आवश्यक है कि उपरोक्त सुझावों को कृषि क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा के प्रति अधिक जागरूकता लाये। पहली 11 पाँचवी कक्षा में लड़कियों की शिक्षा के प्रति अधिक जागरूकता लाये। पहली 11 पाँचवी कक्षा में 24.6% से लड़कियों की प्रतिशत संख्या बढ़कर 33.2% हो गई है, छठी से आठवी कक्षा में 4.5% से 16.7% हो गई है।<sup>1</sup> यद्यपि प्रगति हुई है तथापि प्रगति धीमी है कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति निकट भविष्य में सम्भव नहीं

- \* educating public opinion to overcome traditional prejudice against girls education;
- \* appointing women teachers;
- \* popularising mixed primary schools, and wherever possible and demanded, opening separate schools for girls at higher primary stage.
- \* providing free books and writing materials and, where needed, even clothing, and
- \* providing part time education for girls in the age-group 11—13 who cannot attend schools on a whole-time basis because they are required to work at home.

*Ibid*, p. 16.

1. 'Girl students as a percentage of their population in the relevant age group increased from 24.6 per cent to 33.2 per cent in class I—V, 4.5 per cent to 16.7 per cent in class VI—VIII....'

Fourth Five Year Plan, A Draft Outline, Govt. of India, Planning Commission.

## (6) अपव्यय और अवरोधन

### Wastage and Stagnation

यद्यपि हम इस मुख्य बिन्दु पर किसी अगले अध्याय में विस्तृत रूप से विचार करेंगे तथापि यही प्रसंगवश इतना ही स्पष्ट करना काफी है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के मार्ग में अपव्यय और अवरोधन अम्नोर बाँवा के रूप में हैं। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर जो अपव्यय और अवरोधन है वह शिक्षा के अनिवार्य स्वरूप को प्रतिष्ठित करने में सफल रहा है। 911-12 में 100 छात्रों में से केवल 20 छात्र ही ऐसे थे जो पहली से चौथी कक्षा में जाते थे। 1946-47 में यह अनुपात 39 था। इससे प्रगति तो स्पष्ट होती है परन्तु बहुत कम स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्, जहाँ देश में सुधार होना था वहाँ उसे स्थान पर बिगाड़ हुआ है क्योंकि 1965-66 में 100 बालकों में से चौथी कक्षा में आने वाले बालकों की संख्या 37 थी। इससे स्पष्ट है कि जितनी तेजी से शिक्षा का विस्तार हुआ है उससे कुछ अपव्यय और अवरोधन भी बढ़ा है।<sup>1</sup> इन आँकड़ों से यह सात होता है कि प्राथमिक शिक्षा में ऐसे बालकों की प्रतिशत संख्या अधिक है जो चौथी कक्षा भयवा इससे पूर्व ही बालाघों को छोड़ देते हैं। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो बालक को चौथी कक्षा उतीर्ण करने से पूर्व ही हटा लेना भयवा बालक का एक वर्ष से अधिक किसी कक्षा में रहना। ये दोनों ही कारण प्राथमिक शिक्षा के मार्ग में बाधाएँ हैं, मतः यह बहुत आवश्यक है कि इन बाधाओं को दूर किया जाये जिससे अनिवार्य स्वरूप को अधिकधिक प्रयत्न प्राप्त हो।

## (7) अविकसित क्षेत्रों की समस्या

### Problem of Under developed Areas

यद्यपि तीन पञ्चवर्षीय योजनाओं में शिक्षिक अवसरों की समानता का प्रयास किया गया है तथापि अभी तक हम इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाये हैं। हमारे देश में अभी तक इस प्रकार के अविकसित क्षेत्र हैं जो अनिवार्य शिक्षा की दृष्टि से उपेक्षित हैं। प्राथमिक शिक्षा के विकास की केवलमान्य राज्यों की पृष्ठभूमि में देखने से सन्तोष कर लेना ही उचित नहीं है; हमें जिलों, तहसीलों, नगरों और

1. 'As against 100 children enrolled in class I, there were only 20 in class IV in 1911-12. In 1946-47, this proportion increased to 39. This shows some progress, though a slow one. In the post-independence period, however, the position has not only not improved but has deteriorated to some extent, because in 1965-66 there were only 37 students in class IV as against 100 in class I. The implication is obvious: the rapid expansion that has taken place has led to a slight increase in wastage and stagnation;

ग्रामों की वास्तविक स्थिति को देखना है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमने नगरों में शैक्षिक प्रसार हेतु अनेकों प्रयाग किये हैं परन्तु यदि ग्रामीण क्षेत्रों को देखें तो निराशा के दर्शन होते हैं।

इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था में शैक्षिक अवसरों की घटमात्रता मालूम होती है। गरीब और अमीर परिवारों में शैक्षिक उपलब्धि की दृष्टि से भारी भेद है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों, अनुसूचित वर्गों, विधवा जातियों, आदि के बालकों को प्राथमिक शिक्षा के वांछित अवसर प्रदान करना है। जब तक हम शैक्षिक दृष्टि से अविश्वसित क्षेत्रों को समान शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान नहीं करेंगे तब तक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान नहीं हो सकेगा। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य सरकारें जिसा स्तर पर विस्तृत प्राथमिक शिक्षा योजना बनायें और जो क्षेत्र अभी तक अविश्वसित रहे हैं उनके लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान की जायें।

## (8) अन्य समस्याएँ

### Other Problems

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएँ और भी हैं जैसे माता शिक्षा का निरंतर होना, सामाजिक दुरीनिधी, भवन की समस्या, सम्पूर्ण माँझों की उपलब्धि न होना आदि। इन सभी समस्याओं को दूर करना निताम्न आवश्यक है। कोटारी आयोग ने बताया अत्यन्त की है कि 1956 तक प्राथमिक शिक्षा को नि शुल्क और अनिवार्य कर देना निताम्न आवश्यक है। हुये बताया है कि यदि परिस्थितियाँ अनुकूल रहें तो निश्चित ही इन क्षेत्र में योजनाधीन प्रगति होगी। मध्य प्रजासत्तात्मक शासन पद्धति के लिए निताम्न आवश्यक है कि हुये देन का प्रत्येक मासिक शिक्षा हो। यह सभी सम्भव है अर्थात् अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में आई बाधाओं एवं समस्याओं को दूर दिया जा सके।

## ग्रन्थ - सूची

### Bibliography

1. Boyd, William.  
*The History of Western Education*, London, 1951
  2. Debirasse, Jean  
*Compulsory Education in France*, 1951
  3. Desai, D. M.  
*Universal, Compulsory and Free Primary Education in India*,  
Indian Institute of Bombay, 1953.
  4. Desai, D. M.  
*A Critical Study of Compulsory Primary Education Acts in  
India*, Baroda University, 1956.
  5. *Education in India*, Ministry of Education, 1959.
  6. *Education in the States, A Statistical Survey (1956-57)*, Ministry  
of Education, 1959.
  7. Mukerji, S. N.  
*Education in India, Today and Tomorrow*, Acharya Book  
Depot, Baroda, 1961.
  8. *Report of the National Committee on Women Education*, Ministry  
of Education, 1959.
  9. *Report of the Education Commission, 1964 - 66*, Ministry of  
Education, Govt. of India, 1966.
  10. R. V. Parulker,  
*Mass Education in India, Local Self Govt. Institute Bombay*,  
1934.
  11. *Second Five Year Plan*, Planning Commission.
  12. *Third Five Year Plan*, Planning Commission.
  13. *Fourth Five Year Plan, A Draft Outline*, Planning Commission.
-

# विश्वविद्यालय प्रश्न

## University Questions

1. Trace the development of Primary Education in India from the last thirty years. Also suggest measures to improve the quality which are being experienced in school's high Compulsory Primary Education in India.

Rajasthan 1952

2. Trace the history of Primary Education in India from 1903 to 1921.

Rajasthan 1952, Nagpur 1950

3. What are the main problems of Compulsory Education in India? Give your suggestions for solving them.

B. T. 1951

4. Give a historical review of the attempts made for Compulsory Primary Education in India. How far have these attempts been successful.

Agri 1953

5. Mention the difficulties that have been experienced in establishing a free and compulsory system of education in India and the attempts made to overcome them.

L. T. 1952

6. 'Man is more important than materials.' Enumerate the deficiencies in ordinary primary schools in Rajasthan in point of materials, and show how a good Inspector of schools can take up a school improvement programme effectively by:—

(a) mobilising the community resources, (b) inspiring the school teacher, (c) organising an efficient supervisory procedure.

Rajasthan, 1954.

7. Formulate the two most fundamental problems in the field of primary education in India, analyse them, and suggest measures for solving them.

Rajasthan, 1965

8. Name the problems of (a) Expansion and (b) Qualitative Improvement, in Elementary Education in India. Discuss one of the aforesaid problem areas giving suggestions for improvement.

भारत में प्राथमिक शिक्षा की (अ) प्रसारणत्मक घोर (ब) गुणात्मक समस्याएँ कौन सी हैं? उपरोक्त प्रत्येक में से दो-दो विषयों की समस्याओं की गुणात्मक प्रतिक्रिया कीजिये।

## अध्याय तीन

### Chapter Third

### प्राथमिक शिक्षा का विस्तार एवं गुणात्मक उन्नति

### *Expansion and Qualitative Advancement of Primary Education*

#### अध्ययन बिन्दु Learning Points

- 3.01 पाठ्यक्रम में सुधार  
(Improvement in Curriculum)
    - 1. लोघर प्राथमिक स्तर (कक्षा एक से चार)
    - 2. उच्चतर प्राथमिक स्तर (कक्षा पाँच से आठ)
  - 3.02 अध्यापकों के शैक्षिक स्तर में सुधार  
(Improvement in Teachers' Educational Standard)
    - 1. प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार
    - 2. पत्राचार द्वारा प्रशिक्षण
    - 3. अध्यापकों की न्यूनतम योग्यता
  - 3.03 शिक्षा-प्रणालय में सुधार  
(Improvement in Education Administration)
  - 3.04 वार्षिक व्ययों में सुधार  
(Improvement in Finances)
  - 3.05 शिक्षा विकास हेतु कार्यक्रम  
(Programmes for School Improvement)
  - 3.06 उपसंहार  
(Conclusion)
-

**प्राथमिक शिक्षा  
का  
विस्तार एवम् गुणात्मक उन्नति  
EXPANSION QUALITATIVE ADVANCEMENT  
OF  
PRIMARY EDUCATION**

शिक्षा का वास्तविक अर्थ एवं उद्देश्य मावी नागरिकों को व्यक्तिगत महत्त्व, मानव गौरव एवं सामाजोपयोगी वांछित क्षमताओं का विकास कर उनमें आत्म-साधुति, आत्म-उन्नति तथा सामाजिकता की भावनाओं को विकसित करना है। शिक्षा का अर्थ व्यक्तियों को केवल पढ़ी बठाना नहीं है जिससे वे नहीं जानते, बल्कि उनको व्यवहार करने की शिक्षा प्रदान करना है जैसा कि वे व्यवहार नहीं करते।<sup>1</sup> यदि हमें वास्तव में आम के बालकों और कम के मावी नागरिकों को शिक्षित करना है तथा देश के आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर को ऊँचा उठाना है तो

1. "Education does not mean teaching people to know what they do not know; it means teaching them to behave as they do not behave."

—John Ruskin

निश्चित ही हमें सुनियोजित प्राथमिक शिक्षा का विस्तार कर सर्वलौकिक गुणात्मक उन्नति प्राप्त करनी होगी।

शैक्षिक विस्तार का अर्थ केवल मात्रा में वृद्धि कर लेना ही नहीं है बल्कि मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ गुणात्मक उन्नति करना भी है। अतः स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाईस वर्षों के पश्चात् हमें गम्भीरतापूर्वक यह विचार करना है कि हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के साथ ही गुणात्मक उन्नति के मार्ग में क्या समस्याएँ हैं जिससे उनका समाधान कर प्राथमिक शिक्षा की योजना को अधिक सफल बनाया जा सके। हममें कोई सन्देह नहीं कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार हुआ है परन्तु विस्तार में गुणात्मकता का लोप है। बाहिर क्यों? यह एक प्रश्न है जिसे आज के बालक कम व्यस्त होने पर हमसे पूछेंगे। इसीलिए अब समय था गया है जबकि हम प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ उसके गुणात्मक पक्ष की ओर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

भूतपूर्व केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री श्री एम० सी० छावना ने रायों के शिक्षा मन्त्रियों की बैठक में कहा था कि 'हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विस्तार कर चुके हैं। प्राथमिक शिक्षा में हमने निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली है। अब समय था गया है जब हमें एकीकरण और गुण के त्रिव्य में सोचना चाहिए और मैं सोचना हूँ कि केन्द्र गुणात्मक उन्नति की प्रति हेतु कुछ निश्चित क्षेत्रों को चुने। मैं चाहूँगा कि सम्पूर्ण देश में 'अच्छता के शिखर' हों जो अन्य शानाओं के लिए प्रशस्तान्तर हों और जिनमें समान उच्च स्तर प्राप्त करने की इच्छा हो।' अतः यह निताम्न आवश्यक है कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार गुणात्मक रूप में हो त्रिव्यके लिए निम्नलिखित सुधारों की आवश्यकता है—

### 3.01 पाठ्यक्रम में सुधार

#### Improvement in Curriculum

प्राथमिक शालाओं का पाठ्यक्रम बालोचित आवश्यकताओं के प्रतिकूल है जिसमें बालकों की रचनात्मक क्षति का विकास नहीं होगा। यदि हमें प्राथमिक शिक्षा में बांँदिन उपभक्षियों को प्राप्त करना है तो पाठ्यक्रम में सुधार करना निताम्न आवश्यक है। यदि हमें बेमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय नीति के आधार पर प्राथमिक शिक्षा का आधार बनाना है तो यह आवश्यक है कि हम पुनः सम्पूर्ण

1. 'We have made a tremendous expansion. We have passed targets in primary education. The time has come when we think of Consolidation and quality and I think that the pick out selected sectors for purposes of improving like to have all over the country 'peaks of excellence' a set of beacon lights to all other institutions first attain the same high position.'

*M. C. Chogle, 25th April 1961*



पाठ्यक्रम को देने वाली बेसिक स्तर के उर्ध्व को का संकायान देना छोड़ित है ।  
मजे में हम निम्नी (मिड स्टेज) का विचार कर सकते हैं —

### (1) लोअर प्राथमिक स्तर (कक्षा एक से चार)

Lower Primary Stage (Classes I-IV)

लोअर प्राथमिक स्तर पर एक माता का ज्ञान निश्चित रूप से हो जाना चाहिए—भाते बहुत बच्चे माया हो संयथा प्राथमिक माया । मायावादा का ज्ञान ही इस स्तर पर हो जाना आवश्यक है—इस ज्ञान की विज्ञान और सामाजिक व्यवस्था की महत्त्वता से बच्चा दो से प्रारम्भ दिया जा सकता है । गणितीय के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान हो—दिगो बालक मायो जीवन से उत्पन्न गुरुत्व को समझे । इस स्तर पर बालक को गुरुत्वाकर्षण शक्ति का विचार भी होना चाहिए—यह गुरुत्वाकर्षण विद्यार्थी द्वारा सम्भव है । कार्य अनुभव, समय सेवा और स्वास्थ्य शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में समाप्त दिया जाय । कहने का तात्पर्य यह है कि मायोविज्ञान सभी प्राथमिक विषयों का आधारस्तु ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए ।

### (2) उच्चतर प्राथमिक स्तर (कक्षा पाँच से आठ)

Higher Primary Stage (Classes V-VIII)

इस स्तर पर दो मायोधों का ज्ञान कराया जा सकता है—मातृ माया संयथा प्राथमिक माया में से एक दूसरे हिंदी संयथा संकेतों में से एक । कोठरी मायोध में तो तीसरी माया की भी संज्ञित रूप से विचारित की है । मायोधों के ज्ञान के प्रतिरिक्त गणितीय, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन विषयों में शिक्षा—भूगोल और नागरिक शासन का मिश्रित रूप हो और मानवीय सम्बन्ध और प्रभाव का विशेष रूप से सम्मेलन किया जाये । कला, कार्यानुभव और समाज सेवा क्रियात्मक रूप से आवश्यक है । शारीरिक विकास हेतु शारीरिक शिक्षा का आयोजन हो । साध्यात्मिक विज्ञान हेतु नैतिक और साध्यात्मिक मूल्यों से ओत-प्रोत शिक्षा की व्यवस्था हो । कहने का तात्पर्य यह है कि इस स्तर पर भौतिकज्ञानिक आधार स्वरूप बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास होना चाहिए तथा पाठ्यक्रम में उन रचनात्मक एवं पुस्तकीय ज्ञान को स्थान दिया जाना चाहिए जिससे बालक का सर्वाङ्ग विकास सम्भव हो । प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता उन्नति सभी हो सकती है जबकि हम बालक के सर्वाङ्ग विकास को दृष्टिगत रखते हुए अधिक रूप से उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल हो सकें ।

### 3.02 अध्यापकों के शैक्षिक स्तर में सुधार

Improvement in Teachers' Educational Standards

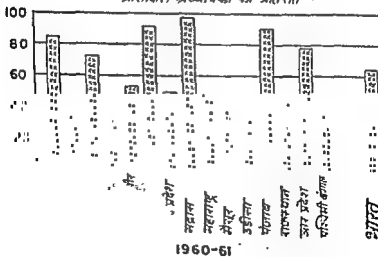
विद्यार्थी संख्या में वितरण का से वर्धा की :

मालाओं के अध्यापकों का शैक्षिक स्तर संशोधन में

प्राथमिक शिक्षा का सुधार करना है तो अध्यापकों के शैक्षिक स्तर पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि अध्यापक का शैक्षिक व्यक्तित्व बालक को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अतः यह आवश्यक है कि प्राथमिक शालाओं के अध्यापक स्तरानुसार शिक्षित और प्रशिक्षित हों। परन्तु वस्तु स्थिति बहुत विपन्न है क्योंकि 1950-51 में स्नातक अथवा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास शिक्षकों की संख्या सम्पूर्ण लोअर प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों की पूर्ण संख्या के 10.3 प्रतिशत थी और 1965-66 में यह 51.0 प्रतिशत हो गई। 1950-51 में उच्चतर प्राथमिक शालाओं में इस प्रकार के अध्यापकों की संख्या 47.2 प्रतिशत थी और 1965-66 में बढ़ कर 60.0 हो गई। उपरोक्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि अध्यापकों के शैक्षिक स्तर में बहुत भीषण गति से सुधार हुआ है। यदि इसी प्रकार की गति रही तो अगले 20-25 वर्षों के पश्चात् ही प्रत्येक प्राथमिक शाला का अध्यापक शैक्षिक दृष्टि से उच्चतर माध्यमिक पास हो सकेगा। यदि इनके समय तक प्रतीक्षा की गई तो देश के मावी भविष्य का निश्चय करना कठिन होगा।

जहाँ तक प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रश्न है उसमें प्रगति तो अवश्य हुई है परन्तु गुणात्मक दृष्टि से सम्तोषजनक नहीं है। अतः आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य

लोअर प्राथमिक स्तर  
के  
प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत 3



1960-61

(i) समस्त नई नियुक्तियाँ केवल उन्हीं अध्यापकों को दी जाएँ जो दस वर्ष की सामान्य शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। स्त्री शिक्षकों तथा घादियाली क्षेत्रों के शिक्षकों के लिये यह उस दशा में अपवाद भी हो सकता है यदि योग्य व्यक्ति न मिलें।

(ii) कम शिक्षित अध्यापकों की सहायता के लिये विशेष धन दिया जाये जिससे वे पचाचार द्वारा अपनी योग्यताओं को बढ़ा सकें। इसके अनिर्दिष्ट उद्देश्य पर्यटन के लिये प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए।

उपरोक्त सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनमें वर्तमान प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था तथा मात्री व्यवस्था को सुलभतापूर्ण योग प्राप्त हो नयेगा।

### 3.03 शिक्षा-प्रशासन में सुधार

#### Improvement in Educational Administration

प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन मुख्यतः तीन एजेंसियों के प्राचीन है—सरकार, स्थानीय शासन और निजी प्रबन्ध। तालिका नं० 3.1 से यह स्पष्ट होता है कि

#### तालिका नं० 3.1

विभिन्न प्रबन्धों में प्राथमिक शिक्षा (1960-61)

#### शालाओं की संख्या

	सरकार द्वारा प्रबन्ध	स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रबन्ध	निजी प्रबन्ध
1. लोघर प्राथमिक शालाएँ	72,380 (21.9)%	184,825 (55.9)%	73,194 (22.2)%
2. उच्चतर प्राथमिक शालाएँ	9,895 (19.5)%	26,481 (53.4)%	13,484 (27.1)%

restricted to those who have had at least ten years of general education. Exceptions should be made, if qualified persons are not available, only in the case of women teachers or teachers for tribal areas.

(iii) For greater emphasis should be placed on helping unqualified teachers in service to improve their qualifications by providing correspondence courses and allowing liberal concessions for study leave.

1960-61 में लोघर तथा उच्चतर प्राथमिक शालाओं की संख्या विभिन्न प्रबन्धों में निम्न प्रकार की थी। उस समय लोघर प्राथमिक शालाओं की कुल संख्या 330,309 और उच्चतर प्राथमिक शालाओं की 49,642 थी जिसमें से स्थानीय प्रबन्ध शालाओं की संख्या सबसे अधिक है और सरकार एवम् निजी प्रबन्धों में विशेष भ्रन्तर नहीं है परन्तु फिर भी निजी शालाओं की संख्या कुछ अधिक है। जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि सरकार द्वारा शिक्षा का प्रबन्ध अपेक्षाकृत कम है और स्थानीय एवम् निजी प्रबन्धों की अधिकता है। हममें सन्देह नहीं कि केन्द्रीय सरकार प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदार नहीं परन्तु प्रान्तीय सरकार को मार्ग-दर्शन करना उसी का उत्तरदायित्व है क्योंकि केन्द्रीय सरकार ही इस प्रकार की करी है जो प्रान्तीय सरकारों की नीतियों में सामञ्जस्य स्थापति कर सकती है। केन्द्रीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्र व्यापी प्राथमिक शिक्षा नीति का निर्धारण करना है जिसमें प्राथमिक स्तर पर प्रशासनिक सुधार हो सके।

प्रान्तीय सरकारों का उत्तरदायित्व है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सुझाई गई नीतियों का यथामन्मव निर्धारण किया जाये। आर्थिक स्रोतों को अधिकधिक बढ़ावा दिया जाये जिसमें गुणसमक पक्ष को सामने रक्खा जाये। अध्यापकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था हो और प्रशिक्षण विद्यालयों को यथामन्मव सुविधाएँ प्रदान की जायें जिससे अच्छे अध्यापकों का निर्माण हो सके। प्राथमिक शिक्षा के गुणसमक पक्ष को बल प्रदान करने के लिए प्रशासकीय विभाग हो जिससे स्थानीय एवम् निजी प्रबन्धों में आधीन शालाओं का निरीक्षण हो सके। स्थानीय एवम् निजी संस्थाओं को राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाये जिससे प्राथमिक शिक्षा की गुणसमकता को सभी प्रबन्धों द्वारा सक्रिय सहयोग प्राप्त हो सके। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा प्रशासन में सुधार हो।

### 3.04 आर्थिक साधनों में सुधार

#### Improvement in Finances

प्राथमिक शिक्षा की गुणसमक वृद्धि हेतु यह नितीय आवश्यक है आर्थिक सहायता में वृद्धि की जाये जिससे प्रशिक्षित अध्यापक, जनसंख्या के अनुसार शालाओं की संख्या में वृद्धि, अच्छे भवन आदि की व्यवस्था की जा सके। यह तभी सम्भव है जबकि प्राथमिक शिक्षा पर अधिक व्यय किया जाये। हममें कोई सन्देह नहीं कि प्राथमिक शिक्षा पर प्रत्यक्ष रूप से व्यय की जाने वाली धन राशि में उत्तरीतर वृद्धि हुई है। तालिका नं० 3.2 में यह स्पष्ट होता है कि 1901 से 1966 तक सम्पूर्ण प्राथमिक शिक्षा योजना के व्यय में वृद्धि हुई है।

निम्नलिखित तालिका से यह स्पष्ट है कि 1901 से 1966 तक प्राथमिक शिक्षा के व्यय की बढ़ावा बना है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या यह वृद्धि देश की वर्तमान



### तालिका सं० 3.3

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिक शिक्षा पर व्यय

( व्यय करोड़ रुपयों में )

प्रथम पंचवर्षीय योजना ( 1951-55 )	85
द्वितीय पंचवर्षीय योजना ( 1956-61 )	87
तृतीय पंचवर्षीय योजना ( 1961-66 )	209
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	322

उपरोक्त अध्ययन विष्णु के सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु अधिक धन की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकारों को उत्तरदायित्व निभाने का प्रयत्न करना चाहिए और केन्द्रीय सरकार को यथा-सम्भव सहायता करनी चाहिए जिससे गुणात्मक विशास सम्भव हो।

#### 3.05 शाला विकास हेतु कार्यक्रम

##### Programmes for School Improvement

प्राथमिक शिक्षा को गुणात्मक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कुछ निश्चित कार्यक्रम बनाये जायें। इन कार्यक्रमों को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि जिले स्तर पर कार्य प्रारम्भ किया जाये। एक जिले में समस्त शहरों के प्राथमिक शालाओं को ध्यान-दास के सामील क्षेत्र दिये जायें जो निश्चित क्षेत्रों को प्राथमिक शालाओं को इन कार्यक्रमों से परिचित करायें। जिले के एक प्राथमिक शाला को जो समस्त प्राथमिक सुविधाओं से सम्पन्न हों, यह कार्य सीपा सेवा-प्रसार विभाग द्वारा अपने क्षेत्र के समस्त प्राथमिक शालाओं को करने।

## तालिका नं० 3.2

प्राथमिक शिक्षा पर कुल व्यय

	1901-02	1921-22	1946-47	1950-51	1960-61	1965-66
सोघर प्राथमिक स्तर	119	509	1849	3649	7344	12200
उच्चतर प्राथमिक स्तर	47	166	480	770	4292	7175
प्रशिक्षण विद्यालय	47	58	91	152	344	600
योग	173 करोड़	733 करोड़	2420 करोड़	4571 करोड़	11980 करोड़	19975 करोड़

शिक्षा को देने में हम सही तरह हैं ? क्या हम हम सही हुई योजनाओं से मुगलक विद्यालय करने में सफल हो सकते हैं ? सम्भव दोनों ही प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है । क्यों ? इसलिए कि देश की वर्तमान अवस्था को देखते हुए योजनाओं को बनाना सही है । हमारे वर्तमान शिक्षा प्रणाली का नाम है तो हम सही तरह का शिक्षा प्रणाली बनाए रखेंगे । यह शिक्षा प्रणाली सही है कि प्राथमिक शिक्षा के मुगलक विद्यालय का सकारात्मक विद्यालय भी सही तरह सहे ।

हम सही योजनाओं के साथ ही सही तरह का शिक्षा प्रणाली बनाए रखेंगे । यह शिक्षा प्रणाली नं० 3.3 के तहत शिक्षा का सही तरह सहे ।

## ग्रन्थ - सूची

### Bibliography

1. Desai, B. M.  
*A Critical Study of Primary Education Acts in India*, M. S. University, Baroda, 1957.
  2. Estimate Committee,  
*Elementary Education*, Lok Sabha Secretariat, New Delhi, 1958.
  3. Ministry of Education, (Govt. of India)  
*Report of the First Meeting of All India Council of Elementary Education*.
  4. ....  
*School for All*, 1958.
  5. ....  
*National Seminars on Compulsory Primary Education (Report I, II, III, IV)*
  6. ....  
*Report of the Education Commission, 1964-66*.
  7. National Council of Educational Research and Training,  
*The Indian Year Book of Education*.
  8. ....  
*Second Year Book (Elementary Education)*, 1964.
  9. Sen, J. M.,  
*History of Elementary Education in India*, M. Book Co., Calcutta, 1943.
-



करेंगी। इसीलिए यह आवश्यक है कि शालाघों को विभाजित किया जाये और कलाघों पर विशेष ध्यान दिया जाये।

3.06 उ  
Co

उपरोक्त समस्त बिधुओं के व्यापार व शिक्षा का विशिष्ट उद्देश्य बालकों को तैयार है। यह सभी सम्भव है जबकि हम शिक्षा के हमारे देश का प्रत्येक शिक्षा शास्त्री प्राप्ति चाहता है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स सब बालकों और बालिकाओं को निःशुल्क एका स्वीकार किया गया था परन्तु यह हमारा धुम नहीं कर पाये हैं। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा सुझावों को स्वीकार कर चौदह वर्ष की आयु के तकने में समर्थ हो सकें और साध-माध गुणात्मक इक्कीस वर्षों के पश्चात् भी यदि प्राथमिक शिक्षा नहीं कर पाये तो निश्चित ही हम सप्ताह के रहेंगे। स्वतंत्र भारत को धन्य विकासशील देश अत्यन्त आवश्यक है सम्पूर्ण शिक्षा जीवन की शिक्षा को गुणात्मक बना सकें।

इसमें सन्देह नहीं कि निरक्षरता देश के यह समय था गया है जबकि हम निरक्षरता को शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दें जिससे देश का

## अध्याय चार

### Chapter Fourth

#### एक-अध्यापक शाळा

#### *Single-Teacher School*

#### अध्ययन बिन्दु

#### Learning Points

#### \* 4.01 ऐतिहासिक विकास

##### Historical Development

- (1) प्राचीन भारतीय शिक्षा का प्रतीक
- (2) मध्यकाल में एक-अध्यापक शाळाएँ
- (3) अंग्रेजी काल में एक-अध्यापक शाळाएँ

#### \* 4.02 स्वतन्त्रता के पश्चात् एक-अध्यापक शाळाएँ

##### Single-Teacher Schools After Independence

#### \* 4.03 एक-अध्यापक शाळा व्यवस्था की समस्याएँ

##### Problems of Single-Teacher School System

- (1) विभिन्न प्रकार की शाळाओं की समस्या
- (2) अध्यापकों की नियुक्ति सम्बन्धी समस्या
- (3) अध्यापकों के स्थानान्तरण की समस्या
- (4) धनकाम प्राप्त करने की समस्या
- (5) समय-सारिणी की समस्या
- (6) अध्यापकों के प्रशिक्षण की समस्या
- (7) पाठ्यक्रम की समस्या

#### \* 4.04 अनुसन्धान की आवश्यकता

##### Need for Research

## विश्वविद्यालय प्रश्न University Questions

1. Formulate the two most fundamental field of primary education in India, analyse the measures for solving them.

2. Name the problems of (a) Expansion and (b) qualitative improvement in Elementary Education in one of the aforesaid problem areas giving suggestions.

भारत में प्राथमिक शिक्षा की (अ) प्रसारणात्मक और (ब) सुधारणात्मक समस्याएँ कौन सी हैं? उपरोक्त में प्रत्येक से दो-दो किन्हीं एक की समस्याएँ चुनकर चर्चा कीजिये।

3. "It is necessary to achieve needed expansion in primary education along with the improvement in quality".  
Rajasthan,  
Discuss the above statement in the light of qualitative primary education.

4. "We have made a tremendous expansion. We have passed our targets in primary education. The time has come when we should think of consolidation and quality and I think that we must pick out selected sectors for purposes of improvement. I would like to have all over the country 'peaks of excellence' which would be a sort of beacon lights to all other institutions fired with ambition to attain the same high position."  
How far do you agree with this statement. ?

‘मालाए’ सम्पूर्ण शिक्षा प्रदान करती थीं और इन्हीं की प्रचुरता थी।<sup>1</sup> गुरुकुल एतासी आधुनिक व्यवस्था एक-अध्यापक शाला पद्धति के प्रतीक माने जाते हैं जहाँ एक-एक गुरु के कुछ छात्रवा आधुनिक में निवास करते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में केवल मात्र एक ही अध्यापक बालक का सर्वाङ्ग विकास कर शिक्षा उद्देश्यों की पूर्ति करता था। डा० भत्नेकर के शब्दों में, “ईश्वर-भक्ति तथा सामरिकता की भावना, चरित्र-निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता, सामाजिक कुशलता की अभिवृद्धि और राष्ट्रीय संस्कृति की सुरक्षा और प्रचार प्राचीन भारतीय शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य और आदर्श थे।”<sup>1</sup> इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति एक ही अध्यापक/गुरु करता था। एक-अध्यापक शाला द्वारा विद्यार्जन और वैदिक आदर्शों की प्राप्ति, बालक का सर्वाङ्गीण विकास, ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन, छात्रों में अश्वत्थी आदर्शों का निर्माण आदि इन शालाओं की विशेषता थी।

प्राचीन भारत में एक-अध्यापक शालाओं के अस्तित्व के मुख्यतः निम्न-लिखित कारण थे—

1. छात्रों की संख्या इतनी कम थी कि एक ही अध्यापक शैक्षिक कार्यों के लिए पर्याप्त था।
2. छात्र एवम् अध्यापक के सम्बन्ध बनानुक्रम से निश्चित परिवारों के बालक ही शिक्षा प्राप्त करते थे और इन परिवारों का गुरु परिवारों से पूर्व सम्बन्ध होता था। इस प्रकार गुरु सम्बन्धित परिवारों में श्रद्धा का पात्र होता था और इसी कारण उस परिवार के बालकों की शिक्षा का उत्तरदायित्व भी उसी पर होता था।
3. प्राचीन शिक्षा पद्धति में अध्यापक-छात्र सम्बन्धों का विशेष स्थान था और यह सभी सम्भव था जबकि गुरु और शिष्य के सम्बन्ध बनित हों।

—J. P. Naik

2. Infusion of a spirit of piety and righteousness, formation of character, development of personality, inculcation of civic and social duties, promotion of social efficiency and preservation and spread of national culture may be described as the chief aims and ideals of ancient Indian education.

A. S. Altekar, *Education in Ancient India*,



में प्राथमिक कठिनाइयों के कारण दूसरे अध्यापक का प्रावधान कठिन है परन्तु जिन गाँवों में एक-अध्यापक प्राथमिक शाला है इसकी अपेक्षा एक भी शाला न हो तो उचित है। इसीलिए हम सिफारिश करते हैं कि जहाँ तक सम्भव हो वहाँ केन्द्रीय शालाओं की स्थापना की जाये और 'एक अध्यापक शाला' को उससे सम्बन्धित शालाओं (Branch Schools) में परिवर्तित कर दिया जाये।<sup>1</sup>

संक्षेप में अंग्रेजी के अन्तर्गत एक-अध्यापक शाला की निम्नलिखित स्थिति थी—

- \* 1813 के एक्ट के अनुसार ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने कुछ प्राथमिक शालाओं की स्थापना की जिनमें एक ही अध्यापक की व्यवस्था थी। यह व्यवस्था 1855 तक उत्तरोत्तर बढ़ती रही।
- \* 1855-1921 के समय में एक-अध्यापक शाला की गति मन्द पड़ गई क्योंकि छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई थी।
- \* 1921-35 का समय हम प्रकार का था जिसमें एक-अध्यापक व्यवस्था की प्रालोचना की गई। हर्टाग कमेटी (1924) ने इस व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश की जिसके परिणामस्वरूप अनेकों गाँवों और सहरो में एक-अध्यापक शालाएँ समाप्त कर दी गईं। यह अंग्रेजों की भारतीयों के प्रति उपेक्षित व्यवहार की नीति थी जिसकी पूर्ति उन्होंने भारतीयों को शिक्षा से वंचित करने अभिनाया से की।

1. We entirely hold that no primary teachers. Unless the one teacher and can be converted into a branch school consisting of one or two classes only, it is better closed for realising that financial of a second teacher that minimum number on the point of view of economical administration is about a hundred, whereas the average number attending each primary school at the end of 1925-26 was only 43. But nothing is to be gained by failure to face the fact that a village which has a primary school with only one teacher might almost as well be without a school at all. We, therefore, recommend that, wherever possible, the policy of establishing 'central' schools and of converting 'single-teacher' schools into 'branch' schools should be adopted.

—Royal Commission on Agriculture, 1926

पताओं में एक प्रमुख विशेषता यह भी थी उस समय एक-प्रध्यापक शालाएँ  
जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों और आदर्शों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जाता था।

## 2. मध्यकाल में एक-प्रध्यापक शालाएँ Single Teacher Schools in Medieval Period

मध्यकालीन शिक्षा की व्यवस्था में भी एक-प्रध्यापक शालाओं की प्रचुरता थी। इस्लामी शिक्षा में मकतबों की व्यवस्था थी, मकतबों में मुख्यतः एक ही प्रध्यापक होता था। वहाँ बालकों को कुरान की भाषनों को कठस्थ कराया जाता था जो कि मुसलमान के लिये आवश्यक समझे जाते थे। मकतबों के प्रतिरि लानकाह और दरगाह भी होते थे। लानकाह और दरगाह के बनाने वाले ए मौलवी की नियुक्ति कर देते थे तथा एक मौलवी बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करता था।

प्राचीन शिक्षा की भाँति मध्यकाल में भी शिक्षक और शिष्य के सम्बन्ध थड़ापूर्ण थे। परन्तु शर्तें कर्त, इन सम्बन्धों में कटुता आती गई क्योंकि युव मति का आवश्यक गोण होता चला गया। इसके अनेकों कारण थे परन्तु उनमें से एक यह था कि प्रध्यापक का शिष्य के प्रति कठोर व्यवहार हो गया था जिसके परिणाम- रूप प्रेम के स्थान पर भय का आतंक हो गया था। इसके प्रतिरिक्त छात्रों का स्वरूप बढ़ने लगी थी और प्रध्यापक की सत्ता केवल एक ही थी।

## सर्वेजी काल में एक-प्रध्यापक शालाएँ Single-Teacher Schools in British Period

ब्रिटिश शासन काल में भी एक-प्रध्यापक शालाएँ थीं। 1835-36 में बिहार के अंग्लिकन प्राय सभी शालाओं में एक ही प्रध्यापक की व्यव- स्था के लक्षों में प्रशासन में प्रत्येक गाँव के अंग्लिकन एक प्राथमिक शाला की स्था की सत्ता बहुत कम थी।

1921-47 का समय इन प्रकार का था जबकि शाला में एक-प्रध्यापक की प्राप्ति की गई। राज्य धारोव ने इनके सम्बन्ध में मान विचार लिहम शिक्षा प्रविष्टियों के इन मन से पूर्ण सहमत हैं कि यदि भी उन समय तक सुधार का ये कार्य नहीं कर सकी जब तक कि शाला न हो। — हम यह स्वीकार करते हैं कि प्राथमिक शालाओं

पढ़ने के लिए दूर न जाना पड़े। इसी कारण स्वतन्त्रता प्राप्त के तेरह वर्षों के पश्चात् इन शालाओं की प्रतिशत संख्या में दुगुनी वृद्धि हुई। 1950-51 में प्राथमिक शालाओं में 33 प्रतिशत एक-प्राध्यापक शालाएँ थीं। 1960-61 में इन शालाओं की प्रतिशत संख्या कुल प्राथमिक शालाओं की संख्या की 43 प्रतिशत थी। तालिका न० 4-1 में इन शालाओं की उत्तरोत्तर वृद्धि की बताया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि ये शालाएँ प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में महावर्ण्य स्थान रखती हैं।

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता के पश्चात् हमारे देश में एक प्राध्यापक व्यवस्था की संख्या में वृद्धि हुई है। संसार के अन्य प्रगतिशील देशों में भी इस व्यवस्था को विकसित किया गया है। यह व्यवस्था उन देशों के लिए बहुत आवश्यक है जहाँ गाँवों की संख्या अधिक है। हमारा देश भी कृषि प्रधान है अतः यह नितान्त आवश्यक है कि इस व्यवस्था को और भी गुणात्मक बनाया जाये और अमेरिका, आस्ट्रेलिया आदि देशों की एक-प्राध्यापक शाला व्यवस्था का अध्ययन कर कुछ आवश्यक कदम उठाये जायें। श्री जे. पी. नाटक के शब्दों में यह बड़ा खेद का विषय है कि हम हमेशा से इंग्लैंड को आदर्श मानकर उसका अनुकरण करते आये हैं। हम सामान्य रूप से ग्रामीण शिक्षा की समस्या को तथा विशिष्ट रूप से एक-प्राध्यापक शालाओं की समस्या को जानबूझ कर उपेक्षित करते रहे हैं और इसका कारण यही है कि इंग्लैंड में इन व्यवस्था की कोई महत्ता नहीं है क्योंकि वह एक शहरी देश है। अब वे सम्बन्ध जिनके कारण हम संयुक्त थे, वे प्रायः टूट चुके हैं, अब हमारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध होना चाहिए और संसार के प्रत्येक भाग की नमूने के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यदि यह किया गया और यदि हम अमेरिका, आस्ट्रेलिया और स्वीडन आदि देशों की शिक्षा व्यवस्था में यह देखने का प्रयत्न करें कि एक-प्राध्यापक शालाओं को किस प्रकार विकसित किया गया है तथा हम किस प्रकार इस व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो सकती है।<sup>1</sup>

1 'It is a pity that, throughout the past we have followed England as the only model. The problem of rural education in general and of single-teacher school in particular have, therefore been ignored because they have not much significance in an urban country like the United Kingdom. Now that the ties which linked us exclusively to England are broken, we must cultivate wider international contacts and seek our models in every part of the globe. If this is done and we study closely what countries like U.S.A., Australia or Sweden are doing to improve their single-teacher schools, the first step in raising the quality of instruction in our small schools will have been taken.'

J. P. Naik, *Single Teacher School*, p. 271



“ नई नयी भारतीयों से प्राप्ति पाई, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की म  
की। 1937 में ब्रिटेन में-विप्लव के बाद में तथा बाद में  
परिणामस्वरूप एक-अध्यापक शालाओं को विकसित किया गया। 194  
तक इन शालाओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई।

#### 4.02 स्वतन्त्रता के पश्चात् एक-अध्यापक शालाएँ Single Teacher Schools After Independence

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इन शालाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।  
इसका एक मात्र कारण यह है कि प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक बनाने के लिए  
यह नितांत आवश्यक है कि प्रत्येक बच्चे को उसके घर के समीप शिक्षा सुविधाएँ  
प्राप्त हो सकें। अतः शिक्षा सुविधाओं और सार्वजनिकता की दृष्टि से एक-  
अध्यापक शाला का प्रावधान आवश्यक है। इसके अनिश्चित बाधोप  
यह बहुत जरूरी है कि प्रत्येक गाँव में प्राथमिक शालाएँ हों जिससे बालकों को  
शालिक न० 4.1

#### एक-अध्यापक शालाएँ

वर्ष	संख्या	पिछले वर्ष से बढ़ी हुई प्रतिशत संख्या
1960-51	68,841	11
1951-52	71,361	73
1952-53	75,214	51
1953-54	86,031	14.4
1954-55	1,01,342	17.8
1955-56	1,11,220	9.7
1956-57	1,16,272	4.5
1957-58	1,23,248	6.0
1958-59	1,26,238	2.4
1959-60	1,58,943	0.8

### (3) अध्यापकों के स्थानान्तरण की समस्या

#### Problem of Teachers' Transfers

यदि इन शालाओं में अध्यापकों का स्थानान्तरण हो जाता है तो वे इस दण्ड के रूप में समझते हैं। अध्यापकों का दण्ड रूप में समझना कोई अनुचित भी नहीं है क्योंकि सहायक निता निरीक्षकों का व्यवहार इन शालाओं के प्रति भी इसी प्रकार का होता है कि इन शालाओं में उन्हीं अध्यापकों को भेजा जाये जिनकी कुछ शिकायतें हों।

यदि शिक्षा अधिकारियों का व्यवहार इसी प्रकार का रहा और इन शालाओं के स्थानान्तरण सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त समग्रदृष्टि से तो समस्या का समाधान सम्भव नहीं। अतः यह आवश्यक है कि जिन अध्यापकों का स्थानान्तर इन शालाओं में हो उन्हें प्रतिरिक्त पनराजि दी जाय। इससे अध्यापकों में इन शालाओं के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा और शिक्षा निरीक्षकों के परिवर्तित व्यवहार में भय कम होगा।

### (4) अवकाश प्राप्त करने की समस्या

#### Problem of Grant of Leave

जिस शाला में एक ही अध्यापक हो और किन्हीं कारणोंवश वह अवकाश ले तो उस शाला में शिक्षण कार्य कैसे सम्भव हो सकता है? प्रायः ऐसा देखा गया है कि परिस्थितियों में एक-अध्यापक जाम्पाएँ बन्द पड़ी रहती हैं जिनके परिणामस्वरूप इन शालाओं के प्रति असमभावक उदासीन हो जाते हैं। इस समस्या का समाधान के लिये निम्नलिखित गुणाव कार्यान्वित किये जा सकते हैं—

- यदि अध्यापक कुछ दिनों के लिए अवकाश पर जाये तो कक्षा का मानिटर शिक्षण कार्य को देखे।
- यदि अध्यापक अधिक दिनों के लिये अवकाश पर जाये तो पास के बड़े प्राथमिक शाला के प्रधानाध्यापक को सूचित करे और वहाँ से अन्य अध्यापक को भेजा जाये।
- कुछ अध्यापकों की नियुक्ति केवल इसी लिए की जाये जिससे वे सम्बन्धित क्षेत्रों के एक अध्यापक शालाओं में अवकाश की स्थितियों में कार्य कर सकें। यद्यपि इस विधि को कार्य रूप में परिणित किया गया है जिससे इन शालाओं को 20 समूहों में विभाजित करके एक अनिश्चित अध्यापक की नियुक्ति द्वारा अवकाश पर जाने वाले अध्यापकों की पूर्ति की गई।

### (5) समय तालिखी की समस्या

#### Problem of Time Table

शाला में एक अध्यापक के रहने से यह समस्या सर्वत्र रहती है कि वह समय कक्षाओं की किस प्रकार के व्यस्त रह सके। इसके लिये आवश्यक है कि समय



सांख्यिक नं० 42

प्राथमिक शालाओं/बच्चों में अध्यापकों द्वारा पढ़ाई खाने वाली कक्षाओं का वर्गीकरण<sup>1</sup>

राज्य	एक कक्षा	दो कक्षाएँ	तीन कक्षाएँ	चार कक्षाएँ	पाँच कक्षाएँ	योग
	%	%	%	%	%	%
झारख प्रदेश	35.9	27.7	16.9	4.5	15.0	100.0
केरल	83.5	14.1	0.6	1.8	...	100.0
मध्य प्रदेश	30.5	26.1	17.4	8.5	17.5	100.0
मैसूर	50.9	21.4	3.7	24.7	...	100.0
उड़ीसा	43.0	29.6	26.2	0.7	0.5	100.0
पंजाब	46.4	26.9	14.8	1.1	10.8	100.0
राजस्थान	10.1	20.8	26.0	13.6	24.3	100.0
उत्तर-प्रदेश	36.5	35.9	19.8	2.5	5.6	100.0
योग	43.7	26.8	14.2	8.4	8.1	100.0

where one teacher/teachers one class is very small. More than half of our teachers, therefore, have to teach more than one class at a time. In a situation of this type, research in multiple-class teaching is badly needed, and training institutions have to make a special effort in orientating teachers to the special techniques that have to be used under such conditions.

*Report of the Education Commission, 1964-66, p. 235.*

1. The information is based on statistics collected from districts in 3 states.



प्रभावशाली निदा प्रदान करने में समर्थ हो सकें। इसके लिये निम्नलिखित कदमों को ध्यान में रख कर अनुसन्धान किये जा सकते हैं —

- अन्य देशों जैसे—आस्ट्रेलिया, अमेरिका और स्वीडन में एक अध्यापक शालाओं का प्रशासन।
- अन्य देशों और भारतीय एक अध्यापक शालाओं का सुलनात्मक अध्ययन।
- एक-अध्यापक शाला की समस्याओं का समाधान।
- एक-अध्यापक शालाओं में कियारमक शिक्षण सम्पादन।

अंत में हम यह कह सकते हैं कि इन शालाओं के कार्यों को प्रभावशाली बनाना अत्यन्त आवश्यक है। इन शालाओं के दोषों का दृष्टिपात कर उन्हें दूर करने चाहिए क्योंकि ये शालाएँ राष्ट्र के भावी नागरिकों का निर्माण कर रही हैं और सम्पूर्ण देश की प्राथमिक शालाओं में ये शालाएँ 40% हैं।

---

अतः हम तथा मैं यह धारणा आवश्यक है कि जिससे विधियों पर नवीन अनुसंधान किये जायें और इन शालाओं में पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण विद्यालयों से पृथक् प्रवृत्त किया जावे तथा शिष्ट विधियों से परिचिन कराया जावे जिससे इन शालाओं द्वारा शैक्षिक उत्पादन सन्तोषप्रद हो सके ।

## (7) पाठ्यक्रम की समस्या

### Problem of Curriculum

म.ना में एक ही अध्यापक होने के कारण यह समस्या सर्वत्र समीचीन है कि एक-अध्यापक शाला का पाठ्यक्रम क्या हो ? यदि एक-अध्यापक शाला का पाठ्यक्रम वही रखा जाये जो सामान्य शालाओं में होता है और जहाँ एक से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं तो एक अध्यापक द्वारा कार्य सम्पन्न होना मुश्किल है । यदि पाठ्यक्रम को परिवर्तित किया जाये तो दोनों शालाओं के शैक्षिक स्तर में अन्तर आ जायेगा जो प्रायः रक्षक सिद्धान्तों के प्रतिकूल होगा । दोनों स्थितियों में प्रजातांत्रिक प्रतिष्ठा से यही उचित है कि दोनों शालाओं का शैक्षिक स्तर तो समान होना चाहिए । यदि हम समान पाठ्यक्रम को स्वीकार करते हैं तो एक अध्यापक शालाओं में उत्तरदायित्व बढ़ जाता है क्योंकि एक अध्यापक को निश्चित समयावधि में दृष्ट कार्य करना होगा ।

यदि ऐसी स्थिति में यही उचित है कि पाठ्यक्रम की सामान्य रूप रेखा को शालाएँ स्वीकार करें और अध्यापक को यह पूर्ण स्वतन्त्रता हो कि पाठ्यक्रम को वह अवधि विवेक से समस्त कार्य समाप्त कर लेगा । इसके लिए अधिक हो यदि इन शालाओं की कक्षाओं का शिफ्टों में विभाजित कर दिया जाये कक्षाओं को पहले तीन घण्टे देय किया जाये और अन्य दो कक्षाओं को बाद घण्टों में देय लिया जाये । इससे इन शालाओं का स्तर सामान्य शालाओं के समान होगा । निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार समस्त कार्य सम्पन्न हो सकेगा ।

### अनुसंधान की आवश्यकता

#### Need for Research

शैक्षिक मनन वर्षों के साधारण पर यह बहुत विनाशकारी आवश्यकता बन गया है । प्रथम, गठन, शिष्ट विधियों, इनकी सफलता यदि पर अनुसंधान की आवश्यकता है । अब हम पूर्ण रूप से यह हैं कि देश की प्राथमिक एवं माध्यमिक स्थिति को देखते हुए आवश्यक है और इनके बिना कार्य नहीं चल सकेगा तब हमारे शिक्षण प्रणाली को सम्बन्धित समस्याओं का समाधान निरन्तर अनुसंधान करें जिससे हमें देना है ।

प्रभावशाली शिक्षा प्रदान करने में समर्थ हो सकें। इसके लिये निम्नलिखित कदमों को ध्यान में रख कर अनुसन्धान किये जा सकते हैं:—

- अन्य देशों जैसे—घास्ट्रुनिया, अमेरिका और स्वीडन में एक अध्यापक शालाओं का प्रशासन।
- अन्य देशों और भारतीय एक अध्यापक शालाओं का तुलनात्मक अध्ययन।
- एक-अध्यापक शाला की समस्याओं का समाधान।
- एक-अध्यापक शालाओं में कियारमक शिक्षण अभ्यास।

अतः मैं हम यह कह सकते हैं कि इन शालाओं के कार्यों को प्रभावशाली बनाना अत्यन्त आवश्यक है। इन शालाओं के दोषों का दृष्टिपात कर उन्हें दूर करने चाहिए क्योंकि ये शालाएँ राष्ट्र के भावी नागरिकों का निर्माण कर रही हैं और सम्पूर्ण देश की प्राथमिक शालाओं में ये शालाएँ 40% हैं।



## ग्रन्थ - सूची Bibliography

1. Govt. of India,  
*Handbook of Suggestions for Teachers in Small Rural Schools*  
Manager of Publications, Delhi, 1954.
2. J. P. Naik,  
*The Single - Teacher Schools*, 1963.
3. Mukerji, S. N.  
*Education in India To-day and Tomorrow*, Acharya  
Depot, Baroda, 1964.
4. N. C. E. R. T.,  
*Second Year Book*, 1964.
5. J. M. Sen  
*History of Elementary Education in India*, Book I  
Calcutta, 1962.

## अध्याय पाँच

### Chapter Fifth

#### आध्यमिक शिक्षा का ऐतिहासिक पर्यावलोकन

#### *Historical Survey of Secondary Education*

#### अध्ययन बिन्दु

#### Learning Points

- 5.01 ईसाई मिशनरी के शैक्षिक प्रयासों से 1853 तक  
From Educational Efforts of Christian Missionaries to 1853
- 5.02 सन् 1854 के वुड चोपला पत्र से सन् 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट तक  
From Wood's Despatch of 1854 To Indian Universities Act of 1904
  - (1) वुड का चोपला-पत्र (1854)
  - (2) भारतीय शिक्षा आयोग (1882)
  - (3) सरकारी शिक्षा नीति (1904)सन् 1882 से 1902 तक माध्यमिक शिक्षा का विकास
- 5.03 सन् 1905 से 1921 तक  
From 1905 To 1921
  - (1) शिक्षा-नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव (1913)
  - (2) कमलता विश्वविद्यालय आयोग (1917)
- 5.04 सन् 1922 से 1937 ई० तक  
From 1922 To 1937
  - (1) हर्तग समिति (1929)
  - (2) एक्ट-वुड रिपोर्ट (1936-37)
- 5.05 सन् 1937 से 1947 तक  
From 1937 To 1947  
सार्जेंट रिपोर्ट (1944)
- 5.06 सन् 1852 से 1947 तक माध्यमिक शिक्षा का विकास  
Development of Secondary Education From 1852 To 1947

.. आरम्भ के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा का विकास  
Development of Secondary Education After Independence

## माध्यमिक शिक्षा का ऐतिहासिक पर्यावलोकन

### HISTORICAL SURVEY OF SECONDARY EDUCATION

सम्पूर्ण शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा का विशेष महत्व है। माध्यमिक शिक्षा देश के राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि इस शिक्षा से राष्ट्र के राष्ट्र-सदस्य निर्धारित होते हैं। हमारे देश की समृद्धि, सफलता और प्रशासनिक विकास माध्यमिक शिक्षा पर ही अवलम्बित करता है। माध्यमिक स्तर के परचाए ही व्यक्ति अपने भावी जीवन का स्वप्न साकार करता है। आज माध्यमिक शालाओं में पढ़ रहे बालक कल के भावी नागरिक होंगे जिनके कर्मों पर देश का भावी भार होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि माध्यमिक शिक्षा का भारत में अत्यधिक महत्व है। सम्पूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में माध्यमिक शिक्षा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। कि यह प्राथमिक और उच्च शिक्षा के बीच की कड़ी है। इससे पूर्व कि हम माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं पर विचार करें, उससे पहले यह उत्तम होगा 5.01 ईसाई मिशनरों के शैक्षिक प्रयासों से 1853 तक

*From Education Efforts of Christian Missionaries To 1853*

यदि हम वर्तमान माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप का धारम्भ देखने का प्रयास इसका स्रोत ईसाई मिशनरियों के शैक्षिक प्रयासों से धारम्भ होता है। 1830 के आता पत्र के अनुसार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्राप्त हुई और उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार हेतु शिक्षा व्यवस्था की

पर ध्यान दिया। सन् 1830 ई० में स्काटलैण्ड निवासी थो अलक्जेंडर डफ ने भारतीयों को मोक्ष दिलाने का मार्ग 'पश्चिम और वाइबिल' बताया। उसने भ्रष्टेजी शिष्टा का माध्यम बनाया और कलकत्ता में एक चर्च की स्थापना की। इससे वर्ष 1813 से 1823 तक मिशनरियों ने अनेक शिष्टा संस्थाओं की स्थापना कर दी थी जिनमें अधिकांश प्राथमिक शिक्षा से और कुछ संस्थाओं में माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा भी दी जाती थी। माध्यमिक शिक्षा का जो वर्तमान स्वरूप में प्राप्त दिखाई देता है उसका श्रेय इन्हीं मिशनरियों को है। इस समय उक्त प्राथमिक-शालाओं का नामकरण नहीं हुआ था क्योंकि कुछ माध्यमिक शालाओं की सजा दी गई और कुछों को 'कालिज' की। परन्तु इतना अवश्य है कि कुछ शालाओं में माध्यमिक स्तर की शिक्षा दी जाती थी।

1. मे सबसे पहले मिशनर 'सीरामपुर कालेज' की स्थापना की, 10 वर्नाक्यूलर स्कूल खोले गये। 1820 में धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों आगरा, मेरठ, जौनपुर आदि स्थानों में स्कूलों की स्थापना की गई, जिसके परिणामस्वरूप मिशनरियों का आस फैल गया और

नवीन मान्योनन धारण्य हो बना कीर दूधे र टिप्प कीर सगुनि को सगिा किया जाने मगा । इन प्रयासों के अनुसार 1852 तक सम्पूर्ण भारत में बतोंड म येजी शासाएँ स्थापित हो चुकी थी ।

5.02 सन् 1854 के वुड घोषणा पत्र से सन् 1884 के भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट तक

*From Wood's Despatch of 1854 To Indian Universities Act of 1884*

1854 से 1904 तक माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई । भारत में शैक्षिक प्रगति की दृष्टि से ये पचास बरें अत्यन्त महत्वपूर्ण थे । इन वर्षों में तीन महत्वपूर्ण कार्य हुए जो निम्नलिखित हैं—

- (1) वुड का घोषणा पत्र (1854)
- (2) भारतीय शिक्षा आयोग (1882)
- (3) सरकारी शिक्षा बोर्ड (1904)

शिक्षा की दृष्टि से यह अधिक उदात्त होता यदि माध्यमिक शिक्षा का ऐतिहासिक पर्यावलोकन उपरोक्त तीन महत्वपूर्ण कार्यों की पृष्ठभूमि में देखा जाये ।

- (1) वुड का घोषणा-पत्र (1854)
- Wood's Despatch (1854)*

19 जुलाई सन् 1854 में वुड का महत्वपूर्ण घोषणा-पत्र जारी हुआ । भारतीय शिक्षा के इतिहास में इस घोषणा पत्र द्वारा एक नवीन दिशा मिली जिसके फलस्वरूप भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विभिन्न रूप से सुरूरात हुआ । इस घोषणा-पत्र द्वारा माध्यमिक शिक्षा में निम्नलिखित परिवर्तन आये—

- (1) सर्वप्रथम यह स्वीकार किया गया कि भारतीयों को

- (3) शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की स्वीकार किया गया क्योंकि भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों का अभाव था। शिक्षा के माध्यम के संबंध में घोषणा-पत्र के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया कि 'हमारी यह इच्छा नहीं है कि स्थानीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को जबर दस्ती घोषा जाये। परन्तु उच्च स्तरीय शिक्षा अंग्रेजी द्वारा सम्भव है। माध्यम के सम्बन्ध में निर्णय किया गया कि 'यूरोपीय ज्ञान के लिए ~~the~~ अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं की साथ साथ शिक्षा माध्यम के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, और यह हमारी इच्छा है कि ये भाषाएँ समान रूप से भारतीय भाषाओं में उन्नति करें।' <sup>1</sup>
- (4) घोषणा-पत्र में शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा गया 'हमें स्पष्ट रूप से घोषणा करनी चाहिए कि हम भारत में जिस शिक्षा प्रसार की अभिलाषा करते हैं उसका उद्देश्य यूरोपीय उच्च कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य अथवा संक्षेप में यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है <sup>2</sup>।'
- (5) शिक्षा के अधिकारिक प्रसार हेतु अनुदान प्रथा को प्रवर्धन दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने इस प्रथा का प्रारम्भ इसलिए किया क्योंकि इंग्लैंड में यह सफलता प्राप्त कर चुकी थी। घोषणा-पत्र में कहा गया कि हमने भारत में अनुदान-प्रथा को प्रारम्भ करने का निश्चय किया है। इंग्लैंड में इस पद्धति के सफलतापूर्वक क्रियान्वन होने ~~the~~ आधार पर हमें पूर्ण विश्वास है कि राज्य के अतिरिक्त स्थानीय साधनों का सहयोग प्राप्त कर शिक्षा का प्रसार राज्य ~~the~~ स्वयं

of the thought and labour of Europeans on the subject of every description and to extend the means of imparting this knowledge must be the object of any general system of education."

—Wood's Despatch, 1854.

1. We look to the English language and to the vernacular languages of India together as the media for the diffusion of European Knowledge, and it is our desire to see them cultivated together in all schools in India.

*Ibid*

2. We must emphatically declare that the education which we desire to see extended in India is that which has for its object the diffusion of the improved Arts, Science, Philosophy and Literature of Europe, in short of European knowledge.

*Ibid*

नवीन ग्रामोन्नतन प्रारम्भ हो गया और प्राचीन शिक्षा और संस्कृति का रक्षण करने लगा। इन प्रयासों के फलस्वरूप 1852 तक सम्पूर्ण भारत में 'अंग्रेजी शालाएँ' स्थापित हो चुकी थी।

5.02 सन् 1854 के बृहद् घोषणा पत्र से सन् 1804 के मां विश्वविद्यालय एक्ट तक

*From Wood's Despatch of 1854 To Indian Universities Act of 1904*

1854 से 1904 तक माध्यमिक शिक्षा के प्रसार में काफी प्रगति हुई। इस में शैक्षिक प्रगति की दृष्टि से ये पचास वर्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण थे। इन 50 वर्षों में महत्वपूर्ण कार्य हुए जो निम्नलिखित हैं—

- (1) बृहद् का घोषणा पत्र (1854)
- (2) भारतीय शिक्षा आयोग (1882)
- (3) सरकारी शिक्षा नीति (1904)

शिक्षा की दृष्टि से यह अधिक उपादेय होगा यदि माध्यमिक शिक्षा का विकास पर्याप्त होकर उपरोक्त तीन महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्णभूमि ले सके। बृहद् का घोषणा-पत्र (1854)

*Wood's Despatch (1854)*

19 जुलाई सन् 1854 में बृहद् का महत्वपूर्ण घोषणा-पत्र जारी हुआ। इस शिक्षा के इतिहास में इस घोषणा पत्र द्वारा एक नवीन शिक्षा विचार-प्रणाली का स्वरूप भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विधिवत रूप से स्थापित हुआ। इस पत्र द्वारा माध्यमिक शिक्षा में निम्नलिखित परिवर्तन आये—

- (1) सर्वप्रथम यह स्वीकार किया गया कि भारतीयों को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर है।
- (2) माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्राचीन ज्ञान और विज्ञान को उपयुक्त समझा गया और यूरोपीय ज्ञान, साहित्य एवं विज्ञान को भारत में प्रसारित करने की जरूरत अत्यन्त की गई। घोषणा पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया।

‘कि भारतीयों को योशरीय सेवाओं के कार्यों के परिचय कराया जाये और सामान्य शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि प्रत्येक विषय पर हुए यूरोपीय विचारों और व्यवस्था के भारतीयों को अद्यतन कराया जाये’।

शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को स्वीकार किया गया क्योंकि भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों का अभाव था। शिक्षा के माध्यम के संबंध में घोषणा-पत्र के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया कि 'हमारी यह इच्छा नहीं है कि स्थानीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को जबर दस्ती घोषा जाये। परन्तु उच्च स्तरीय शिक्षा अंग्रेजी द्वारा सम्भव है। माध्यम के सम्बन्ध में निर्णय किया गया कि 'यूरोपीय ज्ञान के लिए हम अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं को साथ साथ शिक्षा माध्यम के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, और यह हमारी इच्छा है कि ये भाषाएँ समान रूप से भारतीय शास्त्राओं में उन्नति करें।'<sup>1</sup>

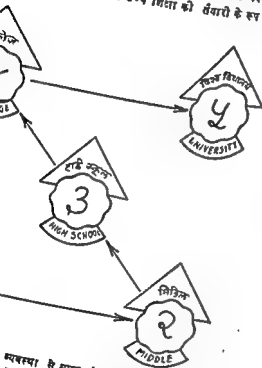
- 4) घोषणा-पत्र ने शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा गया 'हमें स्पष्ट रूप से घोषणा करनी चाहिए कि हम भारत में जिस शिक्षा प्रसार की अभिलाषा करते हैं उसका उद्देश्य यूरोपीय उच्च कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य अथवा संक्षेप में यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है।'<sup>2</sup>

- 5) शिक्षा के अधिकारिक प्रसार हेतु अनुदान प्रथा को प्रघष दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने इस प्रथा का प्रारम्भ इसलिए किया क्योंकि इंग्लैंड में यह सफलता प्राप्त कर चुकी थी। घोषणा-पत्र में कहा गया कि हमने भारत में अनुदान-प्रथा को प्रारम्भ करने का निश्चय किया है। इंग्लैंड में इस पद्धति के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन होने के आधार पर हमें 'पूर्ण आशा है कि राज्य के अतिरिक्त स्थानीय साधनों का सहयोग प्राप्त कर शिक्षा का प्रसार राज्य के सर्व

on the subject of *...*



...मिथा से घबिह हो लहेगा। अनुदान प्रवा से माध्म  
 मिथा प्रसार को बाधो सहायता मिलो।  
 यद्यपि बूढ़ के योगला-यत्र में माध्यमिक मिथा के सम्बन्ध में कोई प्रयः  
 न्यु गुभाय प्रागुन गही दिये गये तथापि माध्यमिक मिथा को धरन्त प्रेम्पः  
 इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि योगला-यत्र में कम विद्यार्थी  
 की गई थी। कमबद्ध मिथा (हाई स्कूल) को स्थान दिया गया था  
 नार से माध्यमिक मिथा को उच्च मिथा की तैयारी के रूप में स्वीकार



ब्यवस्था से स्पष्ट है कि हाई स्कूल (माध्यमिक  
 किया गया ये विद्यालय भाग की माध्यमिक शिक्षा  
 fore, resolved to adopt in India the  
 which has been carried out in the country  
 and we confidently anticipate by thus  
 resources in addition to contribute to  
 progress of education than  
 by government

के आदि स्वरूप हैं। उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि माध्यम शिक्षा मिडिल स्तर तथा कालेज स्तर के बीच की कड़ी थी। इसके प्रतिरिक्त जिस क्रमबद्ध शिक्षा योजना की व्यवस्था घोषणा-पत्र में की गई थी, वह आज भी विद्यमान है।

इस घोषणा-पत्र से भारत में अंग्रेजी का प्रसार बढ़ता गया और अंग्रेजी स्कूलों की संख्या में वृद्धि होती चली गई। यद्यपि सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार किया गया था कि अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में कोई भेद नहीं होगा तथापि स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाने लगी क्योंकि उच्च शिक्षा और विश्व विद्यालय शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही था। परिणामस्वरूप माध्यमिक शिक्षा में दोष धाने लगे जिनका कारण मातृ भाषा की उपेक्षा, अध्यापकों के प्रशिक्षण का अभावस्थित स्वरूप आदि था।

## (2) 1882 का भारतीय शिक्षा आयोग

### Indian Education Commission of 1882

लार्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की जिसके अध्यक्ष विलियम ह्यूटन थे। आयोग ने सम्पूर्ण भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर विचार किया परन्तु माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में विमनसिलित्त मुझाव दिए—

- (1) माध्यमिक शिक्षाओं की उच्च कक्षाओं की दो भागों में विभाजित किया जाये—एक विद्याविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा के रूप में हो, दूसरी अत्यधिक प्रियात्मक हो जो कि युवकों को व्यवसायिक और व्यवहारिक बना सके।<sup>1</sup>

यद्यपि आयोग ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किया परन्तु इन में कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया गया।

- (2) माध्यमिक शिक्षा के प्रसार हेतु यह सुझाव दिया गया कि अधिक से अधिक माध्यमिक विद्यालय खोले जायें और इसके लिए भारतीय जनता इस उत्तरदायित्व को संभाले। सरकार द्वारा अनुदान प्रणाली को स्वीकार किया जाये। परन्तु जिन स्थानों पर जनता स्कूल खोलने में असमर्थ हो वहाँ राजकीय स्कूल खोले जा सकते हैं। इन स्कूलों की संख्या जितने में एक से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- (3) सन् 1882 तक भारतवर्ष में केवल दो प्रशिक्षण विद्यालय थे। प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आयोग ने कुछ टोस सुझाव

1. "That in the upper classes of high schools there be two divisions - one leading to the Entrance Examination of Universities, the other of a more practical character, intended to fit youths for commercial or other non-literary pursuits."

दिये और यह भिन्न शिक्षा की कि प्रशिक्षण की समयावधि योजना के आधार पर होना चाहिए। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सुधार होना चाहिए।

- (4) माध्यमिक शिक्षा स्तर पर माध्यम के प्रश्न को छात्रों ने नहीं देखा परन्तु अत्यन्त रूप से अंग्रेजी की जड़ों को मजबूत अवश्य किया और विभिन्न स्तर पर भी अंग्रेजी का ज्ञान बांखतीय कर दिया।

1882 से 1902 तक माध्यमिक शिक्षा का विकास

उपरोक्त कार्यकाल में माध्यमिक शिक्षा का जो विकास हुआ वह ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। तालिका नं० 5.1 से यह स्पष्ट है कि माध्यमिक शिक्षा की संख्या में कुछ वृद्धि अवश्य हुई।

तालिका नं० 5.1

माध्यमिक शिक्षा का विकास (1882-1902)

1882	<div> <div>विद्यालयों की संख्या</div> <div>छात्रों की संख्या</div> <div>मैट्रिक पास विद्यार्थियों की संख्या</div> </div>	<div> <div>3,016</div> <div>2,14,077</div> <div>7,429</div> </div>	
1902	<div> <div>विद्यालयों की संख्या</div> <div>छात्रों की संख्या</div> <div>मैट्रिक पास विद्यार्थियों की संख्या</div> </div>	<div> <div>8,124</div> <div>6,22,868</div> <div>22,767</div> </div>	
1882-1902	<div> <div>प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या</div> <div>प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या</div> </div>	<div> <div>2</div> <div>6</div> </div>	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1902 में माध्यमिक शिक्षा का विकास तुलना में निम्न था। इन छात्रों पर यह भी बड़ा असर पड़ा है। कि विकास भी अवश्य हुआ।

शिक्षा नीति (1904)

Government Resolution on Educational Policy

इस नीति की शिक्षा की नीतियों का मान्य करना के बाद विशेष दिशा देने के निमित्त ने निर्धारित नहीं किया और 19 मार्च 1904 को एक अधिनियम को 21 मार्च, 1904 को लागू बन गया। इसने कोई संशोधन

हैं कि कर्जन ने भारतीय शिक्षा का वास्तविक स्वरूप देखने का प्रयास किया था और शिक्षा प्रसार हेतु सन्तोषप्रद कदम भी उठाये थे। प्रस्ताव में कहा गया था कि संख्यात्मक दृष्टि से जो कमियाँ आज की प्रणाली में हैं वे सर्वविदित हैं। पाँच गाँवों में से चार बिना शालाओं के हैं। चार सड़कों में से तीन बिना शिक्षा के ही विकसित होते हैं, और चालीस सड़कियों में से केवल एक सड़की किसी प्रकार की शाला में जाती है।<sup>1</sup> इन वक्तव्यों को देखकर हमें अपने देश की दयनीय दशा का आभास हो निश्चित होता है, परन्तु जो शिक्षा-नीति इस दयनीय दशा को ठीक करने के लिए अपनाई गई वह हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए बाने चलकर बिय बन गई और इसीलिए हमारे देशवासियों ने इस शिक्षा व्यवस्था का विरोध किया था। परन्तु फिर भी इस सरकारी शिक्षा-नीति ने माध्यमिक शिक्षा को प्रभावित किया जिसके कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित हैं—

- (1) माध्यमिक शालाओं के माय्यता प्राप्त सम्बन्धी नियमों को निर्धारित कर दिया गया जिससे व्याप्त दोषों को दूर करने में काफी सहायता मिली।
- (2) इस सरकारी प्रस्ताव से विश्वविद्यालयों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे शालाओं के माय्यता सम्बन्धी नियमों में वांछनीय परिवर्तन कर सकते हैं। इन नियमों के आधार पर अब केवल माय्यता प्राप्त शालाओं को ही मैट्रिक परीक्षा दिलाने का अधिकार था। कहने का तात्पर्य यह कि माध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालय के आधीन हो गई थी।
- (3) शालाओं में शुल्क की दर इतनी होनी चाहिए जिससे पड़ोसी विद्यालयों पर गलत प्रभाव न पड़े।
- (4) माध्यमिक शालाओं में प्रशिक्षण अध्यापकों को रखा जाये।
- (5) माध्यमिक शिक्षा को अधिक जीवनोपयोगी बनाने हेतु व्यावसायिक विषयों के शिक्षण की व्यवस्था हो।
- (6) हर एक जिले में एक सरकारी शाला हो।

1. The shortcomings of the present system in point of quantity are well known. Four out of five villages are without a school. Three boys out of four grow up without education, and only one girl in forty attends any kind of school.

*From 1905 To 1921*

From 1905 To 1921

20 वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही भारतवासियों के हृदय में राष्ट्रीय भावनाएँ गहरी हो गई थीं। लार्ड कर्जन की शिक्षा नीतियों ने भारतीयों के हृदय में शक्ति उत्पन्न कर दी थी। इस समय राष्ट्रीय चेतना अपनी चरम सीमा पर थी। राष्ट्रीय नेता यह अनुभव करने लगे थे कि ब्रिटिश सरकार भारत में शिक्षा का विकास नहीं चाहती। वास्तव में उस समय हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था अत्यन्त विकृत थी। जब 1906 में जापान की शिक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित एक प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ तो भारतीयों के हृदय में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हुई जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा गुहार हेतु भारतीय नेताओं द्वारा माँग होने लगी और अनुभव किया जाने लगा कि प्रचलित शिक्षा में राष्ट्रीय तत्वों की कमी है। महात्मा गांधी ने भारतीय शिक्षा के विदेशी स्वरूप के प्रति आवाज उठाई और धीरे-धीरे राष्ट्रीय धारमोक्षण उत्पन्न होना आता गया। एनी बेसेंट ने भारतीय शिक्षा के तद्देश्यता का अनुमान, बुद्धिमत्ता और संनिष्ठा होना चाहिए। इसमें भारतीयों को प्रयोग होते भी साम्प्रदायिक भी भावनाओं से परे हो।

बढ़ने का कारण यह है कि राष्ट्रीय धारमोक्षण का शिक्षा पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा और नेताओं ने यह माँग की कि भारतीय शिक्षा का अर्थ भारतीयता ही होना चाहिए जिसमें स्वदेश प्रेम की भावनाएँ हों, नवीन ज्ञान की प्राप्ति हो, न्याय व्यवस्था का बचावोपन स्थान हो और जीवनव्यवस्था शिक्षा हो।

प्रचलित शिक्षा नीति का अन्त विरोध करने के लिए अन्त में राष्ट्रीय धारमोक्षण करने के लिए मण्डल का निर्माण किया गया जिसके प्रमुख नेता श्रीमान्, सुप्रसिद्ध शिक्षा माय ईश्वर आदि थे। इन निर्माता ने अन्तरी प्रमुख धारमोक्षण और राष्ट्रीय धारमोक्षण से जोन जोन शिक्षा प्रसार हेतु एक योजना तैयारी की। परन्तु यह धारमोक्षण बहुत दिनों तक न चल सका। 1911 तक इसकी कल्पना ही नहीं की गई।

शिक्षा नीति निर्धारण की ओर गया और सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु निम्नलिखित आवश्यक कार्य किये—

### 1) शिक्षा-नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव (1913)

#### Resolution on Educational Policy (1913)

प्रस्ताव में माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी निम्नलिखित सिफारिशों की गई—

(1) शालाघों की न बढ़ाया जाये।

(2) शिक्षा के प्रसार हेतु मंद सरकारी शालाघों को अधिकधिकार  
जाये।

शालाघों में प्रशिक्षित अध्यापकों को रखा जाये।

गुणार किया जाये और मनुष्य प्रशिक्षण एवं विज्ञान आदि  
जाये।

क्रम में निश्चितता जाये।

छात्रावासों की व्यवस्था हो।

यह निश्चित है कि माध्यमिक शिक्षा का प्रसार के  
रहे परन्तु उन्हें वास्तविकता प्रदान नहीं की गई।

(1917)

100 (1917)

1917 को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग

डा. माइकेल सैंडलर थे। आयोग ने सत्तरह

1919 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

पर विस्तृत रूप से विचार किया क्योंकि

शिक्षा उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालय

यह अत्यन्त आवश्यक था कि माध्यमिक शिक्षा

के निम्नलिखित दोष बताए—

का गुणात्मक विकास नहीं है।

साधों में प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव है।

जीवनोपयोगी विषयों की कमी है।

शेखा लचीली है जिसके कारण अनेकों विद्यार्थी  
से बचि रह जाते हैं।

5.03 सन् 1905 से सन् 1921 तक

From 1905 to 1921

20 वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही भारतवासियों के हृदय में भावनाएँ गहरी हो गई थीं। साटें कर्जत वीं मिश्रा नीतिगों ने भारतीयों में जगता उत्पन्न कर दी थी। इस समय राष्ट्रीय चेतना अपनी परम सीमा राष्ट्रीय नेता यह अनुभव करने लग ये कि ब्रिटिश सरकार भारत में शिक्षा नहीं चाहती। भारत में उन समय हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था दयनीय थी। जब 1906 में जापान ने शिक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित एक प्रकाशित हुआ तो भारतीयों के हृदय में शिक्षा के प्रति दबि जाग्रत हुई परिणाम स्वरूप शिक्षा सुधार हेतु भारतीय नेताओं द्वारा मांग होने लगी अनुभव किया जाने लगा कि प्रचलित शिक्षा में राष्ट्रीय तत्त्वों की कमी है। शोध ने भारतीय शिक्षा के विदेशी स्वरूप के प्रति आकाश उठाई और भी राष्ट्रीय आन्दोलन उग्र होना जाता गया। एनी बेसेंट ने भारतीय शिक्षा स्वरूप के पक्ष में अपने विचार रखते हुए कहा कि भारतीय शिक्षा पर मा द्वारा नियन्त्रण, मौलिक योजना एवं कार्यान्वयन होना चाहिए। इनमें मा मादमी का समुदाय, बुद्धिमत्ता और नैतिकता होनी चाहिए जो भारतीय शिक्षा से छोट प्रोत होते भी साम्प्रदायिक भी माननाओं म परे हो।<sup>1</sup>

कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय आन्दोलन का शिक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा और नेताओं ने यह मांग की कि भारतीय शिक्षा का जन्म भारत से होना चाहिए जिसमें स्वदेश प्रेम की भावनाएँ हों, तथैव ज्ञान की प्राप्ति भारतीय भावनाओं का दबावोध्य स्थान हो और जीवनप्रयोगी शिक्षा हो।

प्रचलित शिक्षा नीति का प्रत्यक्ष विरोध करने के लिए बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करने के लिए संघठन का निर्माण किया गया जिसके प्रमुख नेता श्री बिहारी घोष, मुकुन्द रविन्द्र नाथ टैगोर आदि थे। इस समिति ने अपनी पृष्ठ शिक्षा नीति बनाई और राष्ट्रीय माननाओं में प्रोत-प्रोत शिक्षा प्रदान हेतु विस्तृत योजना तैयारी की। परन्तु यह आन्दोलन बहुत दिनों तक न चल सका और दिसम्बर 1911 तक इसकी गति बहुत धीमी पड़ गई। सरकार का ध्यान

1. It must be controlled by Indians, shaped by Indian carried on by Indians. It must hold up Indian ideas of devotion wisdom and morality, and must be permeated by Indian religious spirit rather than fed on the letter of creeps.

शिक्षा नीति निर्धारण की थी और गया और सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु निम्नलिखित आवश्यक कार्य किये—

## (1) शिक्षा-नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव (1913)

Government Resolution on Educational Policy (1913)

इस प्रस्ताव में माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी निम्नलिखित सिफारिशों की गई —

- सरकारी शालाओं की न बढ़ाया जाये ।
  - माध्यमिक शिक्षा के प्रसार हेतु सरकारी शालाओं की अधिकारिता प्रभावित प्रदान की जाये
  - माध्यमिक शालाओं में प्रशिक्षित अध्यापकों को रखा जाये ।
  - पाठ्यक्रम में सुधार किया जाये और मनुष्य प्रशिक्षण एवं विज्ञान प्रादि विषयों को सम्मिलित किया जाये ।
  - अध्यापकों के वेतन क्रम में निश्चितता पाये ।
  - छात्रों के विकास हेतु छात्रावासों की व्यवस्था हो ।
- उपरोक्त प्रस्तावों से यह निश्चित है कि माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार के लिखित प्रयास तो रहे परन्तु उन्हें वास्तविकता प्रदान नहीं की गई ।

## (2) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (1917)

Calcutta University Commission (1917)

सरकार ने 14 सितम्बर सन् 1917 को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की । इन आयोग के अध्यक्ष डा. माइकेल मैडलर थे । आयोग ने सत्तरह नाम तक भारत का भ्रमण किया और 1910 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । आयोग ने माध्यमिक शिक्षा पर विस्तृत रूप में विचार किया क्योंकि सदस्यों की यह भावना थी कि माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा एवम् विश्वविद्यालय शिक्षा की आधार जिन्या है अतः यह अत्यन्त आवश्यक था कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार किया जाये ।

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के निम्नलिखित दोष बताए—

- (1) माध्यमिक शिक्षा का गुणात्मक विकास नहीं है ।
- (2) माध्यमिक शालाओं में प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव है ।
- (3) पाठ्यक्रम में जीवनोपयोगी विषयों की कमी है ।
- (4) माध्यमिक शिक्षा खर्चीली है जिसके कारण अनेकों विद्यार्थी अधिक अवसरों से वंचित रह जाते हैं ।



(5) जालामों में सहायक सामग्रियों एवं दृश्य श्रव्य सामग्री का अभाव है।

(6) परीक्षा प्रणाली दूषित है।

उपरोक्त दोषों को स्पष्ट करते हुए आयोग ने माध्यमिक शिक्षा पर पुनर्विचार आवश्यक समझा और इसके लिए निम्नलिखित सुझाव दिये—

- (1) माध्यमिक शिक्षा के समुचित उपयोग हेतु वाठमक्रम व विभिन्नोद्देश्य कर देना आवश्यक है।
- (2) माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक विकास हेतु अधिक धन राशि निश्वसन की जाये।
- (3) इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालय से पुनर्गठन दिया जाये।
- (4) बी० ए० का कार्यकाल तीन वर्ष का कर दिया जाये।
- (5) हाई स्कूलों को इंटरमीडिएट कालेज कर दिया जाये।
- (6) माध्यमिक कक्षाओं तक भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाये और इंटरमीडिएट कक्षाओं में अंग्रेजी भाषा को समुचित स्थान दिया जाये।
- (7) सभी प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्थापना की जाये।
- (8) माध्यमिक जालामों में छात्रावास की व्यवस्था की जाये।

यदि हम ऊपरोंक्त दो महत्वपूर्ण वैशेषिक कारणों अर्थात् 1913 का शिक्षा-विचार सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव और 1917 का कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग वृष्टिभूमि में 1905 से 1921 तक के कार्यकाल में माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु तो यह निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि माध्यमिक जालामों की या में बृद्धि अवरुद्ध हुई।

इस कार्यकाल में माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के प्रश्न को लेकर भी मतभेद रहा। भारतीय भाषाओं में भारतीय भाषाओं के विकास हेतु अंग्रेजी भाषा को दोहराना एकदम निराकार तरीके से अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहित किया

(3) भारतीय भाषाओं का सभी प्रान्तों में समान न होने के कारण ।

(1) अंग्रेजी का अन्तर-प्रादेशिक स्वरूप होने के कारण ।

उपरोक्त कारणों से भारतीय भाषाएँ विकसित न हो सकीं और अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ता चला गया ।

5.04 सन् 1922 से 1937 ई० तक

From 1922 To 1937

सन् 1921 से द्वैत शासन की व्यवस्था की गई । प्रांतीय सरकारों के उत्तरदायित्वों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया—(1) संरक्षित विषय (2) हस्तान्तरित विषय । संरक्षित विषयों की देखभाल करना गवर्नर का उत्तरदायित्व था जो एक्जीक्यूटिव काउन्सिलरों की सहायता से कार्य करता था । हस्तान्तरित विषयों का उत्तरदायित्व भी गवर्नर पर था पर इन विषयों पर सम्बन्धित कार्य मन्त्रियों के परामर्श से होता था और ये सभी व्यवस्थापिका समारोहों के प्रति उत्तरदायी थे । शिक्षा का स्थान हस्तान्तरित विषयों में था जो भारतीय मन्त्रियों के अधिकार क्षेत्र में थी । परन्तु वित्त सम्बन्धी समस्त कार्यवाही अंग्रेज मन्त्रियों के हाथ में थी । ऐसी स्थिति में कठिनाइयों का होना स्वाभाविक ही था परन्तु फिर भी इस कार्यकाल में शिक्षा की काफी प्रगति हुई ।

इस कार्यकाल में भारतीय शिक्षा की समस्याओं का कुछ प्रतिवेदनों में परीक्षण किया गया जिनमें माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं की चर्चा की गई । इस काल में दो शैक्षिक कार्य हुए—

(1) हार्टग समिति (1929)

(2) ऐक्ट और बूड प्रतिवेदन (1936-37)

(1) हार्टग समिति (1929)

Hartog Committee (1929)

जैसा हम ऊपर कह चुके हैं कि ब्रिटिश भारत ने 1921 से दोहरे शासन प्रबन्ध की व्यवस्था की गई थी । द्वैत शासन प्रबन्ध में भारत की व्यवस्था बहुत बिगड़ गई थी जिसके कारण भारतीय जनता में असन्तोष होना स्वाभाविक था । भारतीयों को सन्तोष प्रदान करने के लिये ब्रिटिश पार्लियामेण्ट ने 8 नवम्बर 1927 को भारतीय व्यवस्था की जाँच हेतु साइमन कमिशन को नियुक्ति की । कमिशन ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की जाँच करना भी आवश्यक समझा क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा हेतु घनेकोई आन्दोलन हो रहे थे । अतः कमिशन के एक सदस्य सर फिलिप हार्टग (Sir Philip Hartog) को भारतीय शिक्षा की जाँच का कार्य दिया गया । इसी कारण यह समिति हार्टग समिति के नाम से प्रसिद्ध है । इस समिति ने सितम्बर

(5) शालाओं में सहायक माध्यमियों एवं दृश्य श्रव्य सामग्री व्यवस्था है ।

(6) परीक्षा प्रणाली द्रुवित है ।

उपरोक्त दोषों को स्पष्ट करने हुए भाषीय ने माध्यमिक शिक्षा पर विचार आवश्यक समझा और इसके लिए निम्नलिखित सुझाव दिये—

- (1) माध्यमिक शिक्षा के समुचित उपयोग हेतु पाठ्यक्रम विभिन्नीकरण कर देना आवश्यक है ।
- (2) माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक विकास हेतु अधिक धन का निश्चित की जाये ।
- (3) इण्टरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालय से वृत्तक दिया जाये ।
- (4) बी० ए० का कार्यकास तीन वर्ष का कर दिया जाये ।
- (5) हाई स्कूलों को इण्टरमीडिएट कालेज कर दिया जाये ।
- (6) माध्यमिक कक्षाओं तक भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाये और इण्टरमीडिएट कक्षाओं में अंग्रेजी भाषा को समुचित स्थान दिया जाये ।
- (7) सभी प्रांतीय में माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्थापना की जाये ।
- (8) माध्यमिक शालाओं में छात्रावास की व्यवस्था की जाये ।

यदि हम उपरोक्त दो महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यों अर्थात् 1913 का शिक्षा नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव और 1917 का कलकत्ता विश्वविद्यालय भाषीय की वृत्तभूमि में 1905 से 1921 तक के कार्यकाल में माध्यमिक शिक्षा के विकास की देखें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि माध्यमिक शालाओं की संख्या में वृद्धि अवश्य हुई ।

इस कार्यकाल में माध्यमिक  
द रहा । भारत

शिक्षा के माध्यम के प्रश्न को लेकर  
के विकास हेतु अपनी

- (4) शालाघों का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये निरीक्षकों की नियुक्ति की जाये।
- (5) व्यावसायिक शिक्षा की सामान्य शिक्षा का स्तर प्रदान किया जाये।
- (6) व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के लिये पृथक्-पृथक् शालाघों की व्यवस्था हो।
- (7) व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु जूनियर और सीनियर व्यावसायिक स्कूल खोले जायें। जूनियर व्यावसायिक शालाघों में मिडिल पाठ्यक्रमों को प्रवेश दिया जाये और सीनियर व्यावसायिक शालाघों में हायर मैकेनिकल पढ़ाई के बाद प्रवेश दिया जाये।

यदि 1922 से 1937 के बीच मसौदा में माध्यमिक शिक्षा का विकास देखा जाये तो निम्नलिखित चीकों से स्पष्ट हो जाता है जो तालिका न० 5.2 में प्रस्तुत किया गया है।

**तालिका नं० 5.2**  
**माध्यमिक शिक्षा का विकास 1921—1937**

	1921—22	1936—37
(अ) माध्यमिक प्राप्त माध्यमिक शालाघों की संख्या	7,530	13,056
(ब) माध्यमिक शालाघों में छात्रों के छात्रों की संख्या	11,06,803	22,87,872

उपरोक्त तालिका में प्रस्तुत चीकों से यह स्पष्ट होता है कि ईश शासन प्रणाली में राजनैतिक और सामाजिक संघर्षों के बावजूद भी माध्यमिक शिक्षा का विकास सन्तोषप्रद गति में हुआ। इसका एक मात्र अर्थ राष्ट्रीय शिक्षा मान्योत्तन की था। इसके अनतिरिक्त इस कार्यकाल में भारतीय भाषाओं की शिक्षा के माध्यम के रूप में स्मान मिला जो कि एक बहुत बड़ी सफलता थी।

5.05 सन् 1937 से सन् 1947 तक

From 1937 To 1947

इस कार्यकाल में शिक्षा की प्रगति तो हुई परन्तु वह उतनी नहीं थी। जितनी हमने पूर्व हुई थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि संसार में युद्ध की

1179 की कानून प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और भारतीय शिक्षा के सभी धर्मों पर विचार कर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये। भारतीय शिक्षा के माहिरों द्वारा निम्नलिखित थे—

- (1) मिडिल क्लासों का वास्तविक जीवनशैली नहीं है इसलिए वह आवश्यक है वास्तविक को जीवनशैली और व्यावहारिक बनाया जाये।
- (2) हाई स्कूल के वास्तविक को भी जीवनशैली बनाया जाये और सभी को औद्योगिक लक्ष्य व्यावहारिक विषयों का अध्ययन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।
- (3) हाई स्कूल के वास्तविक में 77 वैकल्पिक विषयों को स्थान दिया जाये जिसके आधार पर छात्र की रुचि प्रमाण हो।
- (4) मिडिल स्कूल को शिक्षा समाप्त होने पर करीब 40 व्यावहारिक हो और सभी विद्यार्थियों को विभिन्न उद्योगों एवं व्यवसायों की शिक्षा हेतु भेजा जाये।
- (5) माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक विकास हेतु सभी व्यावहारिक प्रशिक्षण विद्यालय लाने जायें।
- (6) व्यावहारिकों के तार में सुधार लाने के लिए उनके क्षेत्र में वृद्धि की जाये।
- (7) व्यावहारिकों के सेवा नियमों में सुधार किया जाये और नितिव अनुसंधान के अनुसार उनके कार्य दिया जाये। व्यावहारिकों के सेवा काल में उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षा का अनुभव होना चाहिए।

## (2) ऐबट-वुड रिपोर्ट (1936-37)

Abbott-Wood Report (1936-37)

केन्द्रीय शिक्षा समीक्षार बोर्ड सुझाव पर ऐबट जो कि हर्लैण्ड के शिक्षा बोर्ड के टेक्निकल शालाओं के भूतपूर्व चीफ निरीक्षक थे एच० एच० वुड जो कि हर्लैण्ड की शिक्षा बोर्ड के इंस्ट्रक्टर आफ इन्टेलेक्चुअल थे, भारत सरकार के निमन्त्रण पर भारत आये। इन दोनों महानुभावों ने 1937 में सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने निम्नलिखित सिफारिशों की—

- (1) अनिवार माध्यमिक कक्षाओं में अंग्रेजी के अध्ययन पर विशेष जोर न दिया जाये।
- (2) माध्यमिक स्तर तक भारतीय मायाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाये।
- (3) ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ की आवश्यकतानुसार शालाओं में शिक्षा दी जाये।

- (4) शालाघों का कार्य गुंजाऊ रूप से चलाने के लिये निरीक्षकों की नियुक्ति की जाये ।
- (5) व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा का स्तर प्रदान किया जाये ।
- (6) व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के लिये पृथक्-पृथक् शालाघों की व्यवस्था हो ।
- (7) व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु इन्वियर और सीनियर व्यावसायिक स्कूल खोले जायें । इन्वियर व्यावसायिक शालाघों में मिडिल पास बच्चों को प्रवेश दिया जाये और सीनियर व्यावसायिक शालाघों में हमार मैट्रिकरी बरता के बाद प्रवेश दिया जाये ।

यदि 1922 से 1937 के बीच संक्षेप में माध्यमिक शिक्षा का विकास देखा जाये तो निम्नलिखित आँकड़ों से स्पष्ट हो जाता है जो मानिस्तर न० 5.2 में प्रस्तुत किया गया है ।

**तालिका न० 5.2**  
**माध्यमिक शिक्षा का विकास 1921—1937**

	1921—22	1936—37
(अ) मान्यता प्राप्त माध्यमिक शालाघों की संख्या	7,530	13,056
(ब) माध्यमिक शालाघों में छात्रों के छात्रों की संख्या	11,06,803	22,87,812

उपरोक्त तालिका में प्रस्तुत आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि द्वितीय शासन प्रणाली में राजनैतिक और सामाजिक संघर्षों के बावजूद भी माध्यमिक शिक्षा का विकास संतोषप्रद गति से हुआ । इसका एक मात्र श्रेय राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन को या । इसके प्रतिरिक्त इस कार्यकाल में भारतीय भाषाघों की शिक्षा में माध्यम के रूप में स्थान मिला जो कि एक बहुत बड़ी सफलता थी ।

5 05 सन् 1937 से सन् 1947 तक

From 1937 To 1947

इस कार्यकाल में शिक्षा की प्रगति तो हुई परन्तु वह उतनी नहीं थी । जितनी हमने पूर्व हुई थी । इसका प्रमुख कारण यह था कि तत्काल में युद्ध की



माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित सुझावों के आधार पर यह कहा जा सकता है सार्जेंट रिपोर्ट राष्ट्रीय शिक्षा प्रवृत्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ।

इस काल में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति पर विह्वल दृष्टि डालें तो तालिका 5.3 से यह स्पष्ट होता है कि विकास की गति धीमी रही ।

#### तालिका नं० 5.3

#### माध्यमिक शिक्षा का विकास (1937—47)

प्रकरण	1937	1947
(अ) माध्यमिक शालाओं की संख्या	13,056	11,907
(ब) माध्यमिक शालाओं के छात्रों की संख्या	22,87,872	26,81,081

#### 5.06 सन् 1852 से 1947 तक माध्यमिक शिक्षा का विकास (एक दृष्टि)

#### Development of Secondary Education From 1852 To 1947 (A Look)

सन् 1852 से 1947 तक माध्यमिक शिक्षा का क्रमिक विकास तालिका 5.4 में दर्शाया गया है जिसमें यह स्पष्ट होता है ब्रिटिश भारत में माध्यमिक शिक्षा का सन्वयात्मक विकास तो हुआ परन्तु गुरुत्वात्मक नहीं । इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि ॥ प्रेसों ने भारतीय शिक्षा के विकास हेतु उपेक्षित दृष्टि अपनायी और जो कुछ भी विकास इन 95 वर्षों में हुआ वह भारतीय जनता की आगच्छता ॥ कारण था । ब्रिटिश सरकार यह कदापि नहीं चाहती थी कि भारतीय जनता शिक्षित हो और इसी कारण उसने दमनकारी नीति के द्वारा भारतीय जनता को रोपण किया जिसके फलस्वरूप भारत में अनिच्छा का जाल फैलता गया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारतीयों की बेबसी पर हसता रहा ।

#### 5.07 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा का विकास

#### Development of Secondary Education After Independence

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश के नेताओं का ध्यान माध्यमिक शिक्षा के संयोजन की ओर गया । माध्यमिक शिक्षा का विकास करने के लिए और



धमि प्राज्वलित हो चुकी थी। युद्ध के कारण मूल्यों में भारी रसका सबसे अधिक प्रभाव मध्यम वर्ग पर पड़ा जिसने शासकों में शासकों की सभा में बुझि न हो सकी। परिणाम के कारण छात्रों की सभा में हास हो गया।

जैसे-जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और भारतीय जीवन के विविध पक्षों में भारतीय शिक्षा पर भी रसका भार वाइतराय की प्रबन्ध-कारणी कौशल की पुनर्निर्माण सलाहकार सर जान साजेंड को युद्धोत्तर शिक्षा प्रस्तुत करने का आदेश दिया—

रिपोर्ट ) 1944

Sargent Report (1944)

सर जान साजेंड ने सन् 1944 में सम्बन्धित स्मृति पत्रकार बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन को भारतीय योजना या केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन। इस रिपोर्ट में भारतीय शिक्षा के समस्त पहलुओं का विशाल-द्वितीय शिक्षा-पद्धति की दृष्टि से इसका अत्यधिक महत्व है। इस रिपोर्ट में माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित निम्नलिखित दिये गये—

- (1) छात्रों के लिए हाईस्कूलों में प्रवेश पाने के लिए न्यूनतम 11 वर्ष निश्चित की गई।
- (2) निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था होनी चाहिए।
- (3) सामान्य और औद्योगिक आलाए प्रथक - में कुछ विषय समान होंगे जैसे मातृभाषा, गणित, विज्ञान, कृषि, शारीरिक शिक्षा।
- (4) हाईस्कूल कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम
- (5) अंग्रेजी का स्थान द्वितीय प्राथमिक विषय

1. Reconstruction Committee of Council.

2. Central Advisory Board of

3. Scheme of Post-War

4. Report of the Central

स आयोग की नियुक्ति विश्वविद्यालय शिक्षा की जांच करने के लिए की गई थी।  
परन्तु इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए भी कुछ सुझाव दिये और यह  
जाता कि हमारी सम्पूर्ण शिक्षा-पद्धति में माध्यमिक शिक्षा-पद्धति दोषपूर्ण है  
और उसके सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है।

#### (4) माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53)

**Secondary Education Commission (1952-53)**

केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड और साराबन्द समिति की सिफारिशों के  
आधार पर माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। आयोग ने समस्त  
माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन किया और उसके विकास हेतु अनेकों महत्वपूर्ण  
सुझाव दिये इस आयोग का विस्तृत विवेचन अगले अध्याय में किया जायेगा।

#### (5) भारत शिक्षा आयोग (1964-66)

**Indian Education Commission (1964-66)**

शिक्षा के सभी-अंशों पर विचार करने हेतु भारतीय सरकार ने 1964 ई०  
में एक नये शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर डी० एम०  
कोठारी थे। इस शिक्षा आयोग की नियुक्ति 14 जुलाई 1964 को गई। आयोग  
की नियुक्ति का सबसे बड़ा कारण यह था कि एक ऐसी राष्ट्रीय जीवन की मूलक  
हो। इस आयोग ने इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सभी शिक्षा स्तरों पर विचार प्रस्तुत  
किये हैं। माध्यमिक शिक्षा को प्रगट बनाने हेतु आयोग ने महत्वपूर्ण सुझाव  
दिये हैं। कोठारी आयोग की सिफारिशों को हमने सभी समस्याओं से सम्बन्धित  
किया है जिससे सामयिक विवेचन हो सके।

## ग्रन्थ - सूची

### Bibliography

1. एन्स, H.  
*A New Deal in Secondary Education*, Orient Longman,  
Bombay, 1957.
  2. Croxall, F.  
*The Foundation of Secondary Education*, Melbourne, Australia  
(Council for Educational Research) 1961.
  3. D'Saiz, A. A.  
*History of Education in India and Around Orient Longman*,  
1958.
  4. डू, K. N.  
*Secondary Education*, The Indian Press Publications P. Ltd.,  
1960.
  5. Kabb, H.  
*Indian Philosophy of Education*, Asia Publishing House,  
Bombay, 1964.
  6. Kaejel, I. L.  
*The New Era in Education*, George G. Harrap and Co., Ltd.,  
London, 1955.
  7. Malarji, S. N.  
*Education in India To-day & Tomorrow*, Acharya Book Depot,  
Faridkot, 1964.
-

# विश्वविद्यालय प्रश्न

## University Questions

1. Analyse the main recommendations in respect of Secondary education made in the report of the Central Advisory Committee on post-war educational instruction

(L. T., 1942)

2. Describe and discuss the proposals made by Sargent Report on the organization of Secondary Education in India.

(Saugar, 1953)

3. Summarise the views expressed by Messrs Abbot and Wood on the development of Vocational education in this country. How far have they been put in practice in Indian Schools.

(Agra, 1951.)

4. Summarise and criticise the main recommendations of the Hartog Committee and say how far they have influenced modern conception of Secondary Education in India

(L. T. 1947)

5. Trace briefly that relationship since 1884 between government and private enterprise in Secondary Education in India,

(Poona 1953)

6. Summarize the chief recommendations of the Hunter Commission of 1882 for secondary education and trace their influence on the subsequent development of secondary education in India.

(Agra 1953)

7. माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु भारतीय शिक्षा आयोग ने कौन-कौन से महत्वपूर्ण सुझाव दिये। विस्तृत विवेचना कीजिये।

अध्याय छः  
Chapter Sixth  
माध्यमिक शिक्षा आयोग  
Secondary Education Commission  
समय-सारणी  
Learning Schedule

- 6.01 आयोग का विवरण देना  
Terms of Reference of the Commission
- 6.02 आयोग की सिफारिशों और सुझाव  
Recommendations & Suggestions of the Commission

(I) माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र

(II) माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य

1. प्रशासनिक व्यवस्था का विभाग
2. जीवन-साधन में दोष
3. व्यक्तित्व का विकास
4. व्यावसायिक चुनौतियों की पूर्ति
5. भविष्य के लिए शिक्षा
6. राष्ट्रीय विकास की आवश्यकता का विकास

(III) माध्यमिक शिक्षा का नव संवर्धन रूप

(IV) माध्यमिक शिक्षा का समय-सारणी

(V) माध्यमिक शिक्षा के स्तरों का वर्गीकरण

(VI) माध्यमिक स्तर पर शिक्षा-सुविधाएँ

(VII) गणितीय शिक्षण विधि

(VIII) चरित्र निर्माण की शिक्षा

(IX) माध्यमिक शिक्षा के माध्यम-संसाधन और परामर्श

(X) माध्यमिक स्तर पर परीक्षा और मूल्यांकन

(XI) अध्यापकों की स्थिति

(XII) अध्यापकों का प्रशिक्षण

(XIII) माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन

(XIV) माध्यमिक शिक्षा हेतु वित्त व्यवस्था

6.03 माध्यमिक शिक्षा आयोग का आलोचनात्मक मूल्यांकन  
Critical Evaluation of Secondary Education Commission.

## माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53)

*SECONDARY EDUCATION COMMISSION (1952-53)*

मुदालियर आयोग

*Mudaliar Commission*

जैसा कि हम पिछले अध्याय में कह चुके हैं कि स्वायत्तता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश की सम्पूर्ण व्यवस्थाओं में परिवर्तन आये। इन परिवर्तनों के कारण यह आवश्यक हो गया कि हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को भी उसी के अनुकूल करें जिससे यह शिक्षा जीवनीययोगी होकर सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने में समर्थ हो सके। इन्हीं आधारभूत विद्यान्तों को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' ने 1948 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति हेतु सरकार को सुझाव दिया था। जनवरी 1951 में बोर्ड ने पुनः पत्र प्रस्ताव की दोहराया और माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल दिया। भारत सरकार ने 23 सितम्बर, 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की जिसके अध्यक्ष डा० लक्ष्मणस्वामी मुदालियर थे।

### 6.01 आयोग का विषय-क्षेत्र

*Terms of Reference of the Commission*

आयोग के विषय क्षेत्र निम्नलिखित थे—

1. माध्यमिक शिक्षा के समस्त पहलुओं को जाँच करना।

2. निम्नलिखित तथ्यों के संदर्भ में उनके पुनर्संरूपण और सुधार हेतु सुझाव देना—

1. उनके उद्देश्य, व्यवस्था और विषय वस्तु;
2. उसका प्राथमिक, वैज्ञानिक और उच्च शिक्षा से सम्बन्ध;
3. घनेको प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का पारस्परिक सम्बन्ध और
4. अन्य सम्बन्धित समस्याएँ ।

जिससे समस्त देश को उसकी आवश्यकताओं और साधनों के अनुरूप, समान माध्यमिक शिक्षा गति दी जा सके ।<sup>1</sup>

6.02 आयोग की सिफारिशों और सुझाव

*Recommendations & Suggestions of the Commission*

आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशों और सुझाव दिये—

(I) माध्यमिक शिक्षा के दोष—

*Defects of Secondary Education*

- (i) माध्यमिक शिक्षा पूर्णरूपेण नीरस एवं अवास्तविक है ।
- (ii) यह शिक्षा छात्रों की रूचि एवं क्षमिकता के अनुरूप नहीं है ।
- (iii) यह शिक्षा बालकों के व्यक्तित्व को विकसित करने में असमर्थ है ।
- (iv) वर्तमान पाठ्यक्रम में पुस्तकीय ज्ञान की अधिकता है जिसके कारण बालक उपयोगी नागरिक नहीं हो सकते ।
- (v) शिक्षण-विधियाँ दोषपूर्ण हैं ।

1. (A) "To enquire into and report of the present position of Secondary Education in India in all its aspects,

(B) Suggest measures for its reorganisation and improvement with particular reference to—

- (1) the aims, organization and content of secondary education,
- (2) its relationship to primary, basic and higher education,
- (3) the inter-relation of Secondary Schools of different types and
- (4) other allied problems

so that a sound and reasonably uniform system of secondary education suited to our needs and resources may be provided for the whole country."

*Report of the Secondary Education Commission, p. 2.*

- (vi) परीक्षा प्रणाली दूषित है।
- (vii) पाठ्य पुस्तकें नीरस हैं।
- (viii) अंग्रेजी अनिवार्य विषय होने के कारण छात्रों की मानसिक शक्ति का दुरुपयोग होता है।
- (ix) यह शिक्षा सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने में असमर्थ है।
- (x) वर्तमान शिक्षा पद्धति चारित्रिक शिक्षा का कोई स्थान नहीं है।
- (xi) इस शिक्षा व्यवस्था में भासकों की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति के विकास हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं किये जाते।

## (II) माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य

### Aims of Secondary Education

भाषा के अनुसार विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण नितान्त आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा से उन उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए जिससे हम आदर्श नागरिकों का निर्माण कर सकें और अपने देश में सफल प्रजातन्त्र की स्थापना कर सकें। समय हो सके। भाषा लोकतन्त्रीय भारत में माध्यमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये—

#### (1) प्रजातान्त्रिक नागरिकता का विकास

##### Development of Democratic Citizenship

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्रवादी देश है। प्रजातन्त्रात्मक शासन पद्धति में नागरिकों के बहुत उत्तरदायित्व होते हैं। जन-प्रत्येक व्यक्ति को सफल नागरिक जीवन व्यतीत करने का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। नागरिकता का प्रशिक्षण शिक्षा के माध्यम द्वारा दिया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा द्वारा उन सभी बाधाओं को दूर करना आवश्यक है जो आदर्श नागरिक के मार्ग में उपस्थित होती हैं। अतः नागरिकों में मानसिक परिपक्वता, सत्य और असत्य का ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, अन्धविश्वासों और लड़खड़ी परम्पराओं का त्याग कर सकने की सामर्थ्य आदि का विकसित होना नितान्त आवश्यक है। विद्यार्थियों में सफल नागरिक के गुणों का विकास करना, माध्यमिक शिक्षा का सत्य प्रथम उद्देश्य है।

हमारे देश में प्रजातन्त्र सभी सकल हो सकता है जब कि हमारे छात्रों में भारतीय संस्कृति का ज्ञान हो और विचार स्वातन्त्र्य, भाषण और लेखन की स्वतन्त्रता का अर्थ, समस्याओं का शान्तिमय ढंग से हल करने की क्षमता आदि नागरिक गुणों का विकास हो सके। माध्यमिक शिक्षा के द्वारा भारतीय लोकतन्त्र को सफल बनाना है और यह सभी सम्भव है जबकि प्रजातन्त्रीय नागरिकता का विकास हो सके।



## प्राविधिक शिक्षा Technical Education

- (i) इस शिक्षा के लिए प्राविधिक शास्त्राग्रे की व्यवस्था यथाशीघ्र की जाये ।
- (ii) स्थानीय शास्त्राग्रे की पूर्ति हेतु बड़े नगरों में केन्द्रीय टैकनिकल इंस्टी-ट्यूट खोले जायें ।
- (iii) क्रियात्मक शिक्षण हेतु प्राविधिक शास्त्राग्रे की स्थापना उद्योगों के समीप की जाये ।
- (iv) प्राविधिक शिक्षा के चार स्वरूप होने—

(अ) इस वर्ग का छात्र औद्योगिक उच्च शास्त्राग्रे में शिक्षा प्राप्त करेंगे ।

(ब) इस वर्ग के छात्र माध्यमिक शिक्षा समाप्त होने से पूर्व ही उद्योग प्रयत्न व्यापार शिक्षा प्राप्त करेंगे ।

(ग) माध्यमिक शिक्षा के पश्चात् प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करेंगे ।

(घ) इस वर्ग में वे छात्र होंगे जो साथ बच्चाग्रे में प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करेंगे । यह मुविद्या लौकरी करने वाले व्यक्तियों को प्रदान की जायेगी ।

## अन्य शास्त्राग्रे Other Schools

- (i) पब्लिक स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देना चाहिए । इन शास्त्राग्रे को पाँच वर्ष खलने दिया जाये तत्पश्चात् इनका स्वरूप भी माध्यमिक शास्त्राग्रे जैसा हो जाना चाहिए । इन शास्त्राग्रे के प्रतिभाशाली छात्रों को सरकार द्वारा छात्रवृत्तियों की व्यवस्था होनी चाहिए ।
- (ii) कुछ चुने हुए स्थानों पर निवास विद्यालयों की स्थापना की जाय ।
- (iii) विज्ञान बच्चों के लिए गृहस्थ शास्त्राग्रे खोली जायें । इन शास्त्राग्रे के निवास की व्यवस्था शास्त्राग्रे में ही की जानी चाहिए ।
- (iv) छात्र ०५५ छात्राग्रे की शिक्षा में कोई भेद न किया जाये । लड़कियों के लिए दृढ़ विज्ञान के अध्ययन की मुविद्या दी जाये । छात्रवृत्तता होने पर छात्राग्रे के लिए गृहस्थ शास्त्राग्रे खोली जायें ।

## (iv) भाषाग्रे का अध्ययन

### Study of Languages

छात्रों में हिन्दी, उर्दू की और संस्कृत भाषाग्रे के स्थान पर विशेष प्रकाश देने के प्रतिष्ठित छात्रों ने निम्नलिखित भाषा सम्बन्धी सुझाव दिये—

- (1) माध्यमिक शालाओं में शिक्षा का माध्यम मातृ भाषा अथवा प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए ।
- (2) अल्पसंख्यक भाषकों की सुविधा ■ लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सुझावों के अनुसार विशेष व्यवस्था होनी चाहिए ।
- (3) मिडिल स्कूलों में दो भाषाओं की व्यवस्था होनी चाहिए ।
- (4) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कम से कम दो भाषाओं का अध्ययन होना चाहिए । जिसमें से एक मातृ-भाषा प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए ।

### (F) माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम

#### Curriculum of Secondary Schools

आयोग ने सर्वप्रथम वर्तमान पाठ्यक्रम के निम्नलिखित दोष बताये—

- (1) पाठ्यक्रम लकीरुं है ।
- (2) इसमें पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है ।
- (3) इससे बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता ।
- (4) इसमें छात्रों की रुचि, मानसिक शक्ति और शैक्षिक पक्ष का कोई ध्यान नहीं रखा गया है ।
- (5) यह जीवनोपयोगी नहीं है ।
- (6) इसमें तकनीकी एवं व्यवसायिक विषयों का अभाव है ।

आयोग ने पाठ्यक्रम के दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये—

- (1) पाठ्यक्रम के लकीरुं अर्थ को छोड़कर उनके विस्तृत अर्थ को लिया जाये और वास्तविक में बालकों की रुचि, योग्यताओं एवं शैक्षिक पक्ष को समावेश कर, वर्तमान आवश्यकतानुसार निर्माण किया जाये ।
- (2) पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाये ।
- (3) पाठ्यक्रम का निर्माण स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाये ।
- (4) पाठ्यक्रम में विविधता और लचीलापन होना चाहिए ।

आयोग ने उपरोक्त सुझावों के आधार पर पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों के अध्ययन हेतु विचारित की—

(i) मिडिल हायर धेनिक स्कूलों का पाठ्यक्रम  
Curriculum of Middle or Basic Schools

- (i) भाषाएँ
- (ii) सामाजिक अध्ययन
- (iii) सामान्य विज्ञान
- (iv) गणित
- (v) कला और संगीत
- (vi) पारंपरिक शिक्षा
- vii) उद्योग

(ii) माध्यमिक स्तराध्यों का पाठ्यक्रम  
Curriculum of Secondary Schools

इस स्तर पर आयोग ने पाठ्यक्रम के विभिन्नकरण की सिफारिश की। पाठ्यक्रम में कुछ आन्तरिक विषयों का समावेश किया गया जिनका अध्ययन समस्त छात्रों के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कुछ वैकल्पिक विषय निश्चित किये जिन्हें छात्र समूहों में विभक्त किया गया। अतः पाठ्यक्रम की रूपरेखा निम्नलिखित निश्चित की गई—

आन्तरिक विषय  
Core Subject

- (1) मातृ-भाषा या प्रादेशिक भाषा या मातृ-भाषा तथा शास्त्रीय भाषा का संश्लिष्ट पाठ्यक्रम।
- (2) निम्नलिखित भाषाओं में से एक अन्य भाषा—
  - (1) हिन्दी (जिनकी मातृ-भाषा हिन्दी नहीं है)
  - (2) प्रारम्भिक अंग्रेजी (जिन्होंने मिडिल स्तर अंग्रेजी नहीं पढ़ी है)
  - (3) उच्च अंग्रेजी (जिन्होंने पहले अंग्रेजी पढ़ी है)
  - (4) हिन्दी के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा
  - (5) अंग्रेजी के अतिरिक्त विदेशी भाषा
  - (6) एक शास्त्रीय भाषा
- (3) सामान्य विज्ञान (केवल प्रथम दो वर्षों के लिए)
- (4) गणित तथा सामान्य विज्ञान (केवल दो वर्षों के लिए निम्नलिखित में से एक विषय—
  - (1) बुनाई और बुनाई (Sp. and Weaving)
  - (2) काष्ठ कला (Wood work)

- (3) धातु कार्य (Metal work)
- (4) बागवानी (Horticulture)
- (5) सिलाई (Tailoring)
- (6) मुद्रण (Typography)
- (7) प्रयोग शाला कार्य (Workshop Practice)
- (8) सुई का काम (Needle Work)
- (9) कढ़ाई बुनाई (Embroidery)
- (10) प्रतिरूपण (Modelling)

### वैकल्पिक विषय

### Optional Subjects

आयोग ने निम्नलिखित सात समूह निश्चित किये जिनमें से कोई से एक समूह में से तीन विषय आवश्यक हैं—

#### समूह नं० 1—मानव विज्ञान (Humanities)

- (1) एक शास्त्रीय भाषा (जो अनिवार्य विषय में से न ली गई हो)
- (2) इतिहास
- (3) भूगोल
- (4) अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र के सामान्य सिद्धान्त
- (5) मनोविज्ञान तथा दर्शनशास्त्र के सामान्य सिद्धान्त
- (6) गणित
- (7) संगीत
- (8) गृह विज्ञान

#### समूह नं० 2—विज्ञान (Sciences)

- (1) भौतिक शास्त्र
- (2) रसायन शास्त्र
- (3) जीव विज्ञान
- (4) भूगोल
- (5) गणित
- (6) शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्य विज्ञान (यदि जीव विज्ञान नहीं लिया है तो)

#### समूह नं० 3—प्राविधिक (Technical)

- (1) व्यावहारिक गणित और व्यावसायिक कला
- (2) व्यावहारिक विज्ञान

- (3) मिथेनिकल इन्जीनियरिंग के तत्व  
(4) इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग के तत्व

समूह न० ४—वाणिज्य (Commerce)

- (1) वाणिज्यिक प्रयोग
- (2) बुद्ध-दीपिका
- (3) वाणिज्य भूयोन अथवा अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र
- (4) आर्सेनल और टावर

समूह सं० ८—कृषि (Agriculture)

- (1) सामान्य कृषि
- (2) पशु पालन
- (3) उद्योग एवम् वापवानी कार्य
- (4) कृषि रसायन और वनस्पति विज्ञान

समूह नं० ८-सहित कलाएं (Fine Arts)

- (1) कला का इतिहास
- (2) ड्राइंग तथा आलेखन
- (3) विमल
- (4) प्रतिस्पर्ध
- (5) समीक्षा
- (6) नृत्य

समूह नं० ७—गृह विज्ञान / Domestic Science

- (1) શ્રુતિ સંપ્રદાય
- (2) ગ્રાહ્ય, ગોપણ તથા પાક જતા
- (3) માતૃ જન્મ ઓર બિશુ વાતન (Mother Craft and Child care)
- (4) શુદ્ધ રક્તદ્વય કાચાર (Moron-Nursing)
- (5) માધ્યમિક સ્તર પર શાલ્ય-પુરતકો  
Text Books at Secondary Stage

आमोव के अनुसार काहू बगुनी का मर मामोव मरी का १ पाहू-  
बगुनी ठे मरमिन्व आमोव के बगुनी

## (1) पाठ्य पुस्तक समिति

## Text-Book Committee

आयोग ने सम्बन्धित पाठ्य पुस्तकों के लिये प्रत्येक राज्य में एक समिति के गठन की सिफारिश की। समिति के गठन के लिये निम्नलिखित सदस्यों के रकबे आने का सुझाव दिया:—

- (1) उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश
- (2) लोक सेवा आयोग का एक सदस्य
- (3) राज्य के किसी एक विश्वविद्यालय का उपकुसुपति
- (4) राज्य की भाषाओं के भाषाओं में से एक
- (5) दो प्रतिष्ठित शिक्षा-शास्त्री
- (6) शिक्षा निदेशक

## (2) पाठ्य-पुस्तकों के सम्बन्ध में सुझाव

## Suggestions Regarding Text-Books

- (1) एक विषय में समिति द्वारा कई पाठ्य-पुस्तकें निर्धारित की जायें। यह भाषाओं की दृष्टि पर छोड़ दिया जाये कि वे कौनसी पुस्तक का अयम करते हैं।
- (2) पाठ्य पुस्तकों में किसी धर्म, जाति, समुदाय के विरुद्ध कोई भी तथ्य नहीं होना चाहिए।
- (3) एक पाठ्य पुस्तक को गीघ ही न बढ़ता जाये।

## (VII) गतिशील शिक्षण विधियाँ

## Dynamic Methods of Teaching

शिक्षा के सर्वेक्षणों की प्राप्ति शिक्षण विधियों के द्वारा ही सम्भव है। शिक्षण विधियों का जीवन उनकी गतिशीलता पर आधारित है। आयोग ने शिक्षण विधियों से सम्बन्धित निम्नलिखित सुझाव दिये:—

- (1) शिक्षण विधियों का उद्देश्य केवल ज्ञानात्मक पर्य तक ही सीमित नहीं है बल्कि बौद्धिक गुणों का विकास भी होना चाहिए।
- (2) शिक्षण में रटने की क्रिया का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। शिक्षण की सफल बनाने के लिए नया प्रमाण विधियों तथा योजना विधि को प्रयोग करना चाहिए।
- (3) छात्रों में सहयोग, प्रेम और सहिष्णुता की भावना को विकसित करने हेतु इन विधियों को प्रयोग में लाना चाहिए जो इन गुणों की प्रमोद कर सजने में सहायक हो सकें।

(६) शिक्षण विधि में यह सुझाव दी गई है कि विद्यार्थियों को अपना अपना होना चाहिए और दूसरों के इस विचारों का उद्देश्य है कि वे अपने अपने विचारों के द्वारा अपने को दूसरों से अलग करें। यह विचार ही है।

(७) कुछ विचारों को उचित रूप में हैसिये के लिए कुछ छात्रों को अपने को अपनी भाँति को इस विचारों पर कठिनाई कर रहे हैं। इसका समाधान का साधन द्वारा विचारों को अपने अपने भाँति।

### (VIII) चरित्र निर्माण की शिक्षा

#### *Education of Character*

शास्त्राचार्य में चरित्र शिक्षा की आवश्यकता का होना सामान्य बात है। इस कारण से हम इसका विचार विचारित करने लगे हैं। —

- (१) छात्रों में चरित्र निर्माण का अनिवार्यतापूर्ण ध्यान होना चाहिए है। शास्त्र का वास्तविक रूप प्रसार होना चाहिए जिससे छात्रों का चरित्र बन सके।
- (२) चरित्र निर्माण की शिक्षा हेतु यह ध्यान आवश्यक है कि शिक्षण इस शिक्षा में सहयोग प्रदान करें।
- (३) छात्रों के शिक्षण साधन हेतु 'साधारण शिक्षा' का होना आवश्यक है।
- (४) छात्रों में धार्मिक शिक्षा और अनुशासन की भावना विकसित करने के लिए छात्रों में स्वशासन का प्रवर्धन निम्नलिखित आवश्यक है।
- (५) शास्त्राचार्य में पाठान्तर विद्यालयों को विशेष स्थान दिया जाये और उन्हें छात्रों के व्यवहार का आवश्यक भाग माना जाये।
- (६) शास्त्राचार्य में एकाग्रता, एन० सी० सी० ए० सी० सी०, की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- (७) शास्त्राचार्य में धार्मिक और नैतिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।
- (८) शास्त्राचार्य का सम्पूर्ण कार्य इस प्रकार का होना चाहिए जिससे छात्रों को स्वतः उत्तम चरित्र निर्माण की शिक्षा मिल सके।

### (IX) माध्यमिक शालाओं में मार्ग दर्शन और परामर्श

#### *Guidance and Counselling in Secondary Schools*

साधन से छात्रों की रुचि को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा के वास्तविक को सात वर्षों में बढ़ा

कि बालक का धार्मिक चिन्तन विषयों को लेने में मार्ग दर्शन दिया जा सके और परामर्श दिया जा सके। अतः इसके लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये —

- (1) बालकों के व्यक्तिगत भेदों, मानसिक योग्यताओं, रुचियों आदि को आधार मानकर मार्ग दर्शन किया जाये।
- (2) बालकों को विभिन्न व्यवसायों और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह निताम्त आवश्यक है कि उनका मार्ग दर्शन दिया जाये और उचित परामर्श दिया जाये।
- (3) माध्यमिक स्तरों में सैनिक, शिल्प, प्रशिक्षित मार्ग-दर्शन अधिकारियों तथा जीविकोपार्जन सहायकों की नियुक्ति की जाये।
- (4) केन्द्रीय सरकार द्वारा मार्ग-दर्शन अधिकारियों तथा जीविकोपार्जन सहायकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।
- (5) प्रत्येक राज्य में एक व्यावसायिक और शैक्षणिक मार्ग-दर्शन कार्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए।

### (X) माध्यमिक स्तर पर परीक्षा और मूल्यांकन

#### Examination and Evaluation at Secondary Stage

इस सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये—

- (1) परीक्षाओं में बन्धु-निष्ठता का भ्रान्त निरास्य आवश्यक है। परीक्षाओं में परीक्षकों के व्यक्तिगत मत द्वारा ही निर्णय नहीं होना चाहिए।
- (2) परीक्षा के निष्पक्षत्मक ढंग को परिबर्धित किया जाने और परीक्षा प्रणाली को इस प्रकार का बनाया जाये जिससे छात्रों का शैक्षिक पक्ष स्पष्ट हो सके।
- (3) छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन प्रणाली में न किया जाये बल्कि सांकेतिक (Symbolic) रूप में किया जाये। मूल्यांकन का आधार पाँच बिन्दु मापदण्ड (Five Point Scale) बनाया जाये।
- (4) वास्तव परीक्षाओं में कमी की जाये।
- (5) माध्यमिक शिक्षा समाप्त होने पर एक सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए तथा पुरक परीक्षा (Compartmental Examination) की व्यवस्था होनी चाहिए।





- (2) माध्यमिक शिक्षा प्राप्त मध्यापकों का प्रशिक्षण शिक्षा विभाग के प्राधीन होना चाहिए।
- (3) स्नातक शिक्षा प्राप्त मध्यापकों का प्रशिक्षण विश्वविद्यालयों के प्राधीन होना चाहिए।
- (4) प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सह क्रियाओं, भूमिगत पाठ्यक्रमों और त्रिमासिक प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।
- (5) प्रशिक्षण महाविद्यालयों में छात्राध्यापकों एवम् छात्राध्यापिकाओं के रहने की व्यवस्था होनी चाहिए।
- (6) प्रशिक्षण की अवधि में छात्रों एवम् छात्राओं से कोई शुल्क न लिया जाये।
- (7) एम० एड० की व्यवस्था केवल उन प्रशिक्षित मध्यापकों के लिए होनी चाहिए जो तीन वर्ष का मध्यापन अनुभव रखते हों।
- (8) मध्यापिकाओं की कमी को दूर करने के लिए अर्न्तकालिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- (9) प्रशिक्षण महाविद्यालयों में छात्राध्यापकों तथा छात्राध्यापिकाओं के लिए दो विषयों की शिक्षण विधियों का अध्ययन करना अनिवार्य होना चाहिए।

### (XIII) माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन

#### Administration of Secondary Education

सायोग में माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये—

#### (1) माध्यमिक शिक्षा का संगठन

##### Organization of Secondary Education

(i) मौलिक विषयों पर शिक्षा मंत्री की परामर्श देने का कार्य शिक्षा निदेशक का होना चाहिए।

(ii) केन्द्र एवम् प्रांशों की शिक्षा समिति होनी चाहिए जो उपर्युक्त योजनाएँ बनाये।

(iii) शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होना चाहिए जिसके सदस्यों की संख्या 25 होनी चाहिए।

(iv) एक सहायक प्रशिक्षण परिषद् होनी चाहिए जो शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करे।

(v) प्रांत में एक 'राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड' होना चाहिए जैसा कि केन्द्र में 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' है।



नितान्त आवश्यक है। परन्तु यहाँ यह निश्चित रूप से कह देता आवश्यक है कि आयोग के महत्वपूर्ण गुणों के होते हुए भी इसमें अभाव के दर्शन भी होते हैं और सम्भवतः इसका मूल कारण यही है कि इस आयोग में सामान्य शालाओं के अध्यापकों का प्रतिनिधित्व नहीं था जो कि सामयिक एवम् वास्तविक रूपरेखा के निरूपण के लिए नितान्त आवश्यक था।

आयोग ने परिवर्तित सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप ही माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किये जो कि देश की वर्तमान व्यवस्था के अनुकूल हैं। भावी नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु एक पक्षीय ज्ञान के स्थान बहुपक्षीय ज्ञान प्रदान करना माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों की आचार शिक्षा है। अतः माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा निश्चित उद्देश्य गलततन्त्र भारत में लिए निश्चित ही व्यवहारिक हैं।

उद्देश्यों को कार्यरूप में परिचित करने हेतु माध्यमिक शिक्षा का नवनिर्मित संघटन नितान्त आवश्यक है। आयोग ने बहु उद्देशीय शालाओं की स्थापना हेतु सुझाव दिये। प्राचीन विद्यालयों में कृषि की अनिवार्य विषय बनाने का सुझाव निश्चित रूप से कृषि प्रधान देश के लिए महत्वपूर्ण है। आयोग द्वारा दिया गया यह सुझाव भारतीय मिट्टी से उत्पन्न हुआ मान्य होना है। परन्तु बहुउद्देशीय शालाओं की स्थापना निश्चित रूप से महती योजना है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए भारत में प्रत्येक बहु उद्देशीय शाला में बहुमुख्य प्रयोग शालाएँ कीमती रसम आदि की व्यवस्था वर्तमान में कठिन अवश्य है।

प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता पर आयोग ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं परन्तु आयोग ने औद्योगिकरण पर बल नहीं दिया। देश की औद्योगिक उन्नति अत्यन्त आवश्यक है और इसके लिए मात्र के अधिक को शिक्षित करना भी आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षा के वादक्य का अन्तिम मार भी राज्य सरकारों को बहन करना चाहिए।

आयोग के सम्बन्ध में आयोग ने क्षेत्रीय भाषाओं की शिक्षा का माध्यम बनाना स्वीकार किया है, यह सुझाव निश्चित रूप से प्रस्ताव के योग्य है क्योंकि अंग्रेजी से भारत का संगठनमय भविष्य नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त आयोग ने माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाओं का अध्ययन आवश्यक बताया है अर्थात् माध्यमिक स्तर पर दो भाषाएँ तो बङ्गी-बङ्गी ही परन्तु साथ ही हिन्दी का अध्ययन भी आवश्यक होना है। अतः त्रिन विद्यालयों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है तो उसे तीन भाषाएँ बङ्गी होगी। तीन भाषाओं के अध्ययन का भार कुछ अधिक प्रतीत होता है। आयोग का यह सुझाव हिन्दी भाषा क्षेत्रों के लिए लाभदायी नहीं है क्योंकि हिन्दी मातृ भाषा भी है और राष्ट्र भाषा भी।

आयोग के विविध वादक्यन सम्बन्धी सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं।

मानवशास्त्रिक दृष्टिकोण से अतिमहत्वपूर्ण है। दृष्टिकोण से इसे हमें पूर्ण वास्तविकता के रूप में समझना चाहिए। मानवशास्त्र के अभाव में हमें मानव के अस्तित्व के अभाव में वास्तविकता को महत्वपूर्ण मानने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है।

मानवीय विचारधारा की दृष्टि से, अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मानवीय विचारधारा के अभाव में हमें मानव के अस्तित्व के अभाव में वास्तविकता को महत्वपूर्ण मानने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है।

मानवीय विचारधारा के अभाव में हमें मानव के अस्तित्व के अभाव में वास्तविकता को महत्वपूर्ण मानने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है।

मानवीय विचारधारा के अभाव में हमें मानव के अस्तित्व के अभाव में वास्तविकता को महत्वपूर्ण मानने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है।

मानवीय विचारधारा के अभाव में हमें मानव के अस्तित्व के अभाव में वास्तविकता को महत्वपूर्ण मानने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है।

मानवीय विचारधारा के अभाव में हमें मानव के अस्तित्व के अभाव में वास्तविकता को महत्वपूर्ण मानने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है।

## ग्रन्थ - सूची

### Bibliography

1. Ministry of Education.  
*Report of the Secondary Education Commission, (1952-53),*  
Government of India, New Delhi, 1953.
  2. Mukerji, S. N.  
*Secondary School Administration, Acharya Book Depot,*  
Baroda, 1963.
  3. Mudaliar, A. Lakshmanaswami.  
*Education in India, Asia Publishing House, Bombay, 1960.*
  4. Nalk, J P.  
*The Role of Government of India in Education, Ministry of*  
*Education, New Delhi, 1963.*
  5. Shrivastava, B. Dayal,  
*The Development of Modern Indian Education, Orient Long-*  
*mans, New Delhi, 1963.*
-



## 7.01 माध्यमिक शिक्षा की प्रगति (1947-68)

## Progress of Secondary Education (1947-68)

यद्यपि शिक्षे क्कों में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति द्रुत गति से हुई है तथापि स्वतन्त्रता प्राप्ति से अब तक माध्यमिक शिक्षा के प्रसार को देखते हुए यह अवश्य कहा जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा हमारी सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की दुर्बलतम कड़ी है। सन् 1947 में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 12,693 थी जिनमें 29,53,095 छात्र थे। सन् 1950 में विद्यालयों की संख्या 20,884 थी जिनमें 52,32,009 छात्र थे। सन् 1955 में विद्यालयों की संख्या 32,568 थी जिनमें 85,26,509 छात्र थे और 1960-61 में विद्यालयों की संख्या बढ़कर 66,916 हो गई जिनमें 1,80,26,594 छात्र थे। तालिका नं० 7.1 में उपरोक्त संख्याएँ स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की गई हैं।

## तालिका नं० 7.1

## माध्यमिक शिक्षा (1947-61)

वर्ष	माध्यमिक विद्यालय	छात्रों की संख्या	व्यय पर राशि ( करोड़ों में )
1947-48	12,643	29,53,096	14
1950-51	20,884	52,32,009	31
1955-56	32,568	85,26,509	51
1960-61	66,916	1,80,26,594	110

उपरोक्त तालिका से यह भी प्रतीत होता है कि माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई, छात्रों की संख्या में भी बड़ी वृद्धि हुई।

for both elementary and adult education. It also prepares pupils for the universities and other institutions of higher learning. Besides, it is the stage which in all countries marks the completion of education for the vast majority. Even the minority which goes for higher education can not take full advantage of the wider opportunities by the universities unless they have received their grounding in a system of sound secondary education. If for no other reason these considerations alone demand that secondary education must be of the highest quality, if it is to satisfy the needs of the modern age.

Humayun Kabir, *Education in New India*, p. 3.



... 1950-51 ...

... 1950-51 ...

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...
- (4) ...
- (5) ...

... 1950-51 ...

... 1950-51 ...

... 1950-51 ...

करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1,500,000 थी जो कि 1985-86 में बढ़कर 6,100,000 हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि औसत वार्षिक वृद्धि 10% थी। कोठारी प्रायोगिक संभावना के अनुसार अगले 20 वर्षों में अर्थात् 1980-81 तक 13-15 वर्ष के लड़कों की कुल जनसंख्या के 67.2%, 13-16 वर्ष की लड़कियों की कुल जनसंख्या के 21.3% और लड़के लड़कियों की सम्मिलित जनसंख्या के 45% विद्यार्थी लोअर माध्यमिक शालाओं में अध्ययन करेंगे।

इसी प्रकार की स्थिति उच्च माध्यमिक स्तर की है। सन् 1950-51 में कुल 282,010 विद्यार्थियों में शिक्षा प्राप्त की। सन् 1985-86 में यह संख्या 1,400,010 हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि औसत वार्षिक वृद्धि 11.3% थी। अगले 20 वर्षों में यह संख्या 6,900,000 होगी परन्तु औसत वार्षिक वृद्धि 11.3% से घटकर 8.3% होगी। लालिका नं० 7.2 और 7.3 देखा बिचों से यह स्पष्ट है।

### तालिका नं० 7.2

लोअर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की संख्या

संख्या ( 000, में )

वर्ष	लड़के	लड़कियाँ	कुल योग
1950-51	1,304	204	1,508
1955-56	1,965	406	2,371
1960-61	2,941	741	3,682
1965-66	4,707	1,420	6,127
1970-71	6,559	2,259	8,818
1975-76	9,104	3,581	12,685
1980-81	12,256	5,285	17,541
1985-86	16,526	7,842	24,368

तालिका नं० 7.3 वर्षों की जनसंख्या का प्रतिशत

वर्ष	नर	महिला	कुल
1950-51	10.9	1.8	6.5
1955-56	14.7	3.3	9.3
1960-61	20.4	5.4	13.1
1965-66	28.7	9.0	19.1
1970-71	34.2	12.2	23.4
1975-76	40.8	16.9	29.1
1980-81	49.1	22.6	36.3
1985-86	60.4	30.6	46.0

उक्त तालिका एवं तालिका नं० 7.3 से यह तो स्पष्ट है कि हमें तब तक जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा जब तक कि यह जनसंख्या को नियंत्रित करने में सक्षम हो सके। यदि जनसंख्या की गति को देखा जाये तो यह जनसंख्या वर्षों से अधिक गति से माध्यमिक शिक्षा को ग्रहण करने का मुख्य कारण देश की धार्मिक स्थिति है।

### तालिका नं० 7.3

उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की संख्या  
संख्या ( 000, में )

वर्ष	सदके	सदकियाँ	कुल योग
1950—51	245	37	282
1955—56	431	71	502
1960—61	717	112	849
1965—66	1,172	226	1,398
1970—71	1,698	391	2,079
1975—76	2,351	638	2,989
1980—81	3,423	1,089	4,512
1985—86	5,001	1,869	6,870

उपरोक्त तथा निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होता है कि छात्रों की सम्भावित संख्या के अनुसार वर्ष 11 और 12 में छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी। इस समय अनुसूच जाति के विद्यार्थियों की कुल संख्या के 7.0% विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सन् 1970-71 में यह संख्या बढ़कर 9.2%, सन् 1975-76 में 11.0%, और 1985-86 में बढ़कर 20.8% हो जायेगी। इसका अर्थ यह होगा कि उस समय 16 से 17 वर्षीय समूह के 5 विद्यार्थियों में से 1 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करेगा और 10 सदकियों में से 1 सदकी उच्च माध्यमिक स्तर में शिक्षा प्राप्त करेगी।

## 16 से 17 वर्षीय आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत

वर्ष	सड़के	सड़कियाँ	कुल
1950—51	3.3	0.5	
1955—56	6.2	0.9	
1960—61	8.0	1.6	
1965—66	11.5	2.3	
1970—71	14.6	3.5	
1975—76	17.0	4.8	11
1980—81	21.7	7.4	14
1985—86	28.8	11.4	20

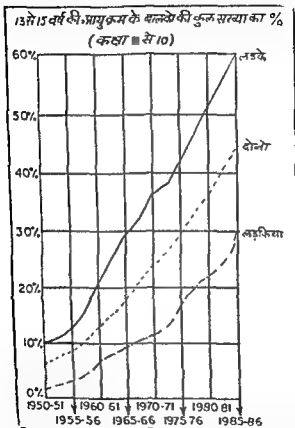
निम्नलिखित रेखा चित्रों से यह स्पष्ट होता है कि 1985-86 माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बहुत कुछ करना बगले पृष्ठों पर अंकित थाको से यह स्थिति स्पष्ट होती है।

## 7.02. माध्यमिक शिक्षा की भावी प्रगति (1969-1986) हेतु सुझाव

*Suggestions for Future Progress (1969-1986)  
of Secondary Education*

जैसा कि हम पिछले पृष्ठों में कह चुके हैं कि भारतीय शिक्षा प्रणाली (1964-66) ने वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा की प्रगति हेतु कुछ सार्वजनिक किये हैं। इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु तीन प्रमुख दिशुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया है। यदि हम माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में बेरोजगारी की समस्या को देखें तो निराशा होती है और यदि हम बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने का प्रयास नहीं किया तो निश्चित ही स्थिति दयनगम बनस्यीर गी। अब हमारे देश की माध्यमिक शिक्षा का भावी स्वरूप हम प्रचार के माध्यम से सार्वजनिक शिक्षा

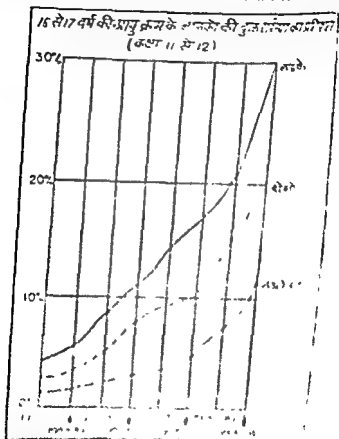
नैराश्य की भावना भी न बड़े घोर सभी अपनी संचित शक्तियों को देश के उत्थान एवं भगनमय प्रविध्य में लगा सकें। इसके लिए अत्यन्त आवश्यक है कि शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाये (इसको विस्तृत चर्चा हम किसी भगले अध्याय में करेंगे) घोर प्रवर्तित माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जाये। भगले पृष्ठों



पर चर्चित बाकी से यह स्पष्ट है कि 1986 तक माध्यमिक शिक्षा का विनाश प्रवृत्ति से होगा अतः भारतीय शिक्षा आयोग ने भारी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सुझाव दिये हैं—

(1) प्रत्येक जिले में माध्यमिक शिक्षा की एक विकास योजना होनी चाहिए, जो वर्तमान घोर भारी आवश्यकताओं के आधार पर बने। इस योजना

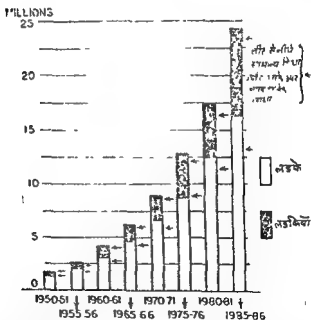
मे व्यय स्वरूप सम्भावित घनराशि का उल्लेख हो तथा प्रत्येक मासिक आय को वांछित स्तर पर लाने, नई शालाओं के शुलभाने, क्षेत्रों के आधार पर न.स.स. की स्थिति देखने तथा भव्योद्घनीय शैक्षिक प्रतिस्पर्धा आदि का नगराशिर हो।



परिचाल भी कोई विकास न हो तो कम शाला का कार्य करने की स्वीकृति न दी जाये।

(2) प्रत्येक माध्यमिक शाला में अच्छे प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिए जिससे गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके लिये यह आवश्यक है प्रत्येक नई शाला को निश्चित स्तर प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक कक्षा में अधिक छात्र नहीं होने चाहिए। यदि यह सम्भव हो सका तो सोमर माध्यमिक शालाओं में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो सकती।

### माध्यमिक शिक्षा (सोमर) का विकास (कक्षा 8-10) (सन् 1950-1986)



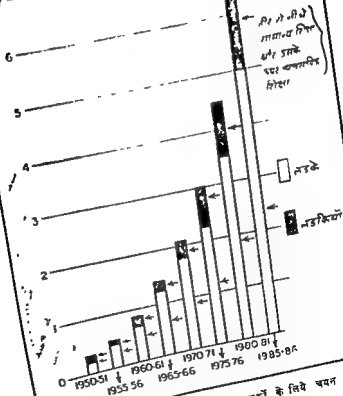
(3) प्रत्येक माध्यमिक शाला में अच्छे विद्यार्थियों को प्रवेश दे। सोमर माध्यमिक स्तर पर 'स्वयं चयन वृद्धि' (Self Selection), को अपनाया जाये। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर चयन की वृद्धि अधिक बढ़ोद नही चाहिए। चयन का



य छात्र नही है छात्र घर ही जा चाहिए। परन्तु नही के घर, माता  
 के विद्यापीठ के (न) छात्र नही होवे चाहिए और उनके विद्यापीठ  
 (School Record) विद्यापीठ की योजना तथा छात्र नभविष्य कार्य भी

# उच्च माध्यमिक शिक्षा का विकास (कक्षा 11-12) (सन् 1950-1986)

MILLIONS



प्रवेश या छात्र होना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों के लिये चयन में  
 भूट भी दो जानी चाहिए।

# 7-03 माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता Need For Expansion Educational Facilities at Secondary Stage

जुलाई माह में खानाभो के खुलने पर प्रायः शैक्षिक सुविधाओं की कमी के कारण विद्यार्थियों के प्रवेश की समस्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। 11 से 17 वर्ष के विद्यार्थियों की संख्या घटने, घटने बढ़ रही है। तालिका नं० 7-4 और 7-5 से स्पष्ट है।

तालिका नं० 7-4

11 से 14 वर्ष के बालकों की शैक्षिक सुविधाओं की स्थिति

वर्ष	11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत		
	लड़के	लड़कियाँ	कुल योग
1950-51	20.7	4.5	12.7
1951-52	22.0	4.9	13.7
1952-53	22.6	5.3	14.2
1953-54	23.5	5.9	15.9
1954-55	24.3	6.3	15.5
1955-56	25.5	6.9	16.5
1956-57	26.4	7.7	17.3
1957-58	29.2	8.8	19.3
1958-59	29.5	9.1	19.5
1959-60	31.5	10.2	21.2
1960-61	34.3	10.8	22.8
1961-62	34.9	12.2	23.8
1962-63	36.3	13.3	25.1
1963-64	39.9	16.5	28.6

## तालिका न० 7-5

14 से 17 वर्ष के बालकों की शैक्षिक सुविधाओं की स्थिति

वर्ष	14 से 17 वर्ष की आयु क्रम की जनसंख्या का प्रतिशत		कुल योग
	लड़के	लड़कियाँ	
1950-51	5.4	1.7	5.4
1951-52	6.1	1.8	5.1
1952-53	6.5	2.0	6.5
1953-54	6.7	2.1	6.7
1954-55	7.0	2.3	7.0
1955-56	8.0	2.8	8.0
1956-57	9.1	3.0	9.1
1957-58	9.2	3.4	9.2
58-59	9.4	3.5	9.4
59-60	10.6	3.9	10.6
60-61	11.8	4.3	11.8
61-62	19.7	4.8	19.7
1961-62	20.8	5.5	20.8
1962-63	25.0	7.3	25.0
1965-66			

उपरोक्त तालिकाओं से 11-17 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा का ज्ञान होता है जिससे यह स्पष्ट है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रती ही संस्था में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है जिसका प्रत्यक्ष रूप बालाओं पर प्रभाव पड़ रहा है। विशेष बालकों की संस्थाओं में भी बालाओं के अध्ययन, सुविधाओं आदि की व्यवस्था

यही स्थिति रही तो माध्यमिक शिक्षा से राष्ट्रीय हित की सम्भावना करना व्यर्थ है। यदि हम माध्यमिक शिक्षा से वांछित उपलब्धि प्राप्त करनी है तो केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों का यह पुनोत्त कर्तव्य है कि माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक सुविधाओं की वृद्धि की जाये जिससे शैक्षिक भविष्यकार से सभी सामान्वित हो सकें।

### 7.04 माध्यमिक शिक्षा की समस्याएँ एवं समाधान

#### Problems & Remedies of Secondary Education

भारत की वर्तमान बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए यह धारणा आवश्यक है कि हम माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं और उनके समाधान पर विचार करें तथा यह देखें कि राष्ट्र की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार भाज की माध्यमिक शिक्षा है प्रथमा नहीं। हमारे देश की भृष्टता, सफ़ाई और प्रकाशमय सविध्य माध्यमिक शिक्षा पर ही अवलम्बित करता है। माध्यमिक स्तर के पश्चात् ही व्यक्ति अपने भावी स्तर का स्वप्न साकार करता है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमने प्रजातान्त्रिक शासन-व्यवस्था की प्रवर्धना की। इस पद्धति के अनुसार ही हमने अपने विद्यार्थियों की अभिवृत्ति को परिवर्तित करना होगा और यह उत्तरदायित्व माध्यमिक शालाओं का है। इन्हीं शालाओं के माध्यम से प्रजातन्त्र की नींव को दृढ़ कर भावी महान का निर्माण करना होगा जो देश के परिवर्तित मूल्यों के अनुसार सुधमायोजित एवं संगठित नागरिकों का योगदान पर निर्भर है। परन्तु यदि हम सूक्ष्म रूप से देखने का प्रयास करें तो इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आज की माध्यमिक शिक्षा परिवर्तित सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है क्योंकि इससे हमें उस फल की प्राप्ति नहीं हो रही है जो कि अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इसका एक मात्र कारण यही है कि हमारी माध्यमिक शिक्षा में घनेको दोष विद्यमान है और इसी कारण घनेको समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं जो इस प्रकार हैं—

#### (1) पाठ्यक्रम

##### Curriculum

माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम दोषपूर्ण है। जैसा कि हम पिछले पृष्ठों में यह धारणा है कि माध्यमिक स्तर के पश्चात् जीवन-यापन करने की क्षमता का ध्यान नितान्त प्राथमिक है। परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हमारे देश में माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की वास्तविक जीवन अनुभवों से दूर रक्खा गया है और यह कारण है कि माध्यमिक कक्षा पास करने के पश्चात् भी विद्यार्थी-जन जीवन के किसी भी क्षेत्र में समायोजित नहीं हो पाते। माध्यमिक शाला में पुस्तकीय ज्ञान को ही महत्ता प्रदान की जाती है और दैनिक अनुभवों से दूर रक्खा जाता है। इस दोष के प्रति उत्तरदायी माध्यमिक शालाएँ नहीं हैं बल्कि पाठ्यक्रम निर्माता हैं जिन्हें बाल

गती बनाया कि इस समस्या का समाधान सभी हो सकता है जबकि प्रशिक्षण शिक्षा में सुधार किया जाये। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में धर्म अनुशासन प्रदान करना होना चाहिए। यह सभी सम्भव है जब कि छात्रों को अधिक से अधिक सशिक्षित मुक्ति प्राप्त की जाये और छात्रों में धर्म जाग्रत की जाये। इसके बिना यह प्रत्यक्ष आवश्यक है कि शिक्षा के सभी स्तरों में सुधार दिया जाये। जब तक यह नहीं किया जाये तब तक इस समस्या का समाधान सम्भव है।

1. Briefly there have been many ugly strikes and demonstrations—often without any justification—leading to violence, walk-out from examination halls, ticketless travel, clashes with the police and sometimes, even manhandling of teachers. . . . Urgent steps are, therefore, needed to curb these trends and to ensure that whatever else education may or may not aim at doing, it should at least strive to enable young men and women to learn and practice civilized norms of behaviour and commit themselves honestly to social values of significance. . . . Some of the remedies for student's unrest, therefore, go beyond the education system. But even if we leave them out, there are two major things that the education system itself can and must do:—

... that contribute

### (3) परीक्षा प्रणाली Examination System

परीक्षा प्रणाली के दोषों से आज सभी अवगत हैं। माध्यमिक शिक्षा के अन्त में जब असफलता मिलती है तो उसके ऊपर इसका कुप्रभाव पड़ता है और यही कारण है कि आज प्रत्येक माता-पिता अथवा अभिभावक के हृदय में परीक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में एक टीस है। आज बालक भाग्य और उसका मावी भविष्य उसकी मानसिक योग्यता पर अवलम्बित नहीं है बल्कि परीक्षाफल पर आधारित है। आज परीक्षा व्यवस्था बन गई है और बालकों के अपराधी होने का बहुत कुछ धर्म परीक्षा पद्धति को ही है। सन् 1952 से 1960 के परीक्षाकर्मों से यह स्पष्ट होता है कि सामान्यतया 48 प्रतिशत बालक प्रतिवर्ष असफल रहते हैं। तालिका नं० 7.6 से पूर्णतया स्पष्ट है।

तालिका नं० 7.6

मैट्रिक तथा समरथ परीक्षाओं का परीक्षाफल<sup>1</sup>

वर्ष	प्रविष्ट छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशत
1951-52	583,470	261,059	44.7
1952-53	724,799	331,760	46.2
1953-54	818,620	397,005	48.5
1955-56	830,001	400,014	48.2
1954-56	920,026	420,494	46.7
1956-57	1,012,309	486,764	48.1
1957-58	1,079,988	521,552	48.3
1958-59	1,175,706	530,136	45.1
1959-60	1,349,465	572,369	42.4

के नारीशिक्षण, सामाजिक, सामाजिक और मध्यमशिक्षण विकास का कोई ध्यान नहीं है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में विचार व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया था कि जो शिक्षा हमारा समाज में दी जाती है वह जीवन-तृप्त है। पाठ्यक्रम को जिन परम्परागत शिक्षालय विधियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसमें बालक को विश्व-पटलाओं का ज्ञान नहीं हो पाता और न ही सर्वांगीण विकसित हो पाती है।<sup>1</sup> यही कारण है कि बालक में मध्यमशिक्षण विज्ञान और मौलिक विचार उत्पन्न नहीं हो पाते।

भारतीय शिक्षा आयोग<sup>2</sup> ने माध्यमिक मान्य पाठ्यक्रम को उद्देशपूर्ण बनाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। पाठ्यक्रम में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं को आवश्यक बताया है—

### (1) पाठ्यक्रम में अनुसंधान

#### Research in Curriculum

पाठ्यक्रम के समाधान हेतु सर्वप्रथम व्यवस्थित अनुसंधान की आवश्यकता है

1. The education given in our schools is isolated from life. The curriculum as formulated and as presented through the traditional methods of teaching does not give the students insight into the everyday world in which they are living. When they pass out of school, they feel ill adjusted and can not take their place confidently and competently in the community.

Secondary Education Commission, 1953, p. 22

2. For upgrading the school curriculum, a number of important steps have to be taken. The more important of these have been indicated below—

(i) *Research in Curriculum*—The first is the need of systematic curricular research so that the revision of the curriculum may be worked out as a well coordinated programme of importance on the basis of the finding of experts instead of being rushed through haphazardly and in a piecemeal fashion.

(ii) *Preparation of Text Books and other Teaching Aids*—Basic to the success of any attempt at curriculum improvement is the preparation of suitable text books, teachers guides and other teaching and learning materials. These define the goals and the content of the new programmes in terms meaningful to the school, and as actual tools used by the teacher and the pupil, they lend substance and significance to the proposed changes.

(iii) *In-service Education of Teachers*—In addition to this, it is necessary to make the teacher understand the chief features of the new curriculum with a view to, developing improved teaching competence, better teaching skills, and a more sensitive awareness of the teaching-learning process in the changed situation. Accordingly, an extensive programme of in-service education consisting of seminars and refresher courses, should be organised for the teachers in the revised curriculum.

Report of the Education

जिससे विशेषज्ञों के निर्णयों द्वारा प्रचलित पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाया जा सके। आजकल बहुत से राज्यों में निरर्थक पाठ्यक्रम है जिसके कारण माध्यमिक स्तर पर शिक्षित उपलब्धियाँ प्राप्त नहीं हो पाती। इस प्रकार के अनुसन्धानों की सुविधा विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण महाविद्यालयों और राज्य शिक्षण संस्थानों में होना चाहिए। इन अनुसन्धानों में पाठ्यक्रम विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त किया जा चाहिए।

## (2) पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री एवं पाठ्य पुस्तकें

### Preparation of Text books and other Teaching Aids

पाठ्यक्रम का विकास एवं सफलता मुख्यतः अच्छी पाठ्य-पुस्तकों, अध्ययन निर्देशकों, और शिक्षण सामग्री पर आधारित है। नवीन योजना तथा उद्देश्यों का पूर्णता से ही पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना सम्भव है।

## (3) शिक्षा के अध्यापकों की शिक्षा

### In service Education of Teachers

इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम में परिवर्तन तथा अध्यापकों की शिक्षण कला विकसित करने हेतु यह आवश्यक है कि नवीन पाठ्यक्रम से अध्यापकों को परिचित कराया जाये जिससे नवीन स्थितियों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समन्वयन आसानी से हो सके। इसके लिये शिक्षकों के अध्यापकों की विचार गोष्ठी के माध्यम से शिक्षित किया जाये जिससे परिष्कृत पाठ्यक्रम से परिचित कराया जा सके।

## (2) अनुशासनहीनता

### Indiscipline

माध्यमिक शिक्षा स्तर पर छात्रों में अनुशासन की बहुत कमी है। पिछले कुछ वर्षों से छात्रों में अनुशासनहीनता के अनेकों दान प्रदर्शन किये हैं। छात्रों की हिंसा, परीक्षा में अवैधानिक कार्य, पुस्तक के साथ भजने, राष्ट्रीय सम्पत्ति की लूट, सभाओं की पीटना एवं अनेकों असामाजिक कार्य करना आज के समय का दैनिक कार्यक्रम बन गया है। आज हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि हम इस व्यवस्था का कारण क्या है? यदि ध्यान से देखा जाये तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कमी है। अनुसन्धित पाठ्यक्रम सबसे बड़ा कारण है क्योंकि वर्तमान पाठ्यक्रम छात्रों की अतिरिक्त शक्ति (Surplus Energy) तथा आधी व्यावहारिक समस्याओं की मुलमात्र में अक्षम है। इनसे विद्यार्थी असमर्थ बन जाते हैं। अतः शिक्षा प्रक्रिया में छात्रों के वैयक्तिक विकास को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान शिक्षा प्रक्रिया में छात्रों के वैयक्तिक विकास को ध्यान में रखना आवश्यक है।

इन समस्या के समाधान हेतु भारतीय शिक्षा आयोग (1986) ने सर्व



यही बताया कि इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जबकि शैक्षिक प्रक्रिया में सुधार किया जाये। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में चरित्र अनुशासन प्रदान करना होना चाहिए। यह तभी सम्भव है जब कि छात्रों को अधिक से अधिक शैक्षिक मुश्किलें प्रदान की जायें और छात्रों में रुचि जाग्रत की जाये। इसके लिये यह प्रत्यक्ष आवश्यक है कि शिक्षा के सभी स्तरों में सुधार किया जाये। जब तक यह हा नहीं किया जाये तब तक इस समस्या का समाधान सम्भव है।<sup>1</sup>

1. Briefly there have been many ugly strikes and demonstrations—often without any justification—leading to violence, walk-out from examination halls, ticketless travel, clashes with the police and sometimes, even manhandling of teachers .... Urgent steps are, therefore, needed to curb these trends and to ensure that whatever else education may or may not aim at doing, it should at least strive to establish civilized norms and social values of student's unrest, therefore, go beyond .... But even if we leave them out, there are two major things that the education system itself can and must do:—

—remove the educational deficiencies that contribute to it and

—set up an adequate consultative and administrative machinery to prevent the occurrence of such incidents.

The first of these ... of the educational process, is the heart education cultivates should ... which from within which does ... eeted Moreover, such discipline can grow ... ntrol. the pursuit of deeper goals in life, and rises out of interest and devotion to scholarship. In other words, the incentives to positive discipline have to come from the opportunities that the institution presents and the intellectual and social demands it makes on the students. .... We have also stressed the need, side by side for providing a better standard of student services. Unless this is done, a radical cure to the problem is not possible.

... What we have to strive to generate is a spirit of comradeship between teachers and students based on mutual affection and esteem and on a common allegiance to the pursuit of truth, of excellence in many directions and of the good of the society as a whole. If this spirit could be created, many of the problems of discipline which bedevil our academic life at present will become easier to solve and, will, we hope, disappear in course of time.

## (3) परीक्षा प्रणाली

## Examination System

परीक्षा प्रणाली के दोषों से आज सभी अवगत हैं। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में जब असफलता मिलती है तो उसके ऊपर इसका कुप्रभाव पड़ता है और यह कारण है कि आज प्रत्येक माता-पिता अथवा अभिभावक के हृदय में परीक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में एक टीस है। आज बासक माग्य और उसका भावी भविष्य उसकी मानसिक योग्यता पर अवलम्बित नहीं है बल्कि परीक्षाफल पर आधारित है। आज परीक्षा घबराह बन गई है और बालकों के अचराधी होने का बहुत कुछ र्थय परीक्षा पद्धति को ही है। सन् 1952 से 1960 के परीक्षाफलों से यह स्पष्ट होता है कि सामान्यतया 48 प्रतिशत बालक प्रतिवर्ष असफल रहते हैं। तालिका नं० 7.6 पूर्णतयास्पष्ट है।

तालिका नं० 7.6

मेट्रिक तथा समकक्ष परीक्षाओं का परीक्षाफल<sup>1</sup>

वर्ष	प्रविष्ट छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशत
1951-52	583,470	261,059	44.7
1952-53	724,799	337,760	46.2
1953-54	818,620	397,005	48.5
1955-55	830,001	400,014	48.2
1954-56	920,026	429,194	46.7
1956-57	1,012,309	486,761	48.1
1957-58	1,079,986	521,552	48.3
1958-59	1,175,706	530,136	45.1
1959-60	1,349,468	572,369	42.4

1. S. N. Mukerjee *Education in India To-day and Tomorrow*



परीक्षा के पश्चात् बाह्य परीक्षा का जो प्रमाण पत्र दिया उन्ने छात्र को उनी प्रगति का विवरण हो जिन विषयों में वह उत्तीर्ण हो परन्तु सम्पूर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण भवना अनुत्तीर्ण को कोई टीका दिव्यणी न हो । माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमाण पत्र के प्रतिरिक्त एक लेखा पत्र अवश्य दे जिसमें छात्र द्वारा पृथक् पृथक् विषयों में मापदण्ड का विवरण हो । यदि छात्र अपनी अधी की विकसित करना चाहे तो उसे सम्पूर्ण परीक्षा भवना पृथक् विषयों में पुनः परीक्षा देने का अवसर प्रदान करना चाहिए ।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953) ने भी शिक्षा आयोग (1968) की नीति मूल्यांकन की नवीन पद्धति पर प्रकाश डाला था, जिसके कारण मातृशिक्षा और बाह्य परीक्षाओं के सुधार के लिए कुछ समय के लिए आन्दोलन भी आया जिसके फलस्वरूप भारतीय सरकार ने 1958 में केन्द्रीय परीक्षा यूनिट की स्थापना की । इससे पिछले सात वर्षों में काफी सफलता प्राप्त हुई है । मूल्यांकन की नवीन प्रणाली से माध्यमिक शिक्षा स्तर पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । मूल्यांकन यूनिटों ने 12 राज्यों तथा एक केन्द्रीय प्रदेश में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है । परन्तु जब तक सम्पूर्ण देश के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मूल्यांकन की नवीन पद्धति को नहीं अपनायेंगे तब तक छात्रों की असफलताएँ राष्ट्रीय सम्पत्ति की हानि के रूप में होनी रहेगी । राष्ट्रीय धन को बचाने के लिए परीक्षा पद्धति में सुधार अत्यन्त आवश्यक है । शिक्षा आयोग<sup>1</sup> के अनुसार यह कार्य अत्यन्त कठिन है और नवीन साधनों को अपनाने में समय लगेगा तथा माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य और सीखने के अनुभव प्रभावित हो सकेंगे । अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के द्वारा बाह्य परीक्षा के दोषों को दूर नहीं किया गया है ।

#### (4) प्रशिक्षित अध्यापक

##### Trained Teachers

माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम की सन्तुष्टता प्रशिक्षित अध्यापकों पर ही निर्भर करती है । माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति तब तक नहीं हो जब तक उन्हें प्रशिक्षित अध्यापक ही पढ़ाते रहेंगे । यद्यपि तीन पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयत्न किये हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना

1. But the task is a stupendous one, and it will take considerable time for the new measures to make their impact on objectives learning experiences and evaluation procedures in school education. The improvements already made in the external examination by different boards have not removed all its major defects. The objectives have not yet been enlarged to include the testing of application and...



परीक्षा के पश्चात् बाह्य परीक्षा का जो प्रमाण पत्र दिया उपरने छात्र ही उसी प्रगति का विवरण हो जिन विषयों में वह उत्तीर्ण हो परन्तु सम्पूर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कोई टीका टिप्पणी न हो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमाण पत्र के प्रतिरित्त एक लेखा पत्र प्रत्येक दे जिसमें छात्र द्वारा पृथक्-पृथक् विषयों में प्राप्तांक का विवरण हो। यदि छात्र अपनी थोड़ी सी विकसित करना चाहे तो उसे सम्पूर्ण परीक्षा प्रमाण पत्र पृथक् विषयों में पुनः परीक्षा देने का अवसर प्रदान करना चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953) ने भी शिक्षा आयोग (1966) की प्रति सुझावों की नवीन पद्धति पर प्रकाश डाला था, जिसके कारण प्राथमिक और बाह्य परीक्षाओं के सुधार के लिए कुछ समय के लिए आन्दोलन भी आया जिसके फलस्वरूप भारतीय सरकार ने 1958 में केन्द्रीय परीक्षा यूनिट की स्थापना की। इसके पिछले सात वर्षों में काफी सफलता प्राप्त हुई है। मूल्यांकन की नवीन प्रणाली से माध्यमिक शिक्षा स्तर पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। मूल्यांकन यूनिटों ने 12 राज्यों तथा एक केन्द्रीय प्रदेश में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। परन्तु जब तक सम्पूर्ण देश के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मूल्यांकन की नवीन पद्धति को नहीं अपनायेंगे तब तक छात्रों की सफलताएँ राष्ट्रीय सम्पत्ति की हानि के रूप में होती रहेगी। राष्ट्रीय धन की बचाने के लिए परीक्षा पद्धति में सुधार अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षा आयोग के अनुसार यह कार्य अत्यन्त कठिन है और नवीन साधनों को अपनाने में समय लगेगा तथा माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य और सीखने के अनुभव प्रभावित हो सकेंगे। अभी एक माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के द्वारा बाह्य परीक्षा के दोषों को दूर नहीं किया गया है।

#### (4) प्रशिक्षित अध्यापक

##### **Trained Teachers**

माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम की स्थूलता प्रशिक्षित अध्यापकों पर ही निर्भर करती है। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति तब तक नहीं हो जब तक उन्हें प्रशिक्षित अध्यापक ही पढ़ाते रहेंगे। यद्यपि तीन पञ्चवर्षीय योजनाओं में शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयत्न किये हैं और चोवी पञ्चवर्षीय योजना

"the task is a stupendous one, and it will take new measures to make their impact on evaluation procedures in schools already made in the external examinations have not removed all its major defects. been enlarged to include the testing of abilities

*Education Commission, 1966, p. 243.*

में भी शिक्षकों के प्रशिक्षणार्थ गुणियाओं को बढ़ाने का अनुमान है तथा शिक्षा प्रशासनिक शिक्षा की आवश्यकता पूर्ण करने में समर्थ रहे हैं। वास्तविकता यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अध्यापकों की व्यवसायिक शिक्षा को उन्नत दृष्टि देना गया है अर्थात् विभिन्न आयोगों तथा अनेकों संयोगियों, सम्मेलनों अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए अनेकों सुभाव प्रस्तुत किये थे परन्तु इन दिनों बहुत कम कार्य हो गया है। जब तक अध्यापकों के प्रशिक्षण पर ध्यान नहीं दिया जायेगा तब तक माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊँचा उठना सम्भव है।

देश की बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था के लिए यह अत्यन्त अनिवार्य है कि विज्ञान और वाणिज्य अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाये। मात्र हमें रूप से उन छात्रों की आवश्यकता है जो विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखें। प्राथमिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, वह सभी सम्भव है अर्थात् हमारे छात्रों की प्रशिक्षण अध्यापकों से समुचित शिक्षा प्राप्त हो सके।

शिक्षा आयोग (1966) ने इसके महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा के लिए अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा का स्थूल कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। अध्यापक शिक्षा पर ध्यान देने से अधिक लाभ हो सकता है इसके लिए कम आर्थिक साधनों की आवश्यकता होती है और जिससे व्यक्तियों की शिक्षा को सुधारा जा सकता है।<sup>1</sup>

इसके सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित दोष बताये हैं—

- (i) पाठ्यक्रम में सजीवता एवं वास्तविकता का अभाव,
- (ii) प्रशिक्षण महाविद्यालयों में योग्य शिक्षकों का अभाव,
- (iii) परम्परागत प्रशिक्षण का होना,
- (iv) शिक्षण विधियों की वर्तमान शैक्षिक चर्चों की प्रासंगिकता

(v) पाठ्यक्रम का शिक्षा समस्याओं से सम्बन्ध न होना।  
सुझाव हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये हैं—

- (i) अध्यापक शिक्षा में सुधार,
- (ii) प्रशिक्षण काल में अभिवृद्धि,
- (iii) प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रमों में सुधार,

1. A sound programme of professional education is essential for the qualitative improvement of education in teacher education can yield very rich dividends the financial resources required are small when measured the resulting improvements in the education of millions.

Report of the Education Commission

(iv) प्रशिक्षण महाविद्यालयों का विश्वविद्यालयों से सम्बन्ध,

(v) पाठ्यक्रम का शिक्षा समस्याओं से सम्बन्ध ।

'अध्यापक शिक्षा' पर हम पृथक रूप से किसी अध्याय में विस्तृत चर्चा करेंगे परन्तु यहाँ केवल इतना ही स्पष्ट करना है कि माध्यमिक शिक्षा को सार्थकता प्रदान करने लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की नितान्त आवश्यकता है ।

(5) एकव्यता का अभाव

*Lack of uniformity*

माध्यमिक शिक्षा स्तर में एक रूपता का अभाव है । उदाहरणार्थ गुजरात, महाराष्ट्र का कुछ भाग, उत्तर प्रदेश आदि ने उच्चतर माध्यमिक स्तर को स्वीकार नहीं किया । जबकि महाराष्ट्र, बिहार, मध्यप्रदेश, हैदराबाद, राजस्थान आदि ने उच्चतर माध्यमिक स्तर को स्वीकार किया है ।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953) ने माध्यमिक शिक्षा की निम्नलिखित व्यवस्था की सिफारिश की :—

(i) मिडिल अथवा जूनियर माध्यमिक अथवा सीनियर ब्रिटेन स्तर जिसका कार्यकाल तीन वर्ष होना चाहिए,

(ii) उच्चतर माध्यमिक स्तर जिस की समयावधि चार वर्ष होनी चाहिए.<sup>1</sup>

उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इण्टरमीडिएट स्तर को समाप्त करने की सिफारिश की ।<sup>2</sup>

माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझावों पर विचार करने के लिए भारतीय सरकार ने राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्डों से विचार-विमर्श किया । सन् 1955 में केन्द्रीय शिक्षा समाहरण समिति तथा उपकुलपतियों के सम्मेलन ने निम्नलिखित शिक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया—

(i) आठ वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा—इस स्तर में सामान्य रूप से 6 से 14 वर्ष के बालक होंगे ।

(ii) तीन वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा—जिसमें सामान्य रूप से 14 से 17 वर्ष के बालक होंगे ।

(iii) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात् तीन वर्ष की विश्वविद्यालय शिक्षा ।

1 *Secondary Education Commission, 1953, p. 33*

2 *Ibid p. 32*



मुख्य लोगों का विचार है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को ग्यारह वर्ष करने से शिक्षा के स्तर में कमी आयेगी इसीलिए माध्यमिक स्तर को बारह वर्ष का ही रखा जाये। राज्य शिक्षा मंत्रियों, उपकुलपतियों तथा अन्य शिक्षा विद्गों का सम्मेलन<sup>1</sup> जो नई दिल्ली में 10-12 नवम्बर, 1963 को हुआ निम्नलिखित सुझाव दिये :—

‘देश में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति को देखते हुए गुणवत्तात्मक रूप से शिक्षा की स्थिति को सुधारने हेतु, अरुद्धों बाह्य पुस्तकों और प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता के प्रतिरिक्त यह अत्यन्त आवश्यक है कि सम्मेलन स्तरों में एक लयता हो अतः सम्मेलन निम्नलिखित बिन्दुओं पर सहमति प्रगट करता है—

(i) देश को 12 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य की ओर अग्रसर होना चाहिए, यद्यपि अधिक एवम् मानव शक्ति की दृष्टि से सभी राज्यों में निश्चित अवधि में यह सम्भव नहीं हो सके ;

(ii) देश में माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के पश्चात् इन्टरमीडिएट परीक्षा का स्तर प्राप्त करना चाहिए।

(iii) विश्वविद्यालयों में  
सामान्यतः 17 वर्ष

— — — — —

(iv) सम्पूर्ण देश में प्रथम स्नातक कोर्स 3 वर्ष का होना चाहिए ।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से हमारा मन्तव्य यह है कि कुछ शिक्षा शास्त्रियों का विचार है कि माध्यमिक स्तर को बारह वर्ष के स्थान पर बारह वर्ष का कर दिया जाये, इसके विपरीत कुछों का विचार है कि बारह वर्ष करना निरर्थक है और धार्मिक दृष्टि से अनुचित है ।

शिक्षा आयोग (1966) ने इन सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं:—

- (i) एक वर्ष से तीन वर्ष तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा,
- (ii) पाठ वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा जिसमें प्रारम्भिक प्राथमिक स्तर चार अथवा पाँच का हो और उच्चतर प्राथमिक स्तर तीन अथवा दो वर्ष का हो ।
- (iii) सामान्य शिक्षा के रूप में उच्चतर माध्यमिक स्तर को दो वर्षों का रखा जाये अथवा एक से तीन वर्षों तक व्यावसायिक शिक्षा ।
- (iv) माध्यमिक शालाएँ दो प्रकार की हों, उच्च शालाएँ जिसका 10 वर्ष का शिक्षाक्रम हो और उच्चतर माध्यमिक शाला जिसमें 11 अथवा 12 वर्ष का शिक्षाक्रम हो ।

कहने का तात्पर्य यह है कि माध्यमिक स्तर को एकरूपता प्रदान करना निम्नलिखित आवश्यक है, चाहे वह दस वर्षों का हो अथवा बारह वर्षों का । माध्यमिक शिक्षा कितने वर्ष की हो—यह एक विचारप्रश्न प्रश्न है ? शिक्षा आयोग<sup>1</sup> की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आयोग ने भी समस्त देश में एकरूपता पर बल दिया है ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा की प्रगति, नवी सम्भावित विकास, समस्याएँ आदि का विचार करने के पश्चात् अब हमें यह विचार करना

---

1. 'The Commission has shown great wisdom in keeping the first degree stage at the present 5 years — " " The abolition of the one year Pre-University course is the most urgently needed reform but its replacement by the 2 year Higher Secondary course will not yield the expected benefit if this is done in secondary course which has already 111 classes. Even from the psychological point it is wrong to have a mixed age group from 8 to 15 in one institution. We would all have welcomed a clear and forthright recommendation that this should be entrusted to independent junior colleges or to existing under graduate colleges rather than to secondary schools.

ऐ कि राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा की क्या विशेषताएँ होनी चाहिए। प्रागिर उम शिक्षा का क्या साम जो विद्यालयों में राष्ट्रीय चरित्र निमित्त न कर सके घोर देश के विद्यार्थी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार अपना योग प्रदान कर सकने में समर्थ हों। अतः स्वतन्त्रता के इतने वर्षों के पश्चात् हमें माध्यमिक शिक्षा की उन विशेषताओं पर अवश्य विचार करना चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर के लिए आवश्यक है।

### 7.05 राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा की विशेषताएँ

#### Characteristics of Secondary Education at National Level

राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का सम्बन्ध शक्तियों के जीवन, उनकी आवश्यकताओं एवं महत्वकांक्षाओं से होना चाहिए। इसके लिए शिक्षा को साधन के रूप में स्वीकार करना होगा। हमारे राष्ट्रीय विकास की गति के क्षीण होने का कारण यह है कि वर्तमान शिक्षा के उद्देश्य एवं वाटवक्त्र राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। यही कारण है कि हमें चारों घोर निराशा, प्रमत्तोप, वृथारूपता और आक्रोश दृष्टिगत हो रहा है अतः यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा की विशेषताओं के विषय में विचार करें।

संक्षेप में राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा की निम्नलिखित होनी चाहिए :—

#### (1) शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता पर बल

##### Emphasis on National unity by Education

राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा की सर्वप्रथम विशेषता यह होनी चाहिए कि जो समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सके। मूलतः केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री श्री सागला ने<sup>1</sup> राज्य शिक्षा मन्त्रियों के सम्मेलन में शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए कहा था कि शिक्षा को राष्ट्रीय एकता पर बल देना चाहिए और समस्त भारतीय शिक्षा संस्थाओं को जातीयता और साम्प्रदायिकता की भावना को दूर करना चाहिए।

1. "What do I mean when I talk of a national system of education. ? In the first place I think of education that emphasises the unity of our country. I think of all - Indian institutions - the more the better for our country—institutions which will get over differences of caste and communities"

माध्यमिक शिक्षा स्तर में छात्र एवम् छात्राओं की भावु इस प्रकार की होती है जबकि उनमें अन्धे संस्कारों को मरा जा सकता है। यही वह समय है जिसमें भावी जीवन की आदतों का निर्माण होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस भावु का विशेष महत्व है घत यह आवश्यक है कि इस भावु में राष्ट्रीय चरित्र की भावना प्रत्येक विद्यार्थी में हो। यही हमारे देश की सबसे पहली और महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

## (2) शिक्षा द्वारा प्रजातान्त्रिक भावनाओं का विकास

### Development of Democratic Feelings by Education

माध्यमिक शिक्षा अधिकांश नागरिकों के लिए शैक्षिक जीवन का अन्त होता है। राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह नितास्त आवश्यक है कि हमारे प्रत्येक विद्यार्थी में आदर्श नागरिक-मुलुम गुणों का विकास प्रजातान्त्रिक भावनाओं पर आधारित हो। प्रजातान्त्रिक मूल्यों की समिवृद्धि केवल माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव है। शिक्षा द्वारा बालकों में चिन्तन करने की शक्ति, नवीन विचारों को ग्रहण करने की शक्ति, सहनशीलता, न्याय करने की मांग, देश भक्ति आदि अनेक गुणों का विकास किया जा सकता है।

## (3) शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय पद्धति का विकास

### Emergence of National System by Education

माध्यमिक शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय पद्धति का विकास होना आवश्यक है। शिक्षा में यह बल होना चाहिए जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति यह कह सके कि भारतीय शिक्षा पद्धति का भी अस्तित्व है। ब्रिटिश शिक्षा-पद्धति, अमेरिकन शिक्षा पद्धति अथवा सोवियत शिक्षा पद्धति का अन्तर आसानी से देखा जा सकता है। यह क्या है जो हमें उस अन्तर को स्पष्ट करने में सहायक होता है? क्या हम यह कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा पद्धति भी अपनी भिन्नता के कारण अस्तित्व रखती है?"<sup>1</sup>

इस प्रश्न का उत्तर उस समय मिन सकता है जबकि हमारी शिक्षा राष्ट्रीय पद्धति का विकास कर सके।

1. "Though we can not precisely define the term, we can recognise what it stands for. For example, we can readily distinguish the British System of education from the American system or the soviet system of education from both. What is it that gives them their hall mark, their distinction. ? Can we say that the educational system of India carries its own distinction on its own signature. ?"

Raja Roy Singh, *Emerging Problems of Indian Education*, p 64.



## विश्वविद्यालय प्रश्न

### University Questions

(1) Trace the development of Higher Secondary Education in India. What special problems confront the educationists in organizing Secondary Education.

(2) The Secondary Schools are the backbone of a country's national life, from here are trained the nation's potential leaders and experts in all walks of life. How would you like to reorganize the present system of Secondary Education to fulfil this purpose ?

(B. T., 1955)

(3) What in your opinion are the major problems of Secondary Education in India and in Rajasthan ? What attempts have been made in recent times to tackle them ? To what extent do you agree with the solutions suggested ?

आपके विचार में भारत में तथा राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा की कौन से प्रमुख समस्याएँ हैं ? हाल ही में उनके समाधान के क्या क्या प्रयत्न किये गये हैं ? उन दिये गये सुझावों से आप कहाँ तक सहमत हैं ?

(राजस्थान विश्वविद्यालय, 1967)

(4) With reference to the nature and type of the social order that we envisage for the future, What in your opinion are the new needs and requirements of the nation to which secondary education should be geared ?

भविष्य के सामाजिक स्वरूप की कल्पना करते हुए विवरण कीजिए कि आपके विचार में राष्ट्र की कौन सी नवीन आवश्यकताएँ हैं जिनके अनुकूल माध्यमिक शिक्षा को होना चाहिए ?

(राजस्थान विश्वविद्यालय, 1966)

(5) Estimate the effect of Reorganisation of Secondary Education in Rajasthan. What suggestions do you have to offer for complete success in the scheme ?

(Rajasthan University, 1962)

(6) Comment upon the view that the present system of Secondary Education in India is the gift of the British regime and needs drastic changes. What modifications would you like to introduce to suit our present needs ?

भारत में माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान प्रणाली ब्रिटिश राज्य की देन थीर उसमें परिवर्तनों की आवश्यकता है। इस कथन की विवेचना कीजिए प्राधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप आप कौन से परिवर्तन करना चाहेंगे ?

(B. T., 1951)

(7) There is no standard definition of Secondary Education for India. In terms of what would you define secondary education and secondary stage of education ? If the different states are permitted to adopt their own definitions with modifications, what variations would you permit in the general definition suggested by you ?

(Agra University, 1956)

## अध्याय आठ

### Chapter Eight

#### पाठ्यक्रम का विविधीकरण

#### *Diversification of Curriculum*

#### अध्ययन बिन्दु

#### Learning Points

- 8.01 पाठ्यक्रम के विविधीकरण हेतु प्रयत्न  
Efforts for Diversification of Curriculum
    1. भारतीय शिक्षा आयोग (1882)
    2. हर्टॉग समिति (1929)
    3. सप्रू कमेटी (1934)
    4. बुड-ऐबट रिपोर्ट (1936-37)
    5. आचार्य नरेन्द्र देव समिति (1939)
    6. सार्जेंट रिपोर्ट (1944)
    7. माध्यमिक शिक्षा पुनर्संगठन समिति (1952-53)
    8. माध्यमिक शिक्षा आयोग (1962-63)
  - 8.02 पाठ्यक्रम का विविधीकरण क्यों ?  
Why Diversification of Curriculum ?
    1. वैयक्तिक भिन्नता
    2. सामाजिक परिवर्तन
    3. विद्यार्थियों की आवश्यकता हेतु
    4. राष्ट्रीय उत्थान हेतु
  - 8.03 पाठ्यक्रम के विविधीकरण के पक्ष में विचार  
Views in Favour of Diversification of Curriculum
-



पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण  
DIVERSIFICATION  
OF  
CURRICULUM

CURRICULUM

साधुनिक समय में माध्यमिक शिक्षा का सबसे बड़ा दोष उतका है। मात्र की प्रगति, ज्ञान का विस्तार और नवीन विचारधाराओं के विकास आवश्यक हो गया है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में वांछित परिवर्तन किये जायें। माध्यमिक स्तर पर सुधार किया जा सके। स्वस्थता प्राप्ति के पश्चात् स्थिति को सुधारने के लिए यह अनुभव किया गया कि माध्यमिक शिक्षा क्रम में परिवर्तन लाया जाये जिससे देश का सामाजिक, राजनैतिक, धर्म-आर्थिक विभाग हो सके और सभी भागों नागरिक माध्यमिक स्तर तक के पश्चात् देश की प्रगति में अपना योगदान कर सकें। विविध प्रकार के प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि बापकों की समीक्षाओं और अनुसार शिक्षा प्रदान की जाये इससे परिणामस्वरूप ही पाठ्यक्रम में विचारधारा प्रवाहित हुई। भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1936 द्वारा शिक्षा बोर्डों की नियुक्ति की जिससे माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाया जा सके। स्वस्थता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा बोर्डों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा में सुधार लाया जा सके।

## 8.01 पाठ्यक्रम के विविधीकरण हेतु प्रयत्न Efforts for Diversification of Curriculum

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व एवं पश्चात् पाठ्यक्रम के विविधीकरण हेतु निम्नलिखित प्रयत्न हुए—

### (1) भारतीय शिक्षा आयोग (1882)

Indian Education Commission (1882)

भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम शिक्षा की सम्पूर्ण समस्या पर विचार सन् 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा किया गया। आयोग ने सुझाव दिया कि परम्परागत पाठ्यक्रम द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास नहीं है और प्रास्तुत पाठ्यक्रम से आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। आयोग ने पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित करने का सुझाव दिया—

(i) साहित्यिक पाठ्यक्रम

(ii) व्यावसायिक या औद्योगिकीकरण सम्बन्धी पाठ्यक्रम

### (2) हार्डिंग समिति (1929)

Harding Committee (1929)

इस समिति ने भारतीय शिक्षा आयोग के पाठ्यक्रम सम्बन्धी सुझावों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम के औद्योगिकीकरण सम्बन्धी उद्देश्य पर विचार किया। समिति ने सुझाव दिया कि विहित स्तर का पाठ्यक्रम संशुद्धित है जिससे औद्योगिकीकरण का कार्य नहीं कर सकता। अतः विहित स्तरों के पाठ्यक्रम को छोड़ कर हाई स्कूल की शिक्षा में औद्योगिक एवं व्यावसायिक विषयों का प्राधान्य दिया जाये। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में इस प्रकार के संशुद्धित उद्देश्य आये जिससे विद्यार्थियों का भविष्य जीवन सुलभ हो सके और यह आवश्यक है कि तकनीकी और औद्योगिक सामान्य को भी आये।<sup>1</sup>

### (3) सप्टे कमिटी (1934)

Sept Committee (1934)

यू० ए० प्रान्त की सरकार ने सन् 1934 में सर हेनरी सप्टे की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि माध्यमिक शिक्षा स्तर पर विद्यार्थियों का एक मात्र उद्देश्य औद्योगिकीकरण

1 The diversion of more boys to industrial and commercial careers at the end of the middle stage, for which provision should be made by alternative courses in that stage, preparatory to instruction in technical and industrial schools.

करना मान रह गया है और इसमें उनके जीवन की वास्तविकताओं का कोई सम्बन्ध नहीं है। जिससे बेकारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस समस्या का केवल एक ही उपाय है और वह यह कि माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी उच्च शिक्षा की ओर भी अग्रसर सकें और व्यावसायिक दक्षता भी प्राप्त कर सकें।<sup>1</sup>

#### (4) वुड-ऐबट रिपोर्ट (1936-37)

Wood-Abbot Report (1936-37)

वुड और ऐबट ने तरकामीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था की जाँच की थी बेकारी की समस्या के समाधान स्वरूप शिक्षा के पुनर्संरचना की आवश्यकता पर बतौर दिया। सामान्य शिक्षा के मध्यम में पाठ्यक्रम की विविधता पर बल देते हुए प्रभाव दिया गया कि प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाया जाये और पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर वास्तविक जीवन की दक्षियों और अभिवृत्तियों का ध्यान रखा जाये। सामान्य स्तरों का पाठ्यक्रम सामान्य आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर कला एवं हस्तकला की शिक्षा का प्रवर्धन होना चाहिए।

रिपोर्ट में व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया और इसके माध्यम से निम्नलिखित सुझाव दिये गये :—

- (i) देश की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यावसायिक शिक्षा का विकास होना अनिवार्य है।
- (ii) व्यावसायिक शिक्षा का पूर्ण होना आवश्यक अनिवार्य है धनः व्यावसायिक शिक्षा के साथ सामान्य शिक्षा भी होनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा का प्रारम्भ कुछ सामान्य शिक्षा के पश्चात् होना चाहिए।
- (iii) व्यावसायिक शिक्षा के विकास हेतु उद्योगपतियों को सहयोग करनी चाहिए।

1. In situation like this the real remedy is to provide diversified courses of study at the secondary stage and to make that stage more practical and complete in itself and more closely related to the vocational requirements of different types of studies. At the secondary stage, side by side, with the general courses being taught in the university there should be parallel courses offering instruction in technical, commercial, industrial

(iv) व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार हेतु प्रत्येक प्रान्त में व्यावसायिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड होना चाहिए जो कुटीर उद्योगों, कपड़ा उद्योग तथा इन्जीनियरिंग की शिक्षा हेतु व्यवस्था करे।

(v) वाणिज्य की प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में बैंकरीक विषय बनाया जाये।

(vi) विभिन्न उद्योगों की शिक्षा हेतु पालीटेक्निक शालाएँ खोली जायें।

(vii) दो प्रकार की व्यावसायिक शालाएँ खोली जायें—

1. जूनियर व्यावसायिक शालाएँ 2. सीनियर व्यावसायिक शालाएँ

उपरोक्त सुझावों से स्पष्ट है कि सामान्य एवम् व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव अनेकानेक महत्वपूर्ण थे और भारत की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप थे। पाठ्यक्रम को विविध स्वरूप प्रदान किया गया था।

(5) आचार्य नरेंद्र देव समिति (1939)

Acharya Narendra Deo Committee

समिति ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु संश्लेषिक सुविधाओं के प्रसार के लिए सुझाव दिये। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैयक्तिक अभिनता को आचार मानकर पाठ्यक्रम में विभिन्नता लाने की आवश्यकता पर बल दिया और पाठ्यक्रम को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने का सुझाव दिया—

सामान्य वर्ग

(i) साहित्यिक

(ii) कलात्मक

(iii) वाणिज्य

विज्ञान वर्ग

(i) व्यावसायिक श्रम

(ii) टेक्नालाजी

(iii) वैज्ञानिक पाठ्यक्रम

समिति ने सुझाव दिया कि पाठ्यक्रम का विनियोजन किया जाये और तत्कालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाये।

(6) सार्जेंट रिपोर्ट (1944)

Sargent Report (1944)

रिपोर्ट में हाई स्कूलों को दो भागों में विभाजित किया गया—

(i) साहित्यिक हाईस्कूल (Academic High School)

(ii) शारीरिक हाईस्कूल (Technical High School)

साहित्यिक हार्ड स्कूलों में सामान्य विषयों के अध्ययन की व्यवस्था होनी थी। प्राविधिक हार्ड स्कूलों में काष्ठ कला, धातु कला, इन्जीनियरिंग एवम् वाणिज्य सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था होनी। रिपोर्ट में स्पष्टतः कहा गया कि पाठ्यक्रम प्रत्येक दशा में परिस्थितियों के अनुसार विविध होना चाहिए न कि विश्वविद्यालयों के लिए अथवा परीक्षा मात्र के लिए।<sup>1</sup>

### (7) माध्यमिक शिक्षा पुनर्संरचना समिति (1952-53)

Secondary Education Reorganisations Committee (1952-53)

समिति ने पुनः आचार्य सरेंद्र देव की अध्यक्षता में पाठ्यक्रम की व्यावहारिकता के लिए सुझाव दिये। पाठ्य विषयों के चयन हेतु विद्यार्थियों के लिए मार्ग दर्शन आवश्यक बताया। समिति ने बहुउद्देशीय ज्ञानार्थों की स्थापना के लिए भी सुझाव दिये।

### (8) माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53)

Secondary Education Commission (1952-53)

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण हेतु एक स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की। आयोग ने विचारानुसार माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम छात्रों की योग्यता एवम् अभिरुचियों के आधार पर बनाया जाये। इसके लिए पाठ्यक्रम का विविध होना अत्यन्त आवश्यक है। अतः ये पाठ्यक्रम की रूप रेखा निम्नलिखित प्रकार प्रस्तुत की गई—

#### अनिवार्य विषय

1. मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा अथवा सानुभाषा तथा शास्त्रीय भाषा का विधित पाठ्यक्रम।

2 निम्नलिखित भाषाओं में से एक भाषा :—

(i) हिन्दी (उन विद्यार्थियों के लिए जिनको मातृभाषा हिन्दी नहीं है)

(ii) प्रादेशिक अथवा शास्त्रीय (उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने विशिष्ट स्तर तक अध्ययन नहीं किया है।)

(iii) उच्च अथवा शास्त्रीय

1. The curriculum in all cases should be as varied as circumstances permit and should not be unduly restricted by the requirements of universities or examining bodies.

Sargent Report, p. 27

(iv) कोई भारतीय भाषा (हिन्दी के अतिरिक्त)

(v) प्राधुनिक विदेशी भाषा (अंग्रेजी के अतिरिक्त)

(vi) एक शास्त्रीय भाषा

यम दो वर्षों के लिए समाज विज्ञान का सामान्य पाठ्यक्रम ।

यम दो वर्षों के लिए महिला तथा सामान्य विज्ञान ।

अनलिखित में से कोई एक शिल्प ।

(i) बटाई बुनाई

(ii) काष्ठ कला

(iii) धातु कार्य

(iv) बागवानी

(v) सिलाई

(vi) कढ़ाई

(vii) मुद्रण

(viii) प्रतिकृपण

प्रत्येक विषय

निम्नलिखित सात समूहों में से एक समूह के तीन विषयः

मानव विज्ञान (Humanities)

विज्ञान (Science)

प्राविधिक (Technical)

वाणिज्यिक (Commercial)

कृषि (Agriculture)

सूक्ष्म कलाएँ (Fine Arts)

गृह विज्ञान (Domestic Science)

योग ने उत्कृष्टतम परिस्थितियों के अनुसार एक आदर्श विविध पाठ्य  
क्रम प्रस्तुत की थी । पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण अनिवार्य  
रूप से आधारित था ।

प्रकार हम देखते हैं कि माध्यमिक स्तर पर घने-घायो-घोर  
ने पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण हेतु सुझाव दिये । निम्न प्रयोग  
56) ने पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण पर बल नहीं दिया है । यद्यपि प्रयोग

विद्युत विद्युत के लिए इसी पुस्तक का अध्याय छटा देखिये ।

ने गृहमार्गक शिक्षाओं, कार्पोरुमों, और माध्यमिक शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाया है तथापि विविध पाठ्यक्रम की रूप रेखा को प्रभावित नहीं किया गया है। सम्भवतः माध्यमिक ने पाठ्यक्रम के विभिन्नोकरण को महत्व प्रदान नहीं किया जिसकी नितांत आवश्यकता थी।

## 8.02 पाठ्यक्रम का विभिन्नोकरण क्यों ?

### *Why Diversification of Curriculum ?*

प्रश्न: यह प्रश्न पूछा जाता है कि पाठ्यक्रम का विभिन्नोकरण क्यों हो ? यद्यपि हम इन प्रश्न का उत्तर उपरोक्त माथों और समितियों के सुझावों के प्राथमिक रूप से पा सकते हैं तथापि विषय के महत्वपूर्ण होने के कारण यह आवश्यक कि इसका विशद विश्लेषण किया जाये। सुविधा की दृष्टि से इन प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर दिया जा सकता है—

### (1) वैयक्तिक भिन्नता

#### *Individual Differences*

वैयक्तिक भिन्नता के कारण यह नितांत आवश्यक है कि विविध पाठ्यक्रम की व्यवस्था हो। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सव्यवहारिक विकासों के कारण प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होता है। सभी विद्यार्थियों की क्षमता और अभिवृत्ति भिन्न होती है। किसी विद्यार्थी की साहित्य के प्रति जागरूकता होती है तो किसी की विज्ञान के प्रति। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी विद्यार्थियों में कोई न कोई विलक्षणता अवश्य होती है—और यदि हम इस आधारभूत सिद्धान्त को भी स्वीकार करते हैं तो पाठ्यक्रम की विभिन्नता को भी स्वीकार करना चाहिए।

### (2) सामाजिक परिवर्तन

#### *Social Change*

शिक्षा का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों से वातावरण के प्रति समायोजन कराना मात्र ही नहीं है बल्कि उसमें वांछित सामाजिक परिवर्तन करने की क्षमता प्रदान करना भी है। आज जब हम अन्य प्रगतिशील देशों की ओर देखते हैं तो हमें आभास होता है कि हम उनसे कितने बंधे पिछड़े हुए हैं। इस पिछड़ेपन का प्रमुख कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था की दुर्बलता है जो शिक्षा व्यवस्था घरेलू छोड़कर गये थे उसमें अभी तक बहुत कम अंतर आया है, और इसी का कारण है कि हम अभी तक प्राच्य-व्यवस्थानुसार प्रगति नहीं कर पाये हैं। यदि हमें प्रगति करनी है तो देश की घाते वाली रीढ़ों के लिए इस प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था बनानी होगी जिसमें उनकी अनुसार शिक्षा प्रदान की जा सके। यह सभी सम्भव है कि माध्यमिक शिक्षा के लिए हम जागरूक हों और पाठ्यक्रम में समस्त दशाओं की उपस्थिति करने में

समय हो सकें जिनसे सभी नागरिकों को लाभ होने की सम्भावना हो। अतः पाठ्यक्रम का विभिन्नोद्देश्य करना आवश्यक है।

### (3) विद्यार्थियों की आवश्यकताओं

#### For the Needs of Students

पाठ्यक्रम के विभिन्नोद्देश्य से विद्यार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति होती है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार हमारी माध्यमिक शालाएँ एक मार्गीय नहीं होनी चाहिए बल्कि उनके अन्दर वैश्विक कार्यक्रमों की विविधता होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों की विभिन्न रुचिधृति, रुचियों और योग्यताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान की जा सके तथा अनिवार्य शिक्षा की समाप्ति तक उनमें दक्षता प्राप्त हो सके। शालाओं में अधिक व्यापक पाठ्यक्रम की मुविधा होनी चाहिये जिसमें सामान्य और व्यावसायिक विषय हों और विद्यार्थियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विषयों को चुनने के अवसर प्राप्त होने चाहिए।<sup>1</sup> कहने का सरल यह है कि विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम की व्यवस्था का होना मनोवैज्ञानिक और वैश्विक आधारस्वरूप नितान्त आवश्यक है।

### (4) राष्ट्रीय उत्थान हेतु

#### For National Prosperity

सम्पूर्ण शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय उत्थान हेतु वैश्विक अवसर प्रदान करना है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा का तो यह निश्चित उद्देश्य है कि इसके द्वारा राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सभी प्रकार के वांछित नागरिकों का निर्माण हो सके। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने राष्ट्रीय जीवन में माध्यमिक शिक्षा के उत्तरदायित्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वास्तव में राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक चरण-कला, विज्ञान, उद्योग और वाणिज्य आदि के लिए समस्त देश को कुशल नेता प्रदान करने का निश्चित कार्य माध्यमिक शिक्षा का ही है। वर्तमान एक पक्षीय वैश्विक व्यवस्था से नेतृत्व प्राप्त होना सम्भव नहीं है और इसीलिए पाठ्यक्रम का विभिन्नोद्देश्य आवश्यक है।<sup>2</sup> अतः राष्ट्रीय उत्थान हेतु हमें सभी प्रकार के व्यक्तियों की

1. ———— That our secondary schools should no longer be 'single track' institutions but should offer a diversity of educational programmes calculated to meet varying aptitudes, interests and talents which come into prominence towards the end of the period of compulsory education. They should provide more comprehensive courses which will include both general and vocational subjects and pupils should have an opportunity to choose from them according to their needs

*Report of the Secondary Education Commission, 1953, p. 38.*

2. In fact it is the special function of Secondary Education to provide the country with the second line of its leaders in all



आवश्यकता है जो अपनी पूर्ण क्षतियों में मनायोग्य सहयोग प्रदान कर सकें। तब तक समाप्त है जब तक पाठ्यक्रम का निश्चित स्वरूप न हो।

### 8.03 पाठ्यक्रम के विविधीकरण के पक्ष में विचार

#### Views in Favour of Diversification of Curriculum

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं के आधार पर यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रत्येक विद्यार्थी की जीवन की वास्तविकताओं के समीप का ही उत्तरदायित्व है। हमारी शिक्षा का यह उद्देश्य प्रमुख हो रहा है कि विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान की ओर उन्मुख कर दिया जाता है। इसका विकास एक पक्षीय हो जाता है और वास्तविक जीवन की अनुभूति रहने के कारण वह अपने भावी जीवन को एक अपरिवर्तित की भाँति पाठ्यक्रम के जीवन की वास्तविकताओं से शून्य शिक्षा प्राप्त हुई है।

यदि हमें वास्तव में अपनी भावी वाली पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त कर देश की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करना है तो निरर्थक, संकुचित और पाठ्यक्रम के रचना पर वास्तविक, विस्तृत और सारगर्भित पाठ्यक्रम बनाने होंगे, जिसका आधार विद्यार्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति, योग्यता, शारीरिक विकास, रुचियाँ और अभिवृत्तियाँ होंगी। हमें एक ऐसा शिक्षार्थी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जो उनके जीवन में पूर्णता, वास्तविक भावी जीवन का कार्यक्षेत्र, राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार बसत भागद्वारा गुण और कर्तव्य परामर्श आदि को विकसित करने में सहाय और सभी क्षतियों को विकसित कर सम्बुद्धि स्थापित करने का निर्माण करने में हो सके। यह तभी सम्भव है जबकि हम अपने पाठ्यक्रम में विविधता लान सन्तति के लिए अधिकाधिक शैक्षिक अवसर प्रदान कर सकने में समर्थ हो स

## ग्रन्थ - सूची

### Bibliography

1. Bobbitt J. Franklin,  
*The Curriculum of Modern Education*, Mc Graw Hill Book Co., Inc., New York, 1911.
  2. Giles, H. H. & others,  
*Exploring the Curriculum*, Progressive Education Association, Harper and Bros., New York, 1941.
  3. Gwynn, J. Minor,  
*Curriculum Principles and Social Trends*, The Macmillan Co., New York, 1929.
  4. Harap & Others,  
*The Changing Curriculum*, Appleton Century Co., New York, 1937.
  5. *Report of the Secondary Education Commission*, Government of India, Ministry of Education, 1953.
  6. *Report of the Secondary Education Reorganization Committee*, Uttar Pradesh, Superintendent, Printing and Stationary, U. P., 1953.
  7. Smith, Othanel, William O. & Others,  
*Fundamentals of Curriculum Development*, World Book Co., New York, 1950.
-

आवश्यकता है जो अपनी पूर्ण क्षतियों से यथायोग्य सहयोग तब तक असम्भव है जब तक पाठ्यक्रम का विविध स्वरूप न।

### 8.03 पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण के पक्ष में विचार

#### *Views in Favour of Diversification of Curriculum*

उपरोक्त समस्या बिन्दुओं के आधार पर यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को जीवन की वास्तविकताओं के समीप लाना ठीक का ही उत्तरदायित्व है। हमारी शिक्षा का यह सत्रसे प्रमुख दोष रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान की ओर उन्मुख कर दिया जाता है। इससे शिक्षा का विकास एक पक्षीय हो जाता है और वास्तविक जीवन की अनुभूतियों से वंचित रहने के कारण वह अपने भावी जीवन को एक अपरिचित की भाँति पाता है जोकि उसे जीवन की वास्तविकताओं से शून्य शिक्षा प्राप्त हुई है।

यदि हम वास्तव में अपनी जाने वाली पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त करना है और देश की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करना है तो निरर्थक, लक्षुधित और पुस्तकीय पाठ्यक्रम के स्थान पर वास्तविक, विस्तृत और सारगर्भित पाठ्यक्रम की आवश्यकता होगी, जिसका आधार विद्यार्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति, मानसिक योग्यता, शारीरिक विकास, रुचियाँ और क्षमकृतियाँ होंगी। हमें एक ऐसा पाठ्यक्रम बालकों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जो उनके जीवन में पूर्णता, वास्तविक भावी जीवन का कार्यक्षेत्र, राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार मानसिक गुण और कर्तव्य परापूर्णाता आदि को विकसित करने और सभी क्षतियों को निरमिल कर सम्पुर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करे। यह सभी सम्भव है जबकि हम अपने पाठ्यक्रम में शिक्षा के विभिन्न अधिकाधिक शैक्षणिक अवसर प्रदान कर सकने में

## अध्याय नौ

### Chapter Ninth

माध्यमिक स्तर पर निर्देशन व समुपदेशन,  
पाठ्य-पुस्तकें, शिक्षक निर्देशिकाएँ और शिक्षण सामग्री

*Guidance & Counselling, Text Books, Teachers  
Guides and Instructional Material at Secondary Stage*

#### अध्ययन बिन्दु

#### Learning Points

#### \* 9.01 निर्देशन व समुपदेशन

##### Guidance & Counselling

निर्देशन सेवाओं की वर्तमान स्थिति

1. शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन का केन्द्रीय कार्यालय
2. शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के राजकीय कार्यालय
3. माध्यमिक शालाओं में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन  
माध्यमिक शिक्षा आयोग (1963) के निर्देशन एवं समुपदेशन  
हेतु मुझाव  
शिक्षा आयोग (1966) के निर्देशन एवं समुपदेशन हेतु मुझाव

#### \* 9.02 पाठ्य पुस्तकें शिक्षक-निर्देशन पुस्तकें और शिक्षण सामग्री

##### Text-Books, Teacher's Guides and Teaching Material

पाठ्य पुस्तकों के सम्बन्ध में

पाठ्य पुस्तकों के सुधार हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग के मुझाव  
सुझावों की आलोचना

पाठ्य-पुस्तकों, शिक्षक निर्देशिकाओं (Teacher's Guides)

और शिक्षण सम्बन्धी शिक्षा आयोग (1966) के मुझाव

निम्न स्तर की वृद्धि के कारण

पाठ्य-पुस्तकें सम्बन्धी मुझाव

शिक्षक निर्देशिकाओं से सम्बन्धित मुझाव

आवश्यक शिक्षण सामग्री सम्बन्धी मुझाव

आलोचनात्मक मूल्यांकन

# विश्वविद्यालय प्रश्न

## University Questions

1. Discuss the functions of the 'Core subjects' and the electives in the Secondary School Curriculum, and say what subjects or groups of subjects are to be included under each category. Explain how the aims of Secondary Education are to be realised through this curriculum

(Rajasthan, 1963)

2. Suppose that you are the Head of a Higher Secondary Institution. Choose a subject and justify its place in the curriculum. Show to what extent the object of keeping the subject in the curriculum is realised, and point out the weaknesses which are observed to remain and the way you will remedy them.

(Rajasthan, 1964)

3. Explain fully what is meant by 'Diversified Courses'

(Agra, 1950)

4. Write a note on 'Value of Multilateral Courses'

(L. T., 1959)

5. पाठ्यक्रम से पूर्व एवं पश्चात् पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण हेतु क्या क्या प्रयत्न किए गये ? संक्षिप्त विवरण दीजिये ।

6. माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण की क्या आवश्यकता है । इसके पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कीजिये ।

7. 'बालकों के सर्वांग विकास हेतु यह निताम्य आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में उनकी समिपक्षि, बौद्धिक स्तर, समिवृत्ति एवम् कार्यकुशलता को विनिष्ठ स्थान दिया जाये ।'

उपरोक्त कथन के सदर्थ में स्पष्ट कीजिये कि माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण हो अपषवा नहीं । यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

## अध्याय नौ

### Chapter Ninth

भाष्यभिक स्तर पर निर्देशन व समुपदेशन,  
पाठ्य-पुस्तकें, शिक्षक निर्देशिकाएँ और शिक्षण सामग्री

*Guidance & Counselling, Text Books, Teachers  
Guides and Instructional Material at Secondary Stage*

#### अध्ययन बिन्दु

#### Learning Points

#### \* 9.01 निर्देशन व समुपदेशन

##### Guidance & Counselling

निर्देशन सेवाओं की वर्तमान स्थिति

1. शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन का केन्द्रीय कार्यालय
  2. शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के राजकीय कार्यालय
  3. माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन
- माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953) ने निर्देशन एवं समुपदेशन हेतु सुझाव  
शिक्षा आयोग (1966) के निर्देशन एवं समुपदेशन हेतु सुझाव

#### \* 9.02 पाठ्य पुस्तकें शिक्षक-निर्देश पुस्तकें और शिक्षण सामग्री

##### Text-Books, Teacher's Guides and Teaching Material

पद : पुस्तकों के सम्मीर बोध

पाठ्य पुस्तकों के सुचारु हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव  
सुझावों की आलोचना

पाठ्य-पुस्तकें, शिक्षक निर्देशिकाएँ (Teacher's Guides)  
और शिक्षण सम्बन्धी शिक्षा आयोग (1966) के सुझाव

निम्न स्तर की वृद्धि के कारण

पाठ्य-पुस्तकें सम्बन्धी सुझाव

शिक्षक निर्देशिकाओं से सम्बन्धित सुझाव

आवश्यक शिक्षण सामग्री सम्बन्धी सुझाव

आलोचनात्मक मूल्यांकन

# विश्वविद्यालय प्रश्न

## University Questions

1. Discuss the functions of the 'Core subjects' and the electives in the Secondary School Curriculum, and say what subjects or groups of subjects are to be included under each category. Explain how the aims of Secondary Education are to be realised through this curriculum.

(Rajasthan, 1963)

2. Suppose that you are the Head of a Higher Secondary Institution. Choose a subject and justify its place in the curriculum. Show in what extent the object of keeping the subject in the curriculum is realised, and point out the weaknesses which are observed to remain and the way you will remedy them.

(Rajasthan, 1964)

3. Explain fully what is meant by 'Diversified Courses'.

(Agra, 1950)

4. Write a note on 'Value of Multilateral Courses'.

(L. T., 1959)

5. 'विकास' से पूर्व एवं पश्चात् पाठ्यक्रम के विभिन्नकरण हेतु क्या क्या प्रयत्न किए गये? संक्षिप्त विवरण दीजिये।

6. माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के विभिन्नकरण की क्या आवश्यकता है। इसके पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करें।

7. 'वातकों के सर्वांग विकास हेतु यह नितांत आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में उनकी धार्मिक, बौद्धिक स्तर, समिवृत्ति एवं कार्यकुशलता को विशेष स्थान दिया जाये।'

उपरोक्त कथन के सदृश में स्पष्ट कीजिये कि माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का विभिन्नकरण हो सक्ता नहीं। यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं?

## अध्याय नौ

### Chapter Ninth

माध्यमिक स्तर पर निर्देशन व समुपदेशन,

पाठ्य-पुस्तकें, शिक्षक निर्देशिकाएँ और शिक्षण सामग्री

*Guidance & Counselling, Text Books, Teachers*

*Guides and Instructional Material at Secondary Stage*

अध्ययन बिन्दु

*Learning Points*

#### \* 9.01 निर्देशन व समुपदेशन

*Guidance & Counselling*

निर्देशन सेवाओं की वर्तमान स्थिति

1. शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन का केन्द्रीय कार्यालय

2. शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के राष्ट्रीय कार्यालय

3. माध्यमिक शालाओं में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन  
माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953) के निर्देशन एवं समुपदेशन  
हेतु मुभाव

शिक्षा आयोग (1966) के निर्देशन एवं समुपदेशन हेतु मुभाव

#### \* 9.02 पाठ्य पुस्तकें शिक्षक-निर्देश पुस्तकें और शिक्षण सामग्री

*Text-Books, Teacher's Guides and Teaching Material*

प.द. पुस्तकों के सम्मोद दोष

पाठ्य पुस्तकों के सुधार हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग के मुद्दाव  
मुद्दावों की प्रालोचना

पाठ्य-पुस्तकों, शिक्षक निर्देशिकाओं (Teacher's Guides)

और शिक्षण सम्बन्धी शिक्षा आयोग (1966) के मुद्दाव

निम्न स्तर की वृद्धि के कारण

पाठ्य-पुस्तकें सम्बन्धी मुद्दाव

शिक्षक निर्देशिकाओं से सम्बन्धित मुद्दाव

आवश्यक शिक्षण सामग्री सम्बन्धी मुद्दाव

प्रालोचनात्मक मूल्यांकन



# विश्वविद्यालय प्रश्न

## University Questions

1. Discuss the functions of the 'Core subjects' and the electives in the Secondary School Curriculum, and say what subjects or groups of subjects are to be included under each category. Explain how the aims of Secondary Education are to be realised through this curriculum

(Rajasthan, 1963)

2. Suppose that you are the Head of a Higher Secondary Institution. Choose a subject and justify its place in the curriculum. How to what extent the object of keeping the subject in the curriculum is realised, and point out the weaknesses which are observed remain and the way you will remedy them.

(Rajasthan, 1964)

3. Explain fully what is meant by 'Diversified Courses'

(Agra, 1960)

4. Write a note on 'Value of Multilateral Courses'

(L. T., 1959)

5. स्वतंत्रता के बाद से पूर्व एवम् पश्चात् पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण का क्या प्रयत्न किये गये ? संक्षिप्त विवरण दीजिये ।

6. माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण की क्या आवश्यकता है ? इसके पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कीजिये ।

7. 'बालकों के सर्वांग विकास हेतु यह निताम्त आवश्यक है कि पाठ्य-क्रम की समिवृत्ति, बौद्धिक स्तर, समिवृत्ति एवम् कार्यकुशलता को विनिष्ट दिया जाये ।'

उपरोक्त कथन के समर्थन में स्पष्ट कीजिये कि माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण हो अथवा नहीं । यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों ?

## अध्याय नौ

### Chapter Ninth

माध्यमिक स्तर पर निर्देशन व समुपदेशन,  
पाठ्य-पुस्तकें, शिक्षक निर्देशिकाएँ और शिक्षण सामग्री

*Guidance & Counselling, Text Books, Teachers  
Guides and Instructional Material at Secondary Stage*

#### अध्ययन बिन्दु

#### Learning Points

#### \* 9.01 निर्देशन व समुपदेशन

##### Guidance & Counselling

निर्देशन सेवाओं की वर्तमान स्थिति

1. शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन का केन्द्रीय कार्यालय
2. प्रांतीय एवं व्यावसायिक निर्देशन के राजकीय कार्यालय
3. माध्यमिक स्तरों में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953) के निर्देशन एवं समुपदेशन हेतु सुझाव

शिक्षा आयोग (1966) के निर्देशन एवं समुपदेशन हेतु सुझाव

#### \* 9.02 पाठ्य पुस्तकें शिक्षक-निर्देश पुस्तकें और शिक्षण सामग्री

##### Text-Books, Teacher's Guides and Teaching Material

प.द. पुस्तकों के सम्बन्ध में शोध

पाठ्य पुस्तकों के सुधार हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव  
सुझावों की धारणा

पाठ्य-पुस्तकों, शिक्षक निर्देशिकाओं (Teacher's Guides)

और शिक्षण सम्बन्धी शिक्षा आयोग (1966) के सुझाव

निम्न स्तर की वृद्धि के कारण

पाठ्य-पुस्तकों सम्बन्धी सुझाव

शिक्षक निर्देशिकाओं से सम्बन्धित सुझाव

आवश्यक शिक्षण सामग्री सम्बन्धी सुझाव

धारणात्मक मूल्यांकन

## विद्यार्थ्यालय प्रश्न

### University Questions

1. Discuss the functions of the 'Core' and 'electives' in the Secondary School Curriculum, and explain how the aims of Secondary Education are achieved through this curriculum.

(Rajasthan)

2. Suppose that you are the Head of a Higher Institution. Choose a subject and justify its place in the curriculum. Show to what extent the object of keeping the subject in the curriculum is realised, and point out the weaknesses which are to remain and the way you will remedy them.

(Rajasthan)

3. Explain fully what is meant by 'Diversified Course'.

(Agra)

4. Write a short note on 'Value of Multilateral Course'.

(L. T., B.)

5. स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व एवम् पश्चात् पाठ्यक्रम के विभिन्निकरण हेतु क्या क्या प्रयत्न किये गये ? संक्षिप्त विवरण दीजिये ।

6. माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के विभिन्निकरण की क्या आवश्यकता है । इसके पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कीजिये ।

7. 'बालकों के सर्वांग विकास हेतु यह नितान्त आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में उनकी अभिवृत्ति, बौद्धिक स्तर, अभिवृत्ति एवम् कार्यकुशलता को विविध स्थान दिया जाये ।'

उपरोक्त कथन के सदर्थ में स्पष्ट कीजिये कि माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का विभिन्निकरण हो अवकाश नहीं । यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

## अध्याय नौ Chapter Ninth

माध्यमिक स्तर पर निर्देशन व समुपदेशन,  
पाठ्य-पुस्तकें, शिक्षक निर्देशिकाएँ और शिक्षण सामग्री  
*Guidance & Counselling, Text Books, Teachers  
Guides and Instructional Material at Secondary Stage*

### अध्ययन बिन्दु Learning Points

#### \* 9.01 निर्देशन व समुपदेशन

##### Guidance & Counselling

निर्देशन सेवाओं की वर्तमान स्थिति

1. शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन का केन्द्रीय कार्यालय
2. शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के राजकीय कार्यालय
3. माध्यमिक शालाओं में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन  
माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953) के निर्देशन एवं समुपदेशन  
हेतु सुझाव  
शिक्षा आयोग (1966) के निर्देशन एवं समुपदेशन हेतु सुझाव

#### \* 9.02 पाठ्य पुस्तकें शिक्षक-निर्देशन पुस्तकें और शिक्षण सामग्री

##### Text-Books, Teacher's Guides and Teaching Material

पाठ्य पुस्तकों के गम्भीर दोष

पाठ्य पुस्तकों के सुधार हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव  
सुझावों की प्रासंगिकता

पाठ्य-पुस्तकों, शिक्षक निर्देशिकाओं (Teacher's Guides)

और शिक्षण सम्बन्धी शिक्षा आयोग (1966) के सुझाव

निम्न स्तर की वृद्धि के कारण

पाठ्य-पुस्तकें सम्बन्धी सुझाव

शिक्षक निर्देशिकाओं से सम्बन्धित सुझाव

भावपूर्ण शिक्षण सामग्री सम्बन्धी सुझाव

प्रासंगिकतात्मक मूल्यांकन

# माध्यमिक स्तर पर निर्देशन व समुपदेशन, पाठ्य- पुस्तकें, शिक्षक निर्देशिकाएँ और शिक्षक सामग्री *GUIDANCE & COUNSELLING, TEXT BOOKS, TEACHERS' GUIDES & INSTRUCTIONAL MATERIAL AT SECONDARY STAGE*

हमारी माध्यमिक स्तराधी की शिक्षा व्यवस्था में कदेको होत है जिसमें वे निर्देशन व समुपदेशन का अभाव, पाठ्य-पुस्तकों का अभाव, शिक्षक निर्देशिकाओं का अभाव, शिक्षक सामग्री की अभाव का व होश बारीक विचार का वे करते नहीं हैं। माध्यमिक स्तर पर अधिकांश मुद्दों को जाने के बिना वह अभाव व्यवस्था है कि अतीत समय लोगों को हुए बिना आये और अनुसूचित व्यवस्था करने का प्रयत्न किया आये। अतः व्यवस्था में हम हम सभी मुख्य शिक्षकों पर निर्भर कर रहे हैं विचार करेंगे।

## 9.01 निर्देशन व समुपदेशन *Guidance & Counselling*

माध्यमिक स्तर पर निर्देशन और समुपदेशन का निम्नो महत्व है। पश्चिमी देशों की शैक्षिक प्रणाली में निर्देशन का महत्वपूर्ण स्थान है। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि अमेरिका की शिक्षा में निर्देशन आन्दोलन द्वारा काफी प्रगति हुई है। निर्देशन द्वारा केवल शैक्षिक प्रगति ही नहीं बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों,

सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक सभी में प्रगति सम्भव है। यही कारण आज निर्देशन का महत्व बहुत बढ़ गया है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है निर्देशन वह यन्त्र है जिससे शैक्षिक, सामाजिक और धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति है क्योंकि निर्देशन का मूल स्रोत मानवीय आवश्यकताएँ होती हैं। मानव शक्तियों का सदुपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे निश्चित दृष्टिकोण और भावी जीवन की रूपरेखा का आभास हो। इसके लिये आवश्यक कि उसे सम्बन्धित क्षेत्रों का निर्देशन प्रदान किया जावे। यदि हम आज विश्व में बेरोजगारी की समस्या को देखें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है नौकरियों का अभाव नहीं है बल्कि शिक्षित वर्ग में कार्य न करने की इच्छा अभाव है क्योंकि जो शिक्षा प्रदान की गई अथवा की जा रही है वह निर्देशन है, वस्तुतः वहाँ निर्देशन नहीं है वहाँ अनिश्चितता है और अनिश्चितता का सर्वत्र सम्प्रसारण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण बनाने में निर्देशन की आवश्यकता होती है। रूप से निर्देशन द्वारा व्यक्ति को दो बातों का आभास होता है, प्रथम व्यक्ति की सामर्थ्य और क्षमता है दूसरे इनका अधिकाधिक सदुपयोग कैसे कर सकता है। यदि इसी बिन्दु को शैक्षिक दृष्टिकोण से देखा जाये तो शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को यह आभास कराना है कि उसकी शक्ति द्वारा समाज को किस प्रकार लाभान्वित किया जा सकता है और क्षति का सही लाभ निर्देशन संभव है। अतः शिक्षा में निर्देशन का महत्वपूर्ण स्थान है। परन्तु यह हमारा कि हमारे देश की माध्यमिक शालाओं में निर्देशन के प्रति सही दृष्टिकोण नहीं हुआ है और इसी कारण अनेकों समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं।

### निर्देशन सेवाओं की वर्तमान स्थिति

#### Present Position of Guidance Services

#### 1. शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन का केन्द्रीय कार्यालय

#### Central Bureau of Educational & Vocational Guidance

अक्टूबर सन् 1954 में केन्द्रीय सरकार द्वारा सेंट्रल इन्स्टीट्यूट एडुकेशन देहली में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन हेतु केन्द्रीय कार्य स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य सल्लाहकारों (Counsellors) तथा कर्कराज्यों (Career Masters) की प्रशिक्षण देना है। इसके प्रतिरिक्त सम्बन्धी साहित्य का गृहण, विचार शोधियों का आयोजन, राजकीय कार्यालयों का मार्ग प्रदर्शन और विभिन्न प्रकार की बुद्धि परीक्षाओं तथा मापन विधियों को तैयार करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसका कार्य राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाना और समन्वय करना है देशव्यापी प्रसारण के अभाव में इसका समुचित उपयोग नहीं हो सका।



विद्यालयों में नियुक्त होते हैं उनका वेतन कम निश्चित है। राजस्थान में निर्देशन कार्यालय बोकानेर में है जो कि विभिन्न प्रकार के परीक्षण तैयार करता है। पहले व्यावसायिक अध्यापकों के लिए प्रारम्भिक काल में प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। मात्रक माध्यमिक शिक्षा जोड़ने के बाद ने व्यापक आन्तरिक मूल्यांकन योजना प्रारम्भ कर दी है और निर्देशन कार्यालय विभिन्न प्रकार की बुद्धि परीक्षाओं एवं व्यक्तित्व सापन विधियों को तैयार कर रहा है। राजस्थान में माध्यमिक स्तर पर व्यापक आन्तरिक मूल्यांकन के प्रारम्भ कर देने से निर्देशन कार्यों में काफी गति आयेगी, ऐसी सम्भावना है।

परन्तु अभी बहुत से इस प्रकार के राज्य हैं जहाँ निर्देशन शून्य माध्यमिक शिक्षा दी जा रही है। सम्पूर्ण देश में माध्यमिक शिक्षा स्तर पर निर्देशन सेवाओं का होना नितान्त आवश्यक है। राज्य सरकारों को चाहिए कि यथासम्भव सभी शाखाओं में ये सुविधाएँ प्रदान की जायें जिससे बालक अपने भावी जीवन के सम्बन्ध में विचार कर सके।

**माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953) के निर्देशन एवं**

**समुपदेशन हेतु सुझाव**

**Recommendations of Secondary Education Commission (1953)**

**Regarding Guidance & Counselling**

जैसा कि हम पिछले अध्याय में कह आये हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सर्वस्तर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के विभिन्नकरण का महत्वपूर्ण सुझाव दिया था। पाठ्यक्रम का विभिन्नकरण सभी सम्भव है जबकि विषयों के चयन में अध्यापकों द्वारा छात्रों को निर्देशन प्राप्त हो सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आयोग ने माध्यमिक शाखाओं में निर्देशन और समुपदेशन हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये :—

1. शिक्षा अधिकारियों द्वारा शैक्षिक निर्देशन पर अधिक ध्यान दिया जाये।
2. विभिन्न प्रकार के व्यावसायों तथा उद्योगों के ज्ञान प्रदान करने हेतु सम्बन्धित फ़िल्म तैयार किये जायें और छात्रों को विभिन्न उद्योगों में वास्तविक कार्य देखने के लिये से जाया जाये।
3. सभी विद्यालयों में प्रशिक्षित निर्देशकों तथा व्यावसायिक अध्यापकों की नियुक्ति की जाये और उनकी सेवाओं से पूर्ण लाभ उठाया जाये।
4. निर्देशन अधिकारियों तथा व्यावसायिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार को करनी चाहिए।
5. व्यावसायों की जानकारी देने के लिये 'व्यावसाय सम्मेलनों' (Career conferences) का आयोजन किया जाये और इन सम्मेलनों में शिक्षकों, अभिभावकों आदि को आमन्त्रित किया जाये।



6. माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक बालक को शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जाये।

### शिक्षा आयोग (1966) के निर्देशन और समुपदेशन हेतु सुझाव *Recommendations of Education Commission (1966) Regarding Guidance & Counselling*

कोठारी आयोग ने निर्देशन और समुपदेशन के महत्व को स्वीकार करते हुए बालकों के समायोजन और विकास के लिये इन सेवाओं को नितांत आवश्यक बताया है। 'निर्देशन केवल मात्र विशिष्ट मनोवैज्ञानिक अथवा समाज सेवाओं के रूप में बाहरी सीमाओं तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसे शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। यह सामान्य आदर्शों से पृथक् बालकों के लिये ही नहीं बल्कि सभी बालकों के लिये आवश्यक है। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शक्ति में समय-समय पर निरुन्ध करने की क्षमता तथा समायोजन की क्षमता का विकास करना है।<sup>1</sup>

माध्यमिक स्तर पर निर्देशन का प्रमुख कार्य किशोर विद्यार्थियों की पहचान तथा उनकी योग्यता तथा रुचियों का विकास करना है। यह विद्यार्थियों को उनकी सामर्थ्य, योग्यतानुसार शाला कार्य करने की क्षमता, शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों की सूचना, सम्बन्धित सूचनाओं पर आधारित योजना, मान्य और पर वैयक्तिक तथा सामाजिक समायोजन की समस्याओं का समाधान करने की क्षमता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त निर्देशन सेवाओं से प्रधान-व्यक्तियों तथा अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों के लिए प्रभावशाली ढंग से निश्चित करने के अवसर भी प्राप्त होते हैं।<sup>2</sup>

1. Guidance, therefore, should be regarded as an integral part of education and not a special psychological or social service which is peripheral to educational purposes. It is meant for all students, not just for those who deviate from the norm in one direction or the other. It is also a continuous process aimed at assisting the individual to make decisions and adjustments from time to time.

*Report of the Education Commission, 1966, p. 231.*

2. One of the main functions of guidance at the secondary level is to aid in the identification and development of the abilities and interests of adolescent pupils. It helps them pupils to understand their own strengths and limitations and to do scholastic work at the level of their ability, to gain information about educational and vocational opportunities and requirements, to make realistic educational and vocational choices and plans based on a consideration of all relevant factors.

जैसा कि हम पिछले पृष्ठों में कह आये हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953) के सुझाव के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने सन् 1954 में शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन कार्यालय की स्थापना की जिसका उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर निर्देशन आन्दोलन को बढ़ाना और सम्बन्धित सलाह देना था। मात्रकल विभिन्न राज्यों में 13 कार्यालय कार्य कर रहे हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक सम्पूर्ण देश में केवल 3000 माध्यमिक शालाओं में निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था थी जो कि देश की कुल माध्यमिक शालाओं की संख्या की 13 प्रतिशत थी। इन 3000 शालाओं में भी व्यवसाय अध्यापक का कार्य केवल सूचना प्रदान करना ही है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि हमारे देश में निर्देशन सेवाएँ नगण्य रही हैं।

शिक्षा आयोग ने देश व्यापी निर्देशन आन्दोलन के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :—

1. समस्त माध्यमिक शालाओं के लिये न्यूनतम निर्देशन कार्यक्रम तैयार किया जाये।
2. निर्देशन हेतु दस माध्यमिक शालाओं के लिये एक समुपदेशक की नियुक्ति की जाये और शाला के समस्त शिक्षक उसे सहयोग प्रदान करें।
3. प्रत्येक जिले में कम से कम एक शाला को निर्देशन का विस्तृत कार्यक्रम निर्धारित करने को कहा जाये।
4. माध्यमिक शाला के सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण बाल में निर्देशन की धारणा से अवगत कराया जाये और जो अध्यापक इनका अधिक अध्ययन करना चाहें उन्हें यह सुविधा प्रदान की जाये। प्रत्येक प्रशिक्षण महाविद्यालय में कम से कम एक अध्यापक ऐसा अवसर हो जो शालाओं में समुपदेशकों को प्रशिक्षण दे सके।
5. निर्देशन कार्यकर्ताओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये उचित प्रवर्धन होना चाहिए। अधिक समयोपधि के पाठ्यक्रम की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा होनी चाहिए।

अन्य सामान्य सुझाव

Other General Proposals

1. निर्देशन और समुपदेशन सम्बन्धी समस्याओं पर देश की परिस्थितियों अनुसार अनुसंधान करना जाये।

problems of personal and social adjustment in the school and home. Guidance services also help headmasters and teachers understand their students as individuals and to create situation in which the students can learn more effectively.

*Ibid*, p. 22

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मार्ग-प्रदर्शन अत्यन्त महत्व है। मार्ग-प्रदर्शन की उपयोगिता और साधन आवश्यक है कि माध्यमिक स्तर पर सम्बन्धित अनुसंधान शैक्षिक परिस्थितियों में मार्ग-प्रदर्शन की सेवाएँ प्राप्त निरर्थक में विभिन्न प्रकार के परीक्षण हैं न ही प्रशिक्षित मार्ग-निर्देशक यह है कि माध्यमिक शास्त्रों में मार्ग-प्रदर्शन का कार्य सन्तोष नितान्त आवश्यक है कि राज्य सरकारें अधिकाधिक मार्ग-प्रविस्तार करें जिससे सन्तोषप्रद सत्या में अध्यापक प्रशिक्षित हो स्तर पर प्रत्येक छात्र का मार्ग-प्रदर्शन किया जा सके।

### 9.02 पाठ्य-पुस्तकें, शिक्षक-निर्देश पुस्तकें और शिक्षक Text Books, Teacher's Guides and Teaching

सम्पूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में पाठ्य-पुस्तकों का निजी महत्व उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्य पुस्तकें भी साधन के रूप में सहायक हैं। पाठ्य पुस्तक के महत्व की स्पष्ट करते हुए शिक्षा आयोग का विचार है कि पाठ्य पुस्तक को एक योग्य, अनुसूची और प्रतिभावादी विशेषज्ञ द्वारा जिसका मूद्रण उत्तम होता है, जिसमें व्यवस्थित विषय और उपयुक्त छात्रों में प्रेरणा का संचार करती है एक अध्यापक को सहायता प्रदान करती पाठ्य-पुस्तकें और अन्य शिक्षण तथा सीखने की सामग्री शिक्षकों को उठाने में अत्यन्त प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं।<sup>1</sup>

परन्तु यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ उत्तम पाठ्य सामग्री है और विषयों के अधिकांश पाठ्य पुस्तकों का मूद्रण नहीं करते हैं। पाठ्य-पुस्तकें स्तरानुसार प्रकाशित होती हैं वे प्रकाशकों की बेईमानी हो जाती हैं जिससे परिणामस्वरूप मेसर्स की पुस्तकों के मूद्रण में रुचि नहीं

3. A good text-book, written by a qualified and competent specialist in the subject, and produced with due regard to the quality of printing, illustrations and general get up stimulates the interest and helps the teacher considerably in his work. The provision of quality text-books, and other teaching materials, can thus be an effective means of improving the quality of education.

अच्छी पाठ्य-पुस्तकों, उत्तम अध्यापक निर्देशिकाओं तथा उचित शिक्षण सामग्री के अभाव में सम्पूर्ण शिक्षण व्यवस्था घस्त व्यस्त हो जाती है और वाछित शैक्षिक उपलब्धियाँ प्राप्त नहीं हो पाती; फलतः शिक्षा का स्तर गिरने लगता है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिये यह निताम्न आवश्यक है कि पाठ्य-पुस्तकों की दशा में सुधार हो, उत्तम शिक्षक-निर्देश पुस्तिकाएँ प्रकाशित हों और प्रभावशाली शिक्षण सामग्रियों का उपयोग हो। पाठ्य-पुस्तकों की दशा पर, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् विभिन्न समितियों, सम्मेलनों तथा आयोगों ने ध्यान आकषिप्त कराया। सर्व प्रथम द्वितीय वात्सव्य मन्त्रि समिति (1953) ने पाठ्य-पुस्तकों की स्थिति का अध्ययन किया और उसके सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिये। इसके पश्चात् माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953) ने पाठ्य-पुस्तकों के गिरते हुए स्तर को ऊँचा उठाने के लिये उनका राष्ट्रीयकरण करने का सुझाव दिया। तत्पश्चात् कीर्त फाल्गुदेशन (1954) के कार्य-क्रमानुसार एक दस में भारतीय पाठ्य-पुस्तकों की स्थिति को देखा जिनमें पाठ्य-पुस्तकों को समिति बनाने का सुझाव दिया। सन् 1966 में शिक्षा आयोग ने पाठ्य-पुस्तकों के सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

### पाठ्य-पुस्तकों के गम्भीर दोष

#### Grave Defects of Text Books

माध्यमिक शिक्षा आयोग<sup>1</sup> ने पाठ्य-पुस्तकों के गिरते हुए स्तर पर लेख प्रगट किया और पाठ्य-पुस्तकों में निम्नलिखित दोष बताये हैं :—

1. पाठ्य-पुस्तकों की सामग्री विद्यार्थियों की उम्र और योग्यता के अनुसार नहीं होती।
2. पाठ्य-पुस्तकों का सूत्रन इकाई के अनुसार नहीं होता जिससे एक पाठ का दूसरे पाठ से सम्बन्ध नहीं रह पाता।
3. पाठ्य-पुस्तकों की छायाई असन्तोषजनक होती है जिसके कारण विद्यार्थी-गण उनके प्रति निष्क्रिय हो जाते हैं।
4. पाठ्य-पुस्तकों में जिन और रेखाचित्र उपयुक्त नहीं होते और उन्हें गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है।

1. Most of the books submitted and prescribed are poor specimens in every way—the paper is usually bad, the printing is

5. इन पुस्तकों में बेराग गणनों की प्रचालना दी जाती है और तदनुसार की विवरणें दिये गये हैं।
6. प्रायः पाठ्य-पुस्तकों के लेखक भाषा परिवर्तनियों से अनभिज्ञ होते हैं जिसके कारण वे पुस्तकें बाधित आधार पर लिखी जाने में अनर्थ रहती हैं और छात्रों की शिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती।
7. पाठ्य-पुस्तकें प्रजासत्तात्मिक सिद्धान्तों, राष्ट्रीय भावनात्मक एकता और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना से भूय होती हैं जिसके कारण बाधित उपलब्धियाँ प्राप्त नहीं हो पाती।
8. अनेक पाठ्य-पुस्तक समितियाँ निम्नस्तर भाव हैं। पाठ्य-पुस्तकों का बचन नहीं करती जिसके कारण निम्न स्तर की पुस्तकों की निरर्थक रूप से सहयोग प्राप्त हो जाता है।
9. शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाएँ हो जाने के कारण पाठ्य-पुस्तकों के लेखन और प्रकाशन में रुकावटें उत्पन्न हो गई हैं क्योंकि लेखकों और प्रकाशकों की संख्या कम हो जाने से साधन सीमित हो गये हैं।

पाठ्य-पुस्तकों के सुधार हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सुझाव  
*Recommendations of Secondary Education Commission for Reform of Text Books.*

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने समस्त दोषों को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये जो निम्नलिखित हैं :—

1. प्रत्येक राज्य में एक 'शक्तिशाली पाठ्य-पुस्तक समिति' होनी चाहिए जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष होना चाहिए और कार्य करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए।
2. शक्तिशाली पाठ्य-पुस्तक समिति में छह सदस्य रहने इस प्रकार हों :—  
 हाईकोर्ट का जज  
 लोक-सेवा आयोग का सदस्य  
 राज्य के किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति  
 राज्य के शालाओं के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका  
 प्रतिष्ठित शिक्षा शास्त्री  
 शिक्षा सचालक  
 उपरोक्त समिति को अप्रतिष्ठित कार्य सौंपे गये :—

- ( i ) प्रत्येक विषय की पाठ्य-पुस्तकों का निरीक्षण करने हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति करना ।
- ( ii ) पाठ्य-पुस्तकों के सुझाव हेतु विशेषज्ञ विद्वानों को नियुक्त करना ।
- (iii) ग्रन्थ राज्यों की समितियों से सम्पर्क रखना ।
- (iv) लेखकों के लिये उचित पारित्यक्तिक की व्यवस्था करना ।
- ( v ) प्रकाशन से प्राप्त धन की पृथक् व्यवस्था कर कोष स्थापित करना ।
- (vi) इसे हुए धन को नीचे लिखे अनुसार खर्च करना :—

- निर्धन और प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति देना ।
- सब विद्यार्थियों के लिये भोजन व्यवस्था रख देना ।
- माध्यमिक शिक्षा स्तर के सुधार में व्यय करना ।

3. पाठ्य-पुस्तक समिति को कला का प्रतिपादन देने का लिये नवीन शिक्षकाला विद्यालय खोलने चाहिए जहाँ पाठ्य-पुस्तकों के लिये अच्छे चित्र बनाने का प्रतिपादन दिया जा सके ।
4. केन्द्रीय और राज्य सरकारें चित्रों के नमूनों के संग्रहालय स्थापित करें जहाँ से प्रकाशकों को दिये जा सकें और चित्रों के स्तर को सुधारा जा सके ।
5. एक विषय के लिये एक से अधिक पाठ्य-पुस्तकें निर्धारित की जायें और जाला अधिकाधिकों को स्वतन्त्रता दी जाये कि वे अपनी इच्छानुसार कोई भी पुस्तक चुनें ।
6. भारत के चर्म निरपेक्ष राज्य होने के कारण पाठ्य-पुस्तकों में किसी चर्म व्यवस्था समुदाय विशेष के प्रति घृणास्पद तथ्यों को स्थान न दिया जाये ।
7. पाठ्य-पुस्तकों और अन्य अध्ययन की पुस्तकों (अध्यापक निर्देशिका आदि) को अस्ती-अस्ती न बदला जाये ।

### सुझावों की समीक्षा

#### Criticism and Recommendations

इसमें कोई संदेह नहीं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा दिये गये पाठ्य-पुस्तक सम्बन्धी समस्त सुझाव धार्मिक उपयोगी हैं तथाकि कुछ सुझाव प्रतिप्रयोजितपूर्ण भी हैं जैसे 'शक्तिशाली पाठ्य-पुस्तक समिति' (High Power Committee) की नियुक्ति । त्रिन प्रशासिकाधिकारियों की इन समेटी में रखता गया है उनका कोई उपयोग



निम्न स्तर की वृद्धि के कारण

Causes of Proliferation of Low Standard

धायोग के अनुसार इसके निम्नलिखित कारण हैं :—

1. पाठ्य-पुस्तकों के मूलन में विद्वानों की दक्षि नही होती और इसी कारण यह कार्य उन व्यक्तियों द्वारा होता है जो इस कार्य को करने की उपयुक्त योग्यता नहीं रखते ।
2. पाठ्य-पुस्तकों के चयन में कुप्रवृत्तियों को प्रयोग में लाया जा ॥ है ।
3. घनेकों प्रकाशकों द्वारा सन्दिग्ध आदनों के कारण ।
4. पाठ्य-पुस्तकों के प्रस्तुतीकरण तथा उत्पादन में अनुगमन के अभाव के कारण ।
5. प्राईवेट प्रकाशकों द्वारा (जो केवल बचत में ही रक्षित हैं) शिक्षक निर्देशिकाओं (Teachers' Guides) और सहायक पुस्तकों का प्रकाशन नहीं किया जाता ।

पाठ्य-पुस्तकों सम्बन्धी सुझाव

Recommendations Regarding Text-Books

1. पाठ्य-पुस्तकों की दशा सुधारने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम बनाया जाये और प्रतिभावान लोगों को पुस्तकों के मूलन हेतु प्रोत्साहित किया जाये ।
2. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुगमन एवं प्रशिक्षण परिषद् (National Council of Educational Research & Training) के सिद्धांत एवं कार्य योजना के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी पाठ्य-पुस्तकों की दशा सुधारने हेतु कार्य हो ।
3. पाठ्य-पुस्तकों के उत्पादन का निष्ठा सम्प्रदाय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य स्वीकार करना चाहिए और इसके लिये स्वायत्त संगठन (Autonomous Organisation) की स्थापना करनी चाहिए ।
4. प्रत्येक राज्य में पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण के लिये पूर्ण रूप से विशेष समितियों की नियुक्ति होनी चाहिए ।
5. पाठ्य-पुस्तकों की संपादकीय और मूल्यांकन का समस्त भार राज्य के शिक्षा विभाग पर होना चाहिए ।
6. पाठ्य-पुस्तकों के बेचने के लिये छात्रों के सर्वोपयोगी व्यवहार होने चाहिए ।
7. पाठ्य-पुस्तकों का उत्पादन एक निरन्तर प्रक्रिया है अतः पाठ्य-पुस्तकों के परिशुद्धित संस्करण सार्वजनिक रूप से समयानुसार निरूपण चाहिए ।



8. प्रत्येक विषय में कम से कम तीन या चार पाठ्य-पुस्तकें होनी चाहिए और भाषा की आवश्यकतानुसार अध्यापकों को किसी भी पुस्तक का चयन करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए।
9. राज्य द्वारा पाठ्य-पुस्तकों के सृजन में योग्य लेखक आकर्षित नहीं होते क्योंकि राज्य द्वारा उदार पारित्यमिक नहीं दिया जाता और यही कारण है कि निजी कार्य ( Private Enterprise ) राजकीय कार्य पर विजय प्राप्त कर लेता है। अतः यह आवश्यक है कि प्राईवेट कार्य की तुलना में राज्य द्वारा अधिक उदार पारित्यमिक की व्यवस्था हो जिससे अच्छे लेखकगण आकर्षित हो सकें।
10. पाठ्य-पुस्तकों का उत्पादन साम के आधार पर नहीं होना चाहिए, इसका एक मात्र उद्देश्य अच्छी पुस्तकों का सृजन होना चाहिए जिससे कम कीमत पर पुस्तकें प्राप्त हो सकें।
11. पाठ्य-पुस्तकों पर केवल मात्र पाच वैसे की वृद्धि करने से सम्बन्धित अनुसन्धान, शिक्षक निर्देशिकाएँ ( Teachers' Guides ) तथा सहायक सामग्री ( Ancillary aids ) पर धन व्यय किया जा सकता है और शिक्षक निर्देशिकाओं एवं अन्य शिक्षण सामग्री द्वारा पाठ्य पुस्तकों की पूर्ति हो सकती है।
12. पाठ्य-पुस्तकों के सृजन के लिए अधिकधिक रुचि उत्पन्न करने के लिए योग्य व्यक्तियों से पाण्डुलिपियाँ प्राप्त की जानी चाहिए और लेखकों से उचित प्रवन्ध करने के पश्चात् पुस्तकों का प्रकाशन करना चाहिए।

### शिक्षक-निर्देश-पुस्तकें सम्बन्धी सुझाव Recommendations Regarding Teachers' Guides

सम्पूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में केवल मात्र अच्छी पाठ्य-पुस्तकें ही पर्याप्त नहीं हैं। पाठ्य-पुस्तकों के साथ साथ अच्छी शिक्षक-निर्देश-पुस्तकें भी होनी चाहिए। शिक्षक निर्देशिकाओं द्वारा अध्यापक को पूर्ण सहायता प्राप्त होनी चाहिए। समुक्त राज्य अमेरिका में तो स्नातक डिग्री प्राप्त अध्यापकों को भी गणिता, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन आदि विषयों में अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए शिक्षिकाओं का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश के घल्प ज्ञान प्राप्त अनुरक्षित अध्यापकों के लिए तो यह निताम्न आवश्यक है कि उनकी सहायता इन पुस्तकों का निर्माण किया जाए।

हमारी तो यह निधि-

निम्न प्रकार शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षक निर्देशिका-

को दिया जाये। इन निर्देशिकाओं में विस्तृत रूप से विषय से सम्बन्धित सुझाव होने चाहिए और प्रायः सभी इकाई योजनाएँ और पाठ योजनाएँ होनी चाहिए। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवम् प्रशिक्षण परिषद की पाठ्यक्रम, विधि और पाठ्य-पुस्तक विभाग की सहायता से कुछ विचार गोष्ठियों का आयोजन किया था परन्तु यह योजना अभी तक कार्यरूप में परिणित नहीं हो पाई है। कोठारी आयोग ने शिक्षक निर्देशिकाओं का उपयोग प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिए अत्यन्त आवश्यक बताया है परन्तु हमारी राय में माध्यमिक स्तर तक के अध्यापकों के लिए इन निर्देशिकाओं का उत्पादन होना चाहिए जिससे अध्यापकों के ज्ञान में अभिवृद्धि की जा सके और प्रतिपक्ष एक ही प्रकार की विषय सामग्री को परोसने की आदत को समाप्त किया जा सके।

### आवश्यक शिक्षण सामग्री सम्बन्धी सुझाव

#### Recommendations Regarding Essential Teaching Aids

यह कथन कोई अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि हमारे देश की अधिकांश शालाएँ शिक्षण सामग्री से शून्य हैं। अच्छे इयाम पट, पुस्तकालय, भवनचित्र और चार्ट, विज्ञान सम्बन्धी आवश्यक सामग्री आदि किसी की भी व्यवस्था सन्तोषप्रद नहीं है। जब तक हमारे देश में इन भूतनम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तब तक शिक्षा का स्तर ऊँचा उठना प्रायः असम्भव है। शिक्षा आयोग ने शिक्षण सामग्री निम्न-लिखित सुझाव दिये हैं :—

1. प्रत्येक श्रेणी के विद्यालय में न्यूनतम शिक्षण सामग्री होनी चाहिए और इनकी प्राप्ति के लिये शीघ्र कदम उठाने चाहिए।
2. प्रगतिशील देशों में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधियों का प्रयोग करना नितान्त आवश्यक है।
3. शिक्षण विधियों के प्रयोग के लिए फ़िल्म, रेडियो, टेप-रिकार्डर और अन्य दृश्य-श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाये।
4. प्राथमिक यहाँगी शिक्षण सामग्री को निकटवर्ती विद्यालय मिलकर चरीदें।

### प्रासंगिकतात्मक मूल्यांकन

#### Critical Evaluation

शिक्षा आयोग (1964-66) के समस्त सुझावों पर विचार करने के पश्चात् यह अवश्य कहा जा सकता है कि पाठ्य-पुस्तकों के लिये राष्ट्रीय स्तर निश्चित कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना नितान्त आवश्यक है। केन्द्रीय स्तर पर कार्य सम्पादित करने से पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हो जायेगा, क्या इस कार्यक्रम से निजी

कार्य (Private Enterprise) हयोगादि नही होगा ? क्या वाद्व-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण से समाज के मूल्य नष्ट हो जायेंगे ? क्या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार सम्पूर्ण उत्तरदायित्वों को निभाने में सफल हो सकेगी ? क्या वाद्व-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण से प्रतिबोधिता की भावना को क्षति नहीं पहुँचेगी ? क्या इस प्रकार शैक्षणिक कार्य सम्भव हो सकेगा ?

ये कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर प्राप्त होना निम्न आवश्यक है। परन्तु इन सवालों के अर्थ यह नहीं कि वाद्व-पुस्तकों के मुद्धार हेतु सरकार कुछ भी न करे। छात्र वाद्व-पुस्तकों का सम्पूर्ण कार्यभार भी सरकार को ही बहन करना होगा, परन्तु इसके लिये परितुष्ट कार्यक्रम बनाना निम्न आवश्यक है।

हमारी राय में केन्द्रीय सरकार द्वारा आदर्श वाद्व-पुस्तकों का उत्पादन निम्न आवश्यक है। इसके लिये सरकार द्वारा वाद्व-पुस्तकों से सम्बन्धित मूल्य निर्धारित मापदण्डें निश्चित कर देने चाहिए और प्रतिबोधिता की भावना स्वयं निजी कार्य करने वाली संस्थाओं को सामान्यतः दिया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को यह पूर्ण स्वायत्ता होनी चाहिए कि वे अपनी परिस्थितियों के अनुसार वाद्व-पुस्तकों की परिभाषित कर सकें। इनके लेखकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और वाद्व-पुस्तकों की हीन दशा में मुद्धार भी हो सकेगा।

बहने का तात्पर्य यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित वाद्व-पुस्तकों का आदर्श स्वरूप राज्य सरकारों के लिये उत्तेजना प्रेरक होना चाहिए। वाद्व-पुस्तकों के प्रकाशन में व्यापक भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। वाद्व-पुस्तक के अर्थ का आधार उसकी संख्या होनी चाहिए।

## ग्रन्थ - सूची

### Bibliography

1. Government of India,  
*Report of the Education Commission (1964-66)*, Delhi, 1966.
2. ....  
*Report of the Secondary Education Commission*, Publication Division, Delhi, 1953
3. Report of a Study by an International Team,  
*Teachers and Curricula in Secondary Schools*, Ford Foundation, Delhi, 1954.

# विश्वविद्यालय प्रश्न

## University Questions

1. What are the recommendations of the Secondary Education Commission and Education Commission (1966) regarding guidance and counselling at Secondary stage ?

माध्यमिक स्तर पर निर्देशन और समुपदेशन के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग और शिक्षा आयोग (1966) ने क्या सुझाव दिये हैं ?

2. 'Guidance should be regarded as an integral part of education and not a special psychological or social service which is peripheral to educational purpose.'

In the light of the above remark of Education Commission (1966), discuss what is the importance of guidance services in the schools.

'निर्देशन केवल मात्र विशिष्ट मनोवैज्ञानिक अथवा समाज सेवाओं के रूप में बाहरी सीमाओं तक ही सीमित नहीं होना चाहिये बल्कि इसे शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना चाहिये।

शिक्षा आयोग (1966) के उपरोक्त कथन के सदर में निर्देशन सेवाओं का शाला में क्या महत्व है ?

3. What is the system of prescribing and/or recommending text-books for secondary stage in your state ? Are you satisfied with that system ? If not, why, and what is your alternative suggestion for the same. ?

आपके प्रान्त में माध्यमिक शालाओं के लिए पाठ्य-पुस्तकों निर्धारित करने या उनकी सिफारिश करने की क्या प्रणाली है ? क्या आप उस प्रणाली से सन्तुष्ट हैं ? यदि नहीं, तो बताएं कि क्यों और साथ ही उनके बदले की दूसरी प्रणाली भी सुझाएं।

(राजस्थान विश्वविद्यालय, 1966)

4. What is your opinion about nationalization of text-books at secondary stage ?

चार हैं ?

(राजस्थान विश्वविद्यालय, 1967)

'The provision of quality text books, and other teaching materials, can thus be an effective programme for schools'.

In the light of the above statement how far the provision of quality text books, teacher's guides and teaching materials is helpful in raising the educational standards ?

यदि पाठ्य-पुस्तकों और अन्य शिक्षण तथा सीखने की सामग्री उपलब्धता में पर्याप्त प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं ।

उक्त कथन के सदर्भ में यह बताइये कि अच्छी पाठ्य सामग्री और शिक्षण सामग्री का प्रावधान शैक्षिक स्तर में प्रसार सहायक सिद्ध हो सकता है ?

---

अध्याय दस

## Chapter Tenth

परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता  
और

मूल्यांकन की नवीन विधियाँ

*Need for Reform in Examination System  
&*

*New Methods of Evaluation*

अध्ययन बिन्दु  
Learning points

\* 10.01 वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोष

(Defects of Present Examination System)

1. प्रमाणिकता और विश्वसनीयता का अभाव
2. अपूर्ण ज्ञान एवं संयोग पर आधारित
3. विज्ञान के एक पक्ष का प्रतिरूप
4. सम्पूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया पर परीक्षा का आधिपत्य
5. विद्यार्थियों के सम्पूर्ण विकास पर कुरा प्रभाव

\* 10.02 परीक्षा-वद्धति में सुधार की आवश्यकता ?

(Need for Examination Reform) ?

1. शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु
2. शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन हेतु
3. सर्वार्थ विकास की श्रुति हेतु

\* 10.03 मूल्यांकन का क्षेत्र

(Scope of Evaluation)

1. शारीरिक विकास
2. मानसिक सम्बन्धी उन्नति

३. व्यक्तित्व और सामाजिक गुण

4. रचियाँ और अभिवृत्तियाँ

5. पाठ्यपत्र प्रवृत्तियाँ

• 10.04 मूल्यांकन की नवीन विधियाँ

(New Methods of Evaluation)

परीक्षा सुधार का नवीन कार्यक्रम

• 10.05 माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशें

(Recommendations of Secondary Education Commission)

• 10.06 शिक्षा आयोग (1964-66) की सिफारिशें

(Recommendations of Education Commission 1964-66)

# परीक्षा-प्रणाली में सुधार की आवश्यकता और

## मूल्यांकन की नवीन विधियाँ

*NEED FOR REFORM IN EXAMINATION SYSTEM*

*&*

*NEW METHODS OF EVALUATION*

वर्तमान भारतीय शिक्षा की समस्याओं में प्रचलित परीक्षा-प्रणाली भी विद्यार्थी समस्या के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित है। आज प्राथमिक स्तर से विश्व-विद्यालय स्तर तक की समस्त परीक्षाओं में विद्यार्थियों का एक मात्र उद्देश्य किसी भी तरह परीक्षा पास करना हो गया है जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा के अन्य उद्देश्य वर्तमान परीक्षा की दूषित पद्धति की बन्धनबंदी पर होम हो गये हैं और समेकित-सम्पूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया से ज्ञानात्मक पक्ष समाप्त होता जा रहा है। हमारे सम्पूर्ण समाज में अनुशासनहीनता, राजनैतिक अस्थिरता, स्वार्थपरता और अन्य असाधारण कार्यों का प्रमुख कारण शैक्षिक विवेक-शून्यता है तथा इसका प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व परीक्षा-प्रणाली पर है। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान परीक्षा-पद्धति ने



सामुहिक शिक्षण प्रणाली के अन्तर्गत जो शिक्षण चल रहा है और जो चलना ही  
आगे के सुदूर और दूरबीनी आती दृष्टि से ठीक नहीं लगता वह अस्तित्व की  
विश्वास में उद्देश्य करने है। जो आगे चलकर निम्नलिखित, अत्यन्त ही अनेक  
कारणों से निरस्त हो रहा है। इसी कारण स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त राष्ट्रीय  
आन्दोलन, सुशासनिक आन्दोलन और जातीय आन्दोलन के अन्तर्गत सुशासन  
परिष्कार-प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर विचार चल रहा है। सामुहिक  
में परिष्कार-प्रणाली के दोष सुधार जातीय आवश्यकता की और सुशासन की  
विधिनी पर विचार करना है।

### 10.01 वर्तमान परीक्षा-प्रणाली के दोष

#### Defects of Present Examination System

जहाँ तक परीक्षा-प्रणाली के दोष का प्रश्न है उनके विषय में यह नि-  
श्चय हो जाता है कि वर्तमान समय में परीक्षा-प्रणाली एक अत्यन्त  
ही गड़बड़ है। यह ध्यानीय के अन्तर्गत यह है कि परीक्षकों की भूमिका न होकर, आ-  
ज के समाज-युग बन गई है। इनके द्वारा बोलीयता और सूत्रनामकता का प्र-  
योग होकर केवल मात्र ज्ञानहीनता की प्रतियोगिता का प्रदर्शन किया जाता है। ए-  
क के सामने से यह निर्विचार रूप में कहा जा सकता है कि परीक्षा-सूत्रनामकता का  
राम है। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान परीक्षा-प्रणाली अपनी दुरा-  
कारण आलोचना का पात्र बन गई है। अतः से वर्तमान परीक्षा-प्रणाली के नि-  
म्नलिखित दोष हैं —

#### 1. प्रामाणिकता और विश्वसनीयता का अभाव

##### Lack of Validity & Reliability

वर्तमान परीक्षाओं का सबसे बड़ा दोष उनका अप्रामाणिक और अविश्वसनीय  
पक्ष है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इनमें परीक्षकों के समक्ष उद्देश्यों की पूर्ण  
महती की जाती है। आध्यात्मिक स्तर पर प्रायः निम्नग्राहक प्रश्न पूछे जाते हैं जि-  
स कारण परीक्षकों के अंकों में विभिन्नता का होना स्वाभाविक है। यदि एक उत्तर-  
पुस्तिका की पृष्ठ-पृष्ठ परीक्षकों को दिया जाये तो सबसे अधिक अलग-अलग होते हैं।  
इसके अतिरिक्त यह भी देखने में आया है कि यदि एक ही परीक्षक को दो व-  
त्तार-पुस्तिका जांचने को दी जाये तो प्राप्तक पृष्ठ होंगे। हेतु के शोध से यह नि-  
श्चित हो चुका है कि जो विद्यार्थी अध्यापक के अधिक प्रिय होते हैं उन्हें अधिक  
अंक प्राप्त होते हैं और जो छात्र अप्रिय होते हैं उन्हें उनके ज्ञान की तुलना में कम

प्राप्त होने हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि परीक्षकों की व्यक्तिगतता (Subjectivity) के परीक्षण पर विशेष प्रभाव पड़ता है। एशबर्न के मतानुसार 40% एक अथवा असफल परीक्षार्थियों का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि कौन प्रश्न-पत्र पढ़ता है और 10% इस बात पर निर्भर करता है कि प्रश्न-पत्र कब पढ़े गए ?<sup>1</sup>

परीक्षाओं की अविश्वसनीयता के उदाहरण स्टाच और इलिफ्ट के अनुसन्धानों से स्पष्ट होते हैं। उन्होंने एक परीक्षार्थी के उत्तरों की कुछ नकलें की और पृथक-पृथक परीक्षकों के पास भेज दीं। प्राप्तांकों में 50% से 98% तक भ्रमर दिये गये।

इस प्रकार यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वर्तमान परीक्षा-प्रणाली अविश्वसनीय एवम् अप्रामाणिक है और इसका एक मात्र कारण व्यक्तिगत विमिश्रता है जिसकी परीक्षा की वर्तमान प्रणाली में दूर किया जाना सम्भव नहीं। यदि इसी प्रकार परीक्षा पद्धति रही तो परीक्षार्थियों के भाग्य के साथ खिलवाड़ होना निश्चित रूप से सम्भव है।

## 2. अपूर्ण ज्ञान एवं सयोग पर आधारित

**Based on Incomplete Knowledge and Chance**

वर्तमान परीक्षा पद्धति का एक अन्य दोष अपूर्ण ज्ञान और सयोग पर आधारित होना भी है। आज विद्यार्थी को सम्पूर्ण विषय के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परीक्षा में सामान्यतः पाँच प्रश्न करने होते हैं, पाँच प्रश्नों के लिये सम्पूर्ण पुस्तक का अध्ययन करना विद्यार्थी को उचित प्रतीत नहीं होता और वह सम्भावना के आधार पर ही कुछ चुने हुए प्रश्नों के उत्तर तैयार करता ही अक्सर समझता है, जिसमें अपूर्ण ज्ञान की प्रोत्साहन मिलता है।

इसके अनिश्चित वर्तमान परीक्षा पद्धति से बालक के बौद्धिक पक्ष का आभाव नहीं होता। एक मूढ़ बुद्धि छात्र भी परीक्षा में ऊँचे अंक प्राप्त कर सकता है क्योंकि सयोग में यदि उसने तैयार किये हुए प्रश्न ही परीक्षा में आ गये तो निश्चित रूप से उसे लाभ होगा। इसी प्रकार एक प्रतिभाशाली छात्र सयोगवश बहुत कम अंक प्राप्त कर सकता है। संक्षेप में वर्तमान परीक्षा पद्धति दूषित है।

## 3. विकास [ एक पक्ष का प्रतिरूप

**Symbol of Single Aspect of Development**

आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाएँ बालक की सैद्धिक उन्नति और बौद्धिक,

1. Passing or failing of about 40% depends on who reads the papers and of about 10% depends upon when the papers are read'

प्रवृत्ति की ही जांच करने का प्रयत्न करती है। इन परीक्षाओं द्वारा वाद्य के विषय के अन्य पक्षों का परीक्षण नहीं होता, यदि इनके द्वारा परीक्षण होता भी है अत्यल्प रूप में। गिद्या का एक मात्र उद्देश्य वाद्यकों में बौद्धिक कुशलताओं प्रतिपादन करना ही नहीं है बल्कि छात्रीयक स्वस्थ, ज्ञान सम्बन्धी उच्च शक्तिगण और सामाजिक गुण जैसे भावात्मक स्थिरता, उत्तरदायित्व की भावना, श्रम शक्ति सहयोग की भावना, सामाजिक सेवा की भावना, अनुशासन, नियमित स्वच्छता, वादित्व कवियों जैसे साहित्यिक, कलात्मक, वैज्ञानिक और महावृत्त अभिवृत्तियों जैसे अध्ययन, अध्यापकों, विद्यालय कार्यकर्तों, विद्यालय सम्पत्ति आदि की ओर एक सर्वोच्च विकास हेतु पाठ्यपत्र प्रवृत्तियों में भाग लेना आदि की जांच के लिये उचित व्यवस्था करना भी है।

बहने का तात्पर्य यह है कि आज की गिद्या का उद्देश्य केवल मात्र बौद्धिक क्षमता प्रदान करना ही नहीं है बल्कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना भी है जब कि आज की परीक्षा प्रणाली केवल आधिक रूप से बौद्धिक दक्षता की ही जांच करती है और अन्य विद्या के अन्य पक्षों की जांच करने में असमर्थ रहती है।

#### 4. सम्पूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया पर परीक्षा का आधिपत्य

##### *Dominance of Examination on Whole Educational Process*

आजकल सम्पूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया पर परीक्षा का पूर्ण रूप से आधिपत्य हो गया है। समस्त विद्यालयों का उद्देश्य नैतिक अथवा अनैतिक रूप से परीक्षा में उत्तीर्ण होना ही रह गया है। अध्यापक की विद्यालय कर्मा परीक्षाफल की चार दीवारी तक सीमित रह गई है। वर्तमान शैक्षिक प्रक्रिया में पाठ्यपत्र और विद्यालय विधियाँ परीक्षाओं की दक्षता में प्रयत्न हो चुकी हैं। यही कारण है कि अजब का विद्यार्थी सस्ती पुस्तकें, कुञ्जिया और गैस पेपर पढ़ना ही उचित समझता है। जिससे गिद्या का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। आज की स्थिति में परीक्षाओं द्वारा पाठ्यक्रम को निर्दिष्ट किया जाता है जबकि वास्तविकता ठीक इसके विपरीत होनी चाहिए।

छात्रों के समस्त आकांक्षों में परीक्षाएँ इस प्रकार छा गई हैं कि छात्र और अध्यापक के लिए परीक्षाएँ ही एक मात्र प्रेरक शक्ति हो गई हैं। छात्रों के शैक्षिक जीवन का एक मात्र केन्द्र बिन्दु परीक्षाएँ उत्तीर्ण करना हो गया है। अब तक छात्रों का कोई भी कार्यक्रम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से परीक्षा से सम्बन्धित

3. Both are intended to test mainly the academic attainments of a pupil and his progress in intellectual pursuits. They do not test the other aspects of the pupil's development, or if they do it is only indirectly

*Report of the Secondary Education Commission p 145.*

नहीं किया जाता, तब तक यह प्रायः असफल रहता है।<sup>1</sup> माध्यमिक शिक्षा आयोग के उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण शैक्षिक जीवन में परीक्षाओं का अतिक्रम है।

### 5. विद्यार्थियों के सम्पूर्ण विकास पर दुरा असर

#### Bad Influence on Students' Development

परीक्षा के भय का बालको के विकास पर बहुत दुरा प्रभाव पड़ता है। परीक्षा के दिनों में अत्यधिक परिश्रम करने के कारण विद्यार्थी शारीरिक दृष्टि से अबाध हो जाते हैं। सवेगारमक रूप से इन दिनों विद्यार्थियों में अस्थिरता आ जाती है, निराशा, उदासीनता, भगनाहट आदि के कारण वे अस्त व्यस्त हो जाते हैं। परीक्षा का कुप्रभाव शालक के नैतिक और सामाजिक विकास पर भी पड़ता है। विद्यार्थी का एक मात्र उद्देश्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना होता है। प्रायः परीक्षा के दिनों में अनैतिक और असामाजिक कार्यों की प्रवृत्ति रहती है। परीक्षा भवन में नकल करना, अध्यापकों के साथ मारपीट, परीक्षकों के पास सीधी पहुँच आदि इन प्रकार के दुरा हैं जो विद्यार्थी के अनैतिक और असामाजिक दुरूप बहूँ जा सकते हैं।

जब विद्यार्थियों में अनैतिकता और असामाजिकता की भावना विकसित होने लगती है तो अनुशासनहीनता का प्रारम्भ हो जाता है। आज के विद्यार्थियों में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई अनुशासनहीनता का सर्व प्रधान कारण—दूषित परीक्षा पद्धति ही है क्योंकि हमारे देश में परीक्षाओं की उत्तीर्ण करने पर ही भावी जीवन की रूपरेखा अवलम्बित है। एक विद्यार्थी जो पूरे वर्ष असामाजिक और अनैतिक काम करता है, परीक्षा में अभिव्यक्तिक तरीकों से अच्छे अंक प्राप्त करता है, परिणामतः उसका भावी जीवन अरुण की अधिकता में सुखमय हो जाता है। इसका प्रभाव अन्य विद्यार्थियों पर भी पड़ता है जिनमें सम्पूर्ण सामाजिक जीवन कुदृष्टियों में प्रभावित हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परीक्षा ही विद्यार्थियों में कलुषित भावनाएँ भरने की उत्तरदायी है।

उपरोक्त किन्तुओं से यह तो स्पष्ट है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन करना है तो सर्वप्रथम परीक्षा पद्धति को ही परिवर्तित करना होगा।

1. They have so pervaded the entire atmosphere of school life that they have become the main motivating force for all effort on the part of pupil as well as teacher. It is not often clearly realised that a pupil's effort throughout his education is concentrated almost wholly on how to get through the examinations. Unless a subject is included in the examination scheme, the pupil is not interested in it. If any school activity is not related directly or indirectly to the examination, is fail to enlist his enthusiasm.



व्यावसायिक निर्देशन सम्भव है। उचित परीक्षा पद्धति न केवल शैक्षिक विकास बल्कि विद्यार्थी की कुशलताओं, योग्यताओं, रुचियों, अभिवृत्तियों सृजनात्मक चिन्तन आदि का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करने में समर्थ होती है। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर शैक्षिक एवम् व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तविक निर्देशन देने के लिए परीक्षा-पद्धति में सुधार की नितान्त आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान परीक्षा प्रणाली सामान्यतया शैक्षिक स्तर की अस्पष्ट सूचना ही प्रदान कर पाती है जिससे निर्देशन सम्भव नहीं।

### 3. सर्वांग विकास को सूचना हेतु

#### For Information of Harmonious Development

परीक्षा पद्धति में सुधार की आवश्यकता इसलिए भी है कि इसके द्वारा बालक की सर्वांग विकास की सूचना नहीं मिल पाती। अतः यह आवश्यक है कि विद्यार्थी की ज्ञान सम्बन्धी सूचना के साथ-साथ उनके अन्य क्षेत्रों में सम्पन्न विकास की सूचना भी प्राप्त हो सके। विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास हेतु यह आवश्यक है कि सम्बन्धित व्यक्तित्वगत सूचना,<sup>1</sup> पारिवारिक पृष्ठ-भूमि सम्बन्धी सूचना<sup>2</sup>, शारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना,<sup>3</sup> बुद्धि सम्बन्धी सूचना,<sup>4</sup> ज्ञान उल्लेख की सूचना,<sup>5</sup> व्यक्तित्वगत एवं सामाजिक गुण तथा रुचियाँ एवं अभिवृत्ति से सम्बन्धित सूचना<sup>6</sup> प्राप्त की जा सके। वर्तमान परीक्षा-पद्धति इन सभी सूचनाओं को देने में असमर्थ है अतः यह नितान्त आवश्यक है कि हममें बाधित सुधार किया जाय।

उपरोक्त बिन्दुओं से यह तो स्पष्ट है कि वर्तमान परीक्षा पद्धति में सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है। सम्पूर्ण शिक्षा प्रक्रिया की सफलता और असफलता का पता परीक्षा द्वारा ही लगाया जा सकता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि परीक्षा पद्धति में सुधार लाया जाय जिनसे उद्देश्यों की पूर्ति हो सके और यह सब तक सम्भव नहीं है जब तक मूल्यांकन का क्षेत्र निर्धारित निश्चित न कर लें।

### 10 DE मूल्यांकन का क्षेत्र

#### Scope of Evaluation

जैसा कि हम कह चुके हैं कि मूल्यांकन त्रिक प्रक्रिया है। इसके अन्तर्गत समस्त मानवीय पहलुओं का अध्ययन करना आवश्यक है जिससे आधार पर निश्चित

1. Personal Information.
2. Information Regarding Family Background.
3. Information Regarding Physical Health.
4. Information Regarding Intelligence.
5. Scholastic Achievement.
6. Information Regarding Personal & Social Qualities and Interests & Attitudes.

पर पहुँचा जा सके। सामान्य रूप में मूल्यांकन के क्षेत्र में निम्नलिखित को समाहित किया जा सकता है —

## शारीरिक विकास

### Physical Development

विद्यार्थियों के शारीरिक विकास की निश्चित सूचना प्राप्त करना नितांत है। इसमें लिये जहाँ तक सम्भव हो किसी योग्य डॉक्टर द्वारा स्वास्थ्य की जाँच। साधारणतया सत्र में तीन बार स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्त प्राप्त की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ शारीरिक दोष जैसे दोष-दन्त, मुँह में कठिनाई, गढ़े दाँत, गढ़े नाखून आदि की सूचना अभ्यापक स्वयं कर सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त सूचनाएँ सत्र-सत्र में अंकित होनी चाहिए और प्रगति पत्र में इसका समावेश होना हमसे अभिभावकों को सभी स्वास्थ्य-सम्बन्धी सूचनाएँ प्राप्त हो सकें। स्वास्थ्य यह है कि शारीरिक विकास का मापन सभी विद्यार्थियों में होना चाहिए। इसका मूल्यांकन के क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है।

एक दृष्टिकोण से यह नितांत महत्वपूर्ण है कि छात्र की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के स्वास्थ्य इतिहास, शारीरिक सीटब, शारीरिक अयमस्यताएँ होती रहे। प्रायः शारीरिक दोषों के कारण अनियमित और जान-बूझ कर प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। शारीरिक अयमस्यताओं का विद्यार्थी विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

किसी एक विशेष विधियों में स्वास्थ्य का सामान्य विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन के क्षेत्र में प्रत्येक छात्र का पुनीत बर्तन है कि स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनाओं का अभिलेखन किया जाये।

### सम्बन्धी उपलब्धि

### Academic Achievement

एक शैक्षणिक प्रक्रिया में ज्ञानार्जन की शैक्षणिक महत्त्व प्रदान किया जाता है। एवमात्र कारण यह है कि अब तक काय प्रतीक्षा की ही महत्त्व प्रदान है और मूल्यांकन के अन्तर्गत सभी संबंधी उपलब्धि की जाँच है। यह नितांत आवश्यक हो गया है कि ज्ञान प्राप्ति का एक मात्र आधार ही नहीं होनी चाहिए। जब यह आवश्यक है कि छात्र के शैक्षणिक ज्ञान, ज्ञान के उपयोग की क्षमता, समस्याओं में पुनर्स्थापना आदि का बर्तन का मापन है कि ज्ञानार्जन सम्बन्धी सम्बन्धी उपलब्धि की जाँच में समाहित करना है। अभिलेखन किया जाये और केवल मात्र

### Conclusion

वाह्य परीक्षा को ही सफलता का आधार न मानकर वर्ष भर की ज्ञानार्जन उपलब्धि को अभिलक्षित किया जाये।

### 3. व्यक्तिगत और सामाजिक गुण

#### Personal & Social Qualities

बौद्धिक सत्त्व को किसी सीमा विनये तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। बौद्धिक पक्ष के अनेक स्वरूप हैं जो दैर्घिक प्रगति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने हैं। भ्रम की महत्ता, सहयोग, भावात्मक स्थिरता, उत्तरदायित्व की भावना, सामाजिक सेवा, अनुशासन, नियमितता, स्पष्टता, समय का ध्यान आदि गुण शैक्षिक जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। ये समस्त व्यक्तिगत और सामाजिक गुण विद्यार्थी के ज्ञान एवं कौशल को प्रभावित करने हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का मूल्यांकन करना नितान्त आवश्यक है। प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति एवं जीवन की सफलता इन्हीं गुणों पर निर्भर रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन समस्त गुणों को मूल्यांकन के कार्यक्रम में समाहित करना नितान्त आवश्यक है।

### 4. रुचियाँ और अभिवृत्तियाँ

#### Interests and Attitudes

रुचियों और अभिवृत्तियों का प्रदर्शन मानवीय व्यवहारों में होता है। विद्यार्थी में जैसी रुचियाँ और अभिवृत्तियाँ होती हैं उसी के अनुरूप वह व्यवहार करता है। अतः रुचियाँ और अभिवृत्तियाँ मानव विकास का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। यदि बालकों की रुचियों और अभिवृत्तियों में वांछित परिमार्जन किया जाये तो निश्चित ही उनके सम्कारों को परिष्कृत किया जा सकता है। रुचियों में सामान्य रूप से कलात्मक, मगीतात्मक, वैज्ञानिक और सामाजिक सेवा आदि को समाहित किया जा सकता है। अभिवृत्तियों के अन्तर्गत अभ्ययन, शिक्षक शाला एवं अन्य वांछित सामग्रियों के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों को समाहित कर सकते हैं। अतः मूल्यांकन के क्षेत्र में रुचियों और अभिवृत्तियों को भी सम्मिलित करना आवश्यक है।

### 5. पाठ्येतर प्रवृत्तियाँ

#### Co-curricular Activities

सम्पूर्ण दैर्घिक व्यवस्था में पाठ्येतर प्रवृत्तियों का महत्वपूर्ण स्थान है।

के साथ-साथ रुचियों, अभिवृत्तियों और वांछित गुणों के विकास में आता है। मूल्यांकन की व्यापक योजना में पाठ्येतर प्रवृत्तियों तथा खेल कूद आदि को समाहित किया जा

है



उपरोक्त विन्दुओं से यह स्पष्ट है कि बालक के सर्वांगीण विकास हेतु की विस्तृत योजना बनाना नितान्त आवश्यक है जिसमें शारीरिक, मान-सामाजिक और सवेगात्मक विकास को सम्मिलित करना नितान्त आवश्यक है। इसके लिए यह आवश्यक है कि मूल्यांकन का नवीन कार्यक्रम बनाया जाये जो नवीन विधियों पर आधारित हो।

### 10.0.4 मूल्यांकन की नवीन विधियाँ New Methods of Evaluation

जैसा कि हम स्पष्ट कर चुके हैं कि मूल्यांकन सम्पूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का एक अविच्छेद्य अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक साधन है। मायका के द्वारा केवल मात्र बालकों में व्यवहार परिवर्तन ही नहीं बल्कि शिक्षा प्रक्रिया में सुधार भी सम्भव है। इसके द्वारा पंक्षिक उपलब्धि का गही मापन तो जा ही है, इसके अतिरिक्त शिक्षण प्रक्रिया में सुधार होता है। पहले का तात्पर्य यह है कि मूल्यांकन का शिक्षा व्यवस्था में अडिनीय स्थान है। परन्तु हमारे देश में अभी तक निबन्धात्मक पद्धति को ही अपनाया जाता रहा है और अन्य देशों में मूल्यांकन के क्षेत्र में हुए नवीन प्रयोगों और नवीन विधियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बालकों के समय विकास हेतु यह निगमन आवश्यक है कि हम मूल्यांकन प्रक्रिया में सभी पक्षों के मूल्यांकन को ध्यान दे और मूल्यांकन की उन विधियों की प्रयोग में लायें जो विश्वसनीय हों, यथानुचित हों तथा व्यावहारिक हों। शिक्षण परीक्षा द्वारा छात्रों के सम्पूर्ण विद्या क्षेत्रों का मूल्यांकन सम्भव नहीं है, इसके लिए आवश्यक है कि अन्य विधियों जैसे निरीक्षण, मौखिक परीक्षा, विद्यात्मक परीक्षा तथा अन्य विधियों को प्रयोग में लाया जाये।

मूल्यांकन की नवीन विधियों को प्रयोग में लाने समय हमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण विन्दुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में हम यह कहते हैं कि मूल्यांकन विधियों को निम्नलिखित नवीनी पर परा उपरता निगमन आवश्यक है—

#### 1. विश्वसनीयता Reliability

विधि का विश्वसनीय होना शिक्षण आवश्यक है। विश्वसनीय विधि के अन्तर्गत शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन करने विधि में अंतर होने के सम्बन्ध में प्रश्न है कि शिक्षक विधि में अंतर होने के कारण मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों के मूल्यांकन में अंतर होगा या नहीं? यदि हाँ तो यह अंतर कितना होगा? यदि नहीं तो यह अंतर कितना होगा?

## 2. वैधता

### Validity

परीक्षा का वैध होना भी आवश्यक है। वैधता का सामान्य अर्थ है परीक्षा में शुद्धता और साधकता का विद्यमान होना। विद्वत्सनीयता के साथ वैध होना आवश्यक नहीं है परन्तु वैध होने के लिए विद्वत्सनीय होना आवश्यक है। उदाहरणार्थ किसी विषय की अनेकों बार परीक्षा लेने पर सदैव एक ही फल की प्राप्ति विधि की विद्वत्सनीयता की ओतक तो होगी परन्तु सम्भव है कि उस परीक्षा विधि द्वारा वांछित योग्यता का मापन ही न हो रहा हो, ऐसी स्थिति में परीक्षा विद्वत्सनीय तो होगी परन्तु वैध नहीं।

## 3. वस्तुनिष्ठता

### Objectivity

परीक्षा में वस्तुनिष्ठता का होना नितात्म आवश्यक है। वस्तुनिष्ठता का विद्वत्सनीय एवं वैधता में घनिष्ठ सम्बन्ध होना आवश्यक है। परीक्षा में वस्तुनिष्ठता का सामान्य अर्थ है—प्रत्येक प्रश्न का निश्चित मूल्यांकन होना तथा प्रत्येक प्रश्न का निश्चित उत्तर प्राप्त होना।

## 4. भेदकरण

### Discrimination

भेदकरण से तात्पर्य है—विभिन्न बौद्धिक क्षमता वाले विद्यार्थियों में भेद करने की क्षमता। विभेदकारी प्रश्नों में यह क्षमता होनी चाहिए जिससे प्रतिभाशाली, सामान्य और मामान्य में नीचे के बौद्धिक योग्यता वाले छात्रों का पता लगाया जा सके।

## 5. व्यापकता

### Comprehensiveness

परीक्षा में व्यापकता का अर्थ है—सम्पूर्ण विषय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व। जैसा कि हम पिछले पृष्ठों में कह चुके हैं कि वर्तमान परीक्षा पद्धति का सबसे बड़ा दोष व्यापकहीनता है अर्थात् विद्वत्सनीय प्रश्नों में सम्पूर्ण विषय को समाहित नहीं किया जाता क्योंकि सामान्य रूप से हम प्रश्न पूछे जाते हैं और यह विद्यार्थी के समीप पर निर्भर करता है कि वह उस विषय के अन्य अध्ययन में कितने अंक प्राप्त करें। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रश्न पत्र पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित होना चाहिए।

सफल मूल्यांकन हेतु यह आवश्यक है कि किसी भी परीक्षा को बनाने से पूर्व हम यह देखें कि उसमें उपरोक्त विशेषताएँ हैं अथवा नहीं। यह तो हम सभी स्वीकार करते हैं कि शिक्षा में परीक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है और वर्तमान

उपरोक्त विन्दुओं में यह स्पष्ट है कि वास्तव में नवीनीकरण प्रणाली मूल्यांकन की विस्तृत योजना बनाना निम्नलिखित आवश्यक है जिसमें कार्यात्मक, सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय और नैतिक विचारों का सम्मिलन करना शामिल है। निष्ठा के उद्देश्यों की व्याख्या को ध्यान में रखते हुए निष्ठा का संपूर्ण विषय ज्ञान की प्राप्ति में न केवल सम्पूर्ण जीवन के कार्यक्रमों में सेना बित्त आवश्यक है। इसके लिए यह आवश्यक है कि मूल्यांकन का नवीन कार्यक्रम बना जाये जो नवीन विधियों पर आधारित हो।

### 10.04 मूल्यांकन की नवीन विधियाँ New Methods of Evaluation

जैसा कि हम स्पष्ट कर चुके हैं कि मूल्यांकन सम्पूर्ण निष्ठा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है और निष्ठा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक माध्यम है। मूल्यांकन के द्वारा केवल मात्र वास्तविक में व्यवहार परिवर्तन ही नहीं बल्कि निष्ठा विधियों में सुधार भी सम्भव है। इसके द्वारा संक्षिप्त उपलब्धि का सही मापन होता है, इसके अतिरिक्त निष्ठा प्रक्रिया में सुधार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूल्यांकन का निष्ठा व्यवस्था में अतिरिक्त स्थान है। परन्तु हमारे देश में अभी तक निष्ठाप्रणाली की ही अपेक्षा जाता रहा है और अन्य देशों में मूल्यांकन के क्षेत्र में हुए नवीन प्रयोगों और नवीन विधियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। वास्तविक में समय बिताने से यह निष्ठा आवश्यक है कि हम मूल्यांकन प्रक्रिया में सभी पक्षों के मूल्यांकन को स्थान दें और मूल्यांकन की उन विधियों के प्रयोग में लायें जो विश्वव्यापी हों, प्रत्युत्पन्न हों तथा व्यावहारिक हों। निम्न परीक्षा द्वारा छात्रों के सम्पूर्ण विचार क्षेत्रों का मूल्यांकन सम्भव नहीं है, इसके लिए आवश्यक है कि अन्य विधियों जैसे निरीक्षण, भौतिक परीक्षा, विचारमंच परीक्षा तथा अन्य विधियों को प्रयोग में लाया जाये।

मूल्यांकन की नवीन विधियों को प्रयोग में लाने समय हमें महत्वपूर्ण विन्दुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे सामने हैं कि मूल्यांकन विधियों को निम्नलिखित कमीडों पर तथा आवश्यक है—

#### 1. विश्वसनीयता Reliability

विधि का विश्वसनीय होना नितांत आवश्यक है। विभिन्न विचारों द्वारा प्राप्त की सभी स्थिति में अन्य बातों के रहते हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षा की सचेतनता अतिपरता तथा भारणा द्वारा प्रसार से परीक्षाफल की प्रभावित नहीं करेगा

- नवीन उद्देश्य निरूपणता एवं परीक्षण हेतु शिक्षण प्रविधा में परिवर्तन किया जाये।
- नवीन मूल्यांकन की धारणा को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने के माध्यमिक स्तर के समस्त अध्यापकों को इससे परिचित कराया जा
- इस कार्यक्रम को समस्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में आ
- दिया जाये जिससे समस्त छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिका सम्बन्धित ज्ञान दिया जा सके।
- परीक्षण और शिक्षण को नवीन उद्देश्यों से निरूपित करने के लिए
- क्रम को परिवर्धित किया जाये।

### 10.0॥ माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशें

*Recommendations of Secondary Education Com*

आयोग ने परम्परागत परीक्षा पद्धति को अनुचित एवं निरर्थक तथा परीक्षा सुधार हेतु निम्नलिखित सिफारिशें की—

1. बाह्य परीक्षाओं की संख्या में कमी की जाये। निष्पक्षतात्मक प
- की व्यवस्था कम करने के लिए, नवीन प्रकार के प्रश्न पूछे जा
2. परीक्षा में प्रश्न सम्पूर्ण विषय सामग्री से पूछे जायें।
3. परीक्षा में वस्तुनिष्ठ जोकों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाय।
4. विद्यार्थियों के क्षमों का अन्तिम मूल्यांकन करते समय 3
- मूल्यांकन तथा सचित अमिलेय को उचित महत्व प्रदान किया
5. बाह्य परीक्षा में पूरक परीक्षा की प्रणाली का प्रयोग किया जाय
6. छात्रों का अन्तिम मूल्यांकन आन्तरिक परीक्षाओं तथा विद्याल
- केन्द्रों पर आधारित होना चाहिए।
7. बाह्य एवं आन्तरिक परीक्षाओं में मूल्यांकन का आधार पा
- मापदण्ड (Five Point Scale) होना चाहिए।
8. परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् यदि कोई विद्यार्थी बाहे
- अतिरिक्त विषय की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

उपरोक्त सुझावों से यह स्पष्ट है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। बालक के सर्वांग विकास के मूल्यांकन हेतु यह आ कि बाह्य और आन्तरिक परीक्षाओं, नियतकालिक जोकों, विद्यालय आदि को उचित महत्व प्रदान किया जाय। यह प्रमत्तता का विषय है कि के सुझावों के अनुसार कुछ माध्यमिक शिक्षा बोर्डों ने इस ओर प्रभावश किया है।

# 10 ८६ शिक्षा आयोग (1964-66) की सिफारिशें

Recommendations of Education Commission (1964-66)

बोर्डों आयोग ने मूल्यांकन को शिक्षा प्रणाली का अंग बनाना है। मूल्यांकन के द्वारा केवल मात्र बालकों के व्यवहार और आदतों में परिवर्तन ही नहीं होगा बल्कि हमारे शिक्षण विधियों में सुधार भी होगा है। मूल्यांकन पद्धति में सुधार लाने तथा कार्यक्रम को विस्तृत बनाने हेतु आयोग ने अग्रनिर्दिष्ट सिफारिशें की —

1. मूल्यांकन के नवीन कार्यक्रम द्वारा निम्नित परीक्षाओं को सुधारा जाय एवं उन्हें अधिक विद्यमान बनया जाय।
2. छात्रों के समस्त विद्यालय क्षेत्रों को मानने का प्रयत्न किया जाय, इसके लिए आवश्यक है कि उन विषयों का पता लगाया जाय जिनमें छात्रों के शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, सव्यवहारिक विद्यालय में मूल्यांकन हो गये क्योंकि निम्नित परीक्षाओं में यह सम्भव नहीं है।
3. पूर्व प्राथमिक स्तर पर बाह्य बुद्धिमानता, योग्यताओं, आदतों एवं व्यवहारों में परिवर्तन करने के लिए उचित मूल्यांकन पद्धति को अपनाया जाय।
4. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर निम्नित परीक्षाओं के अतिरिक्त मौखिक और निदानात्मक परीक्षाओं को उपयोग में लाया जाये।
5. सभी पक्षों में प्रगति देखने के लिए सचित अभिलेख पत्रों का प्रयोग किया जाये।
6. प्राथमिक स्तर की समाप्ति पर बाह्य परीक्षा की व्यवस्था हो और उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण-पत्र (Certificate) दिया जाय।
7. छात्रवृत्तियाँ और योग्यता प्रमाण-पत्र विविष्ट जातों के आधार पर दिये जाने चाहिये।
8. बाह्य परीक्षाओं को अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ बनाया जाये।

योगात्मक विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। इन विद्यालयों में यह स्वतन्त्रता दी जाय कि वे अपना पाठ्यक्रम और सम्बन्धित पाठ्य-पुस्तकों का चयन कर सकें, एवं मूल्यांकन के लिए नवीन विधियों का प्रयोग कर सकें। कक्षा दस के पश्चात् पुष्क परीक्षाएँ लेने का अधिकार प्रदान किया जाय सफल छात्रों को प्रयोगात्मक परीक्षाओं की सहाय्य के आधार पर राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रमाण-पत्र दिये जाने चाहिये।

मूल्यांकन योजना (Comprehensive Internal Evaluation Scheme) बनाई जाय जिसमें बालकों के समस्त पक्षों को मूल्यांकन किया जाय।

11. बाह्य परीक्षाओं के साथ ही आन्तरिक जाँचों जैसे निरीक्षण, मौखिक परीक्षा, रूचियों, योग्यताओं, अभिवृत्तियों आदि को जाँचने के लिए विभिन्न प्रमाणीकृत जाँचों का प्रयोग किया जाय।

कोटारी आयोग द्वारा दी, गई उपरोक्त सिफारिशों वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान परीक्षा-पद्धति के दोषपूर्ण होने के कारण विद्यार्थियों में दिन प्रतिदिन अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है, वास्तविक प्रतिभा वाले छात्रों का चपन नहीं होता जाता जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था में अराजकता फैल गई है। हमने अभी तक निबन्धात्मक प्रणाली को ही अपनाया है। हमारे देश में समुचित नवीन मूल्यांकन विधियों का प्रयोग नहीं हुआ है। कोटारी आयोग ने सचित अमि-लेस और आन्तरिक मूल्यांकन के सुझावों द्वारा बालक के सर्वाङ्ग विकास की जाँच सुझाई है जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आन्तरिक मूल्यांकन योजना सम्बन्धी सुझाव अति उत्तम है, हमने केवल वास्तविक मूल्यांकन ही नहीं बल्कि अनुशासन-हीनता भी कम होयी। यह प्रमत्तता का विषय है कि कुछ राज्यों में आन्तरिक मूल्यांकन के आरम्भ करने हेतु विचार हो रहा है। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग, राष्ट्रीय वैश्विक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्, देहली के सहयोग से परीक्षा सुधार का एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया है। इसके अतिरिक्त आन्तरिक मूल्यांकन की प्रणाली को सुधारने के लिए एक व्यापक योजना आरम्भ कर दी है। इस योजना का परीक्षण राज्य के कुछ चुने हुए विद्यालयों में 1965 से 1967 तक किया गया। इन विद्यालयों के अध्यापकों तथा प्रधानाध्यापकों ने आन्तरिक मूल्यांकन के सम्बन्ध में विभिन्न उपकरण तथा प्रक्रियाएँ विकसित की तथा अपने अपने विद्यालयों में उनका परीक्षण किया। विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मापदण्ड निश्चित करने के अतिरिक्त उन्होंने निदानात्मक जाँच-पत्र, इकाई परीक्षा-पत्र तैयार किए। बोर्ड एवं मूल्यांकन व पाठ्यक्रम विभाग ने इस योजना की अंतिम रूप दिया। बोर्ड की वर्तमान संचितवस्तु प्रणाली के अनुसार आन्तरिक परीक्षाओं में प्राप्तांक बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों से जोड़े जाते हैं। यह प्रथा 1969 की माध्यमिक स्कूल परीक्षा एवं हायर सेकेंडरी परीक्षाओं से निरस्त कर दी जायगी। विद्यालयों की आन्तरिक मूल्यांकन का प्रमाण-पत्र जिस पर बोर्ड की मुद्रा अंकित होगी 1969 से देने का अधिकार होगा।<sup>1</sup> यदि अन्य राज्यों के शिक्षा बोर्ड भी मूल्यांकन का नवीन कार्यक्रम प्रारम्भ कर दें तो माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र की अनेकों समस्याओं का समाधान सम्भव है।

1. Board of Secondary Education, Rajasthan, Ajmer, *Manual of Instructions on Comprehensive Internal Assessment*, Department of Curriculum & Evaluation, N C, E R T, New Delhi—16



## विश्वविद्यालय प्रश्न

### University Questions

Examine the major defects in the examination system in the light of the above statement.

1. यदि शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में किसी एक सुधार का सुझाव दिया जाय, तो वह केवल मुद्दांकन से सम्बन्धित है।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग

उपरोक्त कथन के सम्बन्ध में वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोष बताओ।

2. How far do you think that there is a need for examination reform?

परीक्षा पद्धति में सुधार की आवश्यकता के विषय में आपका क्या विचार है?

3. 'The whole purpose of the proposal is to reform the existing examination by making it less formal, reducing its burden on the pupils' mind, and increasing its validity as a measure of educational attainment.'

(Education commission, 1966.)

Suggest measures of reform in examination system.

‘वर्तमान समय में सुधार करने का उद्देश्य उन्हें कम औपचारिक बनाना, विद्यार्थियों के मस्तिष्क से भार कम करना और वैधता बढ़ाना है जिससे संक्षिप्त उपलब्धि का मापन किया जा सके।’

(शिक्षा आयोग, 1966)

उपरोक्त कथन के सन्दर्भ में परीक्षा प्रणाली के सुधार हेतु सुझाव दीजिए।

4. The cumulative Record is a systematic accumulation of significant factual information about an individual which when progressively developed and maintained over a sufficient period of





## अध्याय ग्यारह

### Chapter Eleventh

## भारतवर्ष में उच्च (विश्वविद्यालय) शिक्षा का विस्तार *Expansion of Higher (University) Education in India*

### अध्ययन बिन्दु

### Learning Point

- 11.01 प्राचीन काल में उच्च शिक्षा

Higher Education in Ancient Period.

- 11.02 मध्यकाल में उच्च शिक्षा

Higher Education in Mediaeval Period.

- 11.03 ब्रिटिश काल में उच्च शिक्षा

Higher Education in British Period;

1. प्रारम्भिक ब्रिटिश शासन से 1857 तक

2. सन् 1857 से 1917 तक

3. सन् 1917 से 1947 तक

- 11.04 स्वतन्त्र भारत में उच्च शिक्षा

Higher Education in Free India

1. भारत में विश्वविद्यालय

2. उच्च शिक्षा का प्रसार

3. वैश्वीय विश्वविद्यालय

4. प्राथमिक उच्च शिक्षा

## भारतवर्ष में उच्च (विश्वविद्यालय) शिक्षा का विस्तार

### *EXPANSION OF HIGHER (UNIVERSITY) EDUCATION IN INDIA*

उच्च शिक्षा का विस्तार प्राचीन भारतीय शिक्षा-व्यवस्था से प्रारम्भ होता है। यद्यपि प्राचीन अथवा मध्यकालीन उच्च शिक्षा का आधुनिक उच्च शिक्षा पर कोई भी प्रभाव नहीं है तथापि भारत का एतियाई देशों से जो 'सांस्कृतिक सम्बन्ध' है उसका अर्थ प्राचीन उच्च शिक्षण संस्थाओं की ही है। अतः भारत में उच्च शिक्षा का विस्तार प्राचीन भारतीय शिक्षा-व्यवस्था से देखना अधिक आवश्यक है।

#### 11.01 प्राचीनकाल में उच्च शिक्षा

##### *Higher Education in Ancient Period*

प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का प्रावधान था। वैदिक युग में परिषदों द्वारा उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। परिषदों में अनेकों विद्वान एकत्र होने से ओर शान्तिपूर्ण करते थे। तत्कालीन प्राचीन भारतीय शिक्षा का केन्द्र था। तत्कालीन शासक प्राचीन भारत ने इसकी नींव डाली थी और अपने गांधार प्रदेश की राजधानी थी एवम् भारत ने इसकी नींव डाली थी और अपने गांधार प्रदेश की राजधानी थी।

उच्च शिक्षा सरपाओं का सुमंगलित प्रारम्भ बौद्ध काल में हुआ। काशी (वाराणसी), नासन्दा (बिहार), तथशिला (पश्चिम बंगाल), विक्रमशिला और जगद्गला तथा ओदन्तपुरी (बंगाल), जयन्दरा बिहार (काश्मीर), काशी (मद्रास), बल्लभी (सौराष्ट्र) आदि इन प्रसिद्ध शिक्षा केन्द्रों के अतिरिक्त कुछ और भी शिक्षा केन्द्र थे जिनमें मुख्यतः चिनपति और जालधर के बौद्ध बिहार (पंजाब), माणपुर बिहार (उत्तर प्रदेश), मदबिहार, अमरावती (आंध्र प्रदेश), सालोली विद्यापीठ (बम्बई), एन्नामियरम देवालय विद्यापीठ और व्यक्टेरा वेरुमल देवालय तथा थिरवोरियूर विद्यापीठ (दक्षिण भारत) आदि विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे शिक्षा केन्द्र भी रहे होंगे जो काल के काल से समा गये और जिनके अवशेष मात्र भी शेष नहीं रहे।

उपरोक्त उद्धरणों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्राचीन युग में हमारे देश के अन्तर्गत उच्च शिक्षा की अत्यन्त ही सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित दशा थी। इन शिक्षा केन्द्रों ने केवल भारत के ही नहीं बल्कि सुदूर देशों के छात्रों को भी आकर्षित किया एवम् अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त किया। समय के क्रम ने हमारे विद्या मन्दिरों को अधिक समय तक न रहने दिया और आज केवल कुछ शिक्षा केन्द्रों के अवशेष मात्र हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में उच्च शिक्षा की अत्यन्त ही सुव्यवस्थित व्यवस्था थी।

## 11.02 मध्यकाल में उच्च शिक्षा

### Higher Education in Mediaeval Period

मध्यकाल में शिक्षा का स्वरूप बिल्कुल परिवर्तित हो गया। भारतीय संस्कृति पर आघातित प्राचीन शिक्षा धीरे-धीरे लोप होने लगी। मध्यकाल में उच्च शिक्षा हेतु, 'मदरसे' लोप गये। अरबी भाषा में 'दरसे' का अर्थ है 'भाषण करना' अतः मदरसों में भाषण द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी जिनमें उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। इन मदरसों की मुसलमान बादशाह अथवा उनके प्रतिनिधि सौमते थे। दिल्ली, आगरा, मसनाऊ, रामपुर, लाहौर, अजमेर, बीनपुर आदि में प्रतिष्ठित मदरसे थे। इन मदरसों में इतिहास, दर्शनशास्त्र, अरबी, फारसी, धर्म, राजनीति एवम् व्याकरण का अध्ययन किया जाता था। सामान्यतया शिक्षा का भाष्यम अरबी था। कुछ मदरसों में विशिष्ट विषयों की भी व्यवस्था थी, उदाहरणार्थ रामपुर तर्कशास्त्र और चिकित्सा के लिए, लखनऊ धर्म-शास्त्र के लिए और लाहौर गणित एवम् सगोल के लिए विख्यात थे।

गर्भ-स्थान देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया, फलस्वरूप सत्तरहवीं और अठारहवीं शताब्दी में उच्च शिक्षा के केन्द्र लोप होने लगे।

... of the ...  
... of the ...  
... of the ...  
... of the ...

11-01 [illegible] [illegible] [illegible]  
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

1. ब्रह्मिन्द सिंघा राज्य 1927 मे
2. म० 1857 मे 1917 मे
3. म० 1917 मे 1947 मे
1. ब्रह्मिन्द सिंघा राज्य मे 1857 म०  
From Early British Rule to 1857

1. 1937  
2. 1938  
3. 1939  
4. 1940  
5. 1941  
6. 1942  
7. 1943  
8. 1944  
9. 1945  
10. 1946  
11. 1947  
12. 1948  
13. 1949  
14. 1950  
15. 1951  
16. 1952  
17. 1953  
18. 1954  
19. 1955  
20. 1956  
21. 1957  
22. 1958  
23. 1959  
24. 1960  
25. 1961  
26. 1962  
27. 1963  
28. 1964  
29. 1965  
30. 1966  
31. 1967  
32. 1968  
33. 1969  
34. 1970  
35. 1971  
36. 1972  
37. 1973  
38. 1974  
39. 1975  
40. 1976  
41. 1977  
42. 1978  
43. 1979  
44. 1980  
45. 1981  
46. 1982  
47. 1983  
48. 1984  
49. 1985  
50. 1986  
51. 1987  
52. 1988  
53. 1989  
54. 1990  
55. 1991  
56. 1992  
57. 1993  
58. 1994  
59. 1995  
60. 1996  
61. 1997  
62. 1998  
63. 1999  
64. 2000  
65. 2001  
66. 2002  
67. 2003  
68. 2004  
69. 2005  
70. 2006  
71. 2007  
72. 2008  
73. 2009  
74. 2010  
75. 2011  
76. 2012  
77. 2013  
78. 2014  
79. 2015  
80. 2016  
81. 2017  
82. 2018  
83. 2019  
84. 2020  
85. 2021  
86. 2022  
87. 2023  
88. 2024  
89. 2025  
90. 2026  
91. 2027  
92. 2028  
93. 2029  
94. 2030  
95. 2031  
96. 2032  
97. 2033  
98. 2034  
99. 2035  
100. 2036  
101. 2037  
102. 2038  
103. 2039  
104. 2040  
105. 2041  
106. 2042  
107. 2043  
108. 2044  
109. 2045  
110. 2046  
111. 2047  
112. 2048  
113. 2049  
114. 2050  
115. 2051  
116. 2052  
117. 2053  
118. 2054  
119. 2055  
120. 2056  
121. 2057  
122. 2058  
123. 2059  
124. 2060  
125. 2061  
126. 2062  
127. 2063  
128. 2064  
129. 2065  
130. 2066  
131. 2067  
132. 2068  
133. 2069  
134. 2070  
135. 2071  
136. 2072  
137. 2073  
138. 2074  
139. 2075  
140. 2076  
141. 2077  
142. 2078  
143. 2079  
144. 2080  
145. 2081  
146. 2082  
147. 2083  
148. 2084  
149. 2085  
150. 2086  
151. 2087  
152. 2088  
153. 2089  
154. 2090  
155. 2091  
156. 2092  
157. 2093  
158. 2094  
159. 2095  
160. 2096  
161. 2097  
162. 2098  
163. 2099  
164. 2100  
165. 2101  
166. 2102  
167. 2103  
168. 2104  
169. 2105  
170. 2106  
171. 2107  
172. 2108  
173. 2109  
174. 2110  
175. 2111  
176. 2112  
177. 2113  
178. 2114  
179. 2115  
180. 2116  
181. 2117  
182. 2118  
183. 2119  
184. 2120  
185. 2121  
186. 2122  
187. 2123  
188. 2124  
189. 2125  
190. 2126  
191. 2127  
192. 2128  
193. 2129  
194. 2130  
195. 2131  
196. 2132  
197. 2133  
198. 2134  
199. 2135  
200. 2136  
201. 2137  
202. 2138  
203. 2139  
204. 2140  
205. 2141  
206. 2142  
207. 2143  
208. 2144  
209. 2145  
210. 2146  
211. 2147  
212. 2148  
213. 2149  
214. 2150  
215. 2151  
216. 2152  
217. 2153  
218. 2154  
219. 2155  
220. 2156  
221. 2157  
222. 2158  
223. 2159  
224. 2160  
225. 2161  
226. 2162  
227. 2163  
228. 2164  
229. 2165  
230. 2166  
231. 2167  
232. 2168  
233. 2169  
234. 2170  
235. 2171  
236. 2172  
237. 2173  
238. 2174  
239. 2175  
240. 2176  
241. 2177  
242. 2178  
243. 2179  
244. 2180  
245. 2181  
246. 2182  
247. 2183  
248. 2184  
249. 2185  
250. 2186  
251. 2187  
252. 2188  
253. 2189  
254. 2190  
255. 2191  
256. 2192  
257. 2193  
258. 2194  
259. 2195  
260. 2196  
261. 2197  
262. 2198  
263. 2199  
264. 2200  
265. 2201  
266. 2202  
267. 2203  
268. 2204  
269. 2205  
270. 2206  
271. 2207  
272. 2208  
273. 2209  
274. 2210  
275. 2211  
276. 2212  
277. 2213  
278. 2214  
279. 2215  
280. 2216  
281. 2217  
282. 2218  
283. 2219  
284. 2220  
285. 2221  
286. 2222  
287. 2223  
288. 2224  
289. 2225  
290. 2226  
291. 2227  
292. 2228  
293. 2229  
294. 2230  
295. 2231  
296. 2232  
297. 2233  
298. 2234  
299. 2235  
300. 2236  
301. 2237  
302. 2238  
303. 2239  
304. 2240  
305. 2241  
306. 2242  
307. 2243  
308. 2244  
309. 2245  
310. 2246  
311. 2247  
312. 2248  
313. 2249  
314. 2250  
315. 2251  
316. 2252  
317. 2253  
318. 2254  
319. 2255  
320. 2256  
321. 2257  
322. 2258  
323. 2259  
324. 2260  
325. 2261  
326. 2262  
327. 2263  
328. 2264  
329. 2265  
330. 2266  
331. 2267  
332. 2268  
333. 2269  
334. 2270  
335. 2271  
336. 2272  
337. 2273  
338. 2274  
339. 2275  
340. 2276  
341. 2277  
342. 2278  
343. 2279  
344. 2280  
345. 2281  
346. 2282  
347. 2283  
348. 2284  
349. 2285  
350. 2286  
351. 2287  
352. 2288  
353. 2289  
354. 2290  
355. 2291  
356. 2292  
357. 2293  
358. 2294  
359. 2295  
360. 2296  
361. 2297  
362. 2298  
363. 2299  
364. 2300  
365. 2301  
366. 2302  
367. 2303  
368. 2304  
369. 2305  
370. 2306  
371. 2307  
372. 2308  
373. 2309  
374. 2310  
375. 2311  
376. 2312  
377. 2313  
378. 2314  
379. 2315  
380. 2316  
381. 2317  
382. 2318

3. 1917 to 1947

1. भारतीय विधि शास्त्र से 1857 तक  
From Early British Rule to 1857

प्रारम्भिक विदेश प्रवास १८५१-५२  
1 from Early British Rule to 1857

[illegible]

2) जनवरी 1817 में राजाराम मोहनराय और हेन्रि क्लेयर ने  
 में हिन्दु धर्म की स्थापना की जिसका प्रमुख उद्देश्य हिन्दु धर्म के  
 शिक्षा के विधान करना था। सन् 1818 में मिशनरियों द्वारा सीराम  
 सोला गया। 1830 में एनडिग एवं क्लिज सोला गया। 1832 में  
 क्लिज एवं सीराम की सीराम और 1837 में मद्रास में मिशनरियों  
 गया। व्यावसायिक शिक्षा की दृष्टि से कलकत्ता में मिशनरियों  
 क्लिज और कलकत्ता में दार्जीलिंग में क्लिज सोले गये। सन् 1845 से  
 कलकत्ता में विश्वविद्यालय सोलने के प्रयाग हुए परन्तु सफलता न मिली।  
 में क्लिजों की जो स्थिति थी वह तालिका नम्बर

तालिका नं० 11.1

1857 में कॉलेज

प्रान्त :	सामान्य शिक्षा के कॉलेज	मेडिकल कॉलेज	सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज
<b>बंगाल</b>			
सरकार द्वारा संचालित	7	1	—
मिशनरी द्वारा संचालित	7	—	—
<b>बम्बई</b>			
सरकार द्वारा संचालित	2	1	—
मिशनरी द्वारा संचालित	—	—	—
<b>पश्चिमोत्तर प्रान्त</b>			
सरकार द्वारा संचालित	4	—	1
मिशनरी द्वारा संचालित	—	—	—
<b>मद्रास</b>			
सरकार द्वारा संचालित	1	1	—
मिशनरी द्वारा संचालित	2	—	—
<b>कुल योग</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

2. सन् 1857 से 1917 तक

From 1857 to 1917

सन् 1854 के ब्रुड के घोषणा-पत्र के द्वारा सर्वप्रथम शिक्षा सम्बन्धी नीति स्पष्ट हुई। घोषणा पत्र में विश्वविद्यालय कोलने की सिफारिश की गई। इसी सिफारिश पर जनवरी 24, 1857 को विश्वविद्यालयों की स्थापना सम्बन्धी बिल

1. B Nurullah and J. P. Naik, *History of Education in India*, Macmillan Bombay, 1931, p. 279

पर गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर हुए। सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय उत्तरवात बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इन तीनों विश्वविद्यालय को संगठन स्वरूप तन्मन् विश्वविद्यालय को आदर्श माना गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय के चान्सलर स्वयं गवर्नर थे। अन्य दोनों विश्वविद्यालयों के चान्सलर वहाँ के गवर्नर थे। चान्सलर की सहायता के लिए वाइस चान्सलर<sup>1</sup> एवम् फेलो<sup>2</sup> की व्यवस्था की गई। तीनों विश्वविद्यालयों में कला, कानून, चिकित्सा और इंजिनियरिंग संकायों की स्थापना की गई। सन् 1882 में पंजाब और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय जोड़े गये। इन समस्त विश्वविद्यालयों का कार्य-केवल सम्बन्धित कॉलेजों और स्कूलों के विद्यापियों की परीक्षा लेना था। सन् 1881-82 में महाविद्यालयों की कुल संख्या 68 थी।

सन् 1864 में लखनऊ में लखनऊ कैनिंग कॉलेज, 1861 में तिनारवेली कॉलेज मद्रास, 1872 में म्योर सेंट्रल कॉलेज और 1875 में सर मैथिल अहमद साहिब द्वारा अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरियण्टल कॉलेज की स्थापना की गई। बंगाल के तीन स्कूलों को कॉलेज बना दिया गया।

1901-2 में महाविद्यालय शिक्षा की सीपता से युद्ध हुई। इस समय तक महाविद्यालयों की कुल संख्या 179 हो गई।

सन् 1890 में लार्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त किये। इस समय राष्ट्रीयता की भावना से भ्रष्ट प्रोत समाज सुधारक भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा की मांग कर रहे थे। लाहौर में दयानन्द ऐंग्लो वैदिक कॉलेज, हरिद्वार में स्वामी अदाकान्त द्वारा स्थापित गुरुकुल और सेंट्रल हिन्दू महाविद्यालय बनारस राष्ट्रीय शिक्षा हेतु तथा इण्डियन नेशनल कावेस भारत की स्वाधीनता हेतु आन्दोलन कर रहे थे। इन्हीं दिनों देश दो दुश्मनों का भी सामना कर चुका था अतः लार्ड कर्जन का भारतीय शिक्षा की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था। इसी लिए लार्ड कर्जन ने 27 जनवरी, 1902 ई० को भारतीय विश्वविद्यालय कमिशन की नियुक्ति की क्योंकि इसके मतानुसार विश्वविद्यालय के दो कार्य होने चाहिए, प्रथम ज्ञान का प्रसार दूसरा मानव जाति को शिक्षित करना। अतः विश्वविद्यालयों का कार्य केवल परीक्षा संबंधी व्यवस्था करना ही नहीं होना चाहिए बल्कि शिक्षण और अनुसंधान करना भी होना चाहिए अतः भारतीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तन करना आवश्यक समझा जा रहा था।

विश्वविद्यालय कमिशन ने विश्वविद्यालयों की दशा का अध्ययन किया और

— निम्नलिखित दिये—

गठन किया जाये सीनेट की अवधि 5 वर्ष हो और उसका आकार छोटा कर दिया जाये।

- सिंडीकेट के सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ाकर 15 कर दी जाये।
- विश्वविद्यालयों के विधान में इस प्रकार से परिवर्तन किया जाये जिससे शिक्षण कार्य की व्यवस्था हो सके।
- सम्बन्धित महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के नियमों में अधिक कड़ाई लायी जाये।
- विश्वविद्यालयों की सीनेटों में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
- विश्वविद्यालयों का सम्बन्धित महाविद्यालयों पर कड़ा निरीक्षण होना चाहिए।
- महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों तथा परीक्षा प्रणाली में वांछित परिवर्तन किया जाये।
- छात्रों के निवास हेतु उचित छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए।
- विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाये।
- प्रत्येक महाविद्यालय में एक प्रबंधकारिणी समिति हो जो महाविद्यालयों की व्यवस्था करें तथा भवन एवं छात्रावास आदि का समुचित निर्माण कराये।

यद्यपि उपरोक्त सिफारिशों का भारतीय जनता में विरोध किया तथापि लाई कर्जेन ने 10 मार्च, 1904 को एक शिक्षा विधेयक प्रस्तुत किया जो 21 मार्च 1904 को कानून बन गया। इस विधेयक के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित थे—

- विश्वविद्यालयों के कार्य क्षेत्र को बढ़ा दिया गया।
- सीनेट के आकार को सीमित कर कैलेंडर की न्यूनतम संख्या 50 और अधिकतम 100 कर दी गयी, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया।
- पुराने विश्वविद्यालयों - कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 और पंजाब एवं इलाहाबाद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 15 निश्चित कर दी गई।
- सिंडीकेट को विधिवत स्वीकृति प्रदान कर उनमें अध्यापकों के प्रतिनिधित्व की उचित व्यवस्था की गई।
- महाविद्यालयों के मान्यता प्राप्त करने के नियमों को कड़ा कर दिया गया।
- महाविद्यालयों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की सीमाएँ निर्धारित करने का अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया।

उपरोक्त विश्वविद्यालय अधिनियम (1904) का भारतीय जनता द्वारा पोर विरोध किया गया। भारतीय नेता यह सोचने लगे कि लाई कर्जेन की शिक्षानीति का सरकारी नियंत्रण द्वारा उच्च शिक्षा के मार्ग में बाधाएँ हैं। विश्वविद्यालयों पर





- (1919) विश्वविद्यालयों में विभिन्न फेल्लोशिप की स्थापना की जाये ।  
 (1920) विश्वविद्यालयों के पारस्परिक सम्बन्धों को बढ़ाने के लिए अन्तर्विश्व-  
 विद्यापीठ बोर्ड की स्थापना की जाये ।  
 (1921) उपरोक्त सुझावों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई :—

अन्तर्गत विश्वविद्यालय (1919), मुंबई विश्वविद्यालय (1920), हाफा  
 स्ली विश्वविद्यालय

(1920), मागध

विश्वविद्यालय (1921), अग्रामसई विश्वविद्यालय (1920), ट्रावनकोर विश्व-  
 विद्यालय (1937), उत्कल विश्वविद्यालय (1943), सागर विश्वविद्यालय  
 (1946), रायपूताना विश्वविद्यालय (1947) ।

सन् 1920 में महाविद्यालयों की कुल संख्या 231 थी जिनमें छात्रों का संख्या 50,591 थी । सन् 1947 तक महाविद्यालयों की संख्या 933 हो गई जिनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 190,253 थी ।

#### 11.04 स्वतन्त्र भारत में उच्च शिक्षा

Higher Education In Free India

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेकों विश्वविद्यालय खोले गये, जिसके कारण महाविद्यालयों एवं छात्रों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई, परन्तु देश की जनसंख्या को देखते हुए यह विकास बहुत कम था । राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 4 नवम्बर, 1948 को भारतीय सरकार ने विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की जिसके अध्यक्ष डा० सर्वेपल्ली राधाकृष्णन थे । इस आयोग का कार्य क्षेत्र भारतीय विश्वविद्यालयों शिक्षा के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था जिससे देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास और प्रसार के लिए वांछित सुझाव दिये जा सकें ।

आयोग ने अपने कार्यक्षेत्र के अनुरूप 6 दिसम्बर, 1948 से कार्य आरम्भ किया और 25 अगस्त, 1949 को अपना प्रतिवेदन सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया । आयोग द्वारा प्रस्तावित सुझावों से प्रभावित होकर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 22 व 23 अप्रैल, 1950 की विशेष बैठकों में समस्त सुझावों को कार्यान्वित करने का निर्णय किया । आयोग के अन्य सुझावों से सबसे महत्वपूर्ण सुझाव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करना था और उच्च शिक्षा के अनुरूप

1. To Report on Indian University Education and suggest improvements and extensions that may be desirable to suit present and future requirements to the Country.

The Report of the University Education Commission, 1948-49, Govt. of India, New Delhi, p. 1.

2. University Grants Commission.

150 में इसे कार्य रूप में परिणत भी किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान का 70 विश्वविद्यालयों तथा 10 विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं को दिया जाता है। यह अनुदान विज्ञान विषयों, मानविकी और समाज विज्ञानियों और शिल्प विज्ञान, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान अनुदान, छात्रवृत्तियाँ तथा अधिवृत्तियाँ (फेलोशिप) आदि के रूप में विभिन्न विद्यालयों तथा उनसे सम्बन्धित महाविद्यालयों को दिया जाता है। विश्वविद्यालय आयोग द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों को शत प्रतिशत और राज्य विद्यालयों को उनकी विषय योजनाओं के लिए सहभागिता के आधार पर अनुदान दिया जाता है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा का विकास जानने के लिए पत होगा कि हम निम्नलिखित विन्दुओं पर विचार करें—

1. भारत में विश्वविद्यालय
2. उच्च शिक्षा का प्रसार
3. केंद्रीय विश्वविद्यालय
4. सामान्य उच्च शिक्षा

### 1. भारत में विश्वविद्यालय

#### Universities in India

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत में कुल 19 विश्वविद्यालय थे जो 1988 में बढ़कर 70 हो गये हैं। यद्यपि विकास की गति तेज है तथापि यह विकास देश आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है। हमारे देश में कुल विश्वविद्यालयों में उनसे सम्बन्धित महाविद्यालयों की संख्या तालिका नं० 11.2 के अनुसार है।

#### तालिका नं० 11.2

#### विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संख्या

विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष	प्रकार	महाविद्यालयों की संख्या
2	3	4	5
कलकत्ता विश्वविद्यालय	1857	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन	189
अम्बई विश्वविद्यालय	"	सभी और अध्यापन	68
मद्रास विश्वविद्यालय	"	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन	157
इलाहाबाद विश्वविद्यालय	1887	आवासी और अध्यापन	6
बनारस हिन्दु विश्व-विद्यालय	1916	"	18
मैसूर विश्वविद्यालय	"	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन	83
पटना विश्वविद्यालय	1917	आवासी और अध्यापन	
उस्मानिया विश्वविद्यालय	1918	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन	

1	2	3	4	5
9	अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय	1921	आवासी और अध्यापन	4
10	ससनऊ विश्वविद्यालय	"	"	18
11	दिल्ली विश्वविद्यालय	1922	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन	41
12	नागपुर विश्वविद्यालय	1923	"	84
13	आन्ध्र विश्वविद्यालय	1926	"	61
14	बांगलूर विश्वविद्यालय	1927	सम्बद्ध करने वाला	143
15	अन्नमलै विश्वविद्यालय	1929	आवासी और अध्यापन	
16	केरल विश्वविद्यालय	1937	सूचीबद्ध और अध्यापन	140
17	वल्हल विश्वविद्यालय, बरीबिहार, मुबनेस्वर	1943	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन	72
18	सागर विश्वविद्यालय	1946	"	67
19	राजस्थान विश्वविद्यालय	1947	"	75
20	पंजाब विश्वविद्यालय	1947	"	149
21	गोहाटी विश्वविद्यालय	1948	"	75
22	जम्मू और कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर	1948	"	34
23	हडको विश्वविद्यालय	1949	आवासी और अध्यापन	
24	पूना विश्वविद्यालय	1949	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन	46
25	महाराजा समाजीराज बडोदा विश्वविद्यालय बडोदा	1949	आवासी और अध्यापन	46
26	कनाटक विश्वविद्यालय, पारवाड	1949	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन	63
27	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	1949	"	128
28	एच एन डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, अम्बई	1951	"	17
29	बिहार विश्वविद्यालय, पटि अम्बई	1952	"	44
30	डी बडोदे विश्वविद्यालय, विरूपति	1954	"	28

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा के अनुदान  
 विश्वविद्यालय की मान्यता के संदर्भ  
 Institutions Deemed to be Universities Under  
 U. G. C. Act.

1. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंदनोर	1959
2. भारतीय कृषि अनुसंधान, नई दिल्ली	1959
3. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय, नई दिल्ली	1961
4. गुप्तल बागरी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	1962
5. आधिया गिनिया इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली	1962
6. गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	1963
7. काशी विद्यापीठ, वाराणसी	1963
8. राजा रामानुज विद्यालय संस्थान, बम्बई	1964
9. विद्या शिखरविज्ञान और विज्ञान संस्थान, दिल्ली	1964
10. भारतीय लघु विद्यालय, बनारस ( इतिहास स्कूल और माध्यम )	—

2. उच्च शिक्षा का प्रसार

Expansion of Higher Education

स्वातंत्र्यता प्राप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा का प्रसार द्रुत गति से।  
 सामान्यतः 11.3 से यह संख्या 1947 है। बोर्डारी आयोजन का सुझाव है।  
 शिक्षा के प्रसार हेतु युविधायी का आयोजन आवश्यक शक्ति की आवश्यकताओं  
 को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। इसके अतिरिक्त  
 भी प्रसार अब तक हुआ है उससे स्तर में बहुत कमी आई है। अतः उच्च शिक्षा  
 प्रसार में मानव शक्ति आवश्यक है। सन् 1905-06 में पूर्व स्नातक  
 स्तर को बनाये रखना विज्ञान आवश्यक है। सन् 1905-06 में पूर्व स्नातक  
 स्नातकोत्तर स्तरों पर छात्रों की संख्या 10 लाख थी। देश में शिक्षा की  
 हुई मांग की देखते हुए सन् 1985-86 तक यह संख्या 40 लाख करनी  
 है, परन्तु सीमित मानव शक्तियों को ध्यान में रखते हुए इस मांग को पूरा  
 करना नहीं तो शक्ति आवश्यक है।

1	2	3	4	5
50	रवीन्द्र चारतो, विरय- विद्यालय, फसकता	1962	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन	20
51	मगध विश्वविद्यालय बौद्धगया	1962	"	34
52	जोधपुर विश्वविद्यालय	1962	आवासी और अध्यापन	2
53	सदयपुर विश्वविद्यालय	1962	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन	11
54	हन्दीर विश्वविद्यालय	1964	सम्बद्ध करने वाला	17
55	बीवाजी विश्वविद्यालय, म्यालियर	1964	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन	30
56	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	1964	अध्यापन और आवासी	8
57	रक्षितकर विश्वविद्यालय रायपुर	1964	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन	44
58	कृषि विज्ञान विश्व- विद्यालय मल्लेश्वरम्, बयलोर	1964	आवासी और अध्यापन	3
59	मध्य प्रदेश कृषि विश्व- विद्यालय, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद	1964	"	6
60	बंगलौर विश्वविद्यालय	1964	सभीय	31
61	विश्वभारती, छान्ति निकैशन	1951	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन	17
62	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर-4	1962	"	31
63	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय राजमेडा, डिब्रूगढ़	1963	"	34
64	कानपुर विश्वविद्यालय	1965	"	—
65	सीराष्ट्र विश्वविद्यालय	1965	"	—
66	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत	1965	"	—
67	मेरठ विश्वविद्यालय	1966	"	—
68	मदुरै विश्वविद्यालय	1966	"	3
69	बहुरामपुर विश्वविद्यालय	1967	"	—
70	संजयपुर विश्वविद्यालय			—

1.	2.	3.	4.	5.
31	सरदार, पटेल विश्व- विद्यालय, बल्लभ विद्यानगर, आनन्द	1965	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन	43
32	जादवपुर विश्वविद्यालय कलकत्ता-32	1955	"	4
33	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	1956	आवासी और अध्यापन	32
34	इन्दिरा कला संगित विश्वविद्यालय खैरागढ़	1956	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन	39
35	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	1957	"	41
36	गोरखपुर विश्वविद्यालय	1957	"	21
37	जबलपुर विश्वविद्यालय	1957	"	75
38	वाराणसी संस्कृत विश्व- विद्यालय, वाराणसी	1958	"	28
39	मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद	1958	"	4
40	उत्तर प्रदेश कृषि विश्व- विद्यालय, पल्लनगर, मैनीताल	1960	आवासी और अध्यापन	43
41	बर्दवान विश्वविद्यालय	1960	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन	44
42	बलियाँ विश्वविद्यालय	1960	आवासी और अध्यापन	35
43	आगनपुर विश्वविद्यालय	1960	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन	38
44	रांची विश्वविद्यालय	1960	"	26
45	बामदेवरविह-दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा	1961	"	29
46	पञ्चाय कृषि विश्वविद्या- लय, मुर्शिदाबाद	1962	रांची और अध्यापन	13
47	पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाणा	1962	आवासी और अध्यापन	19
48	उड़ीसा कृषि तथा औद्यो- गिकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर	1962	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन	19
49	उत्तर बंगाल विश्व- विद्यालय रात्रामान कोलकाता (रात्रामान)			

1	2	3	4	5
50	रवीन्द्र भारती, विश्व- विद्यालय, कलकत्ता	1962	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन	20
51	मगध विश्वविद्यालय बोडगया	1962	"	34
52	जोधपुर विश्वविद्यालय	1962	भाषासी और अध्यापन	2
53	उदयपुर विश्वविद्यालय	1962	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन	11
54	इन्दौर विश्वविद्यालय	1964	सम्बद्ध करने वाला	17
55	धौलाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	1964	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन	30
56	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	1964	अध्यापन और भाषासी	8
57	रविचन्द्र विश्वविद्यालय रायपुर	1964	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन	44
58	कृषि विज्ञान विश्व- विद्यालय मल्लेश्वरम्, बंगलौर	1964	भाषासी और अध्यापन	3
59	भांग्र प्रदेश कृषि विश्व- विद्यालय, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद	1964	"	6
60	बंगलौर विश्वविद्यालय	1964	सूचीय	31
61	विश्वभारती, धानि त्रिकैतन	1951	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन	17
62	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोरहापुर-4	1962	"	51
63	बिबू गढ़ विश्वविद्यालय राजमेठा, डिब्रूगढ़	1965	"	34
64	मानपुर विश्वविद्यालय	1965	"	
65	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय	1965	"	
66	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत	1965	"	
67	मेरठ विश्वविद्यालय	1966	"	
68	मडु विश्वविद्यालय	1966	"	34
69	महाराजपुर विश्वविद्यालय	1967	"	
70	सबलपुर विश्वविद्यालय, सबलपुर	1967	"	

महाविद्यालय की संख्या=2565



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक्ट के अनुसार  
विश्वविद्यालय की मानी गई संस्थाएँ

Institutions Deemed to be Universities Under  
U. G. C. Act.

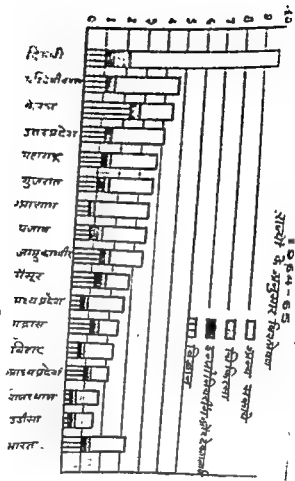
1. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर
2. भारतीय कृषि अनुसंधान, नई दिल्ली
3. भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय, नई दिल्ली
4. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
5. जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
6. गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
7. कोसी विद्यापीठ, बाराणसी
8. टाटा समाज विज्ञान संस्थान, बम्बई
9. विजला शिल्पविज्ञान और विज्ञान संस्थान, पिलानी
10. भारतीय चतुर्न विद्यालय, बनारस  
( इण्डियन स्कूल ऑफ मान्स )

## 2. उच्च शिक्षा का प्रसार Expansion of Higher Education

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा का प्रसार द्रुत गति  
प्राप्तिका नं० 11.3 से यह तथ्य स्पष्ट है। कोटारी आयोग का मुकाम  
शिक्षा के प्रसार हेतु सुविधाओं का आयोजन मात्र एक राशि की आवश्यकता  
रोजगार के अवसरों की ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। इसके अति  
श्री.प्रसार अब तक हुआ है उससे स्तर में बहुत कमी आई है। अतः उ  
प्रसार में मानव शक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं, रोजगार में अवसरों  
स्तर को बनाये रखना निताम्न आवश्यक है। सन् 1965-66 में पूर्व 1  
स्तरको स्तरों पर छात्रों की संख्या 10 लाख थी। देश में शिक्षा  
2 इस मांग को देखते हुए सन् 1985-85 तक यह संख्या 40 लाख करने  
दे-परन्तु सीमित आवधिक व्ययों की ध्यान में रखते हुए इस मांग को  
असम्भव नहीं हो कठिन अवसर है।

	1950-51				1955-56				1960-61				1965-66			
	सड़के	सड़कियाँ	योग		सड़के	सड़कियाँ	योग		सड़के	सड़कियाँ	योग		सड़के	सड़कियाँ	योग	
कला, वाणिज्य, विज्ञान	153	22	175		249	46	295		313	82	395		550	9147	9697	
	16	—	16		27	—	27		38	—	38		61	1	62	
	169	22	191		276	46	322		351	82	433		611	148	759	
योग																
स्नातकोत्तर	14	2	17		21	4	25		38	9	47		62	10	72	
	1	—	1		2	—	3		4	1	5		6	1	7	
	15	2	18		23	4	28		42	10	52		68	17	85	
योग																
व्यावसायिक	46	4	50		74	7	82		121	15	136		195	33	228	
	4	—	4		6	1	7		12	1	13		20	2	22	
	50	5	55		80	8	88		133	16	149		215	35	250	
योग																
कनसंख्या की कुल छात्र संख्या	234	28	262		379	58	437		536	108	644		804	200	1004	
	1-2	0-1	0-7		1-7	0-3	1-0		2-2	0-5	1-4		3-3	0-8	2-1	
	1-2	0-1	0-7		1-7	0-3	1-0		2-2	0-5	1-4		3-3	0-8	2-1	

# हजार



विश्वविद्यालय के छात्रों की संख्या

— जनसंख्या की प्रति-हजार

१९५५ - ५६

राज्यों के अनुसार विश्वविद्यालय

□ अल्प संख्या

□ अधिक संख्या

□ जनसंख्या के अनुसार

□ शिक्षा

तालिका नं० 11.3 से यह स्पष्ट होता है कि पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में उच्च शिक्षा का विकास सभी क्षेत्रों में हुआ है। कला, वाणिज्य और विज्ञान की पूर्वस्नातक कक्षाओं में 1950-51 में छात्रों की संख्या 101,000 थी जो 1965-66 में बढ़कर 759,000 हो गई अर्थात् औसत वार्षिक वृद्धि 9 प्रतिशत थी।

स्नातकोत्तर (कला एवं विज्ञान) और अनुसन्धान के छात्रों की संख्या 1950-51 में 18,000 थी, जो 1965-66 में क्रमशः बढ़कर 86,000 हो गई अर्थात् औसत वार्षिक वृद्धि 11 प्रतिशत रही।

व्यावसायिक शिक्षा (इंजिनिअरिंग, मेडिकल, इन्जीनियरिंग, टेक्नालॉजी, बिजनेस, पशु चिकित्सा) प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 1950-51 में 54,000 थी और 1965-66 में 249,000 थी। औसत वार्षिक वृद्धि 10 प्रतिशत हुई अर्थात् यह वृद्धि कला और विज्ञान स्तरों से अधिक थी।

यदि सम्पूर्ण उच्च शिक्षा के विकास को देखा जाये तो यह कहा जा सकता है कि औसत वार्षिक वृद्धि 10 प्रतिशत रही। विश्वविद्यालय के छात्रों की संख्या का राज्यों के अनुसार विश्लेषण पृष्ठ 213 पर देखें।

### 3. केन्द्रीय विश्वविद्यालय

#### Central Universities

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विस्तार हेतु कुछ महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए जिनमें कुछ का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय  
Aligarh Muslim University

सितम्बर 1, 1967 को छात्रों की संख्या 6,667 थी। इसी सत्र से सेमिस्टर पद्धति आरम्भ की गई है। कला, विज्ञान और वाणिज्य सहायों में आनर्स पाठ्यक्रम आरम्भ कर दिया है। इन्जीनियरिंग में उन छात्रों ■■■ लिए जो डिप्लोमा प्राप्त हैं और जिन्हें कुछ अनुभव है, एक अर्धकालिक इन्जीनियरी डिग्री भी आरम्भ कर दी गई है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय  
Banaras Hindu University

सत्र 1967-68 में विश्वविद्यालय के छात्रों की संख्या 6540 थी। अनेक संकायों में सेमिस्टर पद्धति आरम्भ कर दी गई है। विश्वविद्यालय परिषद् ने हिन्दू को शिक्षा का माध्यम स्वीकार दिया है, इस निर्णय को कार्यान्वित करने हेतु हिन्दू माध्यम बोर्ड की स्थापना की है जो आवश्यक साहित्य प्रकाशित करेगा।



इसीलिए यह आवश्यक है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वांछित शिक्षा का आयोजन किया जाये। इसके लिये समय-समय पर विचार भी किया गया। हण्टर कमीशन, सैटलर कमीशन और हर्टाग कमेटी आदि ने स्वतन्त्रता प्राप्ति से इस शिक्षा के महत्व पर प्रत्यक्ष बल दिया। सन् 1948 में विश्वविद्यालय आयोग ने भी कृषि-विश्वविद्यालयों के आरम्भ करने का सुझाव दिया।

सन् 1956 में ग्रामीण उच्च शिक्षा की योजना आरम्भ की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण नवयुवकों को ग्रामीण समुदाय में माध्यमिक स्तर के पश्चात् शिक्षा प्रदान करना और ग्राम्य जीवन के प्रति वांछित दृष्टिकोण विकसित करना था। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के ग्रामीण कार्यक्रमों को लागू करने के लिए प्रशिक्षित करना भी था।

इस समय देश के विभिन्न भागों में सैकड़ों ग्रामीण संस्थान हैं—

1. हनुमान गढी	(मद्रास)
2. राजपुरा	(पंजाब)
3. चारंगोटी	(महाराष्ट्र)
4. छानोसरा	(गुजरात)
5. बिरोली	(बिहार)
6. जामिया नगर	(दिल्ली)
7. धी निवेसन	(बंगाल)
8. मापीबाव	(मद्रास)
9. बर्धा	(मध्य प्रदेश)
10. उदयपुर	(राजस्थान)
11. अमरावती	(महाराष्ट्र)
12. बिचपुरी	(उत्तर प्रदेश)
13. कीयम्बहूर	(मद्रास)

इनमें 11 राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद् से सम्बन्धित हैं। गोवा, जामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया और उदयपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हैं।

कोटारी आयोग ने भी कृषि शिक्षा के सभी अंगों पर ध्यान दिया। निम्नलिखित सुझाव दिये हैं—

\* प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना चाहिये। इनके अन्तर्गत वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रमों का निर्धारण होना चाहिये।



## ग्रन्थ-सूची

### "Bibliography"

1. Basu A. N.

*University Education in India*, Book Emporium 1944.

2. Dongerkery, S. R.

*Thoughts on University Education*, Popular Book Depot,  
Bombay, 1955.

3. Government of India,

*Report of University Education Commission*, Publication  
Division, Delhi, 1949.

4. —————

*Report of Education Commission*, Publication Division,  
Delhi, 1966

5. *Hindustan Varshiki*, (1968-69)

Hindustan Samachar, Mandi House, New Delhi-1, 1968

6. Mukerji S N,

*Education in India To-day & Tomorrow*, Acharya Book  
Depot, Baroda, 1964.

7. Nusrullah S. & J. P. Naik

*History of Education in India*, Macmillan & Co. Bombay,  
1951.





\* 12.03 अनुशासन और सामाजिक समायोजन की समस्या

*Problem of Discipline & Social Adjustment*

अनुशासनहीनता और सामाजिक कुसमायोजन के कारण

1. नैतिक शिक्षा का अभाव
2. महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का दूषित वातावरण
3. अध्यापकों में नेतृत्व का अभाव
4. राजनैतिक दलों द्वारा विद्यार्थियों का शोषण
5. महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सुविधाओं का अभाव

समस्या का समाधान

1. नैतिक शिक्षा
2. माता पिता, राजनैतिक दलों और जनता के सहयोग की आवश्यकता
3. शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता
4. आत्म अनुशासन

## उच्च शिक्षा की समस्याएँ

### PROBLEMS OF HIGHER EDUCATION

विश्वविद्यालयों का निर्माण मात्रकता, सहनशीलता, वैचारिकता का प्रतीक के लिए होता है। विश्वविद्यालय अथवा उच्च शिक्षा मानव जाति की उत्थान के मार्ग की ओर अग्रसर करना है जिससे हम मार्ग प्रशस्त हो और विश्व की परिवर्तित परिस्थितियों में अपना स्थिति कर सकें। विश्वविद्यालय नूनन उच्च शिक्षा के पवित्र मन्दिर है जिसमें रुग्ण ॥ दो उद्देश्य हैं—प्रथम, देश के नवयुवक और नवयुवनियों को किसी के लिए प्रशिक्षित करना तथा दूसरे बिना किसी भी प्रकार के अर्थसहायता में सहायता प्रदान करना। न तब तक उद्देश्यों की प्राप्ति तभी। जबकि हमारे देश के विश्वविद्यालयों में सभी प्रकार की सुविधाएँ हों। सुखी प्राप्ति की जा सकती है जबकि उच्च शिक्षा के मार्ग में बाधाएँ न हों। दुर्भाग्यवश हमारे देश की स्थिति कुछ निम्न है। भारतीय विश्वविद्यालयों के अनेकों समस्याएँ हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से बर्षों परचात भी हम इन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहे हैं। आज उच्च शिक्षा के मार्ग में जो गूढ़ समस्याएँ उत्पन्न हो चुकी हैं, स्तर, अनुशासन और सामाजिक संघर्षों की समस्याएँ मुख्य प्रस्तुत अघ्याय में हम इन समस्याओं और उनके समाधान की चर्चा करेंगे।

#### 12.01 चयन की समस्या

##### The Problem of Selection

बनाया गया है, यह अभी तक अनिवार्य क्यों नहीं हुई—यह अन्य प्रश्न है और इसकी चर्चा हम दूसरे पाठ में करें चुके हैं, परन्तु यहाँ हमारा अभिप्राय केवल मात्र यह है कि प्राथमिक पाठशालाओं में बालकों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव माध्यमिक शिक्षा पर पड़ रहा है। माध्यमिक स्तर पार करने के पश्चात् विश्वविद्यालयों में प्रवेश की समस्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है।

इसमें संदेह नहीं कि सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि सभी प्रकार के छात्रों को विश्वविद्यालयों अथवा महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाना आवश्यक है। न तो यह व्यावहारिक ही है और न सैद्धांतिक ही। यदि हम भारत सरकारों के आधार पर सन् 1916-17 से 1963-64 तक विश्वविद्यालयों के छात्रों की बढ़ती हुई संख्या देखें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसमें अत्यधिक वृद्धि हुई है। तालिका 12.1 से यह स्पष्ट है कि 1916-17 में छात्रों की कुल संख्या 61,145 थी जो कि 1963-64 में 13,84,697 हो गई और 1970-71 तक यह 19 लाख से ऊपर हो जायेगी। पूर्व अनुभवों और सीमित साधनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इतनी बढ़ती हुई संख्या को प्रशिक्षित करना कठिन अवश्य हो जायेगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों और सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा वस्तुनिष्ठ चयन पद्धति को अपनाया जाये। 'सभी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय जीवन की पूर्ण सुविधाएँ प्रदान करना असम्भव एकमात्र आवश्यक है। हमें इस हेतु छात्रों का चयन करना होगा परन्तु हमें यह भी देखना होगा कि कोई गरीबी के कारण इससे वंचित न रह जाये, यदि वह वास्तव में इस लाभ से उठाने योग्य है।'<sup>2</sup>

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष डा० सी० डी० देशमुख के अनुसार 'यदि उच्च शिक्षा के सीमित साधनों को व्यर्थ नहीं करना है तो विश्वविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश चयन द्वारा ही होना चाहिए।'<sup>3</sup> इसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि अयोग्य छात्रों के कारण अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या में वृद्धि होती है जिससे राष्ट्र का धन व्यर्थ होता है। जिसके परिणामस्वरूप समय, धन और मानवीय प्रयासों का अपव्यय होता है। प्राप्त आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि

1. It is impossible and unnecessary to provide all the students with the full benefits of University life. We have to be selective while seeing that no one, however poor is excluded from this benefit as he will really benefit from it.

Chagla, Convocation address delivered in Delhi University, 1964.

2. 'That admission to Universities should be on a selective basis if the limited resources available for higher education were not to be frittered away.

Dr. C. D. Deshmukh, Chairman, U. G. C., 1960

विभिन्न शकाओं के अनुसार विश्वविद्यालय

Faculty Wise Total University

(1916-17 के

वर्ष	कुल संख्या	शका	विज्ञान	साहित्य	व्यावसायिक और हस्तकला
1	2	3	4	5	6
1916-17	61,145	29,655	22,364	—	383
1920-21	92,262	94,747	28,611	832	1,506
1936-37	1,26,371	61,289	41,221	2,239	2,459
1942-43	1,84,164	86,225	69,985	7,540	3,574
1946-47	2,05,814	1,21,067	85,735	20,322	5,348
1947-48	2,65,917	1,17,609	89,043	22,589	6,763
1948-49	3,23,081	1,40,710	1,14,340	21,685	8,662
1949-50	3,66,986	1,63,075	1,23,345	32,396	10,414
1950-51	3,96,745	1,80,806	1,27,168	34,067	12,094
1951-52	4,59,024	2,12,923	1,42,666	41,458	13,900
1952-53	5,12,853	2,53,494	1,48,676	46,279	14,162
1953-54	5,80,218	2,93,677	1,62,234	53,124	15,613
1954-55	6,51,479	3,33,412	1,82,161	58,718	16,935
1955-56	7,12,697	3,61,004	1,97,475	64,167	19,699
1956-57	7,69,468	3,95,672	2,10,039	66,674	21,237
1957-58	8,27,341	4,15,313	2,29,899	69,570	27,534
1958-59	9,28,622	4,61,081	2,56,145	78,762	32,809
1959-60	9,97,137	4,72,183	2,92,190	84,127	39,324
1960-61	10,30,384	4,87,016	2,94,329	92,802	45,139
1961-62	11,55,380	4,99,974	3,36,722	1,25,142	59,168
1962-63	12,72,666	5,32,680	3,86,374	1,20,051	68,589
1963-64	13,84,697	5,79,049	4,35,925	1,30,579	73,015

पर 12.1 के अनुसार -

को को कुल संख्या

Enrollment

1963-64 (सक)

संविधान	रुपि	समु विविधता	नित्य	विधि	सम्य
7	8	9	10	11	12
2,408	—	—	61	5,272	440
4,485	537	—	796	9,220	1,520
5,215	685	—	2,603	8,028	2,432
6,615	1,820	100	2,118	5,863	300
8,847	4,302	—	2,006	9,774	4,843
8,206	4,280	398	2,675	10,310	4,009
14,311	4,215	958	3,724	9,620	4,847
13,540	4,848	885	3,397	11,363	3,623
15,280	4,744	—	4,135	13,649	4,822
16,942	4,856	—	4,082	16,746	4,551
17,929	4,798	—	6,104	17,118	4,293
18,756	5,053	—	7,046	18,706	6,000
10,767	6,378	—	8,609	19,491	5,918
21,405	8,230	—	11,371	20,162	8,284
23,431	10,385	3,572	13,000	20,707	4,747
2,859	12,475	4,139	14,357	22,424	6,039
27,537	16,828	4,524	15,297	24,376	11,203
30,949	21,306	5,021	16,609	25,966	9,442
34,139	23,380	4,788	18,990	27,240	2,552
39,569	24,704	5,214	21,718	29,401	14,678
40,546	31,427	5,524	25,638	28,944	14,013
54,708	41,110	6,624	26,727	29,571	8,084

संसार में विश्वविद्यालय स्तर पर जितना अध्ययन भारत में होता है इतना अन्यत्र नहीं है।<sup>1</sup>

उपरोक्त तथ्यों में यह स्पष्ट कर देना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि इंग्लैंड में उच्च शिक्षा का कुल अध्ययन 14% है, जबकि भारतवर्ष में अध्ययन का प्रतिशत बहुत ऊँचा है। अमेरिकी विश्वविद्यालय के रेक्टर ने अपने अध्ययन में पाया कि स्नातक स्तर पर निश्चित समयावधि में केवल 25% छात्र ही सफलता प्राप्त करते हैं। बशीदा विश्वविद्यालय में हुए अध्ययन से ज्ञात होता है कि 33% छात्र अपनी शिक्षा पूर्ण करे बिना ही विश्वविद्यालय छोड़ जाते हैं।

भारतीय विश्वविद्यालयों में परीक्षाफलों पर हुए अनेको तात्कालिक अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि बी० ए०, बी० एस० सी०, बी० कॉम स्तर में 50% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं और स्नातकोत्तर स्तर पर 20 और 30% छात्र असफल रहते हैं।<sup>2</sup>

यद्यपि छात्रों की असफलता के अनेको कारण हैं जैसे अपूर्ण पुस्तकालय, दूषित शिक्षण विधियाँ, अध्यापकों के ज्ञान की अपूर्णता आदि परन्तु इसका मुख्य कारण छात्रों के प्रवेश के समय यस्तुनिष्ठ चयन पद्धति को न अपनाना ही है।

विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु बाधित चयन पद्धति के विषय में सभी शिक्षा शास्त्री एकमत नहीं हैं। कुछ लोगों का मत है कि प्रवेश हेतु किसी भी प्रकार की चयन पद्धति को न अपनाकर सभी माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिया जाये, क्योंकि माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम के पश्चात् सभी छात्रों की मौकरी मिलना सम्भव नहीं है। विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या सीमित करने हेतु एक समिति की नियुक्ति की और प्रवेश के समय चयन करना आवश्यक बताया परन्तु समिति ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया कि 17 से 21 वर्ष की आयु में छात्रों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना वे बेकारी के कारण शहर की गलियों में निरर्थक घूमते हैं और राज्य के लिए समस्याएँ उत्पन्न करते हैं।<sup>3</sup>

1. 'It appeared from the figures available, that the degree of wastage in India of University education was the highest in the world.'  
Ibid

2. 'Several recent studies of examination results in Indian universities indicate that the failure rate at the B. A., B. Sc., B. Com., level is generally of the order of 50% and that at the Post-graduate stage it ranges between 20 and 30%.'

Report on Standards of University Education, 1965.

3. 'That it was much better that students got some kind of education at the very impressionable age of 17 to 21 rather than being left unemployed or unemployable roaming in the streets of the city, and creating problems for the state'

इसके अतिरिक्त हमारे देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना सामाजिक हेतुत्व की जाती है। हमारे समाज के रीति-रिवाजों में जो व्यक्ति जितना अधिक पढ़ा था होता है उसे उतना ही सम्मान दिया जाता है चाहे उसमें योग्यता हो अथवा हो। लड़कियों के वैवाहिक सम्बन्ध भी प्राप्त शिक्षा के आधार पर होते हैं। अतः सामाजिक परम्पराओं के कारण भी आज प्रत्येक विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय चयन किया जाये अथवा नहीं, यह एक विवादास्पद प्रश्न है।

### समस्या का समाधान

#### Solution of the Problem

शिक्षा के गिरते हुए स्तर, असफल छात्रों की बढ़ती हुई संख्या ( देखिये तालिका नं० 12.2), शिक्षाओं की बेकारी और राष्ट्रीय धन की हानि को देखते हुए हम अत्यन्त आवश्यक है कि एक चयनात्मक प्रवेश प्रणाली को स्वीकार किया जाये। उच्च शिक्षा केवल उन छात्रों को दी जाये जो उसे प्राप्त करने योग्य हैं और लाभ उठाने की सामर्थ्य रखते हैं।

उल्लेखित संदर्भ में देश के अधिकतम विश्वविद्यालयों ने छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कुछ तरीके अपनाये हैं। उदाहरणार्थ दिल्ली, जादवपुर, उत्तमानंगा, पटना और श्री वैद्येश्वर विश्वविद्यालयों ने चयन हेतु कुछ विशेष मापदण्ड अपनाये हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने चयन हेतु बी. एस. सी. और कला तथा विज्ञान के आनर्स में प्रवेश पाने के लिए पूर्व परीक्षाओं में 45% अंकों को मापदण्ड माना

#### तालिका नं० 12.2

#### विभिन्न परीक्षाओं के फल<sup>1</sup>

#### Results of Various Examinations

परीक्षा	परीक्षा दन बाल		उत्तीर्ण छात्र संख्या		उत्तीर्ण प्रतिशत	
	1959-60	1960-61	1959-60	1960-61	1959-60	1960-61
प्रीयमीवमिटी	1,53,885	2,14,997	64,848	92,288	42.2	42.9
इंटर (कला)	2,36,146	2,01,340	87,615	80,754	37.1	40.1
इंटर (विज्ञान)	96,188	84,370	41,526	34,977	43.2	40.0
बी. ए.	1,35,347	1,42,273	58,452	65,138	43.2	45.8
बी एस सी	50,506	61,666	22,397	27,814	44.3	45.1
एम. ए.	19,854	23,276	16,343	18,984	82.3	81.4
एम.एस सी.	5,010	6,304	3,971	4,737	79.3	75.1
पूर्व व्यावसायिक	13,920	7,475	6,145	4,670	44.1	62.6



है। आरबुद्ध विश्वविद्यालय में श्री. युनिवर्सिटी अथवा कुम्भनगर माध्यमिक परीक्षा में शिरीष भैली एवं वातावरण को धारणा प्रदान की है। इसी प्रकार अन्य विश्व-विद्यालयों में श्री अथवागमक प्रवेश प्रणाली हेतु युवा मातृगण बनाये हैं।

युवा विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या को कम करने के लिए न्यूनतम आयु निर्दिष्ट कर दी है। तानिका नं० १२३ में विभिन्न विश्वविद्यालयों में आयु मा-  
दर को स्पष्ट दिया गया है। हमने अनिश्चित युवा विश्वविद्यालयों में विभिन्न  
संख्या में छात्रों की संख्या को निर्दिष्ट कर दिया है।

### तानिका नं० १२३

विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयुक्रम  
Minimum Age Range to Take Admission in Various Universities

विश्वविद्यालय	आयु	प्रवेश हेतु कक्षा
आंध्र प्रदेश	१४ वर्ष ६ महीने	श्री-युनिवर्सिटी
असम	"	"
बड़ोदा	१५ वर्ष	प्रीवेरेटरी
दिल्ली	"	बी० यू० सी०
गुजरात	"	"
कादंबपुर	१५ वर्ष ६ महीने	स्नातक प्रथम वर्ष
कर्नाटक	"	"
कुश्नोत्र	"	"
मद्रास	"	"
राजस्थान	१६-१० वर्ष	"
सागर १	"	"
बिरोबमारी	"	"

उपरोक्त चयनारम्भक प्रवेश प्रणाली में वस्तुनिष्ठता का अभाव है और इसी कारण राजनैतिक अथवा अन्य दवावों के कारण अयोग्य छात्रों को भी प्रवेश प्राप्त जाता है। अतः चयन की समस्या का समाधान करने के लिए विश्वविद्यालय आयोग की 'परीक्षा सुधार' समिति ने यह सुझाव दिया था कि माध्यमिक की अन्तिम परीक्षा में दो अतिरिक्त प्रश्न पत्र आरम्भ कर दिये जायें, प्रथम विद्यालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा से सम्बन्धित और दूसरा औद्योगिक परीक्षा से सम्बन्धित, परन्तु अधिकांश विश्वविद्यालयों ने इनके सम्बन्ध में व्यावहारिक कार्रवाई नवाई और सन् 1961-62 की उप-नियुक्तियों के अधिवेशन ने भी इस बात को निरस्त कर दिया।

चयनारम्भक प्रवेश प्रणाली को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए हम अन्य देशों में लिखित परीक्षाओं को प्रयोग कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में छात्रों के चयन कॉलेज बोर्ड द्वारा कुछ परीक्षाएँ प्रयोग में लाई जाती हैं जिन्हें विद्यालय अभि- परीक्षा<sup>1</sup> कहा जाता है। ये परीक्षाएँ सरल होती हैं और वस्तुनिष्ठ भी हैं। लैंड में भी राबिन्स समिति<sup>2</sup> ने इन प्रकार की परीक्षाओं को विद्यार्थियों के चयन लिए प्रयोग हेतु सुझाव दिया था। हमारे देश में यद्यपि इन प्रकार की वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का अभाव है तथापि एन० सी० ई० आर० टी दिल्ली<sup>3</sup> और इन्डियन टिचटीचल इन्स्टीट्यूट, बनारस के मासूहिक प्रयास से इन परीक्षाओं को तैयार जा सकता है। इनके अतिरिक्त प्रदेश विश्वाचालय का मनोविज्ञान विभाग इन परीक्षाओं को तैयार करे। इन कुछ वर्षों में वस्तुनिष्ठ परीक्षाएँ भी तैयार<sup>4</sup> सकेंगी और छात्रों की अपेक्षित सख्या पर भी नियन्त्रण हो सकेगा।

परन्तु छात्रों के चयन में एक समस्या सामने आयेगी, उन छात्रों का क्या जा जिन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश नहीं मिलेगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय उनके व्यक्तित्व पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा जिसके परिणाम स्वरूप उनमें<sup>5</sup> निराशा और हताशा की भावनाएँ आ जायेंगी। इसीलिए ऐसे छात्रों के विषय में सोचना आवश्यक है। हमारी दृष्टि में इसके लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं—

1. माध्यमिक स्तर पर कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किये जायें जिससे सम्बन्धित योग्यता और रुचि वाले छात्र विश्वविद्यालयों में जाने की ओर इन् प्रशिक्षण केन्द्रों में जाकर भावी व्यवसाय हेतु तैयार हो सकें और देश की प्रगति में अपना सहयोग प्रदान कर सकें।

1. Scholastic Aptitude Tests (SAT)

2. Robbins Committee's Report, England.

3. National Council of Educational Research and Training,

को शिक्षा के अन्तर्गत भी प्रान्त हो सकते हैं।  
 स्नातक करने के बिना ही स्नातक होने में उपरोक्त  
 करने वाले लोगों को ही स्नातक है, इसके सम्बन्ध  
 है कि वे सुविधाएँ, यहाँ की प्रान्त होनी चाहिये  
 को स्नातकों के अन्तर्गत करने में सम्मिलित हो सके।  
 ब्रिटिशों के कारण उच्च शिक्षा प्रान्त करने के  
 समान सीमा अन्तर्गत प्रान्त हो गए।

आज में छात्रों के विवेचन के आधार पर हम यह स्नातक  
 में अन्तर्गत की सम्मिलित का सम्मिलित आवश्यक है। छात्रों को महाविद्यालयों में प्रवेश देने के लिए अन्तर्गत प्रवेश-प्रणाली को  
 कोठारी आयोग ने भी इस पर भी पुष्टि की है।

अन्तर्गत के सम्बन्ध में कोठारी आयोग के सुझाव  
*Suggestions of Kothari Commission Regarding*

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की बढ़ती हुई संख्या  
 आयोग ने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि उच्च शिक्षा की  
 देश की अन्तर्गत सम्मिलित आवश्यकताओं तथा रोजगार के अन्तर्गत  
 रखकर लिया जाना आवश्यक है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर  
 संख्या जो सन् 1965-66 में 10 लाख थी, उसे बढ़ाकर सन् 1975  
 लाख हो जायेगी। अतः इसके लिए आवश्यक है कि छात्रों की  
 किया जाये और प्रवेश के समय अन्तर्गत पद्धति को अपनाया जाये।

\* विश्वस्तरीय अन्तर्गत आवश्यक विधि को अपनाया जाये। अन्तर्गत  
 ने भी उच्च शिक्षा के अन्तर्गत विकास हेतु अनुसंधानों  
 को अपनाया है। आयोग ने इसके सम्बन्ध में निम्न  
 दिये हैं—

1. शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकों तथा अन्य सुविधाओं का  
 आधार पर यह देखा जाये कि संस्था में कितने छात्रों  
 का संख्या है। शिक्षा के स्तर हेतु इस पर ध्यान देना  
 एक है।
2. विश्वविद्यालयों द्वारा प्रवेश योग्यता का निर्धारण,
3. महाविद्यालय विशेष में प्रवेश की दृष्टि से छात्रों में से  
 चुनाव हेतु विश्वस्तरीय विधि।

## 12 02 स्तर की समस्या

## The Problem of Standards

विश्वविद्यालय वह पवित्र स्थान है जहाँ राष्ट्र के तरुणों और नागरिकों के व्यक्तित्व को भावी जीवन हेतु ढाला जाता है। तरुणों की धृष्टता और योग्यता प्राप्त उच्च शिक्षा पर निर्भर करती है। दुर्भाग्य का विषय है कि भारतीय विश्व-विद्यालयों द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वह वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है। इसका एक मात्र कारण शिक्षा के स्तरों की गिरावट है। कवि की ये पंक्तियाँ आज की स्थिति में सत्य प्रतीत होती हैं—

Where is the wisdom we have lost in knowledge ?

Where is the Knowledge we have lost in information ?

The cycles of Heaven in twenty Centuries,

Bring us farther from God and nearer to the dust<sup>1</sup>

उच्च शिक्षा के स्तरों का अस्तु निष्ठ मूल्यांकन करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है परन्तु साथ ही अत्यन्त कठिन है। यह कहा जाता है कि पिछले कुछ वर्षों से विश्व विद्यालयों का स्तर घटने लगे गिरता जा रहा है। आज का सामान्य व्यक्ति भी यह कहता है कि 15 या 20 वर्ष पूर्व की शिक्षा आज की तुलना में अधिक श्रेष्ठकर थी और उस समय के विद्यालयों का बोर्डिक स्तर भी ऊँचा था। इसके अतिरिक्त एक दोष यह भी बताया जाता है कि विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षाफलों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी आती जा रही है और तृतीय श्रेणी में वृद्धि होती जा रही है। तालिका न० 12.4 से इस तथ्य की पुष्टि होती है।

तालिका न० 12.4

विभिन्न परीक्षाओं में श्रेणियों का प्रतिशत

Percentage of Divisions in Various Examinations

वर्ष	बी. ए.			बी एस सी.			बी ए.			एम एस. सी.		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1952	12	26.8	70.0	63	36.0	58.7	5.2	40.9	53.9	23.5	55.8	20.7
1957	0.8	28.4	72.8	7.1	34.8	58.1	4.6	37.2	58.2	22.3	53.9	23.8
1962	1.0	24.2	74.8	8.5	39.6	51.9	3.7	41.3	55.0	24.6	57.2	18.2

अनेकों विरवविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम निश्चित किये गये हैं वे शैक्षिक उद्देश्यों की पृष्ठभूमि में ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं हैं। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वर्तमान स्थितियों में शिक्षा के उद्देश्य कुछ और हैं और पाठ्यक्रम छात्रों को कहीं और ले जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव शैक्षिक स्तर पर पड़ता है क्योंकि जो शिक्षा देश की आवश्यकताओं को पूर्ति न करे—उस शिक्षा से कोई लाभ नहीं है। प्रायः लोगो को यह कहते सुना गया है कि आज की उच्च शिक्षा के निम्न स्तरों के कारण ही छात्रों की व्यवसाय नहीं मिल पाते। यदि हम इस कथन पर ध्यान दें तो सरपता के दर्शन होते हैं क्योंकि विश्वविद्यालय की शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी है कि उसके द्वारा छात्रों में सामान्य व्यावसायिक कौशल का विकास हो सके। जिससे छात्र समाज के सामुदायिक सदस्य के रूप में देश की आवश्यकताओं के अनुरूप अपना सज्जि योग प्रदान कर सकें।

समीक्ष लोक सेवा आयोग ने अपने सातवें प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि, "छात्रों की लिखित परीक्षाओं के स्तर पर परीक्षकों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, वे अत्यन्त ही शोचनीय हैं। सामान्यतया छात्रों के उत्तरों में विषय का ज्ञानात्मक पद दृष्टिगोचर नहीं होता और उनके उत्तर रटने की प्रक्रिया पर आधारित रहते हैं। साक्षात्कार के समय उनके विषय के ज्ञान का सही पता लगता है।" ... अतः गम्भीर होकर यह सोचने की आवश्यकता है उत्तरोत्तर शैक्षिक स्तरों के गिरने का क्या कारण है। इसके लिए यह भी देखना चाहिए कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था छात्रों के बौद्धिक, चारित्रिक और व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए आखिरी सुविधायें प्रदान करती है अथवा नहीं।<sup>1</sup> तालिका न० 12 में उपरोक्त तथ्य की पुष्टि होती है। तालिका के विवेचन से यह ज्ञात होता है कि उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतिशत संख्या उत्तरोत्तर घटती है। ये तथ्य भी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उच्च

शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि स्तर के निरन्तर गिरावट के कारणों को जाना जाये।

सांख्यिक नं० 125

भारतीय प्रशासकीय सेवाओं के परीक्षाफल<sup>1</sup>

Examination Results of Indian Administrative Service

( 1957-62 )

वर्ष	परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	प्रतिशत
1957	5,216	1,010	19.4
1958	6,207	680	10.8
1959	6,511	750	11.5
1960	4,849	110	12.6
1961	4,610	623	13.3
1962	4,446	434	9.8

स्तर के गिरावट के कारण

Causes of Overall Deterioration in Standards

जैसा कि हम पिछले पृष्ठों में कह चुके हैं कि उच्च शिक्षा के स्तरों का सही मूल्यांकन करना नितान्त आवश्यक है। किसी भी देश की समृद्धि और उच्चतम भविष्य शिक्षित मनुष्यों और मनुष्यवृत्तियों पर निर्भर करता है। हमें उच्च शिक्षा का केवल सकारात्मक विकास ही नहीं करना है बल्कि गुणात्मक विकास भी करना है। यह सभी सम्भव है जब उच्च शिक्षा का स्तर ऊँचा हो, परन्तु इसके मार्ग में कुछ बाधाएँ हैं जो इस प्रकार हैं—

1. समान प्रवेश नीति का अभाव

Lack of Similar Admission Policy

हम अध्ययन बिन्दु नं० 12.01 में स्पष्ट कर चुके हैं कि विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों

1. Ibid.

ने अपनी-अपनी पृथक् प्रवेश नीतियाँ बना रखी हैं जो विमान है। जो थोड़ी बहुत औपचारिकताएँ निभाई भी जाती हैं नहीं हैं।

सन् 1956 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने नई नीति पारित किया था—

“प्रथम स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होना चाहिए और प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 17+ होनी चाहिए।<sup>1</sup>

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित सुझाव दिया—

“विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु न्यूनतम करना यांछनीय होगा। इसका निश्चय हो चुका है कि न्यून निर्धारित की जाये, परन्तु सीमा ही कुछ कठिनाईयोंका है, इसीलिए यह निर्दिष्ट किया गया कि वर्तमान में सभी को सुझाव दिया जाये कि प्रथम स्नातक पाठ्यक्रम के नि 16+ निर्धारित कर दी जाये।<sup>2</sup>

उपरोक्त सुझाव सन् 1964 में प्राचार्यों की समिति में भी परन्तु आज तक भी सभी विश्वविद्यालयों ने इस सुझाव को कार्यरत किया है। अतः एकरूपता का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रवेश नीति होने के कारण निम्न योग्यता के छात्रों की अधिकता हो जाती है प्रभाव दीक्षित स्तर पर पड़ता है।

## 2. 12 वर्षीय विद्यालय शिक्षा की अपहेलना

To Neglect 12 Years Schooling

इम्प्लीमेंट कलियों से दो उद्देश्यों की पूर्ति होती है—प्रथम Is

1. “The first degree course should be of 3 years should be the minimum age for entry into the University”

Central Advisory Board of Education, resolution (at it held in New Delhi in January, 1955)

2. It would be desirable to prescribe a minimum admission to university courses. It was agreed that while “... it would be difficult to ... of that it might be ... as a first step, to ... which is to the first courses”

Report on “Standards of University Education, Vol.

अथवा महाविद्यालयों में प्रवेश लेने से पूर्व विद्यार्थियों को सभी स्तरों का प्रतिक्षण प्राप्त हो जाता है और स्वयंसेव ही अधिष्ठाता योग्य विद्यार्थियों का चयन हो जाता है क्योंकि उच्च शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व उसे दो बाह्य परीक्षाओं (हार्ड स्कूल और इण्टरमीडिएट) को उत्तीर्ण करना होता है। इण्टरमीडिएट कार्य प्रणाली का दूसरा उद्देश्य यह है कि इस परीक्षा के उपरान्त विद्यार्थियों में इतनी मानसिक परिपक्वता आ जाती है कि वे किसी भी व्यवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए सन् 1910 में सेल्डर आयोग ने इण्टरमीडिएट कॉलेजों को खोलने का सुझाव दिया था। सन् 1949 में राधाकृष्णन आयोग ने भी सुझाव दिया था कि 'इण्टरमीडिएट कॉलेज' में 12 वर्षीय पाठ्यक्रम को समाप्त करने के पदचान ही विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाये। सभी प्रांतों में स्थापन सम्पन्न इण्टरमीडिएट कॉलेजों (कक्षा 9 से 12 अथवा 0 से 12) की स्थापना की जाये।<sup>1</sup> योजना आयोग की शिक्षा समिति ने भी जनवरी 1960 को यह सुझाव दिया कि स्कूल कीर्ण की कार्यविधि 12 वर्ष होंगी चाहिये न कि 11 वर्ष और प्राथमिक स्तर में उच्च शिक्षा स्तर का कार्यकाल 14 वर्ष (11+3) की अपेक्षा 15 वर्ष (12+3) होना चाहिये क्योंकि विश्वविद्यालयों में 18 वर्ष का परिपक्व विद्यार्थी ही आना चाहिये इसके पक्ष में एक ठक यह है कि सेल्डर और राधाकृष्णन आयोग ने भी इसी कार्यप्रणाली की सिफारिश की थी और जो स्कूल शिक्षा के लिए 11 वर्षीय कार्य प्रणाली स्वीकार की गई है वह अवस्थ समझौता है।<sup>2</sup> अखिल भारतीय माध्यमिक अध्यापक केंद्रीय 1962 ने 12 वर्षीय साला पाठ्यक्रम के विषय में स्पष्ट किया कि 11 वर्षीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय योजना पूर्णरूपेण अमल में रही है। इसीलिए यह सिफारिश कि 5-7 का पाठ्यक्रम स्वीकार किया जाये निम्न अर्थ है,

admission to the University Courses of the present intermediate examination of 11 years of study at a school and on In each a large number of well-qualified students (with class IX to XII)

Education Commission, 1940.

on -  
at 11  
level  
very

and

it should be 12 years and 11 education from primary to 12 years (12+3) instead of 14 mature students of the stage. In support of this recommendation of the Sadler Commission and that 11 year system was accepted

1960.



वर्ष का प्राथमिक स्तर, 3 वर्ष का जूनियर सेकण्डरी स्तर और 4 वर्ष का उच्चतर माध्यमिक स्तर।<sup>1)</sup> राज्य शिक्षा मंत्रियों, उप-कुलपतियों और प्रतिष्ठित शिक्षकों की बैठक में नवम्बर, 1963 को यह प्रस्ताव पारित किया कि उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट आने का एक मूल कारण 11 वर्षीय शाला पद्धति अपनाती है। इसी विचार को सन् 1964 में राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में पुनः विचार के लिए रखा गया और इस सम्मेलन में भी स्नातक स्तर के प्रवेश हेतु 12 वर्षीय शाला कार्यक्रम की सिफारिश की गई।

उपरोक्त समस्त आयोगों, प्रतिवेदनो और शैक्षिक गोंटियों के विचारों से यह स्पष्ट होता है कि 11 वर्षीय शाला पद्धति का उच्च शिक्षा पर प्रभाव पड़ा है और कुछ अंशों में स्तर की गिरावट का कारण उच्चतर माध्यमिक शालाएँ भी रही हैं। हमारी स्वयं की धारणा भी यही है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से पूर्व यह अवर्ष आवश्यक है कि प्रत्येक छात्र 12 वर्ष के माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम समाप्त करे और उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो।

### 3 विश्वविद्यालयों में शिक्षण सुविधाओं की कमी Lack of Teaching Facilities in Universities

विश्वविद्यालयों में शैक्षिक स्तर के गिरावट का कारण यह भी है कि उन शिक्षण सुविधाओं की कमी है। विश्वविद्यालयों के सम्बन्धित महाविद्यालयों में छात्रों की समस्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। छात्रों की समस्या के वृद्धि के अनुरूप शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान नहीं की जा रही हैं, क्योंकि छात्र और अध्यापकों का अनुपसृत नही है। ट्यूटोरियल पद्धति को आरम्भ नहीं किया गया है। एक बधा में अधिक छात्र बैठते हैं कि उमे बधा न बहुर भीट वर देना अधिक उत्तम हो। बहुत में सम्मिलित महाविद्यालय तो पारियों (Shifts) में चलते हैं किन्हें दे। ऐसा आभास होता है जैसे कि आज के महाविद्यालय कैंटरीन हो गये हों।

प्राप्त आँकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 1965-66 में अध्यापकों की कुल संख्या 60,031 थी जिनमें से 10,439 अमान्य विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों के थे और अन्य मान्य महाविद्यालयों के थे। छात्रों व

1 The seminar was unanimously of the opinion that the class higher secondary school scheme has failed. It recommended the pattern of 5-3-4 meaning five years of primary education, followed by 3 years of Junior or lower secondary education, followed by 4 years of higher secondary stage.  
The All India Secondary Teachers Federation, (Bombay) Secular Education 1962.

सख्या 10 लाख थी। इसका अर्थ यह हुआ कि अध्यापक और छात्रों का अनुपात 1 : 17.3 था। जवाबोस विश्वविद्यालयों के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तालिका नं० 12.6 में अध्यापक छात्र अनुपात को स्पष्ट किया गया है, जिससे स्पष्ट आभास होता है कि अधिकांश विश्वविद्यालयों में अध्यापक छात्र अनुपात बहुत अधिक है अतः स्तर में गिरावट आना स्वाभाविक है।

### तालिका नं० 12.5

विश्वविद्यालयों में अध्यापक छात्र अनुपात<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Staff Students Ratio in Universities

श्रेणी	अध्यापक छात्र अनुपात	विश्वविद्यालयों की संख्या (श्रेणी के अनुसार)
A	1 : 10	4
B	1 : 10 एवं 1 : 20	33
C	1 : 20	17

इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में पुस्तकों की सुविधाएँ संतोषप्रद नहीं हैं। सामान्य रूप से पुस्तकों की संख्या छात्रों के अनुपात में बहुत कम होती है, कुछ पुस्तकालयों के भवन ही इन प्रकार के होते हैं कि वहाँ एकत्रित होकर पढ़ना तो असंभव, बैठने तक की जगह नहीं होती जबकि स्नातकोत्तर और अनुसंधान के विद्यार्थियों के लिए तो पुस्तकालय ही बरदान होते हैं।

विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों की अच्छी व्यवस्था होनी है, परन्तु वहाँ छात्र उमरा उपयोग नहीं करते। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त एक समिति ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि 70 प्रतिशत से अधिक छात्र पुस्तकालय सुविधाओं से लाभान्वित होना ही नहीं चाहते क्योंकि अधिकतर छात्रों की यह अभिवृत्ति विकसित हो जाती है कि परीक्षा से दो या तीन महीने पहले पढ़ लेना ही आवश्यकता से अधिक है अतः उनके अनुसार पुस्तकालय में जानकर समय नष्ट करना निरर्थक है। जिस देश के नवयुवकों का पुस्तकालयों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार हो, उस देश की निशा वा क्या भविष्य होगा यह स्वयं ही निश्चि है।

#### 4. अध्यापन विषय का अवांछनीय स्वरूप

##### Undesirable Nature of Teaching Methods

उच्च शिक्षा के स्तर की गिरावट का एक कारण अध्यापन विषय का प्रयोग भी है। साधारणतया महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में व्याख्यान विधि ही प्रयोग की जाती है। अध्यापकों द्वारा निश्चित व्याख्यानों की पूर्ति कर देना ही कर्तव्य का पालन समझा जाता है। हमारी समस्या में तो बहुत ही कम ऐसे अध्यापकों को सीखने की प्रक्रिया के अनुसार अपनी बोर्डिंग बुद्धि के द्वारा छात्रों को लाभान्वित करने का प्रयास करना होता है। कुछ लोगों का तो यही तर्क रहता है कि अधिकांश अध्यापक अपने व्याख्यानों को इतना सम्भाल कर रखते हैं कि जीवन भर उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि नवीन ज्ञान का हम प्रकार के अध्यापकों के शिक्षण में कोई महत्व नहीं है।

बोप केवल अध्यापकों तक ही सीमित नहीं है। इस प्रकार के तथ्य अध्यापक भी हैं जो कक्षा में जाने से पूर्व बहुत ही तन्मयता से व्याख्यान को सम्बन्ध पुस्तकों की सहायता से तैयार करते हैं और प्रतिभाशाली छात्रों के सस्तिष्क पर अपने व्याख्यान द्वारा प्रभाव छोड़ते हैं परन्तु अधिकांश विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोताओं के समान केवल मात्र शारीरिक तौर पर ही उपस्थित रहते हैं। आज के अधिकांश छात्र अध्यापक के शैक्षिक व्यक्तित्व से प्रभावित न होकर केवल सस्ते पुस्तकों पर अवलम्बित रहते हैं।

सक्षेप में हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि अध्यापकों द्वारा केवल भाष्य व्याख्यान विधि से ज्ञान प्रदान करना और छात्रों द्वारा ज्ञान की खोज एवम् विषय विमर्श किये बिना ही व्याख्यानों को सुनना शिक्षण विधि की उपयोगिता नहीं जब तक हमारे विश्वविद्यालयों में जयवा महाविद्यालयों में ऐसा होता रहेगा तब स्तर में सुधार आना असम्भव है।

##### 5. विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनेक परीक्षा पद्धतियाँ

##### Various Examination Practices in Different Universities

हमारे देश में अनेकों प्रकार के विश्वविद्यालय हैं और प्रत्येक विश्वविद्यालय में अनेकों संकायों हैं। इन संकायों में विभिन्न परीक्षा पद्धतियों को व्यवहार में लाया जाता है और उनकी अनेकों समस्याएँ हैं। इन समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं हो सका है, यही कारण है कि उच्च शिक्षा का स्तर घटने का निरन्तर है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण सुझाव दिया था, "हम यह दृढ़ता से कह सकते हैं कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा में एक भी सुधार करना है तो वह परीक्षाओं में सुधार किया जाना चाहिए।"<sup>1</sup>

1. "We are convinced that if we are to suggest any single reform in University Education, it should be that of Examinations." University Education Commission, 1918-19.

कोठारी शिक्षा आयोग ने भी परीक्षा सम्बन्धी समस्या का अध्ययन किया और यह सुझाव दिया कि "वर्तमान पद्धति द्वारा छात्रों का भविष्य केवल मात्र एक ही बाह्य परीक्षा के द्वारा वर्ष के अन्त में निश्चित किया जाता है, इसी कारण वे अध्यापकों को कम से कम महत्व देते हैं और पूरे वर्ष स्वतन्त्र रूप से अध्ययन करने की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा के लिए कुछ तथ्यों को रट लेना ही श्रेयस्कर समझते हैं। इन हानिकारक बाह्य परीक्षाओं का प्रभाव उच्च शिक्षा के स्तर पर इतना अधिक हो गया है कि परीक्षा में सुधार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है जिससे शिक्षण में उत्पत्ति की जा सके।"<sup>1</sup> उच्च शिक्षा के स्तरों की गिरावट और परीक्षा प्रणाली को दोषों पर सन् 1954 से गम्भीरतापूर्वक विचार होना रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सन् 1957 में डा० झूम को नियुक्त किया और सन् 1958 में उस्मानिया, पूना, पटना, अलीगढ़ विश्वविद्यालयों में परीक्षा प्रणाली सुधार पर आवश्यक विचार विमर्श एवम् गोष्ठियाँ भी हुईं। सन् 1958 में भारतीय शिक्षा शक्तिमो का एक दम अमेरिका भी गया। परीक्षाओं में आवश्यक सुधार करने के लिए बड़ोदा, मोहाटी, त्रिवेन्द्रम विश्वविद्यालयों में परीक्षा अनुसंधान इकाईयों की स्थापना भी की गई। वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोषों की गम्भीरता पर विचार करने के लिए सन् 1967-68 ने एन० सी० ई० आर० टी० के पाठ्यक्रम एवम् मूल्यांकन विभाग के प्रयास से बेगनोर, बड़ोदा, दक्षिण गुजरात के विश्वविद्यालय अध्यापकों ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया कि उच्च शिक्षा के स्तरों में जो गिरावट आ रही है उसका मूल कारण वर्तमान परीक्षा प्रणाली है। अतः उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षा प्रणाली में सुधार होना बहुत आवश्यक है।

परीक्षा सुधार हेतु व्यापक योजना पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली में पाठ्यक्रम एवम् मूल्यांकन विभाग ने मार्च 18-21, सन् 1968 को तीन सत्राध्यक्ष (कला, विज्ञान, वाणिज्य) के वरिष्ठ सदस्यों को आमन्त्रित किया जो पाँच विश्वविद्यालयों—बंगलौर, मेरठ, राजस्थान, सरदार पटेल विश्वविद्यालय और दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे। सम्बन्धित प्रतिवेदन और

1. "In the present system when the future of students is totally decided by one external examination at the end of the year, the independent  
the independent  
am desperately  
external exami-  
is so great that  
gress and has to



अतः यह निर्विवाद आवश्यक है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में से वे अंश हटा दिये जायें जिनकी कोई त्रिषात्मक महत्ता नहीं है एवं जो बहुत पुराने ज्ञान और अनुसंधानों पर आधारित हैं। इसके स्थान पर नवीन ज्ञान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु यह बहुत आवश्यक है कि अस्तित्व भारतीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया जायें जिसमें केवल हमारे देश के ही अध्यापक और शिक्षा वास्तु न हो बल्कि विदेशों के लब्ध प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय आचार्यों को आमन्त्रित किया जायें। जब तक हम अपनी सुलगा अन्य देशों से नहीं करेंगे और विदेशों के विकासार्थक दृष्टिकोण को नहीं अपनायेंगे तब तब स्तर में सुधार होना सम्भव नहीं।

यह प्रसन्नता का विषय है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सश्रिय प्रयास से हम शिक्षा में एक नवीन आन्दोलन आया है और विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुछ विशिष्ट विषयों के स्तरों की उच्च बनाने के लिए कुछ केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इन केन्द्रों का उद्देश्य उच्चतम सम्भावित स्तरों की प्राप्ति करना है।

### 3. माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के विभिन्निकरण की आवश्यकता

#### Need for Diversification of Curriculum at Secondary Stage

1. आधुनिक समय में माध्यमिक शिक्षा का सबसे बड़ा दोष उसका पाठ्यक्रम है। यदि यह कहा जाये तो अतिशयोक्ति न होगी कि उच्च शिक्षा के स्तर को गिराने में माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में बहुत सहयोग प्रदान किया है। सन् 1953 में माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति तक प्रत्येक विद्यार्थी में जीवन क्षेत्र में प्रवेश करने की क्षमता का ज्ञान चाहिए और इसके लिए आवश्यक है कि माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में विभिन्निकरण किया जायें जिससे माध्यमिक स्तर की शिक्षा समाप्त करने पर प्रत्येक विद्यार्थी अपनी अभिरुचि और योग्यता के अनुसार व्यवसाय चुन सकें। इस सुझाव के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में दो लाभ हैं, प्रथम शिक्षितों में बेरोजगारी की समस्या का समाधान होता है और दूसरे विश्वविद्यालयों में प्रवेश की समस्या का समाधान होता है। यद्यपि यह सुझाव अत्यन्त ही मूल्यवान् था और इसी सुझाव के कारण बहुउद्देशीय योजनाओं की स्थापना भी हुई परन्तु समय-समय में इसके अनुसार कार्य नहीं हुआ। परन्तु उच्च शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का विभिन्निकरण कर विद्यार्थियों में व्यावसायिक दक्षता का विकास किया जाए जिससे विश्वविद्यालयों में केवल वे ही विद्यार्थी आ सकें, जिन्हें उच्च शिक्षा की वांछना में आवश्यकता है। यदि यह किया जाना सम्भव हुआ तो निश्चित ही उच्च शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने में कुछ सहूलियत मिल पायेगी।

#### 4. विश्वविद्यालय प्रवेश से पूर्व 12 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा आवश्यक हो Necessity of 12 years Secondary Education before University Admission

विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व एक विद्यार्थी को किनने वही छात्र है। कुछ लोगों का मत होता है कि माध्यमिक स्तर 11 वर्ष का होना चाहिए और कुछ के अनुसार 12 वर्षीय छात्र जीवन का। सामान्य रूप से यह स्वीकार किया जाता है कि 11 वर्षीय छात्र को परीक्षा के पश्चात् जो छात्र 3 वर्षीय स्नातक कोर्स में प्रविष्ट होता है उसी प्रकार 12 वर्षीय स्नातक कोर्स में प्रविष्ट होता है जो 12 वर्षीय कोर्स के पश्चात् कार्यरत 12 वर्ष का होना चाहिए जिसका स्वरूप  $10+2$  हो। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि छात्र 10 वर्ष तक छात्रा जीवन का अनुभव होगा और विश्वविद्यालय में समावेशन का मिश्रित अनुभव प्राप्त होगा जिससे उन्हें विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए मानसिक एवं शारीरिक तैयारी हो सकेगी।

इंग्लैंड, अमेरिका और अन्य यूरोपिय देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्वीटजरलैंड में भी विश्वविद्यालय में प्रविष्ट होने से पूर्व छात्रा जीवन 12 वर्ष का होना आवश्यक दिया जा चुका है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) ने भी यह ही होना चाहिए। विश्वविद्यालय में प्रवेश का स्तर इण्टरमीडिएट परीक्षा के पश्चात् 3 वर्ष का होना चाहिए। अक्टूबर, 1962 में नई दिल्ली में उपकुलपतियों के सम्मेलन के अन्तर्गत 3 वर्षीय स्नातक कोर्स की स्थापना की गई। इस सम्मेलन से स्वीकार किया गया कि प्रथम स्नातक कोर्स 17 वर्ष होना चाहिए। 15 वर्ष (12+3) और तकनीकी डिग्री तक 16 वर्ष होना चाहिए।

एकदश वर्ष की अवधि को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है —

12 वर्ष स्कूल शिक्षा और 3 वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम

अथवा

स्नातक शिक्षा

11 वर्ष स्कूल शिक्षा, 1 वर्ष प्री यूनिवर्सिटी और 3 वर्ष स्नातक

1. It is sometimes said that the student who is admitted to a three year degree course is not as good as the first year student of an old two year degree course.

Report on Standards of University Education, p. 31

## अथवा

10 वर्षे स्कूल शिक्षा, ३ वर्षे इंटरमीडिएट/जूनियर कॉलेज,

3 वर्षे स्नातक शिक्षा

मई, 1964 में आचार्यों के अधिवेशन में भी उच्च शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए यह निश्चित किया गया कि प्रथम स्नातक प्रमाण पत्र 15 वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रदान किया जाये, पहले 12 वर्षों को किमी भी सुविधाजनक तरीके से उपयोग में लाकर 3 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम होना निश्चित आवश्यक है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए विश्वविद्यालय प्रवेश से पूर्व माध्यमिक स्तर की कार्यवधि 12 वर्ष होनी चाहिए और प्रथम स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होना चाहिए।

### 5. स्नातकोत्तर और अनुसंधान हेतु वांछित आवश्यकताएँ

#### Desirable Needs of Postgraduate Studies & Research

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् स्नातकोत्तर शिक्षा का काफी विकास हुआ है। यह सन्तोष का विषय है कि स्नातकोत्तर स्तर पर अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या स्नातक स्तर की अपेक्षा कम है। तानिका न० 12.6 से यह स्पष्ट है कि बीरह वर्षों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 30 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ी है। डा० बी० एन० कोठारी के शब्दों में शिक्षा के सभी स्तरों में गुणात्मकता का विशेष महत्व है, परन्तु जहाँ तक स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान का प्रश्न है वहाँ तो 'द्वितीय उत्तम' भी विशेष महत्वपूर्ण नहीं। हमें उसमें भी अधिक अच्छे की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए।<sup>1</sup> इसमें सन्देह नहीं कि स्नातकोत्तर स्तर का विश्वविद्यालय में विशेष स्थान है क्योंकि इसके पश्चात् ही मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, नेता और अनुसंधानकर्त्ता विकसित होते हैं। अतः यह आवश्यक है कि इस स्तर के प्रति पूर्ण सावधानी के साथ विकासत्मक दृष्टिकोण अपनाया जाये जिससे विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर ऊँचा हो सके। संक्षेप में इस स्तर की निम्नलिखित वांछित आवश्यकताएँ हैं—

- \* स्नातकोत्तर वक्ताएँ केवल उन्हीं महाविद्यालयों में आरम्भ की जायें जो सभी आवश्यक सुविधाओं को जुटाने में समर्थ हों।

1. 'Quality is important at all stages of education, but when it comes to postgraduate studies and research even the second best' is not good enough—it will not do, we must go in for the best attainable.



- \* स्नातकोत्तर विद्या की गहरी भर्षों में उन्नतिनीय बनाने हेतु यह आवश्यक है कि महाविद्यालयों में इन बर्षाओं की सोचने में पूर्व विद्यविद्यार्थियों

सांख्यिक नं० 12.6

स्नातकोत्तर स्तर पर उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत  
Percentage of Successful Candidates at Post Graduate Level

एम. ए.				एम. एम. बी. और एम. एम. एम. सी. होम साइन्स		
वर्ष	प्रविष्ट संख्या	उत्तीर्ण संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशत	प्रविष्ट संख्या	उत्तीर्ण संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशत
1940	4,654	3,632	78.0	1,137	846	74.4
50	5,940	4,423	74.7	1,267	984	77.7
51	8,123	5,969	73.5	1,723	1,308	81.1
52	8,404	6,467	77.0	2,085	1,641	78.7
53	9,256	7,038	76.0	2,234	1,780	79.7
54	10,488	7,880	75.2	2,772	2,146	77.4
55	11,754	8,886	75.6	3,108	2,348	75.6
56	13,630	9,526	70.0	3,263	2,520	77.5
57	13,009	10,483	80.6	3,652	2,933	80.3
58	14,355	11,670	81.3	3,724	2,942	79.0
59	17,462	13,997	80.2	4,376	3,508	80.2
60	19,053	15,662	82.2	4,398	3,613	79.9
61	23,013	18,026	82.2	5,108	4,721	77.3
62	25,217	21,003	83.3	6,726	5,193	77.2

को चाहिए कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करें जिससे बाहरी दबाव के कारण स्नातकोत्तर बढ़ाए न मुल सकें ।

- \* अनुसंधान के स्तर सन्तोषप्रद हैं तथापि विश्वविद्यालयों को चाहिए कि उन्हें और बस्तुनिष्ठ बनायें ।
- \* हम हमारे देश में 33 विश्वविद्यालयों में अनुसंधान विभाग हैं । इन विभागों को चाहिए कि वे 14 राष्ट्रीय अनुसंधानशाखाओं जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक प्रयोगशाला नई दिल्ली, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुना, केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था भावनगर, केन्द्रीय विद्युत रासायनिक संस्था मद्रास, केन्द्रीय जल अनुसंधान संस्था मद्रास, केन्द्रीय दूध रिमर्च संस्था ससनऊ, केन्द्रीय खाद्य पदार्थ तकनीकी अनुसंधान संस्था मैसूर, केन्द्रीय प्लास तथा सिरेमिक अनुसंधान संस्था कलकत्ता, केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था दिग्बानी घनबाद, राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला जमशेदपुर और राष्ट्रीय बोटेनीकल गार्डन ससनऊ आदि से तथा 88 रिमर्च इन्स्टीट्यूट से सहयोग प्राप्त करें जिससे अनुसंधान का कार्य बलिष्ठ भारतीय स्तर का हो सके ।
- \* विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे वैज्ञानिक अनुसंधानों पर अधिक व्यय करें क्योंकि आज देश को वैज्ञानिक उन्नति की आवश्यकता है ।
- \* अन्य विषयों जैसे शिक्षा, भाषाएँ, दर्शनशास्त्र, ज्योतिष, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र आदि में भी अनुसंधान की सुविधाओं को बढ़ाया जाये ।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर और अनुसंधान स्तर पर बहुत कुछ करना शेष है, सभी हम सत्तर के अन्य प्रगतिशील देशों के साथ चल सकने में समर्थ हो सकते हैं ।

### 6 परीक्षा सुधार हेतु व्यापक योजना की आवश्यकता

#### 'Need for Comprehensive Scheme of Examination Reform

1. विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए यह भी आवश्यक है कि विद्यमान परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाये और मूल्यांकन की नवीन विधियों को प्रयोग में लाया जाये । आज विश्वविद्यालय स्तर का विद्यार्थी भी किसी तरह परीक्षा पास करना चाहता है जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा के सभी उद्देश्य वर्तमान परीक्षा की दूषित पद्धति की बलिबेदी पर होम हो गये हैं । वर्तमान परीक्षा प्रणाली में प्रमाणितता और विश्वसनीयता का अभाव है, ये अपूर्ण ज्ञान और मयोग पर आधारित है, विकास के एक पक्ष का परीक्षण करती हैं एवम् विद्यार्थी के सर्वा-

हीन विवाह पर गुरा प्रभाव डालती है। इन दोनों को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि परीक्षा पद्धति में सुधार हो।

इसके लिए जरूरी है कि मूल्यांकन पद्धति को स्वीकार किया जाये क्योंकि मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें मूल रूप से तीन तथ्य होते हैं—प्रथम दार्शनिक तथ्य, दार्शनिक तथ्यों की दृष्टभूमि में उद्देश्य निहित होते हैं। इसके द्वारा हमें ज्ञात होता है कि निष्ठा और मूल्यांकन किस ओर निर्दिष्ट होने चाहिए। सैद्धांतिक उद्देश्यों से सैद्धांतिक उपलब्धि का अर्थ समझने में सहायता मिलती है, जिसका मूल्यांकन के लिए समझना नितांत आवश्यक है। मूल्यांकन का दूसरा सम्बन्ध मूल्य से होता है जिसमें विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता और भेदभाव सम्मिलित होते हैं। मूल्यांकन का तीसरा सम्बन्ध मानवीय सम्बन्धों, सीखने और व्यक्तित्व के मनोविज्ञान से है। मूल्यांकन को सही अर्थों में सही स्वीकार किया जा सकता है जबकि परीक्षा में सुधार कर व्यापक योजना को नियान्वित किया जाये।

परीक्षा सुधार के व्यापक कार्यक्रम में निम्नलिखित मूल निष्ठाओं का समावेश किया जाना आवश्यक है—

1. परीक्षा पद्धति शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए। सकल मूल्यांकन हेतु यह जरूरी है कि परीक्षा का मूलाधार समस्त मानसिक योग्यताएँ, कुशलताएँ, रचियाँ और अभिवृत्तियाँ होनी चाहिए।
2. प्रश्न पत्रों में निम्नलिखित प्रश्नों की संख्या कम करनी चाहिए और यथासम्भव वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए।
3. प्रश्न पत्र बनाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है—

- \* सम्पूर्ण पाठ्यक्रम में से प्रश्न पूछे जायें।
- \* उद्देश्यों के अनुरूप ही समस्त प्रश्नों का स्वरूप निर्धारित किया जाना चाहिये।
- \* समस्त प्रश्नों के उत्तर निश्चित एवम् विवाद रहित होने चाहिये।
- \* प्रश्न पत्र में सरलता और कठिनाई को यथावत स्थान दिया जाना चाहिये।

4. परीक्षा पद्धति में आन्तरिक एवम् बाह्य मूल्यांकन को समाविष्ट किया जाये जिससे विद्यार्थी का समग्र मूल्यांकन सम्भव हो सके।

यदि वर्तमान परीक्षा पद्धति में आवश्यक सुधार कर उक्त सुझावों के अनुसार कार्य किया जाये तो निश्चित ही उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकेगा।

समग्र रूप से सुधार सभी सम्भव है जबकि उपरोक्त समस्या समाधानों पर विचार कर, सभी विश्वविद्यालय स्तर की समस्या के प्रति जागरूक हों और आवश्यक कदम यथाशीघ्र उठाये जायें।

### 12.03 अनुशासन और सामाजिक समायोजन की समस्या

#### Problem of Discipline & Social Adjustment

आज विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रायः अनुशासनहीनता और सञ्चलनता के दर्शन होते हैं। छात्रों की अनुशासनहीनता और सामाजिक कुसमायोजन केवल विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों तक ही सीमित न होकर अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भी फैल गई है। बाहरी क्षेत्रों में जहाँ थोड़ी भी निरकुशता होती है, उसमें छात्रों का नाम पहले आता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज का छात्र पहले की अपेक्षा अधिक अनुशासनहीन और कुसमायोजित हो गया है; परन्तु क्यों? क्या आज के छात्र के साथ ही कोई जन्मजात घुराई हो गई है जो पहले छात्र के साथ नहीं थी? यदि हाँ तो इस समस्या का कोई समाधान नहीं, यदि ऐसा नहीं है तो इस अनुशासनहीनता और कुसमायोजन के कुछ कारण अवश्य होने चाहिये। यदि कारण हैं तो उन्हें दूर भी किया जा सकता है।

### अनुशासनहीनता और सामाजिक कुसमायोजन के कारण

#### Causes of Indiscipline & Social Maladjustment

हमारी दृष्टि में विश्वविद्यालय स्तर पर अनुशासनहीनता के निम्नलिखित कारण हैं—

#### 1. नैतिक शिक्षा का अभाव

##### Lack of Moral Education

छात्र देश की अमूल्य निधि है जिसमें विश्वविद्यालय का छात्र तो देश का कर्णधार है। किन्तु नैतिकता के अभाव में शिक्षा भी अधूरी है और छात्रों का व्यक्तित्व भी असंतुलित है। आज ऐसा आभास होता है जैसे हमारे समाज के उच्च आदर्श कहीं छिप गये हों। स्वतन्त्रता के पश्चात् हमारे देश में यथार्थवाद का बोलबाला और अनैतिकता की आँधी चलने लग गई कि हम अपने आध्यात्मिक मूल्यों को छोड़ दें। एक समय था जबकि हमारे देश का प्रत्येक घर एवम् नारी आध्यात्मिक भावनाओं से भोत प्रोत था और सम्पूर्ण भारतीय जीवन पर धर्म का साम्राज्य था। आज का भारतीय समस्त नैतिक मूल्यों को मूल में डाल रहा है—यही कारण है कि आज समाज में अनुशासनहीनता का साम्राज्य है। फिर छात्र सामाजिक प्राणी है अतः उसका अनुशासनहीनता होना अस्वाभाविक क्यों? संशोधन में विद्यापियों के अस्तित्व नैतिकता का ह्रास अनुशासनहीनता और कुसमायोजन का प्रमुख कारण है।

## 2. महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का दूषित वातावरण Coggery Environment of Colleges & Universities

भरोच से साठव, बालक से गुरुमार, गुरुमार से विनोर, विनोर से मुडा हुभा विद्यार्थी जब महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रवेश करता है तो अपने को अत्यन्त विचित्र वातावरण में पाता है। इन 'विद्य' और 'महा' गर्थों से अलङ्कृत विद्यामन्दिरों में यह अपने परिवर्ष का निर्माण करना चाहता है परन्तु यहाँ के प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम, दोषपूर्ण परीक्षा-पद्धति, अधोष्ण अध्यापक, जातिवाद और कुत्रिम माटकीय वातावरण से उसमें अवाञ्छनीय जकड़नियाँ विरहित हो जाती हैं जिसके कारण विद्यालय जीवन के सचित षट् अनुभव जो ग्यारह अथवा बारह वर्षों से दबे हुए थे, एवाएक उजालामुग्धो व रूप में फूट पडते हैं और जिसका शिचार सर्वप्रथम महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय होता है तत्पश्चात् समाज। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों का अनुपात्मनहीन होना बड़ा तक अस्वाभाविक है।

### 3. अध्यापकों में नेतृत्व का अभाव

#### Lack of Leadership among Teachers

प्रायः ऐसा कहा जाता है कि जब किसी का बोर्ड अध्यापक नहीं मिलता तो वह अध्यापन अध्यापक रबीकार करता है। यह बात केवल माध्यमिक स्तर के शिक्षकों तक ही सीमित हो, ऐसी मान नहीं है, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अध्यापक भी बहुत कुछ वर्षों में इसी बीमारी के शिरार होते हैं। अन-इन प्रकार के अध्यापक सामाजिक रूप से कुसमायोजित अवस्थ में हैं—जो सामाजिक कुसमायोजन से ग्रस्त होगा, उसमें तिरस्कार और होमता की भावना का भाना स्वाभाविक है। जो समाज अथवा वातावरण से तिरस्कृत है, उसमें नेतृत्व की शक्ति का विकास हो ही नहीं सकता। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक व्यक्ति उस समय सामाजिक रूप से कुसमायोजित हो जाता है जब उसकी दृष्टि सन्तुष्ट नहीं हो पाती अथवा उसकी प्रगति अवरोध हो जाती है। अध्यापक की स्थिति भी ठीक इसी प्रकार है अतः नेतृत्व की भावना के विकसित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहाँ अध्यापक के नेतृत्व की शक्ति नहीं है वहाँ छात्रों का अनुपात्मन हीन और सामाजिक कुसमायोजित होना स्वाभाविक है।

### 4. राजनैतिक दलों द्वारा विद्यार्थियों का शोषण

#### Exploitation of Students by Political Parties

प्रजातन्त्र बहुमत का शासन होना है, बहुमत बनाने के लिए सबसे सरल

1. A person becomes socially maladjusted whenever the satisfaction of a need is thwarted or progress toward a goal is blocked. Such a condition arouses tension.

Ratan Lal Sharma, *Social Maladjustment: Its Causes and Remedies* - 10

विधि छात्रों की अभिवृत्तियों को परिवर्तित करना है और उनकी स्वाभाविक शक्ति को क्षोभित करना है। उच्च शिक्षा का विद्यार्थी इसके लिए सबसे उपयोगी है और इसीलिए हमारे देश में राजनैतिक दलों द्वारा विद्यार्थियों को उत्तेजित किया जाता है और जब आयु के तकाजों के कारण वे उत्तेजित हो जाते हैं तो उन्हें असामाजिक कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार, 'दुर्भाग्यवश कुछ राजनैतिक दल अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु महाविद्यालय के छात्रों का शोषण करते हैं। आयोग ने कलकत्ता यात्रा के समय देखा कि छात्रों को रक्त पात और अराजकता फैलाने के लिए राजनैतिक दलों ने किस प्रकार प्रयोग किया। यह कार्य असामाजिक और हिंसक व्यक्तियों का था, इसके लिए छात्रों अथवा विश्वविद्यालयों को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता।'<sup>1</sup>

### 5. महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सुविधाओं का अभाव

#### Lack of Educational Facilities in Colleges & Universities

छात्रों के अनुशासनहीन और सामाजिक कुसमायोजन के सबसे प्रबल कारण महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सुविधाओं का अभाव है। कोठारी आयोग के अनुसार, 'छात्रों के भ्रष्टे और अनन्य प्रदर्शन का कारण शिक्षण और अधिगम की अपर्याप्त सुविधाएँ, छात्रों और अध्यापकों के सम्बन्ध, अध्यापकों का छात्रों की समस्याओं में अकस्मिक दखल, पाठ्यक्रम की अपूर्णता, प्राचार्यों में व्यवहार कृपणता का अभाव, अध्यापकों की राजनीति आदि है।'<sup>2</sup> राधाकृष्णनन् आयोग ने

1 Unfortunately, some political cliques and even anarchical elements are continuing to exploit college students for their purposes. During the visit of the Commission to Calcutta, a riot was started in which students were apparently used as pawns and which issued in blood-shed and lawlessness that continued two or three days. This disorder was the work of anti-social and violent elements, and neither the University nor students could be held responsible.

*Report of the University Education Commission, 1948-49, ¶ 380.*

2 There is a variety of causes which has brought about these ugly expressions of uncivilized behaviour e.g. the uncertain further facing educated young men leading to a sense of frustration which breeds irresponsibility the mechanical and unsatisfactory nature of many curricular programmes, the totally inadequate facilities

Universities.

*Report of the University Education Commission, 1961-66 p 297.*



## 2. माता-पिता, राजनैतिक दलों और जनता के सहयोग की आवश्यकता Need of Cooperation from Parents, Political Parties and Public

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि अनुशासन और व्यवस्थापन की समस्या का उत्तरदायित्व किसी कारण विशेष पर ही नहीं है बल्कि सम्पूर्ण समाज में व्याप्त अनेकों गुराईयों इसका कारण है। अतः यदि केवल शिक्षा के माध्यम से ही इस समस्या का समाधान करना है तो असम्भव है—इसके लिए यह नितान्त आवश्यक है कि समाज के सभी वर्गों सहयोग प्रदान करें—हमारा आशय विशेष रूप से राज-नैतिक दलों से है। विश्वविद्यालय आयोग के अनुसार 'शासक और अध्यापक शिक्षा क्षेत्र में सन्तोषप्रद जीवन स्थापित नहीं कर सकते। उनको माता-पिता, राजनैतिक नेताओं, जनता और प्रेस के सहयोग की आवश्यकता है।'

## 3. शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता Need for Education Facilities

शैक्षिक सुविधाओं की प्राप्ति नितान्त आवश्यक है। अज्ञान पाप को जन्म देता है। असमर्थता व्यक्ति में अपराधी भावनों को जन्म देती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि कोण से उपरोक्त कथन सत्य है। शैक्षिक सुविधाओं का अभाव समस्याओं को जन्म देता है, अतः आवश्यक है कि पुस्तकालयों, शोध स्थलों, अन्य सहायक सामग्री आदि की उचित व्यवस्था हो।

## 4. आत्म-अनुशासन Self Discipline

सच्ची शिक्षा को आत्म-अनुशासन की भावना को जागृत करना चाहिए—यह वह अनुशासन है जो अन्तः द्वारा निरदिष्ट होता है। यह सभी सम्भव है जबकि छात्र अध्ययन में रुचि लें और विद्या की प्राप्ति हेतु मर्तत प्रयत्नशील हों। यदि आत्म अनुशासन आ जाये तो अनुशासन की कोई समस्या ही नहीं है।

अन्त में हम यही कह सकते हैं कि उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर हम भय-कर समस्या का समाधान सम्भव है।



## ग्रन्थ-सूची

### Bibliography

1. Dasu A. N.  
*University Education in India*, Book Emporium, 1966.
2. Kothari, D. B.  
*Some Aspects of University Education* U G C New Delhi 1952
3. *Report of the working Group for Developing A Comprehensive Scheme of Examination, Reform in University Education*, National Institute of Education, New Delhi, 1968.
4. *Report on Evaluation in Higher Education*,  
University Grants Commission, New Delhi, 1961.
5. *Report on Standards of University Education*,  
University Grants Commission, New Delhi, 1965.
6. *Report of University Education Commission*,  
Manager Publication, Govt. of India, Delhi, 1949.
7. *Report of the Education Commission*,  
Ministry of Education, Govt. of India, 1966

# विश्वविद्यालय प्रश्न

## University Questions

1. What are the needs for expansion of higher education in India? In what sectors should expansion be accelerated? Support your answer by the recommendations of Indian Education Commission.

2. 'It is said that during the last few years University standards have generally suffered <sup>not the</sup> <sup>fully</sup> <sup>in</sup>

What measures should be taken to raise the standards of the University Education.

3. The Indian Universities as they exist today, despite many admirable features, do not fully satisfy the requirements of the national of education. Comment upon this view.

4. What are the problems of higher education in India? What measures can be taken to solve these problem.

5. 'Universities in India have to be internationally minded. If they are to benefit from the vast expansion of knowledge that is taking place in different parts of the world today, their channels of Communication and reception have to be kept open.

In the light of the above statement, What should be done in our Universities to make them active participants in the work of the world community of learning.

**अध्याय तेरह**  
**Chapter Thirteenth**

**अध्यापक शिक्षा**  
**Teacher Education**

**अध्ययन बिन्दु**  
**Learning Points**

- 13.01 अध्यापक शिक्षा की परिवर्तिन धारणा  
*Changing Concept of Teacher Education*  
धारणा में परिवर्तन के कारण
- 13.02 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अध्यापक शिक्षा  
*Teacher Education After Independence.*
  - 1. छात्र अध्यापकों की योग्यताएँ
  - 2. अध्यापकों की समस्या
  - 3. प्रशिक्षित अध्यापक
  - 4. निम्नक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
  - 5. निम्नक प्रशिक्षण महाविद्यालय
- 13.03 विभिन्न स्तरों के लिए अध्यापकों की प्रारम्भिक व्यावसायिक तैयारी  
*Initial Professional Preparation of Teachers For Various Levels*
  - 1. पूर्ण प्राथमिक स्तर हेतु प्रशिक्षण
  - 2. प्राथमिक स्तर हेतु प्रशिक्षण विद्यालय
  - 3. माध्यमिक स्तर हेतु प्रशिक्षण महाविद्यालय
  - 4. शिक्षा के क्षेत्रीय महाविद्यालय
  - 5. स्नातकोत्तर प्रशिक्षण महाविद्यालय
  - 6. समाकलन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
  - 7. विशेष प्रशिक्षण केन्द्र
    - (अ) शारीरिक शिक्षा
    - (ब) सौन्दर्य धारा सम्बन्धी शिक्षा
    - (घ) छात्र अध्यापकों के प्रशिक्षण विद्यालय
    - (ङ) गृह-विज्ञान

• 13.04 सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा

Inservice Teacher Education.

(अ) सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य एवं सध्य

1. व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि
2. शैक्षिक सामर्थ्य की प्राप्ति
3. नवीन ज्ञान की सम्भावनाएँ

(ब) शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए सेवाकालीन शिक्षा

1. प्राथमिक गाला के अध्यापक और सेवाकालीन शिक्षा
2. माध्यमिक गाला के अध्यापकों की सेवाकालीन शिक्षा
3. उच्च शिक्षा स्तर के अध्यापकों की सेवाकालीन शिक्षा

(स) 'सेवाकालीन शिक्षा की विधियाँ

• 13.05 अध्यापक शिक्षा की समस्याएँ और समाधान

Problems & Solutions of Teacher Education

1. प्रशिक्षण कार्यक्रमों और स्कूल कार्य में सम्बन्ध बिहीनता
2. अध्यापकों का सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक स्तर

सामाजिक स्तर

आर्थिक स्तर

व्यावसायिक स्तर

अध्यापकों के स्तर को विकसित करने की आवश्यकता  
भारतीय शिक्षा (कोठारी) आयोग की सिफारिशें

वेतन त्रम

पदोन्नति की आवश्यकता

सेवा-विवृति साम

## अध्यापक शिक्षा TEACHER EDUCATION

शिक्षा में गुणारमक उपरति हेतु अध्यापको की शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य बनाना निरान्त आवश्यक है। अध्यापक शिक्षा पर किये हुए व्यय और प्रयत्नों अनुपात में प्राप्त लाभों की मात्रा वही अधिक होती है। अध्यापक शिक्षा के प्रा हेतु जितने धन की आवश्यकता है वह लाखों और करोड़ों व्यक्तियों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने की तुलना में बहुत कम है। एक प्रशिक्षित अध्यापक अपने जीवन में हजारों छात्रों को दीक्षित करता है अर्थात् एक अध्यापक को प्रशिक्षित करने लिए खर्च किया हुआ कुछ धन हजारों छात्रों को शिक्षित करने की तुलना में कम है।

आज नवीनतम एवम् यतिशील पद्धतियों की आवश्यकता है, यह उभा सम्भव है जबकि अध्यापकों को उसके अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाये। इसके दो लाभ सम्भव हैं, प्रथम अध्यापकी में व्यावसायिक क्षमता का विकास, और द्वितीय शिक्षा में अपेक्षित ज्ञानि का शुमारम्भ। हमारी तो यह निश्चित धारणा है कि जो भी नवीन प्रयोग और शिक्षा में वाछित परिवर्तन करना हो उसे अध्यापक शिक्षा से ही प्रारम्भ किया जाये।

### 13.01 अध्यापक शिक्षा की परिवर्तित धारणा Changing Concept of Teacher Education

अध्यापको ने प्रशिक्षण हेतु कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं थी जब शिक्षा ने कुछ छात्रों को मुक्त द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया

जाता था। उस समय अध्यापक शिक्षा की सर्वप्रथम धारणा 'पित्ताचार्य'<sup>1</sup> की थी। 'पित्ताचार्य'<sup>2</sup> का तात्पर्य उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे उन प्रतिभाशाली छात्रों से था। अन्य छात्रों के शिक्षण में गुरु की सहायता करते थे। एक तरीके से यह कहा सकता है कि प्राचीन काल में गुरु द्वारा कुछ प्रतिभाशाली छात्रों को अप्रत्यक्ष रूप से अध्यापन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था और वे छात्र गुरु की अनुपस्थिति में अन्य छात्रों को पढ़ाने की समुचित व्यवस्था करते थे।

'पित्ताचार्य' की धारणा के परिवर्तन अध्यापक शिक्षा की धारणा में कुछ परिवर्तन हुआ। शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए 'छात्रनायक पद्धति'<sup>3</sup> का आरम्भ हुआ। इस पद्धति का अर्थ था कि छात्रों के नायक द्वारा शिक्षण कार्य करना। अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की इस विधि का प्रारम्भ उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ था। इस पद्धति के अनुरूप सम्पूर्ण बच्चा अपना शाला को कुछ समूहों में विभाजित कर दिया जाता था। प्रत्येक समूह में कुछ छात्र होते थे और एक समूह का एक नायक होता था। नायक का कर्तव्य था कि वह अपने समूह का शिक्षण करे और इसकी सहायता अध्यापक को दे। यद्यपि इस समय तक किसी प्रकार की सैद्धांतिक शिक्षा का प्राक्घान नहीं था तथापि व्यावहारिक प्रशिक्षण कई वर्षों तक प्राप्ति होता था क्योंकि ये नायक अपने अध्यापक के समान ही अवशर्त शिक्षण प्रदान करने का प्रयास करते थे। सन् 1787 में डा. एण्ड्रयुस ने मद्रास में इस प्रणाली को स्वीकार किया और इस पद्धति पर एक पुस्तक<sup>4</sup> लिखी जिसने ब्रिटिश शिक्षा धारणा का ध्यान आकषिप्त किया। तत्पश्चात् इसे अध्यापक पद्धति<sup>5</sup> भी कहा जाने लगा।

अध्यापक शिक्षा की परिवर्तित धारणाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति ने ही अध्यापकों के प्रशिक्षण का शुभारम्भ किया जो धीरे-धीरे सत्तर के अन्य देशों में छोड़े छोड़े परिमार्जन के साथ स्वीकार किया जाने लगा। हमारे देश में सर्वप्रथम सीरायपुर में डेनिश मिशनरियों के धारणियों में एक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की तत्पश्चात् बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में कुछ केन्द्र खोले गये।

सन् 1854 में लुड घोषणा पत्र ने यह सुझाव दिया गया कि इंग्लैंड के धारणों पर भारत में भी प्रशिक्षण विद्यालय खोले जायें। सन् 1882 में भारतवर्ष के अध्यापक, 106 नॉर्मल स्कूल थे जिनमें 3886 प्रशिक्षाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

1. Pittacharya

2. Pittacharya

the Male Asyle

5. Report of the Indian Education Commission, p. 131

अध्यापक शिक्षा की माँग पर सरकार ने 1947 में दो प्रणाली शुरू कीं। पहली प्रणाली में माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने के बाद छात्रों को प्रविष्टि दी जाती थी। दूसरी प्रणाली में माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने के बाद छात्रों को प्रविष्टि दी जाती थी। 1947 में दो प्रणाली शुरू कीं। पहली प्रणाली में माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने के बाद छात्रों को प्रविष्टि दी जाती थी। दूसरी प्रणाली में माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने के बाद छात्रों को प्रविष्टि दी जाती थी।

(1) नार्मल स्कूल (Normal Schools)—इनके आगमन के बाद अध्यापकों के लिए प्रविष्टि दी जाती थी। यह और भी अधिक लाभदायक एवं प्रभावी प्रणाली के अविशारी है।

(2) प्रशिक्षण स्कूल (Training Schools)—इनके आगमन के बाद अध्यापकों के लिए प्रविष्टि दी जाती थी। यह और भी अधिक लाभदायक एवं प्रभावी प्रणाली के अविशारी है।

(3) प्रशिक्षण महाविद्यालय (Training Colleges)—इनके आगमन के बाद अध्यापकों के लिए प्रविष्टि दी जाती थी। यह और भी अधिक लाभदायक एवं प्रभावी प्रणाली के अविशारी है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर गौरव में यह कहा जा सकता है कि धारणाओं में समानानुसार परिवर्तन आया जो इस प्रकार है—

\* छात्र-अध्यापक प्रणाली (1801-1882)

Pupil-Teacher System (1801-1882)

\*\* अध्यापक प्रशिक्षण (1882-1947)

Teacher Training (1882-1947)

\*\*\* अध्यापक शिक्षा (स्वतंत्रता के पश्चात)

Teacher Education After Independence)

धारणा में परिवर्तन के कारण

Causes of Changes in Concept

जैसा कि हम पहले कह आये हैं कि धारणाओं में आवश्यकतानुसार कुछ परिवर्तन हुए और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमने नवीन धारणा को स्वीकार किया। इसके कई कारण थे जो इस प्रकार हैं—

1. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के सभी क्षेत्रों में विकास करना था। अतः देश की आवश्यकताओं के अनुरूप हमें वैश्विक कार्यक्रमों में कुछ परिवर्तन करने आवश्यक थे। अध्यापकों के प्रशिक्षणार्थ हमें शिक्षा की आवश्यकता थी अतः 'अध्यापक प्रशिक्षण' के अभाव पर 'अध्यापक शिक्षा' की नई धारणा को स्वीकार करना आवश्यक था।

2. अध्यापक शिक्षा नि: सांकेतिक और मनोवैज्ञानिक आधार भारतीय शिक्षा सांस्त्रियों को सम करने थे । स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व प्रशिक्षण के सम सिद्धान्त विदेशी शिक्षा सांस्त्रियों के बनाये हुए थे । अतः धारणा परिवर्तन अस्वाभाविक था ।
3. अध्यापक शिक्षा की धारणा समस्त संसार में परिवर्तित हो रही थी 'अध्यापक शिक्षा' का अर्थ विस्तृत था जबकि 'अध्यापक प्रशिक्षण' का अर्थ सीमित था । 'अध्यापक शिक्षा' जीवन के समस्त पहलुओं को प्रभावित करती है ।
4. डब्ल्यू. एच. किलेपेट्रिक के मतानुसार 'ट्रेनिंग' तो सरफत में काम करने वालों और आनवरों को दी जाती है, अध्यापकों को तो 'प्रशिक्षण' किया जाता है । अतः 'प्रशिक्षण' के स्थान पर 'शिक्षा' को स्वीकार किया जाना उचित ही है ।
5. वैदिक शिक्षा का पृथक् अनुशासन स्वीकार करते हुए यह अनिवार्य था कि हम 'प्रशिक्षण' के स्थान पर 'शिक्षा' को स्वीकार करें ।
6. इसी धारणा को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53), भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66) द्वारा स्वीकार किया गया । विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार, 'वास्तविक शिक्षा केवल मात्र कुछ पाठों को पढ़ना और रटना ही नहीं है, बल्कि जीवनयापन और सौन्दर्यपूर्ण क्रियाएँ करना है' ।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अध्यापन की दक्षता को विकसित करने के लिए मात्र 'शिक्षा' की आवश्यकता है, न कि 'प्रशिक्षण' की ।

### स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अध्यापक शिक्षा (Teacher Education After Independence)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा के सभी क्षेत्रों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं उनमें अध्यापक शिक्षा के परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं । सभी प्रगतिशील देशों में अध्यापक शिक्षा की महत्ता को स्वीकार किया है । अतः हमारे देश की प्रगति हेतु यह नितास्त आवश्यक था कि अध्यापकों की शिक्षा का भी प्रसार किया जाये ।

1. 'A real education is not so much a matter of lessons to be learnt and memorized as of a life to be lived and purposeful activities to be shared.'

*Report of the University Education Commission, p. 21*

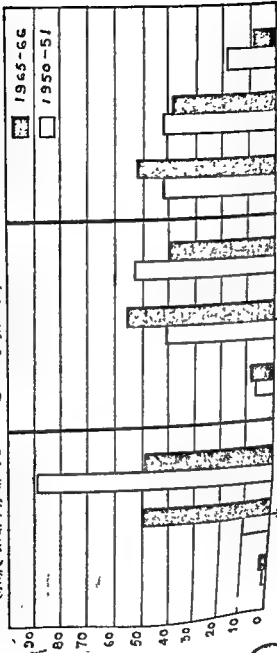


# शालाओं के प्रदूषण की योग्यताएँ

1950-51 और 1965-66

प्राथमिक शालाएँ

लोअर प्राथमिक शालाएँ उच्चतर प्राथमिक शालाएँ



स्नातक और स्नातकोत्तर

मैट्रिक और स्नातकोत्तर से कम

मैट्रिक से कम

स्नातक और स्नातकोत्तर

मैट्रिक और स्नातकोत्तर से कम

स्नातक और स्नातकोत्तर

मैट्रिक और स्नातकोत्तर से कम

मैट्रिक से अधिक

# 1. शाला अध्यापकों की योग्यताएँ

## Qualifications of School Teachers

स्वतन्त्रता से पूर्व अध्यापकों की योग्यताएँ अत्यन्त ही न्यून थीं। ग्राफ द्वारा इस स्थिति को स्पष्ट किया गया है। तालिका न० 13.1 से यह स्थिति और भी स्पष्ट है। माध्यमिक शालाओं के अन्तर्गत 1950-51 में स्नातक अथवा उससे अधिक केवल 40.1% अध्यापक थे, 1965 में इन अध्यापकों का प्रतिशत 50.2 था।

### तालिका न० 13.1

#### प्राथमिक अध्यापकों की सामान्य शिक्षा (1950-51 से 1965-66)

वर्ग	स्नातक और उससे अधिक	माध्यमिक शिक्षा और स्नातक से कम	माध्यमिक शिक्षा से कम	कुल योग
सोझर प्राथमिक शालाएँ				
1950-51				
पुरुष	898 (0.2)%	44,730 (9.8)%	410,009 (90.0)%	455,637 (100)%
महिलाएँ	410 (0.5)%	9,670 (11.8)%	72,201 (87.7)%	82,281 (100)%
योग	1,308 (0.3)%	54,400 (10.1)%	482,210 (89.6)%	537,918 (100)%
1965-66 (अनुमानित)				
पुरुष	7,100 (0.6)%	430,650 (50.7)%	412,250 (48.5)%	850,000 (100)%
महिलाएँ	3,400 (1.7)%	94,350 (47.2)%	102,250 (51.1)%	200,000 (100)%
योग	10,500 (1.0)%	525,000 (50.0)%	514,500 (49.0)%	1,050,000 (100)%

## उच्चतर प्राथमिक स्तर

1950-51				12,609
पुरुष	3,020 (5.4)%	31,267 (43.1)%	37,422 (51.5)%	(100)%
महिलाएँ	887 (6.0)%	4,323 (33.5)%	7,677 (59.6)%	12,897 (100)%
योग	4,807 (5.6)%	35,590 (41.6)%	45,099 (52.8)%	85,498 (100)%
1965-66 (अनुमानित)				350,000
पुरुष	23,500 (6.2)%	212,200 (55.8)%	144,300 (38.0)%	(100)%
महिलाएँ	7,700 (5.5)%	68,600 (49.0)%	63,700 (45.5)%	140,000 (100)%
योग	31,200 (6.0)%	280,800 (56.0)%	208,400 (40.0)%	520,000 (100)%

## 2. अध्यापकों की संख्या

## Number of Teachers

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अध्यापकों की संख्या में वृद्धि हुई है। सन् 1950-51 में अध्यापकों की संख्या केवल मात्र 860 थी जो 1965-66 तक बढ़कर 65,000 हो गई। प्राथमिक स्तर पर 1950-51 में कुल संख्या हजारों की जो 1965-66 में 1030 हजार हो गई। उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्यापकों की संख्या में तीन गुनी वृद्धि हुई है। सदीय में इन देश में माध्यमिक स्तर के अध्यापकों की कुल संख्या दस लाख है जिसमें चौपाई महिवाएँ हैं। सालिका नं० 13.2 में अध्यापकों की संख्या को योजनाओं के आधार पर स्पष्ट किया गया है।

**तालिका न० 13.2**  
**अध्यापकों की संख्या**  
**(1950-51 से 1965-66)**

विभिन्न स्तरों के अध्यापक	लिंग एवं योग	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66
पूर्व प्राथमिक शालाओं के अध्यापक	—	866	1880	4000	6500
प्राथमिक शालाओं के अध्यापक (हजार में)	पुरुष	456	574	615	880
	स्त्री	82	117	127	200
	योग	538	691	742	1080
मिडिल शालाओं के अध्यापक (हजार में)	पुरुष	73	124	201	380
	स्त्री	13	24	84	140
	योग	86	148	344	520
उच्च/उच्चतर माध्यमिक शालाओं के अध्यापक (हजार में)	पुरुष	107	155	235	345
	स्त्री	20	35	—	95
	योग	127	190	296	440
प्रशिक्षण शालाओं के अध्यापक	पुरुष	3511	4942	6826	—
	स्त्री	1287	1431	1755	—
	योग	4798	6373	8581	—

**3. प्रशिक्षित अध्यापक**  
**Trained Teachers**

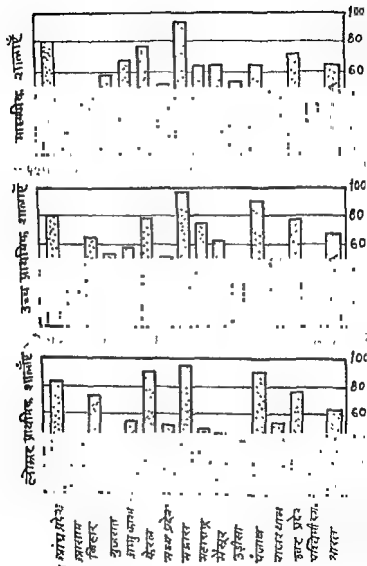
सन् 1947 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में आये ॥ अध्यापक अप्रशिक्षित थे । सन् 1968 तक सामान्य तौर पर लोअर प्राथमिक स्तर 68%; उच्च प्राथमिक स्तर के 72% और माध्यमिक स्तर पर 71% अध्यापक प्रशिक्षित हैं । विभिन्न राज्यों में सन् 1965-66 के अन्तर्गत प्रशिक्षित अध्यापकों की कुल संख्या और प्रतिशत, सम्बन्धित ग्राफ और तालिका न० 13.3 में स्पष्ट किया गया है ।

तालिका न० 13.3  
राज्यों में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या और प्रतिशत  
Number & Percentage of Trained Teachers in the States  
(1965-66)

राज्यों के नाम	माध्यमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर	लोअर प्राथमिक स्तर
1. आंध्र प्रदेश	34,215 (82.4)	15,625 (80.5)	80,501 (90.0)
2. आसाम	9,210 (18.6)	14,810 (22.4)	37,500 (55.0)
3. बिहार	24,398 (60.2)	32,018 (72.6)	90,563 (82.7)
4. गुजरात	22,290 (66.4)	83,640 (61.4)	उच्च प्राथमिक में शामिल
5. जम्मू व काश्मीर	4,613† (25.6)	3,467† (51.2)	4,874† (31.0)
6. केरल	22,031 (89.0)	39,406 (82.7)	69,703 (93.0)
7. मध्य प्रदेश	107,016 (69.0)	27,961* (72.0)	670,006 (80.0)
8. महाराष्ट्र	48,194* (86.3)	59,440* (93.1)	76,635* (96.7)
9. महाराष्ट्र	48,590 (71.4)	131,700 (74.8)	उच्च प्राथमिक में शामिल
10. मेघालय	10,334 (59.5)	91,932 (60.9)	उच्च प्राथमिक में शामिल
11. नागालैंड	309 (13.9)	745 (8.7)	1,704 (20.5)
12. छत्तीसगढ़	8,461* (52.0)	10,322* (31.0)	48,376* (61.0)
13. पंजाब	26,234 (96.0)	14,911* (25.0)	34,462* (40.0)
14. राजस्थान	12,671* (60.0)	19,235* (71.0)	41,500 (73.0)
15. उत्तर प्रदेश	23,311 (51.9)	46,819 (47.1)	162,173 (73.3)
16. तमिलनाडु	10,234 (33.6)	12,441 (16.3)	94,106 (34.3)

† 1961-62 का आँकड़ा  
\* 1961-62 का आँकड़ा

# प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत



#### 4. शिक्षक प्रशिक्षण शालाएँ Teachers' Training Schools

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षक प्रशिक्षण शालाओं की संख्या बृद्धि हुई है। छात्रों की अपेक्षा छात्राओं की संख्या अधिक बढ़ी है। के शिक्षण हेतु यह और भी आवश्यक है कि महिला अध्यापकों की संख्या बृद्धि हो। तालिका न० 13.4 से शिक्षक प्रशिक्षण शालाओं की प्रगति आभास होता है।

तालिका न० 13.4  
शिक्षक प्रशिक्षण शालाएँ

वर्ष		1964-67	1950-51	1955-56	1960-61
1. शालाओं की संख्या	पुरुषों के लिए	443	567	678	881
	महिलाओं के लिए	206	215	252	287
	योग	649	782	930	1138
2. विद्यार्थियों की संख्या	लड़के	27662	52069	65033	91130
	लड़कियाँ	11111	17094	26881	31552
	योग	38773	70063	90914	122685
3. कुल खर्चा (हजार रु० में)	लड़के	6294	11468	16506	20109
	लड़कियाँ	2807	3761	4251	6402
	योग	9101	15229	19757	34811

### 5. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय Teachers' Training Colleges

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय हमारे देश में कुल 42 महाविद्यालय थे। प्राप्त आकड़ों के आधार पर 1965-66 में इनकी संख्या बढ़कर 269 हो गई। इस समय इनकी संख्या में कुछ और वृद्धि हुई है। वहीं तक छात्रों की संख्या का प्रश्न है, उसमें भी काफी प्रगति हुई है, जिसकी सम्भावित वृद्धि ग्यारह गुनी है। छात्र एवम् छात्राओं के अनुपात में भी सन्तोषप्रद वृद्धि हुई। तालिका न० 13.5 में इस स्थिति को और भी स्पष्ट किया गया है।

तालिका न० 13.5

शिक्षक—प्रशिक्षण महाविद्यालय

सद	1946-47	1950-51	1955-56	1960-61	1965-6
1. महाविद्यालयों की संख्या	42	53	107	—	269
2. छात्र संख्या					
पुरुष	—	3851	9962	—	20000
महिला	—	1930	4318	—	10000
योग	3095	5781	14280	—	30000
3. वर्षा (हजार इ० में)	2201	3547	6566	21514	24000

### 13.03 विभिन्न स्तरों के लिए अध्यापकों को प्रारम्भिक व्यावसायिक संयारी

Initial Professional of Teachers for Various Levels

विभिन्न स्तरों के लिए अध्यापकों के प्रारम्भिक व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु हमारे देश में सामान्य रूप से निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थाएँ विद्यमान हैं—



### 1. पूर्वं प्राथमिक स्तर हेतु प्रशिक्षण Training for Pre-Primary Level

हमारे देश में मुख्य रूप से तीन प्रकार की पूर्व-प्राथमिक शाळाएँ हैं

(अ) माण्टेसरी शाळाएँ (Montessori Schools)

(ब) किण्डरगार्टन (Kindergartens)

(ग) पूर्वं-बेसिक शाळाएँ (Pre Basic Schools)

किण्डरगार्टन, मॉन्टेरी, माण्टेसरी के प्रशिक्षण में सामान्य रूप से समाज और बाल मनोविज्ञान, आरोग्य विज्ञान, बाल शिक्षण पद्धति, संगीत, चित्र आदि हस्त शिल्प अथवा मारीक ग्यागलस आदि का ज्ञान प्रशिक्षण काल में आता है।

पूर्व बुनियादी स्तर के प्रशिक्षण में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया गया है—सामुदायिक जीवन का संगठन, सप्ताह-प्रशिक्षण, बाल शिक्षा का इतिहास पूर्व-बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त कार्य संगठन, बाल स्वास्थ्य, संगीत, कला आदि शिल्प।

### 2. प्राथमिक स्तर हेतु प्रशिक्षण विद्यालय Training Schools for Primary Stage

प्राथमिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण का एक अथवा दो वर्ष हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए न्यूनतम योग्यता मेट्रिक/ हायर सेकेंडरी निर्धारित की गई है। इस समय हमारे देश में दो प्रकार के प्राथमिक प्रशिक्षण विद्यालय हैं—बुनियादी, और बुनियादी। सम्पूर्ण देश में सन् 1956-57 में बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या 876 थी और गैर बुनियादी विद्यालयों की 196 थी। सन् 1965-66 पुरुषों के लिए प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या 1000 थी और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या 300 थी जिनमें 110,000 पुरुषों और 60,000 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

राजस्थान में 1950-51 में पुरुषों के लिए 12 और महिलाओं के लिए 3 शिक्षण विद्यालय थे। सन् 1963-64 में यह संख्या बढ़कर पुरुषों के लिए 46 और महिलाओं के लिए 12 हो गई। सावित्रा नं० 13.6 से राजस्थान में प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थिति का सही आभास होता है। सन् 1968-69 में प्रशिक्षण विद्यालयों को बन्द कर दिया है।

तालिका न० 13.6  
राजस्थान में शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय<sup>1</sup>  
Teachers' Training Schools in Rajasthan

वर्ष	शालाओं की संख्या			छात्रों की संख्या			प्रति विद्यार्थी औसत व्यय
	लड़के	लड़कियाँ	योग	लड़के	लड़कियाँ	योग	
1950-51	12	3	15	984	305	1287	311 7
1955-56	11	2	13	1015	162	1177	522 6
1960-61	51	4	55	6031	547	6576	501 2
1961-62	45	5	50	5392	644	6038	539 6
1962-63	45	6	51	5160	977	6137	570 7
1963-64	46	12	58	—	—	—	—

इस प्रशिक्षण के पदचात उत्तीर्ण छात्रों का विश्वविद्यालय अथवा शिक्षा विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा प्रदान किए जाते हैं विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण की अवधि और प्रमाण-पत्रों के नाम भिन्न हैं (देखिये तालिका 13.7।)

तालिका न० 13 7  
विभिन्न राज्यों द्वारा प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र और अवधि

स्थान का नाम	प्रमाण-पत्र का नाम	प्रशिक्षण अवधि
1. बम्बई	टी० सी०	एक वर्ष
2. बड़ोदा	" "	" "
3. गुजरात	" "	" "
4. कर्नाटक	" "	" "
5. पूना	" "	" "
6. मैसूर	टी० सी०	" "
7. कलकत्ता	एल० टी०	" "
8. नागपुर	डिप० टी०	दो वर्ष
9. सागर	" "	" "
10. बिहार	सी० टी०	" "
11. मद्रास	टी० एम० एल	" "
12. उत्तर प्रदेश	जे० टी० सी०	" "

1. Progress of Education Rajasthan, Govt of Rajasthan, 1964 p. 9.

### 3. माध्यमिक स्तर हेतु प्रशिक्षण महाविद्यालय Training Colleges for Secondary Stage

अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में स्नातकों अथवा इससे अधिक शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी हो प्रवेश ले सकते हैं। शिक्षा की स्नातक उपाधि सामान्यतया विर-विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है जिसे बी. टी., बी. एड. अथवा डिप. एड. कहते हैं। उत्तर प्रदेश में बी. एड. के अतिरिक्त एल. टी. का प्रमाण पत्र भी शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाता है जिसकी अवधि एक अथवा दो वर्ष है। इन महाविद्यालयों का उद्देश्य माध्यमिक शालाओं के लिए अध्यापकों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है।

राजस्थान में सन् 1969-70 में क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के अतिरिक्त सोलह महाविद्यालय थे जिनमें से दो राजकीय और चौदह गैर सरकारी थे। प्राप्त आँकड़ों के आधार पर सन् 1963-64 तक राजस्थान में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थिति को तालिका नं० 13.8 में स्पष्ट किया गया है।

तालिका नं० 13.8

#### राजस्थान में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय<sup>1</sup> Teachers Training Colleges in Rajasthan

वर्ष	महाविद्यालयों की संख्या	छात्रों की संख्या				निकाश		प्रति विद्यार्थी औसत खर्च
		लड़के	लड़कियाँ	योग	लड़कियाँ	योग		
1950-51	2	1.5	20	155	180	26	206	612.0
1955-56	3	286	25	311	260	26	286	404.3
1960-61	4	441	62	503	438	48	486	885.0
1961-62	5	531	95	626	530	97	627	873.5
1962-63	6	627	125	752	610	95	605	774.8
1963-64	7	—	—	—	—	—	—	—

इस संपूर्ण देश में 280 प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं जिनमें से 78 राज्य सरकारों द्वारा, 150 निजी शालाओं द्वारा और अन्य विर-विद्यालयों द्वारा संचालित होते हैं। हमारे देश में दो प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं —

1. परम्परागत महाविद्यालय (Traditional Colleges)

2. बुनियादी महाविद्यालय (Basic Colleges)

परम्परागत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में निम्नलिखित सैद्धान्तिक प्रश्न-पत्र हैं—

(अ) शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार  
(Philosophical & Sociological Foundations of Education)

(ब) शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार एवं मूल्यांकन  
(Psychological Foundations of Education & Evaluation)

(ग) विद्यालय संगठन एवं स्वास्थ्य शिक्षा  
(School Organization & Health Education)

(द) दो विषयों की अध्यापन विधियाँ  
(Methods of Teaching of two School subjects)

(इ) भारतीय शिक्षा की सार्वजनिक समस्याएँ  
(Current Problems of Indian Education)

उपरोक्त सैद्धान्तिक प्रश्न-पत्रों में विश्वविद्यालयों ने अपनी सुविधानुसार कुछ परिवर्तन भी कर रखे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय ने स्वास्थ्य शिक्षा को भारतीय शिक्षा समस्याओं के साथ और विद्यालय संगठन को शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार के साथ सम्मिलित कर दिया है। हमने अतिरिक्त स्नातक स्तर पर लिये हुए वैकल्पिक विषयों में से दो विषयों की अध्यापन विधियाँ को पृथक रूप से दो प्रश्न-पत्र हैं। अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों ने उपरोक्त पाठ्यक्रम को आंशिक परिवर्तन द्वारा स्वीकार कर रखा है।

सैद्धान्तिक प्रश्न-पत्रों के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी को निर्धारित संख्या के अनुरूप अध्यापन-अभ्यास करना पड़ता है।

सैद्धान्तिक और अध्यापन अभ्यास के अतिरिक्त यदि कोई विद्यार्थी चाहे तो विशिष्ट प्रश्न-पत्र की योग्यता भी प्राप्त कर सकता है। सामान्यतः भारतीय विश्व-विद्यालयों में निम्नलिखित विषय प्रचलित हैं:—

1. शाला पुस्तकालय संगठन (School Library Organization)

2. शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देशन

(Educational & Vocational Guidance)

3. ग्रामीण शिक्षा (Rural Education)

4. ह्रस्व श्रव्य शिक्षा (Audio Visual Education)

5. मापन एवं मूल्यांकन (Measurement & Evaluation)

6. समाज शिक्षा (Social Education)
7. बुनियादी शिक्षा (Basic Education)
8. स्वास्थ्य शिक्षा (Physical Education)
9. कला एवं उद्योग (Art & Crafts)
10. पिछड़े बच्चों की शिक्षा (Education for Backward Children)
11. सहकामो विद्याओं का संगठन

(Organization of Co-curricular Activities)

बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों का पाठ्यक्रम भिन्न दिशवृत्तों में अपनी सुविधानुसार बना रखा है। परन्तु बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों की समिति में निम्नलिखित पाठ्यक्रम निश्चित किया गया था —

(I) सैद्धान्तिक—(i) बुनियादी शिक्षा के सन्दर्भ में शिक्षा दर्शन और शिक्षा समाज-शास्त्र

(ii) शिक्षा मनोविज्ञान

(iii) शिक्षा प्रशासन और निरीक्षण अथवा  
शैक्षणिक शिक्षा एवं शिक्षा अनुसन्धान

(iv) बुनियादी शिक्षण पद्धतियाँ

(v) उद्योग कार्य का संचालन और निजात

(II) मुख्य उद्योग—निम्नलिखित में से कोई एक बुनियादी उद्योग

(i) कृषि (गुग्गु पालन)

(ii) कपाई और बुनाई

(iii) चमड़े, लकड़ी और धातु कार्य

सहायक उद्योग—(i) कृषि शिक्षा

(ii) कपाई (उनके लिए विशिष्ट कपाई मुख्य उद्योग के रूप में नहीं ली है)

(iii) लकड़ी कागज (उनके लिए विशिष्ट मुख्य उद्योग में कृषि नहीं ली है)

(iv) चमड़े का काम (Leather work)

(v) लपेटकामी काम (Lekaping)

(vi) चमड़े के दर्जन करने का काम (Dyeing)

सहायक कार्य—(i) कार्य का संचालन

(iii) वैयक्तिक और सामूहिक परीक्षाओं का परिचालन ।

(iv) शिक्षण सामग्री का सङ्कलन और निर्माण

(v) बुनियादी साक्षात्कारों के लिए सहायक सामग्री का निर्माण ।<sup>1</sup>

#### 4 शिक्षा ■ क्षेत्रीय महाविद्यालय

##### The Regional Colleges of Education

बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के पश्चात् यह अनुभव किया जा कि प्रयोगात्मक विषयों के शिक्षण हेतु योग्य अध्यापकों का अभाव था । इसके साथ ही विचार किया गया कि विद्यमान शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय बल मात्र परम्परागत अध्यापकों को प्रशिक्षण देने में समर्थ है और वाणिज्य, ज्ञान तथा अन्य प्रयोगात्मक विषयों के प्रशिक्षण देने में असमर्थ हैं । देश की प्रगति हेतु यह भी अनुभव किया गया कि औद्योगिक विकास हेतु यह अत्यन्त अनिवार्य है कि योग्य और प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा देश के भावी नगरों को विज्ञान और उच्च विज्ञान में दीक्षित किया जाये । अतः उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई । इस समय हमारे देश में चार क्षेत्रीय महाविद्यालय कार्य कर रहे हैं जो कि अजमेर भुवनेश्वर, रायचूर और मैसूर में स्थित हैं । पिछले वर्ष इन महाविद्यालयों के कार्यक्षेत्र का पुनर्विभाजन करने के लिए एक समीक्षा समिति का गठन हुआ था, आशा है निम्न भविष्य में इन क्षेत्रीय महाविद्यालयों के कार्यक्षेत्र में कुछ परिवर्तन आये । अजमेर (राजस्थान) में स्थित क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में भाषा शिक्षण के प्रशिक्षण हेतु एक नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है जिसकी अपनी वैशेषिक महत्ता है और आशा है कि इसमें कुशल भाषा अध्यापक तैयार हो सकेंगे ।

इन चारों महाविद्यालयों में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित हैं :—

##### 1. क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर (राजस्थान)

Regional College of Education Ajmer (Raj)

(उत्तरी क्षेत्र हेतु) जम्मु-काश्मीर,

पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश ।

##### 2. क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय भुवनेश्वर (उड़ीसा)

Regional College of Education, Bhubaneswar (Orissa)

1. शिक्षा मन्त्रालय, संव्यवस्था योजना (Schemes of Educational Development, P. 4-5

(पूर्वी क्षेत्र हेतु) मिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, आसाम, मणीपुर, त्रिपुरा ।

### 3. क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भूपाल (मध्य प्रदेश)

Regional College of Education Bhopal (M. P.)

पश्चिमी क्षेत्र हेतु ) महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात ।

### 4. क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर, (मैसूर)

Regional College of Education Mysore (Mysore)

(दक्षिणी क्षेत्र हेतु ) आंध्र-प्रदेश, मैसूर, मद्रास, केरल ।

इन सभी क्षेत्रीय महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं—

1. स्नातकों के लिए सिव्य विज्ञान, कृषि, गृह विज्ञान, वाणिज्य, विज्ञान  
एवं उद्योग शिक्षण हेतु एच-वर्षीय पाठ्यक्रम ।

2. सेवा कालीन कार्यक्रम

3. उद्योग के अध्यापकों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम

4. पत्राचार द्वारा बी. एड ।

### 5. स्नातकोत्तर प्रशिक्षण महाविद्यालय

Post Graduate Training College

इस स्तर में एम. एड और पी एच. डी का पाठ्यक्रम सम्मिलित है । एम.

ड. शिक्षण की सुविधा 28 विश्वविद्यालयों में है जिनमें 19 विश्वविद्यालयों में प्रवेश  
ने हेतु स्पूनरतम योग्यता बी. टी. बी. एड. एम. टी और व्यावसायिक अनुभव है ।

कुछ विश्वविद्यालयों में एम. ए / एम. एस. सी. की व्यवस्था है, जैसे  
लकनौ और गोहाटी विश्वविद्यालयों में एम. ए / एम. एस. सी. (शिक्षा) की  
व्यवस्था है जो दो वर्ष का पाठ्यक्रम है । शिक्षा में अनुसन्धाओं को बढ़ावा नितान्त  
अवश्यक है ।

### 6. समाकलन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

(Integrated Training Course)

भारतवर्ष में सर्वप्रथम कुश्नेर विश्वविद्यालय में समाकलन प्रशिक्षण पाठ्य-  
क्रम आरम्भ किया गया । इसमें प्रथम वर्षीय में उत्तीर्ण मैट्रिक छात्रों को प्रवेश दिया  
जाता है जिन्हें 4 वर्ष की अवधि तक सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की  
जाती है । और उत्तीर्ण छात्रों को बी. ए., बी. एड. अथवा बी. एस. सी., बी. एड की  
सहाय्य प्रदान की जाती है । विश्व के प्रगतिशील देश जैसे अमेरिका, रूस आदि में  
भी प्रकार अध्यापक शिक्षा प्रदान की जाती है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस  
क्रम को उत्तीर्ण करने के पश्चात् जो अध्यापक निकलेंगे वे अन्य अध्यापकों से

हमारे देश में इसी पाठ्यक्रम को धारों क्षेत्रीय महाविद्यालयों ने भी स्वीकार किया है। अन्तर केवल इतना है कि यहाँ प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता हायर सेकेन्डरी है और अवधि 4 वर्ष है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी को पहले तीन वर्षों में 75 रु० मासिक छात्रवृत्ति मिलती है और चौथे और अन्तिम वर्ष में 100 रु० मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

## 7. विशेष प्रशिक्षण केन्द्र

कुछ केन्द्र द्वारा अध्यापकों की विशेष प्रशिक्षण भी दिये जाते हैं जो निम्नलिखित हैं—

(अ) शारीरिक शिक्षा (Physical Education)—शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण में दो स्तर होते हैं—स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर। दोनों प्रशिक्षणों की अवधि एक वर्ष होती है। सन् 1963 में हमारे देश में इसके लिए 18 महाविद्यालय थे और 46 विद्यालय थे।

(ब) सौन्दर्य शास्त्र सम्बन्धी शिक्षा (Aesthetic Education)—प्रमुख केन्द्र निम्नलिखित हैं—

- |  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| 1. के. जे. स्कूल आफ आर्ट्स, बम्बई        | — | कला               |
| 2. स्कूल आफ आर्ट्स, बड़ौदा               | — | संगीत, कला        |
| 3. कला होल, अम्बार, मद्रास               | — | नृत्य             |
| 4. विश्वभारती, शान्ति निवेशन             | — | संगीत, नृत्य, कला |
| 5. टीचर्स कालेज आफ म्यूजिक, मद्रास       | — | संगीत             |
| 6. इंस्टीट्यूट आफ आर्ट्स एजुकेशन, दिल्ली | — | कला, हस्तशिल्प    |

(आमिया मिलिया इस्लामिया)

(स) भाषा अध्यापकों के प्रशिक्षण महाविद्यालय (Training Colleges for Language Teachers)—भाषा शिक्षण हेतु भी कुछ महाविद्यालय की व्यवस्था है जिनमें दो महाविद्यालय—प्रथम हिन्दी अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालय, आगरा दूसरा इन्स्टीट्यूट आफ इंग्लिश, हैदराबाद—यह केवल अंग्रेजी के अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। राजस्थान में भी इसी प्रकार का एक इन्स्टीट्यूट है जो अजमेर में है।

(घ) गृह विज्ञान (Home Science)—इसके प्रमुख केन्द्र निम्नलिखित हैं—

1. सेरी इरविन कॉलेज, दिल्ली
2. गवर्नमेंट कॉलेज आफ होम साइन्स फॉर वीमेन, इलाहाबाद
3. होमेटिक् साइन्स ट्रेनिंग कालेज, हैदराबाद



नगरीय नगरपालिका सेवा (Town-Service) अध्यापकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए है। अगले आयामन विभाग में एक सेवादात्री शिक्षा (In-Service Education) पर चर्चा करेंगे।

### 13.04 सेवादात्री अध्यापक शिक्षा (Inservice Teacher Education)

शिक्षा भी देश की भावी प्रगति उसके अध्यापकों पर अवलम्बित करती है। अध्यापकों की प्रगति प्राप्त प्रशिक्षण पर करती है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जो जीवन भर चालू है। जब प्राथमिक व्यावसायिक शिक्षा को बेवकूफ माना जा रहा है, वहीं अध्यापकों को परिवर्तित गुणवत्ता के स्वयं, शिक्षा के क्षेत्र में निम्नतर होने वाले परिवर्तनों और अन्य प्रगतिशील देशों के अनुभवों से अवगत होना है जो यह निष्कर्ष आया है कि हम सरकार अध्यापकों को सममानुसार शिक्षा प्रदान करते रहें। कुछ अध्यापकों और शिक्षा क्षेत्र में लगे लोगों का विचार है कि केवल मात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त है, जबकि वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। एच. टी. गी. और बी. एच. अथवा एम. एच. से तो हम केवल मात्र शिक्षा प्रदान करते रहें हैं, यहाँ से तो जीवन का प्रारम्भ होना है जबकि सामान्य अध्यापक इसे अपने जीवन की परिपूर्णता समझना है। अध्यापकों में व्यावसायिक दक्षता प्रदान करने के लिए यह निम्नलिखित अनिवार्य है कि प्राथमिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें सेवा-काल में साप्ताहिक अभिधारणाओं, नये ज्ञान और देश विदेशों की शैक्षिक प्रगति से अवगत कराया जाये। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सेवादात्री अध्यापक शिक्षा के लिए बहुत कुछ करना है—हमारे देश में इन और बहुत कम प्रयास हुए हैं और आवश्यकता है कि सभी स्तरों पर सेवादात्री अध्यापकों की और शैक्षिक विद्या का जितने से अधिक कार्यक्रमों और व्यवसाय के प्रति अधिक निष्ठावान हो सकें।

### (घ) सेवादात्री अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य (Aims & Objectives of Inservice Teacher Education)

#### 1. व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि (Increase in Professional Efficiency)

अध्यापक के लिए यह अनिवार्य है कि वह जीवन भर नवीन ज्ञान की खोज में लगा रहे। शिक्षा एक प्रक्रिया है जो वर्तमान से मनुष्य पर्यन्त चलती रहती प्रारम्भिक व्यावसायिक प्रशिक्षण तो ज्ञान का प्रारम्भ मात्र है जो भावी अध्यापक ज्ञान, कौशल और अभिवृत्तियों को एक नवीन मार्ग की ओर अप्रसर करता प्रशिक्षण महाविद्यालयों में ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् वास्तविक अनुभव तो जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से प्राप्त होते हैं। अतः व्यावसायिक दक्षता वृद्धि हेतु यह अत्यन्त अनिवार्य है कि सेवादात्री शिक्षा की व्यवस्था पाये।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) के मतानुसार शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के कार्यक्रम कितने भी सुन्दर क्यों न हों, उनसे अच्छे अध्यापक नहीं बनाये जा सकते। उनसे केवल ज्ञान, कौशल और अभिवृत्तियों की वृद्धि होती है जिससे आत्मविश्वास और कुछ ध्यावसायिक अनुभव प्राप्त होता है। कार्यक्षमता में वृद्धि सभी सम्भव है जब वास्तविक अनुभवों के आधार पर नवीन ज्ञान प्राप्त किया जा सके।

## 2. शैक्षिक लाभों की प्राप्ति

(Attainment of Educational Benefits)

अध्यापक का समस्त जीवन उसके शिक्षण पर आधारित होता है। सकल शिक्षण सभी सम्भव है जबकि उसे अपने विषय का विषय ज्ञान हो विषय का ज्ञान व्यक्तिगत अध्ययन, अनुभव और स्वयं की दूसरे से तुलना करने पर एवं विद्वानों के सहसर्ग से सम्भव है। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा से अध्यापक को अपने विषय का नवीन ज्ञान, दूसरे के अनुभवों के लाभ, आत्मसोचन, विचारों का आदान-प्रदान और शैक्षिक समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है।

## 3. नवीन ज्ञान की सम्भावनाएँ

(Possibilities of New Knowledge)

हमारे देश का सामान्य अध्यापक चाहे वह शाळा अथवा किसी भी प्रकार के महाविद्यालय का हो दिन प्रतिदिन आलसी होता जा रहा है और नवीन ज्ञान के प्रति तो बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। प्रशिक्षण महाविद्यालयों में तो यह बहुत बड़ी समस्या है कि 75% छात्राध्यापकों की आय 35 वर्ष से अधिक होती है और जब वे प्रशिक्षणार्थ आते हैं तो उनके ज्ञान का स्तर देखकर दुःख होता है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यापक भी नवीन ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते और निधन वक्त में केवल एक बार व्याख्यान तैयार करते हैं और जीवन भर उसी को पढ़ाते रहते हैं। जिस देश के प्रशिक्षण महाविद्यालयों की दशा इतनी खोबनीय है उस देश के अध्यापकों को क्या दशा होगी यह स्वयं सिद्ध है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यदि यह कहा जाये कि आज के अध्यापक को कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है वह अपनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने तक सीमित है। यदि इस प्रकार के अध्यापक से यह आशा की जाये कि वह स्वयं नवीन ज्ञान प्राप्त कर छात्रों के समुच्च परीक्षेया तो घेरे पिछार से यह मान्यता स्वयं ही होगी। अतः यह अत्यन्त अनिवार्य है कि अध्यापकों को सेवाकाल में अभिनवन, अल्पकालीन सघन पाठ्यक्रम द्वारा कार्यक्षाला का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जाये। यदि स्वतन्त्रता के 32 वर्षों के परवान भी आज हमारे देश के अध्यापकों को नहीं मिलेगा तो यह देश का बड़ा हास है।

पकों की यह शोचनीय दशा है तो इसके लिए जागरूक होना नितान्त आवश्यक है कि वह अपने ज्ञान का अभिनवन करे, अपनी अभिवृत्तियों को वांछित स्वरूप प्रदान करे, शिक्षा की समस्याओं के प्रति जागरूक हो और सेवाकालीन शैक्षिक कार्यक्रमों द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करे।

अन्त में हम कोठारी आयोग (1964-66) के कथन से पूर्णरूपेण सहमत कि प्रत्येक व्यवसाय में प्रारम्भिक प्रशिक्षण के पश्चात् विशेष अध्ययन और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। शिक्षण व्यवसाय में भी इसी नितान्त आवश्यकता है क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र में निरन्तर परिवर्तन हो रहे हैं।

सेवाकालीन शिक्षा के कुछ मनोवैज्ञानिक लाभ भी हैं। जब अध्यापक किसी सेमिनार अथवा गोष्ठी में सम्मिलित होते हैं तो उनमें सुरक्षा की भावना, पारस्परिक सम्बन्धों की अभिवृद्धि, सामूहिकता, और व्यावसायिक दक्षता की भावनाओं का विकास होता है।

(घ) शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए सेवाकालीन शिक्षा  
(In Service Education for Various Educational Levels)

सेवाकालीन शिक्षा की समस्त शैक्षिक स्तरों के लिए आवश्यकता है, अतः यह अनिवार्य है कि सभी स्तरों पर अध्यापकों का अभिनवन हो, जिसकी रूपरेखा निम्नलिखित है—

1. प्राथमिक शाला के अध्यापक और सेवाकालीन शिक्षा  
(Primary School Teachers and Inservice Education)

हमारे देश में प्राथमिक शाला के अध्यापकों के लिए सेवाकालीन शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। अनेकों इस प्रकार के राज्य हैं जिनमें प्राथमिक शाला के अध्यापकों को निरक्षर रूप से देता है। प्रथम तो अप्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या बहुत अधिक है, दूसरे सेवाकालीन शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का यह प्रयत्न बर्नाम्स है कि प्राथमिक शाला के अध्यापकों के लिए यथासम्भव वीनमकालीन संस्थानों, अल्पकालीन तयन वाटय और मोटिवों का आयोजन करे जिनसे प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे भावनात्मक परिवर्तनों से अध्यापकों को परिचित किया जा सके। स्टेट इन्स्टीट्यूट

1. In all professions there is a need to provide further training and special Courses of study, on a continuing basis, after initial professional preparation. The need is most urgent in the teaching profession because of the rapid advance in all fields of knowledge and the consequent evolution of pedagogical theory and practice.  
Report of Education Commission 1964-65 p. 81

आफ एजूकेशन, उदयपुर (राजस्थान) इस दृष्टि से पूर्ण सक्रिय है और यथासम्भव सेवाकालीन शिक्षा का आयोजन किया जा रहा है।

## 2. माध्यमिक छात्रा के अध्यापकों की सेवाकालीन शिक्षा (In-service Education of Secondary School Teachers)

माध्यमिक छात्रा के अध्यापकों का विशेष उत्तरदायित्व है क्योंकि उन्हें किशोरावस्था के विद्यार्थियों को शिक्षित करना होता है। इसके लिए निरन्तर आवश्यक है कि माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की सेवाकालीन शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकीय समस्याओं का प्रवर्धन किया जाये। अधिक उचित हो यदि विषयानुसार सेवाकालीन शिक्षा का प्रावधान किया जा सके। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक अध्यापक अपनी पाँच वर्ष की सेवा अवधि में कम से कम दो या तीन मास की सेवाकालीन शिक्षा अवश्य प्राप्त करे। यद्यपि नेशनल कौंसिल आफ एजूकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग के प्रयास से सेवाकालीन शिक्षा हेतु कुछ विषयों पर प्रौद्योगिकीय समस्याओं का आयोजन किया जाने लगा है, तथापि अध्यापकों की संख्या को देखते हुए अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

कोटारी आयोग के अनुसार गैमीनार अथवा प्रौद्योगिकीय समस्याओं का तब तक कोई लाभ नहीं है जब तक इन कार्यक्रमों में अनुसरण कार्यक्रम (Follow up programme) का क्रमिक रूप में न आया जाये। पिछले तीन वर्षों में जितने प्रौद्योगिकीय समस्याओं का आयोजन हुआ, उसका प्रभाव निश्चित रूप से अधिक होता यदि शिक्षा विभागों और माध्यमिक शिक्षा बोर्डों में उचित समन्वय होता। यही कारण है कि अभी तक पाठ्यक्रमों, वास्तव परीक्षा प्रणाली और अन्य छात्रा समस्याओं का उचित समाधान नहीं हो सका है।

## 3. उच्च शिक्षा स्तर के अध्यापकों की सेवाकालीन शिक्षा

### In service Education for the teacher's of higher Education

विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थाओं तथा समस्त उच्च शिक्षा के अध्यापकों के लिए सेवाकालीन शिक्षा का सहयोगिक रूप में एक विशाल कार्यक्रम बनाया जाना निरन्तर आवश्यक है। कोटारी आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा के अध्यापकों से किसी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है और भारतवर्ष में कॉलेज प्राध्यापकों के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान निरर्थक समझा जाता है अतः उनके लिए यह निरन्तर आवश्यक है कि उनका अभिनवधन किया जाये जिससे उन्हें शिक्षा के उद्देश्यों, विभिन्न शिक्षण विधियों, मनोवैज्ञानिक तथ्यों और अपने विषय का विशद अध्ययन हो सके। इसके लिए विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से कुछ निश्चित कार्यक्रमों का बनाया जाना निरन्तर आवश्यक है।

महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हमने विज्ञान के माध्यम से यह जाना है कि हमारे शरीर में जो अणु हैं, वे वास्तव में हमारे अस्तित्व के लिए ज़रूरी हैं। इसलिए, हमें इन अणुओं को सुरक्षित रखना चाहिए।

भाग III इस योजना का लोचन (1964-68) के वर्ष में पूर्ण होने का  
निर्देश व्यवस्था में आर्थिक विभाग के अध्यक्ष द्वारा सरकार को  
की आवश्यकता होती है। विभाग व्यवस्था में भी हमारे विभाग  
व्यक्तिगत ज्ञान के क्षेत्र में विस्तृत परिचय हो रहे हैं।

मेवावालीन निशा के कुछ मोड़ोंपरिचालन भी है, वह अत्यन्त ही तीव्रतर अथवा मोड़ी में सम्मिलित होते हैं जो उनके मुखों की चाल, चालों सम्बन्धों की अभिवृद्धि, सामुद्रिकता, और अत्यन्तविशेष दशाओं की अवस्थाओं विचार होता है।

(घ) शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए सेवाशालीन शिक्षा

(In Service Education for Various Educational Levels)

ऐसा करीब १००० वर्षों के लिए प्रचलित रहा है, यह अनिवार्य है कि सभी लोगों पर अत्याचारों का अहित बन हो, जिससे वह निम्नलिखित है—

f  
i  
e

## प्रशिक्षण कार्यक्रमों और स्कूल कार्य में सम्बन्ध विहीनता

### Absence of Relationship between the Training Programme and School Work

अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहली समस्या यह बताई जाती है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों और स्कूल के कार्यों में कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रायः यह कहते सुना गया है कि प्रशिक्षण काल में छात्रों को जिस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता उसका प्रयोग वास्तव परिस्थितियों में सम्भव नहीं है। जो विद्यार्थीगण प्रशिक्षण समाप्त करके जाते हैं उन्हें भी यही कहते देखा गया है कि, प्रशिक्षण काल में प्राप्त ज्ञान स्कूल की दशाओं में व्यावहारिक नहीं है। इसका प्रत्यक्ष अर्थ यह हुआ कि सिद्धान्त और व्यवहार में अन्तर है। श्री सैयदैन के अनुसार प्रशिक्षण महाविद्यालय शिक्षा का सबसे बड़ा दोष सिद्धान्त और व्यवहार की सम्बन्ध विहीनता है, जब तक इस दोष को दूर नहीं किया जायगा। जब तक इसका फल प्रदानवाचक रहेगा।<sup>1</sup> अध्यापक शिक्षा की मद्देता पर अपने विचार स्पष्ट करते हुए श्री सैयदैन ने आगे कहा है कि अन्य महान कलाओं के समान ही शिक्षण कला के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यह निरन्तर प्रक्रिया होती है जो अध्यापक के पहले दिन से अन्तिम दिन भग नहीं होनी चाहिए। भावी अध्यापकों को तैयार करने में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों को बेबल प्राविधिक साधन ही नहीं बुझाने हैं बल्कि उन्हें एक उचित दृष्टिकोण भी प्रदान करना पड़ता है।<sup>2</sup>

उपरोक्त बचन के सहर्ष में यह तो स्वयं सिद्ध है कि अध्यापक को व्या

1. The divorce of theory from practice is one of the most serious defects of training College education and, unless it is removed its effectiveness will continue to be very questionable indeed.

K. G. Saigidam, *Problems of Educational Reconstruction*

p. 32

2. Like the other great Arts through which mankind has been built up, but of this first Col

it before the prospective teacher enters any professional institution, the training colleges have then to provide not only technical equipment but a proper orientation and outlook, when the teacher emerges from the

*Ibid*, p. 329

अनुसंधान प्रयोगशाला में करने का प्रयत्न करो कि शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थी का व्यवहार क्या होता है जिससे अनुसंधान की ओर बढ़ेगा या शिक्षण से विचार विकसित होता है। यदि नहीं तो अनुसंधान की ओर बढ़ेगा या शिक्षण से विचार विकसित होता है।

(ग) मेधावर्गीय शिक्षा की विधियाँ

Methods of Inheretence Education

अनेक ही मेधावर्गीय शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग

किए जाते हैं —

1. आनुवंशिक विविधता का संरक्षण
2. व्यावहारिक प्रयोग
3. शिथिलता
4. अभिव्यक्ति का संरक्षण
5. विज्ञानों द्वारा व्याख्या
6. पारंपरिक विचार-प्रवाह
7. अनुसंधान विधि
8. हृदय-धर्म्य विचारों का अभिव्यक्ति प्रवाह

ज्ञान में मेधावर्गीय शिक्षा की महत्ता का स्वीकार करने हुए यही कहना उचित होता कि व्यावहारिक प्रयोग के परमाणु यह निश्चय आवश्यक है कि सभी स्तरों के अध्यापकों को अधिक से अधिक सीखें सभी के परमाणु मेधावर्गीय शिक्षा के रूप में सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुभव प्रदान दिये जायें।

13.05 अध्यापक शिक्षा की समस्याएँ और समाधान  
Problems & Solutions of Teacher Education

अध्यापक शिक्षा सम्पूर्ण देश की शिक्षा की आधारशिला है। यही वह शिक्षा है जिसके द्वारा अध्यापकों के व्यक्तित्व को निर्दिष्ट शिक्षा में ढाला जाता है। अध्यापक शिक्षा द्वारा अध्यापकों में यही एक ओर व्यावहारिक समझ का विकास होता है यही दूसरी ओर वैज्ञानिक ज्ञान की सम्पादनार्थ भी इसी के द्वारा सम्भव है। यह निश्चय आवश्यक है कि इस प्रकार की महत्वपूर्ण शिक्षा की समस्याओं का समाधान यथाशीघ्र ढूँढा जाये जिससे वर्तमान पर्याप्त, कर्मठ और योग्य अध्यापकों निर्माण किया जा सके।

अध्यापक शिक्षा की महत्वपूर्ण समस्याएँ निम्नलिखित हैं—

## प्रशिक्षण कार्यक्रमों और स्कूल कार्य में सम्बन्ध विहीनता

### Absence of Relationship between the Training Programmes and School Work

अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहली समस्या यह बतई जाती है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों और स्कूल के कार्यों में कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रायः यह कहते भी सुना गया है कि प्रशिक्षण काल में छात्रों को जिस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है उसका प्रयोग शाळा परिस्थितियों में सम्भव नहीं है। जो विद्यार्थीगण प्रशिक्षण समाप्त करके जाते हैं उन्हें भी यही कहते देखा गया है कि, प्रशिक्षण काल में प्राप्त ज्ञान स्कूल की दशाओं में व्यावहारिक नहीं है। इसका प्रत्यक्ष अर्थ यह हुआ कि सिद्धान्त और व्यवहार में अन्तर है। श्री सैयदेन के अनुसार प्रशिक्षण महाविद्यालयी शिक्षा का सबसे बड़ा दोष सिद्धान्त और व्यवहार की सम्बन्ध विहीनता है, जब तक इस दोष को दूर नहीं किया जायगा। तब तक इसका फल प्रत्यक्ष ही रहेगा।<sup>1</sup> अध्यापक शिक्षा की महत्ता पर अपने विचार स्पष्ट करते हुए श्री सैयदेन ने आगे कहा है कि अन्य महान् कलाओं के समान ही शिक्षण कला के लिए जीवन भर साधना की आवश्यकता होती है। यह निरन्तर प्रक्रिया होती है जो अध्यापक के पहले दिन से अन्तिम दिन अग नहीं होती चाहिए। भावी अध्यापकों को तैयार करने में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को केवल प्राविधिक साधन ही नहीं छुटाने हैं बल्कि उन्हें एक उचित दृष्टिकोण भी प्रदान करना पड़ता है।<sup>2</sup>

उपरोक्त कथन के मर्म में यह तो स्वयं सिद्ध है कि अध्यापक की व्याव-

- 1 The divorce of theory from practice is one of the most serious defects of training College education and, unless it is removed its effectiveness will continue to be very questionable indeed.

K. G. Saiyidain, *Problems of Educational Reconstruction*, p. 323

2. Like the other great Arts through which mankind has been  
of  
this  
fire

Colleges and the Universities have a part to play in it before the prospective teacher enters any professional institution, the training colleges have then to provide not only technical equipment but a proper orientation and outlook, when the teacher emerges from there  
*Ibid.*, p. 329



सांख्यिक प्रशिक्षण की निरन्तर आवश्यकता है और इसी प्रशिक्षण के द्वारा एक वांछित दृष्टिकोण विकसित होता है। इस पर प्रशिक्षण महाविद्यालयों पर यह आरोप लगाया कि उनके कार्यक्रमों का चाला कार्यों में कोई सम्बन्ध नहीं है, सांख्यिक रूप प्रयुक्त या प्रतीत होता है। प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा जो भी सैद्धांतिक और व्यावहारिक शिक्षा प्रदान की जाती है, वह आदर्श है और उन मादरों के अनुस्यू चाला कार्यों का होना निरन्तर आवश्यक है।

विद्युत् सर्वे क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर में 'अध्यापक शिक्षा की समस्याओं' पर नवम्बर 8, 1968 में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसमें 10 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो सभी प्राचार्य अथवा प्राध्यापक थे। अध्यापक शिक्षा की अन्य समस्याओं के साथ इस समस्या पर भी विचार किया गया कि प्रशिक्षण महाविद्यालय के कार्यक्रमों का चाला जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है। जो शिक्षण-विधियाँ और प्रयोगात्मक अभ्यास प्रशिक्षण महाविद्यालयों में दिया जाता है उनका चालाओं में प्रयोग नहीं होता। परन्तु विचार विमर्श के पश्चात् यही विचार धारा सामने आई कि प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधियाँ और चालाओं में प्रयुक्त शिक्षण विधियाँ कोई दो चीज़ें नहीं हैं। प्रशिक्षण महाविद्यालयों और चालाओं के कार्यों में जो अन्तर दिखाई पड़ता है उसका कारण चाला के वातावरण की सीमाएँ हैं। प्रशिक्षण महाविद्यालयों की विधियों और अभ्यासों के साथ कोई बुराई नहीं है।<sup>1</sup>

कुछ लोगों का यह भी मत है कि प्रशिक्षण विधियों से चालाओं का पाठ्यक्रम समाप्त नहीं किया जा सकता है। हमारा इस धारणा के प्रति निश्चित विरोध है क्योंकि यदि शिक्षण विधियों को ठीक प्रकार समझा जाये और उचित ढंग से प्रयोग किया जाये तो निश्चित समय में पाठ्यक्रम समाप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि चाला का अध्यापक शिक्षण विधियों के प्रति पूर्ण दायें जानक हो और अपने व्यवसाय के प्रति बकादार हो तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि अध्यापक के मार्ग में कोई बाधा जाये। अतः इस समस्या का एक ही समाधान है कि प्रशिक्षण महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में और सकारात्मक और उचित अभिवृत्ति विकसित की जाये जिससे वे प्रशिक्षण काल में प्रयुक्त विधियों को ठीक प्रकार समझ सकें।

इसी समस्या के सदर्भ में एक वाया यह बताई जाती है कि महाविद्यालयों में बहुत लम्बी योजनाएँ बनाई जाती हैं जो चाला के अध्यापक द्वारा सम्भव नहीं

1. Report of the conference of Teacher Educators held at Regional college of Education, Ajmer, November 8 to 10, 1968, Problems of Teacher Education Extension Services Dept. P 14

हैं। परन्तु वाषा के उत्तर में हमारा यही नम्र निवेदन है कि प्रारम्भ में लम्बी पाठ योजनाएँ बनाना सिद्धान्तों को समझने के लिए नितान्त आवश्यक है, परन्तु जब पाठ योजना के आधार भूत सिद्धान्तों का ज्ञान हो जाये तो छोटी पाठ योजनाएँ ही पर्याप्त हैं। यदि इसी तथ्य को और स्पष्ट किया जाये तो यह बहा जा सकता है कि पाठ योजना का उद्देश्य शिक्षण को वैज्ञानिक और विधिवत बनाना है। पाठ योजना लम्बी हो, छोटी हो अथवा न हो यह कोई विवादास्पद प्रश्न नहीं है।

अन्त में इस सम्पूर्ण समस्या का समाधान इस प्रकार किया जा सकता है कि व्यवहार और सिद्धान्त को विकसित सत्ताओं के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, सिद्धान्त व्यवहार का पथ-प्रदर्शन करे और व्यवहार सिद्धान्त को निरन्तर सुधारे।<sup>1</sup>

### अध्यापकों का सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक स्तर Social, Economic and Professional Status of Teachers

कोठारी आयोग ने अत्यन्त ही बलपूर्वक यह मुद्दा रखा है कि शिक्षा के स्तर को ऊँचा घटाने के लिए और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए शिक्षकों के सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक स्तर को सुधारना नितान्त आवश्यक है। यदि हमें अपने देश की शिक्षा को कारगर बनाना है तो प्रतिभाशाली नवयुवकों को आमन्त्रित करना होगा और यह तभी सम्भव है जबकि उनकी स्थिति को सुधारा जाये।

जब हम अपने देश की स्थिति की देवत हैं तो हमें यही आग्रह होता है कि इस देश का अध्यापक सबसे अधिक गरीब प्राणी है और यही कारण है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति इस व्यवसाय की ओर आकर्षित नहीं होते। प्रो० सैयद के शब्दों में 'शिक्षण अभी भी आकर्षकहीन व्यवसाय' और इसलिए अधिकतर व्यक्ति इसे अन्तिम आश्रय के रूप में स्वीकार करते हैं।<sup>1</sup> यही कारण है कि अध्यापक की सामाजिक स्थिति इतनी शोचनीय हो गई है कि आज उसे आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता। संक्षेप में अध्यापकों के स्तर की स्थिति निम्नलिखित है—

\*सामाजिक स्तर (Social Status).—आज समाज में अध्यापक की कोई स्थिति नहीं है यहाँ तक कि आज शिक्षित लड़कियाँ एक अध्यापक से शादी तक करने में आनाकानी करती हैं। इसका एकमात्र कारण है अध्यापक की हीन सामाजिक दशा। आज का युग आर्थिक युग है और आर्थिक युग में पूँजीपतियों का साम्राज्य होता है। अध्यापक तो जन्म से ही गरीब है अतः उसके सम्मानित होने का तो प्रश्न ही नहीं

1. Practice and theory must both be visualized as growing entities : theory illuminating practice, practice constantly modifying theory.  
K G. Selyidan, *op. Cit.*, p 314

सापेक्ष प्रशिक्षण की नितान्त आवश्यकता है और इसी प्रशिक्षण के द्वारा एक सौदृष्ट दृष्टिकोण विकसित होता है। इस पर प्रशिक्षण महाविद्यालयों पर यह आरोप लगाना कि उनके कार्यक्रमों का घाला कार्यों में कोई सम्बन्ध नहीं है, आश्रित रूप अनुचित सा प्रतीत होता है। प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा जो भी वैज्ञानिक और व्यावहारिक शिक्षा प्रदान की जाती है, वह आदर्श है और उस आदर्श के अनुरूप घाला कार्यों का होना नितान्त आवश्यक है।

पिछले वर्ष क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर में 'अध्यापक शिक्षा की समस्याओं' पर नवम्बर 8, 1968 से एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसमें 19 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो सभी प्राचार्य अथवा प्राध्यापक थे। अध्यापक शिक्षा की अन्य समस्याओं के साथ इस समस्या पर भी विचार किया गया कि प्रशिक्षण महाविद्यालय के कार्यक्रमों का घाला जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है। जो शिक्षण-विधियाँ और अभ्यात्मक अभ्यास प्रशिक्षण महाविद्यालयों में दिया जाता है उनका घालाओं में प्रयोग नहीं होता। परन्तु विचार विमर्श के पश्चात् वही विचार धारा साधने आई कि प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधियाँ और घालाओं में प्रयुक्त शिक्षण विधियाँ कोई दो चीजें नहीं हैं। प्रशिक्षण महाविद्यालयों और घालाओं के बाव्यों में जो अन्तर दिखाई पड़ता है उसका कारण



उठता । आज का समाज अध्यापक से जेना तो बहुत कुछ चाहता है परन्तु उसे देने के लिए समाज दिवालिया हो चुका है । इस पर भी समाज की उँगलियाँ आज के अध्यापक पर उठी हुई हैं, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह आदर्श हो, चरित्रवान हो समाज का पथप्रदर्शक हो और न जाने क्या आशयों हैं इस समाज की । यदि समाज से अध्यापक के लिए कुछ माँगा जाये तो उसके पास सहानुभूति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ।

**\*आर्थिक स्तर (Economic Status)** — हमारे देश में अध्यापक का आर्थिक स्तर निम्न है । प्राथमिक शाला का अध्यापक तो उन गरीब प्राणियों में से है जिसे सौ ६० मासिक भी नहीं मिलते । राजकीय प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों को तो फिर भी कुछ पैसा मिल जाता है परन्तु प्राइवेट प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों से लिखाया कुछ और जाता है और दिया कुछ जाता है । माध्यमिक शालाओं के अध्यापकों का भी यही हाल है । देश के अनेको राज्यों में प्राइवेट शालाओं की अधिकता है जिसके कारण उनका शोषण स्वाभाविक है, उनके लिए न तो प्राइवेट फण्ड की व्यवस्था है और न ही चिकित्सा भत्ता मिलता है । कॉलेजों के अध्यापकों की दशा भी बहुत कुछ वैसी ही है । देश में राजकीय महाविद्यालयों की संख्या तो बहुत कम है, अधिकतर महाविद्यालय प्राइवेट संस्थानों द्वारा ही चलाये जाते हैं और उनका स्वरूप विद्या-मन्दिरों के स्थान पर दुकानों का हो जाता है जिनका उद्देश्य मुनाफे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । विश्वविद्यालयों द्वारा भी इस प्रकार के महाविद्यालयों को प्रोत्साहन मिलता है जिसके कारण अध्यापकों के समक्ष चुपचाप पेट पासने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं रहता ।

**\*व्यावसायिक स्तर (Professional Status)** — आज का अध्यापक जब कुछ वर्षों के सेवाकाल में इस वास्तविकता से परिचित हो जाता है कि अध्यापन व्यावसाय में किसी भी प्रकार की भावी प्रगति की सम्भावना नहीं है तो वह भी इस व्यावसाय के प्रति उदासीन हो जाता है । जो अध्यापक जीवन भर मानसिक कार्य करता है, एक सप्ताह में सामान्यतया चालीस ग़ांतास कार्य करता है, देश के भावी नागरिकों को अपने व्यावसायिक धर्म द्वारा आदर्श स्वरूप प्रदान करता है—जब यही अध्यापक अपनी तुलना समाज में छोटे-छोटे व्यावसायिक और कम शिक्षित लोगों से करता है तो उसे प्रमाणा होना स्वाभाविक है । व्यावसायिक दृष्टि से

भारत में अध्यापक का व्यवसाय सामान्यतया उसी स्थान पर है जैसा कि अन्य प्रगतिशील देशों में। परन्तु भारतीय अध्यापक को भारतीय संस्कृति और परम्पराओं के संदर्भ में अपने व्यावसायिक उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। परन्तु परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि अध्यापकों के स्तर को ऊँचा उठाया जाये।

अध्यापकों के स्तर को विकसित करने की आवश्यकता

*Need for Improving the Status of Teachers*

जैसा कि हम पिछले पृष्ठों में स्पष्ट कर चुके हैं कि समस्त मान्यताओं को स्वीकार करते हुए भी अध्यापकों के स्तर को ऊँचा उठाने की बहुत आवश्यकता है। सन् 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया था कि 'शैक्षिक पुनर्निर्माण अध्यापक, उसके व्यक्तिक गुणों, शैक्षिक योजनाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शाला तथा समाज में उसके उसके स्थान पर निर्भर करता है'। परन्तु हम इस तथ्य से बहुत दुःखित हैं कि अध्यापक का सामाजिक स्तर, उसके वेतन त्रम, और सामान्य सेवा दसाएँ अत्यन्त ही असन्तोषप्रद हैं। 'हम इस तथ्य से भी सहमत हैं कि यदि अध्यापक की शोचनीय दशा और भ्रष्टाचार को दूर किया जाये तो शिक्षा राष्ट्रीय निर्माण की महत्वपूर्ण त्रिया हो सकती है, परन्तु इसके लिए अध्यापक के स्तर को उन्नत करना होगा और उसकी सेवा दशाओं में सुधार लाना होगा।'।

भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66) ने अध्यापक की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर निम्नलिखित सुझाव दिये हैं:—

भारतीय शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग) की सिफारिशें

*Recommendations of India Education Commission (Kothari)*

वेतन-क्रम

*Pay Scales*

1. सरकार द्वारा विद्यालय-शिक्षकों का भूतनक्रम वेतन निर्धारित किया जाये।
2. केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों को निर्धारित वेतन-क्रम अथवा उससे अधिक देने में सहायता करनी चाहिए।
3. सरकारी एवं गैर सरकारी शालाओं के अध्यापकों को समान वेतन मिलना चाहिए। अधिक उत्तम हो यदि वेतन त्रम में शीघ्र समानता लाई जाये। परन्तु यदि कारणवश यह सम्भव न हो तो पाँच वर्ष में लागू कर दिया जाये।

# ग्रन्थ-सूची

## Bibliography

1. All India Association of Training Colleges,  
*A Symposium on Teacher Education in India*, Indian Publications, 1961
2. ....  
*Report of the Study Group on the Education of Secondary Teachers in India*, 1964
3. Dsouza & Chatterji,  
*Training for Teaching in India & England*.
4. Hodenfield, G H & Stinett, T. M.  
*Education of Teacher, Conflicts and Consensus*, Prentice Hall, England Cliffs, 1961
5. Jaffrey, M V. C.  
*Revolution in Teacher Training*, Pitman and Sons, London, 1961
6. Kabir, H.  
*Trends in Soviet Education*, Ministry of Education, New Delhi.
7. Ministry of Education,  
*Report of the Study Group of the Training of Elementary Teachers in India*, 1963
8. ....  
*Teachers in India Today*, 1957
9. Menon, T K N and Kaul, G N.  
*Experiments in Teacher Training*, Ministry of Education, New Delhi
10. Mukerji, S N  
*Education in India, Today & Tomorrow*, Acharya Book Depot, Baroda
11. *Report of Secondary Education Commission, 1952-53*
12. *Report of Indian Education Commission, 1966*
13. *Report of University Commission, 1948*
14. Safaya R. N.,  
*Current Problems in Indian Education*, Dhanpat Rai & sons, Delhi, 1964
15. Salykhaln, K. G  
*Problems of Educational Reconstruction*, Asia Publishing House, Bombay, 1962
16. Sharma, K. L.  
*Better Teacher Education*

# विश्वविद्यालय प्रश्न

## University Questions

1. 'A real education is not so much a matter of lessons to be learnt and memorised as of a life to be lived and purposeful activities to be shared.'

*University Education Commission*

What do you know about the changing Concept of teacher education in the light of above statement

2. Improvement in school work mainly depends upon the improvement of the teaching personnel' Discuss and suggest way and means for bringing about the much needed improvement among the teaching personnel in schools

What are the major ills from which teacher education in your state is suffering? How can these be rectified

(P. U , 1968)

3. What do you know about initial and in service teacher education?

What type of inservice training should be given to the teachers for the professional growth?

4. What are the professional preparation of teachers for various levels?

5. 'Their Knowledge of theory and their school room practices remain confined in two water-tight compartments instead of mutually enriching and interpreting each other.'

K. G Sayidain.

Discuss the above statement in the training programme and school work.

6. What do you know about the Social, Economic and Professional status of teachers. What measures do you suggest for improving the status of teachers.



## अध्याय चौदह

### Chapter Fourteenth

#### प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा

#### Technical and Vocational Education

#### अध्ययन बिन्दु

#### Learning Points

- 14.01 प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के सिद्धान्त और उद्देश्य  
Principles and Aims of Technical and Vocational Education

1. मानवीय धर्म की महत्ता
2. दारिद्र्य एवं मानसिक दोषयुक्त व्यक्तियों की सहायता करना
3. समाज के परिवर्तित स्वरूप में तकनीकी ज्ञान आवश्यक

- 14.02 स्वतन्त्र भारत में प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा  
Technical & Vocational Education in Free India

विभिन्न आयोग और प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948

माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953

भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66

प्राविधिक शिक्षा का प्रसार

- 14.03 व्यावसायिक संस्थाएँ और उनकी प्राविधिक शिक्षा देने में महत्ता  
Vocational Bases Institution & Their Importance for Technical Education

(अ) व्यावसायिक और प्राविधिक संस्थाएँ और उनके वास्तविक

1. व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ
2. शिक्षा का प्रसार करने वाली संस्थाएँ
3. शिक्षा प्रसार करने वाली संस्थाएँ

4. स्नातकोत्तर और अनुसंधान सुविधाएँ प्रदान करने वाली संस्थाएँ
5. भारतीय सिल्प विज्ञान संस्थान और उनके पाठ्य विषय
6. विज्ञान मन्दिर

(d) प्राविधिक संस्थाओं का प्रशासन

\* 14.04 प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा की समस्याएँ

Problems of Technical & Vocational Education

1. मानवशक्ति का उपयोग
2. प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा में मिश्र व्यवस्थाओं की कमी
3. व्यावहारिक प्रशिक्षण में उद्योगों के सहयोग की कमी
4. अध्यापकों की समस्याएँ
5. पाठ्य पुस्तकों का अभाव
6. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की कमी
7. राज्यों में पारस्परिक सहयोग की कमी
8. अनुसंधान की कमी
9. सैद्धान्तिक और व्यावहारिक शिक्षा में असन्तुलन

\* 14.05 विदेशों में प्राविधिक शिक्षा

Technical Education in Foreign Countries

जर्मनी में प्राविधिक शिक्षा

प्राविधिक शिक्षा व्यवस्था

व्यावसायिक निर्देशन की सुविधाएँ

रूस में प्राविधिक शिक्षा

प्राथमिक व्यावसायिक प्रशिक्षण

माध्यमिक व्यावसायिक प्रशिक्षण

## प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा

### TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION

किसी भी राष्ट्र की समृद्धि मानवीय तथा भौतिक स्रोतों की उपयोगिता निर्भर करती है। उपयोगीकरण हेतु मानवीय स्रोतों का प्रयोग विज्ञान की शिक्षा तकनीकी कौशल के प्रशिक्षण की माँग करता है। उपयोग द्वारा व्यक्ति की क्षमता पूरी होती है। भारतवर्ष की मानवशक्ति आधुनिक विश्व में सभी योगदान करती है जबकि उसकी प्रशिक्षण कर दिया जाये।<sup>1</sup>

#### 14.01 प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के सिद्धांत और उद्देश्य Principles & Aims of Technical and Vocational Education

प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के निम्नलिखित सिद्धांत और उद्देश्य हैं

##### 1. मानवीय श्रम की महत्ता

Dignity of Manual Labour

तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा, सभी स्तरों पर मानवीय श्रम को महत्ता

1. The wealth and prosperity of a nation depends on its effective utilization of its human and material resources through industrialization. The use of human material for industrialization demands its education in science and training in technical skills. Industry opens up possibilities of great resources of manpower can only become an asset in the modern world, when trained and educated.

Report of Indian Education Commission, 1976, p. 202.

करती है तथा वर्तमान उद्योगीकरण प्रक्रिया में मानवीय श्रम के स्थान को स्थिर करती है।

## 2. शारीरिक एवं मानसिक दोषयुक्त व्यक्तियों की सहायता करना

### To Help Physically and Mentally Handicapped Persons

प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य उन व्यक्तियों की सहायता करना भी है जो मन्द बुद्धि है अथवा शारीरिक दोषों से युक्त है। दोषयुक्त मानव शक्ति की सहायता करना सम्पूर्ण मानव समाज की सेवा है। शारीरिक अथवा किन्हीं दोषों से युक्त व्यक्तियों को साधारण कार्यों का प्रशिक्षण देकर समाज में व्यवस्थित किया जा सकता है।

## 3. समाज के परिवर्तित स्वरूप में तकनीकी ज्ञान आवश्यक

### Necessity of Technical Knowledge for Changing Nature of Society

समाज के परिवर्तित स्वरूप के कारण तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है। इसके लिए केवल मान सामान्य ज्ञान ही आवश्यक नहीं है बल्कि विशेष वैज्ञानिक ज्ञान का विकास होना आवश्यक है। समाज के परिवर्तित स्वरूप के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाएँ अधिक से अधिक प्रदान की जायें जिससे अधिकतम तकनीकी विशेषज्ञ, अधियन्ता तथा हस्तकौशल प्राप्त विशेषज्ञों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि नवीन शिक्षण विधियों पर अनुमन्याने किये जायें और भारत में अधिक से अधिक सम्बन्धित शिक्षण संस्थाएँ खोली जायें।

## 14.02 स्वतन्त्र भारत में प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा

### Technical & Vocational Education in Free India

स्वतन्त्रता के पश्चात् देश में औद्योगिक विकास के लिए जम्बूक प्रयत्न हुए जो देश की प्रगति के लिए स्वाभाविक थे। स्वतन्त्रता से पूर्व देश में प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा की बहुत कम सुविधाएँ थी। सन् 1947 में सम्पूर्ण देश में केवल 33 डिग्री संस्थान थे जिनमें कुल 2,940 छात्रों के प्रवेश की व्यवस्था थी। देश में कुल 111 पॉलिटेक्निक संस्थाएँ थी जिनमें केवल 3,670 विद्यार्थियों की क्षमता थी। परन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात् देश के औद्योगिकरण हेतु यह अनुभव किया गया कि व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाना, निरन्तर आवश्यक है। अतः सन् 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने सर्वप्रथम प्राविधिक शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार करने हुए 'व्यावसायिक शिक्षा' के विषय में निम्नलिखित कि व्यावसायिक

शिक्षा यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पुरुष एवं स्त्रियों व्यावसायिक भावना के साथ परिचय एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रारित होते हैं।<sup>1</sup>

विभिन्न आयोग और प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा

*Different Commissions and Technical & Vocational Education*

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ( राधाकृष्णनन समीक्षण ) ने प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये—

1. कृषि-विद्यालयों को अधिक सहायता दी जाये।
2. कृषि पाठ्यक्रम में सामान्य शिक्षा, आधारभूति विज्ञान, कृषि और पशु-पालन को समाविष्ट किया जाये।
3. 'इण्डियन काउंसिल आफ एग्रोकल्चरल रिसर्च' के साधनों में वृद्धि की जाये और अन्य कृषि अनुसन्धान केन्द्रों के लिए सहयोग का कार्य करे।
4. वाणिज्य शिक्षा में प्रयोगात्मक कार्यों को स्थान देते हुए छात्रों को विभिन्न फर्मों में व्यावहारिक कार्य का प्रशिक्षण दिया जाये।
5. इन्जीनियरिंग और टेक्नासाफी की संस्थाओं को राष्ट्रीय सम्पत्ति मानकर उनकी उपयोगिता को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाये।
6. व्यावहारिक शिक्षण हेतु छात्रों को सम्बन्ध अवकाश में कार्य करने दिया जाये एवं स्नातक होने के पश्चात् एक वर्ष शिक्षा के तौर पर कार्य करें।
7. फौर्मन, डाफ्ट्समैन और ओवरनिशर्स की शिक्षण संस्थाओं को बढ़ाया जाये।
8. प्राविधिक क्षेत्र में अनुसन्धान की सुविधाएं बढ़ाई जायें।

भाष्यनिक शिक्षा आयोग ( मुद्रालियर समीक्षण ) ने तकनीकी शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये—

1. प्राविधिक शाखाओं की स्थापना बड़ी संख्या में की जाये।
2. बड़े नगरों में केन्द्रीय प्राविधिक संस्थाओं ( Central Technical Institutes ) की स्थापना की जाये जो स्थानीय शाखाओं की मार्गों को पूरा कर सकें।

1. Professional education is the process by which men and women prepare for exacting responsible service in the professional spirit.

3. प्राविधिक शालाओं की स्थापना यथाम्भव उद्योगों के पास की जाये।
4. उद्योगों पर 'उद्योग-शिक्षा-कर' लगाया जाये। प्राप्त धन को प्राविधिक शिक्षा के विस्तार में लगाया जाये।

भारतीय शिक्षा आयोग ( चौथारी कमिशन ) 1964-66 ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रगति पर अत्यधिक जोर दिया है और भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा निम्नलिखित शब्दों में प्रकाश डाला—

एक राष्ट्र की समृद्धि और प्रगति उद्योगीकरण द्वारा मानवीय एवं भौतिक साधनों के प्रभावशाली उपयोग पर निर्भर है। उद्योगीकरण हेतु मानवीय सत्त्वों का प्रयोग विज्ञान की ज्ञाना और दित्प कीशल प्रशिक्षण की माँग करता है। भारतीय विद्यालयनम मानवशक्ति आधुनिक विश्व के लिए अभी सामर्थ्यक हो सकती है जबकि उसे प्रशिक्षित और शिक्षित किया जाये।<sup>1</sup>

उपरोक्त वचन के सन्दर्भ में आयोग ने व्यावसायिक, प्राविधिक और इञ्जीनियरिंग शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये हैं—

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में सुविधाओं का अधिक विस्तार किया जाय।
2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं तथा टेक्निकल शाखाओं में उत्पादन कार्यों पर अधिक बल दिया जाये।
3. व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षणार्थ अग्रकालीन शिक्षा एवं पत्र व्यवहार द्वारा शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान की जायें।
4. 1986 तक इञ्जीनियरों और टेक्निशियनों का अनुपात 1 : 4 कर दिया जाये।
5. औद्योगिक क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक विद्यालयों की स्थापना की जाये।
6. राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पॉलिटेक्निक संस्थाओं के पाठ्यक्रम को चौथी और पाँचवी पञ्चवर्षीय योजनाओं में पुनर्गठित किया जाये।

---

1. The wealth and prosperity of a nation depends on the effective utilization of its human and material resources though industrialization. The use of human material for industrialization demands its education in science and training in technical skills. Industry opens up possibilities of greater fulment for the individual. India's enormous resources of manpower can only become an asset in the modern world, when trained and educated.

*Science Policy Resolution Government of India, March 4, 1959.*

इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों जैसे विद्युत, अणुसम्बन्धी (Electronics) और उपकरण सम्बन्धी (Instrumentation) शिक्षा हेतु प्रतिभाशाली बी० एस० सी० उत्तीर्ण छात्रों को चुना जाये।

वर्कशॉप प्रैक्टिस (Workshop Practice) में उत्पादन कार्य पर बल दिया जाय।

रसायनिक प्रौद्योगिकी (Chemical Technology) विमान-चिदा (Aeronautics), नक्षत्र विज्ञान (Astronautics) आदि पाठ्यक्रमों को विकसित किया जाये।

अधिक शिक्षा का प्रसार

Expansion of Technical Education

कि हम पहले कह चुके हैं कि 1947 में केवल 6,600 विद्यार्थियों के लिए और तकनीकी शिक्षा देने के साधन थे परन्तु 1963 में 4,35,796 लिए इस शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई। 1966 में इंजीनियरिंग में डिग्री हेतु 25,000 तथा डिप्लोमा हेतु 49,000 विद्यार्थियों को भर्ती कराया गया।

1966-67 में 137 सम्वाह्य डिग्री स्तर पर इंजीनियरी और तत्सम व्यवस्था बना रहा था और 284 सम्वाह्य डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में। इन दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं में प्रविष्ट छात्रों की वास्तविक संख्या 24,031 और 40,461 थी। इन व्यवस्थाओं से स्नातक स्तर पर छात्रों की कुल संख्या 13,081 और डिप्लोमा प्राप्त छात्रों की संख्या 13,081 थी।

गरीबी की भीषण स्थिति के कारण अभी प्रसार हेतु बाई विचार नहीं है। वर्तमान स्थिति में उपाधि (डिग्री) और डिप्लोमा स्तर की शिक्षा को सुविधाओं के लिए तब तक योजना नहीं बनाई जायगी जब तक कि प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं की निश्चित शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में निश्चित शिक्षा और तकनीकी कर्मियों के लिए उचित माहौल न बने। जनन उद्योग में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण 1967-68 और डिप्लोमा स्तर पर जनन पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या कम हो गई।

इस निष्कर्ष शिक्षा की व्यवस्था का मूल उद्देश्य है की शिक्षा और उद्योग में सम्बन्ध बनाना और उद्योगों की सुविधाओं का प्रसार करना। यह उद्योगों में रोजगार के अवसरों को बढ़ा देगा। शिक्षा में 1967 में इस

# तालिका नं० 14.1

## भारतीय शिल्प विज्ञान संस्थान

स्थानों के नाम	पूर्वस्नातक स्तर 1967 में प्रविष्ट छात्र	छात्रों की कुल संख्या	संस्थान से निकले छात्रों की संख्या		
			प्रथम उपाधि	स्नातकोत्तर	डाक्टर उपाधि
बम्बई	371	2,145	304	161	5
दिल्ली	270	1,607	199 + 8 (द्विप्राप्ता)	19	4
कानपुर	320	1,802	70	28	11
छद्दपुर	451	2,628	387	208	29
मद्रास	354	1,718	259	50	12

इंजीनियरिंग कालिजों और पालिटेक्निक संस्थाओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है जिनमें अधिक विद्यार्थियों को प्राविधिक शिक्षा की सुविधाएँ प्राप्त हुई हैं। सन् 1950-51 में किसी पाठ्यक्रम हेतु केवल 49 महाविद्यालयों में और 1965-66 में यह संख्या बढ़कर 117 हो गई। पालिटेक्निक संस्थानों की संख्या 1950-51 में 88 थी जो 1965-66 में बढ़कर 263 हो गई। छात्रों की संख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। तालिका नं० 14.2 में इस स्थिति को स्पष्ट किया गया है।

# तालिका नं० 14.2

## इंजीनियरिंग कालिजों और पालिटेक्निक संस्थाओं की संख्या

1950-51 से 1965-66

वर्ष	दिल्ली पाठ्यक्रम			द्विप्राप्ता पाठ्यक्रम		
	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश क्षमता	निवासी	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश क्षमता	निवासी
1950-51	40	4,120	2,200	88	5,960	2,480
1955-56	68	5,890	4,020	114	10,480	4,500
1960-61	100	13,880	5,700	196	25,570	8,000
1965-66	117	19,140	12,000	263	37,390	19,000



### 14.3 व्यावसायिक संस्थाएँ और उनकी प्राविधिक शिक्षा हेतु महत्ता Vocational Biased Institutions & Their Importance For Technical Education

#### (घ) व्यावसायिक और प्राविधिक संस्थाएँ और उनके पाठ्यक्रम Vocational & Technical Institutions And Their Courses

इस समय हमारे देश में सामान्यता चार प्रकार की संस्थाएँ हैं जो इस प्रकार हैं—

##### 1. व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ Vocational & Industrial Training Institutions

यह प्रशिक्षण कुशल और अर्द्धकुशल कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। इनके लिए दो प्रकार की संस्थाएँ हैं प्रथम कला एवं उद्योग शाखाएँ, द्वितीय प्राविधिक एवं औद्योगिक शाखाएँ। कला एवं उद्योग शाखाओं में किसी उद्योग अथवा लघु-उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरे प्रकार की शाखाओं में विभिन्न कौशल और हस्त कार्यों को विकसित किया जाता है। इन संस्थाओं का उद्देश्य नवयुवकों को कुशल कार्यकर्ता बनाना है।

##### 2. डिप्लोमा प्रदान करने वाली संस्थाएँ Institutions Giving Diplomas

डिप्लोमा प्रदान करने वाली संस्थाओं को पॉलिटेक्निक कहा जाता है। इन संस्थाओं में अध्ययन समाप्त करने के पश्चात् नवयुवकों को कोर्सिंग, मोटरवाहन आदि मोटरियाँ प्राप्त होती हैं। प्रशिक्षण वाला तीन वर्ष का होता है और प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल है। इनमें विविध, मेकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रदान की जाती है। कुछ पॉलिटेक्निकों में टेक्नाईन टेक्नालॉजी, चर्म टेक्नालॉजी, लवन इंजीनियरिंग की भी शिक्षा दी जाती है। विद्यार्थियों से कुछ पॉलिटेक्निक लड़कियों के लिए भी लोहे गव है।

##### 3. डिग्री प्रदान करने वाली संस्थाएँ Institutions Imparting Degree Courses

प्रथम स्नातक पाठ्यक्रम का कार्यक्रम सामान्य रूप से चार वर्षों का होता है। प्रत्येक प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट है। कुछ टेक्नालॉजीकल संस्थाओं में स्नातक पाठ्यक्रम तीन वर्षों का भी है। इन स्नातक पाठ्यक्रम में विविध, मेकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल कोम्युनिकेशन (Communication) इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्नाईन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (Electrical Engineering) इत्यादि

और एरोनाटिकल ( Aeronautical ) इन्जीनियरिंग आदि में प्रथम स्नातक डिग्री अथवा इसके समबल डिग्री प्रदान की जाती है ।

#### 4. स्नातकोत्तर और अनुसन्धान सुविधाएँ प्रदान करने वाली संस्थाएँ

##### Institutions Imparting Post-graduate & Research Facilities

पहले हमारे देश में स्नातकोत्तर सुविधाओं का पूर्णरूपेण अभाव था । आज इण्डिया कौंसिल फॉर टेक्नीकल एज्युकेशन ने इसके लिए एक विशेष समिति का गठन किया जिसका मूल उद्देश्य देश में वांछित सुविधाओं को देखते हुए स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण सुझाव देना था । समिति के सुझावों के अनुसार 36 संस्थाओं को स्नातकोत्तर विषयों में हाई वे इन्जीनियरिंग (High Way Engineering), वायु, निर्माण, फाउन्डेशन इन्जीनियरिंग ( Foundation Engineering ), प्रोडक्शन टेक्नालाजी ( Production Technology ), केमिकल इन्जीनियरिंग (Chemical Engineering), जिओफिजिक्स (Geophysics) आदि का अध्ययन होता है ।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पश्चात् अनुसन्धान कार्य की सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं । अनुसन्धान कार्य पर सामान्यता पी० एच० डी० अथवा डी एस सी. की उपाधि प्रदान की जाती है ।

#### 5. भारतीय इंस्तिट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी और उनके पाठ्य विषय

##### Indian Institutes of Technology & Their Courses

इन संस्थानों का निर्माण देश की आवश्यकताओं के आधार पर किया गया था । सामान्य पाठ्यक्रम के अतिरिक्त निम्नलिखित स्थानों पर विश्व विज्ञान स्थानों में महीन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी आरम्भ कर दिये हैं जो इस प्रकार हैं—

बम्बई—संगणक विज्ञान ( Computer Technology ), वायुयान उत्पादन विज्ञान प्रणोदन (Air Craft Production Technology Propulsion) ।

दिल्ली—कपटी निर्माण कार्य और विज्ञान, वस्त्र इन्जीनियरी (Textile Engineering ), अद्वितीय इन्जीनियरी (Design Engineering), मस्वात्मक विश्लेषण, स्वचालित संगणन (Automatic Computing) आदि ।

कानपुर—वैमानिक इन्जीनियरी ( Aeronautical Engineering ), सिविल और यान्त्रिक इन्जीनियरी आदि ।

कलकत्ता—मास्टर ऑफ टेक्नालाजी इन माइनिंग, मास्टर ऑफ रीजनल प्लानिंग, विद्युत वर्णन और दुग्धशाला इन्जीनियरी आदि ।

मद्रास—द्रव इंजीनियरी, मुद्रा यांत्रिकी और भौव इंजीनियरी (Mechanics and Foundation Engineering), संरचना इंजीनियरी (Structural Engineering), माप शक्ति प्रणाली (Measurement Power System) आदि ।

## 6 विज्ञान मन्दिर

### Vigyan Mandirs

सामुदायिक विज्ञान मन्त्रालय की सहायता से 48 विज्ञान मन्दिरों की स्थापना की गई है । इन मन्दिरों का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रगति से बड़ी लोगों की जानकारी कराना है । प्रत्येक मन्दिर में एक प्रयोगशाला और प्रविष्टि बर्तनकारी होते हैं । विज्ञान मन्त्रालय इन विज्ञान मन्दिरों की संस्था व्यवस्थापन पर विचार कर रहा है । इन मन्दिरों की संचालनप्रणाली उच्चतर माध्यमिक स्तर से सम्बन्धित किया जायेगा ।

### (घ) प्राविधिक संस्थाओं का प्रशासन

#### Administration of Technical Institutions

विज्ञान के राज्यपाल होने के कारण यह सच्यों का उत्तरदायी है कि वे प्राविधिक विज्ञान का प्रशासन कर । परन्तु केन्द्रीय सरकार पर प्राविधिक विज्ञान का उत्तरदायी होने का कारण उम्मीद विषय क्षेत्र बड़ा गया है । अतः केन्द्रीय सरकार प्राविधिक विज्ञान व विकास, संस्थाओं की स्थापना और आर्थिक सहायता के लिए उत्तरदायी है मन्त्र 1957 तक प्राविधिक विज्ञान केन्द्रीय विज्ञान मन्त्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान व आधुनिकता का परन्तु अब यह विज्ञान मन्त्रालय का अधिकार है ।

#### एशियन भाषणीय तकनीकी विज्ञान परिषद

#### All India Council of Technical Education

इसका कार्य केन्द्रीय और राज्य सरकारों का प्राविधिक विज्ञान में सहाय देना है । यह विज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर पर कार्य करेगा, आर्थिक सहायताओं पर विचार और उत्तरदायीता करेगा यह इस परिषद का कार्य है । इस परिषद की स्थापना वर्ष 1953 में हुई । इसने कुछ ही समय में कार्य शुरू किया है । इस परिषद की स्थापना वर्ष 1953 में हुई । इसने कुछ ही समय में कार्य शुरू किया है । इस परिषद की स्थापना वर्ष 1953 में हुई । इसने कुछ ही समय में कार्य शुरू किया है ।

इस परिषद और राज्यपाल विज्ञान मन्त्रालय हेतु तीसरी अगस्त के अनुसार  
 Memorandum of Understanding Commission Regarding the Administration of Technical & Vocational Education

होना चाहिए जिसमें व्यावसायिक संगठनों, संघों और सम्बन्धित मन्त्रालयों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ।

2. यह संगठन योजना आयोग और जनबल अनुसन्धान संस्थान (Institute of Applied Manpower Research) के सहयोग से कार्य करे ।
3. सभी राज्यों में प्राविधिक शिक्षा निदेशालयों (Directorate of Technical Education) की स्थापना की जाये । इन निदेशालयों को शिक्षकों की नियुक्ति एवं संस्थाओं के संचालन तथा नियन्त्रण का पूर्ण अधिकार होना चाहिए ।
4. क्षेत्रीय इंजीनियरिंग विद्यालयों (Regional Engineering Colleges) के बाइस आफ गवरनर्स के अध्यक्ष पद पर शिक्षा शास्त्री की नियुक्ति होनी चाहिए ।
5. संस्थाओं के प्राचार्यों को अपनी संस्थाओं में शैक्षिक सुविधाओं के सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार प्रदान किये जाने चाहिए ।

#### 14.04 प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा की समस्याएँ

##### Problems of Technical & Vocational Education

भारतवर्ष में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं परन्तु इस क्षेत्र में कुछ समस्याओं के कारण हम निम्नलिखित कदमों की प्राप्ति करने में असमर्थ रहे हैं । यद्यपि यह सही है कि भविष्य भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद्, 1945 (All India Council for Technical Education), वैज्ञानिक मानवशक्ति समिति, 1947 (Scientific Manpower Committee), स्नातकोत्तर इंजीनियरिंग शिक्षा और अनुसन्धान समिति, 1961 (Postgraduate Engineering Education and Research Committee) आदि के द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये और प्राविधिक शिक्षा के प्रसार हेतु अथक प्रयत्न भी किये गये तथापि इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना शेष है । प्राविधिक शिक्षा की प्रगति देश की प्रगति है । जब हम अन्य प्रगतिशील देशों की ओर देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हमारी प्रगति उनके सम्मुख कुछ भी नहीं है । इसका स्पष्ट अर्थ है कि हमें अभी बहुत कुछ करना शेष है परन्तु यह सभी सम्भव होगा जबकि हम उन समस्याओं का निराकरण कर सकेंगे जो व्यावसायिक और प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में हैं । समस्याओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

##### 1. मानवशक्ति का उपयोग

##### Utilization of Man Power

हमारे देश में प्राविधिक मानव शक्ति की निरान्त आवश्यकता है । यद्यपि

मशीन—इन मशीनों, कुछ मशीनों और भी  
 Mechanics and Foundation of  
 मशीनरी (Structural Engineering  
 Measurement Power System) में

#### 6 विज्ञान मंदिर Vignyan Mandira

सांख्यिक विज्ञान विभाग की स्थापना के कुछ दिनों  
 तक की गई है। इन मंदिरों का कार्य प्राथमिक रूप से वैज्ञानिक  
 लोगों की जानकारी बढ़ाना है। प्रत्येक मंदिर में एक प्रयोगशाला  
 कार्यकारी होते हैं। विज्ञान विभाग इन विज्ञान मंदिरों की तरफ  
 पर विशेष धन दे रहा है। इन मंदिरों की वित्तीय व्यवस्था  
 से सम्बन्धित विषय आदमी।

#### (ख) प्राविधिक संस्थाओं का प्रशासन

##### Administration of Technical Institutions

विज्ञान के विभागीय होने के कारण यह राज्य का उत्तम  
 विभाग विज्ञान का प्रशासन कर। परन्तु केन्द्रीय सरकार पर प्रा-  
 विधिक होने के कारण उम्मीद विषय क्षेत्र बड़ा गया है। अठ-  
 विधिक विज्ञान के विकास, संस्थाओं की स्थापना और प्रावि-  
 1956 तक प्राविधिक विज्ञान केन्द्रीय विज्ञान  
 न के आर्थिक या परम्परा अब यह विज्ञान विभाग  
 भारतीय तकनीकी





कोठारी आयोग ने इस समस्या के समाधान स्वरूप निम्ना है कि कुछ देशों में जैसे इंग्लैंड में औद्योगिक विकास एक्ट के अनुसार उद्योग (Industry) पर प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करने के लिए दार्ढ्य प्रतिगत कर लगाया जाता है। हमारे देश में इसकी तो आवश्यकता नहीं है परन्तु इसके स्थान पर यह नितांत आवश्यक है उद्योगों द्वारा शिक्षा संस्थाओं को प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान की जाये। उद्योगों और शिक्षा संस्थाओं के प्रतिनिधि समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विचार करें।<sup>1</sup>

#### 4. अध्यापकों की समस्याएँ

##### Problems of Teachers

जैसा कि हम पहले कह आये हैं कि तीन पञ्चवर्षीय योजनाओं में प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा की काफी वृद्धि हुई है, परन्तु इन संस्थाओं में अध्यापकों की अनेकों समस्याएँ हैं। मूल रूप से दो प्रकार की समस्याएँ हैं—

1. अध्यापकों में व्यावहारिक ज्ञान की कमी।

2. अध्यापकों की कमी।

प्रथम समस्या के समाधान स्वरूप कोठारी आयोग ने सुझाव दिये हैं कि अध्यापकों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए मन्वी छुट्टियों का प्रयोग करना चाहिए। पाठ्यक्रम के परिवर्तित स्वरूप और विकासात्मक दृष्टिकोण तथा नवीन ज्ञान के कारण यह नितांत आवश्यक है कि अध्यापकगण सभी नवीन प्रगतियों से अपने आप को परिचित रखें और सम्बन्धित उद्योगों से अपना निकट सम्पर्क बनाये रखें इसके अतिरिक्त औद्योगिक संस्थानों द्वारा अध्यापकों को नवीन ज्ञान से परिचित किया जा सकता है।

अध्यापकों में कमी की समस्या भारतवर्ष में बहुत विवट है। जब तक व्यावसायिक और प्राविधिक संस्थाओं में सभी विषयों से सम्बन्धित अध्यापक नहीं होंगे तब तक सम्बन्धित शिक्षा की प्रगति सम्भव नहीं है। अच्छे अभियन्ताओं और अन्य व्यावसायिक व्यक्तियों का इस ओर आकर्षित न होने का कारण अच्छे वेतन का अभाव है। तालिका सं० 14.3 से यह स्थिति अधिक स्पष्ट होती है कि इन्जीनियरिंग

1. This has been a central theme of our recommendations. In some countries such as the U. K. under its recent Industrial Development Act, a levy of 2½ per cent of the wage bill is imposed on industry. In the U. S. a similar levy is imposed on the cost of production. In the U. S. a similar levy is imposed on the cost of production.



और पालीटेक्निकों में कितने स्थान रिक्त पड़े हुए हैं अतः यह आवश्यकताओं के वेतन में सुधार किया जाये जिससे रिक्त स्थानों की पूर्ति हो। अध्यापक वर्ग औद्योगिक छात्रों में कार्य करने की अपेक्षा-प्राविधिक विद्यालयिक संस्थाओं में कार्य करना पसन्द करें। वेतन में सुधार के साथ ही उन्हें को अन्य सुविधाएँ भी प्रदान की जाये। इस समस्या का एक समाधान हो सकता है कि शिक्षकों को विभिन्न उद्योगों में भी आंशिक रूप से को रोज़गार दी जाये।

तालिका न० 143

प्राविधिक संस्थाओं में अध्यापकों की कमी

Shortage of Teachers in Technical Institutions

नाम	संस्थाओं अध्यापकों के की संख्या स्वीकृत स्थान	31.12.63 तक अध्यापकों की संख्या	31.12.63 पर रिक्त स्थान	रिक्त स्थानों का %	
इंजीनियरिंग कालेज					
1	8	351	266	85	24.2
	2	115	54	61	53.0
	6	602	378	224	37.2
	5	223	135	88	39.4
	6	406	249	157	38.6
	9	549	382	167	30.4
	8	296	210	86	29.6
	7	459	267	192	41.8
	8	516	352	164	46.6
	2	190	90	100	52.6
	5	68	68	—	—
	2	188	59	129	68.6
	8	281	124	157	55.9
कुल	11	552	292	260	47.1
	1	22	10	2	16.7
83	4,808	2,936	1,872	38.9	

Report of the Education Commission, 1966 p 379.

**प्रायोगिक संस्थाएँ**

आंध्र प्रदेश	19	570	472	98	17.2
आसाम	4	110	48	62	56.3
बिहार	22	282	197	115	40.8
गुजरात	11	413	325	88	21.3
जम्मू काश्मीर	1	15	9	6	40.0
केरल	14	428	322	106	24.7
मध्य प्रदेश	13	420	231	189	45.0
महाराष्ट्र	21	568	395	173	30.4
मणिपुर	25	625	446	179	28.6
मैसूर	25	536	428	108	20.1
उड़ीसा	6	144	78	66	45.8
पंजाब	10	155	72	83	53.5
राजस्थान	6	114	95	19	16.7
उत्तर प्रदेश	30	489	289	200	40.9
पश्चिमी बंगाल	21	572	367	205	35.8
<b>केन्द्रापीन क्षेत्र</b>					
मणीपुर	1	13	8	5	38.5
मिजोरम	1	20	8	12	60.0
पाटीबेटा	1	40	30	10	25.0
हिमाचल प्रदेश	1	16	13	2	13.3
<b>भारत</b>	<b>221</b>	<b>5,529</b>	<b>3,803</b>	<b>1,726</b>	<b>31.2</b>

**5. पाठ्य-पुस्तकों का अभाव**

**Lack of Text Books**

वैदिक और व्यावसायिक शिक्षा की अन्य समस्या यह भी है कि सम्बन्धित का अभाव है। इन समस्या के समाधान हेतु यह निम्नलिखित आवश्यक

है कि अच्छी पुस्तकों का अनुवाद हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में किया जाए। शिक्षा मन्त्रालय इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है और अच्छे स्तर की पुस्तकों का अनुवाद भी किया जा रहा है। अमरीका ने पब्लिक ला 480 के अधीन कुछ अच्छी पुस्तकें भारत सरकार को दी हैं और उन्हें कम मूल्यों पर प्रकाशित भी किया गया है।

#### 6. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की कमी *Lack of Vocational Education at Secondary Level*

हमारे देश में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की कमी है। कोठारी आयोग<sup>1</sup> ने सुझाव दिया था कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था हो तथा वाणिज्य, वैज्ञानिक और औद्योगिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था इसी स्तर के साथ हो। लड़कियों के लिए गृह विज्ञान, नर्सिंग और सामाजिक कार्यों की व्यवस्था भी शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ होती चाहिए। माध्यमिक शिक्षा स्तर को व्यावसायिक रूप प्रदान करना अधिक दृष्टि से तथा देश की वर्तमान आवश्यकताओं की दृष्टि से बहुत आवश्यक है।

#### 7. राज्यों में पारस्परिक सहयोग की कमी *Lack of Cooperation in Different States*

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की उपलब्धि के मार्ग में एक सबसे बड़ी बाधा यह है कि राज्यों में पारस्परिक सहयोग की कमी है। इंजीनियरिंग तथा पाथीटेविक संस्थाओं में हड़ताल होने का यही कारण है। यदि राज्यों में पारस्परिक सहयोग हो तो विद्यार्थियों के आन्दोलनों को रोकना जा सकता है। उदाहरणार्थ राजस्थान के इंजीनियरिंग स्नातकों तथा डिप्लोमा प्राप्त छात्रों को उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में नौकरी के लिए भेजा जा सकता है। परन्तु यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम अपने को भारतीय न समझ कर प्रांतीयता की भावना से अधिक प्रभावित हैं और इसी कारण अन्य राज्यों के छात्रों को नौकरी में नहीं लेते जिसके कारण इन संस्थाओं के छात्रों में असन्तोष व्याप्त रहता है। यदि हम तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को अधिक लोकप्रिय बनाना चाहते हैं तो राज्यों में पारस्परिक

— 1. Report of the Commission on Higher Education, 1948.

## 8. अनुसन्धान की कमी

### Lack of Research

देश की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति न होना और छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों का मुँह ठाकना इसी कारण से है कि हमारे देश में अनुसन्धान की कमी है। इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न राज्यों में अनुसन्धान के सुविधाएँ प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा को विशेष रूप प्रदान किया जा सके।

## 9. सैद्धान्तिक और व्यावहारिक शिक्षा में असन्तुलन

### Lack of Coordination Between Theoretical and Practical Education

शिक्षण विधियों की कमी के कारण सैद्धान्तिक और व्यावहारिक शिक्षा असन्तुलन का अभाव है। हमारे देश में सैद्धान्तिक पक्ष पर अधिक बल दिया जा रहा है जिसके कारण प्राविधिक शिक्षा पुस्तकीय ही हो जाती है। जबकि अन्य देशों में शिक्षण व्यवस्था औद्योगिक एवं वैज्ञानिक है वहाँ व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। देश की प्रगति हेतु यह आवश्यक है कि प्राविधिक शिक्षा में निरंतर अनुभव को अधिक महत्ता प्रदान की जाये जिससे सैद्धान्तिक और व्यावहारिक पक्ष में समन्वय और सन्तुलन हो सके।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में प्राविधिक और व्यावहारिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है परन्तु फिर भी अनेकों समस्याएँ विद्यमान हैं। यदि केन्द्रीय और राज्य सरकारें प्रयत्न करें तो समस्याओं का समाधान सम्भव है।

## 14.15 विदेशों में प्राविधिक शिक्षा

### Technical Education in Foreign Countries

किसी भी देश की प्रगति का सही मूल्यांकन तुलनात्मक दृष्टिकोण से ही सकता है। यदि हम प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में अपने देश की तुलना अन्य देशों से करें तो पायेंगे कि हमारे देश में बहुत अधिक विकास नहीं हुआ है, इसका मुख्य कारण यही है कि हमारी प्राविधिक शिक्षा का इतिहास बहुत थोड़े वर्षों का है जबकि इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, रूस आदि देशों में प्राविधिक शिक्षा के प्राचीन पुराने हैं। प्रस्तुत अध्याय में हम जर्मन और रूस की प्राविधिक शिक्षा अध्ययन करेंगे।

## जर्मनी में प्राविधिक शिक्षा

### Technical Education in Germany

प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में जर्मनी बहुत ही विशिष्ट देश है। यद्यपि जर्मनी की विशेषिका ने सम्मोच दिया जा रहा है इस देश ने प्राविधिक

के आधार पर पुनः अपने आपको सभाला और विश्व के सम्मुख एक प्रविष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया।

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् जर्मनी को दो भागों में विभाजित किया। पूर्वी जर्मनी पर साम्यवादियों का प्रभाव है और पश्चिमी जर्मनी पर पूँजीवाद का। एक ही देश के दो भाग हो जाने पर भी इस देश ने अपने साहस को नहीं हटाया और प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति ही की है और इस कारण है कि जो प्राविधिक शिक्षा का स्वरूप इस देश में विद्यमान है, ऐसा कहीं नहीं है। केम्ब्रिज के छात्रों में जर्मनी के अन्तर्गत अनेको स्तर पर व्यावसायिक शिक्षाओं द्वारा विशिष्ट प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। संसार सम्मिलित: जर्मनी के अतिरिक्त कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अनेकों प्रकार व्यावसायिक शिक्षाओं द्वारा इतनी अधिक शिक्षा प्रदान करता हो।<sup>1</sup> जर्मनी में 18 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से टेक्नीकल हायरसूल (Technische Hochschulen) के अतिरिक्त 8 टेक्नीकल महाविद्यालय हैं। प्राविधिक संस्थाओं में प्रदान की प्रवेश दिया जाता है जो भी वर्षीय माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं।

### प्राविधिक शिक्षा व्यवस्था

#### Technical Education Set-up

जर्मनी में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं नि:शुल्क है। अठ्ठारह वर्ष तक। लड़के लड़कियों को अनिवार्य एवं नि:शुल्क प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा दी व्यवस्था है। प्राविधिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालयों की संख्या, अभिवृत्ति और योग्यता का विशेष ध्यान रखा जाता है और इसके आधार पर दस वर्ष की आयु में समस्त विद्यालयों को तीन विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है। सामान्य रूप से 80 प्रतिशत विद्यालयों को 14 वर्ष की आयु में उच्चतर प्राथमिक स्तर के परवाना प्रदत्त है। शेष 20 प्रतिशत विद्यालयों को 14 वर्ष और 10 वर्ष की आयु के परवाना समस्त प्राविधिक शिक्षाओं और विश्वविद्यालयों में प्रवेश कर दिया जाता है।

की जाती है। विद्यार्थियों की रुचियों और योग्यता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और इसे वहाँ की शिक्षा का आवश्यक अंग माना जाता है। व्यावसायिक निर्देशन का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि वहाँ शिक्षा में अपव्यय नहीं होता।

उपरोक्त विवेचन यह स्पष्ट है कि जर्मनी में प्राविधिक शिक्षा की सुविधाएँ प्रायः सभी नवयुवकों और नवयुवतियों को प्राप्त हैं। जो व्यक्ति पूर्णकालीन शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं उन्हें अंशकालीन शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त वहाँ पत्र व्यवहार द्वारा भी शिक्षा प्रदान की जाती है। जर्मनी ही इस प्रकार का देश है जहाँ श्रम की महत्ता को शोकार किया जाता है और यही कारण है कि द्वितीय महायुद्ध में जो देश पूर्णरूपेण स्वस्त हो चुका था तथा वहाँ चारों ओर विनाश का साम्राज्य था आज वही देश आर्थिक रूप से पूर्णरूपेण सुदृढ़ है।

### हम में प्राविधिक शिक्षा

#### Technical Education in U. S. S. R.

सोवियत संघ की शिक्षा व्यवस्था का आधार व्यावसायिक प्रशिक्षण है। यहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण को दो भागों में विभाजित किया जाता है।

1. प्राथमिक व्यावसायिक प्रशिक्षण।
2. माध्यमिक व्यावसायिक प्रशिक्षण।

#### प्राथमिक व्यावसायिक प्रशिक्षण

##### Primary Vocational Training

सोवियत संघ में प्रशिक्षण का यह कार्य सांस्कृतिक मन्त्रालय के लेबर रिजर्म्स विभाग द्वारा संचालित होता है। इस विभाग का कार्य राष्ट्रीय आवश्यकतानुसार निम्न प्रकार के कृशल अधिक बनाना है। इस उद्देश्य हेतु अनेकों बोकेचनल स्कूल हैं जिनमें ट्रेड स्कूल, टेक्निकल और औद्योगिक प्रशिक्षण स्कूल सम्मिलित हैं। ट्रेड स्कूलों के द्वारा विविध व्यावसायों के लिए कृशल अधिक तैयार किये जाते हैं। इन स्कूलों के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त 14 और 16 वर्ष के युवक और युवतियों को प्रवेश देने का अधिकार होता है। इन स्कूलों में प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष है।

औद्योगिक प्रशिक्षण छात्रागणों में सामान्य व्यावसायों के लिए कृशल अधिक तैयार किये जाते हैं। प्रशिक्षण की अवधि व्यावसाय विशेष पर निर्भर करती है। सामान्यतः प्रशिक्षण अवधि पाँच महीने से एक वर्ष तक की होती है।

उपरोक्त समस्त छात्रागणों का संचालन एक संचालक द्वारा होता है। संचालक की सहायता की सहायक होने हैं। एक सहायक प्रशिक्षण और सामान्य शिक्षा का कार्य देता है और दूसरा सहायक विद्यार्थियों की सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन करता है। विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा निःशुल्क है।

## 1. माध्यमिक व्यावसायिक प्रशिक्षण

### Secondary Vocational Training

यह प्रशिक्षण विशिष्ट माध्यमिक शालाओं में दिया जाता है। इन शालाओं में 14 से 30 वर्ष तक के नवयुवकों और नवयुवतियों को प्रवेश दिया जाता है। इन शालाओं में प्रवेश प्राप्त करने के लिए एक परीक्षा ली जाती है। प्रशिक्षण अवधि चार वर्ष होती है। इन प्रशिक्षण संस्थाओं में साहित्य, गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र आदि अनिवार्य विषय हैं और इनके अतिरिक्त किसी विशेष क्षेत्र का व्यावहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। प्रत्येक विद्यार्थी को सरकार द्वारा आश्रित परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् सभी विद्यार्थियों को किसी व्यावसाय में लगा दिया जाता है।

इस की श्रान्ति से पूर्व सन् 1914 में इन संस्थाओं की संख्या 295 थी जिनमें 35,800 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। सन् 1951 में इन संस्थाओं की संख्या 3,543 थी जिनमें 13,84,000 विद्यार्थी थे। सन् 1955-50 में इन संस्थाओं की संख्या 3,612 थी।

### टेक्नीकम्स

#### Technicums

इन संस्थाओं द्वारा मध्यस्तरीय विशेषज्ञों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इन संस्थाओं की आवश्यकतानुसार किसी भी व्यावसाय के लिए आरम्भ किया जा सकता है। इस संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए न्यूनतम योग्यता माध्यमिक स्तर है और अध्ययन काल 4 अथवा 5 वर्ष है। इन संस्थाओं के विद्यार्थियों को सम्बन्धित कारखानों अथवा कार्यस्थलों के सम्पर्क में रखा जाता है। इन संस्थाओं में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। अनायासियों और युद्ध में बर्बाद हुए सैनिकों के बच्चों को विशेष मुविषा प्रदान की जाती है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में कस बहुत आगे है। पिछले कुछ वर्षों में इस में अमेरिका से भी अधिक प्रगति की है। 1957 में एक अमरीकी केन्द्रीय शिक्षा कार्यालय के प्रतिवेदन के अनुसार सोवियत विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष 80 हजार इन्जीनियर तैयार करते हैं जबकि अमेरिका में केवल 30 हजार ही तैयार होते हैं। जग में 70 प्रतिशत विभिन्न विज्ञान और टेक्नालाजी प्रदान की जाती है।

17 शिष्ट है कि हमारे देश में इन्जीनियरों की व्यावसाय नहीं मिलता।

# ग्रन्थ-सूची

## Bibliography

1. D'sunza, A. A.  
*Technical Education in India, & England*, Orient Longmans.
2. Lowman, E.  
*Report on Soviet Education*, U. S. Office of Education, Washington D. C.
3. Ministry of Education,  
*Education in India*, New Delhi.
4. . . . .  
*Report of the Education Commission, 1906.*
5. - - - - -  
*Report of Secondary Education Commission, 1953.*
7. Mukerji S. N.  
*Education in India To-day & Tomorrow*, Acharya Book Depot, Baroda.



## विश्वविद्यालय प्रश्न

### University Questions

1. Analyse the problem of the educated unemployed in India. How can Technical and Vocational education be a solution ?

( राजस्थान )

2. The father of a student of class XI comes for advice as to the vocational prospects before him or her. Discuss the various diversified courses into consideration, and advise the father as to the Careers open to the student.

( राजस्थान )

3. What problems are being faced in the field of technical and vocational education in India ? How can they be tackled ?

भारत में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार की कोशिशें हैं ? इन समस्याओं को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है ?

( राजस्थान )

4. Describe the system of technical and vocational education in Germany or U. S. S. R. To what extent can it be adopted to the needs of our Country ?

जर्मनी अथवा रूस की प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली का वर्णन कीजिये । हमारे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप उनका उपयोगी बताया जा सकता है ?

( राजस्थान )

5. Define Technical Education. Describe briefly the different types of institutions for technical education in India. state To what extent is technical education calculated to solve the problems of unemployment ?

प्राविधिक शिक्षा की परिभाषा कीजिये । अपने राज्य की विभिन्न प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं का वर्णन कीजिये । प्राविधिक शिक्षा द्वारा बेरोजगारी की समस्या का समाधान किस सीमा तक होने का अनुमान है ?

( राजस्थान )

6. Define 'Technical Education' Describe briefly the different types of institutions for Technical Education in U. P. To what extent is Technical Education calculated to solve the problems of unemployment ?

प्राविधिक शिक्षा की परिभाषा लिखिये । उत्तर प्रदेश की विभिन्न प्रकार की प्राविधिक शिक्षा का संक्षेप में वर्णन कीजिये । प्राविधिक शिक्षा बेकारी की समस्या का हल किस सीमा तक करेगी ?

( आगरा, बी० टी० 1965 )

7. What are the main handicaps responsible for the slow pace of progress in sphere of Technical Education in India ? Suggest ways for its rapid expansion in the right direction.

भारत में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में मन्द प्रगति के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन हैं ? उचित दिशा में इसके क्षेत्र विस्तार के लिए सुझाव दीजिये ।

( आगरा, बी० एड० 1968 )

# विश्वविद्यालय प्रश्न

## University Questions

1. Analyse the problem of the educated unemployed in India. How can Technical and Vocational education help in its solution ?

( Hijaasthan, 1961 )

2. The father of a student of class XI comes to you for advice as to the vocational prospects before him or her. Taking the various diversified courses into consideration, enlighten the father as to the Careers open to the student.

( Hijaasthan, 1964 )

3. What problems are being faced in the expansion of technical and vocational education in India ? How can they be tackled ?

भारत में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार की कौन-सी समस्याएँ हैं ? इन समस्याओं को किस प्रकार नियन्त्रित किया जा सकता है ?

( राजस्थान, 1966 )

4. Describe the system of technical and vocational education in Germany or U. S. S. R. To what extent could these be adopted to the needs of our Country ?

जर्मनी अथवा रूस की प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली का वर्णन कीजिये । हमारे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप उनको उपयोगी बताया जा सकता है ?

( राजस्थान, )

5. Define Technical Education. Describe briefly different types of institutions for technical education in state. To what extent is technical education calculated to the problems of unemployment ?

प्राविधिक शिक्षा की परिभाषा कीजिये । अपने राज्य की विभिन्न प्रविधिक शिक्षा संस्थाओं का वर्णन कीजिये । प्राविधिक शिक्षा द्वारा बेरोजगारी को समाप्त करने का समाधान किस सीमा तक होने का अनुमान है ?

( राजस्थान, 1 )

III. नव-साक्षरों के लिए साहित्य का उत्पादन

Production of Literature for Neo-Literates

3. पुनः निरक्षरता की ओर

Relapse into Illiteracy

4. शिक्षण विधियाँ

Methods of Teaching

5. कार्यकर्त्ताओं और उनके प्रशिक्षण का अभाव

Lack of workers and there Training

6. महिलाओं के निरक्षरता की समस्या

Problem of Illiteracy of women

..

---

**अध्याय पन्द्रह**  
**Chapter Fifteenth**

**समाज शिक्षा**  
**Social Education**

**अध्ययन बिन्दु**  
**Learning Points**

**15.01 समाज शिक्षा की परिवर्तित धारणा**

**Changing Concept of Social Education**

- ग्रौढ़ शिक्षा का अर्थ
- ग्रौढ़ शिक्षा की नवीन धारणा
- समाज शिक्षा का अर्थ
- समाज शिक्षा क्यों
- ग्रौढ़ साक्षरता

**15.02 समाज शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य**

**Aims & Objectives of Social Education**

1. व्यावसायिक समता का विकास
2. सामाजिक कौशल का विकास
3. समोरजनार्मक अभिवृत्ति का विकास
4. आत्म विश्वास की सुविधाएं प्रदान करना
- 5 राष्ट्रीय स्रोतों की सुरक्षा और उन्नति करना

**15.03 ग्रौढ़ पाठ्यक्रम के लक्ष्य**

**Objectives of Adults Curriculum**

**15.04 समाज शिक्षा की समस्याएं**

**Problems of Social Education**

1. ग्रौढ़ों की शिक्षा का समन्वय

**Organisation of Education for Adults:**  
**कोटारी आयोग के सुझाव**

2. नव-साक्षरों के लिए साहित्य का उत्पादन

*Production of Literature for Neo-Literates*

3. पुनः निरक्षरता की ओर

*Relapse into Illiteracy*

4. शिक्षण विधियाँ

*Methods of Teaching*

5. कार्यकर्ताओं और उनके प्रशिक्षण का अभाव

*Lack of workers and there Training*

6. महिलाओं के निरक्षरता की समस्या

*Problem of Illiteracy of women*

---

## समाज शिक्षा *SOCIAL EDUCATION*

भारतवर्ष में निरक्षरता की समस्या बहुत गम्भीर है। हमारे देश की सक्षमता में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है और इसके कारण प्रत्येक पग में विकास का मुँह देखना पड़ रहा है। यदि हमें देश में प्रजातन्त्र की जड़ों को मजबूत करना है तो निरक्षरता को समूल नष्ट करना होगा अन्यथा हमारी समस्या का समाधान संभव नहीं हो सकेगा।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् निरक्षरता को समाप्त करने के लिए प्रयास हुए। राज्य सरकारों को समाज शिक्षा के प्रसार हेतु पर्याप्त धन मिल गई। केन्द्रीय सरकार ने जनता कालिजों की स्थापना की। समाज सेवा सेविकाओं द्वारा समाज शिक्षा का प्रसार किया गया। समाज शिक्षा की प्रशिक्षण प्रणालियों में सुधार किये गये। ग्रोइंग को साधर करने के लिए ग्रोइंग सामग्री की व्यवस्था की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाज शिक्षा में रुपये तथा राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास योजनाओं द्वारा समाज के लिए 10 करोड़ रुपये निर्दिष्ट किये। तृतीय योजना में भी वयस्क साक्षरता विकास हेतु अनेकों प्रयास हुए और इसके लिए 12 करोड़ रुपये की धन-राशि आवंटित की गई। तृतीय योजना में सामान्य के कार्यक्रमों के अन्तर्गत

प्रावधान किया है और समाज शिक्षा हेतु 64 करोड़ रुपये की धन राशि निश्चित की गई है।<sup>1</sup>

इतने अधिक प्रयास होते हुए भी भारत 1961 में 1951 की अपेक्षा अधिक निरक्षर या धीरे निरक्षरों की संख्या 360 लाख थी। सन् 1960 में निरक्षरों की संख्या में 200 लाख की और वृद्धि हो गई। प्राथमिक शिक्षा के द्रुत गति से विकास और साक्षरता के लिए अनेकों कार्यक्रमों के परचात भी स्थिति यह है।<sup>2</sup> निरक्षरता की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण जनसंख्या की वृद्धि है।

### 15.01 समाज शिक्षा की परिवर्तित धारणा

#### Changing Concept of Social Education

समाज शिक्षा की धारणा बहुत प्राचीन नहीं है, स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व हमारे उद्देश्य कुछ सीमित थे परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति के कारण उद्देश्यों में व्यापकता आई, अतः धारणाओं में परिवर्तन आना स्वाभाविक था। यहाँ हम धारणाओं के क्रमिक परिवर्तनों को स्पष्ट करेंगे।

#### प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ

#### Meaning of Adult Education

प्रारम्भ में प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ प्रौढ़ म्रिचो व पुरुषों को साक्षर बनाना था। निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षर ज्ञान कराना ही प्रौढ़ शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य समझा जाता था। परन्तु भारत में इस उद्देश्य को और व्यापक कर सकना सम्भव भी नहीं था। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् यह अनुभव लिया गया कि प्रौढ़ों को केवल मात्र साक्षर कर देने से ही प्रजातन्त्र को सफल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा का क्षेत्र अत्यन्त सङ्कुचित और औपचारिक था। अतः प्रौढ़ शिक्षा की धारणा में परिवर्तन आना स्वाभाविक ही था।

#### प्रौढ़ शिक्षा की नवीन धारणा

#### New Concept of Adult Education

जिस समय भारत परतन्त्रता की जंजीरों से जकड़ दृष्टा था उस समय हमारे देश के नेताओं का हृदय अधिशित जनता की देखकर द्रवित हो उठता था, परन्तु

1. चौथी पञ्चवर्षीय योजना (प्रारम्भिक रूपरेखा) पृ. 231

2. India was more illiterate in 1961 than in 1951, with an addition of about 36 million illiterates than in 1951. This has happened despite unprecedented expansion of primary education and despite many literacy drives and programmes

Report of Education Commission, 1966, p. 423





## समाज शिक्षा का अर्थ

### Meaning of Social Education

समाज शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रो० हुमायूँ कबीर ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये हैं, 'समाज शिक्षा की परिभाषा इस उस पाठ्य विषय के रूप में कर सकते हैं जिसका मूल उद्देश्य प्रौढ़ों में नागरिकता एवं सामाजिक एकाता की भावना को प्रवर्धित करना है। इसका विषय क्षेत्र केवल परिपक्व प्रौढ़ों की संसार करना ही नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य जनता में शिक्षित मस्तिष्क का निर्माण करना है। अतः स्वाभाविक रूप से यह शिक्षा व्यक्तियों को व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप में उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है।'

भारत के सूतपूर्व शिक्षा मन्त्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद<sup>2</sup> ने ग्रामीण प्रौढ शिक्षा पर हुए युनेस्को के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, समाज शिक्षा के अर्थ के विषय में कहा था, समाज शिक्षा से हमारा तात्पर्य सम्पूर्ण मानव की शिक्षा से है। यह उसे साक्षर करेगी जिसमें उसे समाज का ज्ञान होगा। इसके

1. Social Education may be defined as a course of study directed towards the production of consciousness of citizenship among the people and the promotion of social solidarity among them. It is not content with the introduction of literacy among the grown-up illiterates but aims at the production of an educated mind among the masses. As a natural corollary, it seeks to inculcate in them a lively sense of rights and duties of citizenship both as individuals and members of the community.

—Humayun Kabir, *Education in New India*, p. 62

2. By Social Education we mean... man in will world may I him how to h make the bet subsists. It is and modes of

... for peace and progress.

Maulana Abul Kalam Azad Inaugural address in UNESCO Seminar on Rural Adult Education held at Mysore in Dec. 1949

हामें उमड़े सामाजिक में समग्र रूप में स्थिति का  
 एक प्रयोग करने की क्षमता का अभिव्यक्ति  
 उमड़े प्रयोग और समाज में लोगों के अलग-  
 गले प्रवृत्ति कर लेंगे ।

इसके अनिवार्य रूप शिक्षा का उद्देश्य  
 सामाजिक विज्ञान के नियमों से परिचित कराना  
 और समुद्रियताही हो लेंगे । आज में हम शिक्षा का  
 प्रदान करना है जिसमें उमड़े शिक्ष की बातों का  
 विचारने द्वारा वह अपनी तरफ़ार को उन नियमों  
 लेंगे जिसमें सामाजिक और प्रवृत्ति का प्रभाव हो ।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान  
 द्वारा व्यक्तियों को साक्षर बनाते हुए सामाजिक विज्ञान  
 क्षमता का विस्तार किया जा लेंगे और आर्थिक रूप  
 नागरिकों के रूप में अपने अधिकारों और कर्तव्यों का  
 मानव समाज की सुगति रक्ष लेंगे ।

सामाजिक शिक्षा के अर्थ को और भी स्पष्ट  
 कि 'सामाजिक शिक्षा' की धारणा 'प्रौढ शिक्षा' की धारणा  
 में 'सामाजिक शिक्षा' प्रौढ-शिक्षा का ही विस्तृत  
 अन्तर्निहित है ।

**सामाजिक शिक्षा क्यों ?**

**Why Social Education ?**

एक शिक्षित व्यक्ति देश के लिए बरदान होता है  
 जो अज्ञानता के अंधकार से प्रभावित है वह समाज के  
 भी प्रभावित तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक  
 और सामाजिक रूप से शिक्षित नहीं होंगे । सामाजिक शिक्षा  
 साधन के सुसज्जित तरीकों से परिचित किया जाता है ।  
 नागरिकों की स्वस्थ जीवन की दशाओं, बाल्य-युवावस्था  
 अशिक्षा और सुखमय जीवन की सम्भावनाओं की ।

निर्णय के व्यक्तित्व को दूसरे के आग्रह पर छोड़ देता है।

16. निराश होकर उसे अपने जीवन की आवश्यक गोपनीयता दूसरों के सामने प्रकट करनी पड़ती है।

\* राजनीतिक अधिकारों को अपनी बुद्धि अनुसार प्रयोग करने में असमर्थ रहता है।

\* एक अशिक्षित नारी एक कच्ची माछा और कुशल गृहणी के रूप में जीवन व्यतीस कर लेती है।

उसके जीवन का मुख और प्रमत्तता तथा जीवन ज्योति सदैव के लिए लोप हो जाती है।

उपरोक्त व्यक्तिगत और सामाजिक विवशताओं के कारण एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन दूमर हो जाता है। अतः आवश्यक है कि समाज शिक्षा के कार्य-क्रमों को द्वास्तमय, तेजी से बढ़ाया जाये जिनसे हमारे देश के हजारों नर-नारियों को शिक्षित किया जा सके।

सामान्यता यह कहा जाता है कि भारतवर्ष संसार का सबसे बड़ा प्रजातन्त्र है। परन्तु प्रजातन्त्र का आकार बड़ा होने से देश सहान नहीं हो सकता यदि हम अपने देश में प्रजातन्त्र की नींव मजबूत करनी है तो व्यक्तियों का सुशिक्षित होना अनिवार्य है। परन्तु हमारे देश में सन् 1951 से 1961 तक साक्षरता की संख्या में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 1961-66 तक केवल 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, परन्तु निरक्षरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होती जा रही है और इसका प्रमुख कारण जनसंख्या की वृद्धि है। यदि देश की यही स्थिति रही तो देश का भविष्य निश्चित रूप से जन्यकार्मय है। यदि देश के भविष्य को उज्ज्वल करना है तो बहुत आवश्यक है कि समाज शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाया जाये। अन्त में हम कह सकते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में हमारे समाज शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। हमारे देश को चाहिए कि वे कम से कम एक व्यक्ति को

देश अज्ञानता के कूप से

from 10.6  
Percent  
ished the

आन्दोलन चलाया जाये। इस कार्य को कोई एक संस्था नहीं कर सकती, अतः आवश्यक है कि सरकार, ऐच्छिक संगठन, श्रमिक संघ और व्यावसायिक संगठन आदि सब मिल कर इस पुनीत कार्य को करें।

रूस वा हमारे सम्मुख जीता जागता उदाहरण है जिसने थोड़े समय में ही III वर्ग से III वर्ग तक की आयु के मध्य समस्त व्यक्तियों को साक्षर कर दिया। प्रौढ़ साक्षरता के क्षेत्र में उसका यह कार्य सराहनीय है। जिस देश में सन् 1897 की जनगणना के अनुसार 76 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर थे और स्त्रियों में निरक्षरता इससे भी कई गुनी अधिक थी, आज दही देश साक्षरता का अविश्व उदाहरण है। इसका एक मात्र कारण यह सकता है वहाँ लेनिन ने एक बार कहा था कि हम साम्यवादी राज्य की स्थापना निरक्षर लोगों से नहीं कर सकते।<sup>1</sup> यही स्थिति भारत की है, यहाँ प्रजातन्त्र तक तक सफल नहीं होगा जब तक यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति साक्षर नहीं होगा। तालिका न० 15.1 से हमें ज्ञात होता है कि भारत में साक्षरता का प्रतिशत अन्य देशों की तुलना में कितना कम है।

तालिका न० 15.1

विश्व साक्षरता

World Literacy

देश	प्रतिशत	देश	प्रतिशत
डेनमार्क	100	इटली	80
स्वीडन	100	स्पेन	70
डिनेमार्क	99	ईथन	70
एंगोला	99	सका	60
कनाडा	98	साजील	58
फ्रान्स	99	वाईलेट	52
रूस	98	मैक्सिको	50
अमेरिका	97	टर्की	50
यूना	96	चीन	45
बेल्जियम	95	भारत	24
यूरोप	95	पाकिस्तान	19
ब्रासिलिया	95	इन्डोनेशिया	15

1. We cannot build a Communist State with an illiterate people. — B. I. Lenin

तालिका न० 15.2 ये सम्पूर्ण देश की स्थिति का ज्ञान होता है कि  
की विभिन्न राज्यों में क्या स्थिति है।

तालिका न० 15.2

विभिन्न राज्यों में साक्षरता का प्रतिशत<sup>1</sup>

Percentage of Literacy in Different States

राज्य	पुरुष	महिलाएँ	कुल प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	30.2	12.0	21.2
आसाम	37.3	16.0	27.4
बिहार	20.8	6.0	16.4
गुजरात	41.1	10.1	30.5
केरल	55.0	38.9	46.8
मद्रास	44.5	18.2	31.4
मध्य प्रदेश	27.0	6.7	17.1
महाराष्ट्र	42.2	16.8	29.3
मेघालय	36.1	14.2	25.4
उड़ीसा	34.7	8.6	21.7
पंजाब	33.0	14.1	24.2
विश्वनाथ	23.7	6.8	15.2
तमिल प्रदेश	27.3	7.0	17.6
देवगढ़ जिला	40.1	17.0	29.3
कोलकाता	50.8	42.5	52.7
राजस्थान प्रदेश	27.2	6.2	17.1
सिक्किम	45.1	15.9	30.4
उत्तर प्रदेश	29.6	10.2	20.2
तेलंगाना	24.0	11.3	17.9
दार्जिलिंग जिला	42.4	19.4	33.6
बम्बई	54.9	48.8	58.47

## 15.02 समाज शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य

### Aims & Objectives of Social Education

समाज शिक्षा का प्रावधान उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिन्होंने कभी किसी पाठशाला में विद्या अध्ययन नहीं किया अथवा जो बहुत ही छोड़े समय के लिए विद्यालय जा पाते हैं। अतः समाज शिक्षा का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को शिक्षित करना है, जिस शिक्षा द्वारा उनको व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव हो सके।

संक्षेप में समाज शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

#### 1. व्यावसायिक क्षमता का विकास

##### Development of Vocational Efficiency

व्यक्तियों में व्यावसायिक क्षमता के विकास करने के लिए नगरों में व्यापारिक एवं औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं उद्योगों की जानकारी देना समाज शिक्षा का मूल उद्देश्य है।

#### 2. सामाजिक कौशल का विकास

##### Development of Social Skill

समाज शिक्षा का उद्देश्य पारस्परिक सम्बन्धों की अभिवृद्धि प्रभावशाली पारिवारिक जीवन की दशाओं से सम्बन्धित जानकारी, अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सजगता आदि का विकास करना जिससे सामाजिक कौशल का विकास हो सके।

#### 3. मनोरंजनार्थक अभिवृत्ति का विकास

##### Development of Recreational Attitude

समाज शिक्षा व्यक्तियों में मनोरंजनार्थक अभिवृत्ति का विकास कर सांस्कृतिक परम्पराओं को सुरक्षित करती है। नृत्य, लोक गीत, लोक नृत्य तथा अन्य साधनों से स्वस्थ परम्परा का निर्माण किया जाता है इस उद्देश्य के पीछे एक ही आधारभूत सिद्धान्त है कि स्वस्थ मनोरंजन द्वारा जीवन में अच्छे संस्कारों का विकास हो सकता है।

#### 4. आराम विकास की सुविधाएँ प्रदान करना

##### To Foster Facilities of Self Development

समाज शिक्षा से व्यक्तियों में ज्ञान विद्या प्राप्त करना, आराम विकास के लिए वांछित अभिवृत्ति विधित करना, जीवन के प्रति कलात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना आदि सम्भव है।

#### 5. राष्ट्रीय स्रोतों की सुरक्षा और उन्नति करना

##### Conservation & Improvement of National Resources

समाज शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय संपदों को पूर्ण सम्भव है। वांछित जीवन मूल्य हेतु यह निदान आवश्यक है कि उत्पादक योग्यताओं और कुशलताओं की

तालिका न० 15.2 से सम्पूर्ण देश की स्थिति का ज्ञान होता है।  
को विभिन्न राज्यों में क्या स्थिति है।

तालिका न० 15.2  
विभिन्न राज्यों में साक्षरता का प्रतिशत<sup>1</sup>  
Percentage of Literacy in Different States

राज्य	पुरुष	महिलाएँ	कुल
आंध्र प्रदेश	30.2	12.0	21.2
आसाम	37.3	16.0	27.4
बिहार	29.8	6.9	18.4
गुजरात	41.1	19.1	30.5
केरल	55.0	38.9	46.8
मद्रास	44.5	18.2	31.4
मध्य प्रदेश	27.0	6.7	17.1
महाराष्ट्र	42.2	16.8	29.8
संभार	36.1	14.2	25.4
उड़ीसा	34.7	8.6	21.7
पंजाब	33.0	14.1	24.2
राजस्थान	23.7	5.8	15.9
उत्तर प्रदेश	27.3	7.0	17.1
पश्चिमी बंगाल	40.1		
दिल्ली	60.8		
हिमाचल प्रदेश	27.2		
ममीपुर	45.1		
त्रिपुरा	29.6		
नागालैंड	24.0		
अरुणचल और निकोबार	42.4		
वृहत् भारद्वाज	64.9		



उपयोग तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार पाठ्यक्रम का निर्माण हो, उस प्रश्न पर भी विचार करना आवश्यक है कि साक्षरता न तो जीवन का अन्त है और न ही प्रारम्भ, यह तो मात्र एक माध्यम है जिसके द्वारा पुरुषों और स्त्रियों को विधित किया जाता है।<sup>1</sup>

अतः सर्वप्रथम पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास हो, तत्पश्चात् सामान्य ज्ञान, सहीन, सामरिक सामग्री, इति, सामिग्य राष्ट्रीयता सहकारी समितियों की स्थापना, प्रारम्भिक विनियम और म्यामाम आदि का ज्ञान प्रदान किया जाये।

### 15.04 समाज शिक्षा की समस्याएँ

#### Problems of Social Education

समाज शिक्षा की समस्याएँ अन्य संघिक समस्याओं से भिन्न हैं। एक बालक को पढ़ाने में और एक प्रौढ़ को पढ़ाने में बहुत अन्तर है क्योंकि दोनों का मनोविज्ञान पूर्णरूपेण भिन्न है। इससे अतिरिक्त प्रौढ़ निरक्षर हो सकते हैं परन्तु अधिज्ञात नहीं हैं। अतः समाज शिक्षा की निम्नलिखित समस्याएँ हैं —

#### 1. प्रौढ़ों की शिक्षा का समन्वय

##### Organisation of Education for Adults

समाज शिक्षा के प्रारम्भ हेतु केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय में एक पुष्क विभाग है। परन्तु राज्यों में समाज शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय का कार्य समाज शिक्षा को प्रगति हेतु वय प्रशिक्षण, विभिन्न संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करना और विभिन्न संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। केन्द्रीय सरकार ने 1953 में एक बोर्ड की स्थापना की जिसे केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड कहते हैं। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय के अतिरिक्त अन्य मन्त्रालय जैसे श्रम एवं सामुदायिक विकास आदि भी समाज शिक्षा के प्रसार हेतु कार्य कर रहे हैं।<sup>2</sup>

राज्यों में समाज शिक्षा हेतु प्रदेश जिके में समाज शिक्षा अधिकारी होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इससे लिए सामुदायिक विकास ब्लॉक (Community & Extension Development Block) द्वारा किया जाता है। प्रदेश ब्लॉक में समाज सेवक और ग्राम सेवक होते हैं। 100 गाँवों के लिए एक विकास-क्षेत्र में समाज शिक्षा के समन्वय हेतु एक आर्गेनाइजर होता है।

1. Literacy is not the end of education, nor even the beginning. It is only one of the means whereby men and women can be educated.

Mahatma Gandhi, *Harjan*, July 31, 1937

## 2. कोटारी आयोग के सुझाव

### Suggestions of Kotari Commission

प्रौढ़ शिक्षा के संयोजन और प्रवर्धन के सम्बन्ध में कोटारी आयोग ने कि एक 'राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद' (National Board of Education) की स्थापना होनी चाहिए। इस समिति में सम्बन्धित सभी प्रतिनिधि होने चाहिए। इस परिषद के निम्नलिखित कार्य होने चाहिए —

1. प्रौढ़-शिक्षा के प्रविधान और योजना के सम्बन्ध में केन्द्र एवं राज्य स्तर पर अनौपचारिक परामर्श देना।

2. विवाह कार्यक्रम, साहित्य निर्माण, शिक्षण सामग्री आदि को बनाना।

3. विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना।

4. उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं भावी विचार योजनाएँ बनाना।

राज्य स्तर पर भी प्रौढ़-शिक्षा परिषदों की स्थापना की जानी चाहिए और जिला स्तर पर इस प्रकार की समितियों को जिला परिषदों का अंग होना चाहिए। प्रौढ़-शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यक्ति एवं संस्थाएँ ऐच्छिक रूप से कार्य कर रहे हैं उन्हें अधिक एवं प्राविधिक सहायता मिलनी चाहिए।

### 3. नव-साक्षरों के लिए साहित्य का उत्पादन

#### Production of Literature for Neo-Literates

समाज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या उपयुक्त साहित्य का अभाव है। ऐसा कि हम पहले कह चुके हैं कि प्रौढ़ों में केवल मात्र लिखने पढ़ने की क्षमता का विकास करना ही पर्याप्त नहीं है, उनमें वांछित व्यवहार परिवर्तन करने की भी आवश्यकता है और यह तभी सम्भव है जबकि नव साक्षरों के लिए उचित साहित्य उत्पादन किया जाये, क्योंकि साक्षरता प्रदान करना जितना आवश्यक है, उससे अधिक आवश्यक साक्षरों को पुनः निराक्षर होने से रोकना है। अतः साक्षरता के माध्यम से शिक्षा का प्रबन्ध करना अति आवश्यक है और यह तभी सम्भव है जबकि नव-साक्षरों के प्रौढ़ों के लिए साहित्य का सृजन हो।

श्री संयोजन के शब्दों में 'समाज शिक्षा' के मार्ग में सबसे बड़ी कठिनाई पुस्तकों का अभाव है जो प्रौढ़ों को आकर्षित कर सकें। अतः अच्छी पुस्तकें, अर्थ, समाचार पत्रों, चित्रित, सामग्रियों आदि का अभाव है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि साहित्य ना

विज्ञान पर आधारित, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाये तो समाज विद्या के नद्वैत्यों की पूर्ति निश्चित है।

केन्द्रीय सरकार नव साधनों के लिए उत्तम साहित्य प्रकाशनार्थ काफी प्रयत्नशील है। इसने सम्बन्धित कुछ कार्यक्रम आरम्भ भी किये गये हैं जैसे भारतीय भाषाओं में उल्लेख्य नव साधनोंयोगी पुस्तकों पर लेखकों की प्रतिबन्ध पुरस्कार दिया जाता है, सरकार द्वारा लेखकों की गोप्यियों का आयोजन किया जाता है जिसमें नव-साधनों के साहित्य सृजन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सरकार स्वयं भी नव-साधन साहित्य के प्रकाशनार्थ कार्य करती है तथा अन्य सरकारी मध्यम और सरकारी संस्थाओं को इसके लिए अनुदान भी प्रदान करती है।

अन्त में नवसाधनों के लिए ऐसे साहित्य की आवश्यकता है जिसके द्वारा उनमें भावमोचन, राजनैतिक शिक्षा, सामाजिक भावना और सम्बन्धित व्यवसाय का वांछित ज्ञान सम्भव हो सके एवं आदर्श नागरिक के रूप में देश के उत्थान हेतु अपना सक्रिय योगदान प्रदान कर सके।

### 3 पुनः निरक्षरता की ओर *Relapse into Illiteracy*

सन् 1966 में भारत की कुल जनसंख्या 49,40,02,646 थी।<sup>1</sup> जैसा कि हम तालिका नं० 15.1 में स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारे में 24% व्यक्ति साक्षर हैं। पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत 34.5 है और स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत 13.0 है।<sup>2</sup> प्रसृत साधिका से पता चलता है कि अभी हमारे देश में 76% व्यक्ति निरक्षर हैं। ऐसी स्थिति में देश के उत्थान की बातें करना केवल मात्र स्वप्न है। अधिस्थित जनता का देश-भूक व्यक्तियों का देश होता है। अधिस्थित जनता पर शासन, भूक और निःसहाय व्यक्तियों पर सासन है। यही मूल कारण है कि आज हमारा देश सामाजिक द्वेष, कलह और साम्प्रदायिक भगदोरों का अखाड़ा बन गया है। अ.ज. देश में राजनैतिक अस्थिरता है और इसकी पृष्ठ-भूमि में अधिक्षा छिपी हुई है।

हमारे देश में 1951 की अपेक्षा 1961 में अधिक निरक्षरता थी और 1969 में उसने भी अधिक निरक्षरता है। यदि यही क्रम रहा तो निरक्षरों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली जायेगी अब आवश्यक है कि देश को इस पतन के मार्ग से बचाया जाये। श्री सेक्टर के धर्मों में 'यदि सत्कार के धानचित्र में साक्षरता की

1. *India 1967*, p. 5

2. *Ibid*, p. 62

शिक्षण का प्रश्न जिस आस और निरधार क्षेत्रों को काने रव में प्रदर्शित किया जाये तो भारत उल मानचित्र में एक काने महादीप जंता दिखाई देता । अतः आवश्यक है कि अपनी भूमि से हम निरधारता को समुन नष्ट कर ।

कोटारी आयोग ने इस कार्य हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये हैं—

1. देश की निरधारता को दूर करने के लिए योजनायुक्त प्रयास होने चाहिए और 20 वर्षों में इसे समाप्त कर देना चाहिए । गाररता सन् 1971 तक 80 प्रतिशत और 1976 तक 80 प्रतिशत हो जानी चाहिए ।

निरधारता को रोकने का सबसे पहला उपाय 6 से 11 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए । 11 से 14 वर्ष के उन बालकों के लिए जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, अशकालीन शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए । 15 से 30 वर्ष के प्रौढ़ों के लिए अशकालीन सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ।

2. निरधारता की समाप्ति के लिए अयनात्मक एवं सार्वभौमिक पद्धति का दुहरा कार्यक्रम होना चाहिए ।

3. अयनात्मक पद्धति में उन प्रौढ़ों को शिक्षित करना चाहिए जो सरलता से साक्षर हो सकें । सरकार यदि आवश्यक समझे तो यह नियम बना सकती है कि उद्योगों के मासिक अपन निरधार कार्यक्रमों की नियुक्ति से तीन वर्षों की समयावधि में अवश्य ही साक्षर बनाएं ।

4. सार्वभौमिक पद्धति में सभी शिक्षितों का उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वे निरधारों को साक्षर बनाएं । इस आन्दोलन हेतु शिक्षकों, छात्रों से विशेष लाभ की आशा होनी चाहिए ।

5. शिक्षकों को साक्षर बनाने के लिए 'केन्द्रीय समाज-विकास परिषद्' को कार्य करना चाहिए ।

6. साक्षरता के बनाये रखने हेतु अनुसरण कार्यक्रमों (Follow up Programmes) की व्यवस्था होनी चाहिए ।

उपरोक्त सुझाव वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और यह आवश्यक है कि इन सुझावों अनुसार यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जाये और सम्पूर्ण देश में साक्षरता आन्दोलन प्रारम्भ किया जाये ।

#### 4. शिक्षण विधियाँ

##### Methods of Teaching

जंसा कि हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रौढ़ों की पढ़ाया कोई सरल का

■ जो कि उनके जीवन का अपना जीवन-दर्शन होता है । उसके जीवन में अस्तित्व

होती है। उनमें 'अहम् की' भावना होती है। यद्यपि हम समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए यह कहना बठिन है कि शीशों को दिन दिन विधाय विधियों से शिक्षा प्रदान की जाय।

इस समस्या के समाधान हेतु यह आवश्यक है कि विभिन्न आयु श्रेणियों के अनुसार विधाय विधियों को निरूपित किया जाय। 11 से 45 आयुस्तर के शीशों को विभिन्न-भिन्न विधाय विधियों की आवश्यकता है। यदि हम आयुस्तर के लिए उपयुक्त विधाय विधियों पर अनुसंधान कार्य हो तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसी में निम्नलिखित विधाय विधियों को प्रयोग में लाया जा सकता है—

1. वयस्क प्रथम विधियाँ
2. अप्यायक प्रथम विधियाँ
3. सहकारी विधियाँ

उपरोक्त विधियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विधाय विधियों को प्रयोग में लाया जा सकता है।

#### 5. कार्यकर्ताओं और उनके प्रशिक्षण का अभाव

##### *Lack of workers and Their Training*

समाज शिक्षा के क्षेत्र में एक अन्य समस्या कार्यकर्ताओं का अभाव है। समाज सेवकों की व्यवस्था तो हो जाती है परन्तु समाज सेविकाओं का अभाव रहता है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की बहुत बड़ी मुश्किल है। यद्यपि सरकार द्वारा समाज शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र (Social Education Training Centres) खोले गये हैं तथापि निम्नलिखित अनवस्था को देखते हुए इन प्रशिक्षण केंद्रों की कमी है। अतः आवश्यक है कि सरकार हम और ध्यान दे और प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयत्न करे।

#### 6. महिलाओं की विद्वत्ता की समस्या

##### *Problem of Illiteracy of Women*

समाज शिक्षा की युव समस्या महिलाओं का निराकरण होता है। आवांशिक जातियों के अनुसार पारिवीक महिलाओं की संख्या 34.5 प्रतिशत की विरुद्ध केवल 8.9 प्रतिशत शिक्षा कातर थी। यह निर्विवाद बात है कि जब तक महिलाओं को कातर नहीं किया जायेगा तब तक समाज-शिक्षा की सफलता असाध्य है।

1. The state of literacy among women is particularly dismaying. The census of 1961 showed that 34.5 percent of the women in urban areas and only 8.9 percent of those in rural areas were literate. It is universally acknowledged that unless women become educated, there is little hope for a real transformation.

*Report of Education 19 61, p. 123.*



## ग्रन्थ-सूची

### Bibliography

1. Apte, D. G.  
*Social Education at a Glance*, Faculty of Psychology, Baroda
  2. D'Souza, A.  
*The Folk High Schools in Denmark*, Orient Longmans, 1958
  3. Porulekar, R. V.  
*Literacy in India*, Macmillan & Co.
  4. ... — — — — —  
*The Place of Literacy in Social Education in India*, Presidential Address, All India Adult Conference, Patna, 1954
  5. *Report of the Central Advisory Board Committee on Adult Education*
  6. *Teachers Hand Book of Social Education*  
Ministry of Education, New Delhi, 1957.
-

## नारी शिक्षा WOMEN EDUCATION

**'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तमश्ते तत्र देवता'**

मनु का यह कथन कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इन पक्तियों में नारी के महान को स्वीकार किया गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत की पावन भूमि पर नारी सर्वत्र श्रद्धेय रही है। इसका प्रमुख कारण यही है कि हमारे देश ने अनेक विदुषी नारियों जैसे विश्वतारा, सोपा, लोपमुद्रा, अनाला, उर्वशी, मैत्रेयी और गार्गी आदि को जन्म दिया है। परन्तु आज नारी का वह महत्व नहीं जो प्राचीन भारत में था, यही कारण है कि आज का भारत वह भारत नहीं जो पहले था। आज सम्भवतः हम इस तथ्य को भूल गये हैं कि जब नारी उठती है तो देश और समाज उठता है, जब नारी गिरती है तो देश और समाज का पतन होता है। अतः आवश्यकता है कि हमारा समाज उठे, देश विकास की ओर उन्मुख हो, और यह सभी सम्भव है जब हमारे देश की स्त्रियाँ शिक्षित हों। अतः नारी शिक्षा की बहुत आवश्यकता है।

### 16 01 नारी शिक्षा की आवश्यकता Need of Women Education

**'The hand that rocks the cradle, rules the world.'**

अर्थात् जो हाथ पालना भुलाता है, वह संसार का शासन करता है। कहने का अर्थ यह है कि एक नारी बालक को जन्म देकर उस बालक में संसार को प्रभावित



करती है। बालक के व्यक्तित्व को यदि कोई सबसे अधिक प्रभावित करता है तो वह उसकी माता का व्यक्तित्व है, अतः जैसी माँ होगी वैसा ही बालक होगा। इसीलिए ५० नेहरू ने कहा था कि लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है, परन्तु एक लड़की की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है।<sup>1</sup> इस कथन में स्पष्टतः नारी शिक्षा की आवश्यकता के दर्शन होते हैं।

भारतीय शिक्षा आयोग ने नारी शिक्षा की आवश्यकता बर बत देने हुए लिखा था कि मानवीय श्रोतो के विकास, परिवारों के सुधार और राष्ट्राकाश में शालकों पर पारस्परिक प्रभाव हेतु, स्त्रियों की शिक्षा या पुरुषों की शिक्षा की अपेक्षा अधिक महत्व है।<sup>2</sup> इसका एकमात्र कारण यह है कि एक शिक्षित नारी पारिवारिक जीवन को अधिक सुखी करने, बालकों का अच्छी प्रचार पालन पोषण करने, उनमें आश्रित अभिवृत्तियों के विकास करने, व्यक्तित्व का विवाह करने आदि में अत्यधिक सहायक होती है। इसलिए देश के उदयान और प्रगति के लिए नारी शिक्षा की बहुत आवश्यकता है।

### 16.20 स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व नारी शिक्षा का प्रसार

#### Expansion of Women Education Before Independence

सुविधा की दृष्टि से नारी शिक्षा के प्रसार को निम्नलिखित कालों में विभाजित करना उत्तम रहेगा —

प्रथम काल 1813 से 1881 तक

द्वितीय काल 1882 से 1921 तक

तृतीय काल 1922 से स्वतन्त्रता प्राप्ति तक

1. प्रथम काल 1813 से 1881 तक

First Period From 1813 to 1881

इस काल में स्त्री शिक्षा केवल कुछ ऊँचे वर्ग के परिवारों तक ही सीमित थी। सर्वप्रथम इस प्रकार की पाठशाला सन् 1820 में डेण्डेडैयर ने स्थापित की थी।

1. Education of a boy is education of one person, but education of girl is the education of the entire family.

—Jawaharlal Nehru

2. The significance of the education of girls cannot be over-emphasized. For full development of our human resources, the improvement of homes and for moulding the character of children during the most impressionable years of infancy, the education of women is of even greater importance than that of men.

Report of the Education Commission, p. 135.



विद्यालय की स्थापना हुई। सन् 1916 में महर्षि कर्वे ने महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। सन् 1921 में सम्पूर्ण देश में स्त्री शिक्षा हेतु 19 महाविद्यालय, 675 माध्यमिक विद्यालय और 21956 प्राथमिक विद्यालये थी।

### 3. तृतीय काल, 1922 से 1947 तक

#### Third Period From 1922 to 1947

इस काल की स्थापना के पश्चात् स्त्री शिक्षा का प्रसार सन्तोषप्रद रहा। इस समय राष्ट्रीय नेता और समाज सुधारक महिला उद्योग पर विशेष बल दे रहे थे। राष्ट्रीय जाति बन्धन चरम सीमा पर थी। सन् 1921 और 1937 के विधान के अनुसार शिक्षा का प्रबन्ध भारतीय मन्त्रियों के पास था। स्वतन्त्रता से पूर्व 89 महाविद्यालय, 2370 माध्यमिक विद्यालये और 21,479 प्राथमिक विद्यालये थी। तालिका नं० 16.1 द्वारा विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं की कुल संख्या और स्त्री शिक्षा का प्रसार स्पष्ट किया गया है।

#### तालिका नं० 16.1

#### विभिन्न स्तरों की छात्राओं की संख्या

स्तर	1881-82	1901-02	1921-22	1946-47
उच्च	6	189	905	20,304
माध्यमिक	2054	9,075	26,163	6,02,280
प्राथमिक	1,24,491	3,44,712	11,86,224	34,75,165
विशिष्ट शिक्षा	815	2,457	10,831	58,993

#### 16.03 स्वतन्त्रता के पश्चात् नारी शिक्षा का प्रसार

#### Expansion of women Education after Independence

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् नारी शिक्षा के क्षेत्र में बलवर्धक प्रगति हुई है। पिछले वर्षों में नारी का सामाजिक स्तर भी ऊँचा उठ्य है और शैक्षिक सुविधाओं में समानता भी आई है। तालिका नं० 16.2 से नारी शिक्षा की प्रगति का तुलनात्मक स्वरूप स्पष्ट होता है जिसमें 1919-50 और 1960-61 की स्थिति स्पष्ट की गई है।

तालिका नं० 16-2

महारी शिक्षा का प्रसार (1949-50 और 1960-61)  
Expansion of Woman Education (1949-50 & 1960-61)

विभिन्न स्तर	1949-50		1960-61	
	लड़कियों की संख्या	प्रति 100 लड़कों पर लड़कियों की संख्या	लड़कियों की संख्या	प्रति 100 लड़कों पर लड़कियों की संख्या
सामान्य शिक्षा				
विश्वविद्यालय				
अनुसन्धान	88	10		
एम.ए. और एम.एससी.	1,056	14	768	20
बी.ए. और बी.एससी.	10,759	14	9,227	25
टी.टी.डी.			63,370	27
(कला, विज्ञान)	23,540	13		
ताम्रिक शिक्षा			76,517	20
(विश्वविद्यालय)	4,055	5		
उच्च शिक्षा (विश्व-विद्यालय)	771	18	26,124	11
महारी शिक्षा (स्कूल स्तर)			7,355	51
उच्च स्तर	7,08,007	19		
	—	—	6,86,395	25
महारी शिक्षा	50,34,740	40	19,41,178	35
(स्कूल)	12,306	91	1,09,44,051	48
			82,122	85
महारी शिक्षा (स्कूल)	35,780	28		
	1,70,641	16	85,549	25
			3,36,840	25
कुल	60,11,320	33	1,42,59,505	42

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 1949-50 और 1960-61 के बीच लड़कियों की संख्या दुगुनी हो गई। सन् 1965-66 में कुछ और प्रगति हुई है। 16.3 में स्पष्ट की गई है। स्थिति को देखकर यह आभास होता है कि लड़कियों के बावजूद भी जो प्रगति है वह बहुत अधिक नहीं है।

## तालिका नं० 16.3

1965-66 में नारी शिक्षा की स्थिति

Position of Women Education in 1965-66

विभिन्न स्तर	1965-66
प्राथमिक स्तर (संख्या लाख में)	182
मिडिल स्तर (संख्या लाख में)	11.39
माध्यमिक स्तर (संख्या लाख में)	10.69
उच्च स्तर (संख्या सौ में)	271
व्यावसायिक विद्यालय (संख्या सौ में)	120
व्यावसायिक महाविद्यालय (संख्या सौ में)	50

इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रगति के चरण बढ़े अवश्य हैं परन्तु लड़कें और लड़कियों की संख्या में काफी अन्तर है। विभिन्न आयोगों, समितियों और राष्ट्रीय नारी शिक्षा परिषद् ने इस अन्तर को कम करने के लिए समय-समय पर महत्वपूर्ण सुझाव दिये, परन्तु अभी उन सुझावों के अनुसार कार्य नहीं किया गया है। संक्षेप में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् नारी शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न आयोगों, समितियों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये और जो प्रगति आज दिखाई दे रही है वह उन्हीं सुझावों का परिणाम है।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) और नारी शिक्षा

University Education Commission (1948-49) & Women Education

नारी शिक्षा के महत्त्व और आवश्यकता पर बल देते हुए आयोग ने निम्न-लिखित सुझाव दिये—

1. स्त्री और पुरुषों को समान शैक्षिक अवसर प्राप्त होने चाहिए।
2. यह आवश्यक है कि स्त्रियों को उनके अनुरूप शिक्षा प्रग्त हो जिससे वे अच्छी माता और गृहस्वामिनी हो सकें।
3. नारियों की शिक्षा में गृह वर्णसाम्प्रदाय और गृह प्रवृत्ति की समुचित शिक्षा का प्रावधान हो और उन स्त्रियों के लिए उन्हें अधिकाधिक प्रेरित किया जाये।

4. सहस्रिका शालाओं में छात्राओं के लिए विशिष्ट सुविधाएँ प्रदान की जाये।
5. महिला अध्यापिकाओं को पुरुष अध्यापकों के समान वेतन मिलना चाहिए।

### राष्ट्रीय नारी शिक्षा समिति (1958)

### National Committee on Women's Education (1958)

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों से नारी शिक्षा के क्षेत्र में कोई शीघ्र परिवर्तन नहीं आया। इसीलिए भारत सरकार ने सन् 1958 में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसका कार्य क्षेत्र प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक सुझाव देना था क्योंकि प्राथमिक शिक्षा में अध्यापिकाओं का सर्वथा अभाव था अतः यह निर्दिष्ट किया गया कि प्रस्तुत समिति माध्यमिक शिक्षा के प्रसार हेतु भी सुझाव दे। इस समिति ने सन् 1959 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और नारी शिक्षा हेतु अनेकों सुझावों में से कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित थे:—

1. कुछ समय के लिए लड़कियों की शिक्षा को विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार किया जाये और जाने वाले वर्षों में उचित धन की व्यवस्था की जाये जिससे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा स्तर पर लड़कियों को अधिक शिक्षा सुविधाएँ प्रदान की जा सकें।
2. केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नारी शिक्षा परिषद् की स्थापना की जाये जिसके सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट इकाई बनाई जाये।
3. प्रत्येक राज्य में 'राज्य नारी शिक्षा परिषद्' हो और लड़कियों के शैक्षणिक कार्यों के लिए दृष्टिनिर्देशक हो।
4. उक्त सुझावों को केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्वीकार किया और मार्च 1959 को 'राष्ट्रीय नारी शिक्षा परिषद्' की स्थापना की।

### राष्ट्रीय नारी शिक्षा परिषद् (1959)

### National Council for Women Education (1959)

1959 में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में इस परिषद् ने राष्ट्रीय नारी शिक्षा मंत्रालय में नारी-शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक निपुण टीम की गई। सामान्य रूप से यह परिषद् निम्नलिखित कार्य करता है—

1. शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देना।

2. नारी शिक्षा के प्रसार, कार्यक्रम, प्रगति और आवश्यकता से सम्बन्धित सुझाव देना ,
3. नारी शिक्षा के वस में जनमत संसार करना ।
4. प्राप्त प्रगति का मूल्यांकन करना और भावी प्रगति हेतु योजना बनाना ।
5. नारी शिक्षा की समस्याओं पर अनुसन्धान करना और आवश्यक समितियों का गठन करना ।

इस परिपत्र ने नारी शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए अभी तक दो महत्वपूर्ण समितियों की नियुक्ति की है ।

एक समिति का गठन श्रीमती हसा महता की अध्यक्षता में सन् 1962 में किया गया जिसका कार्य क्षेत्र सरकारी की शिक्षा की विभिन्न आवश्यकताओं पर विचार करते हुए पुष्प पाठ्यक्रम हेतु सुझाव देना था ।

दूसरी समिति का गठन सन् 1963 में श्री एम० भक्तवत्सलम्, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र की अध्यक्षता में किया गया जिसका कार्यक्षेत्र प्राचीन क्षेत्रों में नारी शिक्षा के प्रति उपेक्षा के कारणों का पता लगाना था ।

#### कोठारी आयोग (1964-66) और नारी शिक्षा

#### Kothari Commission (1964-66) & Women Education

आयोग ने श्रीमती दुर्गाबाई देगमुज, श्रीमती हसा महता, श्री एम० भक्तवत्सलम् आदि की अध्यक्षता में गठित समितियों का उल्लेख किया है और श्रीमती दुर्गाबाई देगमुज ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित सुझाव दिये:—

1. निकट भविष्य में नारी शिक्षा के सम्पूर्ण कार्यक्रमों को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग स्वीकार किया जाये ।
2. नारी शिक्षा के मार्ग में आने वाली सम्भावी समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें ।
3. स्त्रियों और पुरुषों की शिक्षा के बीच जो फाई है उसे यथाशीघ्र समाप्त किया जाये और इस कार्य हेतु विशेष योजनाएँ बनाई जायें ।
4. नारी शिक्षा के प्रसार हेतु उदार आर्थिक सहायता प्रदान की जाये ।
5. केन्द्र और राज्य स्तर पर आयोगों और नारियों की शिक्षा हेतु उपयुक्त प्रशासकीय संगठन का निर्माण किया जाये ।

0. अविवाहित स्त्रियों के लिए पूर्णकालीन रोजगार की व्यवस्था हो और अन्य स्त्रियों के लिए अर्धकालीन रोजगार की व्यवस्था हो।

### 16.04 राजस्थान में नारी शिक्षा Women Education in Rajasthan

राजस्थान ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से नारी शिक्षा के क्षेत्र में लोपी पिछड़ा हुआ रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में पूर्व तो यहाँ की स्थिति ही सराबोर थी। सन् 1950-51 में कुल 803 नारी शिक्षा संस्थाएँ थी जिनमें 1 महाविद्यालय थे, 10 उच्च विद्यालय, 102 मिडिल स्कूल थे और 452 प्राथमिक शालाएँ थी। सम्पूर्ण राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत केवल 3.0 था। जोषनीय स्थिति को ठीक करने के लिए सतत् प्रयास किये गये और उन्हीं के फलस्वरूप आज की स्थिति बहुत ही सुसुध है। सन् 1955-56 में लड़कियों की प्राथमिक शालाओं की संख्या 585, मिडिल की संख्या 140, 19 उच्च विद्यालय और 9 महाविद्यालय थे। द्वितीय योजना में स्थिति कुछ सुधरी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 1960-61 में 12 महाविद्यालय, 69 उच्च/उच्चतर माध्यमिक शालाएँ, 2 मिडिल स्कूल तथा 614 प्राथमिक शालाएँ थी। सन् 1963-64 में लड़कियों की संख्या घटकर 10 रह गई परन्तु माध्यमिक शालाएँ 86, मिडिल और प्राथमिक शालाएँ 732 हो गई। तालिका नं० 16.4 में इस स्थिति दिया गया है।

तालिका नं० 16.4

राजस्थान में नारी शिक्षा का प्रसार

Expansion of Women Education in Rajasthan

प्राथमिक	शिक्षा संस्थाओं की संख्या		
	मिडिल	उच्च/उच्चतर	महाविद्यालय
452	102	10	6
585	140	19	9
614	202	69	12
732	247	86	10

शालाओं की संख्या का प्रश्न है सन् 1950-51 में उच्च/उच्चतर 0.02 लाख, मिडिल स्तर में 0.09 लाख, प्राथमिक स्तर में



0.55 लाख और उच्च स्तर में 0.01 लाख छात्राएँ थी। सन् 1963-64 में यह संख्या उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 0.15 लाख, मिडिल स्तर पर 0.54 लाख और प्राथमिक स्तर पर 3.25 लाख हो गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राथमिक स्तर पर 4.80 लाख, मिडिल स्तर पर 0.80 लाख, उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 0.20 लाख छात्राएँ थी। बताया है चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राथमिक स्तर पर 13.00 लाख, मिडिल स्तर पर 1.60 लाख और उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 0.40 लाख छात्राओं की संख्या हो जायेगी। शाला जाने वाली छात्राओं का प्रतिशत 8-11 वर्षीय आयु समूह का 72.5%, 11-14 वर्षीय आयु समूह का 21.5% और 11-14 वर्षीय आयु समूह का 5.8% हो जायेगा।

यद्यपि नारी शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति अवश्य हुई है परन्तु लड़कियों और लड़कियों की संख्या में अभी तक भी बहुत खड़ी खाई है। मिडिल स्तर पर प्रति 5 लड़कों पर 1 लड़की और उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 8 लड़कों पर 1 लड़की स्कूल जाती है। राजस्थान सरकार ने नारी शिक्षा प्रसार हेतु और अध्यापिकाओं को अपने व्यवसाय के प्रति आकर्षित करने की निम्नलिखित विविष्ट योजना बनाई है—

1. नारी शिक्षा हेतु राज्य व्यापी आन्दोलन।
2. कक्षा 6 में 11 की 600 लड़कियों को प्रति वर्ष मुफ्त पुस्तकें देना।
3. नि:शुल्क शिक्षा।
4. अध्यापिकाओं को स्वतन्त्र रूप से परीक्षा में बैठने की सुविधाएँ।
5. अध्यापिकाओं के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष के स्थान पर 35 कर दी गई है।
6. एच. टी. सी. पालाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली छात्राओं को 25 रु० मासिक की छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बी. एड. के लिए 40 रु० मासिक की छात्रवृत्ति देना।

### 16.05 नारी शिक्षा की समस्याएँ और समाधान

#### Problems & Remedies of Women Education

राष्ट्रीय नारी शिक्षा समिति के अनुसार स्त्री शिक्षा की समस्याओं का यथा-शीघ्र समाधान किया जाये, इसके लिए विविष्ट व्यवस्था होनी चाहिए, पर्याप्त धन की व्यवस्था की जानी चाहिए और उन राज्यों में जहाँ व्यक्तित्व प्रयत्नों का अभाव है वहाँ राज्य सरकारों को व्यवस्था करनी चाहिए।<sup>1</sup> भारतीय सविधान 16 के अनुसार भी राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान

1. *Report of the National Commission, on Women's Education*  
1969, p. 3

अपरा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।<sup>1</sup> इसके अतिरिक्त नारी शिक्षा के प्रसार हेतु केन्द्रीय और विभिन्न राज्य सरकारें बराबर प्रयत्न भी कर रही हैं, तथापि एक क्षेत्र में आगाओत उन्नति नहीं हो पाई है, इसका प्रमुख कारण है कुल समस्याओं का भारतीय जीवन में विद्यमान स्वरूप है।

### 1. अपारम्परिक परम्परागत दृष्टिकोण

#### False Conventional Outlook

एक वैज्ञानिक युग में अब भी अज्ञान्य नर नारी अपारम्परिक परम्पराओं और कुरीतियों के शिकार हैं। भारतवासियों की ऋद्धिवादिता को देखकर एक बार एडमंड महोदय ने कहा था कि भारतीयों की यह मान्यता कितनी हान्यकारक है कि यदि वे नारियों को शिक्षा देंगे तो वे विधवा हो जायेंगी अथवा भ्रष्ट हो जायेंगी। बनेकों दृष्टियों और मुरिस्म परिवारों में आज भी बाल विवाह की कुप्रथा विद्यमान है। लहरी को घर से निवानना पारिवारिक प्रतिष्ठित के प्रतिकूल समझा जाता है। अधिवासर भारतीयों को अब भी लहरी को बौद्ध समझते हैं और उन पर व्यर्थ किया हुआ धन निरर्थक समझा जाता है।

यदि लहरीयों के माता पिता अथवा अभिभावकों का यही दृष्टिकोण रहा तो नारी शिक्षा के प्रसार हेतु सरकार के समस्त कार्यक्रम बेकार हो जायेंगे। अतः आवश्यकता है, वचित सामाजिक दृष्टिकोण को विरसित करने की। यदि यह नहीं हुआ तो नारी शिक्षा का समुचित प्रसार असम्भव है।

### 2. अशिक्षित जनसंख्या

#### Uneducated Population

हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आजादी के त्रेहस वर्ष पश्चात् भी 75% नर-नारी अशिक्षित हैं। जिस देश में अशिक्षा का साम्राज्य हो वहाँ ऋद्धिवादिता और कुरीतियों का होना कोई अस्वाभाविक नहीं है। अशिक्षित व्यक्तियों को सही बात समझाना बहुत कठिन कार्य है। नारी शिक्षा के प्रसार में सबसे बड़ी बाधा इसीलिए है जब तक देश की अधिकांश जनता शिक्षित नहीं होगी, जब तक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास असम्भव है, अतः ऐसी स्थिति में नारी शिक्षा की प्रगति केवल स्वप्न मात्र है।

### 3. निर्धनता

#### Poverty

हमारे देश में सामान्य जनजीवन की सर्वप्रमुख समस्या आर्थिक संकट है।

1. The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.

*Constitution of India, Article 15*

अधिकांश परिवार इस प्रकार के हैं जो अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में सरकियों का पराना तो दूर, लड़कों को ही पाठशाला भेजना असम्भव है।

#### 4. पृथक् पाठ्यक्रम का अभाव

##### Lack of Sperate Curriculum

इस संकटमय स्थिति में केवल एक ही उपाय है, और वह सरकार द्वारा नि पुस्क नारी शिक्षा। सरकार को स्वयं ही ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। राष्ट्रीय नारी शिक्षा परिषद् इसके लिए प्रयत्नशील है और चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए समुचित धन राशि की व्यवस्था भी की गई है।

आज की स्थिति में प्राथमिक स्तर में छेकर विश्वविद्यालय स्तर तक छड़के और लड़कियों के पाठ्यक्रम में कोई अन्तर नहीं है। यहाँ हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि पाठ्यक्रम में विशेष अन्तर को आवश्यकता है, बल्कि कहने का अभिप्राय यह है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में बालिकाओं की आवश्यकताएँ, रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, सामर्थ्य और समता बालकों से भिन्न होती है और ऐसी स्थिति में एक ही पाठ्यक्रम का प्रावधान उचित नहीं है। अतः अविचार्य विषयों के अतिरिक्त, कुछ ऐसे विषयों का ज्ञान आवश्यक है जो छात्राओं को भारतीय दृष्टिकोण और पारिवारिक जीवन का ज्ञान प्रदान कर सके।

#### 5. अध्यापिकाओं का अभाव

##### Lack of Lady Teacher

अध्यापिकाओं का अभाव नारी शिक्षा की प्रगति में एक बाधा है। ग्रहण की स्थिति तो फिर भी सन्तोषप्रद है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बहुत खराब है। इसके कई कारण हैं—प्रथम तो स्त्रियों में शिक्षा का अभाव है, दूसरे जो स्त्रियाँ शिक्षित हैं वे नौकरी के लिए दूर नहीं जा सकती, कुछ लड़कियाँ घादी से पूर्व तो अध्ययन व्यवसाय में लगी रहती हैं परन्तु घादी के पड़बाव उन्हें प्रायः नौकरी छोड़नी पड़ती है, इन सब कारणों से अध्यापिकाओं का अभाव बराबर बना रहता है। प्रथम तो लड़कियों के विद्यालयों का अभाव रहता है, परन्तु जैसे जैसे विद्यालयों की व्यवस्था होती है तो अध्यापिकाओं का अभाव बना रहता है, ऐसी स्थिति में माता पिता और अभिभावक यही उचित समझते हैं कि लड़कियों को शाला में भेजने की अपेक्षा घर में काम कराना ही उचित है।

इस समस्या का समाधान सरकार द्वारा ही सम्भव है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापिकाओं के लिए आवास की व्यवस्था की जा सके तो सम्भवतः अध्यापिकाओं का अभाव पूरा हो सके। इसके अतिरिक्त अन्य सामयिक अध्यापन व्यवसाय द्वारा विवाहित स्त्रियों को आवृत्त किया जा सकता है। स्त्रियों के लिए आयु प्रतिबन्ध

हटा दिया जाये तो अधिक उत्तम है। अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठान सुविधाओं को य सम्भव बढ़ाया जाये।

## 6. दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन

### Defective Educational Administration

स्वतन्त्रता से पूर्व नारी-शिक्षा की दशा अत्यन्त शोचनीय थी, परन्तु स्वतन्त्र के पश्चात् भी हम कोई आश्चर्यजनक प्रगति नहीं कर पाये हैं, इसका अन्य कारणों अतिरिक्त एक कारण दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन है। केवल मात्र कुछ छोटे से राज्यों अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में नारी शिक्षा का प्रशासन पुरुषों के पास ही है। राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, आंध्रप्रदेश, दिल्ली, बंगाल के अतिरिक्त समस्त राज्यों प्रशासन का भार पुरुषों के पास है। इससे प्रशासन दोषपूर्ण हो जाता है क्योंकि पुरुष वर्ग स्त्रियों की समस्या से अवगत नहीं होता।

इस समस्या के समाधान स्वरूप यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य में नारी शिक्षा का निदेशालय पृथक् होना चाहिए। एक सचालिका के आधीन क्षेत्रानुसार उप सचालिकाएँ हो और उनके आधीन विद्यालय निरीक्षिकाएँ हो। इस प्रकार नारी शिक्षा के प्रशासन में उचित मुधार करके ही शिक्षा नीति का निर्धारण होना चाहिए।

अन्त में नारी-शिक्षा की समस्याओं और समाधानों के तवर्ध में यह कहना उचित होगा कि स्त्री शिक्षा के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण विकसित करना अनिवार्य है। प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है कि पुरानी परम्परागत धारणाओं, धार्मिक सकीर्णताओं और अनुचित दृष्टिकोणों को परिवर्तित कर नारी-शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करे। भारत की प्रत्येक शिक्षित नारी का यह कर्तव्य है कि वह अपने पढ़ीस और कार्यक्षेत्र में अधिष्ठित नारियों को शिक्षा के महत्त्व से परिचित कराये और बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उनके हृदय में आस्था उत्पन्न करे। यदि नारी वर्ग स्वयं ही सचेत होकर नारी-शिक्षा के लिए आन्दोलन करे तो कोई कारण हमारे देश में निरक्षरों की संख्या अधिक हो सके। सम्पूर्ण समाज को प्रेरित होना आवश्यक है कि भारत में नारियों के निश्चय, ठोस दृष्टिकोण, और कार्यकुशलता पर ही उनकी शिक्षा का भविष्य निर्भर है।<sup>1</sup>

Upon their determination, Compactness, good sense and efficiency rests the future of education women in India.  
Tara Ali Baig (Ed) *women of India*, p 160

## ग्रन्थ-सूची

### Bibliography

1. Desai, D. M.  
*Universal Free and Compulsory Education in India*, Indian Institute of Education, Bombay.
  2. Karlekar, K.  
*Special Curriculum for girls in Secondary Schools*, Teacher Education, New Delhi, Feb 1960
  3. Naik, O,  
*Education of women in Bombay State*, Bombay university, Ph. D. Thesis.
  4. *Report of University Education Commission*,  
Ministry of Education, New Delhi, 1949
  5. *Report of Secondary Education Commission*,  
Ministry of Education, New Delhi, 1953
  6. *Report of the National Committee on women's Education*,  
Ministry of Education, New Delhi, 1959
  7. *Report of the Indian Education Commission*,  
Ministry of Education, New Delhi, 1966
-

## 17.04 भारत में भाषाओं की स्थिति

*Position of Languages in India*

## 17.05 त्रिभाषी सूत्र और उसके कार्यान्वयन में कठिनाई

*Three Language Formula & Difficulties in Its Implementation*

1. संघिक स्तर
2. अमनोवैज्ञानिक हल
3. अंग्रेजी का ज्ञान अनावश्यक स्तर
4. हिन्दी भाषी क्षेत्रों पर अनावश्यक स्तर : 1
5. हिन्दी भाषी क्षेत्रों में व्यावहारिक कठिनाईयाँ

## 17.06 अंग्रेजी का स्थान

*Place of English*

1. माध्यमिक शिक्षा आयोग और अंग्रेजी
2. कोटारी आयोग और अंग्रेजी

## भाषा समस्या *LANGUAGE PROBLEM*

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मानवीय सामाजिकता का प्रदर्शन भाषाओं और विचारों की अभिव्यक्ति पर अवलम्बित है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी भाषा द्वारा अभिव्यक्ति से संतोष प्राप्त होता है, भाषा द्वारा व्यक्ति की छिपी हुई शक्ति का विकास होता है। भाषा के अनुसन्धान से व्यक्ति विकसित अवस्था में पहुँचा है। भाषा के विकास द्वारा मानव और उसकी संस्कृति का विकसित रूप आता है। भाषा के विकास में समस्त मानव जाति का योग समाहित होता है। 'भाषा भवन के समान है जिसके निर्माण में मानव जाति ने पत्थरों को लाकर एक भवन का रूप प्रदान किया है।'<sup>1</sup>

### 17.01 भाषा-एक समस्या *Language-A Problem*

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश के सम्मुख अनेकों समस्याएँ आयी, कुछ समस्याएँ आज भी विद्यमान हैं, अनेकों समस्याओं का समाधान हो चुका है और

---

1. 'Language is like the building of which every human being brought a stone.'  
—Emerson

कुछ समस्याओं का समाधान समय की गति से हो रहा है परन्तु भाषा समस्या ही बनी रही। इस समस्या को ज्यों-ज्यों सुलझाने का प्रयत्न किया गया, समस्या त्यों-त्यों उलझती चली गई और आज यह समस्या अपने विकसित रूप में हमारे सम्मुख है। इस समय हमारे देश में 144 भाषाएँ और बोलियाँ बोल्य जाती हैं और यही कारण है कि सब अपनी भाषा को ही सर्वोपरि समझते हैं और भाषा एक समस्या के रूप में परिणित हो गई है। कोठाड़ी भाषा के अनुसार सभ्यता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश में अनेकों समस्याओं का सामना किया गया है परन्तु भाषा की समस्या अभी तक उन्नी प्रकार से उलझी हुई और अब भी इसकी सबसे बड़ी समस्या के रूप में है।<sup>1</sup> अब देश को एक मूल में बांधने के लिए भाषा नीति का होना नितान्त आवश्यक है। इस समस्या का धीमे एवं समुचित समाधान राजनैतिक स्थिरता, धार्मिक और सांस्कृतिक विकास हेतु नितान्त आवश्यक है। यदि इस समस्या का समाधान धीमे न हुआ तो यह समस्या और भी गंभीर जटिल होती चली जायेगी जिससे देश की एकता तथा अखण्डता को भारी नुकसान की सम्भावना है।

## 17 02 शिक्षा का माध्यम-ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि

### Medium of Instruction-Historical Background

भाषा एक समस्या के मूल में सर्वत्र एक ही प्रश्न है—और वह क्या प्रश्न? माध्यम? इसी प्रश्न को लेकर सघर्ष का प्रारम्भ हुआ और काल की गति के अनुसार भयंकर से भयंकरतम् हल्ला चला गया—आज इस समस्या की भयावह बिगारि देश में व्याप्त है। इस समस्या के भयानक स्वरूप का सक्षिप्त इतिहास निम्नलिखित है।

#### 1. शिक्षा माध्यम के प्रारम्भिक प्रयास (1813-33) और भाषा

##### Early Efforts of Educational Medium (1813-33)

##### & Language

शिक्षा माध्यम का सघर्ष इसी युग में प्रारम्भ हुआ। मूल रूप से तीन भाषाएँ थीं। शिक्षा माध्यम के रूप में—

(अ) प्राचीन भाषाएँ—अरबी, फारसी, संस्कृत रखी जाये

अथवा

(ब) देसी भाषाएँ हों,

1. Of the many problems which the Country has faced since independence, the language question has been one of the most complex and intractable and it still continues to be so.  
Report of the Education Commission, 1964, p. 13



## अथवा

(घ) अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया जाये ।

प्रथम विचारधारा में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों का मत था कि भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की रक्षा हेतु संस्कृत और अरबी भाषा के द्वारा योरोपीय विज्ञानों का ज्ञान प्रदान किया जाये । इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक लार्ड हेस्टिंग्स थे ।

द्वितीय विचारधारा के समर्थक मुन्रो थे और वे देशी एवं प्रान्तीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम रखना चाहते थे । इन समर्थकों का मत था कि देशी और प्रान्तीय भाषा द्वारा इंग्लैंड को कान्ची ज्ञान पहुँचेगा ।

तृतीय विचारधारा के समर्थक अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के पक्षपाती थे । यह समर्थक शायद सभी प्रान्तों में विद्यमान थे । मिशनरियाँ भी इसी विचारधारा की समर्थक थी । अन्त में यही दल विजयी हुआ और भारतीय संस्कृति के ह्रास का प्रथम पाठ यहीं से प्रारम्भ हो गया तथा भारतीय सभ्यता परिचयी सभ्यता के रूप में इसी अनुक्रम काल से रचनी बनो गई, जिसकी प्रक्रिया आज भी उसी गति से विद्यमान है और देश में घुट के दुर्गन्धमय वातावरण की प्रतीक्षा कर रही है ।

#### 5. अंग्रेजी के लिए लार्ड मैकाले के प्रयास

#### Lord Macaulay's Efforts for English

सन् 1833 के लगभग शिक्षा के माध्यम को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ । 10 जून 1834 ई० को लार्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल के 'कानून सदस्य' बनकर भारत पधारे । इसी दिनों 1813 ई० के एक्ट की 43 वीं धारा का प्रश्न उठा । कानूनी सलाहकार होने के नाते लार्ड मैकाले ने सरकार के पूछने पर शिक्षा से सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत किया ।

मैकाले ने अंग्रेजी का पक्ष लेते हुए प्राच्य भाषाओं को गैरकारगर और अविश्वसित बताया । उसके अनुसार एक अच्छी योरोपीय पुस्तकालय की केवल मात्र एक आलमगी सम्पूर्ण भारतीय एवं अरब साहित्य से बढ़कर है ।<sup>1</sup> अंग्रेजी के गुणों का बखान करते हुए मैकाले ने कहा कि पश्चिम की भाषाओं में अंग्रेजी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है । जिसको भी इस भाषा का ज्ञान है उसके पास वह बौद्धिक सम्पत्ति है जिसका निर्माण इस पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान राष्ट्रों ने किया है ।<sup>2</sup>

1. A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India & Arabia.

Lord T. B. Macaulay's Minute

2. English stands pre-eminent among the language of the west. Whoever knows that language has ready access to all the vast intellectual wealth which all the wisest nations of the earth have created. *Ibid.*



और मातृभाषा के विषय में मौन रहा। मिडिल स्तर पर शिक्षा का माध्यम निश्चित नहीं किया गया और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ही माध्यम के प्रश्न को सुलझाने की विचारधारा की गई। परिणामतः माध्यमिक शिक्षा स्तर पर अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ता गया और 1902 तक अंग्रेजी शिक्षण माध्यमिक स्तर का विशिष्ट उद्देश्य हो गया। भारतीय भाषाओं के अध्ययन को तिरस्कृत किया गया।<sup>1</sup>

#### 5. भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (1902) और भाषा

Indian University Commission (1902) & Language

आयोग ने अंग्रेजी को महत्वपूर्ण स्थान दिया और इससे सम्बन्धित निम्न-लिखित सुझाव दिए :—

- \* जिन शिक्षकों की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है उन्हें अंग्रेजी का प्रशिक्षण दिया जाये।
- \* अंग्रेजी पढ़ाने के लिए उन शिक्षकों की नियुक्ति की जाये जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी हो।
- \* स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षण की व्यवस्था की और अधिक बढ़ाया जाये।

उपरोक्त सुझावों से भारतीय भाषाओं का बहुत अधिक अहित हुआ और परिणामतः भारतीय भाषाओं का विकास अवकट हो गया।

#### 6. राष्ट्रीय आन्दोलन और भाषा

National Movement & language

सन् 1902 तक देश में राष्ट्रीय चेतना की विचारियाँ पूर्ण वेग से फैल चुकी थीं। अंग्रेजी का भारतीय भाषाओं के प्रति तिरस्कारपूर्ण एवं उपेक्षित व्यवहार देख कर भारतीय नेताओं के हृदय में रोष उत्पन्न हो रहा था। वे बराबर मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में विचारधारा कर रहे थे। इससे राष्ट्रीय आन्दोलनों के कारण अंग्रेजी के पर उलझ रहे थे। सन् 1917 में 'कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग' की नियुक्ति हुई और आयोग ने इण्टरमीडिएट स्तर तक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा बनाना स्वीकार भी कर लिया। इसके परिणामस्वरूप सन् 1937 तक भारतीय भाषाओं को माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाने लगा परन्तु कुछ विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती रही। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही था।

सन् 1944 में सर जॉन सारजेंट ने सुझाव दिया कि सभी उच्च विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए और अंग्रेजी को द्वितीय अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना चाहिए ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व, संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखने से ज्ञात होता है कि अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजी को जो सम्मान प्राप्त हुआ, वह आवश्यकता से अधिक था । एक ओर अंग्रेजी को पाठ्यक्रम का मुख्य विषय बनाया गया, दूसरी ओर यह शिक्षा का माध्यम भी बनी । अतः भारत की भूमि पर विदेशी पाँपे को डेढ़ सौ वर्ष तक इस प्रकार सोचा गया कि आज उसकी मजबूत जड़ें इतना घर कर चुकी हैं कि उसको उखाड़ फेंकना तो दूर, उसे छूने तक से भय लगता है । भय का कारण भारतीयों की अंग्रेजी के प्रति आस्था और दृढ़ता बलीलें नहीं हैं बल्कि भय का मूल कारण है कि आज भाषा का प्रश्न संसिक न रहकर स्वार्थी राजनीतिज्ञों का बसाड़ा बन गया है ।

## 17 02 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भाषा ?

### Language After Independence ?

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भाषाई प्रश्न का समाधान करने के लिए अनेकों आयोगों ने सुझाव दिये । राष्ट्रीय एकता बनाये रखने के लिए इस समस्या पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया गया । विभिन्न स्तरों पर कितनी भाषाएँ पढ़ाई जायें ? किस भाषा का प्रारम्भ किस स्तर विद्यार्थी से हो ? कितनी अवधि तक किस भाषा को पढ़ाना उपादेय होगा ? विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का क्या माध्यम हो ? आदि सभी प्रश्नों पर आयोगों द्वारा विचार किया गया जो इस प्रकार है—

#### 1. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49)

##### University Education Commission (1948-49)

आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के विषय में गम्भीर रूप से विचार किया और मातृभाषा के द्वारा शिक्षा दिये जाने पर बल दिया । विश्व-विद्यालय स्तर पर तीन भाषाएँ पढ़ाने की व्यवस्था निश्चित की —

प्रादेशिक भाषा (Regional Language)

संघीय भाषा (Federal Language)

अंग्रेजी (English)

आयोग के अनुसार भारत प्रत्येक प्रान्त और इकाई को संघीय त्रियाजों में अच्छी तरह भाग लेने हेतु और प्रान्तों में पारस्परिक सद्भावना की अभिवृद्धि हेतु संयुक्त भारत को दो भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना होगा और माध्यमिक तथा

स्तर पर प्रत्येक छात्र को प्रादेशिक भाषा को जानना भी आवश्यक है,

साथ ही उसे संघीय भाषा की जानकारी भी होनी चाहिए और अंग्रेजी पुस्तकों को पढ़ने की योग्यता भी होनी चाहिए<sup>1</sup>।

भाषा समस्या की जटिलता एवम् गुरुत्वा पर विचार प्रमट करते हुए आयोग ने सिखा है कि शिक्षा-शास्त्रियों एवम् अन्य व्यक्तियों ने इस समस्या पर इतनी विरोधी विचारधाराएँ प्रमट नहीं की हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रश्न को भावनाओं के साथ इस प्रकार सूँघा गया है कि छान्दमय ढंग से विचार करना बहुत ही कठिन है।<sup>2</sup> फिर भी आयोग ने बहुत ही सोच-विचार कर इस समस्या के समाधान हेतु निम्न-लिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं:—

1. अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दों का भारतीय भाषाओं का अनुवाद (भारतीयकरण) किया जाये।
2. उच्च शिक्षा स्तर पर अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए।
3. संस्कृत की जटिलता, पाठ्य-पुस्तकों की कमी और अन्य कठिनाइयों के कारण इसे शिक्षा का माध्यम न बनाया जाये।
4. संघीय एवम् प्रादेशिक भाषाओं का विकास शीघ्रातिशीघ्र किया जाये।
5. उच्चतर माध्यमिक स्तर, स्नातक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर संघीय भाषा का प्रयोग बिधा जाये।
6. अंग्रेजी के अध्ययन को जारी रखा जाये।

यदि आयोग के सुझावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाये तो हम यह स्वरुप कह सकते हैं कि आयोग के सुझाव बहुत व्यावहारिक हैं। समस्या पर

1. But in order to enable every religion and unit of India to take its proper share in the Federal activities and to promote interprovincial understanding and solidarity, educated India has to make up its mind to be bilingual

*University Education Commission, 1948-49, p 321*

2. No other problem has caused greater controversy among education and evoked more contradictory views from our writers. Besides this question is so wrapped up in sentiment that it is difficult to consider it in a calm and detached manner.

*Ibid, p. 305*

यदि विचार किया जाये तो भारतीय भाषाओं तथा संघीय भाषा को शिक्षा माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा का भारतीयकरण होना अत्यन्त उपादेय है। अंग्रेजी को यथावत जारी रखने के विषय में कुछ विद्वानों में मतभेद अवश्य है, परन्तु हमारी राय में अंग्रेजी का वादनीय है। यह निर्विवाद सत्य है कि अंग्रेजी संसार की प्रमुख भाषाओं में से एक है और किसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना किसी भी दृष्टि में अहितकर नहीं है।

## 2. माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53)

Secondary Education Commission (1952-53)

आयोग ने भाषा समस्या पर पर्याप्त विचार कर निम्नलिखित भाषा अध्ययन पर विशेष बल दिया.—

हिन्दी का स्थान

अंग्रेजी का स्थान

संस्कृत का स्थान

उपरोक्त तीनों भाषाओं की महत्ता पर विचार करने के पश्चात् माध्यमिक स्तर पर भाषाओं के अध्ययन के विषय में निम्नलिखित सुझाव दिये,—

(अ) माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा प्रादेशिक भाषा हो।

(ब) मिडिल स्तर पर तीन भाषाओं को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाये—

(i) मातृ भाषा

(ii) अंग्रेजी

(iii) हिन्दी यदि मातृ भाषा है तो अथवा भारतीय भाषा

(ग) उच्च अथवा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कम से कम दो भाषाओं को स्थान दिया जाये। इनमें से एक मातृभाषा हो या प्रादेशिक भाषा। दूसरी भाषा का चयन निम्नलिखित भाषा समूह से किया जाये—

• हिन्दी (अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के लिए)

• प्रारम्भिक अंग्रेजी (जिन्होंने मिडिल स्तर पर अंग्रेजी का अध्ययन नहीं किया है।)

• उच्च अंग्रेजी (जिन्होंने मिडिल स्तर पर अंग्रेजी का अध्ययन किया है।)

• एक आधुनिक भारतीय भाषा (हिन्दी के अतिरिक्त)

- एक आधुनिक विदेशी भाषा (अंग्रेजी के अतिरिक्त)
- एक राष्ट्रीय भाषा

आयोग के भाषा सम्बन्धी सुझावों का अध्ययन करने के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि द्विभाषी मूल के द्वारा एक परिपक्व सुझाव दिया है परन्तु स्थिति की वास्तविकता का ध्यान नहीं रखा गया है। केवल दो भाषाओं के अध्ययन मात्र से समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

### 3. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सुझाव

*Suggestions of Central Advisory Board of Education*

26 जनवरी 1956 को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 23वी बैठक में भाषा के प्रश्न पर विचार किया गया। इस बैठक में त्रिभाषी मूल को अपनाया गया। इस सिद्धान्त के अनुसार विद्यार्थियों को माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाओं का अध्ययन करना होगा जिसकी रूपरेखा इस प्रकार निश्चित की गई—

- (अ) मातृ भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा या उच्चतम मिलातुला रूप या मातृ-भाषा या प्राचीन भाषा का मिलातुला रूप या क्षेत्रीय भाषा और प्राचीन भाषा का मिलातुला रूप।
- (ब) अंग्रेजी अथवा आधुनिक विदेशी भाषा।
- (स) हिन्दी (अहिन्दी क्षेत्रों के लिए) अथवा अन्य कोई आधुनिक भारतीय भाषा (हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लिए)।

यदि त्रिभाषी मूल की दार्शनिक दृष्टि से देखा जाय तो हम कह सकते हैं कि यह समन्वयकारी प्रवृत्ति का सूचक है। यदि वैश्विक दृष्टि से देखा जाय तो यह विद्यार्थियों पर बोझ का प्रतीत होता है। फिर भी यदि राष्ट्र को एक मूल में बाँधना है तो बोझ भी सहन करना होगा और हिन्दी भाषियों को दक्षिण की भाषाओं को सीखने का थोड़ा कष्ट भी सहन करना होगा। (त्रिभाषी मूल के विषय में विस्तृत विवेचन इसी अध्याय के किसी पृष्ठक अध्ययन विन्दु में करेंगे।)

### 4. भावनात्मक एकरता समिति (1961) और भाषा

*Emotional Integration Committee (1961) & Language*

सन् 1961 में डा० सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति हुई। समिति को मूलतः भावनात्मक एकरता पर सुझाव देने थे, परन्तु भाषा का प्रश्न एकरता के लिए विपन्न बना गया है अतः भाषा समस्या के समाधान हेतु त्रिभाषी मूल को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित सुझाव दिये :—





1. हिन्दी संघ की राजभाषा है और एक समय में यह देश की भाषा होगी अतः मातृभाषा के पश्चात् हिन्दी ही दूसरी महत्वपूर्ण भाषा है।
2. अंग्रेजी विश्वविद्यालय की ओर केन्द्र की प्रशासकीय भाषा के रूप में अभी विद्यमान रहेगी। यद्यपि प्रादेशिक भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम होना है तथापि अंग्रेजी का ज्ञान विद्यार्थियों के लिये लाभप्रद है।
3. भाषाओं को सीखने की सबसे उपयुक्त अवस्था प्रारम्भिक अवस्था है। अतः यह निताम्न आवश्यक है कि बालक को प्रारम्भिक अवस्था से ही दूसरी भाषा का ज्ञान प्रदान किया जाये।
4. तीन भाषाओं को सीखने का उपयुक्त समय प्रारम्भिक माध्यमिक स्तर (class VI to X) है।
5. जहाँ तक अंग्रेजी और हिन्दी को अनिवार्य रूप से आरम्भ करने की अवस्था का प्रश्न है, यह प्रेरणा और आवश्यकता पर निर्भर करता है अतः इसे राज्य की इच्छा पर ही छोड़ देना चाहिए।
6. चार भाषाओं का अध्ययन किसी भी स्तर पर अनिवार्य नहीं होना चाहिए, परन्तु यदि कोई चार या अधिक भाषा सीखना चाहे, उसके लिए पूर्ण प्रावधान होना चाहिए।

आयोग ने उपरोक्त सिद्धान्तों के आधार पर निम्नलिखित मधोचित त्रिभाषा सूत्र प्रस्तावित किया है—

- (अ) मातृ-भाषा अथवा प्रादेशिक भाषा
- (ब) संघ की राजभाषा अथवा संघ की वह राजभाषा जब तक वह विद्यमान है।
- (ग) एक आधुनिक भारतीय अथवा विदेशी भाषा जो (अ) और (ब) में न ली गई हो तब जो शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती हो।<sup>2</sup>

1. We, therefore recommend modified or graduated there language formula to include
  - (a) The mother language or the regional language.
  - (b) The official language of the union or the associate official language of the union so long as it exists; and
  - (c) A modern Indian or foreign language not covered under (a) and (b) and other than that used as the medium of instruction.

*Report of the Education Commission, 1964-66, p. 192*

व्यवस्था हो ।

अहिन्दी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को माध्यमिक स्तर पर देवनागरी लिपी द्वारा हिन्दी सिखाने की व्यवस्था हो ।

हिन्दी की पुस्तकों को रोमन लिपि में प्रकाशित किया जाये ।

विश्वविद्यालय स्तर पर अंग्रेजी को उस समय तक माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाये जब तक प्रादेशिक भाषाएँ समृद्ध न हो जायें । इसके साथ-साथ भारतीय भाषाओं को भी समृद्ध किया जाये ।

उ के मुभाव आज स्थिति को दृष्टिगत करते हुए प्रायः ठीक से सगठित तर्कों को रोमन लिपि में प्रकाशित करना किस प्रकार से उपादेय बात कुछ कम समझ में आने वाली है ।

राष्ट्रीय एकता समिति (1962) और भाषा

National Integration Committee (1962) & Language

1962 में श्रीमती इन्दिरा गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता समिति की गई । समिति ने हिन्दी की महत्ता पर प्रकाश डाला गया कि द्विभाषी शब्दकोष तैयार किये जायें जिससे प्रादेशिक भाषाएँ सीप आ सकें ।

एकता समिति ने इस बात पर बल दिया कि हिन्दी क्षेत्रों में किसी भाषा को—विशेषकर दक्षिण भारत की किसी भाषा की पड़ाई दी जाये । इससे उत्तर और दक्षिण का भेद सीधे ही मिट सकेगा । भारत का दो भागों में बँट जाने का खतरा कायम है अविशुद्ध और एक संस्कृति के लोगों को एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाना ।<sup>2</sup>

शिक्षा आयोग (1964-66) और भाषा

Education Commission (1964-66)

शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने (1956) ने त्रिभाषी सूत्र का प्रतिपादन किया मंत्री सम्मेलन (1961) ने उसे पारित किया । कोटारी आयोग त्रिभाषी सूत्र को कार्यान्वित करने में अनेको कठिनाइयाँ हैं और वह सफलता प्राप्त नहीं कर सका है ।

आयोग ने त्रिभाषी सूत्र में निम्नलिखित सुझावन प्रस्तावित किया है—

वर्तमान, अक्टूबर 4, 1961

1. हिन्दी संघ की राजभाषा है और एक समय में यह देश की भाषा होगी अतः मातृभाषा के पश्चात् हिन्दी ही दूसरी महत्वपूर्ण भाषा है।
2. अंग्रेजी विश्वविद्यालय की और केन्द्र की प्रशासकीय भाषा के रूप में अभी विद्यमान रहेगी। यद्यपि प्रादेशिक भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम होना है तथापि अंग्रेजी का ज्ञान विद्यार्थियों के लिये लाभप्रद है।
3. भाषाओं को सीखने की सबसे उपयुक्त अवस्था प्रारम्भिक अवस्था है। अतः यह निवृत्त आवश्यक है कि बालक की आरम्भिक अवस्था से ही दूसरी भाषा का ज्ञान प्रदान किया जाये।
4. तीन भाषाओं को सीखने का उपयुक्त समय प्रारम्भिक माध्यमिक स्तर (class VI to X) है।
5. जहाँ तक अंग्रेजी और हिन्दी को अनिवार्य रूप से आरम्भ करने की अवस्था का प्रश्न है, यह प्रेरणा और आवश्यकता पर निर्भर करता है अतः इसे राज्य की दृष्टि पर ही छोड़ देना चाहिए।
6. चार भाषाओं का अध्ययन किसी भी स्तर पर अनिवार्य नहीं होना चाहिए, परन्तु यदि कोई चार या अधिक भाषा सीखना चाहे, उसके लिए पूर्ण प्रावधान होना चाहिए।

आयोग ने उपरोक्त सिद्धान्तों के आधार पर निम्नलिखित सक्षोभित त्रिभाषा सूत्र प्रस्तावित किया है—

- (अ) मातृ-भाषा अथवा प्रादेशिक भाषा
- (ब) संघ की राजभाषा अथवा संघ की वह राजभाषा जब तक वह विद्यमान है।
- (स) एक आधुनिक भारतीय अथवा विदेशी भाषा जो (अ) और (ब) में न ली गई हो तथा जो शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती हो।<sup>1</sup>

1. We, therefore recommend modified or graduated three language formula to include:
  - (a) The mother language or the regional language.
  - (b) The official language of the union or the associate official language of the union so long as it exists, and
  - (c) A modern Indian or foreign language not covered under (a) and (b) and other than that used as the medium of instruction.

*Report of the Education Commission, 1964-66, p 192*

## प्रत्येक भाषा की समयावधि

## Duration of Each Language

आयोग ने प्रत्येक भाषा की समयावधि के आधार पर निम्नलिखित रूप नियमित करने का सुझाव दिया—

भाषाओं का अध्ययन	कक्षा
1. एक भाषा (मातृ भाषा) का अध्ययन	I—IV
2. इस स्तर पर दो भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए। दूसरी भाषा या तो संघ की राजभाषा ( हिन्दी ) अथवा सह राजभाषा (अंग्रेजी) हो।	V—VII
3. इस स्तर पर तीन भाषाओं का अध्ययन हो। इनमें से एक संघ की राजभाषा हो अथवा सह राजभाषा (जैसा कि कक्षा V—VII में निश्चित किया गया हो) होनी चाहिए।	VIII—X
4. किसी भी भाषा को अनिवार्य रूप प्रदान न किया जाये।	XI—XII

आयोग के भाषा सम्बन्धी समाधान के विषय में भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री एम० सी० छागला ने कहा था कि आयोग ने शैक्षिक विन्दुओं के आधार पर विचार किया है, परन्तु सरकार राजनीतिक विन्दुओं के आधार पर विचार करेगी।

## 17 08 भारत में भाषाओं की स्थिति

## Position of Languages in India

सन् 1961 में जनगणना के साथ विभिन्न भाषा-भाषियों की गणना भी हुई थी। तालिका नं० 17 I में मजिस्टान में उल्लिखित विभिन्न भाषाओं के बोलने वालों की संख्या को स्पष्ट किया गया है। सन् 1961 में भारत की कुल जनसंख्या 44 करोड़ थी। विभिन्न भाषाओं की स्थिति को देखकर यह निश्चय है कि भारत में हिन्दी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है।

तालिका नं० 17.1

संविधान में लिखित विभिन्न भाषाओं के बोलने वालों की संख्या

भाषा	बोलने वालों की संख्या
हिन्दी	17 करोड़ 40 लाख
उत्तुमु	3 करोड़ 70 लाख
बगला	3 करोड़ 38 लाख
मराठी	3 करोड़ 32 लाख
तमिल	3 करोड़ 0 लाख
उर्दू	1 करोड़ 70 लाख
गुजराती	2 करोड़ 3 लाख
कन्नड़	1 करोड़ 74 लाख
मलयालम	1 करोड़ 70 लाख
उड़िया	1 करोड़ 57 लाख
पंजाबी	1 करोड़ 9 लाख
असमिया	68 लाख
कश्मीरी	10 लाख
सिन्धी	13 लाख 71 हजार
संस्कृत	2,544

विभिन्न राज्यों में प्रमुख भाषाओं और बोलीयों की स्थिति इस प्रकार है—

- मागध प्रदेश:—उत्तुमु—90.83%, उर्दू—7.75%
- असम :—असमिया—57.14%, बगला—17.60, हिन्दी—4.4%
- बिहार :—हिन्दी—44.3%, उड़िया—35.39%, उर्दू—8.9%

होता है। फिर अहिन्दी भाषी क्षेत्रों की यह भावना कि हिन्दी भाषी कोई अन्य भारतीय भाषा और जहाँ तक सम्भव हो दक्षिणी भाषा का अध्ययन करें—हमें यह व्यावहारिक ज्ञान नहीं पड़ता। यह भावना तो द्वेष मय प्रवृत्ति का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त यदि किसी अन्य भारतीय भाषा का अध्ययन कर भी लिया तो उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि भाषा का अभ्यास और महत्व उसके प्रयोग में ही है न कि उसके अध्ययन में। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में तो हिन्दी का प्रयोग होता है, भाषा अधिकांश व्यक्ति हिन्दी समझने हैं, यह प्रश्न पृथक् है कि वे पारस्परिक द्वेष का कारण। स्वयं को हिन्दी से अलग रखना चाहते हैं, परन्तु वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। हमारे रहने का तात्पर्य यह है कि हिन्दी को भारत की सामान्य भाषा मानना है क्योंकि यह राष्ट्रभाषा है, अतः अहिन्दी क्षेत्रों को हिन्दी अनिवार्य होनी चाहिए, न कि हिन्दी भाषियों को कोई अन्य भाषा। जहाँ तक पारस्परिक विचारों का आदान प्रदान का प्रश्न है—हिन्दी के व्यावहारिक ज्ञान से सम्पूर्ण भारत में यह भाषा प्रयोग में लाई जा सकती है और वास्तव में देखा जाये तो इस भाषा में अर्थ भी है।

### हिन्दी भाषी क्षेत्रों में व्यावहारिक कठिनाइयाँ

#### Practical Difficulties in Hindi Speaking Areas

हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अन्य भारतीय भाषाओं को प्रयुक्त करने में कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं जो इस प्रकार हैं :—

- 1) विविधान में उल्लिखित चौदह भाषाओं किस भाषा का अध्ययन कराया जाये? इसके अतिरिक्त यदि विभिन्न छात्र एक ही शाला में विभिन्न भाषाओं का अध्ययन करना चाहें, तो यह किस प्रकार सम्भव है कि उनके लिए इतने अध्यापकों की व्यवस्था की जा सके।
- 2) अन्य भाषाओं के शिक्षण हेतु अध्यापकों की व्यवस्था होना प्रायः असम्भव सा प्रतीत होता है क्योंकि यदि भारतीय भाषाओं के अध्ययन हेतु अध्यापकों की नियुक्ति की जाये तो कम से कम दस हजार अध्यापकों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अध्यापकों के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वे हिन्दी भी जानते हों अन्यथा उनका कोई उपयोग नहीं होगा। इस प्रकार की व्यवस्था निकट भविष्य में तो असम्भव ही प्रतीत होती है।
- 3) उपरोक्त कठिनाईयों के अतिरिक्त सबसे बड़ी कठिनाई आर्थिक है। राज्य सरकारों के पास इतना धन नहीं है कि अन्य महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यों को छोड़कर भाषाओं के अध्यापकों की नियुक्ति की जाये।

1. 2. 3. विद्वत् के अन्व राष्ट्र तो वैज्ञानिक प्रगति पर धन व्यय कर रहे हैं  
 4. 5. और हमारा राष्ट्र भाषा समस्या पर ही इतना व्यय करे, यह उपादेय  
 6. 7. नहीं है।

संपरोक्त आलोचनात्मक मूल्यांकन से यह तो स्पष्ट है कि निभापी मूल को स्वीकार करने में अनेकों कठिनाईयाँ हैं। इसके अतिरिक्त जनता के सम्मुख इसका रूप भी प्रत्यक्ष नहीं है। हमारी अपनी राय में तीन भाषाओं का मिश्रण प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक नहीं होना चाहिए। सामान्य शिक्षा हेतु यही पर्याप्त है कि मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग हो तथा निम्न माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग हो। जहाँ तक अन्तरदेशीय सम्पर्क का प्रश्न है, इसके लिए वह आवश्यक है कि कोई एक सम्पर्क भाषा हो अतः सम्पर्क के रूप में राष्ट्रभाषा का प्रयोग ही उत्तम है। इसलिए उन क्षेत्रों में जहाँ क्षेत्रीय भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, वहाँ राष्ट्रभाषा का मिश्रण प्राथमिक स्तर के समाप्त होने पर कर देना चाहिए। वैज्ञानिक तथा इसके सम्बन्धित शिक्षा हेतु अभी कुछ वर्षों के लिए अंग्रेजी ही प्रयोग करनी है कि अनुसन्धान कार्य जिससे कुछ ही वर्षों में राष्ट्रभाषा या तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की समस्या राष्ट्रभाषा में आ सके। अन्त में हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि भाषाई गुणों को अत्यन्त ही ध्यान से समझना है। सारे भारतवासियों को इसमें सहयोग देना है और देश की भाषाओं को त्याग कर ही भाषाओं का अध्ययन सम्भव है। इस समस्या को इस प्रकार हल नहीं किया जा सकता कि आप कहें 'क्योंकि मेरी एक भाषा फूटी हुई है अतः मैं तो तभी साथ दे सकता हूँ वरन् आप भी अपनी भाषा छोड़ लें।' निभापी मूल भी कुछ इसी प्रकार का है कि जनायास ही भाषाओं के बोझ से बच्चों को भासा जा रहा है। हाँ! यदि तीन भाषाओं के अध्ययन में कोई अचूकता प्राप्त हो तो इसे अवश्य स्वीकार किया जाये अन्यथा तो यही जरूरी है कि तीन भाषाओं का प्रावधान नहीं हो जहाँ आवश्यकता है। राष्ट्रभाषा को विकसित करना सभी भारतवासियों का पुनीत कर्तव्य है—अंग्रेजी के अध्ययन से कोई घृणा नहीं होनी चाहिए—प्रादेशिक भाषाओं का विकास करना चाहिए।

भाषा की शिक्षा (17.05) अंग्रेजी का स्थान

18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 Place of English

अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। अंग्रेजी ने हमारे देश पर करोड़ों लोगों को बर्बर बना दिया, इसी कारण अंग्रेजी हमारी शिक्षा में आई। हमने उसे सीखा, बोला, धीरे-धीरे लिखा अतः हमारे व्यवहार में उसका प्रवेश होना कोई अस्वाभाविक नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अंग्रेजी ने अपनी वृत्तवृत्ति और दूरदर्शिता से अंग्रेजी

रूपी बिप का पौषा भारत में लगाया। समय की गति के साथ वह खूब फूला और फल  
तरा आज बिप बुध के रूप में हमारे देश के अन्तर्गत विद्यमान है। पर  
आज की स्थिति में वह भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रचलित भाषा है  
बुद्धिमानों भी यही है कि वास्तविकता को पहचाना जाये क्योंकि पिछले  
में हमने भाषा के प्रश्न पर सम्पूर्ण भारत में अनुयायनहीनता का नग्न नृत्य देखा  
जिसमें राष्ट्रीय सम्पत्ति को बहुत आघात पहुँचा। अतः अंग्रेजी को कुछ  
समय के लिए अंगीकार करना बहुत आवश्यक है।

प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी की कोई आवश्यकता नहीं है। माध्यमिक  
स्तर पर इसका सामान्य ज्ञान ही बहुत है। विश्वविद्यालय स्तर पर अंग्रेजी  
को उस समय तक स्थान दिया जाये जब तक प्रादेशिक भाषाएँ सक्षम नहीं हो  
पड़ी। अंग्रेजी के स्तर को बनाये रखने का यथासम्भव प्रयत्न किया जाये क्योंकि  
अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है और आधुनिक ज्ञान के विस्तृत साधन भण्डार के  
द्वितीय से इसके पास उत्तम सम्पत्ति है।

अंग्रेजी के स्थान को निश्चित करने के लिए यह निश्चित आवश्यक है  
: हम विभिन्न आयोगों के मुझकों को भी देखें जिसमें वर्तमान स्थिति में इस  
भाषा की कसौटी पर कसा जा सके।

### माध्यमिक शिक्षा आयोग और अंग्रेजी

#### Secondary Education Commission and English

आयोग ने स्पष्ट किया कि सभी राज्यों में अंग्रेजी माध्यमिक स्तर तक  
नेवार्थ विषय के रूप में स्वीकार की है अतः भविष्य में भी इसे यह स्थान  
दिया जाना चाहिए। अंग्रेजी के पक्ष में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये:—

1. अंग्रेजी देश के लिखित लोगों की सार्वभौम भाषा है।
2. अंग्रेजी ने भारत में सार्वजनिक तथा अन्य क्षेत्रों में एकता हेतु बहुत  
महत्वपूर्ण कार्य किया है।
3. अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत ने जो स्थिति प्राप्त की है वह अंग्रेजी  
ज्ञान प्राप्त लिखित भारतीयों के कारण है।
4. अनेकों शिक्षा-कारिग्र्यों और वैज्ञानिकों के अनुसार अंग्रेजी का ज्ञान  
निश्चित आवश्यक है और इसके ज्ञान को किसी भी प्रकार नहीं त्याग  
जा सकता।
5. यदि राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर अंग्रेजी को माध्यमिक स्तर के  
पाठ्यक्रम से निकाला गया तो इसके परिणाम भारत के लिए हानिकार  
प्रमाणित होंगे।



माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव परिलक्ष अनुभव पर आधारित है । आयोग ने स्वयं स्वीकार किया है कि कुछ लोगों का मत है कि अंग्रेजी को अत्यधिक महत्व देने के कारण भारतीय भाषाओं की बहुत क्षति हुई है अतः इसे वह स्थान न दिया जाये जो स्वतन्त्रता से पूर्व प्राप्त था । -

1. शिक्षा आयोग और अंग्रेजी

1.3 Education Commission & English

1.3.1 कोठारी आयोग ने अखिल भारतीय शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी को 'शिक्षा माध्यम' के रूप में बनाये रखने पर बल दिया है । आयोग के 'मतानुसार' अंग्रेजी का अध्ययन माध्यमिक स्तर से ही हो जाना चाहिए । उत्तम स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अन्तर्राष्ट्रीय अनुसन्धान कार्य के लिए छात्र महाविद्यालयों को विकसित किया जाये जिससे शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होनी चाहिए । इन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों में से चुना जाये ।

उपरोक्त दो महत्वपूर्ण आयोगों के सुझावों पर दृष्टिपात करने के पश्चात् यह अनिवार्य है कि हम राष्ट्रीय नीति के सदर्भ में अंग्रेजी के स्थान को हल करें । राजकीय भाषा (संशोधन) अधिनियम<sup>1</sup> (1967) लोकसभा में 27 नवम्बर 1967 को पारित हुआ । लोकसभा द्वारा संशोधित बिल राज्यसभा द्वारा 11 दिसम्बर, 1967 को पारित हुआ । इस बिल में स्पष्ट किया गया कि अंग्रेजी 'सहायक अतिरिक्त भाषा' के रूप में रहेगी । इसके अतिरिक्त में यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि संविधान में वर्णित राजभाषा हिन्दी ही है । परन्तु अभी हमारे देश में किन्हीं राज्यों के कुछ लोग इस प्रकार के हैं जो अभी अंग्रेजी को ही चलाना चाहते हैं, अतः यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उन्हें समझें और उनके साथ समायोजित हों जिससे हिन्दी, हमारे देश की राजभाषा हो सके ।

अतः मैं हम यह कहते हैं कि अंग्रेजी का अविव्य सहायक भाषा के रूप में रहेगा । प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी की कोई आवश्यकता नहीं है । माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान ही पर्याप्त है । उच्च स्तर पर कुछ समय के लिये अंग्रेजी को रखा जाये और इसी बीच में प्रादेशिक भाषाओं को माध्यम के रूप में अपनाया जाये ।

अन्ततोयत्वा हम यह कहते हैं कि प्रायः ससार के सभी देशों ने भाषा समस्या का किसी न प्रकार से हल किया है परन्तु हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम इस समस्या को अभी तक नहीं सुलभ पाये हैं । स्वतन्त्रता प्राप्ति के 22 वर्ष पश्चात्

भी हम अंग्रेजी की जड़ों को खींचने में सक्षम हुए हैं। यद्यपि यह निश्चित है कि हिन्दी अंग्रेजी का एक दम स्थान नहीं ले सकती तथापि हमें इसके लिए कुछ करना ही होगा।

यह निश्चित है कि अंग्रेजी को अब अधिक समय तक सम्पर्क भाषा बनाकर नहीं रक्खा जा सकता क्योंकि यह देश के अधिकांश निवासियों की भाषा नहीं है। जो लोग अब भी अंग्रेजी के वृक्ष को हरा-भरा देखना चाहते हैं। वे स्वयं को तो अधिकार में डाल रहे हैं साथ ही समस्त देश को भी उसी अधिकार में ले जाना चाहते हैं और अब भी वे देश को अपनी भाषा पर गुलामी का चदमा लगा कर देखते हैं। हिन्दी ही निकट भविष्य में देश की सम्पर्क भाषा बनेगी क्योंकि यह सभ की राजकीय भाषा है।

---

## ग्रन्थ-सूची Bibliography

1. Avinashlingam, T. S.,  
*Gandhi's Thoughts on Education*, Ministry of Education,  
New Delhi, 1958
2. Basu, A. H.  
*'In what Language shall we teach at our Universities,'*  
*The Education Quarterly*, March 1956, New Delhi.
3. *Hindustan Varshiki*, (1968-69)  
Hindustan Samachar, Mandi House, New Delhi.
4. Parulekar, R. V.  
*The Medium of Instruction*, Parulekar Memorial Committee,  
Bombay.
5. *Report of University Education Commission*,  
Ministry of Education, Govt. of India, 1949
6. *Report of Secondary Education Commission*,  
Ministry of Education, Govt. of India, 1953
7. *Report of Education Commission*,  
Ministry of Education, Govt. of India, 1964
8. *Report of Official Language Commission*,  
Govt. of India, 1957
9. *The Official Language (Amendment) Act, 1967*  
Ministry of Information & Broadcasting, Govt. of India,  
(200, 1968)

# विद्यार्थिप्रश्नोत्तर

## University Questions

1. Express your views on the Language Problem in India. How far can we benefit ourselves the way other countries have solved their problems?

(Rajasthan, 1962)

2. How . . . . .  
the Secretary.  
What is the place of English in . . . . .  
place Hindi to (a) Madras b) U P ?

(Rajasthan, 1961)

3. Write short notes on—

The Third Language—a political artifice or an educational

need?

(Rajasthan, 1961)

4. What is your opinion of the three language formula? How is it working in actual practice? Would you recommend any change in its form and implementation in future?

संस्थान में प्रवेश किये गये विद्यार्थी मूल के सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं? यह पाठ्यक्रम क्या है 'किस प्रकार कार्य कर रहा है'? अन्तिम में इसके रूप एवं परिणामों में परिवर्तन के लिए आपके क्या सुझाव हैं।

5. How far are the suggestion of Kothari Commission in regard to teaching of languages clear and in keeping with constitutional obligations?

भाषाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में कोटारी आयोग के सुझाव कहीं तक स्पष्ट हैं और संविधानिक दायित्वों के अनुरूप हैं?

(उत्तराखण्ड, 1968)

## अध्याय अठ्ठाईस

### Chapter Eighteenth

#### पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण

#### Nationalization of Text Books

##### अध्ययन बिन्दु

##### Learning Points

- 18.01 पाठ्य-पुस्तकों का महत्व  
Importance of Text Books
- 18.02 पाठ्य-पुस्तकों के दोष  
Defects of Existing Text Books
1. मूल्य दोष
  2. वांछित विषयों का अभाव
  3. प्रकाशकों की लोभी प्रवृत्ति
  4. अवांछनीय संस्थापकों का प्रयोग
  5. विषय से सम्बन्धित दोष
- 18.03 पाठ्य-पुस्तकों के सुधार हेतु सुझाव  
Suggestions for the Improvement of Text Books
1. आचार्य नरेन्द्र देव समिति प्रतिवेदन (1953)
  2. माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953) के सुझाव  
सुझावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन
  3. कोटारी आयोग (1966) के सुझाव  
आलोचनात्मक मूल्यांकन
- 18.04 पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण क्यों ?  
Why Nationalization of Text Books
- 18.05 पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण में उत्पन्न समस्याएँ  
Problems by Nationalization of Text Books
1. प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्तों के विरुद्ध
  2. राजनैतिक प्रचार की सम्भावना

3. ଅବସ୍ଥା କି ହୋଇ

4. ବିକାଶ କି ସମ୍ଭାବ

5. ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଦ୍ଵାରା କି ସ୍ଵାଦ କି ମ'ସାଦ

6. ଚେତନା କି ଦୁଃଖ ଚେତନା

18.06 ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କି ଦୁଃଖ କି ଦୁଃଖ  
Agreement for the Improvement of National  
Test Bank

18.07 ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର  
Nationalization of Test Bank in Hospitals

18.08 ଶେଷ  
Conclusion

---

## पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण *NATIONALIZATION OF TEXT BOOKS*

शिक्षा स्वयं में एक प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक निरन्तर एवं अबाध गति से सक्रिय रहती है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य निर्जीव है—शिक्षा की प्राप्ति से वह सजीव है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य जन्म से स्वयं को प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक बाधाकरण के प्रति समायोजित करने का प्रयत्न करता है। संक्षेप में शिक्षा मानव की पक्ष-प्रदर्शनी है जो भौतिक क्षेत्र में सांसारिक सुख एवं ऐश्वर्य प्रदान करती है और आध्यात्मिक क्षेत्र में मुक्ति प्रदान करती है जिसका आकार होता है—ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। पूर्व ज्ञान के कोष को सुरक्षित रखना निरन्तर आवश्यक है जिससे ज्ञान और अज्ञान की परख की जा सके तथा ज्ञान को भावी पीढ़ी तक सुरक्षित तौर पर पहुँचाया जा सके। इसके लिए साधन की आवश्यकता होती है और वह साधन है पाठ्य पुस्तक।

### 18.01 पाठ्य-पुस्तकों का महत्व *Importance of Text Books*

प्रायः समय में पाठ्य पुस्तकें प्राचीन रहा हो अथवा वर्तमान पाठ्य-पुस्तक किसी न किसी रूप में अव्यय रही हैं। प्राचीन भारत के भोज-यज्ञ अथवा ताम्र-यज्ञ, वेद कान के चित्र, आदि की पुस्तकें आदि मानवीय अभिव्यक्ति का साधन रही हैं। पाठ्य-पुस्तकों द्वारा सचित ज्ञान सभी वर्गों तक भावी पीढ़ी को प्रदान की जाती है जो

भावी समाज की रचना हेतु पथ प्रदर्शिका के रूप में कार्य करती । पाठ्य पुस्तक के स्तर से शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है । उत्तम पाठ्य-पुस्तकों द्वारा वांछित रुचि, बौद्धिक योग्यता, अभिवृत्ति आदि को विकसित किया जाता है । मानव के जीवन को सन्तुलित राँचे में ढालने का कार्य और उसमें अच्छे सस्कार उत्पन्न करना का कार्य पाठ्य-पुस्तकों का ही होता है । अतः सम्पूर्ण समाज का सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विकास पाठ्य पुस्तकों के पुण्डो पर अवलम्बित होता हुआ घरोघर के रूप में भावी सन्तति के पास पहुँचता है और इस प्रकार सम्पूर्ण मानव जाति को लाभान्वित करता है ।

पाठ्य-पुस्तक सम्पूर्ण शिक्षा प्रक्रिया की आधार तिता है जो बालको में अन्तर्दृष्टि और ज्ञान के प्रति अनुराग उत्पन्न करती है । अध्यापक के लिए इसकी विशेष महत्ता है क्योंकि इसकी सहायता से वह अध्यापन में दक्षता प्राप्त करता है । शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में पाठ्य-पुस्तकें बहुत सहायक होती हैं—इन्हीं की सहायता से हम विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम का अभ्ययन करते हैं । अन्त में पाठ्य-पुस्तकों का सभी दृष्टियों से महत्त्व है, अतः उनमें आवश्यक सुधार लाना नितांत अनिवार्य है ।

### 18 02 पाठ्य-पुस्तकों के दोष

#### Defects of Existing Text Books

पाठ्य-पुस्तकों का स्तर बहुत ही गिर गया है । माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी पाठ्य-पुस्तकों के निम्न स्तर पर गेद प्रकट किया था । संक्षेप में पाठ्य-पुस्तकों में निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं—



दोष देना व्यर्थ है क्योंकि प्रकाशित पाठ्य-पुस्तक की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति तो पाठ्य-पुस्तकों से सम्बन्धित समिति पर निर्भर करती है। पाठ्य-पुस्तक समिति के सदस्य प्रकाशकों द्वारा खरीद लिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाशकों द्वारा निम्न स्तर की कुछ पुस्तकें विद्या के पुनीत कार्य-क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं जिसके कारण विद्यार्थियों के ज्ञान में अभिवृद्धि होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

#### 4 अवाछनीय शब्दावली का प्रयोग

##### *Use of Undesirable Terminology*

इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमें राष्ट्रभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द भंडार की अभिवृद्धि करनी है, परन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि हम पाठ्य-पुस्तकों में इस प्रकार के कठिन शब्दों का प्रयोग करें जो विद्यार्थियों को विषय वस्तु समझने में कठिनाई उपस्थित कर दें। प्रादेशिक भाषाओं में छापी पुस्तकों का तो हमें ज्ञान नहीं है परन्तु हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों में प्रायः यह दोष दृष्टिगत होता है। हमें विद्यार्थियों के सम्मुख उनकी दैनिक जीवन की भाषा में विषय सामग्री परोसनी है न कि भयंकर शब्दावली का प्रयोग कर अपनी विद्वता का टका बचाना है। हमारे दैनिक जीवन में कुछ शब्द इस प्रकार के हैं जो अज्ञेयी भाषा से लिये गये हैं, अतः यदि उन्हीं शब्दों को देवनागरी लिपि में प्रयोग किया जाये तो हममें कोई हानि नहीं है। शब्द की आत्मा उसके अर्थ में है अर्थ में नहीं।

#### 5 विषय-वस्तु से सम्बन्धित दोष

##### *Defects Concerning Subject Matter*

पाठ्य-पुस्तक शैक्षिक जीवन की पथ प्रदर्शिका है, परन्तु यदि पथ प्रदर्शक ही भ्रष्ट हो जाय तो गलत दिशा में अथवा अज्ञान की ओर अग्रसर होता स्वाभाविक है। आज माध्यमिक स्तर पर अनेकों पाठ्य पुस्तकें इसी प्रकार की हैं जिनमें विषय वस्तु सम्बन्धी अनेकों दोष हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि पाठ्य-पुस्तकों के लिखते समय स्वीकृत पुस्तकों को नहीं देखा जाता, इसके अतिरिक्त पुराने तथ्यों को प्रदर्शित किया जाता है, कुछ पुस्तकों को राष्ट्रीय एकता के बोधक तथ्यों से दूर रखा जाता है, कहने का तात्पर्य यह है कि विषय वस्तु की दृष्टि से पाठ्य-पुस्तकों में अनेकों कमियाँ हैं जिससे शैक्षिक स्तर घटने, घटने: गिर रहा है।

उपरोक्त दोषों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पाठ्य-पुस्तकों में सुधार की आवश्यकता है। समय समय पर जितने आयोग और समितियाँ नियुक्त की गईं, उन्होंने पाठ्य-पुस्तकों के सुधार हेतु आवश्यक सुझाव दिये।

#### 18.03 पाठ्य-पुस्तकों के सुधार हेतु सुझाव

##### *Suggestions for the Improvement of Text Books*

पाठ्य-पुस्तकों के विरते हुए स्तर पर समय समय पर आवश्यक सुझाव दिये

1. स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् विभिन्न समितियों, सम्मेलनों तथा आयोगों ने ध्यान केंद्रित कराया जिनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है—

# 1. आचार्य नरेन्द्रदेव समिति प्रतिवेदन (1953) Report of Acharya Narendar Deva Committee (1953)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सर्वप्रथम इस समिति ने पाठ्य-पुस्तकों का अध्य-  
यन किया और सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये—

- (अ) पाठ्य पुस्तकों की स्वीकृति हेतु शाला के प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों को उचित पाठ्य-पुस्तकें चयन करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए ।
- (ब) एक बार स्वीकृत पाठ्य-पुस्तक का न्यूनतम कार्यकाल तीन वर्ष होना चाहिए ।
- (स) पुस्तक लेखन हेतु लेखकों को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए ।
- (द) लेखकों को पुस्तक लेखन हेतु उचित धन दिया जाना चाहिए ।

# 2. माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953) के सुझाव Suggestions of Secondary Education Commission (1953)

माध्यमिक शिक्षा आयोग<sup>1</sup> ने पाठ्य-पुस्तकों के निरले हुए स्तर पर खेद प्रकट किया और पाठ्य-पुस्तकों में निम्नलिखित दोष बताये—

1. पाठ्य-पुस्तकों की सामग्री विद्यार्थियों की रुचि और योग्यता के अनुसार नहीं होती ।
2. पाठ्य-पुस्तकों का सूजन इवाई के अनुसार नहीं होता जिससे एक पाठ्य-पुस्तक दो-तीन वर्षों तक उपयोग नहीं रह पाता ।
3. पाठ्य-पुस्तकों की छपाई अमशोषजनक होती है जिसके कारण विद्यार्थी पुनः उनके प्रति निरुत्सुक हो जाते हैं ।
4. पाठ्य-पुस्तकों में चित्र और रेखाचित्र उपयुक्त नहीं होते और उन्हें गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है ।

1. Most of the books submitted and prescribed are poor specimens in every way—the paper is usually bad, the printing is unsatisfactory, the illustrations are poor and there are numerous printing mistakes. If such books are placed in the hands of the students it is idle to expect that they would acquire any love for books or find interest in them or experience the joy that comes from handling an attractive, well-produced publication.

6. इन पुस्तकों में केवल तथ्यों की प्रधानता होती है और समस्त सामग्री को सविपूर्ण रूप से नहीं संजोया जाता ।
7. प्रायः पाठ्य-पुस्तकों के लेखक ज्ञाना परिस्थितियों से अनभिज्ञ होते हैं जिसके कारण ये पुस्तकें वाछित व्यवहार परिवर्तन करने में असमर्थ रहती हैं और अध्यापकों की शिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती ।
8. पाठ्य-पुस्तकें प्रजाताम्रिक सिद्धान्तों, राष्ट्रीय भावात्मक एकता और अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना से शून्य होती हैं जिसके कारण वाछित उप-सम्बन्धियाँ प्राप्त नहीं हो पाती ।
9. अनेक पाठ्य-पुस्तक समितियाँ निष्पक्ष भाव से पाठ्य-पुस्तकों का चयन नहीं करतीं जिसके कारण निम्न स्तर की पुस्तकों को निरर्थक रूप से सहयोग प्राप्त हो जाता है ।
10. शिक्षा का मध्यम प्राथमिक भाषाई हो जाने के कारण पाठ्य-पुस्तकों के लेख और प्रकाशन में स्पष्टा समाप्त हो गई है क्योंकि लेखकों और प्रकाशकों की संख्या कम हो जाने से साधन सीमित हो गये हैं ।

मार्थमिक शिक्षा आयोग ने समस्त दोषों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिये जो निम्नलिखित हैं —

1. प्रत्येक राज्य में एक 'शिक्षाशाली पाठ्य-पुस्तक समिति' होनी चाहिए जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष होना चाहिए और उसे कार्य करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए ।
2. 'शिक्षाशाली पाठ्य-पुस्तक समिति' में सात सदस्य रखे जायें जिसका गठन इस प्रकार हो —

* हाईकोर्ट का जज	1
* लोक सेवा आयोग का सदस्य	1
* राज्य के किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति	1
* प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका	1
* प्रसिद्ध शिक्षा धात्री	2
* शिक्षा संचालक	1

उपरोक्त समिति को अपलिखित कार्य सौंपे गये—

- (1) प्रत्येक विषय की पाठ्य-पुस्तकों का विवेचन करने हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति करना ।
- (2) पाठ्य-पुस्तकों में सुजन हेतु विशेषज्ञ विद्वानों को निमन्त्रित करना ।

आयोग ने उपरोक्त दोषों को दृष्टिगत रखते हुए पाठ्य-पुस्तकों सम्बन्धी निम्नलिखित सुझाव दिये :—

1. पाठ्य-पुस्तकों की दशा सुधारने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम बनाया जाये और प्रतिमासान लेखकों को पुस्तकों के सृजन हेतु प्रोत्साहित किया जाये ।

2. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् (National Council of Educational Research & Training) के सिद्धान्त एवं कार्य योजना के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी पाठ्य-पुस्तकों की दशा सुधारने हेतु कार्य हो ।

3. पाठ्य-पुस्तकों के उत्पादन को शिक्षा मन्त्रालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य स्वीकार करना चाहिए और इसके लिए स्वायत्त संगठन (Autonomous Organization) की स्थापना करनी चाहिए ।

4. प्रदेश राज्य में पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए प्रत्येक रूप से विशेष समितियों की नियुक्ति होनी चाहिए ।

5. पाठ्य-पुस्तकों की तैयारी और मूल्यांकन का समस्त भार राज्य के शिक्षा विभाग का होना चाहिए

6. पाठ्य-पुस्तकों के बेचने के लिए छात्रों के सहयोगी मण्डल होने चाहिए ।

7. पाठ्य-पुस्तकों का उत्पादन एक निरन्तर प्रक्रिया है अतः पाठ्य-पुस्तकों के परिवर्द्धित संस्करण सामयिक रूप से समयानुसार निकलने चाहिए ।

8. राज्य द्वारा पाठ्य-पुस्तकों के सृजन में योग्य लेखक आकर्षित नहीं होते क्योंकि राज्य द्वारा उदार पारिश्रमिक नहीं दिया जाता और यही कारण है कि निजी कार्य (Private Enterprise) राजकीय कार्य पर विजय प्राप्त कर लेता है । अतः यह आवश्यक है कि प्राइवेट कार्य की तुलना में राज्य द्वारा अधिक उदार पारिश्रमिक की व्यवस्था हो जिससे अच्छे लेखकगण आकर्षित हो सकें ।

9. प्रत्येक विषय में कम से कम तीन या चार पाठ्य-पुस्तकें होनी चाहिए और छात्रों की आवश्यकतानुसार अभ्यासों को किसी भी पुस्तक का अंग बनाने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए ।

10. पाठ्य-पुस्तकों का उत्पादन लाभ के आधार पर होना चाहिए, इसका एक मात्र उद्देश्य अच्छी पुस्तकों का सृजन होना चाहिए जिससे कम कीमत पर पुस्तकें प्राप्त हो सकें ।

11. पाठ्य-पुस्तकों पर केवल मात्र पाच रुपये की छूट करने से सम्बन्धित अनुसन्धान शिक्षक निर्देशिकाएँ (Teachers' Guides) तथा सहायक सामग्री

(Ancillary aids) पर धन व्यय किया जा सकता है और शिक्षक निर्देशिकाओं एवं अन्य शिक्षण सामग्री द्वारा पाठ्य-पुस्तकों को पूर्ण हो सकती है।

12. पाठ्य-पुस्तकों के सुजन हेतु अधिकाधिक रुचि उत्पन्न करने के लिए योग्य व्यक्तियों से पाठ्यलिपियाँ प्राप्त की जानी चाहिये और लेखकों से उचित प्रयत्न करने के पश्चात् पुस्तकों का प्रकाशन करना चाहिये।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

7 Critical Evaluation

विद्या-आयोग (1964-66) के मसौदा मुद्दों पर विचार करने के पश्चात् यह अवश्य कहा जा सकता है कि पाठ्य पुस्तकों के लिए राष्ट्रीय स्तर निर्दिष्ट कार्यक्रम की कल्पना बनाना नितांत आवश्यक है। केन्द्रीय स्तर पर कार्य सम्पादित करने से पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हो जायेगा, क्या इस कार्यक्रम से निजी कार्य (Private Enterprise) हतोत्साहित नहीं होगा? क्या पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण से समस्त देश में एक रूपता आना सम्भव है? क्या केन्द्रीय सरकार अपना राज्य सरकार सम्पूर्ण उत्तरदायित्वों को निभाने में सक्षम हो सकेगी? क्या पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण से प्रतियोगिता की भावना को क्षति नहीं पहुँचेगी? क्या इस प्रकार सृजनात्मक कार्य सम्भव हो सकेगा?

ये कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर प्राप्त होना नितांत आवश्यक है। परन्तु इन समस्त प्रश्नों का अर्थ यह नहीं कि पाठ्य-पुस्तकों के आधार हेतु सरकार कुछ भी न करे। बाहिर पाठ्य-पुस्तकों का सम्पूर्ण कार्यभार तो सरकार को ही वहन करना होगा, परन्तु इसके लिए पर्याप्त कार्यक्रम बनाना नितांत आवश्यक है।

### 18. पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण क्यों?

Why Nationalization of Text Books

विद्यते दो सम्प्रदाय विद्वानों में हमने प्रचलित पाठ्य-पुस्तकों के दोषों और उनके सुधार हेतु आवश्यक मुद्दों पर विविध चर्चा की है। पाठ्य-पुस्तकों से सम्बन्धित अनेकों मुद्दों में से सामयिक विद्या-आयोग तथा कोटारी आयोग के कुछ मुद्दों पाठ्यपुस्तकों के राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित भी थे। अतः प्रश्न उपस्थित होता है कि पाठ्यपुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की क्या आवश्यकता है? क्या राष्ट्रीयकरण ही सम्बन्धित समस्याओं का समाधान है? यदि निम्नलिखित किन्तुओं के सहर्ष में इन प्रश्नों का समाधान हो जाय तो निश्चित ही राष्ट्रीयकरण एक मात्र हल है—

1. स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमने प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति की अपनाया जिसका एकमात्र उद्देश्य सम्पूर्ण जनता को समान अवसर प्रदान करना था। यह सभी सम्भव था जबकि हम जन जीवन के हृदय में



नहीं कहा जा सकता। सरकार को चाहिए कि वह नवीन पद्धति द्वारा पाठ्यपुस्तकों की रचना हेतु लेखकों को प्रशिक्षण दे और स्वयं ही प्रकाशित कराये। कुछ राज्यों में जहाँ पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है वहाँ स्थिति में काफी सुधार आया है।

4. आज का युव आर्थिक युग है और आर्थिक सहायता को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हमें यह प्रयास करना है कि इस आर्थिक युग में अवांछनीय रूप से पैसा न कमाया जाये क्योंकि इससे भ्रष्टाचार और अनैतिकता का जन्म होता है। अनेकों राज्यों में पाठ्यपुस्तकों को स्वीकृत करने की प्रणाली बहुत दोषपूर्ण थी और जहाँ पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है वहाँ अब भी है। प्रकाशकों द्वारा पाठ्यपुस्तक-समिति के सदस्यों को अनुचित रूप से छान पट्टाया जाता है जिसके कारण निम्न स्तर की पुस्तकें स्वीकृत हो जाती हैं। अतः आवश्यक है कि सरकार स्वयं ही पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन करे।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर कहा जा सकता है कि पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीयकरण समय की माँग के अनुसार है। परन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण से एक आदर्श पद्धति की स्थापना हो सकेगी, इतना अवश्य है कि उससे कुछ समस्याओं का समाधान अवश्य हुआ है तथापि कुछ समस्याएँ आज भी विद्यमान हैं।

### 18.05 पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न समस्याएँ

#### Problems by Nationalization of Text-Books

पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया कि जो समस्याएँ इस क्षेत्र में उत्पन्न हो गई हैं, उनका समाधान हो सकेगा। दुर्भाग्यवश उद्देश्य की प्राप्ति उक्त रूप में नहीं हो सकी है जितनी आशा थी। संक्षेप में पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण से निम्नलिखित समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं—

#### 1. प्रजातन्त्रतात्मक सिद्धान्तों के विरुद्ध

##### Against Democratic Principles

पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। जनतन्त्र में विचारों की विविधता होती है जो पाठ्य-पुस्तकों के रूप में अभिव्यक्त होती है और जिसके द्वारा सभ्यता का विकास होता है। पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण से पुस्तकों की विविधता समाप्त हो जाती है जिसके फलस्वरूप वैचारिक विविधता से लाभ प्राप्त नहीं हो पाता।

## 2. राजनैतिक प्रचार की सम्भावना

### Possibility of Political Propaganda

राष्ट्र-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण से यह भय रहता है कि कहीं सत्ताशुद्ध दल पुस्तकों को अपनी विचारधारा के प्रसार का माध्यम न बना लें। अपरिपक्व अवस्था के बालकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना रहती है। प्रजातन्त्रात्मक शासन पद्धति में यह बहुत अनिवार्य है कि सत्ता को राजनीति से अलग रखा जाये।

### 3. प्रकाशन में विलम्ब

#### Late Publication

राष्ट्र-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् प्रायः यह देखा गया है कि पुस्तकें समय पर प्रकाशित नहीं होती। कभी-कभी तो यह देखने में आया है कि वार्षिक परीक्षाओं के समीप पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। प्रकाशन में विलम्ब होने के मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण हैं :—

- (क) सरकार के पास मुद्रण सम्बन्धी साधनों की कमी रहती है अतः इसके लिए उन्हें अन्य मुद्रकों पर अवलम्बित रहना पड़ता है।
- (ख) धन प्राप्त करने के लिए वित्त विभाग की अनुपति आवश्यक होती है और वित्त विभाग में कठोर नियमों के कारण बड़ी कठिनाई से धन प्राप्त होता है, अतः प्रकाशन में विलम्ब होना स्वाभाविक है।
- (ग) प्रायः ऐसा देखा गया है कि सरकारी कार्यों में कर्मचारी यदि से कार्य नहीं करते। राष्ट्र-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भी ऐसा ही हुआ है।

### 4. वितरण की समस्या

#### Problem of Distribution

कभी-कभी पुस्तकें प्रकाशित तो हो जाती हैं परन्तु सरकार की उचित वितरण व्यवस्था के न होने के कारण पुस्तकें निरर्थक पड़ी रहती हैं। जब सरकार पुस्तक विन्नेताओं की सहायता मांगती है तो वे भीर बाजारी करते हैं जिससे छात्रों को अधिक मूल्य पर पुस्तकें खरीदनी पड़ती हैं। कोटवारी आयोग ने इन समस्या के समाधान हेतु छान सहायरी समितियों की स्थापना का सुझाव दिया है।

### 5. राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के मूल्य में अधिकता

#### Excess Prices of Nationalised Books

राष्ट्र-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण का एक उद्देश्य उनके मूल्यों में कमी करना था, परन्तु वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में शारंगारिक हार्ड के कारण मूल्य कुछ उच्च हो गये हैं। वे परन्तु सरकारी नियमन



से स्वस्थ स्पर्धा समाप्त हो गई है और मूल्यों में कमी का सिद्धान्त प्रायः समाप्त हो गया है जो अवांछनीय है।

#### 6. लेखकों पर बुरा प्रभाव

##### Reverse Effect on Writers

पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण का लेखकों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रीयकरण से पूर्व विभिन्न लेखकों की विविध पुस्तकें प्रकाशित होती थी और प्रत्येक लेखक सर्वोत्तम पुस्तक लिखने का प्रयास करता था, परन्तु राष्ट्रीयकरण से लेखकों का उत्साह प्रायः समाप्त हो गया है जिससे विचारों की अभिव्यक्ति को हानि पहुँची है।

#### 10.08 राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों के सुधार हेतु सुझाव

##### Suggestion for the Improvement of Nationalised Text Books

प्रायः पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन की दो ही विधियाँ हैं, प्रथम विभिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रकाशन-द्वितीय सरकार द्वारा प्रकाशन। दोनों ही विधियों के कुछ लाभ हैं और कुछ हानियाँ। जो विद्या-घारणी पुस्तकों के प्रकाशन में स्वतन्त्रता चाहते हैं वे राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध हैं, कुछ विद्या-घारणी इसके विपरीत हैं। पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे किसी विचारधारा विशेष का प्रोत्साहन नहीं था बल्कि इसका मूल उद्देश्य पाठ्य-पुस्तकों के स्तर को ऊँचा करके सर्वसाधारण को वैश्विक सुविधाएँ प्रदान करना था। अब हमारी सम्मति में यही उचित है कि पाठ्य-पुस्तकों की राष्ट्रीयकरण नीति में कुछ आवश्यक सुधार लाये जायें जिनका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

1. पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन, मुद्रण तथा लेखन से सम्बन्धित अनुसंधान की व्यवस्था सरकार स्वयं करे।
2. पुस्तक लेखन हेतु अच्छे लेखकों को प्रोत्साहित किया जाये और अधिक पारिश्रमिक दिया जाये।

एक बार स्वीकृत पाठ्य-पुस्तक को कम से कम तीन वर्ष तक परिवर्तित न किया जाये।

विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को पाठ्य-पुस्तकों के चयन की स्वतन्त्रता दी जाये और इसके लिए आवश्यक है कि सरकार एक नियम कम से कम पुस्तकें प्रकाशित करें।

सरकार लेखकों की सूची तैयार करे और लेखन हेतु आवश्यक प्रदान करे।

6. पाठ्य-पुस्तकों को राजनैतिक प्रचार का केन्द्र बिन्दु न बनाया जाये। सरकार को चाहिए कि इससे सम्बन्धित सभी प्रकार की सावधानी बरती जाये जिससे हमारे देश में प्रजातन्त्र की नींव अधिक गहरी हो सके और बालकों को स्वतन्त्र चिन्तन के अवसर प्राप्त हो सकें।
7. सरकार को चाहिए की वह पाठ्य-पुस्तकों का मुद्रण स्वयं करे। इसके लिए आवश्यक है सरकारी प्रेसों की व्यवस्था की जाये।
8. प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकों में होने वाली सामान्य त्रुटियों को समाप्त किया जाये। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश की पाठ्य-पुस्तकों में इतनी गलतियाँ होती हैं कि विद्यार्थियों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जबकि विदेशों में प्रकाशित बड़े, प्रयोगों में एक भी त्रुटि नहीं होती। इससे स्पष्ट है कि हम अपने व्यवसाय के प्रति अकर्मण्य हैं। सरकार को चाहिए कि राष्ट्रीयकृत पुस्तकों द्वारा आदर्श स्वरूप प्रदान करे जिससे अन्य प्रकाशकों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ सके।
- राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों के वितरण हेतु यह बहुत आवश्यक है उनका प्रकाशन निर्धारित समय से पूर्व हो और वितरण व्यवस्था उत्तम हो। उचित वितरण व्यवस्था के लिए कोठारी आयोग के सुझाव-नुसार छात्र सहकारी समितियों की स्थापना उत्तम रहेगी जिससे बाला बाजारी को रोका जा सकता है।

उक्त सुझावों के तदर्थ में हमारे सम्पूर्ण विवेचन का उद्देश्य यही है कि पाठ्य-पुस्तकों का आदर्शमय स्वरूप उपस्थित करना चाहिए क्योंकि लेखकों द्वारा लिखी गई उत्तम पाठ्य-पुस्तकें विद्यार्थियों की रचियों की हैं और अध्यापकों को अपने व्यवसाय के प्रति अधिक सचेत करती हैं।

### 18.07 राजस्थान में पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण Nationalization of Text-Books in Rajasthan

कि हम अध्ययन बिन्दु 18.03 में स्पष्ट कर चुके हैं कि कुछ राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा और केरल में आंशिक पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। इसी प्रकार सन् 1954 में सरकार ने भी पहली बार आठवीं कक्षा तक की पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीय-कृत है। सन् 1954 में राष्ट्रीयकरण पाठ्य-पुस्तक परिषद् की स्थापना की समय हमारे राज्य में पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण का स्वरूप इस

### 1. शक्तिशाली पाठ्य-पुस्तक समिति

#### High Power Text Book Committee

माध्यमिक शिक्षा आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव के अनुसार राजस्थान में शक्तिशाली पाठ्य-पुस्तक समिति की स्थापना की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं—

- ( I ) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश,
- ( II ) राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य,
- (III) राष्ट्रीयकरण बोर्ड का अध्यक्ष ।

### 2 राष्ट्रीयकरण बोर्ड

#### Nationalization Board

राष्ट्रीयकरण बोर्ड का संगठन इस प्रकार है—

- ( I ) शिक्षा सचालक,
- ( II ) राजस्व बोर्ड का अध्यक्ष,
- (III) वित्त विभाग का उपसचिव,
- (IV) शिक्षा विभाग का सचिव,
- ( V ) उपाध्याय सचालक अथवा सहायक अध्यापक ।

### 3. अन्य व्यवस्थाएँ

#### Other Arrangements

विभिन्न विषयों पर लेखकों से पाठ्यनियमों आमन्त्रित की जाती हैं तत्परचात् समस्त पाठ्यनियमों समीक्षा हेतु समीक्षकों के पास भेजी जाती हैं। सभी समीक्षक अपना प्रतिवेदन मुख्य समीक्षक के पास प्रेषित करते हैं। मुख्य समीक्षक सभी समीक्षाओं के सम्पन्न के पश्चात् पाठ्यनियमों को राष्ट्रीयकरण बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, जो भी निर्णय होता है उसे 'शक्तिशाली पाठ्य-पुस्तक समिति' के पास भेजा जाता है।

उपरोक्त सभी औपचारिकताओं और व्यवस्थाओं के पश्चात् स्वीकृत पाठ्य-लिपि को मुद्रण हेतु भेज दिया जाता है। अन्त में प्रकाशित पाठ्य-पुस्तक को आवश्यकानुसार वितरित किया जाता है।

### 18.08 निष्कर्ष

#### Conclusion

हमारी राय में केन्द्रीय सरकार द्वारा आदर्श पाठ्य-पुस्तकों का उत्पादन नितांत आवश्यक है। इसके लिए सरकार द्वारा पाठ्य-पुस्तकों से सम्बन्धित न्यूनतम

निर्धारित मान्यताएँ निश्चित कर देनी चाहिए और प्रतियोगिता की भावना स्वरूप निजी कार्य करने वाली संस्थाओं को आमन्त्रित किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को यह पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वे अपनी परिस्थितियों के अनुकूल पाठ्य-पुस्तकों को परिमार्जित कर सकें। इससे लेखकों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और पाठ्य-पुस्तकों की हीन दशा में सुधार भी हो सकेगा।

कहने का तात्पर्य यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तकों का भावार्थ स्वरूप राज्य सरकारों के लिए उत्तेजना पूर्ण होना चाहिए। पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। पाठ्य-पुस्तक के चयन का आधार उसकी श्रेष्ठता होनी चाहिए। यदि पाठ्य-पुस्तकों की हीन दशा और व्याप्त भ्रष्टाचार को राष्ट्रीयकरण द्वारा दूर किया जा सकता है तो राष्ट्रीयकरण कर देना ही उचित है।

---

## ग्रन्थ-सूची

### Bibliography

1. *Report of Secondary Education Commission,*  
Ministry of Education, Govt. of India, 1953.
2. *Report of Education Commission,*  
Ministry of Education, Govt. of India, 1960.
3. *Report of a Study by an International Team,*  
Ford Foundation, New Delhi, 1954.

## विश्वविद्यालय प्रश्न University Questions

1. Do you subscribe to the view that nationalization of text-books is a desirable end ? How far, do you think, has the experiment of nationalization of text books been successful in Rajasthan ? Give reasons for your answer. (Rajasthan, 1961)

2. What are the advantages and disadvantages of nationalization of text-books in a democracy ? What steps would you take to get over the disadvantages ?

3. Formulate your regarding nationalization of text books in the light of situation prevailing in your state in regard to this issue. (Rajasthan, 1965)

4. What is the system of prescribing and/or recommending text books for secondary stage in your state ? Are you satisfied with that system ? If not, why, and what is your alternative suggestion for the same ?

आपके राज्य में माध्यमिक स्तरों के लिए पाठ्य-पुस्तकें निर्धारित करने या उनकी विकारित करने की क्या प्रणाली है ? क्या आप उस प्रणाली से सन्तुष्ट हैं ? यदि नहीं, तो बताएँ कि क्यों और साथ ही उसके बदले की दूसरी प्रणाली भी सुझाएँ ।

5. What is your opinion about nationalization of text books secondary stage ?

माध्यमिक स्तर की पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में आपका क्या विचार है ? (राजस्थान, 1967)

## अध्याय उन्नीस

### Chapter Nineteenth

## राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता

### *National and Emotional Integration*

#### अध्ययन बिन्दु

#### Learning Points

- \* 19.01 राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता का अर्थ  
Meaning of National and Emotional Integration
  - \* 19.02 भारतीय संस्कृति-राष्ट्रीय भावनात्मक एकता की प्रतीक  
Indian Culture-A Symbol of National Emotional Integration
  - \* 19.03 रामायण और महाभारत में राष्ट्रीय एकरता  
National Integration in Ramayana and Mahabharata
  - \* 19.04 राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता के विघटनकारी तत्व  
Destructive Elements of National & Emotional Integration
    1. साम्प्रदायिकता
    2. भाषा संघर्ष
    - 3 'भेदभाव' की संकुचित भावनाएँ
    4. देशद्रोही राजनैतिक दल
  - \* 19.05 शिक्षा : राष्ट्रीय एकता का प्रभावोत्पादक साधन  
Education . An Effective Means of National Solidarity
    1. राष्ट्रीय एकता गोष्ठी (1959)
    2. भावनात्मक एकता समिति (मई, 1961)
    3. उपकुलपति सम्मेलन (अक्टूबर, 1961)
  - \* 19.06 शिक्षा आयोग (1964-66) और राष्ट्रीय एकता  
Education Commission (1964-66) and National Integration
-

## राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता NATIONAL & EMOTIONAL INTEGRATION

‘सर्वप्रथम एक देश के लोगो में अपनी मातृभूमि के प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए, तत्पश्चात् ही कोई अन्य कार्य किया जा सकता है।’

—रबिन्द्र नाथ टैगोर

जिस जागृकारी युग में आज भारत गुजर रहा है, सम्भवतः इस प्रकार का युग भारत के इतिहास में कभी न रहा होगा। इस युग में ■ तो अनेको समस्याएँ हैं परन्तु सबसे भयानक और विकराल समस्या हमारी आपस की फूट है। एक समय था जब हम एक थे और पराधीनता की जबड़ी हुई शृंखलाओं को तोड़ने के लिए कटिबद्ध थे। हमने पराधीनता की जबीरी को तोड़ा, स्वतन्त्रता की बेला में साँत ली और उत्कर्ष की पहली मजिह को पार किया। हमारी दुसरी यात्रा प्रारम्भ हुई, सबको एक सूत्र में बाँधने के प्रयास हुए, परन्तु हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम एक न हो सके। अनेको छोटे-छोटे मनमुटाव के कारण, हम सदैव ‘अनेक थे और अनेक रहे।’ हम ‘अनेक में अनेक’ सम्मिलित होते चले गये और ‘अनेकता में एकता’ के प्रयास लोप होत रहे। हमें बाद में याद आया कि देश की एकरता के सूत्र में ने के लिए शिक्षा के सर्वोत्तुष्टी कार्यक्रमों की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय एकता



सूत्र में बांधने का उत्तरदायित्व शिक्षा के सशक्त कर्मियों पर है जो घालाओं और विषविविधताओं पर निर्भर करता है।

### 19.01 राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता का अर्थ

#### Meaning of National & Emotional Integration

राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता का अर्थ है—एकत्व की भावना और राष्ट्र के प्रति प्रेम जिसमें सद्बुद्धि, जाति, भाषा, धर्म आदि के अन्तर की भावनात्मक रूप से सम्पूर्णता में देखा जाये।<sup>1</sup>

सन् 1961 में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में राष्ट्रीय एकता की भावना को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया गया —

‘राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक एवम् शैक्षिक प्रश्न है जिसके द्वारा सभी व्यक्तियों के हृदय में एकत्व की भावना, समान नागरिकता की अनुभूति और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को विकसित किया जाता है।’

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता हृदय पक्ष से सम्बन्धित है जिसके साथ भावना जुड़ी हुई है। यदि देश में एकता लानी है तो आवश्यकता है हृदय परिवर्तन की, जिससे भावनाएँ बदली जा सकें। यह कार्य भाषणों द्वारा सम्भव नहीं है, इसके लिए राष्ट्रप्रेमी सरकारों को विकसित करने की आवश्यकता है और यह कार्य अभी सम्भव है जबकि वर्तमान पीढ़ी को एकता की महत्ता स्पष्ट करने हुए भावी संवत्ति को शिक्षित किया जाये।

आज की दशा को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारा देश विभिन्न सम्प्रदायों, धर्मों और भाषाओं में बँटा हुआ है तथा हमारे देशवासी राष्ट्रीय एकता के अर्थ से परिचित नहीं हैं। परन्तु वस्तु स्थिति ठीक इसके विपरीत है—आज समस्त देशवासी चाहें वे गरीब हैं अथवा अमीर, शिक्षित हैं अथवा अशिक्षित, ग्रामीण हैं अथवा शहरी इस तथ्य से परिचित हैं कि देश की प्रगति एकता पर अवलम्बित है, यदि देश की एकता को विध्वंस की आघात लगा तो देश की सीमाओं पर शत्रु दल सक्रिय हो सकता है। चीन और पाकिस्तान के आक्रमण के समय जो एकता का प्रदर्शन हुआ वह इस बात का द्योतक है कि भावना से हम सब एकता के सूत्र में बँधे हैं।

### 19.02 भारतीय संस्कृति राष्ट्रीय भावनात्मक एकता की प्रतीक

#### Indian Culture-A Symbol of National Emotional Integration

हमारे देश की संस्कृति में एकता के कारण सदैव उपस्थित रहे हैं। भारत में

1. National and emotional integration may be defined as a feeling of oneness in which the differences of culture, castes languages, religion are seen emotionally in one compact whole.



आस-बाँ महाभारत प्रसिद्ध हुआ। मलयालम में एतुत्तचन का महाभारत उनकी रामायण से भी अधिक प्रचलित हुआ, जो मराठी में श्रीराम व पाण्डवप्रताप लिखकर जयका को देश की एकता का पाठ पढ़ाया। उदिया में तो सरलादास ने महाभारत को जनगण के जीवन में इस प्रकार मिला दिया कि वह उदिया के व्यास ही कहलाने लगे। पंजाबी में कृष्णलाल ने महाभारत को नवित्ता में लिखकर जनता से भारतीयता का संदेश फैलाया, जो अममिया में रामसरस्वती ने महाभारत के आधार पर अनेक पुस्तकों की रचना की। हिन्दी में गोबुलनाथ और मजनमित्र चौहान का महाभारत प्रसिद्ध है। बंगला में महाभारत के तीन से अधिक रूपांतर हुए, जिनमें बामीराम दास के महाभारत ने सर्वाधिक महत्व का स्थान पाया।

इस प्रकार रामायण और महाभारत का गंदेरा सारे देश में फैलकर महलों से भीगती एक पहुँचा और यहाँ के हर भाग के लोग राम और कृष्ण के माध्यम से एक, दूसरे के साथ बस, सांस्कृतिक एकता के मूल में बस गये जिसकी जगहियों की बाढ़ी, विविध विधु-बाधाएँ निखी भी तरह न तोड़ सकी।

2.1. आज यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कुछ प्रान्त अपने को स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब-जब हमने एकता के मूल को छोड़ा, तब-तब हमारे देश पर बाहरी साम्राज्यवादी शक्तियों का आधिपत्य हुआ। आज, आजकल है कि हम पारस्परिक द्वेष को गुलार कर एकता के पवित्र मूल में बसें। हमारे-प्राचीन ग्रन्थ एवं धार्मिक मूल्य इस दृष्टि में बहुत कुछ सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

19.04 राष्ट्रीय और मानवतात्मक एकता के विघटनकारी तत्व

Destructive Elements of National and Emotional Integration

आज हमारा देश पारस्परिक मन-मुटाव के कारण भारतीय उच्चादर्यों को भूल गया है। हम राष्ट्रीय सम्पत्ति को हानि पहुँचाते हैं, हिंसा करते हैं, एक दूसरे को हेय दृष्टि से देखते हैं। आखिर इन सबका कारण क्या है? वे कौन कौन से मूल तत्व हैं जो राष्ट्रीय और मानवतात्मक एकता में विघटन प्रस्तुत कर रहे हैं? हमारी दृष्टि में निम्नलिखित विघटनकारी तत्व हैं जो देश के विकास में बाधक बने हुए हैं—

2.1.1 साम्प्रदायिकता

2.1.2 Communalism

स्वतंत्रता प्राप्ति के 23 वर्षों के पश्चात् भी अनेकों के बोध हुए बीजों की छींक रहे हैं। अहमदाबाद के साम्प्रदायिक भग्ने- इस तथ्य के चोटक है कि आज भी सम्पूर्ण राष्ट्र एक-तहो है। इनके अतिरिक्त साम्प्रदायिकता की मचना से बड़ी-मूल शोक है इस प्रदेश समता का समाधान राष्ट्रीय स्तर पर व छोड़कर साम्प्रदायिक

पर सोचते हैं। जनवरी, 1968 के मेरठ में हुए उपद्रव, बिहार में  
मानवीय व्यवहार और यदा कदा साम्प्रदायिक भगड़े हमारी पशुता के चोकर हैं।  
इसे भावनाओं इसी प्रकार से विनाश के मार्ग पर चलती रही तो निश्चित ही  
इस देश का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा।

## 2. भाषा समस्या

### Language Problem

राष्ट्रीय एकता का दूसरा प्रमुख बिघटनकारी सत्व भाषा है। विद्यते देशे  
भाषा के प्रश्न पर भगड़े मद्रास में हुए और जो उपेक्षित भाव हिन्दी के लिए  
रखे गए, वह राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। अहिन्दी  
क्षेत्र में हिन्दी का विरोध मुख्य रूप से मद्रास और बंगाल में है। अन्य राज्यों  
हिन्दी का विरोध नहीं है। भगड़े का मूल कारण अहिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी का  
विरोध नहीं है बल्कि अंग्रेजों का समर्थन है। आज यह स्थिति हो गयी है कि अंग्रेजी  
समर्थक बिना किसी कारण के हिन्दी का विरोध करने लगे हैं। हमने मैसूर  
में यहाँ तक देखा कि वहाँ के मूल निवासी हिन्दी जानते हुए भी हिन्दी में बातचीत  
नहीं समझते हैं, वार्तालाप से यह भी पता लगा कि वहाँ के लोग हिन्दी नहीं  
जानते परन्तु वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है क्योंकि हिन्दी फिल्मों में वहाँ इतनी  
होती है जितनी कमरे फिल्मों में नहीं। यहाँ हमारे कहने का तात्पर्य केवल  
यही है कि वहाँ के लोग हिन्दी बोलना और समझना जानते हैं परन्तु अंग्रेजों के  
होने के कारण हिन्दी का विरोध करने लगे हैं। परन्तु सम्भवतः हमारे राज्यों  
इस तथ्य से परिचित नहीं हैं कि केवल बीस वर्षों तक अंग्रेजों के आधीन रहने  
से हमारे देश की केवल भाषा दो प्रतिपात जनता ही अंग्रेजी जानती है—मरा-  
ठियों की भाषा को राज्य भाषा अथवा सम्पूर्ण भाषा बनाना भारत के अहित  
है। अन्ततोगत्वा यही कहा जा सकता है कि वर्तमान परिस्थितियों में भाषा  
विवाद समस्या के रूप में उपस्थित है जो राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता के  
अपकार सत्तरा है।

## 3. प्रादेशिकता को संकुचित भावनाएँ

### Narrow Feelings of Regionalism

हमारे देश में भारतीयों की समस्या बहुत कम है क्योंकि देश के प्रति यह  
भावना है। हमारे देश के राजनैतिक दलों ने इस भावना को बढ़ाने में  
बहुत से उपाय किए हैं। जब उपायों के चुलने की योजना होती है तो  
उत्पन्न होता मानने पुनरावृत्ति की प्रगति व विषय में ही सोचते हैं और सामान्य  
जनों की अनुपस्थिति में भी उपायों की स्थापना करने में लगे हो जाते हैं।  
प्रादेशिक भाव को प्रसारित करती है। जब तक हमारा दृष्टिकोण प्रादेशिकता

की संकुचित भावनाओं से हटकर व्यापक रूप में राष्ट्रीय नहीं होगा तब तक राष्ट्रीय और भावनारमक एकता की भावना का आना सम्भव नहीं है।

#### 4. देशद्रोही राजनैतिक दल

##### Disloyal Political Parties

राष्ट्रीय भावनारमक एकता को सबसे बड़ा खतरा उन राजनैतिक दलों से है जो छोटे-छोटे स्वार्थों के लिए विदेशी सत्ताओं से सम्बन्धित हैं। अभी हाल में ही विद्रोही नागाओं का चीन से दख प्रार्थ्य करना और मक्खलवाड़ी में चीन के स्वागत की तैयारी की योजना बनाना राजनैतिक दलों के देशद्रोही कृत्यों का ज्वलन्त उदाहरण है। यदि इस प्रकार के देशद्रोही राजनैतिक दलों पर रोक न लगायी गयी तो देश की अखण्डता खतरे में पड़ सकती है।

#### 19.05 शिक्षा : राष्ट्रीय एकता का प्रभावोत्पादक साधन

##### Education : An Effective Means for National Solidarity

राष्ट्रीय एकता को विवक्षित करने के लिए शिक्षा प्रभावोत्पादक साधन है। शिक्षा द्वारा वांछित अभिवृत्तियों एवं दृष्टिकोणों को विकसित किया जा सकता है। मात्र राष्ट्रीय एकता के मार्ग में जो बाधाएँ उपस्थित हो गई हैं उन्हें शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति संकुचित वृत्तों से निकलकर व्यापक वातावरण में विचरण करता है। सम्पूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण योग प्रदान कर सकती है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल मात्र पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना ही नहीं होता बल्कि विद्यार्थियों में देशभक्ति, राष्ट्रीयता, बलिदान और सहन-शीलता की भावनाओं को विकसित करना भी है। यह केवल तभी सम्भव है जबकि शिक्षा प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन हो।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय और भावनारमक एकता हेतु अनेकों प्रयास हुए और सभी गोष्ठियों एवं समितियों में यह स्वीकार किया गया कि राष्ट्रीय एकता हेतु शिक्षा को साधन के रूप में स्वीकार किया जाये। संक्षेप में इनका विवरण इस प्रकार है—

#### 1. राष्ट्रीय एकता गोष्ठी (1958)

##### National Integration Seminar ( 1958 )

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय एकता पर विचार करने के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में राष्ट्रीय एकता हेतु शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया। शिक्षा को साधन के रूप में स्वीकार करते हुए गोष्ठी ने निम्न-लिखित सुझाव दिये—

1. राष्ट्रीय एकता हेतु यह अनिवार्य है कि भारतीय इतिहास को ठीक

प्रकार लिया जाये और उन अन्यों को हटाया जाये जो साम्प्रदायिकता की भावना को विकसित करते हैं।

2. राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षण सहायकों को महत्वपूर्ण उत्तर देने चाहिए।
3. धर्म और जाति के आधार पर छात्रवृत्तियाँ न दी जायें।
4. साम्प्रदायिकता की भावना को समाप्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि साम्प्रदायिक आधार पर छात्रावास न बनाये जायें।

## 2. भावनात्मक एकता समिति (मई, 1961)

*Emotional Integration Committee (May, 1961)*

भारतीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने डा० सम्पूर्णनाथ की अध्यक्षता में भावनात्मक एकता समिति की नियुक्ति की। समिति का विचार क्षेत्र निम्नलिखित था—

- \* राष्ट्रीय जीवन में भावनात्मक एकता की प्रशिक्षण में शिक्षा का योग।
- \* उपरोक्त विचारधारा के समर्थन में युवकों के लिए सरकारी संश्लेष कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना।

शिक्षा की महत्ता पर विचार स्पष्ट करने हुए समिति ने स्पष्ट किया कि भावनात्मक एकता को सुदृढ़ करने में शिक्षा महत्वपूर्ण योग्य प्रदान कर सकती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल शिक्षा प्रदान करना ही नहीं है बल्कि विद्यार्थियों के सभी पक्षों का विकास करते हुए उनके व्यक्तित्व का विस्तार करना है। अतः शिक्षा का दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए और एका, राष्ट्रीय, बलिदान और सहिष्णुता की भावनाओं को विकसित कर तथा सकीर्णता की भावना को समाप्त कर देश के हित में कार्य करना चाहिए।<sup>2</sup>

शैक्षिक योगदान के सम्बन्ध में भावनात्मक एकता समिति के निम्नलिखित सुझाव थे—

### (I) पाठ्यक्रम का पुनर्गठन (Reorientation of the Curriculum)

समिति के विचारानुसार छात्र और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों का पुन-

1. Education can play a vital role in strengthening emotional integration. It is felt that education should not only aim at imparting knowledge but, should develop all aspects of a student's personality. It should broaden the outlook, foster a feeling of oneness and nationalism and a spirit of sacrifice and tolerance so that narrow group interests are submerged in the larger interests of the country.

*Emotional Integration Committee, 1967.*

गठन करना नितान्त आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर बालकों को राष्ट्रीय भावनाओं से ओत प्रोत करने के लिए राष्ट्रीय गान एवम् देश प्रेम के गीतों का अभ्यास कराया जाये। माध्यमिक स्तर पर भी इस प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों पर बल दिया जाये जिससे भावनात्मक एकता प्रशस्त हो सके।

## (II) भाषा एवं लिपि ( Language and Script )

उन देशों में जहाँ हिन्दी का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, रोमन लिपि का प्रयोग अपेक्षित है। अहिन्दी देशों में हिन्दी को प्रादेशिक लिपि द्वारा लिखने का प्रयास किया जाये तथा हिन्दी की पुस्तकों को प्रादेशिक लिपि में प्रकाशित किया जाये। विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी तथा अंग्रेजी का स्तर समान होना चाहिए। किसी भी प्रदेश पर भाषा बांझो न जाये तथा अल्पसंख्यकों का ध्यान भी रखा जाये। भाषा समस्या का समाधान सौहार्दपूर्ण वातावरण में होना नितान्त आवश्यक है।

## (III) राष्ट्रीय गान ( National Anthem )

राष्ट्रीय गान की महत्ता एवं अर्थ से बालकों को पूर्णरूपेण परिचित कराया जाये। समस्त देश में राष्ट्रीय गान के प्रति आदर की भावना विकसित करना नितान्त आवश्यक है। बालकों को, राष्ट्रीय गान के समय अनुशासनात्मक ढंग के प्रति जागरूक किया जाये।

## (IV) राष्ट्रीय ध्वज ( National Flag )

विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास से परिचित कराना नितान्त आवश्यक है। बालकों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की महत्ता से अवगत कराया जाये। राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त रंगों का अर्थ एवम् उनके दार्शनिक स्वरूप से बालकों को प्राथमिक स्तर से ही परिचित कराया जाये।

## (V) राष्ट्रीय दिवस ( National Days )

समस्त देश की छात्राश्रमों में राष्ट्रीय दिवसों का मनावना अनिवार्य होना चाहिए। अध्यापकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। 15 अगस्त और 26 जनवरी को विशेष रूप से मनाया जाये।

## (VI) पाठ्य सहगामी क्रियाएँ ( Co-Curricular Activities )

समिति के अनुसार राष्ट्रीय भावनात्मक एकता के लिए पाठ्य-सहगामी क्रियाएँ पर्याप्त रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। एक क्षेत्र के विद्यार्थियों को दूसरे क्षेत्रों में अभिप्रेम से जाना, एन० सी० सी०, स्काउटिंग, गादविवाद और पारस्परिक सहभावना हेतु साप्ताहिक कार्यक्रमों के आयोजन आदि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

## (VII) शपथ ग्रहण करना ( To take Pledge )

विद्यार्थियों को देश एवं देशवासियों की सेवा हेतु शपथ ग्रहण करायी जाये जिसका प्राक्ष्य निम्नलिखित है—

- \* भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई और बहिन हैं ।
- \* मैं अपने देश को प्यार करता हूँ, और मुझे अपने देश की सम्पदा एवं परम्पराओं पर गर्व है, मैं इसके लिए योग्य होने का सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न करूँगा ।
- \* मैं अपने माता पिता, अध्यापकों और अपने से बड़ों का मान करूँगा और सबसे शालीनता का व्यवहार करूँगा ।
- \* अपने देश और लोगों के प्रति मैं भक्ति की शपथ ग्रहण करता हूँ । मैं प्रसन्नता उनको भलाई और समृद्धि में निहित है ।

## (VIII) अखिल भारतीय शिक्षा नीतियाँ ( All India Educational Policies )

समिति का मत था कि मानवसमक एवता हेतु अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा नीतियों का निर्धारण होना चाहिए । इन नीतियों का प्राक्ष्य केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य प्रयासों द्वारा तैयार होना चाहिए ।

## (IX) सामाजिक अध्ययन का शिक्षण (Teaching of Social Studies)

समिति के विचारानुसार सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का महत्व केवल प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर तक ही सीमित न होकर विश्वविद्यालय स्तर पर भी होना चाहिए । यही केवल ऐसा विषय है जिसके द्वारा देश की भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान हो सकता है । सामाजिक अध्ययन के अन्तर्गत भारत के महान पुरुषों की जीवनी, उनके द्वारा किये गये कार्य और प्राचीन भारत की गौरवमयी भाषा का उत्प्रेरक अनिवार्य है ।

## 3. उपकुलपति सम्मेलन (अक्टूबर 1961)

Vice Chancellers Conference (Oct 1961)

राष्ट्रीय और मानवसमक एवता हेतु शिक्षा के उपायसमिष्ट पर सम्मेलन ने निम्नलिखित सुझाव दिये—

1. अधिकांश भारतीय उद्योगों की भावना को विवर्धित करने के लिए प्रदेश सरकारों को चाहिए कि सभी उद्योगों के लिए कुछ प्रतिष्ठान स्थापित करें ।
2. विश्वविद्यालयों में सामाजिक भावना को प्रवर्धित करना ।



3. छात्र संघों को समाप्त कर पारस्परिक सहयोग की अभिवृद्धि हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये।

4. विश्वविद्यालयों को छात्रों में धार्मिक सहिष्णुता को विकसित करना चाहिए।

5. विभिन्न भाषाओं और विशेषकर दक्षिण भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था प्रत्येक विश्वविद्यालय में होनी चाहिए।

4. राष्ट्रीय एकता परिषद् ( सितम्बर, अक्टूबर, 1962 )

National Integration Committee ( Sept, Oct, 1962 )

समस्त भारतवासियों को एक मूल में बाँधने और शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए डॉ० राधाकृष्णन् ने परिषद् का उद्घाटन करते हुए कहा कि 'राष्ट्रीय एकता को छेना, छोटे, टूटे व पत्थरों से नहीं मारा जा सकता। इसका जगमग प्रतिबिम्ब के हृदयों और मस्तिष्कों में घने घन होना है जिसका केवल मान एक साधन है और वह है शिक्षा। यह सम्भव है कि यह प्रक्रिया धीमी हो, पर यह स्वयं में स्वायी एवं प्राकृतिक प्रक्रिया है।

राष्ट्रीय एकता हेतु शिक्षा को महत्त्वपूर्ण साधन स्वीकार करते हुए परिषद् ने निम्नलिखित सुझाव दिये—

1. साम्प्रतिक शिक्षा का साम्प्रतिक क्षेत्रीय भाषाएँ हो।
2. विभागीय मूल को लागू किया जाय।
3. हिन्दी को सम्पूर्ण देश की सम्पूर्ण भाषा बनाया जाये।
4. हिन्दी का समुपग्रह होने तक अंग्रेजी को विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का साम्प्रतिक स्वीकार किया जाये।
5. शिक्षा के साम्प्रतिक द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं, पारस्परिक प्रेम और सह-भावना को विकसित किया जाये।
6. शिक्षा द्वारा भारतीयता की भावना उत्पन्न की जाये।
7. छात्रों का राष्ट्रीय मान द्वारा प्रेरित होना चाहिए।

उपरोक्त परिषदों, मीटिंगों और सम्मेलनों के सुझावों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय और भावनात्मक एकरा हेतु शिक्षा को प्रत्यक्षोद्देशक साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता के लिए लोगों के दिलों और दिमागों को परिवर्तित करना आवश्यक है— यह सभी सम्भव है यदि शिक्षा द्वारा वांछित अभिवृद्धि को विकसित किया जाय।

## ग्रन्थ-सूची

### Bibliography

1. Hussain, Zakir

*Educational Reconstruction in India*, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi 1959.

2. Ministry of Education,

*Report of the Committee on Emotional Integration*, New Delhi, 1962.

3. Ministry of Education,

*Report of the Education, Commission*, New Delhi, 1960.

4. Shrimali, K. L.

*Problems of Education in India*, Publication Division, New Delhi, 1961

---

## विश्वविद्यालय प्रश्न

### University Questions

1. Explain the role of education in strengthening and promoting the processes of emotional integration in our national life. Suggest some positive educational programmes to strengthen them and toward off the tendencies which come in the way of their development.

( Rajasthan, 1962 )

2. Was India One ?

*Is India One ?*

Shall India be One ?

What do you mean by India ?

! Give reasons for your belief and show what you can do as a teacher to serve India in the best possible way by shaping the patriotic sentiments of your students.

( Rajasthan, 1963 )

3. 'Is there a 'Crisis of character' today in India ? Support your views with reasons and suggest educational measures to remedy the evil if it exists

( Rajasthan, 1964 )

## अध्याय बीस

### Chapter Twentieth

## शिक्षा और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की समस्याएँ *Education & Problems of National Development*

### अध्ययन बिन्दु

#### Learning Points

#### 20.01 राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की समस्याएँ *Problems of National Development*

1. साध सामग्री में आत्म निर्भरता  
(Self-Sufficiency in Food)
2. आर्थिक विकास और जीविका व्यवस्था  
(Economic Growth and full Employment)
3. सामाजिक और राष्ट्रीय एकता  
(Social & National Integration)
4. राजनैतिक विकास  
(Political Development)

#### 20.02 समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षा आयोग के सुझाव *Suggestions of Education Commission for the Solution of the Problems*

1. विज्ञान की शिक्षा पर बल  
(Emphasis on Science Education)
2. कार्य-अनुभव  
(Work Experience)
3. व्यावसायिक शिक्षा  
(Vocational Education)

## शिक्षा और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की समस्याएँ EDUCATION & PROBLEMS OF NATIONAL DEVELOPMENT

शिक्षा का विनिश्चित उद्देश्य समाज और देश की आवश्यकताओं का पूर्ति करना है। यदि किसी देश की शिक्षा इस उद्देश्य को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है तो उस देश की प्रगति असम्भव है। अतः समाज और देश की आवश्यकताओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप ही शिक्षा व्यवस्था का होना अनिवार्य है। इसके लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय लक्ष्यों को निर्दिष्ट कर उनके अनुरूप ही शिक्षा को पुनर्स्थापना करना होगा क्योंकि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए शिक्षा ही सर्वप्रथम साधन है। वर्तमान वैज्ञानिक प्रगति, तकनीकी ज्ञान और उत्तरोत्तर विकसित ज्ञान को वर आधारित विश्व में शिक्षा ही वह आधार है जो राष्ट्र के प्रगति और समृद्धि माने में सहायक हो सकती है।

आज हमारा देश राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की समस्याओं का समाधान करने में प्रयास है। हमें ज्ञान देश में मुख्यतः दो कार्य करना है—प्रथम जनता के जीवन स्तर को उठाना है, द्वितीय ज्ञान प्रगतिशील देशों के साथ चलकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को बढ़ाना है। इन दोनों ही कार्यों पर राष्ट्रीय विकास निर्देश है और यह लक्ष्य है जो हम सभी शिक्षकों और दूरियों को दोष्य कर सकें। अतः हम सभी को

कारण यह भी है कि हमारी शिक्षा की जड़ें भारतीय परम्पराओं तक पहुँची हुई नहीं हैं जिसके कारण आज के शिक्षित वर्ग में भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था नहीं रही है। प्राचीन मूल्यों जो विभीतक हमारे जन-जीवन के आधार थे आज प्रायः लोप होते जा रहे हैं जिसके कारण राष्ट्रीय अस्थिरता घन, घनः विकसित हो रही है और इतना कुछ होने हुए भी शिक्षा के माध्यम से उन मूल्यों को एकत्रित करने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। आज के विद्यार्थी में असन्तोष है, जन-जीवन में भ्रष्टाचार है और साम्प्रदायिकता की भावनाएँ अधिक महुरी होती जा रही हैं। सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना नितान्त आवश्यक है क्योंकि यह राष्ट्रीय विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा बन गई है।

शिक्षा आयोग ने इनके लिए शिक्षा को उत्तरदायी ठहराया है और मूल रूप से चार महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार दिये हैं—

- (i) सामान्यशाला व्यवस्था
- (ii) सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा
- (iii) भाषा समस्या
- (iv) राष्ट्रीय जागरूकता

#### 4. राजनैतिक विकास

##### *Political Development*

हमारे राजनीतिक जीवन में अनेकों राजनैतिक परिवर्तन आये और अनेकों कठिनाइयों के पश्चात् भारत में प्रजातन्त्रात्मक शासन पद्धति को अपनाया, परन्तु अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना शेष है। अभी हमारे अन्दर वह राजनीतिक चेतना उत्पन्न नहीं हो पाई है जिसकी हमारे देश की आवश्यकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज का सामान्य भारतीय अपने अधिकारों और कर्तव्यों को पक्षों की अपेक्षा अधिक समझने लगा है तथापि इन क्षेत्र में और विशेषकर राजनैतिक अभिवृत्तियों को विकसित करने में बहुत कुछ करना है। हमारे देश में अनेको राजनैतिक दल हैं, सभी राजनीतिक दलों की अपनी नीतियाँ हैं। नीतियों में परिवर्तन होना तो स्वाभाविक है परन्तु राजनीतिक विकास को हानि तब पहुँचती है जब दलों के पारस्परिक द्वेषमय मातामरण से देश में बल्लह उत्पन्न होता है।

राजनीतिक विकास में तीन पक्षों पर ध्यान देने की आवश्यकता है:—

- (i) प्रजातन्त्र को सशक्त बनाना,
- (ii) स्वतन्त्र देश की रक्षा करना,
- (iii) सम्पूर्ण जनता को प्रजातान्त्रिक मूल्यों के अनुसार दली हुई भावनाओं से अतिव्यक्त करने का अवसर प्रदान कर उन्हें शिक्षित, उन्नत राष्ट्रीय

जीवन स्तर और बस्याण जारी सामन-पद्धति के मार्ग को प्रशस्त करना। इसके लिए निम्नलिखित आवश्यक है कि वर्तमान पीढ़ी। अनुशासन और राष्ट्रीय हित के मार्ग को अपनाये। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की उक्त लिखित कुछ समस्याएँ हैं जिनका समाधान शिक्षा के माध्यम से सम्भव है क्योंकि शिक्षा ही इन समस्याओं के समाधान का मुख्य साधन है। शिक्षा द्वारा ही सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। यह सभी सम्भव है जब शिक्षा के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन करके शिक्षा को जन जीवन की आवश्यकताओं और उनकी आवश्यकताओं से सम्बन्धित बना देंगे। राष्ट्रीय विकास के मार्ग में असफलता का प्रमुख कारण शिक्षा उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का राष्ट्रीय जीवन के प्रतिफल होना है।

## 20.02 समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षा आयोग के सुझाव

*Suggestions of Education Commission for the Solution of the Problems*

भारत के माध्यम का निर्माण अ जल के विद्यालयों के अध्ययन वर्गों में हो रहा है। इस युग में जीवन की मजदूरी, बस्याण और सुरक्षा विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की शिक्षा पर आधारित है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से निकलने वाले छात्रों के गुणों पर ही राष्ट्र का पुनर्निर्माण सम्भव है। अतः आज आवश्यकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कामचलायी परिवर्तन लाये जायें। परिवर्तन सभी सम्भव है जबकि शिक्षा के कार्यक्रम का मूल्यांकन हो और मूल्यांकन के पश्चात् जिन परिवर्तनों पर विचार किया जाये उन्हें हट सकल होकर कार्यान्वित बना जायें।

संक्षेप में वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित कार्यक्रमों की आवश्यकता है:—

### 1. विज्ञान की शिक्षा पर बल

*Emphasis on Science Education*

दिल्ले कुछ वर्षों में अनेकों देशों में द्रुतगति से प्रगति की। इसका श्रेय उन देशों की वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी की दक्षता है। हम अभी तक निर्णायक स्थिति में नहीं हैं क्योंकि हमारे देश में विज्ञान की शिक्षा का प्रसार अभी तक अपनी बाल्यावस्था में ही है। विज्ञान की शिक्षा स्कूली शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए। विज्ञान शिक्षण में भी सुधार की आवश्यकता है। हमारे देश में विज्ञान शिक्षा के बहुत सीमित साधन हैं और इन सीमित साधनों में ही हमें उन्नति के पथ पर अग्रसर होना है। विज्ञान शिक्षा का विकास केवल संस्थात्मक ही नहीं होना चाहिए बल्कि गुणात्मक उन्नति की अत्यधिक आवश्यकता है। विज्ञान शिक्षा की सुविधाओं में अधिकता, सम्बन्धित उच्च वेतनों की स्थापना, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों की नियुक्ति,

मेडासिस्ट और व्यावहारिक दलों में आवश्यक सम्बन्ध, गुणवत्ता प्रयोगात्मक आदि की व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है। यह सब सभी सम्भव है जबकि सरकार आवश्यक बजट उठावे और सभी विद्वानों के अनुमति से गुणवत्ता प्रदान करे। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि विज्ञान शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति को निश्चित किया जाय। कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान की शिक्षा की पर्याप्त बहालवाई जिससे हमारा देश अन्य प्रगतिशील देशों के साथ खूब सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके।

## 2. कार्यानुभव

### Work Experience

प्राथमिक शिक्षा यही है जो जीवन से सम्बन्धित हो। आज हमारी शिक्षा जीवन से कुछ दूर हो गई है। सैद्धांतिक ज्ञान तो पर्याप्त होता है परन्तु व्यावहारिक ज्ञान का स्तर बहुत निम्न होता है। शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया है कि कार्यानुभव को समस्त स्तरों पर शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाये। औद्योगिक शिक्षा बालक का सामुदायिक कार्यक्रमों में सम्बन्धित करने देती है जिससे बालकों में कौशल विकसित नहीं हो पाया और कर्म एवं ज्ञान एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।

कार्यानुभव यह विधि है जो शिक्षा के साथ कार्य करने पर धन देती है। कार्यानुभव का कार्यक्रम उच्चतर प्राथमिक स्तर से प्रारम्भ होना चाहिए और माध्यमिक स्तर पर विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं में ले जाकर उचित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कार्यानुभव से विद्यार्थियों में स्वयं कार्य करने की प्रेरणा का विकास होगा जिससे धन की महत्ता को बल मिलेगा।

## 3. व्यावसायिकरण

### Vocationalization

एक अन्य कार्यक्रम जो शिक्षा को राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान कर सकता है वह है माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायिक स्वरूप और विश्वविद्यालय स्तर पर कृषि और प्राविधिक शिक्षा का प्रावधान। भारत की वर्तमान दशा को देखकर तो यही आभास होता है कि प्रत्येक शिक्षित युवक और युवती राजकीय कार्यों में ही जाना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति को सभी रोकना संभव है जबकि माध्यमिक स्तर से ही पाठ्यक्रम को व्यावसायिक बनाया जाये जिससे विद्यार्थी जीवन-वैय में प्रवेश कर सभी व्यावसायिकों को अपना सहयोग प्रदान कर सकें। वर्ष 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग ने सर्वप्रथम यह सुझाव दिया था परन्तु इन सुझावों को कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया और आज की अवस्था यह है कि माध्यमिक स्तर पर केवल 9 प्रतिशत विद्यार्थी व्यावसायिक पाठ्यक्रम लेते हैं और यह संख्या विश्व के अन्य



देशों की तुलना में सम्भवतः सबसे कम है। विश्वविद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा (केवल विधि, चिकित्सा और शिक्षण व्यवसाय के अतिरिक्त) को पूर्ण रूपेण विरस्तृत किया गया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने 1917 में संकेत दिया था कि विश्वविद्यालय स्तर पर 26,000 विद्यार्थियों में से 22,000 छात्र साहित्यिक पाठ्यक्रम चुनते हैं जिसके कारण वे प्रशासनिक, तकनीकी अथवा शिक्षण व्यवसाय को ही चुन पाते हैं। आज की दशा भी ठीक वैसी ही है जबकि हमें स्वतन्त्र हुए 23 वर्ष हो चुके हैं। यदि राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना है और देश से बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करना है तो शिक्षा का व्यवसायीकरण करना नितांत आवश्यक है। हमारे राष्ट्रीय विकास में अवरोध उत्पन्न होने का प्रमुख कारण यह है कि प्रचलित शिक्षा के उद्देश्यों और विषय सामग्री वा राष्ट्र के विकास से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः शिक्षा की व्यक्तियों के जीवन, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से यथाशीघ्र सम्बन्धित किया जाये जिससे राष्ट्रीय विकास सम्भव हो सके और देश के विकास में बाधक समस्याओं का समाधान किया जा सके।

शिक्षा आयोग ने राष्ट्रीय विकास की समस्याओं का समाधान करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये हैं—

1. शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि।
2. शिक्षा द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का विकास करना।
3. शिक्षा द्वारा प्रजातान्त्रिक मान्यताओं में विश्वास उत्पन्न करना।
4. शिक्षा द्वारा जायुनीकीकरण।
5. शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास।

# ग्रन्थ-सूची

## Bibliography

*Report of the Education Commission, (1964-66)*

Ministry of Education, Govt. of India, New Delhi, 1968.

---

**अध्याय इक्कीस**

**Chapter Twenty one**

**प्राचीन भारतीय शिक्षा**

**Ancient Indian Education**

**प्रमुख बिन्दु**

**Learning Points**

**शिक्षा का महत्व**

**Significance of Education**

**शिक्षा के उद्देश्य एवं मूल्य**

**Aims & Ideals of Education**

1. धार्मिक भावना का विकास
2. चरित्र निर्माण
3. व्यक्तित्व का विकास
4. सामाजिक भावनाओं का विकास
5. सांस्कृतिक मूल्यों का प्रसार

**शिक्षा की विशेषताएँ**

**Characteristics of Education**

1. तर्क और साधन का प्रतीक

**21.05 मुख्य विद्या केंद्र और विश्वविद्यालय**  
**Educational Centres & Universities**

1. दधचिन्ता
2. नालन्दा विश्वविद्यालय
3. बलभी विश्वविद्यालय
4. विश्वमणिता विश्वविद्यालय
5. जयदत्ता विश्वविद्यालय
6. ओदन्तपुरी विश्वविद्यालय
7. मिथिला विश्वविद्यालय
8. नदिया विश्वविद्यालय

---

## प्राचीन भारतीय शिक्षा

### ANCIENT INDIAN EDUCATION

प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था अत्यन्त ही सुन्दर थी। हमारी प्राचीन शिक्षा-पद्धति वैदिक साहित्य के आलोक से प्रकाशित थी। ऋग्वेद संसार का प्राचीनतम ग्रन्थ है। वैदिक-साहित्य में वैदिक संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद् और भारव्यक आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। वैदिक संहिता में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आदि चार ग्रन्थ हैं। ये चारों ग्रन्थ ही प्राचीन भारतीय शिक्षा और जीवन दर्शन के आदि स्रोत हैं। इसीलिए श्री टागोर ने लिखा ॥ कि शिक्षा भारत में बिबेची नहीं है। संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ शिक्षा के प्रति प्रेम इतना प्राचीन प्रभावशाली और सर्वत्र जीवित रहने वाला रहा हो। वैदिक युग के कवियों से लेकर आधुनिक बंगाली दार्शनिकों तक विद्वानों और शिक्षकों का सतत प्रेम रहा है।

#### 21.01 शिक्षा का महत्त्व

##### Significance of Education

प्राचीन भारत में शिक्षा का अत्यधिक महत्त्व था। शिक्षा को सीखने के लिए कहा जाता था—

‘ज्ञान मनुजस्य तृतीयं नेत्रं ।’

प्राचीन जन में शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार करते हुए कहा गया है कि—



## 1. धार्मिक भावना का विकास

### Development of Religious Feeling

प्राचीन भारत में धर्म का प्रमुख स्थान था। प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य मूल रूप से आध्यात्मिक, मोक्ष एवं धर्म को विकसित करना था। आत्मा और परमात्मा का मिशन ही जीवन का अभिष्ट था। सम्पूर्ण शिक्षा साधनात्मक प्रक्रिया थी। धार्मिक जीवन-यापन साधनामय जीवन का मार्ग माना जाता था। विद्यापियों में धर्म के प्रति आस्था और धार्मिक भावनाओं से ओत प्रीत करना ही शिक्षा के उद्देश्य थे।

## 2. चरित्र निर्माण

### Formation of Character

प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का चरित्र निर्माण करना था। धार्मिक रूप से जीवन व्यतीत करना चरित्र निर्माण का आधार माना जाता था। चारित्रिक परीक्षा लेने के लिए विभिन्न विधियाँ अपनाई जाती थी। ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना आवश्यक था और इसके लिए गुरु की सदैव यही इच्छा रहती थी कि उसके शिष्य ब्रह्मचर्य से रहे।

## 3. व्यक्तित्व का विकास

### Development of Personality

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु छात्रों में आत्म-सम्मान, आत्म-विश्वास और आत्म-संयम की भावनाओं को विकसित किया जाता था। वांछित भावनाओं को विकसित करने के लिए वाद-विवाद, विचार-विनिमय आदि शिक्षण-विधियों को प्रयुक्त किया जाता था जिससे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास हो सके।

## 4. सामाजिक भावनाओं का विकास

### Development of Social Feelings

शिक्षा का एक उद्देश्य विद्यार्थियों में सामाजिक भावनाओं को विकसित करना भी था। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् प्रत्येक विद्यार्थी से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह गृहस्थ-जीवन व्यतीत करके समाज की सेवा करे। जो छात्र मुद्रा-विद्या प्राप्त करते थे, उनका कर्तव्य देश की रक्षा करना था, अन्य प्रकार की शिक्षाओं के भी पृथक्-पृथक् उद्देश्य थे और इन शिक्षाओं के मूल में समाज-सेवा के भाव ही प्रधान थे।

## 5. सांस्कृतिक मूल्यों का प्रसार

### Expansion of Cultural Values

सांस्कृतिक मूल्यों का मरखब और प्रसार प्राचीन भारतीय शिक्षा का विशिष्ट उद्देश्य था। सभी विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करते समय भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों

से परिचित कराया जाता था और यह अपेक्षा की जाती थी कि वे भारतीय आचार-विचार और धार्मिक जीवन-यापन कर, भारतीय संस्कृति को अधुष्ण रखेंगे। गुरु का आदर्श शिष्यों को पुत्रतुल्य मानना और उन्हें पुत्र, पति व पिता आदि के रूप में सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार जीवन व्यतीत कर उनके उत्तरदायित्वों से परिचित कराना था। सांस्कृतिक परम्परा के अनुसार प्रत्येक शिष्य को देव-श्रृण, श्रृपि-श्रृण और पितृ-श्रृण से मुक्त होना अनिवार्य था। धार्मिक कर्मों से देव-श्रृण, विद्या अध्ययन से श्रृपि-श्रृण और सन्तानोत्पत्ति से पितृ-श्रृण से मुक्ति होती थी।

### 21.03 शिक्षा की विशेषताएँ

#### Characteristics of Education

प्राचीन भारतीय शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएँ थी—

#### 1. तर्क और साधना की प्रतीक

#### Symbol of Logic & Devotion

प्राचीन शिक्षा की विशेषता यह थी कि उसे 'ज्ञानमूलक' और 'भक्तिमूलक' बनाया गया था। ज्ञानमूलक शिक्षा में 'तर्क' और भक्तिमूलक शिक्षा में 'साधना' की प्रधानता थी। ज्ञानमूलक शिक्षा में तर्क की प्रधानता होने के कारण वाकवाणी का प्रयोग किया जाता था और शिष्यों की यह सदैव इच्छा रहती थी कि व्याख्या द्वारा उनका तर्क सर्वश्रेष्ठ हो। भक्तिमूलक शिक्षा का आधार 'साधना' थी और साधना का अवलम्बन 'अभ्यास' था। आत्म-नियन्त्रण, सहनशीलता आज्ञा पालन और उत्प्रेरणा का अभ्यास भक्तिमूलक शिक्षा के लिए आवश्यक था। इसके लिए गुरु के आदेशों का पालन करना ही शिष्यों का कर्तव्य था।

#### 2. सर्वांग विकास

#### Harmonious Development

प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की थी कि विद्यार्थियों के विभिन्न विकासों के लिए पुरुष-पृथक् प्रयत्न नहीं करने पड़ते थे बल्कि समस्त विकास-क्षेत्र स्वतः पुष्पित एवं प्रगुल्लित होते थे। शिक्षा सिद्धान्तों के अनुसार जीवन व्यतीत करना प्रत्येक शिष्य के लिए अनिवार्य था। छात्रों के दैनिक कार्य इतने सुनिश्चित एवं व्यवस्थित थे कि शारीरिक अभ्यास स्वतः हो जाता था। आध्यात्मिक विकास भी उस समय की शिक्षा का आधार ही था। मानसिक विकास ज्ञानमूलक शिक्षा के कारण तर्क द्वारा होता था। नैतिक विकास सर्वत्र वर्धनी शिक्षा के कारण था।

यों के सर्वांग विकास पर विशेष बल दिया



### 3. गुरुकुल-प्रणाली

#### Garukul-System

भारतीय सभ्यता का विकास वनों में हुआ है न कि नगरों में। सामान्यतया गुरुकुल प्रकृति की गोद में स्थित होते थे और शिष्यों पर केवल गुरु के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता था क्योंकि आश्रम का लौकिक केवल गुरु का व्यक्तित्व होता था अतः छात्रों में गुरु के गुणों का आना स्वामात्रिक ही था। गुरुकुल में नियमों का पालन होता था और प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ब्रह्मचर्य जीवन अपेक्षित करना आवश्यक था जिससे शारीरिक सौष्ठव और मानसिक प्रवीणता स्वतः ही आती थी। गुरुकुलों में रहने के कारण सभी शिष्य विचाररत रहते थे और गुरु-सेवा करके अपने जीवन को धर्म करते थे।

#### 4. शिक्षक-गुरु सम्बन्ध

#### People Teacher Relations

प्राचीन भारतीय शिक्षा की एक विशेषता यह भी थी कि शिष्य और गुरु के सम्बन्ध पिता और पुत्र के समान थे और गुरु को आध्यात्मिक गुरु समझा जाता था।

अपवाद है गुरु के व्यक्तित्व में ही अपने जीवन की पूर्णता सम्भलते थे।

### 5. निःशुल्क शिक्षा

#### Free Education

प्राचीन भारत में ब्राह्मण का यह पुरातन कर्तव्य था कि वे अपने शिष्यों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। शिक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक शिष्य दक्षिणा देते थे परन्तु इसका मूल उद्देश्य वैश्विक या आर्थिक नहीं।

### 6. स्त्री-शिक्षा

#### Women Education

प्राचीन भारत में स्त्री-शिक्षा का प्रसार था। बालिकाओं के लिए भी उपयुक्त संस्कार की व्यवस्था थी। जीवन के सभी क्षेत्रों में स्त्रियाँ पुरुषों के समान ही कार्य करती थीं। स्त्री-शिक्षा के प्रावधान के कारण ही लोपा, अपासा, विश्ववारा, गार्गी, मैत्रीय आदि विदुषियों का प्रादुर्भाव हुआ।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्राचीन शिक्षा के उद्देश्य महान् थे। चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास और सामाजिक समृद्धि आदि शिक्षा के आदर्श थे।

### 21.04 शिक्षा के विभिन्न चरण

#### Different Stages of Education

प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में दो चरण थे जिनका विवरण इस प्रकार है—

## 1. प्राथमिक शिक्षा

### Primary Education

प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा का वह स्थान तो नहीं था जो आधुनिक युग में है तथापि कुछ तथ्यों<sup>1</sup> के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उपनयन संस्कार से पूर्व शिक्षा की व्यवस्था थी और उस शिक्षा का स्वरूप प्राथमिक अथवा प्रारम्भिक शिक्षा जैसा था।

प्राचीन भारत में शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी, इसके विषय में कुछ स्पष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं होते और प्राचीन भारतीय ग्रन्थ इस दृष्टि से मौन हैं। ऋग्वेद के आधार पर यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा सम्भवतः पाठशालाओं में ही दी जाती थी, परन्तु पाठशालाओं का स्वरूप आधुनिक पाठशालाओं के समान नहीं था। डा० अल्तेकर के अनुसार सम्भवतः प्राथमिक शिक्षा गृह परिवारों में ही जाती होगी।<sup>2</sup>

प्राथमिक स्तर पर बालक के अन्तर्गत इतनी योग्यता तो अवश्य विकसित की जाती थी जो उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायक हो सके। सामंजस्यपूर्ण धार्मिक संस्कारों के द्वारा बालकों में उच्च शिक्षा की क्षमता विकसित करना प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य था। साधारणतया धार्मिक ग्रन्थों को कंठस्थ करना, भाषा का प्रयोग एवं सामान्य व्याकरण ज्ञान इन स्तर की मूलतम अपेक्षित क्षमता थी।<sup>3</sup>

## 2. उच्च शिक्षा

### Higher Education

वैदिक काल में उच्च शिक्षा हेतु विद्यार्थी गुरु-गृह अथवा आश्रम में जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम में छात्रों का आध्यात्मिक, नैतिक तथा मानसिक विकास किया जाता था। वैदिक काल में सामूहिक रूप से शिक्षा प्राप्त करने वाली शिक्षा संस्थाओं का अभाव था।

उच्च शिक्षा का प्रावधान गुरुकुलों, परिषदों, ढोल, षटिकायें, मठ, विद्यापीठ, मन्दिर महाविद्यालय एवं विरविद्यालयों में था। प्राचीन काल में ऋग्वेद, यजुर्वेद, संहिते, सामवेद, इतिहास, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, देव-विद्या, ब्रह्म-विद्या, नक्षत्र-विद्या, धर्म-विद्या, व्याकरण, ज्योतिष आदि विषयों का अध्ययन किया जाता था।

1. C. Kunhan Raja, *Some Aspects of Education in Ancient India*.
2. It must have been given in the family so long as it continued to be the Centre of education.

—Dr. Alokhay

## 21.05 मुख्य शिक्षा केन्द्र और विश्वविद्यालय Educational Centres & Universities

जैसा कि हम पहले कह आये हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य विद्यापियों की आन्तरिक उन्नति करना था। वैदिक काल और ब्राह्मण काल में बौद्ध-काल और आधुनिक काल के समान सुव्यवस्थित शिक्षा केन्द्र नहीं थे। जहाँ तक प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षण केन्द्रों का प्रश्न है—उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

### 1. तक्षशिला Taxsila

प्राचीन भारत में तक्षशिला शिक्षा का महत्वपूर्ण केन्द्र था जिसकी स्थापति देश और विदेशों में व्याप्त थी। तक्षशिला गांधार प्रदेश की राजधानी थी और बाल्मीकि रामायण के अनुसार दस नगर की नींव भरत ने डाली थी। ईसा से पूर्व सातवीं शताब्दी तक तक्षशिला शिक्षा का केन्द्र माना जाने लगा था।

तक्षशिला में कोई विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय नहीं था और वहाँ की शिक्षा पारिवारिक प्रणाली पर आधारित थी। यहाँ पर अनेकों वैयक्तिक गुरुकुल थे और विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। यही मूल कारण है कि हमें विश्व-विद्यालय न मानकर शिक्षा का केन्द्र मानना अधिक उचित होगा। तक्षशिला में देश के विभिन्न भागों से अनेकों विद्वान एकत्रित हो गये थे और अपनी-अपनी हवि के अनुसार शिक्षा प्रदान करते थे।

तक्षशिला में आकर उच्च शिक्षा प्राप्त करता ही प्रत्येक विद्यार्थी का प्येय होता था। वेदांग, व्याकरण, आयुर्वेद, धैनिक विद्या, ज्योतिष, वास्तुकला, कृषि, व्यापार, सव्य विद्या आदि विषयों का ज्ञान दिया जाता था। इनके अतिरिक्त साहित्यिक विषयों में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का कठस्थ करना आवश्यक समझा जाता था। वैज्ञानिक विषयों में अठारह शिल्पों का अध्ययन किया जाना था जिनमें आयुर्वेद, चिकित्सा, धनुर्विद्या, युद्धकला, मुनीयो, व्यापार, कृषि, रथ संचालन, इन्द्र-जाल गुप्तनिधि अन्वेषण आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

### 2. नालन्दा विश्वविद्यालय Nalanda University

पटना से चालीस मील दक्षिण-पश्चिम की ओर नालन्दा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी बड़ीतरी गौरवमयी भाषा की याद दिला रहे हैं। प्रारम्भ में यहाँ एक छोटा सा गाँव था परन्तु महात्मा बुद्ध के अनेकों धर्मोपदेश इस स्थान पर हुए और इसका महत्त्व धीरे-धीरे बढ़ता चला गया। नालन्दा विहार की स्थापना के विषय में यह भी कहा जाता है कि इसके संस्थापक सम्राट अशोक थे।

नालन्दा का प्रमुख शिक्षा के केन्द्र के रूप में जो उद्भव हुआ वह तीसरी सताब्दी से माना जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि सम्भवतः नालन्दा ब्राह्मणीय शिक्षा का केन्द्र रहा होगा। नालन्दा विश्वविद्यालय की निम्नलिखित विशेषताएँ थीं—

1. प्रारम्भ में नालन्दा में एक अगवा दो सठ थे, कालान्तर में यह अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा का केन्द्र हो गया और चीन, कोरिया, जावा, सुमात्रा आदि से अनेकों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार मठों की संख्या भी बढ़ती गयी।
2. नालन्दा के विकास में कुमार गुप्त प्रथम, बुद्ध गुप्त, बालिदत्त, बख आदि ने सक्रिय सहयोग दिया और प्रारम्भ में पाँच सौ व्यापारियों ने दस कराह स्वर्ण मुद्राओं से नालन्दा के लिए भूमि खरीदी और उसे महात्मा बुद्ध को अर्पित किया। नवी सताब्दी में राजा बालपुत्र देव ने नालन्दा के विकास हेतु छ गौंन दिये।
3. सम्राट अशोक की नालन्दा विहार का प्रथम संस्थापक कहा जाता है।
4. नालन्दा विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाता था तथा न्यूनतम आयु बीस वर्ष थी।
5. नालन्दा विश्वविद्यालय में निःशुल्क परीक्षा का प्रावधान था।
6. नालन्दा में कुल 1,510 शिक्षक थे।
7. विश्वविद्यालय में वैदिक धर्म, जैन धर्म, और बौद्ध धर्म के विषयों की शिक्षा दी जाती थी। ह्युएनत्सांग ने योग शास्त्र, म्याय, क्षुद्र विद्या, प्राणह्य विद्या के विषयों आदि का अध्ययन किया था।
8. अध्यापन पद्धति के तीन स्वरूप—व्याख्यान पद्धति, शब्द विवाद और पुस्तक व्याख्या आदि का प्रयोग किया जाता था। छात्रों की संका का समाधान प्रश्नोत्तर विधि से किया जाता था।
9. विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बहुत विशाल था जिसके तीन भवन थे जिन्हें रत्न सागर, रत्नोदधि भवन थे जिन्हें रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक कहा जाता था।

उपरोक्त विशेषताओं से स्पष्ट है कि नालन्दा विश्वविद्यालय अपने में शिक्षा का महत्वपूर्ण केन्द्र था, परन्तु इस ज्ञान की धरोहर को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया।

### 3. वलभी विश्वविद्यालय Valabhi University

काठियावाड़ के पूर्व किनारे पर वला नाम के स्थान में वलभी विश्वविद्यालय था। यह नालन्दा विश्वविद्यालय का प्रतिद्वन्द्वी था। 640 ई० में वलभी के अन्तर्गत 100 विहार थे। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा के अतिरिक्त व्याकरण, व्यवहार शास्त्र, साहित्य आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। वला पर अरबों पर आक्रमण किया और यह शिक्षा केन्द्र भी विदेही आक्रमण का शिकार बना।

### 4. विक्रमशिला विश्वविद्यालय Vikramshila University

विक्रमशिला उत्तरी मगध में मगादह पर एक सुन्दर पहाड़ी पर स्थित था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना सम्राट चर्मपाल ने की थी। इसमें छठी मन्दिर थे। प्रत्येक मन्दिर का एक अध्यक्ष था जिसे आचार्य कहते थे। विश्वविद्यालय में कुल मिलाकर 114 आचार्य थे। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थी से अनेकों छात्र विद्या प्राप्त करने आते थे।

विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कुलपति होता था और अन्य प्रबन्धों के लिए अनेकों समितियाँ थी। पाठ्य विषयों के रूप में अनेको विषयों का अध्ययन होता था जिनमें प्रमुख रूप से व्याकरण, दर्शन, लक्ष्मी आदि का अध्ययन होता था।

1203 ई० में बलियार खिलजी ने आक्रमण किया और इस विद्या-मन्दिर को भी आक्रान्ताओं का कोपमाजन बनना पड़ा।

### 5. जगद्धला विश्वविद्यालय Jagaddala University

बंगाल के पालवंशीय सम्राट राजा रामपाल ने इस विश्वविद्यालय को मंगलदह पर रामावली नामक स्थान पर बनवाया था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का केन्द्र था। इस विश्वविद्यालय में विमुक्ति चन्द्र, मुपाकर, मोधाकर गुप्त नामक प्रसिद्ध आचार्य थे। इन आचार्यों की स्थाति केवल भारत में ही नहीं बल्कि तिब्बत में भी की और इनके प्रसिद्ध ग्रन्थों का अनुवाद तिब्बती भाषा में हुआ था।

1203 ई० में इसे भी मुघलमनों के आक्रमण का शिकार होना पड़ा।

### 6. ओदन्तपुरी विश्वविद्यालय Odantapuri University

इस विश्वविद्यालय की स्थापना पालवंश के उत्थान से पूर्व ही हुई थी। इस विश्वविद्यालय में एक पुस्तकालय था जो शास्त्रीय और बौद्ध साहित्य की बहु



मूल्य पुस्तकों से परिपूर्ण था। इस विश्वविद्यालय में लगभग 1,000 मित्र रहते। इस विश्वविद्यालय के विषय में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है।

## 7. मिथिला विश्वविद्यालय Mithila University

मिथिला का प्राचीन नाम विदेह था जो उपनिषद् काल में शास्त्रीय शिक्षा का केन्द्र था। बौद्ध काल में यह मिथिला के नाम से प्रसिद्ध हुआ और 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक यह महत्वपूर्ण शिक्षा केन्द्र रहा। मिथिला में शिक्षा स्तर बहुत ऊँचा था और स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता था। सम्पूर्ण अध्ययन समाप्त करने के पश्चात् अन्तिम परीक्षा होती थी जिसे 'सलका' कहते थे। इस परीक्षा के द्वारा छात्र का पुस्तक ज्ञान देखा जाता था।

इस विश्वविद्यालय के विद्वानों ने अनेकों महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे। यहाँ तत्त्वज्ञान, कलाओं, साहित्य एवं वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन किया जाता था।

## 8. नदिया विश्वविद्यालय Nadia University

पालक के शासकों के प्रयासों और सहायता से ग्यारहवीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इस विश्वविद्यालय की स्थापति उसके शिक्षण स्तर के कारण दूर-दूर तक फैली। नालन्दा और विक्रमशिला के नष्ट होने के पश्चात् यह शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था। इस विश्वविद्यालय के शिक्षकों को वाद-विवाद में निपुण होना अत्यन्त आवश्यक था। कुछ तथ्यों से यह भी प्राप्त होता है कि इस विश्वविद्यालय में छात्र बीस वर्ष तक रहते थे। कुछ प्रमाण इस प्रकार के भी मिलते हैं जिनके द्वारा यह कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय में 4,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे और शिक्षकों की संख्या 800 थी। लॉ, वास्तु, कानून, काव्य, ज्योतिष, व्याकरण आदि का विशेष ज्ञान प्रदान करना इस विश्वविद्यालय की विशेषता थी।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सामाजिक राष्ट्रीय प्रगति तथा सभ्यता और सभ्यता का उत्थान करना था। भारत के अतीत में शिक्षा की सुन्दर व्याख्या थी। प्राचीन शिक्षा पद्धति ने उस समय के समाज को अत्यन्त प्रगतिशील और अनेकों विचारकों एवं

विद्वान् छात्राणाम् को व्यापन कार्ये मे कोर्द बाधा तो नही है । प्राचीन भारत मे शिक्षा पर कोर्द जातीय बंधन साम्प्रदायिक प्रभाव नही था ।<sup>1</sup>

- 
1. Education in ancient India was free from any external control like that of the state or the Government or any party politics. It was one of the king's duties to see that the learned pundits pursued their studies and their duty of imparting knowledge without interference from any source whatever. So also, education did not suffer from any communal interest or prejudices in India.

P. H. Prabhu, *Hindu Social Organization*, p. 108.

## अध्याय बाईस

### Chapter Twenty Two

इंग्लैण्ड, अमेरिका और रूस में शिक्षा

*Education in England, America & Russia*

अध्ययन बिन्दु

Learning Points

इंग्लैण्ड में शिक्षा

#### EDUCATION IN ENGLAND

##### 22.01 प्राथमिक शिक्षा का ऐतिहासिक विकास

1. सर जेम्स फ्राहम बिल (1853)
2. न्यू कास्टिल आयोग (1861)
3. फोर्मेटर अधिनियम (1870)
4. पास कमीशन (1888)
5. शिक्षा अधिनियम (1902)
6. फिजर अधिनियम (1919)
7. हेरो आयोग (1926)
8. स्पेन्स प्रतिवेदन (1938)
9. शिक्षा अधिनियम (1944)

##### 22.02 प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य

##### 22.03 माध्यमिक शिक्षा का ऐतिहासिक विकास

1. बालुआ आयोग (1894-95)
2. माध्यमिक शिक्षा और मजदूर राष्ट्रीय सरकार (1924)
3. हेरो प्रतिवेदन (1926)
4. नारवुड आयोग (1943)
5. शिक्षा अधिनियम (1944)

##### 22.04 माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति

##### 22.05 उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा का ऐतिहासिक विकास  
विश्वविद्यालयों का विकास



### अमेरिका में शिक्षा EDUCATION IN U. S. A

- 22.06 प्राथमिक शिक्षा
- 22.07 माध्यमिक शिक्षा
- 22.08 उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा का ऐतिहासिक विकास  
उच्च शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य  
उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएँ  
उच्च शिक्षा का प्रसार

### रूस में शिक्षा EDUCATION IN RUSSIA

- 22.09 रूसी शिक्षा का ऐतिहासिक विकास
  1. सन् 1917 से 1932 तक
  2. सन् 1932 से 1936 तक
  3. सन् 1936 से 1944 तक
  4. सन् 1944 से 1952 तक
  5. सन् 1952 से वर्तमान समय तक
- 22.10 शिक्षा का षट्पद
- 22.11 शिक्षा के विभिन्न स्तर
  - प्राथमिक शिक्षा
  - माध्यमिक शिक्षा
  - उच्च शिक्षा

# इंग्लैण्ड, अमेरिका और रूस में शिक्षा *EDUCATION IN ENGLAND, AMERICA AND RUSSIA*

इंग्लैण्ड में शिक्षा  
 EDUCATION IN ENGLAND

वर्षानु वर्षानुसार बर्सेमोल में पैदा हुए वह देश जहाँ और से बहुत शाप विरा हुआ है जो औद्योगिक दृष्टि से पूर्ण मनुष्य है। देश की मनुष्य के कारण ऐच्छिक दृष्टि से भी वह पूर्णरूपेण मनुष्य है वहीं आज यह प्रतिकूल वातावरण है। वैज्ञानिक और प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से भी वह देश आदर्श प्रयत्नियों है। इंग्लैण्ड की ऐच्छिक वित्तव्यवस्था वहीं की परम्परागत संस्कृति के कारण है जिसके कारण वहीं की वास्तविक और उच्च शिक्षा बहुत प्रभावित हुई है। वर्ष 1900 से 1944 तक शिक्षा प्रणालि में अनेकों परिवर्तन हुए और जिनका मूल आधार ज्ञान की आवश्यकताओं को पूरा करना था।

## 22.01 प्राथमिक शिक्षा का ऐतिहासिक विकास

*Historical Development of Primary Education*

इंग्लैण्ड में अष्टादशवीं शताब्दी में प्राथमिक शिक्षा का विकास हुआ। वर्ष 800 से 1833 तक कुछ इस प्रकार की संस्थाएँ थी जो प्राथमिक शिक्षा का

संचालन करती थी। मूलतः इन शिक्षा संस्थाओं का उत्तरदायित्व धार्मिक संस्थाओं का था। इन विद्यालयों को डेन विद्यालय और चर्च विद्यालय कहा जाता था। सन् 1830 में रविवारीय विद्यालयों की स्थापना हुई। सन् 1903 में कुछ अन्य विद्यालयों को खोला गया जिनका उद्देश्य रविवार के दिन बालकों को शिक्षा प्रदान करना था। सन् 1914 में ब्रिटिश फारेन स्कूल सोसाइटी (British Foreign Schools Society) की स्थापना की गई जिसने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में काफी सहयोग दिया।

प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु निम्नलिखित ऐंथिक कार्य उल्लेखनीय हैं—

#### 1. सर जेम्स ग्राहम बिल (1853)

Sir James Graham Bill (1853)

इस बिल में यह प्रावधान रखा कि वारंटानों में काम करने वाले बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाये। इसके अतिरिक्त शाला बनाने के निर्माण हेतु और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा भ्रण की व्यवस्था होनी चाहिए।

#### 2. न्यू कास्टिल आयोग (1861)

New Castle Commission (1861)

सन् 1861 में इस आयोग की नियुक्ति हुई। आयोग ने सर जेम्स ग्राहम बिल में आवश्यक सुधार हेतु सुझाव दिये। सन् 1860 तक इंग्लैण्ड में जन-जागृति आ चुकी थी और शिक्षा के महत्व को राष्ट्र के विवास हेतु अनिवार्य समझा जाने लगा था। अतः आयोग द्वारा प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु अनेकों शिक्षारिक्तों को कार्य रूप में परिणत करने पर विशेष बल दिया गया।

#### 3. फोर्सेटर अधिनियम (1870)

Forester Act (1870)

सन् 1870 में यह अधिनियम प्रारम्भिक शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए पारित हुआ था। इस अधिनियम का विशेष उद्देश्य बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना था। अधिनियम के आधार पर स्थानीय शिक्षा परिषदों को यह आदेश दिया गया कि उन स्थानों में जहाँ बच्चों की शिक्षा व्यवस्था नहीं है वहाँ नयी छायाएँ खोली जायें और शिक्षा सुविधाओं की प्रगति हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु निजी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाये।

#### 4. क्रॉस कमिशन (1883)

Cross Commission (1883)

सन् 1883 में यह आयोग ने प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार हेतु कुछ

दिये। प्रारम्भिक शिक्षा में सुधार हेतु आयोग ने योग्य शिक्षकों की आवश्यकता पर बल दिया। अध्यापकों की प्रशिक्षण सुविधाओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालयों को अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने चाहिए जिससे अध्यापकों को अधिक कार्यशील बनाया जा सके।

### 5. शिक्षा अधिनियम (1902)

#### Education Act (1902)

सन् 1902 में शिक्षा अधिनियम पारित हुआ जिसके अनुसार स्कूल बोर्डों को समाप्त कर दिया गया। स्कूल बोर्डों को समाप्त कर प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को दे दिया गया। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, हस्तकला, वागवानी और विज्ञान आदि विषयों में सम्मिलित किया गया।

### 6. फिशर अधिनियम (1918)

#### Fisher Act (1918)

सन् 1918 के फिशर अधिनियम से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इस अधिनियम के अनुसार प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया। पूर्व प्राथमिक स्तर पर स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को 2 वर्ष से 5 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा सुविधाओं का प्रसार करने हेतु कहा गया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने की अवधि 14 वर्ष निर्दिष्ट कर दी गई।

### 7. हेडो आयोग (1926)

#### Hadowe Commission (1926)

सन् 1926 में हेडो आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को और अधिक सुव्यवस्थित करने की सिफारिश की। आयोग के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा को पुनर्संगठित किया गया। आयोग के सुझाव के अनुसार अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को सात पन्द्रह वर्ष तक निर्दिष्ट कर दी गई।

### 8. स्पेन्स प्रतिवेदन (1938)

#### Spens Report (1938)

इस प्रतिवेदन 1938 में प्रस्तुत किया। परन्तु इस प्रतिवेदन के सुझावों के अनुसार कार्य न हो सका क्योंकि द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो गया तथा इसलिए इस प्रतिवेदन का ऐतिहासिक महत्व बहुत है।

### 9. शिक्षा अधिनियम (1944)

#### Education Act (1944)

सन् 1944 के शिक्षा अधिनियम के सुझावानुसार प्रारम्भिक शिक्षा का नाव

प्राथमिक शिक्षा कर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का बहुत कुछ श्रेय इसी अधिनियम को है।

### 22.02 प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य Aims of Primary Education

इंग्लैण्ड में प्राथमिक शिक्षा को दैक्षिक जीवन के आधार स्तम्भ के रूप में माना जाता है और इसीलिए प्राथमिक शिक्षा को अत्यन्त ही सुव्यवस्थित एवं संगठित रूप प्रदान किया गया है। प्राथमिक शिक्षा द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति अपेक्षित है—

1. शारीरिक विकास।
2. चरित्र निर्माण।
3. भाषी शिक्षा हेतु साधना जागृत करना।
4. बौद्धिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास।
5. सांस्कृतिक शिक्षा।
6. माध्यमिक शिक्षा।

इंग्लैण्ड की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यहाँ इसी स्तर से बच्चों में अच्छे स्वभाव विकसित किये जाते हैं जिससे उनमें आत्म अनुशासन की भावना का विकास होता है।

### 22.03 माध्यमिक शिक्षा का ऐतिहासिक विकास Historical Development of Secondary Education

इंग्लैण्ड में माध्यमिक शिक्षा का इतिहास भी प्रायः उतना ही पुराना है जितना प्राथमिक शिक्षा का। इस देश में माध्यमिक शिक्षा का आरम्भ सत्रहवीं शताब्दी से हुआ। उसीसेबी शताब्दी तक पब्लिक और ग्रामर स्कूलों की स्थापना हो चुकी थी और ये विद्यालय माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करते थे।

इंग्लैण्ड में माध्यमिक शिक्षा के ऐतिहासिक विकास का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

1. ब्राइस आयोग (1894-95)  
Bryce Commission (1894-95)

इस आयोग ने इंग्लैण्ड की माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप को निश्चित कर महत्वपूर्ण सिद्धान्तों को स्पष्ट किया। यदि यह कहा जाय कि बीसवीं शताब्दी में माध्यमिक शिक्षा का प्रारम्भ इसी आयोग के सुझाव से हुआ तो अतिरिक्त न होगी। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के प्रसार हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये—

1. सामाजिक और आर्थिक दशाओं के अनुरूप ही माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में वांछित परिवर्तन किये जायें।

III. शिक्षण सरथाओं को निर्देशन देने के लिए 'एजुकेशन बोर्ड' की जाये।

3. केन्द्रीय मन्त्री-मण्डल में वृषक शिक्षा मन्त्रालय होना चाहिए। मन्त्री मण्डल में वैश्विक विभाग के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।

4. शिक्षा सरथाओं का कार्य देने के लिए वर्गान्त संस्था में विद्यालयों की नियुक्ति की जाय।

5. अध्यापकों की सेवाओं को रखायी बनाया जाये।

6. प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाया जाये।

## 2. माध्यमिक शिक्षा और मजदूर हलीय सरकार (1924)

Secondary Education & Labour Govt., (1924)

सन् 1924 में मजदूर हलीय सरकार बनी। सरकार के परिवर्तन के स्वकार नीतियों में परिवर्तन आता स्वाभाविक था। डा० टोनी ने माध्यमिक के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये। माध्यमिक शिक्षा को देश की आवश्यक के अनुरूप बनाने का विचार किया गया और डा० टोनी के विचारों ने सरकारी जनता को बहुत प्रभावित किया।

## 3. हैडो प्रतिवेदन (1926)

Hadowe Report (1926)

डा० टोनी के विचारों के कारण सरकार ने डा० हैडो की अध्यक्षता में समिति की नियुक्ति की। समिति ने माध्यमिक स्तर में प्रवेश की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई और समाप्ति की आयु 15 वर्ष निर्दिष्ट की गई। इसने माध्यमिक स्तर पर कला एवं संगीत को पाठ्यक्रम में प्रविष्ट करने का फैसला दिया।

## 4. नारवुड आयोग (1943)

Norwood Commission (1943)

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् इंग्लैण्ड की जनता ने यह स्वीकार किया देश के पुर्ननिर्माण और विकास के लिए शिक्षा अत्यन्त अनिवार्य है। इस आवश्यक के फलस्वरूप सर सरिल नारवुड की अध्यक्षता में इस आयोग की नियुक्ति की जिसने निम्नलिखित सुझाव दिये।

1. माध्यमिक शाला में प्रवेश की आयु 13 वर्ष कर देनी चाहिए।

3. माध्यमिक शिक्षा का आधार विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता और योग्यता होनी चाहिए।
4. योग्य छात्रों को आर्थिक सहायता एवं छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए।
5. शिक्षा अधिनियम (1944)  
Education Act (1944)

माध्यमिक शिक्षा को सुदृढीकृत करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये गये—

1. माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार का होना चाहिए।
2. माध्यमिक छात्राओं में प्रवेश की आयु 15 वर्ष निश्चित की गई। इस आयु में आवश्यकतानुसार एक वर्ष की वृद्धि का प्रावधान किया गया।
3. माध्यमिक विद्यालयों को तीन कोटियों में विभाजित करने का सुझाव दिया गया—

- (i) नियोजित माध्यमिक विद्यालय।
- (ii) सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय।
- (iii) स्वतंत्र विद्यालय।

#### 22 04 माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति Present Position of Secondary Education

जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं कि सन् 1944 के अधिनियम द्वारा इंग्लैण्ड में माध्यमिक शिक्षा को सुदृढीकृत रूप प्रदान किया गया। सन् 1948 में एक और शिक्षा अधिनियम पारित हुआ जिससे माध्यमिक शिक्षा को अधिक प्राथमिक और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया गया।

इंग्लैण्ड में तीन प्रकार की माध्यमिक विद्यालय हैं—

- (i) आधुनिक माध्यमिक विद्यालय (Modern Secondary School)
- (ii) ग्रामर विद्यालय (Grammar Schools)
- (iii) प्राविधिक विद्यालय (Technical Schools)

इंग्लैण्ड में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों प्रयोग किये जा रहे हैं जिनके परिणामस्वरूप विभिन्न पाठ्यक्रमों की पुनर्-पुनर् विद्यालय हैं जो इस प्रकार हैं—

- (i) व्यापक विद्यालय (Comprehensive Schools)
- (ii) सामान्य विद्यालय (Common Schools)
- (iii) द्वि-उत्प्रेषण विद्यालय (Bi-lateral Schools)
- (iv) बहु-उत्प्रेषण विद्यालय (Multi-lateral Schools)

क्षेत्र में व्यापक और सामान्य विद्यालय इंग्लैण्ड में माध्यमिक शिक्षा की अधिकतर आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्राविधिक शिक्षा की विशेष व्यवस्था है।





इंग्लैण्ड की विश्वविद्यालयी परम्परा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

1. निवासी एवं एकात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय  
( Residential Cum-Unitary Teaching Universities )
2. संघात्मक विद्याविद्यालय  
( Federal Universities )
3. सम्बद्ध करने वाले विश्वविद्यालय  
( Affiliating Universities )

उपरोक्त सभी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा का प्रावधान है। सन् 1920 से पूर्व विश्वविद्यालयों में बी.ए. ध्यानसे ही अन्तिम परीक्षा थी। इसके अतिरिक्त स्नातकोत्तर स्तर के पश्चात् छोटे-बड़े का प्रावधान भी सभी विश्वविद्यालयों में है।

### अमेरिका में शिक्षा

Education in United States of America

संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। इस राष्ट्र की नवस्था जगमग 350 वर्ष पुरानी है। सन् 1647 ई० तक इस राष्ट्र में बची-बचे की जातियाँ अपने-अपने बालकों की शिक्षा व्यवस्था करती थीं। सन् 1786 ई० तक 7 से 15 वर्ष के बालकों की शिक्षा अनिवार्य थी। इस समय अमेरिका के अधिकतर स्कूलों में शिक्षा की वही व्यवस्था थी जो इंग्लैण्ड में प्रचलित थी।

अमेरिका में सन् 1821 में बोस्टन हाई स्कूल खुला जो अमेरिकन शिक्षा प्रणाली का प्रथम हाई स्कूल था। इसी काल से शिक्षा की योजना स्थानीय प्रा-  
वस्थाओं के अनुसार निश्चित की गई। सन् 1827 में एक नियम के द्वारा यह निश्चित किया गया कि पाँच सौ परिवारों पर एक पुब्लिक स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए।

### 22.06 प्राथमिक शिक्षा

#### Primary Education

अमेरिका में प्राथमिक शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी स्तर से प्रदेश बालक में उन संस्कारों को पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है जिसके द्वारा राष्ट्र की प्रगति सम्भव है। प्रथम छ. से आठ बालकों में सामान्य शिक्षा प्रदान की जाती है। प्राथमिक शिक्षा का आवरण स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार है। सन् 1930 में छ. वर्ष के 66.3 प्रतिशत बालक, सात वर्ष से बारह वर्ष 95.6 प्रतिशत बालक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। 1940 के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अप्पापकों को कमी हो गई, इसका एक मात्र कारण द्वितीय विश्व-युद्ध था। परन्तु प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता बनाए रखी गई।

-- अमेरिका में प्राथमिक शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं--

1. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ।
2. बाल केन्द्रित प्राथमिक शिक्षा ।
3. शिक्षा का सामाजिक आधार ।
4. मनोवैज्ञानिक शिक्षा ।
5. व्यक्तित्व का विकास, प्राथमिक शिक्षा का आधार ।
6. पाठ्यक्रम द्वारा लोकतन्त्रीय भावनाओं का विकास ।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति ही अमेरिका के प्राथमिक शिक्षा की विशेषता है। यही कारण है कि आज अमेरिका समार का सबसे प्रगतिशील देश है। प्राथमिक शिक्षा को सम्पूर्ण शिक्षा का आधार माना जाता है और इसी स्तर पर वे सभी वांछित संस्कार उत्पन्न किये जाते हैं जो देश की समृद्धि में आवश्यक हैं। शिक्षा की प्रभाव से सभी बालकों को प्रभावित करना प्रत्येक अमरीकी का पुरातन कर्तव्य माना जाता है और यही कारण है कि सम्पूर्ण देश में अमानता का विनाश हो चुका है। प्राथमिक शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण अनिवार्य दीक्षिक इकाई के रूप में स्वीकार किया गया है।

## 22.07 माध्यमिक शिक्षा

### Secondary Education

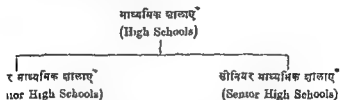
अमेरिका की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को जन जीवन की सामाजिक-प्रक्रिया और मोक्षमार्ग भाषा पर आधारित दीक्षित तन्त्र स्वीकार किया गया है। यहाँ की माध्यमिक शिक्षा मानवीय स्वतन्त्रता और स्वतंत्रता पर आधारित है जिसके कारण यह शिक्षा स्थानीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम है।

माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण की सभी प्रक्रियाएँ परिवर्तित हुई हैं। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनकों परिवर्तन हुए जिसके कारण अनकों प्रकार की माध्यमिक शिक्षा का संशोधन हो आते हैं। अमेरिका में निम्नलिखित माध्यमिक शिक्षाएँ हैं--

1. कक्षा माध्यमिक शिक्षा (Classroom Secondary Education)
2. दूरस्थ शिक्षा माध्यमिक शिक्षा (Distance Secondary Education)
3. निम्नलिखित माध्यमिक शिक्षाएँ (Below Secondary Education)
4. माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education)

### 5. हस्तकला प्रशिक्षण माध्यमिक शालाएँ ( Manual Training High Schools )

अमेरिका में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप निम्नलिखित है—



पाठ्यक्रम के अनुसार शालाओं का वर्गीकरण

Classification of the Institutions according to Curriculum

अमेरिका की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वहाँ विशिष्ट पर बहुत जोर दिया जाता है और इसी कारण वहाँ की माध्यमिक शालाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है।

संक्षेप में अमेरिकी माध्यमिक शालाओं की पाठ्यक्रम के आधार पर तीन में विभाजित किया जा सकता है—

#### 1. सामान्य शालाएँ ( Ordinary Schools )

(i) व्यापक माध्यमिक शालाएँ

(Comprehensive Secondary Schools)

(ii) सीमित शालाएँ

(Limited Schools)

#### 2. विशिष्ट पाठ्यक्रम शालाएँ ( Specialized Schools )

(i) व्यावसायिक शालाएँ

(Vocational Schools)

(ii) औद्योगिक शालाएँ

(Industrial Schools)

#### 3. अल्पकालीन शालाएँ ( Part Time Schools )

(i) निरन्तर शालाएँ

(Continuous Schools)

(ii) प्रौढ़ों की रात्रि-कालीन शालाएँ

(Adults Evening Schools)

उपरोक्त साक्षात्कारों से स्पष्ट है कि अमेरिका में सामान्य और विशेष दोनों ही पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है। अमेरिकी माध्यमिक साक्षात्कारों के पाठ्यक्रम की सबसे विशेष बात यह है कि वहाँ का पाठ्यक्रम इतना विविधता से पूर्ण है कि छात्र किसी भी विषय को ले सकता है। यह छात्रों की रुचि और योग्यता पर आधारित है कि किस विषय का चयन करे। पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना ही माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम की विशेषता है।

## 22.08 उच्च शिक्षा

### Higher Education

अमेरिका की उच्च शिक्षा का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है जितना प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का इतिहास। सन् 1636 में प्रथम महाविद्यालय बोस्टन में स्थापित हुआ। सन् 1760 तक अमेरिका में ही महाविद्यालय स्थापित हो चुके थे। सन् 1838 में रिचमोंड के लिए हाथथोक में एक महाविद्यालय स्थापित हुआ।

### उच्च शिक्षा का ऐतिहासिक विकास

#### Historical Development of Higher Education

सन् 1637 में जॉन हार्वर्ड ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना की। पहले यह महाविद्यालय बोस्टन में स्थापित हुआ था परन्तु बाद में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का नाम हार्वर्ड के नाम पर रख दिया गया। सन् 1700 के आरम्भ में के पश्चात इसे विश्वविद्यालय की छात्रा की गई और आज यह विश्व में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का नाम से विख्यात है।

सन् 1701 में पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सन् 1808 में ब्राउन विश्वविद्यालय बना। सन् 1783 में उत्तरी कोरासीन विश्वविद्यालय बना। सन् 1791 में वेसलेन विश्वविद्यालय बना। सन् 1812 में कोर्नेल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।

### उच्च शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य

#### Aims & Objectives of Higher Education

अमेरिका में उच्च शिक्षा का उद्देश्य समाज में उन्नति लाना है। अमेरिका एक उच्च शिक्षा देश है और समाज की सुदृढ़ता के लिए इसे उच्च शिक्षा का उद्देश्य है।

सन् 1887 में उच्च शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित है -  
 1. उच्च शिक्षा का उद्देश्य समाज में उन्नति लाना है।  
 2. उच्च शिक्षा का उद्देश्य समाज में उन्नति लाना है।  
 3. उच्च शिक्षा का उद्देश्य समाज में उन्नति लाना है।

2. सामाजिक समस्याओं के समाधान कर सकने की क्षमता का विकास करना ।

3. प्रजातान्त्रिक जीवन दर्शन के प्रति वास्था उत्पन्न करना ।

4. पारस्परिक सहयोग और अन्तर्राष्ट्रीय सहभावना का विकास करना ।

उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएँ

*Institutions to impart Higher Education*

अमेरिका में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाएँ हैं—

1. जूनियर कॉलेज
2. सामान्य कॉलेज
3. टेक्निकल कॉलेज
4. म्यूनिसिपल कॉलेज
5. लिबरल आर्ट्स कॉलेज
6. विश्वविद्यालय
7. राज्य विश्वविद्यालय
8. लैंड ग्राण्ट कॉलेज तथा विश्वविद्यालय
9. वेबुएट स्कूल
10. हायर टेक्निकल स्कूल

उच्च शिक्षा का प्रसार

*Expansion of Higher Education*

अमेरिका में उच्च शिक्षा का प्रसार बहुत गति से हुआ है। प्राप्त आँकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सन् 1828 में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली केवल 25 संस्थाएँ थीं जिनमें केवल 3,200 छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। सन् 1950 तक शिक्षण संस्थाओं की संख्या 1,788 हो गई और छात्रों की संख्या 2,500,000 हो गई। आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अमेरिका संसार का सबसे अधिक देश है। तात्त्विक नं० 22.1 में यह स्थिति स्पष्ट हो गई है।

तालिका न० 22.1  
अमेरिका में उच्च शिक्षा  
Higher Education in America

वर्ष	छात्र संख्या	शिक्षण संस्था
1858	3,200	1
1840	16,233	25
1860	56,120	175
1950	2,500,000	1,407
1955	— —	1,788
		1,850

रूस में शिक्षा  
Education in Russia

रूस की प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए और वर्गहीन समाज की स्थापना करने के लिए शिक्षा ने उत्कृष्टतम भूमिका निभाई है। संसार में सम्भवतः कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैधानिक समता विद्यमान हो। रूस ही ऐसा देश है जहाँ शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रयोग किया गया है और समाजवादी राज्य की स्थापना की गई है। रूस का प्रदेश निवासी लेनिन के इस मत से सहमत हैं कि 'तुम साम्यवादी राज्य की स्थापना निरक्षर लोगों से नहीं कर सकते'।

22.09 रूसी शिक्षा का ऐतिहासिक विकास  
Historical Development of Russian Education

रूस की शिक्षा का इतिहास बहुत पुराना है। युरिया की दृष्टि से यह उतम होगा यदि रूस की शिक्षा प्रगति को सन् 1917 की प्रगति के पश्चात् माने क्योंकि रूस की प्रगति से पूर्व इस विद्यालय में भाग्य पर नजर आता था शिक्षा व्यवस्था शासकों और सामान्यों के हाथ में थी। जो लोगों बहुत

1. You cannot build a Communist state with an illiterate people.

• शिक्षा को ज़रूरी और विशेष के सिद्ध सुरक्षित थी। जनता के लिए शिक्षा भी प्रकार-  
 • की शिक्षा सुविधा तभी थी और तब और निरक्षरता का बीतबाता सा-मतः  
 • संबंध निश्चित था और इन सभी घटनाओं के कारण सन् 1917 में जन-कान्ति  
 • हुई। सन् 1917 के पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत प्रगति हुई जिसका ऐतिहा-  
 • सिक विकास इस प्रकार हुआ—

#### 1. सन् 1917 से 1932 तक

From 1917 to 1932

सन् 1919 में सर्वप्रथम यह घोषणा हुई कि सत्तरह वर्ष तक के बालकों के  
 • लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होगी। इस घोषणा के परिणाम  
 • स्वरूप पहले प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का प्रसार करना अनिवार्य  
 • हो गया। मास्टन योजना के आधार पर छोटीछोटी शिक्षा की व्यवस्था हुई।

#### 2. सन् 1932 से 1936 तक

From 1932 to 1936

• इस काल में सन् 1919 की घोषणा के अनुसार व्यावहारिक पक्षों पर विचार  
 • किया गया और स-सर्वाथ शिक्षा को अनिवार्य रूप प्रदान करने का प्रयास किया  
 • गया। इस समय तक स-ने औद्योगिक दृष्टि से क्रांति प्रवृत्ति करती थी। अतः यह  
 • अनिवार्य था कि व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाये। इस समय की  
 • महत्वपूर्ण माध्यमिक शिक्षा थी और इसी के अनुसार सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था  
 • को पुनः सुस्थापित किया गया और सम्पूर्ण शिक्षा की प्राप्ति केन्द्रित कर दिया गया।

#### 3. सन् 1936 से 1944 तक

From 1936 to 1944

• इस काल में शिक्षा की आशाशील प्रगति हुई और माध्यमिक शिक्षा स्तर पर  
 • पाठ्यक्रम का विभिन्निकरण कर दिया गया। विभिन्न व्यवसायों के लिए छात्रों को  
 • प्रशिक्षण दिया गया। इस काल में यह भी कानून पास हो गया कि 14 वर्ष से पूर्व  
 • किसी को किसी भी प्रकार की नौकरी न दी जाये।

#### 4. सन् 1944 से 1952 तक

From 1944 to 1952

• इस काल तक स-सर्वोच्च स्तर पर सुरक्षित हो चुका था। सभी स्तर के पाठ्य-  
 • क्रमों को परिष्कृत कर दिया गया था। देश की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के  
 • उद्देश्य निश्चित हो चुके थे। शिक्षा को अत्यधिक वैज्ञानिक और प्राविधिक बना  
 • दिया गया था और देश आर्थिक दृष्टि से पूर्णतया स्वावलम्बी हो चुका था।

#### 5. सन् 1952 से वर्तमान समय तक

From 1952 to Present Day

सन् 1952 के पश्चात् स-ने जो प्रगति की वह विश्व के समय पर स्वतः  
 • दृष्टिगत है। शिक्षा के सभी क्षेत्रों को नवीन रूप प्रदान किया गया। आज इस





## तालिका नं० 22 2

रूस में उच्च शिक्षा की प्रगति

Progress of Higher Education in Russia

वर्ष	शिक्षा संस्थाएँ	छात्र संख्या
1914	95	117,000
1946	712	653,000
1951	897	1,356,000
1952	890	1,410,000
1956-57	1001	2,756,000

इस समय रूस में 33 विश्वविद्यालय हैं। सोलह रिपब्लिक्सों में कम से कम एक विश्वविद्यालय है। उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त अन्य संस्थाएँ भी हैं।

७११३

३१-६०

## ग्रन्थ-सूची

## Bibliography

1. Armfelt, Roger.  
" *The Structure of English Education*.
2. Bernad, H C.  
*History of English Education*, U. L. P. Ltd, 1932.
3. Clemens Dutt (Ed.)  
*Fundamentals of Marxism-Leninism Manual*, Foreign Language Publishing House, Moscow.
4. Curtis, S. J.  
*Education in Britain Since 1900*, Dakors, 1932.
5. Hofstadter, Richard & Walter P. Metzgar.  
*The Development of Academic Freedom in the United States*, Columbia University Press, New York, 1955.
6. Johnson, William H. E.  
*Russia's Educational Heritage*, Carnegie Press, Pittsburgh, 1950.
7. Kandel, I. L.  
*The New Era in Education*, Houghton, Mifflin Co., U. S. A.
8. Kontalsoff, E.  
*Soviet Education*, Vol VIII, Basil Blackwell, Oxford, 1951.
9. Lester Smith, W. O.  
*Education in Great Britain*, Oxford, 1949
10. Nicholas Hans,  
*Comparative Education*, Routledge Kegan Paul, Ltd.
11. Stephens, W. E. D.  
*English Education*, Longmans, 1947.
12. Storr, Richard J.  
*The Beginnings of Graduate Education in America*, Chicago, University of Chicago Press, 1934.

